मोदी, मुसलमान और नरेंद्र

मोदी के गुजरात से मीडिया की आवाज़ें

मधु पूर्णिमा किश्वर

प्रस्तावना: सलीम खान,
प्रस्तावना: चो रामास्वामी

[redacted]

[redacted]

मानुषी प्रकाशन

नई दिल्ली
मानुषी पब्लिकेशन्स द्वारा पहली बार 2014 में प्रकाशित

ISBN: 978-81-929352-0-1

Cover photo: Narendra Modi leading Jansampark Yatra during राजकोट नगर निगम चुनाव, 2010।

Copyright © Madhu Purnima Kishwar, 2014
इस पुस्तक से प्राप्त सभी रॉयल्टी मानुषी ट्रस्ट को समर्पित है।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक का कोई भी भाग पुनरुत्पादित या किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक, सहित
फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या किसी भी सूचना भंडारण या पुनर्प्राप्ति प्रणाली द्वारा,
प्रकाशक से लिखित अनुमति के बिना।

लेखक और प्रकाशक चाहते हैं कि इन निबंधों का अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो।
क्षेत्रीय भाषाओं में यथासंभव - पुस्तक के रूप में और उसके अंशों के रूप में भी।
समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए। अनुवाद अधिकारों में रुचि रखने वाले लोग संपर्क कर सकते हैं।
निम्नलिखित पते पर:

madhukishwar@manushi.in
madhukishwar@csds.in
□□□□□□□: www.manushi.in

गुजरात के लोगों को समर्पित

भारत की जनता को एक नई उम्मीद का उपहार देने के लिए
गहरी निराशा के बीच
&

मेरे माता-पिता के लिए
मुझे सत्य और न्याय के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद।
चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े।

अंतर्वस्तु
चो रामास्वामी द्वारा प्रस्तावना 7
सलीम खान द्वारा प्रस्तुत 9

1. मुझे 2002 के बाद के गुजरात का अध्ययन करने की प्रेरणा क्यों मिली? 13
2. 'संघर्ष उद्यमियों' द्वारा निर्मित मोदी मिथक 22
गुजराती मुसलमान खुद अपनी बात कहते हैं
3. नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में हवाई जहाज से उतारा गया। 51
नमो का गुजरात की जनता के नाम पहला संदेश
4 शासन के तौर-तरीके सीखना 66
नौसिखिया NaMo की नौकरशाहों के साथ पहली बातचीत
5. मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 75
“Sabka Saath, Sabka Vikas” in Action
6 आपदा को अवसर में बदलना 98
भूकंप से तबाह गुजरात का कायापलट
7. भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 126
एक जीवित बचे व्यक्ति का वृत्तांत
8. कांग्रेस में NaMo को मिल रहे मुस्लिम समर्थन की "तेजी से बढ़ती लहर" पर दहशत 148
फरवरी 2002 में राजकोट से मोदी का पहला चुनाव।
9 कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 164
मोदी के गोधरा-पूर्व चुनाव में कांग्रेस का कानूनविहीन और घिनौना अभियान
10 निर्मल गुजरात और "हम कर सकते हैं" की भावना का लक्ष्य 177 मोदी के गोधरा-पूर्व भाषण

11 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 187
□□□□□□□□ □□ □□□□□?

अंतर्वस्तु

12 गोधरा दंगों के बाद किसे ज़रूरत थी? 211
कांग्रेस या नरेंद्र मोदी?
13 आतंकवादियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 235
मोदी ने कांग्रेस को हताशा की ओर क्यों धकेल दिया?
14 किसने बर्तन को उबलता रखा? 242
गोधरा दंगों के बाद के चार चरण
15 जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 264
राहत शिविरों के संबंध में काम करने वालों और शोर मचाने वालों के विचार
16 खोपड़ी और पिल्ले 283
मीडिया खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है, आग में घी डालता है।
17. क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 304
भारतीय राजनीति में गुजराती मुसलमानों की निर्णायक भूमिका शांति और समृद्धि के 18 वें अध्याय 322
क्या मुसलमान गुजरात के विकास की गाथा का हिस्सा हैं?
19 हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 338
गुजरात में हिंदू-मुस्लिम संबंधों की मिथक बनाम वास्तविकता
20 गैर-मुद्दों पर कमजोर विरोध 354
कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता और समर्थन क्यों खो दिया?
गुजरात के शहरों में नाइटलाइफ़ और फुटपाथ पर पिकनिक के 21 विकल्प (364)
गुजरात पुलिस की बदलती भूमिका और धारणाएँ
22 न्यास, धर्म और करुणा 378
नमो का गांधी जी और गौतम बुद्ध से जुड़ाव

उपसंहार 390
आभार 396

प्रस्तावना द्वारा

चो एस रामास्वामी
संपादक, थुगलक

2001 में आए भूकंप के बाद, जिसने हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को तबाह कर दिया था, गुजरात सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय पुनर्वास कार्यों के बारे में जानने के बाद से ही मैं श्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक बन गया था। मधु किश्वर की पुस्तक 'मोदी, मुस्लिम और मीडिया' पढ़ने के बाद तो मैं उनका और भी बड़ा प्रशंसक हो गया हूँ। जिस तरह से लेखिका ने मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार के कामकाज के बारे में अधिकारियों और आम लोगों से विस्तार से बातचीत की है; राज्य की स्थिति जानने के लिए गुजरात के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है; और अथक परिश्रम से जुटाई गई सामग्री का निष्पक्ष और उत्कृष्ट विश्लेषण किया है, वह इस पुस्तक को लगभग एक शोध प्रबंध बना देता है।
लेकिन अकादमिक शोधपत्र के विपरीत, यह पुस्तक अत्यंत रोचक है; मोदी के पूर्वाग्रही आलोचकों को करारा जवाब देने के साथ-साथ यह इतनी दिलचस्प है कि इसे पढ़ते समय आप पन्ने पलटते ही चले जाएंगे। मोदी के संकीर्ण सोच वाले विरोधियों को भी लेखिका की निष्पक्षता को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी और उनके शासन का उनका आकलन उनकी अपनी राय पर आधारित नहीं है, बल्कि उन अनेक विविध लोगों की धारणाओं पर आधारित है जिनसे वे मिलीं।
मोदी ने राज्य प्रशासन को इतनी कुशलता से कैसे संभाला? विनाशकारी भूकंप के बाद के प्रभावों को उन्होंने प्रशासन की बागडोर संभालते हुए कैसे संभाला? वे पूरे गुजरात में 24x7 बिजली कैसे उपलब्ध कराते हैं? उन्होंने अपनी कई योजनाओं में जनता की भागीदारी कैसे

सुनिश्चित की? उन्होंने राज्य की कृषि उपज में कई गुना सुधार कैसे किया? उनका प्रशासन प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने वाले प्रशासन के रूप में कैसे जाना जाता है? मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें सांप्रदायिक करार दिए जाने के बावजूद, गुजरात के मुसलमान उन्हें मित्र और मुक्तिदाता के रूप में क्यों देखते हैं?
ये और ऐसे ही कई सवाल मोदी के समर्थकों के मन में भी हलचल पैदा कर सकते हैं। यह किताब इन सभी सवालों के जवाब देती है। जैसे ही पाठक को ज़फ़र सारेवाला से परिचय कराया जाता है, किताब इतनी दिलचस्प हो जाती है कि उसे पढ़े बिना छोड़ा नहीं जा सकता। जब मोदी ज़फ़र से कहते हैं, 'तुम मेरे हो। पाँच करोड़ गुजरातियों में तुम भी शामिल हो। जब मैं नर्मदा का पानी साबरमती नदी में मिलाता हूँ, तो क्या मैं उसे जुहापुरा की मुस्लिम बस्ती से बहने से रोकता हूँ? नेहरू पुल के पास साबरमती के पानी का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है?' पाठक को एहसास हो जाता है कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला है जो उसे 8 मोदी, मुसलमान और मीडिया

एक ऐसे दृष्टिकोण से जहां से वह तथ्यों और सच्चाइयों के उस शानदार प्रवाह को देख सके जो मोदी और उनके शासन मॉडल के खिलाफ फैलाए गए सभी झूठे प्रचार को नष्ट कर देगा।
मधु किश्वर का काम किसी भी निष्पक्ष पाठक को हमारे समाज में फैलाई जा रही मोदी-विरोधी दुष्प्रचार की बेईमानी के बारे में आश्वस्त कर देगा। वे इस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं; और यही स्पष्ट संदेश मधु किश्वर ने अत्यंत प्रभावी ढंग से दिया है। सत्य से प्रेम करने वाले सभी लोग जो नरेंद्र मोदी और उनके मिशन को समझना चाहते हैं, मधु किश्वर के प्रति कृतज्ञता के पात्र हैं।

द्वारा परिचय

सलीम खान
पटकथा लेखक एवं स्तंभकार

हाल के समय में, अदालतों में होने वाले मुकदमों से ज़्यादा मीडिया ट्रायल महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमारी निष्पक्षता तथ्यों के व्यवस्थित विरूपण के आगे फीकी पड़ गई है। महाभारत और रामायण के विविध और गहन संस्करण बनाने में हमें लगभग पाँच हज़ार साल लगे, लेकिन हमारे वर्तमान युग में, हर समकालीन त्रासदी या प्रहसन के संदिग्ध संस्करण मिनटों में तैयार हो जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर, सत्य मीडिया का पहला शिकार रहा है। वास्तव में, वास्तविकता इतनी तेज़ी से विकृत हो जाती है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।
फिल्म प्रेमी होने के नाते, मुझे रशोमोन फिल्म से विशेष लगाव है। जापानी निर्देशक कुरोसावा की इस क्लासिक फिल्म में, चार लोग एक ही हत्या के गवाह होने का दावा करते हैं। लेकिन घटना का उनका वर्णन बिल्कुल अलग है—हर एक का वर्णन दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। फिल्म किसी एक वर्णन को प्राथमिकता नहीं देती और दर्शक को यह तय करने देती है कि कौन सा वर्णन सबसे अधिक विश्वसनीय लगता है। मेरा मानना है कि किसी कहानी के अनेक संस्करण सुनना हमेशा एक ज्ञानवर्धक अनुभव होता है—भावनात्मक और बौद्धिक दोनों रूप से। हालांकि, हाल के वर्षों में, हमारी राजनीति और सार्वजनिक जीवन इतना ध्रुवीकृत हो गया है कि लोगों को विविध आवाज़ें सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। यह बात विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के संदर्भ में सच है – जो हमारे समय की सबसे विवादास्पद हस्तियों में से एक बनकर उभरे हैं। एक ओर वे लाखों लोग हैं जो उनकी दिल से प्रशंसा करते हैं और उन्हें भारत का उद्धारकर्ता मानते हैं, जिनमें देश की

राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने और उसे उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता है।
दूसरी ओर, वे लोग हैं जो उन्हें भारत के अल्पसंख्यकों के साथ-साथ इसके लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। मोदी को भारत के लिए अभिशाप मानने वालों द्वारा दिया गया मुख्य प्रमाण 2002 के गुजरात दंगे हैं। उनका यह संस्करण, जो मोदी को हिटलर जैसे सामूहिक हत्यारे के रूप में प्रस्तुत करता है, राजनीतिक चर्चा पर हावी हो गया है। जो लोग इस "सत्य" को मान चुके हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त और निगरानी की गई विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा मोदी को क्लीन चिट दिए जाने और निचली अदालतों द्वारा भी समर्थन मिलने के बाद भी अपनी राय बदलने को तैयार नहीं हैं।
मधु किश्वर की पुस्तक 'मोदी, मुस्लिम और मीडिया' का महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने मोदी के कार्यकाल का गहन अध्ययन करने का प्रयास किया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने मोदी को बदनाम करने के आरोपों को पूरी तरह से अनुचित साबित करने के लिए ढेर सारे सबूत जुटाए।
यह पुस्तक हमारे राजनीतिक जीवन में वस्तुनिष्ठ तथ्यों को उनका उचित स्थान दिलाती है। मधु ने 2002 के बाद के गुजरात के अध्ययन के दौरान कई बार गुजरात का दौरा किया और इस गहन शोध पुस्तक के लिए सटीक सामग्री जुटाने में बहुत मेहनत की। वह एक प्रख्यात खोजी पत्रकार हैं; उनके साक्ष्य गहनता से जुटाए गए हैं और गहन अध्ययन के पात्र हैं। इस प्रयास में किए गए व्यापक और महत्वपूर्ण शोध को देखते हुए, भारत की जनता के कल्याण और स्वस्थ अंतर-सामुदायिक संबंधों की परवाह करने वाले सभी लोगों को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना

चाहिए और इसके निष्कर्षों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।
उनकी पुस्तक पुख्ता सबूतों और अब तक राजनीतिक पर्दे के पीछे दबे तथ्यों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत करती है कि 2002 के दंगों को भड़काने के दोषी होने के बजाय, मोदी ने वास्तव में सांप्रदायिक विभाजन को पाटने का काम किया, जिसे पिछली सरकारों ने राजनीतिक रूप से उकसाए गए दंगों के माध्यम से जानबूझकर बढ़ावा दिया था। वे आसानी से सत्यापित किए जा सकने वाले तथ्यों के साथ ठोस विवरण में बताती हैं कि मोदी ने दंगों को समाप्त करने के लिए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कैसे की। वे बताती हैं कि कैसे एक ऐसे राज्य में, जहाँ पिछली सरकारों के दौरान इतने दंगे हुए थे, मोदी ने गुजरात को सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त कर दिया। वे गुजरात के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2002 के बाद राज्य को पूरी तरह से दंगा-मुक्त दशक दिया है।
किश्वर के वृत्तांत को पढ़कर आश्चर्य होता है कि मीडिया ने हमें यह क्यों नहीं बताया कि मोदी ने फरवरी 2002 में (गोदरा कांड से कुछ ही दिन पहले) राजकोट से अपना पहला चुनाव मुस्लिम समुदाय के भारी समर्थन से जीता था।
यह बात समझ से परे है कि हमें यह मानने के लिए गुमराह क्यों किया गया कि मोदी का एजेंडा गुजरात को मुसलमानों को कुचलने के तरीके खोजने की प्रयोगशाला में बदलना था, जबकि किश्वर द्वारा जुटाए गए सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही मोदी ने समावेशी विकास एजेंडा को प्राथमिकता दी, जिसका एक प्रमुख उदाहरण विनाशकारी भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण की उनकी योजना थी।
अब तक हमने उन लोगों की आवाज़ें सुनी हैं जो मोदी की निंदा करते हुए गुजराती मुसलमानों की ओर से बोलने का दावा करते हैं। किश्वर

के विमर्श का महत्व यह है कि उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों मुसलमानों के साथ अपने वीडियो-रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों से व्यापक रूप से उद्धरण देकर मुसलमानों को स्वयं बोलने का अवसर दिया है।
इसलिए, यह महज एक और रशोमोन कहानी नहीं है। यह वास्तव में यह उजागर करती है कि कैसे एक सुनियोजित गलत सूचना अभियान ने आकार लिया। परिचय 11

यह प्रस्तुति 2002 के दंगों और गुजरात में मुसलमानों की स्थिति की पूरी तरह से भ्रामक तस्वीर पेश करती है।
कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्यारा भारत एक विशाल 70mm स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जहाँ दर्शकों को बैठने की जगह दी गई है ताकि वे 3-D प्रभाव का आनंद ले सकें – लेकिन कुछ लोग डर और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त चश्मे से ही इस स्क्रीन को देखने के आदी हो गए हैं। किश्वर की पुस्तक इन विकृत चश्मों को हटाकर एक स्पष्ट चश्मा प्रदान करती है, जिससे राष्ट्र की विशाल स्क्रीन पर चल रही इस महान फिल्म को देखा जा सके। फिल्म की अंतिम सफलता इसके समग्र प्रभाव पर, विकृतियों को तथ्यों से बदलने पर निर्भर करेगी। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 'गांधी' देखने के बाद जब मैं थिएटर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो मुझे लगा कि फिल्म देखने के बाद मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। इस पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित हो रही फिल्म का मुझ पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है।
किश्वर दिल से बोलती हैं; यही एक कारण है कि उनके पाठकों को उनकी बातें ईमानदार लगेंगी। इस पुस्तक में वर्णित मोदी के शब्द और कार्य अत्यंत प्रभावशाली और सत्यनिष्ठ हैं तथा हमारे देश के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिक हैं।

यह पुस्तक अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करती। लेकिन यह ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एसआईटी द्वारा किया गया गहन शोध किश्वर के तथ्यों और निष्कर्षों का समर्थन करता है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि किश्वर का काम लोगों को गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल पर नए सिरे से विचार करने और राज्य का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। समकालीन इतिहास के इस दौर की निष्पक्ष समझ भारत में लोकतंत्र की सेहत और सौहार्दपूर्ण अंतर-सामुदायिक संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्याय 1

मुझे ऐसा करने की प्रेरणा क्यों मिली?
2002 के बाद के गुजरात का अध्ययन करें

क्या किसी को याद है कि मुंबई दंगों के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे, जो 2002 के गुजरात दंगों से कम घातक नहीं थे? क्या किसी को मलियाना और मेरठ दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद है या कांग्रेस शासन के दौरान भागलपुर या जमशेदपुर दंगों के समय बिहार के मुख्यमंत्री का नाम याद है... नरेंद्र मोदी को ही शैतान का अवतार क्यों मान लिया गया है, मानो उन्होंने ही 2002 के दंगों में सभी हत्याएं करवाई हों?
सलीम खान का निजी साक्षात्कार, 2013
भारत में राजनीतिक चर्चा मोदी-विरोध से इतनी दूषित हो चुकी है कि अगर कोई ग्रामीण गुजरात की सड़कों की गुणवत्ता या राज्य के गांवों और कस्बों में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति की सराहना भी करे, तो उसे 'फासीवाद का समर्थक' करार दिया जाता है। कश्मीरी अलगाववादियों का बचाव करना, भारत में आतंकी दस्ते भेजने वाली पाकिस्तानी सरकार के साथ शांतिपूर्ण बातचीत पर जोर देना और खूंखार माओवादियों को गरीबों का रक्षक बताना राजनीतिक रूप से प्रचलित हो गया है। लेकिन गुजरात में शासन सुधारों की सराहना करना या मोदी को गुजरात को आजादी के बाद पहली बार 12 साल तक दंगा- मुक्त रखने का श्रेय देना राजनीतिक आत्महत्या के समान है— व्यक्ति को हमेशा के लिए फासीवाद के रंग में रंग दिया जाता है। मोदी-विरोधी खेमे द्वारा पैदा किए गए इस बौद्धिक आतंक ने मुझे मोदी के प्रति इस अत्यधिक चिंता के पीछे का कारण स्वयं जानने के लिए प्रेरित किया।

फरवरी 2002 में जब गुजरात के कुछ इलाकों में हिंसक दंगे भड़क उठे, तो मैंने भी राष्ट्रीय मीडिया और हमारे कार्यकर्ता मित्रों द्वारा प्रस्तुत कहानी को मान लिया और यह मान लिया कि मोदी 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में संलिप्त थे। इसलिए, मैंने भी मोदी के खिलाफ बयान पर हस्ताक्षर किए और मानुषी को लेख सौंपे जिनमें गुजरात सरकार को दोषी ठहराया गया था। हमने दंगा पीड़ितों के लिए धन भी जुटाया।
14. मोदी, मुसलमान और मीडिया

हालांकि, 2004 में एनडीए की हार का विश्लेषण करने वाले एक लेख में संक्षिप्त उल्लेख के अलावा, मैंने अपने नाम से कुछ भी लिखने से परहेज किया, क्योंकि मुझे गुजरात जाकर वहां की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव और आकलन करने का समय नहीं मिला। कश्मीर और पंजाब में विभिन्न दंगों और संघर्षों को कवर करने के मेरे पिछले अनुभवों ने मुझे सिखाया था कि व्यक्तिगत सत्यापन के बिना ऐसे मुद्दों पर कोई निश्चित राय बनाने के लिए मीडिया रिपोर्टों पर पर्याप्त भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मीडिया रिपोर्टें अक्सर लेखक के वैचारिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं। इसलिए, मैंने मोदी विरोधी अभियानकर्ताओं के साथ एकजुट होने से परहेज किया।
मैंने कई बड़े दंगों को कवर करने में काफी समय बिताया है—जिनमें 1984 का सिखों का नरसंहार, 1980 के दशक में मेरठ और मलियाना में हुए दंगों की श्रृंखला, 1993 में बंबई में और 1989 में जम्मू में हुए दंगे शामिल हैं। इसके अलावा, मैंने बिहारशरीफ, भिवंडी, जमशेदपुर और अहमदाबाद, सूरत आदि में हुए दंगों की श्रृंखला जैसे कई अन्य दंगों का भी गहन अध्ययन किया है। इन दंगों को कवर करने के

अपने अनुभव के आधार पर, मैं जानता था कि 1984 के दिल्ली दंगों को छोड़कर, जो कांग्रेस पार्टी की एकतरफा कार्रवाई थी, लगभग सभी अन्य दंगों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में भी, कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ बराबर की भागीदार थी। कांग्रेस पार्टी की यह संदिग्ध भूमिका, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी के वैचारिक आधार से पूरी तरह भिन्न थी, ने भारत के बड़े हिस्सों में कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानकार गुजरातियों ने निजी बातचीत में खुलासा किया था कि 2002 में भी, कांग्रेसियों का एक वर्ग दंगा भड़काने वाली भीड़ में उत्साहपूर्वक शामिल होता था और यहाँ तक कि उन्हें उकसाता भी था, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कुछ वर्ग उन्मादी भीड़ को हत्या, आगजनी और लूटपाट के लिए उकसा रहे थे। इसलिए, जब भाजपा को, और विशेष रूप से मोदी को, हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और उन्हें बदनाम किया जाने लगा, तो 'मोदी को हटाओ और नफरत करो' अभियान को लेकर स्वाभाविक बेचैनी महसूस हुई। यह बेचैनी तब और बढ़ गई जब वर्षों बाद यह स्पष्ट हो गया कि मोदी को बदनाम करने में शामिल लगभग सभी गैर सरकारी संगठन, कार्यकर्ता, पत्रकार और शिक्षाविद कांग्रेस पार्टी के सक्रिय संरक्षण में थे। वास्तव में, उनमें से अधिकांश को इस उद्देश्य के लिए भारी वित्तीय सहायता मिल रही थी।
उत्तर भारत में 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के दौरान, पीड़ितों के साथ काम करने वाले और उस अभूतपूर्व नरसंहार का दस्तावेजीकरण करने वाले हम लोगों का नारा था 'दोषियों को दंडित करो', हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, गृह मंत्री नरसिम्हा राव और दिल्ली के उपराज्यपाल की मिलीभगत स्पष्ट थी। फिर भी, न तो

प्रधानमंत्री, न ही गृह मंत्री और न ही उपराज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से खलनायक घोषित किया गया। लेकिन,
मुझे 2002 के बाद के गुजरात का अध्ययन करने की प्रेरणा क्यों मिली? 15

2002 के गुजरात दंगों के मामले में, पूरी चर्चा केवल एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई।
मेरे साथ एक साक्षात्कार के दौरान, फिल्म पटकथा लेखक सलीम खान ने एक दिलचस्प टिप्पणी की:
क्या किसी को याद है कि उस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे?
क्या मुंबई दंगे 2002 के गुजरात दंगों से कम घातक नहीं थे?
क्या किसी को मलियाना और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद है?
मेरठ दंगों के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे या भागलपुर या जमशेदपुर दंगों के समय कौन थे
क्या कांग्रेस शासन के दौरान दंगे हुए थे? क्या हम पूर्व के नेताओं के नाम सुनते हैं?
गुजरात के वे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में सैकड़ों दंगे हुए स्वतंत्रता के बाद का भारत? इनमें से कुछ दंगे तो पहले के दंगों से कहीं अधिक घातक थे।
2002 का हिंसक विस्फोट। राज्य में हर दूसरे महीने हिंसा भड़क उठती थी।
क्या किसी को याद है कि 1984 में दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास था?
भारत की राजधानी में सिखों का नरसंहार हुआ? नरेंद्र मोदी कैसे?

उसे साक्षात शैतान के रूप में चित्रित किया गया है, मानो उसने स्वयं ही सब कुछ अंजाम दिया हो।
क्या ये वही हत्याएं हैं जो 2002 के दंगों के दौरान हुई थीं? दूरदराज के दंगों की ही बात क्यों करें, जुलाई 2012 में लाखों बोडो और मुस्लिम लोगों के साथ हुए अन्याय को जानबूझकर भुला दिया गया है, जिन्हें उनके गांवों से बेदखल कर दिया गया था क्योंकि उनके घर जला दिए गए थे और नष्ट कर दिए गए थे। 8 अगस्त 2012 तक, लगभग 400 गांवों से विस्थापित होने के बाद, 4 लाख से अधिक लोग कथित तौर पर 270 राहत शिविरों में शरण लिए हुए थे। सभी रिपोर्टों के अनुसार, इन शरणार्थी शिविरों में रहने की स्थिति बेहद दयनीय थी। असम के मुख्यमंत्री ने सेना की तैनाती में चार दिन की देरी की, जबकि बड़ी संख्या में सेना की इकाइयां असम में ही तैनात हैं। उन दंगों को सिर्फ इसलिए भुला दिया गया है क्योंकि वे कांग्रेस शासन के दौरान हुए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि 2002 के दंगों को जायज ठहराया जाए या उन्हें भुला दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि अन्य दंगों को राजनीतिक पर्दे के नीचे दबा दिया गया है। यह केवल सभी अपराधों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की अपील है।
मुझे यह बात परेशान करने वाली लगी कि 'मोदी विरोधी' अभियान का नेतृत्व करने वाले लगभग सभी लोग न तो मुस्लिम हैं और न ही गुजरात के निवासी। तीस्ता सेतलवाद, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर मुंबई से हैं, जबकि शबनम हाशमी, प्रशांत भूषण और हर्ष मंदर दिल्ली में रहते हैं। गुजरात के भीतर से मोदी विरोधी ब्रिगेड के चार सबसे प्रमुख चेहरे - मल्लिका साराभाई, आकार पटेल, अमी याग्निक और अच्युत याग्निक - मुस्लिम नहीं हैं। जब भी किसी गुजराती मुस्लिम ने बोलने की कोशिश की है, 16 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

एक अलग लहजे में, उस पर बेरहमी से हमला किया गया है और उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है कि लोग दहशत से चुप हो जाते हैं। प्रख्यात मुस्लिम विद्वान मौलाना वस्तानवी को देवबंद विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ इसलिए कि वे इस विचार से सहमत थे कि गुजराती मुसलमानों को मोदी सरकार की समावेशी विकास नीतियों से लाभ हुआ है। उर्दू दैनिक 'नई दुनिया' के संपादक शाहिद सिद्दीकी को मोदी का साक्षात्कार करने मात्र के लिए गंभीर हमलों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसमें मोदी ने अपनी सरकार पर लगे विभिन्न आरोपों का बचाव किया था। सिद्दीकी ने उनसे मोदी विरोधी समूहों द्वारा पूछे जाने वाले सभी रूढ़िवादी प्रश्न पूछे थे और मोदी के प्रति उनका रवैया बिल्कुल भी नरम नहीं था। फिर भी, मोदी को अपना पक्ष रखने के लिए अखबार में जगह देने मात्र के लिए उन्हें इतना बदनाम किया गया कि उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सिद्दीकी ने जल्द ही मोदी विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी। अल्पसंख्यक अधिकारों के स्वघोषित रक्षक भारत में किस प्रकार की पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं जो एक पत्रकार को तीन बार निर्वाचित मुख्यमंत्री का साक्षात्कार करने का अधिकार नहीं देती, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस और वामपंथी दल उनसे खतरा महसूस करते हैं?
इसी तरह, अमिताभ बच्चन को गुजरात के पर्यटन विभाग के लिए एक विज्ञापन अभियान करने मात्र के लिए बुरी तरह से निशाना बनाया गया। अगर तीस्ता सेतलवाद, शबाना आज़मी और शबनम हाशमी जैसी कांग्रेस पार्टी की समर्थक अपनी मनमानी करतीं, तो वे गुजरात पर वैसे ही आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाना चाहतीं, जैसे दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद शासन के दौरान झेलने पड़े थे। केंद्र में यूपीए सरकार ने राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर युद्ध छेड़े बिना,

[illegible]

2001 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

हैं, “अगर मैं वाकई उन अपराधों का दोषी हूं जिनका आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है, तो सिर्फ माफी मांगना उचित जवाब नहीं है। मुझे इसके लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए ताकि मैं सभी के लिए एक सबक बनूं और कोई भी दोबारा ऐसे अपराध करने की हिम्मत न करे।” अदालतों में चल रहे कई मामलों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त और निगरानी की जा रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच के बावजूद उनका यह जवाब जबरदस्त आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह आमतौर पर अपनी बेगुनाही के प्रति दृढ़ विश्वास का संकेत होता है। हालांकि, मीडिया या हमारे शिक्षा जगत में कोई भी उन्हें उतना संदेह का लाभ देने को तैयार नहीं था जितना वे जाने-माने आतंकवादियों को उदारतापूर्वक देते हैं।
18 मोदी, मुसलमान और मीडिया

हमारे न्यायशास्त्र में, जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक हर किसी को निर्दोष माना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में, मीडिया, सभी वामपंथी बुद्धिजीवी और भाजपा विरोधी सभी गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक दल, जिनमें नरसंहार और अपराधों में शामिल दल भी शामिल हैं, अदालतों और जांच आयोगों के फैसले का इंतजार करने को भी तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एकमत होकर अपना फैसला पहले ही तैयार कर लिया था कि मोदी दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। वही मानवाधिकार कार्यकर्ता जो कुख्यात आतंकवादियों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उन्होंने किसी भी मुकदमे की शुरुआत से पहले ही मोदी को सामूहिक हत्यारा घोषित कर दिया। जैसे ही अदालतों ने मोदी को क्लीन चिट देना शुरू किया, उन्होंने संबंधित न्यायाधीशों पर हमला किया और उच्च न्यायालयों में अपील की। जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी ने भी मोदी को सभी आरोपों से बरी कर दिया, तब भी मोदी विरोधी लॉबी ने एसआईटी

[illegible]
[illegible]
[illegible]

मैंने उन लोगों के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन किया जिन्हें अब
तक समाज से बहिष्कृत या हाशिए पर रखा गया था।
जनसंख्याएँ —छोटे किसान , आदिवासी , दलित , मुस्लिम , ईसाई —
मोदी सरकार को देखें। क्या उनकी सरकार ने समावेशिता को बढ़ावा
दिया है ?
क्या इससे उनके लिए सामाजिक उत्थान का अवसर मिलेगा या उन्हें और
अधिक हाशिए पर धकेला जाएगा ?
मुझे 2002 के बाद के गुजरात का अध्ययन करने की प्रेरणा क्यों
मिली ? 19

गुजरात के मेरे अध्ययन में शासन सुधारों की प्रकृति भी शामिल है ,
जिसमें पुलिस सुधार भी शामिल हैं क्योंकि इन्हें उनके आर्थिक
विकास मॉडल का अभिन्न अंग माना जाता है। हालांकि , यह खंड केवल
निम्नलिखित तक ही सीमित है : □ मोदी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर
घोषित दृष्टिकोण और एजेंडा।
अक्टूबर 2001 में उन्होंने अपने वादों को कितना पूरा किया ; □
पुनर्निर्माण के दौरान उन्होंने जो शासन प्रणाली स्थापित की
भूकंप ने कच्छ को तबाह कर दिया ;
□ उन्होंने शुरुआती कुछ वर्षों में जिन प्रक्रियाओं और सुधारों
को गति दी ,
पदभार ग्रहण करने के महीनों बाद ;
□ गोधरा और गोधरा -पश्चात दंगों का विवरण , जैसा कि विभिन्न स्रोतों
द्वारा स्थापित किया गया है।
जांच आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ; □ मोदी का
मुस्लिम समुदाय के साथ संबंध , उनके शब्दों में
स्वयं मुसलमान ;

[illegible]

नरेंद्र मोदी के साथ वर्षों तक करीब से काम करने वाले अधिकारियों से कुछ सबसे गहन विवरण सामने आए हैं। इनमें कई 20 मोदी, मुस्लिम और मीडिया शामिल हैं।

वरिष्ठ और कनिष्ठ आईएएस अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, साथ ही जिला स्तर के स्थानीय सरकारी अधिकारियों के बयानों से भी जानकारी ली गई। गांवों, कस्बों और बड़े शहरों में कांग्रेस और भाजपा के राजनेताओं के बयान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, मैंने मोदी के मंत्रिमंडल और पार्टी सहयोगियों के साथ संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ भाजपा मंत्रियों और विधायकों से भी बात की। इन सभी जानकारियों से मुझे मोदी की कार्यशैली, संवाद कौशल, व्यक्तित्व और उनसे नियमित रूप से मिलने वाले लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों की अच्छी समझ मिली। इनसे उनकी प्रशासनिक शैली और संगठनात्मक क्षमता की दिलचस्प झलक मिलती है। मैंने विभिन्न आयोगों, समितियों, विभिन्न अदालती आदेशों और निर्णयों की रिपोर्टों के साथ-साथ गोधरा हत्याकांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट का भी सहारा लिया है।
गुजरात पर अपना अध्ययन शुरू करने के लगभग छह महीने बाद, जब तक मुझे मोदी के व्यक्तित्व की अच्छी समझ हो चुकी थी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान मैंने कई साक्षात्कार किए। छह सत्रों में फैले 15 घंटे से अधिक समय तक मैंने मोदी से बातचीत की। मोदी के साथ मेरी अधिकांश बातचीत वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। बाकी बातचीत के लिए मैंने सावधानीपूर्वक नोट्स बनाए। कई अध्यायों में मैंने उनकी रिकॉर्ड की गई बातचीत के अंशों को उद्धृत किया है।
चूंकि यह सारी जानकारी मुझे प्रतिदिन चौंका रही थी, इसलिए मैंने सैकड़ों लोगों के साथ अपनी बातचीत को वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि

मेरी अपील है कि कृपया इन आवाजों को ध्यान से सुनें। उन सभी नेक इरादे वाले लोगों से, जो हवा में फैली मोदी-विरोधी भावना से ग्रसित हो गए हैं, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ: मैं आपके साथ उन लोगों के तथ्यात्मक विवरण साझा कर रहा हूँ जो अपने वास्तविक अनुभवों के आधार पर बोल रहे हैं। वे ठोस सबूत दे रहे हैं कि वे मोदी को दानव की तरह पेश किए जाने को अस्वीकार्य क्यों मानते हैं। चूंकि उनके नाम और स्थान का उल्लेख किया गया है, इसलिए यदि आपको कोई संदेह हो तो कृपया स्वयं इसकी पुष्टि कर लें।
मुझे भली-भांति पता है कि कई लोग इस पुस्तक को मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का अतिरंजित वर्णन मानकर खारिज कर देंगे। उनसे मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि 12 वर्षों तक आपने उनके विरुद्ध फैलाई गई विषैली दुष्प्रचार को बिना सोचे-समझे स्वीकार किया है, जो उन बयानों और गवाहियों पर आधारित है जिन्हें अदालतों और एसआईटी टीम द्वारा प्रेरित, मनगढ़ंत और सरासर झूठा साबित किया जा रहा है। इसे उस दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान का एक आवश्यक प्रतिकार समझिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तीस्ता सेतलवाद के अधिकांश गवाहों के विपरीत, मुझसे बात करने वाले किसी भी व्यक्ति ने प्रशिक्षित भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन सभी ने वीडियो पर स्वाभाविक रूप से बात की। तीस्ता के कई गवाहों के विपरीत, इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा कही गई बातों से मुकरने की संभावना नहीं रखता है।
जो लोग मोदी से नफरत को धर्म बना चुके हैं, उनसे मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूँ: कृपया वैचारिक हमलों से मेरा खंडन करने के बजाय तथ्यों के आधार पर मुझे चुनौती दें। यदि बेहतर प्रतिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं, तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए सहर्ष तैयार हूँ।

अध्याय दो

मोदी मिथक का निर्माण किसके द्वारा किया गया
‘संघर्ष उद्यमी’
गुजराती मुसलमान खुद अपनी बात कहते हैं

मुसलमानों को हमारे लिए वोट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम सरकार से अपना काम तो करवाना चाहिए।
नरेंद्र मोदी ने 2003 में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। महेशभाई, आप पाँच मुसलमानों के साथ आना चाहते हैं, या 50, 500, या 5,000—अपनी पसंद का स्थान चुन लीजिए। मैं आप सभी से मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ... मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं उपलब्ध हूँ। - नरेंद्र मोदी ने 2004 में फिल्म निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट से कहा। दुर्भाग्य से, कुछ संघर्ष-आधारित उद्यमी संघर्षों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा लगता है मानो अगर मानवीय घृणा समाप्त हो जाए तो युद्ध उद्योग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इस घृणा में बहुत बड़ा निवेश किया है, इसलिए इस घृणा को जीवित रखना उनके लिए ईश्वर को जीवित रखने के समान है। वे इसी घृणा से अपना जीवन यापन करते हैं। - महेश भट्ट का निजी साक्षात्कार, 2013

2002 के बाद के गुजरात का अध्ययन करने के लिए मेरी पहली गुजरात यात्रा जनवरी 2013 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के साथ हुई। यह मीडिया और शिक्षा जगत में मोदी के आलोचकों से बनी रूढ़िवादी छवि से बिल्कुल अलग अनुभव साबित हुआ। शिखर सम्मेलन में, अहमदाबाद के एक मुस्लिम व्यवसायी ज़फ़र सारेशवाला से हुई एक आकस्मिक मुलाकात ने मुझे नरेंद्र मोदी और गुजरात में उनके शासन

मॉडल के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से परिचित कराया—यह सब ज़फ़र के मोदी और उनकी नीतियों के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था।
इसके विपरीत, मोदी विरोधी ब्रिगेड द्वारा प्रचारित मोदी की राक्षसी छवि उन लोगों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने मोदी से कभी दस वाक्य भी नहीं बोले हैं, गंभीर रूप से उनसे बातचीत करना तो दूर की बात है। ज़फ़र सारेवाला उन लोगों में से थे जिन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व किया।
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 23

2002 के दंगों के बाद उन्होंने मोदी के खिलाफ अभियान चलाया। जब उन्होंने मोदी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने की घोषणा की तो वे रातोंरात मशहूर हो गए। हालांकि, बहुत जल्द ही उन्होंने अपना रुख बदलने का फैसला किया।
ज़फ़र ने मोदी से संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि 2002 के दंगों में उनके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। जिस इमारत में उनके परिवार के फ्लैट थे, उस पर भी हमला किया गया और आग लगा दी गई। 1960, 1970, 1980 और 1990 के दशक में हुए कई दंगों में भी उन्हें इसी तरह का नुकसान झेलना पड़ा था - हर बार जब उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर राख हो गया, तो उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी।
पिछले कुछ महीनों में मैंने गुजरात पर टीवी बहसों में ज़फ़र की कुछ छोटी-छोटी बातें सुनी थीं। लेकिन चूंकि हमारे टीवी एंकर मोदी को एक फासीवादी कसाई साबित करने पर तुले हुए हैं, इसलिए वे ज़फ़र को शायद ही कभी अपनी बात पूरी करने देते थे। अक्सर ऐसा लगता था मानो उन्हें मोदी विरोधी अभियान को अधिक "संतुलित" दिखाने के लिए सिर्फ एक दिखावटी आवाज़ के रूप में लाया गया हो।

ज़फ़र सारेशवाला के साथ मेरी वीडियो-रिकॉर्ड की गई बातचीत कई मुलाकातों में कई घंटों तक चली। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी बाद की यात्राओं के दौरान, मैंने ज़फ़र द्वारा दिए गए सुरागों का अनुसरण करते हुए तथ्यों की स्वयं पुष्टि की और ज़फ़र ने मुझे जो बताया और ज़मीनी स्तर पर मैंने जो देखा और सुना, उसमें कोई विसंगति नहीं पाई। ज़फ़र की अपनी पृष्ठभूमि भी उल्लेखनीय है: मैं सुन्नी बोहरा समुदाय से संबंध रखता हूँ, जो सऊदी अरब से पलायन करके आया था।
लगभग 250 साल पहले। सुन्नी बोहरा और दाउदी बोहरा को आपस में भ्रमित नहीं करना चाहिए।
जो मुस्लिम आबादी का एक बहुत छोटा और महत्वहीन हिस्सा हैं।
इसके विपरीत, सुन्नी बोहरा एक विशाल रूढ़िवादी और शुद्धतावादी समुदाय है।
गुजरात भर में मुसलमान फैले हुए हैं। हम छोटे और मध्यम आकार के संगठनों के रूप में सफल हैं।
उद्यमी। गुजरात के अधिकांश मदरसे सुन्नी बोहरा समुदाय द्वारा संचालित हैं।
इस्लामी विद्वान मौलाना वस्तानवी भी सुन्नी बोहरा हैं। लोग सिर्फ बातें करते हैं।
देवबंद में तो एक मदरसा है ही, लेकिन डाभेल में सुन्नी बोहराओं का भी उतना ही पुराना मदरसा है।
जिसकी स्थापना 100 साल से भी अधिक समय पहले हुई थी।
धार्मिक मामलों में रूढ़िवादी होने के बावजूद, हम एक उच्च शिक्षित समुदाय हैं।
समुदाय। मेरी शारीरिक बनावट और "छवि" एक रूढ़िवादी व्यक्ति की है।

मैं मुसलमान हूँ। मेरी दाढ़ी है, मेरी पत्नी बुर्का पहनती है, हम दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे पास
हमने हज किया है और हम हर इस्लामी परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन हमारे विचार प्रबुद्ध हैं।
क्योंकि हम इस्लाम की शिक्षाओं को गंभीरता से लेते हैं।
जो लोग 2002 के दंगों के बारे में लगातार बात करते रहते हैं, वे यह भूल जाना चाहते हैं कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी।
दंगों की एक अंतहीन श्रृंखला की पराकाष्ठा। विभाजन के बाद के सबसे भीषण दंगे।
सन् 1969 में अहमदाबाद में एक घटना घटी; जिसमें 5,000 से अधिक मुसलमानों की हत्या कर दी गई।
उस नरसंहार में। लेकिन चूंकि उस समय 24x7 मीडिया नहीं था, इसलिए उन दिनों दंगे हुए। 24 मोदी, मुसलमान और मीडिया

इन दंगों का बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, इसलिए बाहर के किसी भी व्यक्ति को 1969 के दंगों के बारे में पता नहीं चला।
यह एक गाय से जुड़ी एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने एक चौंकाने वाले हंगामे को जन्म दिया।
उस समय कांग्रेस पार्टी के हितेंद्रभाई देसाई मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी केंद्र में सत्ता में थीं। 1969 के दंगों के दौरान, हमारा कार्यालय,
फैक्ट्री में सब कुछ जलकर राख हो गया। वहां कालूपुर नाम का एक इलाका है, जो
यह एक मुस्लिम मोहल्ले का केंद्र है। उस इलाके में, ठीक सामने रिलीफ रोड पर पुलिस स्टेशन है, वहां एक मस्जिद और कई मुस्लिम दुकानें हैं।

इनमें से कुछ दुकानें जलकर राख हो गईं। मुझे आज भी याद है, उस समय मैं पाँच साल का था।
उस समय, श्रीमती गांधी ने दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उस स्थान का निरीक्षण किया।
मैंने अपने दादाजी के साथ वह दृश्य देखा जब इंदिरा गांधी नीचे उतरीं
उसने अपनी कार से कहा, "आखिर ऐसा कैसे हो गया कि महज 40 मीटर की दूरी पर..."
पुलिस स्टेशन, मस्जिद और मुस्लिम दुकानों में आग लगा दी गई?
सजा की तो बात ही छोड़िए, उसके बाद एक भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया।
उस नरसंहार के बारे में। जगमोहन आयोग की रिपोर्ट सबके सामने है। देखो। पूरे समुदाय बिना किसी निशान के मिट गए। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्या उन पीड़ितों के बारे में बात नहीं हो रही है? क्या किसी ने इस घटना का दस्तावेजीकरण किया है?
वे 5,000 परिवार?
कई छोटे दंगों के बाद 1985 में एक और बड़ा दंगा हुआ।
यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक बार फिर, हमारी फैक्ट्री और हमारे घर में आग लगा दी गई।
1985 में गुजरात में कांग्रेस पार्टी के माधवजी सोलंकी सत्ता में थे और
केंद्र में राजीव गांधी का शासनकाल। 1985 से 2002 के बीच, लोगों को उनसे यही उम्मीद रहने लगी थी।
कि हर 2-3 महीने में अनिवार्य रूप से दंगा होता था। एक समय ऐसा भी था जब...
कर्फ्यू 200 दिनों तक चला।

1987 के दंगों के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के अमर सिंह चौधरी ने हिस्सा लिया था।
तब कांग्रेस मुख्यमंत्री थी। इसके बाद 1990 में दंगे हुए। उस समय भी कांग्रेस सत्ता में थी।
पार्टी के चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। फिर से, हमारी फैक्ट्री जल गई।
इसे गिरा दिया गया था। 1992 में भी इसे आग लगा दी गई थी। उस समय चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे।
उस समय भी।
दलित विरोधी हर दंगे को मुस्लिम विरोधी दंगे में बदल दिया गया, चाहे
1981 या 1985 में, हर दंगे में हमारा कार्यालय और कारखाना जला दिया गया था।
और हमें घोर अपमान का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस ने हमारी सहायता तक नहीं की।
एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद बीमा कंपनियों द्वारा अपमान का सामना करना पड़ा।
मुझे याद है, 1992 में मेरा व्यवसाय पूरे चरम पर था। लेकिन हमारी पूरी फैक्ट्री
सब कुछ राख हो गया। हमारे पास 1.5 करोड़ रुपये का बीमा था, लेकिन बीमा राशि
कंपनी ने हमें सिर्फ 9 लाख रुपये का चेक दिया। क्या किसी ने इस बात का दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे
क्या मुसलमान ऐसी प्रत्येक त्रासदी के बाद घटनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं?
सच्चाई यह है कि जहाँ पहले की सरकारें उदासीन रहीं; वहीं बाद में

प्रत्येक दंगे में, हिंदुओं ने स्वयं मुसलमानों के पुनर्वास में सहायता की। मैं हमेशा
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 25

मान लीजिए कि अगर गुजराती हिंदू 100 प्रतिशत सांप्रदायिक हैं, तो मुसलमान भी 100 प्रतिशत सांप्रदायिक हैं।
यह तो बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। इसका कारण यह है कि हिंदू सांप्रदायिक नहीं हैं।
कि गुजरात में मुसलमान समृद्ध होते रहें। वे सभी दंगे राजनीतिक रूप से प्रेरित थे।
यह एक सुनियोजित साजिश थी और कांग्रेस पार्टी इसकी मुख्य दोषी थी।
2002 के दंगों के बाद, हम आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे क्योंकि हम उस समय आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके थे।
शेयर बाजार। कम से कम 250 परिवारों ने मेरे माध्यम से अपनी आजीविका कमाई। हमारा
बैंक गारंटी को भुनाना पड़ा। नरेंद्र मोदी का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक जिन्होंने मुसलमानों के ऋण अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया।
उदाहरण के लिए, 2002 के दंगों के बाद अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, मैंने संपर्क किया।
मैंने ICICI बैंक से संपर्क किया और ऋण के लिए अपना घर गिरवी रखने की पेशकश की। लेकिन आखिरी समय में,
मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने मुझसे कहा, “ज़फ़रभाई, ‘M’ अक्षर आपको नुकसान पहुंचाएगा।

"एक अलिखित कानून जिसके तहत नकारात्मक सूची में शामिल 'सुश्री' को ऋण देने से इनकार किया जाता है।"
क्या नरेंद्र मोदी का नाम उन सूचियों में आता है? केवल कालूपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में।
और जमालपुर अक्सर नकारात्मक सूचियों में आता था। अगर आपका वहां घर होता, तो आप
उन्हें नकारात्मक सूची में डाल दिया गया। पूरे पाल्दी क्षेत्र में, जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं,
निवासी हिंदू हैं, उन्होंने केवल फैज़ मोहम्मद सोसाइटी को नकारात्मक छवि में रखा है।
क्योंकि वह एक मुस्लिम बस्ती है, इसलिए हमने उसे सूची में शामिल नहीं किया। उन्होंने हमें ऋण नहीं दिया, हालांकि हम
अन्य सभी योग्यताएं पूरी कर लीं।
हालांकि 2002 के दंगों के समय मैं इंग्लैंड में था, फिर भी मैं उनसे काफी हद तक जुड़ा हुआ था।
अहमदाबाद में हमारे मुख्य पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने से एक तरह का अहसास होता था।
इस बात से निराशा होती है कि हमारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है।
इंग्लैंड में रहने के दौरान, मैंने इसका इस्तेमाल किया।
ड्यूसबरी में रहने के लिए। ड्यूसबरी के तीन गुजराती मुस्लिम, साथ में दो अन्य लोग।
अन्य लोगों की उन दंगों के दौरान हिम्मत नगर के पास हत्या कर दी गई थी। वे गए थे।
सूरत जिले में अपने पैतृक गांव की यात्रा पर गए थे और भीड़भाड़ में फंस गए।
27 फरवरी की उस मनहूस रात के कुछ लोगों में से एक, जिसका नाम असवाल था, मेरा दोस्त था।

इंग्लैंड में पड़ोसी। लोग सहम गए थे और भयभीत थे और हमने सोचा कि यह
कुछ करने का समय आ गया है। इसलिए, हमने गुजरात सरकार से संपर्क करने का फैसला किया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। एल.के. आडवाणी, जो उस समय गृह मंत्री थे।
मंत्री जी को उस समय के आसपास ब्रिटेन आना था। मैंने इस संबंध में एक मामला दायर किया।
लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आडवाणी को इंग्लैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
ठीक वैसे ही जैसे नेशन ऑफ इस्लाम के लुई फराखान—एक अति दक्षिणपंथी अश्वेत
आवागमन के दौरान ब्रिटेन में प्रवेश से इनकार कर दिया गया। चूंकि मेरा मामला लंदन उच्च न्यायालय में स्वीकार कर लिया गया था, श्री आडवाणी ने...
वह स्पेन से वापस आ गया क्योंकि वह शर्मिंदगी से बचना चाहता था। उन्हें हिंसक प्रदर्शनों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में नकारात्मक खबरों का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए, मामला खारिज कर दिया गया, लेकिन मैं अपनी बात साबित करने में सफल रहा।
इसके बाद हमने मोदी के खिलाफ मुकदमा तैयार करने के लिए एक प्रमुख ब्रिटिश कानूनी फर्म को नियुक्त किया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष। इससे मैं रातोंरात हीरो बन गया, लेकिन 26 मोदी, मुसलमान और मीडिया

इससे मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने खुद से पूछा, हमें इससे क्या हासिल होगा?

क्या यह केस दायर किया जा रहा है? ठीक है, यह टीवी पर आएगा और विरोध का प्रतीक बन जाएगा।
मोदी आंदोलन। लेकिन इसका संभावित परिणाम क्या होगा? उस समय, भले ही
इंतेफादा आंदोलन अपने चरम पर था, जो फिलिस्तीनियों के बीच एक शांति आंदोलन था।
और इस्राइलियों को अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। दरअसल, ठीक उसी समय,
फ़िलिस्तीनी लोग शेरोन और पेरेज़ के साथ बातचीत के लिए बैठने वाले थे।
और इस पूरी बैठक का संचालन जॉर्ज बुश द्वारा किया जाना था। फिलिस्तीनी
यह मुद्दा कम से कम 60 वर्षों से चल रहा था। लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया?
हम दुनिया के बाकी हिस्सों में मुसलमानों की स्थिति पर भी नजर रख रहे थे।
मुसलमानों ने युद्ध लड़े और हर किसी से लड़ाई की। उन्हें इससे क्या मिला?
सभी? फ़िलिस्तीनियों की हालत देखकर मुझे बहुत निराशा होती थी। तीन
लेबनान में लाखों शरणार्थी बेहद दयनीय परिस्थितियों में रह रहे थे।
मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियाँ उन गरीब फिलिस्तीनी शिविरों की तुलना में स्वर्ग हैं।
अगर उन्होंने पहले ही बातचीत शुरू कर दी होती, तो ये तीन मिलियन शरणार्थी

वे स्थिर जीवन जी सकते थे। और कौन तय करता है कि फ़िलिस्तीनी या गुजराती क्या करेंगे?
मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ये आरामकुर्सी पर बैठे आलोचक? वे तो अपने आलीशान घरों में बैठे हैं।
वे दफ्तरों में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक की नौकरी करते हैं और लाखों डॉलर का वेतन पाते हैं। उनका काम बस इतना ही है कि...
ईमेल भेजें। गुजरात में जीना और मरना तो हमें ही है, फिर भी ये दूरियाँ
हमारे भाग्य का नियंत्रण पुरुषों के हाथों में है। वे भारत नहीं आना चाहते, वे नहीं आना चाहते।
अहमदाबाद का दौरा करें, और वे कोई ठोस काम करने की परवाह नहीं करते।
इंग्लैंड में उन वर्षों के दौरान इसने पैन- के बारे में मेरे द्वारा संजोए गए मिथक को भी तोड़ दिया।
इस्लामी एकता। मैं पहले सोचता था कि इस्लाम एक है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अरब, अरब ही हैं।
और पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही हैं। गुजरात को भूल जाइए, भारत के भीतर भी लखनऊ ही काफी है।
मुसलमान लखनवी हैं। उन्हें गुजराती मुसलमानों की मौत की परवाह नहीं है। सबसे बुरे
तब मुझे एहसास हुआ कि अगर आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं, तो सूरत के मुसलमान भी आपको
मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा।
मैं 2002 के लिए पैसे मांगने के लिए इंग्लैंड की मस्जिदों में जाया करता था।
दंगों के पीड़ितों से कह रहा हूँ कि आपको मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे भेज दीजिए।

पीड़ितों या उनके लिए काम करने वाले सामुदायिक गैर सरकारी संगठनों को। लोगों को पैसों की जरूरत है;
हमें घर बनाने की जरूरत है। लेकिन हमें बहुत कम मदद मिली।
उस समय मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमारे समुदाय को भिखारी बना दिया। मैं अपने भाई को बताता जो इसमें शामिल था।
अहमदाबाद के राहत शिविरों में, भगवान के लिए, इन लोगों को पहुँचाने के लिए कुछ करो।
शरणार्थी शिविरों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। मुसलमानों को भिखारी न बनने दिया जाए।
समुदाय।
मैं इंग्लैंड में अपनी आरामदायक जिंदगी जारी रख सकता था। मैं एक वित्तीय सेवा कंपनी। लेकिन, जब मैंने इंग्लैंड में मुसलमानों की उदासीनता देखी,
इससे मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। किसी को भी मृतकों की या उनके प्रियजनों की परवाह नहीं थी।
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 27

उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी सब अपनी-अपनी दुनिया में खुश थे।
गुजरात चर्चा का विषय बन गया था।
ड्राइंग रूम में कबाब खाते हुए होने वाली बातचीत के बारे में।
मैंने खुद से कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते।
ऐसे लोगों की सहानुभूति। लेकिन मैं मोदी के खिलाफ पहले ही यह जंग छेड़ चुका था।
मैं गुजरात भी नहीं लौट सका। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, मैंने सोचा कि जब तक

और जब तक हम बैठकर बात नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन हम किससे बात करें?
इस संवाद की शुरुआत किससे करें? खुद मोदी से क्यों नहीं?
मैंने इस विषय पर दो-तीन प्रमुख मुस्लिम विद्वानों से चर्चा की। उसी समय
समय आने पर हमें पता चला कि मोदी साहब अगस्त में इंग्लैंड आ रहे हैं।
17, 2003 को पहले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के संबंध में। मैंने सोचा, चलो...
उनसे मिलिए और पूछिए, आप खुद वड़नगर से हैं जहां आप उनके साथ रह चुके हैं।
मुसलमानों। आपको हमसे क्या समस्या है? मैंने यह विचार कुछ बुद्धिमानों के सामने रखा।
इंग्लैंड में इस्लामी विद्वानों ने कहा, यदि आप समस्या का समाधान चाहते हैं, तो
मोदी से बात करना सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें, आपको बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा, बाकी सब भूल जाओ। आपके अनुसार सही कार्य क्या है? क्या इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए? कुरान और हदीस के आधार पर मुझे मार्गदर्शन दें।
उन्होंने मुझे दसवीं हदीस सुनाई और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाईं। मुझे सलाह दी गई कि शांति के हित में मुझे बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
उन्होंने सुलेह हुदैबियाह का हवाला दिया और मुझसे पूछा, "इसके पीछे आपका क्या इरादा है?"
यह कदम?” मैंने कहा, मौलाना, दंगों के बाद की स्थिति में मुसलमानों ने सब कुछ खो दिया है।

प्रशासन के साथ संबंध। हम ऐसे माहौल में नहीं रह सकते जहाँ हम
हम प्रशासन से पूरी तरह कटे हुए हैं। हमें स्कूल, अस्पताल चलाने पड़ते हैं,
और हमारे पास मदरसे हैं। हर कदम पर हमें सरकार की मदद की जरूरत है। इन ज्ञानी मौलानाओं ने मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया। फिर मैंने खुद से पूछा कि
मैं मोदी से कैसे मिल सकता था? मैं पहले से ही मोदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कुख्यात था।
अभियान। इसलिए, मैंने अपने मित्र महेश भट्ट से संपर्क किया, जो एक प्रमुख भारतीय हैं।
फिल्म निर्देशक और निर्माता, जो इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं।
दंगों के तीसरे ही दिन अहमदाबाद पहुंचे और लगातार डटे रहे।
मुस्लिम समुदाय द्वारा।
पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है कि भट्ट साहब एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा।
नए घटनाक्रमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं।
इंग्लैंड। मेरी इच्छा है कि हम उनसे मिलें और बात करें। भट्ट साहब ने कहा, "ज़रूर।"
आपको मिलना ही होगा। अंततः सभी समस्याओं का समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही हो सकता है।
उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना किया, लेकिन अंततः, सभी निर्णय
बातचीत की मेज पर लाया गया।"
मैंने उनसे पूछा, लेकिन हम मोदी से कैसे मिलेंगे? उन्होंने कोई न कोई रास्ता निकालने का वादा किया।

मेरी मदद करो। कुछ दिनों बाद, भट्ट साहब ने वापस फोन किया और कहा, "मैंने अपने
मेरे दोस्त रजत शर्मा, जो मोदी के बहुत करीबी हैं, कहते हैं कि आपको भेजना चाहिए।
उन्हें एक ईमेल भेजें जिसमें यह बताया गया हो कि आप मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं।
28 मोदी, मुसलमान और मीडिया

इसलिए मैंने एक ईमेल भेजा जिसमें मैंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हमने मोदी का विरोध किया था। लेकिन अब हम
हमें लगता है कि हमने युद्ध के सभी विकल्प आजमा लिए हैं और हमें एहसास हो गया है कि अब कुछ भी हासिल नहीं होगा।
इससे बाहर। इसलिए, मैं मोदी से मिलना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें इससे क्या समस्या है।
मुसलमानों। रजत ने मेरा ईमेल मोदी साहब को भेज दिया। मुझे लगता है मोदी जी ने ज़रूर
मैंने अपने परिवार की पृष्ठभूमि की जांच की और पाया कि हम अच्छे लोग हैं।
कृपया ध्यान दें कि जब हमने मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया था, तब वे अभी तक नायक नहीं बने थे।
लेकिन वह सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक था; उसे मिलोसेविक, हिटलर आदि नामों से पुकारा जाता था।
अब मोदी साहब से मिलने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और लोग उनसे मिलने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
वे आपस में मिलकर उसकी प्रशंसा करते थे, परन्तु उस समय कोई भी मुसलमान
उससे खुलकर संपर्क करने को तैयार।

जल्द ही रजत के माध्यम से एक मुलाकात तय हुई। मेरे आग्रह पर रजत सहमत हो गया।
मोदी के साथ लंदन जाएं और उस बैठक में उपस्थित रहें।
हमें वेम्बली के किसी हॉल में उनसे मिलने के लिए बुलाया गया था।
मैंने जवाब दिया।
हमने कहा कि हम उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। वे मान गए और उन्होंने हमें शाम 5 बजे फोन किया।
सेंट जेम्स कोर्ट, जहाँ वह ठहरे हुए थे। यहाँ हम चिंता में प्रार्थना कर रहे थे।
मोदी के साथ हमारी पहली मुलाकात के दौरान ही, मेरे खिलाफ पहली खबर सुर्खियों में छाई रही:
“ज़फ़र सारेवाला ने मोदी के बारे में अपना रुख बदल दिया।” वही लोग जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था
जो लोग पहले मुझे हीरो मानते थे, अब उन्होंने मुझ पर जमकर हमला किया।
मैंने अपने आलोचकों से कहा कि अगर आप मोदी के इतने विरोधी हैं, तो आपको...
चुनाव में उन्हें हराने का रास्ता मिल गया। आखिरकार, मोदी ने चुनाव जीत लिया है।
दो तिहाई बहुमत से। इस चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। आप उसे हरा नहीं सकते।
चुनाव तो हो गए लेकिन आप यहां बैठकर उनका विरोध कर रहे हैं? आप तो दूसरों को मोदी से बात भी नहीं करने देते!
जब मैंने यह बयान जारी किया कि, "हम स्वागत करते हैं," तो हंगामा मच गया।
नरेंद्र मोदी की यात्रा, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री हैं।

गुजरात।" अचानक, मैं हीरो से विलेन बन गया। कई बड़े लोग
इंग्लैंड से लोग मुझे मोदी से मिलने से रोकने के लिए आए थे। मैंने किसी की बात नहीं मानी।
मैंने उनसे कहा कि जब फ़िलिस्तीनी शेरोन के साथ बैठ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते?
मोदी मुर्दाबाद? और आप किसी भी पैमाने पर मोदी को शेरोन नहीं कह सकते!
मौलानाओं ने मेरा समर्थन करते हुए कहा, "जब हम अपने दुश्मनों से बात कर सकते हैं, तो फिर क्यों?"
मोदी नहीं? आखिर वो तो हमारे ही हैं। हम उन्हें कॉलर से पकड़ सकते हैं।
क्योंकि वह हममें से ही एक है। यह इन कुछ मौलानाओं का साहस था और कुरान और हदीस से मिले मार्गदर्शन ने मुझे यह कहने की शक्ति दी, अगर 100 करोड़ मुसलमान मेरे खिलाफ भी हों, तो भी मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन
मोदी से मिलने से पहले ही मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और मुझे देशभर से 1100 नफरत भरे ईमेल मिले थे।
दुनिया। मैंने सोचा था कि यही मेरा जिहाद है।
हमें तय दिन पर शाम 5 बजे मोदी साहब से मिलना था। पाँच मिनट।
उससे पहले मुझे महेश भट्ट का फोन आया। अपने अनोखे अंदाज में, उन्होंने कहा: “जफरभाई, अगर आप मोदी की आंखों में सीधे देखकर यह नहीं कह सकते कि
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 29

मैंने कहा, "न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती, इसलिए इस बैठक में मत जाओ।"

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
But the poor Maulana, oh my God, he was branded as kaafir. Bahut zaleel kiya
[illegible]
[illegible]
[illegible]

इस मीटिंग के दौरान। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और हिंदी में "आयो" कहकर बातचीत शुरू की।
यार!” अंदर एक झूला था (गुजराती घरों में पाया जाने वाला एक स्टाइलिश झूला)
(घरों में)। उन्होंने मुझे झूले पर अपने बगल में बिठाया। क्योंकि उस समय
मोदी जी अक्सर गुजराती अस्मिता (पहचान) की बात करते थे, मैंने बातचीत की शुरुआत इस तरह की।
आप मुझसे थोड़े मिश्रित गुजराती हैं, ऐसा कहना गलत होगा। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ।
और अहमदाबादवासी हर लिहाज से सभी गुजरातियों में सबसे शुद्ध हैं, जबकि आप
वड़नगर से। तुम तुलनात्मक रूप से अशुद्ध गुजराती हो। वह हँसा और उन्होंने कहा, "हां, आपकी बात सही है।"
उस बैठक में रजत समेत लगभग अस्सी-दस लोग मौजूद थे।
शर्मा और तलहा, मेरा छोटा भाई, जो भारत से इतनी दूर आया था
बैठक के लिए। तलहा ने यह सब देखा था, और वह राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल था।
काम।
हमने मोदी से किसी भी प्रकार की रियायत की भीख नहीं मांगी। हमने यह नहीं कहा कि यह करो, या
हमारे लिए ऐसा कीजिए। मोदी से मेरा पहला बयान था, आप पांच करोड़ गुजरातियों की बात करते हैं।
क्या 60 लाख मुसलमान पाँच करोड़ में शामिल हैं? यदि उत्तर 'हाँ' है, तो
हम आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 'मैं केवल 4.5 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूं', तो

गुजरात के हिंदुओं के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 30 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उन्होंने कहा, “बेशक तुम मेरी हो। पाँच करोड़ गुजरातियों में से तुम मेरी हो।”
निश्चित रूप से शामिल है। जब मैं नर्मदा का जल साबरमती नदी में डालता हूँ, तो क्या मैं
जुहापुरा की मुस्लिम बस्ती से होकर इसे बहने से कौन रोक सकता है? वे कौन हैं जो इसे रोक सकते हैं?
नेहरू ब्रिज के पास साबरमती के जल से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले लोग कौन हैं?
मेरा अगला कथन था: आप जीवंत गुजरात के लिए, यहाँ आए हैं।
गुजरात की आर्थिक प्रगति। लेकिन इस प्रगति का कोई अर्थ नहीं होगा।
न्याय के बिना। पश्चिम दुनिया पर राज करता है क्योंकि ये देश सुनिश्चित करते हैं
अपने नागरिकों को न्याय दिलाना। और हमारा देश बुरी हालत में है— यहाँ मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।
केवल मुसलमानों का ही नहीं, क्योंकि हममें से हर कोई अपने देश में अन्याय का सामना करता है।
न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती।
उसके बाद मौलाना ने मोदी को न्याय के महत्व पर लंबा प्रवचन दिया।
वहां बैठे गुजरात के एक बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति ने भी यही बात दोहराई।
अपनी घड़ी देखते हुए। मोदी ने उस समय के लिए कोई और बड़ा कार्यक्रम तय कर रखा था।

शाम हो गई। लेकिन मोदी ने उनसे कहा, “घड़ी देखना बंद करो। मैं अपना समय बिताने जा रहा हूँ।”
अब इन लोगों के साथ समय बिताइए।” फिर उन्होंने हमसे कहा, “जितना समय चाहो ले लीजिए, और
मुझे जो कुछ भी कहना है कह दो।
फिर हमने दंगों के बारे में बात करना शुरू किया और उनसे पूछा, आप उस दिन क्या कर रहे थे?
27 फरवरी 2002 की सुबह? आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया?
सेना? आप जुहापुरा क्यों नहीं गए? आपने शरणार्थी शिविरों का दौरा क्यों नहीं किया?
उस दिन हमने मोदी से वे सभी सवाल पूछे जो एसआईटी ने पूछे थे।
उनसे बहुत बाद में मिले। और फिर भी, हम पर मोदी से चापलूसी करने के लिए मिलने जाने का आरोप लगाया गया।
उससे व्यक्तिगत मदद मांगना!
मौलाना ईसा मंसूरी मोदी के प्रति काफी सख्त थे, लेकिन मोदी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया।
उन्होंने अत्यंत आदर के साथ हमारी बात सुनी। उन्होंने चुपचाप हमारी बात सुनी, जिसकी हमें उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। “हिंदू हृदय सम्राट” (हिंदुओं के दिलों के सम्राट)। मौलाना ने उनसे कहा,
“मोदी साहब, बाकी सब कुछ भूल जाइए, हमें न्याय दिलाने में मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको न्याय मिलेगा।”
स्वतः ही आगे बढ़ जाना। हम न्याय की बात केवल इसके संबंध में नहीं कर रहे हैं।
भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या केवल 15 प्रतिशत है।
हिंदुओं की संख्या इससे कहीं अधिक है।

अन्याय के शिकार। सभी को न्याय उपलब्ध कराएं।” मौलाना ने सचमुच मोदी को बनाया
कटघरे में खड़े हो जाओ। चुनाव जीतने के बाद भी मोदी की परिपक्वता यही है कि उन्होंने ऐसा किया।
भारी बहुमत से प्राप्त इस फैसले को उन्होंने सम्मानपूर्वक सुना।
मैंने मोदी से कहा, देखिए, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लगभग 1,000 मुसलमान थे।
मारा गया। पालनपुर और वापी के बीच, भरूच के बीच जो कुछ भी होता है।
और जामनगर—अच्छा हो या बुरा—इसकी अंतिम जिम्मेदारी आपकी होगी।
आप हमारे मुखिया हैं।
मंत्री जी। जब भी कोई समस्या आती है, तो जो भी मुसीबत में पड़ता है — चाहे
हिंदू हो या मुसलमान—यह आपकी जिम्मेदारी है। हमें हमेशा यह अधिकार रहेगा कि हम
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह सब आपके कार्यकाल में क्यों हुआ?’ इस पर मोदी ने जवाब दिया, “हां,
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 31

यह दाग मेरे कार्यकाल के दौरान लगा था और मुझे इसे मिटाना होगा। (हाँ ये मेरे)
kaal ka kalank hai, aur mujhe usko dhona hai).
लोगों ने हमसे कहा कि मोदी कभी माफी नहीं मांगते। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, माफी मांगने का क्या मूल्य है?
क्या ऐसे मामलों में सिर्फ "सॉरी" कहने से काम चल जाएगा? अगर कोई कुख्यात सामूहिक हत्यारा आता है
और अगर वह सिर्फ मुसलमानों से माफी मांगता है, तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? हमारे पास एक अपराधी है।

इस देश की न्याय व्यवस्था, जो 'क्षमा करें' को उचित शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करती।
सजा। नरेंद्र मोदी की माफी का हमारे लिए क्या मतलब होगा? हम उनके फैसले का आकलन करेंगे।
मैदान पर उनके कार्यों के लिए 'क्षमा'।
हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, मोदी ने स्वीकार किया कि हमारी कुछ बातें गलत थीं।
कुछ बातें सही थीं, लेकिन कई बातें अतिशयोक्तिपूर्ण थीं।
उन्होंने बताया कि फरवरी में कैसे
2002 में, उन्हें अचानक मुख्य अधिकारी के रूप में भेजा गया था और वे प्रशासन में बिल्कुल नए थे।
अक्टूबर 2001 में मंत्री बने। वे सरकार में केवल साढ़े चार साल ही रहे थे।
दंगों के भड़कने के महीनों बाद, उन्हें दंगे के बाद फैली गड़बड़ी को साफ करने का काम सौंपा गया था।
पिछली सरकार द्वारा किए गए विरोध के बावजूद, भाजपा ने दिसंबर 2002 के चुनाव जीते।
फिर उन्होंने हमें दंगों को दबाने के लिए उठाए गए सभी कदमों के बारे में विस्तार से बताया।
27 फरवरी से आगे अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में।
हमने उनकी बात समझ ली क्योंकि 2002 के दंगों के विपरीत, जो केवल कुछ ही समय तक चले थे।
तीन दिन, कांग्रेस शासन के दौरान दंगे महीनों तक चलते थे।
अंत। इन पहले के कई दंगों में मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक थी।
2002 का। गुजरात में पुलिस और प्रशासन दोनों पूरी तरह से

सांप्रदायिकरण किया गया। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि ने ऐसा किया था।
जबकि कांग्रेस पार्टी ने हिंदू डॉन को संरक्षण दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम माफियाओं को संरक्षण दिया।
राजनीतिक कारणों से ये संगठित आपराधिक गिरोह बिना किसी रोक-टोक के काम करते रहे।
संरक्षणवाद। विशेष रूप से गुजरात का तटीय क्षेत्र माफियाओं के वर्चस्व में था।
जो दुबई से सोने और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी में शामिल थे।
यह वही गुजरात था जो मोदी को विरासत में मिला था, जो शासन के लिए लगभग एक बाहरी व्यक्ति थे।
अक्टूबर 2001। उनका यह कहना सही था कि फरवरी तक उन्होंने वास्तविक संपत्ति हासिल नहीं की थी।
प्रशासन पर नियंत्रण। उन पर पिछली जिम्मेदारियों का बोझ था।
शासन व्यवस्थाओं के बारे में। हमें इस बात से बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और अपनी राय दी।
हमें सटीक उत्तर मिले। उन्हें सभी तथ्य मुंह जुबानी याद थे।
हमने अब तक यह अनुभव किया है कि मुसलमानों को उचित सुनवाई नहीं मिलती है।
किसी ने भी नहीं। 1969, 1985, 1987 और 1992 के दंगों के बाद, किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया था।
उन्होंने हमारी बात सुनी। वे सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे।
मुझे याद है जब उसके बाद
1992 के दंगों के दौरान, अहमदाबाद के मुस्लिम समुदाय के शीर्ष नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

समुदाय के लोग नरसिम्हा राव से मिलने गए; उन्होंने उन्हें चार दिन तक इंतजार कराया।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे रमजान के महीने में आए हैं। मेरे चाचा उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। जब राव ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं की, तो 32 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

नियुक्ति के दिन मेरे चाचा वापस आकर बोले, “इसका क्या मतलब है?” क्या ऐसे व्यक्ति से मिलने का जोखिम है जो आपसे उस दिन नहीं मिलता जिस दिन उसने आपको समय दिया हो?
प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य चार दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। चौथे दिन,
उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था। कांग्रेस में मुसलमानों की यही स्थिति थी।
पार्टी! और ये किस तरह के मुसलमान थे? गुजरात के शीर्ष अधिकारी। समाज—मुस्लिम समुदाय के टाटा और बिड़ला। एहसान जाफरी, जो
मेरे पिता के 60 वर्षों तक सबसे करीबी दोस्त रहे व्यक्ति ने यह अपॉइंटमेंट तय किया था।
आपको लगता है कि एहसान जाफरी की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, उससे हमें कोई दुख नहीं हुआ?
दंगों के ठीक पहले दिन? उन्होंने उसी सुबह मेरे पिता से बात की थी।
उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
एहसान जाफरी गुजरात के पूर्व कांग्रेस सांसद थे। उन्होंने 1960 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस में शामिल हुए और 1972 तक शहरी इकाई के प्रमुख बन गए। 1977 में आपातकाल के बाद, जब पार्टी को अधिकांश भारतीय राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, तब जाफरी अहमदाबाद सीट जीतने में कामयाब रहे और छठी लोकसभा में सांसद बने।

इसके बाद, वे पार्टी में सक्रिय रहे और गुजरात में कांग्रेस सरकारों में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर रहे। कांग्रेस शासन के दौरान 1969 के दंगों में उनका घर भी जला दिया गया था। जाफरी की कहानी जारी रखते हुए:
एहसान जाफरी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। वे कांग्रेस के विधायक भी थे।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? कांग्रेस के पास काफी शक्ति थी।
गुजरात में भाजपा शासन के दौरान भी नगर निगम पर उनका दबदबा रहा। अहमदाबाद के मेयर कांग्रेसी थे। उन्होंने एहसान को क्यों नहीं बचाया?
जाफरी? उन्हें किसने रोका? उन्होंने मदद के लिए अपनी पार्टी के लोगों को फोन किया लेकिन उन्होंने मदद नहीं की।
उसे बचाने जाओ। दरअसल, कुछ कांग्रेसी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने हत्या की थी।
जाफरी।
मोदी के साथ हमारी बातचीत की बात पर वापस आते हुए, एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ।
जैसे हम किसी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हों। अपनी बात समझाने के बाद,
मोदी ने हमसे कहा, “ठीक है, मुझे आज की समस्याओं के बारे में बताएं। मुझे बताएं, क्या कोई समस्या है?
हिंदुओं के अवैध कब्जे में मौजूद किसी भी मस्जिद के नाम बताइए। उन लोगों के बारे में जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। विस्तार से बताओ।” मैंने कहा,
“मोदी साहब, हम इसके लिए तैयार होकर नहीं आए थे।” फिर मोदी ने एक कागज निकाला।

मैंने उनका फोन नंबर लिख दिया और कहा, "नरेंद्र मोदी आपके लिए उपलब्ध हैं।"
चौबीसों घंटे सातों दिन—चाहे आपको आधी रात को उसकी ज़रूरत हो या सुबह 5 बजे, मैं आपको अपना वादा देता हूँ।
मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको न्याय मिले।
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 33

जब मैंने जफर से पूछा कि क्या उन्होंने उस बैठक की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो उन्होंने कहा:
हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें नहीं लगा था कि बैठक ज्यादा देर तक चलेगी।
ढाई घंटे। हमने सोचा था कि हमें सिर्फ पांच मिनट मिलेंगे। आम तौर पर,
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसे समय में आम आदमी से बात नहीं करते।
अवधि। वे उनसे केवल एक याचिका प्रस्तुत करने और चले जाने के लिए कहते हैं। हमने उनसे बात की।
ढाई घंटे तक हर छोटी से छोटी बात पर चर्चा हुई।
तथ्यों की पुष्टि करने के लिए, मैंने दिल्ली स्थित हिंदी समाचार चैनल इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात का वर्णन इस प्रकार किया:
मौलाना ईसा मंसूरी ने मोदी को एक घंटे तक बोलने नहीं दिया; उन्होंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया।
harshest tones and words. Unhone to bakayda Modi ki class laga di (He gave
मोदी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। लेकिन मोदी ने उनमें से किसी को भी बीच में नहीं टोका।

एक मिनट। उनके जवाब देने के बाद, मोदी ने तथ्यों सहित विस्तार से जवाब दिया।
उन्होंने हर मामले का वर्णन किया। वह हर घटना को गहराई से जानता था और उसे चुनौती देता था।
कई कथित अत्याचारों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए, कई कमियों को स्वीकार किया गया है।
सरकार मदद पहुंचाने में नाकाम रही। तब उन्होंने मौलाना से कहा, “आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं।”
खैर, मैं केवल साढ़े चार महीने ही मुख्यमंत्री रहा था। जब यह
जब यह सब हुआ, तब मुझे प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। मैं विधायक भी नहीं बना था।
तब तक। इसलिए, प्रशासन पर मेरा पूरा नियंत्रण नहीं था। लेकिन सोचिए
पुलिस फायरिंग में मारे गए हिंदुओं की संख्या गिनिए।
मैंने सेना को इन जगहों पर भेजा था।” उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकारी जांच
गर्भवती महिला के गर्भ जैसी कई भयावह कहानियां मिली थीं। चीर-फाड़ कर खोल दिए जाने की बात तो हद से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे
उन्होंने कई राहत शिविरों का दौरा किया और मुसलमानों के पुनर्वास में किस तरह मदद की।
तब मौलाना ने कहा, "अगर यह सब सच है, तो आप इसे खुलकर क्यों नहीं कहते?"
मोदी ने जवाब दिया, “आप मुझे अपने कार्यों में असफल होते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन मुझसे यह कहने के लिए मत कहिए।”
इसे खुलेआम करो। वीएचपी के लोग मुझे खत्म कर देंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं।

रजत शर्मा ने कुछ मदरसों और मुस्लिम आवासीय परिसरों से जुड़ी घटनाओं का भी वर्णन किया, जिससे मोदी के इस दावे की पुष्टि हुई कि उन्होंने मदद के लिए सभी अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। मैंने इनमें से कुछ घटनाओं की पुष्टि गुजरात के लोगों और अन्य स्रोतों से की। प्रत्येक घटना की पुष्टि जानकार लोगों ने की। भाजपा के सबसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक सैयद शाहनवाज हुसैन ने ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया:
34 मोदी, मुसलमान और मीडिया

छोटा उदयपुर के पास गुलाम वस्तानवी के शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित एक अमरद्रासा है।
विश्वास। 2002 के दंगों के दौरान, इस मदरसे को एक हिंसक भीड़ ने घेर लिया था।
मदरसे के अंदर करीब 400 छात्र फंस गए थे। इनमें से कुछ मुस्लिम छात्र भी शामिल थे।
जब मैं वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री था, तब से ही उस क्षेत्र से मुझे फोन आ रहे थे। मैंने तुरंत ही,
नरेंद्र मोदी को उन सभी लोगों के जीवन को मंडरा रहे खतरे के बारे में सूचित किया।
छात्रों से त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। इस मामले में, साथ ही ऐसे अन्य सभी मामलों में,
नरेंद्रभाई ने पूरा सहयोग दिया। लेकिन जो खबरें सामने आईं, वे सब नकारात्मक थीं।
उन्होंने हत्याओं की बात तो की, लेकिन उन सभी लोगों का कोई जिक्र नहीं किया जो बच गए थे।
मोदी के समयोचित हस्तक्षेपों के कारण।
नरसंहार करने वालों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली है?

मुरादाबाद, भागलपुर, मेरठ और कई अन्य स्थानों में?
नेहरू के शासनकाल में भारत में सबसे अधिक दंगे हुए।
इंदिरा गांधी और यहां तक कि राजीव गांधी के शासनकाल में भी भयंकर दंगे हुए। गुजरात
आजादी से पहले भी यहाँ दंगे होते रहते थे। लेकिन उन्होंने इसे इस तरह पेश किया जैसे आजादी के दौरान दंगे हुए हों।
मोदी सरकार सांप्रदायिक थी और कांग्रेस सरकार के सभी अन्य कार्यकाल "धर्मनिरपेक्ष" थे।
शाहनवाज़ हुसैन की कहानी सुनकर मुझे 2003 में नजमा हेपतुल्लाह द्वारा सुनाई गई एक घटना याद आ गई, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों के दौरान मोदी से संपर्क किया था। उस समय वह कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा की उपसभापति थीं। वह मौलाना अबुल कलाम आजाद की परपोती हैं, जो एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और संयुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। आजाद स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री थे। हेपतुल्लाह 2004 में भाजपा में शामिल हुईं। मैंने फरवरी 2013 में फोन करके निम्नलिखित विवरण की पुनः पुष्टि की:
दंगों के चरम पर, मुझे आगा खान के कार्यालय से एक फोन आया कि एक कॉलोनी
हिंदू बहुल इलाकों के बीच बसे खोजा मुसलमानों को हमलों का डर सता रहा था। मैंने फोन किया।
आडवाणी जी, जो उस समय वाजपेयी की एनडीए सरकार में गृह मंत्री थे। आडवाणी जी ने मोदी से बात की। कुछ ही मिनटों में नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया।
और कहा, “नजमाबेन, कृपया चिंता न करें। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख करूंगा और
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

और अपने वादे के मुताबिक, मोदी ने तुरंत उस कॉलोनी की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी।
और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय मुसलमानों ने मुझे बताया कि चूंकि वह चारों ओर से घिरा हुआ था, इसलिए उसे कोई क्षति नहीं हुई। हिंदू बहुल इलाकों से घिरे होने के बावजूद, अगर दंगाई भीड़ वास्तव में कामयाब हो जाती
कंकड़िया नामक इस क्षेत्र पर हमला करने के बाद, बचने का कोई रास्ता नहीं था।
एक और नरोदा पाटिया। मेरा अनुभव यह था कि मोदी ने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया।
जो भी शिकायत उनके संज्ञान में लाई गई, उसे बहुत शीघ्रता से निपटाया गया। मोदी ने
संघर्ष उद्यमियों द्वारा गढ़ा गया मोदी मिथक 35

उन्होंने बोहरा और खोजा समुदायों की बहुत मदद की। वे सैयदना से मिलने भी गए थे।
दाऊदी बोहराओं के नेता, अपने 100 वें जन्मदिन पर। जब आगा खान आए, वह व्यक्तिगत रूप से मुझे धन्यवाद देने आए थे और शायद मोदी से भी मिले थे। तभी
मुझे एहसास हुआ कि मुसलमानों को भाजपा में ही सम्मानजनक स्थान मिलेगा। मैंने पूछा
2007 के चुनाव के दौरान मोदी से पूछा गया था कि क्या वह चाहते हैं कि मैं आकर प्रचार करूं।
उसके लिए। उसने कहा, “तुम्हें गुजरात आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम जानते हो
मेरा रवैया यही है कि आप दिल्ली से ही जितना कर सकते हैं, उतना करें।"

ज़फ़र की कहानी को आगे बढ़ाते हुए:
हमने मोदी का फोन नंबर ले लिया और उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। लगभग दो महीने बाद, अक्टूबर में, मैंने लंदन से मोदी साहब के कार्यालय में फोन किया और
मैंने अपना नाम और नंबर उनके कार्यालय में दे दिया। तीन घंटे के भीतर मुझे एक कॉल आया।
श्री मोदी के साथ फोन पर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था।
एक मुख्यमंत्री जो आम जनता से आने वाले फोन कॉल का जवाब देता है या उन्हें रिसीव करता है।
नागरिकों को, और वह भी इतनी तेजी से।
उन्होंने कहा, “अरे, मुझे याद करने में तुम्हें इतनी देर लग गई! हम अगस्त में मिले थे;
अब अक्टूबर है।” मैंने कहा कि मैं बस यह देख रही थी कि क्या वह वास्तव में मेरे संदेश का जवाब देगा।
मुझे फोन करो और मुझसे बात करो। उसने कहा, "बताओ, तुम कब वापस आ रहे हो?" मैंने जवाब दिया,
मोदी साहब, एक समस्या है। क्योंकि मैंने आपके खिलाफ इतना हंगामा किया था।
(humne aapki pehle jo band bajayi thhi), your police must be ready to handcuff
मेरे आने पर। अगर मुझे जेल हो गई, तो तुम मुझे बचाने नहीं आओगे! मैंने उससे फिर पूछा, "मुझे बताओ तुम कब आने का इरादा रखते हो?" मैंने उसे तारीख बता दी और उसने
भारत में उतरते ही अहमदाबाद में मेरी सुरक्षित वापसी के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी।

नवंबर 2003 में, मुंबई में गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने मेरा स्वागत किया।
मुझे सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिए।
जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आ गया हूँ, उन्होंने अपने सचिव से मुझे फोन करवाया।
और पता लगाया कि मैं उससे कब मिलने वाला था। जब मैं उससे मिलने गया, तो उसने कहा, "बताओ
मुझे मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं के बारे में बताएं। मुसलमानों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें वोट दें, लेकिन उन्हें कम से कम सरकार से अपना काम तो करवाना चाहिए।
ये मोदी के बिल्कुल वही शब्द थे। मुझे उनकी बेवजह प्रशंसा क्यों करनी चाहिए?
हिम्मत नगर में एक मुस्लिम डॉक्टर से संबंधित एक छोटी सी समस्या का जिक्र किया गया।
वह उस व्यक्ति को नाम से जानता था जो उस समय उस क्षेत्र का सरपंच था।
उसने मुझसे कहा कि मैं अपने डॉक्टर दोस्त से कहूँ कि वह जाकर रमनभाई से मिले। मेरे दोस्त ने ऐसा ही किया।
जैसा उसे बताया गया था, उसने वैसा ही किया और जिस व्यक्ति के पास मोदी ने उसे भेजा था, उसने आवश्यक काम पूरा किया।
तुरंत। बाद में, रमनभाई ने डॉक्टर से यह भी कहा, "आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं है।"
हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन कम से कम अपने काम और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए हमारे पास तो आएं।
सभी को नमस्कार, मैं आपका निर्वाचित प्रतिनिधि भी हूँ!
36 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मैंने इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को नागरिकों से इस तरह बात करते नहीं देखा था।
मुस्लिम समुदाय का न तो टाटा है और न ही बिरला।
मैंने ज़फ़र से पूछा कि क्या इस तरह का खुला स्वागत पाने वाले वे अकेले थे? क्या अन्य मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है? ज़फ़र ने कहा, “मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ मोदी ने आम मुसलमानों की पुकारों का भी उतनी ही तत्परता से जवाब दिया।¹ लेकिन महेश भट्ट का वृत्तांत आपको बहुत ही चौंकाने वाला लगेगा। सूरत में मोदी पर सार्वजनिक रूप से हमला करने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें मोदी का फोन आ गया था।”
यह वह विवरण है जो मैंने नरेंद्र मोदी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक महेश भट्ट से सुना। यह 28 जनवरी, 2013 को मुंबई में महेश भट्ट के साथ मेरे द्वारा किए गए वीडियो-रिकॉर्डेड साक्षात्कार से लिया गया है। मैंने अर्थ को जरा भी प्रभावित किए बिना कुछ मामूली संपादकीय परिवर्तन किए हैं।
2004 में, मैं महमूद मदनी साहब के साथ सूरत गया था एक विरोधात्मक टिप्पणी करने के लिए।
नरेंद्र मोदी का भाषण। लोगों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
उस समय गुजरात को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पैगंबर की एक हदीस है, जो मेरे पास थी।
मुझे यह बहुत पसंद था इसलिए मैंने इसे याद कर लिया। इसमें लिखा है, “मज़लूम हो तो मदद कर, ज़ालिम हो तो”
"वो भी मदद कर।" मैंने मौलाना से पूछा कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने समझाया कि

Prophet says, “Zaalim bhi bhai hai, zaalim ko uske zulm se mukt karaana is
तुम्हारा फ़र्ज़, तुम्हारा कर्तव्य। (यहां तक कि अत्याचारी भी तुम्हारा भाई है। उसे छुटकारा दिलाने में मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है।)
उसका अत्याचार भी तुम्हारा कर्तव्य है)। मैंने पूछा कि क्या यह हदीस में निहित है और
क्या पैगंबर ने सचमुच ऐसा कहा था? उन्होंने कहा, "हाँ, हर कोई मजलूम की मदद करेगा।"
लेकिन ज़ालिम नहीं, और जब ज़ालिम अपने ज़ुल्म से मुक्त हो जाता है, तब ऐसा होता है।
यह एक वास्तविक सफलता है।
मुझे याद है कि मैंने जमात-ए-इस्लामी के मंच से बोलते हुए कहा था, “Narendra Modi, sun rahe ho? Jis mazhab ko tum aaye din kehte ho ki ye
aatankvadiyon ki ek gangotri hai, uske Rasool ne kya kaha hai.” (Narendra
मोदी, क्या आप सुन रहे हैं? जिस धर्म को आप मूल स्रोत बताते हैं, वही धर्म!
आतंकवाद के बारे में, क्या आप जानते हैं कि इसके संस्थापक ने क्या कहा है!
मैंने मोदी के कई भाषणों की जाँच की है और कई लोगों से इसकी पुष्टि भी की है। मोदी ने कभी भी इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इस तरह की बात

1. मुझे इसका प्रमाण एक बिहारी मुस्लिम छात्र के खाते से मिला, जिसे यह दिया गया था।

मोदी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक संदेश के आधार पर मोदी से मुलाकात का अवसर मिला। पढ़ें: सुल्तान अलीमुद्दीन, “नरेंद्र मोदी को मेरा ट्वीट,” मानुषी, 1 फरवरी, 2014, वेब। http://www.manushi.in/articles.php? articleId=1750#.Uw3cNPSSxJM.
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 37

प्रवीण तोगड़िया और हरेन पंड्या जैसे लोगों ने भी कटु भाषा का प्रयोग किया है। भट्ट शायद इस गलत धारणा के तहत यह कह रहे हैं कि मोदी के भी ऐसे ही विचार थे। भट्ट के कथन को आगे बढ़ाते हुए: मैंने उस हदीस को पूरे जोश के साथ पढ़ा, जो मुझे मेरे अतीत की याद दिलाती थी।
मैं गांधी के बारे में समझता था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जो कहूंगा उसका क्या परिणाम होगा।
एक फोन कॉल में! उसमें कहा गया, “महेश साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि...”
आपसे बात करूंगा।" मुझे लगा कि यह एक शरारती कॉल है क्योंकि मैं खुलेआम उनसे झगड़ रहा था।
मैं उसके साथ थी, तो वह मुझे क्यों फोन करेगा? इससे पहले कि मैं उस सदमे से उबर पाती, उसने
फोन पर आकर मुझसे गुजराती में बात करने लगा, “महेशभाई केम
"छो?" (महेशभाई, आप कैसे हैं?)
मैंने कहा कि मुझे गुजराती समझ आती है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मेरे पिता गुजराती से थे।
मैं गुजराती था, लेकिन मुझे वहां की भाषा कभी नहीं आती थी। इसलिए मोदी ने हिंदी में बोलना शुरू किया और कहा,

“Suna hai ki aap humse bahut khafa hain.” (I hear that you are very angry
मेरे साथ)। मैंने कहा, हाँ, बहुत सी समस्याएं हैं। मेरे साथ किए गए अत्याचार।
गुजरात में मुसलमानों को न्याय नहीं मिला है। वे इधर-उधर भटक रहे हैं।
शोक मनाना और रोना।
He heard me out and said, “Maheshbhai, 5 aaiyye, 50 aaiyye, 500 aaiyye,
5,000 aaiyye, jahan aana hai aaiyye. Main milne ko taiyyar hoon. Main aapki
saari problems ko solve karne ke liye taiyyar hoon. Main aapko yehi kehna
chahta hoon ki main available hoon.” (Maheshbhai, you want to come with
पांच मुसलमान हों, या 50, या 500 या 5,000—आप अपनी पसंद का कोई भी स्थान चुन लें। मैं तैयार हूँ।
आप सभी से मिलकर खुशी हुई। आप मेरे ध्यान में जो भी समस्याएं लाएंगे, मैं उन सभी का समाधान करने के लिए तैयार हूं।
मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं उपलब्ध हूं।
मुझसे यह मत पूछो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मोदी के इस कथन में सच्चाई थी।
मेरे लिए यही बात मायने रखती है। दिल आवाज़ सुनता है और जान जाता है कि वह सच्ची है या नहीं।
हालांकि यह उस व्यक्ति की ओर से आया है जिससे आपने सार्वजनिक रूप से टकराव किया है। मैंने धन्यवाद कहा।

ऐसा कहने के लिए धन्यवाद। लेकिन चूंकि मैंने महबूब मदनी के मंच से बात की थी।
जमीयत के संबंध में, मैं आपका संदेश महबूबभाई को पहुंचा दूंगा और आपको सूचित कर दूंगा।
मैंने तुरंत महमूद मदनी को फोन किया और कहा, 'महमूदभाई, हदीस'
ne apna kamal kar dikhkaya hai, lagta hai Rasool ki Hadith jaake zaalim ki
chhaati cheer ke nikal gayi hai, kyunki zaalim ne phone kiya hai. Modi sahib ka
phone aaya thha. Unhone kaha thha ki aap logon ko jahan aana hai aaiye, main
aapki saari problems ko solve karne mein interested hoon.’ (Mehmoodbhai,
ऐसा लगता है कि हदीस ने अपना चमत्कार कर दिखाया है। ऐसा लगता है कि रसूल के शब्दों ने दिल को छू लिया है।
अत्याचारी की छाती से होते हुए उसके दिल पर वार किया क्योंकि अत्याचारी ने फोन किया था।
मुझे। मोदी साहब ने मुझे फोन किया और कहा कि हम जब चाहें उनसे मिलने जा सकते हैं।
हम जहाँ भी चाहते थे, वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार था।
38 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मुझे व्यक्तिगत रूप से भट्ट का यह संवाद कुछ फिल्मी और आत्म-प्रशंसात्मक लगा, लेकिन घटना को सच्चाई से बयान करने में उनकी ईमानदारी की मैं सराहना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा:
मदनी ने कहा, “बहुत अच्छा। हम अपनी शासी निकाय की बैठक करेंगे और

इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।” उस समय उनके पिता जीवित थे। इसलिए उन्होंने कहा, “मैं भी बात करूंगा।”
मैं अपने पिता को फोन करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे कभी जवाब नहीं दिया।
आज भी जब महमूदभाई से मेरी बात होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि महमूद भाई,
itihas pe jab main kitaab likhunga to ye to bolna padega ki usne mujhe phone
kiya thha, maine aap se kaha thha, aap ne governing board se meeting kari thhi
magar aap ne jawab nahi diya. (When I write my book on the history of this
मुझे कहना पड़ेगा कि मोदी ने मुझे फोन किया था, और मैंने आपको उनके बारे में बताया था।
प्रस्ताव। आपकी गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई थी, लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
He said, “Haan maine jawab nahi diya. Mere walid ne kaha ki haan baat
karni chahiye. Mere jo aas paas ke log thhe, unhone kaha ki ye nahi karna.
Iss baat par koi bhi baat karna sahi nahi hoga. Tum unki rajneeti mein mohra
"बन जाओगे।" (हाँ, मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे पिता ने कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। लेकिन)
मेरे आस-पास के सभी लोगों ने कहा कि मोदी का प्रस्ताव स्वीकार करना सही नहीं होगा। आप
उनकी राजनीति में महज एक मोहरा बनकर रह जाना।

आज भी अगर मैं महमूदभाई से बात करूं और उनसे पूछूं कि वे क्यों नहीं मिले, तो
मोदी की भी यही प्रतिक्रिया होगी। उनसे मेरी पहली बातचीत ऐसी ही रही थी।
Narendra Modi.
जब मैंने महेश भट्ट से पूछा कि उन्होंने खुद मोदी से मिलकर मुसलमानों की समस्याओं के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा, “मैं उनसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं उस संगठन का हिस्सा नहीं था। वह जमीयत की रैली थी।” मैंने जोर देकर कहा कि आप मुसलमानों की समस्याओं के बारे में जानते हैं; फिर सिर्फ जमीयत के साथ ही क्यों? आप XYZ के साथ भी जा सकते थे। भट्ट का जवाब कुछ संतोषजनक नहीं था, “देखिए, मैं किसी भी समूह से जुड़ा हुआ नहीं था। तीस्ता का समूह अपने दम पर काम कर रहा था। मैंने उस मंच से बोलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इराक आक्रमण के दौरान मेरी मुलाकात महमूदभाई से हुई थी।”
लेकिन किसी भी मुस्लिम समूह से संबद्ध न होने के बावजूद भट्ट ने प्राइम टाइम टीवी पर मोदी को गाली देने और उन पर जघन्य अपराधों का आरोप लगाने से कभी परहेज नहीं किया। भट्ट ने तीस्ता सेतलवाद को यह क्यों नहीं बताया कि मोदी उनकी सभी जायज शिकायतों का निवारण करने को तैयार हैं? भट्ट ने जवाब दिया:
मैंने तीस्ता को बताया क्योंकि उसे और दूसरों को पता चल गया था कि मैं ज़फ़र की मदद कर रही हूँ।
मोदी से मिलने के लिए। उन्हें लगा कि मैं किसी तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था।
गुप्त शांति प्रक्रिया। लेकिन कोई गुप्त रास्ता नहीं था; आखिर होना ही क्यों चाहिए?
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 39

समुदाय को समस्या है। ज़फ़र गुजरात में रहता है, उसे इसके बारे में पता है।
समस्या यह है कि मोदी अपने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ज़फ़र ने चुनाव लड़ा था।
उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली; वह इधर-उधर भटकता रहा; उसे किसी से भी मदद नहीं मिली, तो अब वह क्या करे?
उन्हें सरकार के साथ संवाद प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शायद यही कारण था।
इसे मेरे रुख में किसी प्रकार की नरमी के रूप में देखा गया। मैंने उनसे पूछा कि अगर तीस्ता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती हैं, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिल सकतीं? तीस्ता ने कभी मोदी से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? भट्ट ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता। मैं तीस्ता के इतना करीब नहीं हूं कि यह जान सकूं, और मैं आमतौर पर लोगों से उनके काम के बारे में नहीं पूछता।" जब मैंने भट्ट से पूछा कि शबनम हाशमी, जिनके साथ वह बहुत करीब से काम करते हैं, मोदी से मिलने क्यों नहीं गईं, जबकि मुसलमानों की समस्याओं को लेकर कोई भी उनसे मिल सकता था, तो उनका जवाब था:
मुझे नहीं लगता कि वह कभी ऐसा करेगी क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ये सब
चालबाज़ी। दरअसल, जब उसे पता चला कि शाहिद सिद्दीकीभाई इंटरव्यू ले रहे हैं...
मोदी, उसे लगा कि हमने इसमें हेरफेर किया है। मैंने उससे कहा कि वह सिर्फ कल्पना कर रही है।
मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं था।

मैंने भट्ट से पूछा कि पत्रकार मोदी का साक्षात्कार क्यों नहीं ले सकते? जब उनके पास मुसलमानों की ओर से शिकायतों की एक सूची है और आपने यह जता दिया है कि मोदी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं, तो वह उस सूची के साथ जाकर यह क्यों नहीं कहतीं, "मैं आपको फलां-फलां मुस्लिम समूह की मांगों की सूची दे रही हूं, मुझे दिखाइए कि आपका इरादा नेक है।" वह ऐसा कभी क्यों नहीं करतीं?
इस मौके पर भरूच की आसिफा खान, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “शबनम कभी मोदी से बातचीत नहीं करेंगी क्योंकि वह राजनीतिक रूप से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं।” महेश भट्ट ने शबनम का बचाव करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। वह कभी भाजपा में नहीं जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं भाजपा की विचारधारा के करीब नहीं हूं।”
मैंने कहा, महेशभाई, हम विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं; हम मुस्लिम समुदाय की जायज़ शिकायतों की बात कर रहे हैं। अगर आप और मैं 1984 के दंगों से नाराज़ थे, तो ऐसा नहीं था कि हम कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे थे। हम इसलिए नाराज़ थे कि कांग्रेस नेताओं ने भाड़े के गुंडों को उकसाकर निर्दोषों की हत्या करवाई। अगर आप लोगों की हत्या करते हैं, चाहे आप 'भारत माता की जय' का नारा लगाएं या 'लाल सलाम' (माओवादियों का लाल सलाम) चिल्लाएं, हत्या तो हत्या ही है। चूंकि आप मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हैं, तो क्यों न मोदी को एक सूची सौंपकर बताएं कि ये उनकी शिकायतें हैं, उन्हें दिखाएं कि आप उनकी भलाई चाहते हैं और उनका समाधान करेंगे? इस पर भट्ट ने कहा:
40 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मैंने शबनम से मोदी से मिलने के लिए कभी नहीं कहा। हालाँकि, अगली बार जब मैं
जब गुजरात में बाढ़ आई थी तब मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ वहां गया था।
2005 में, हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की तलाश कर रहे थे ताकि पता चल सके कि वे
उस प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य से सहायता प्राप्त करना। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुस्लिम
कई परिवार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उन्हें उनका उचित मुआवजा मिल गया है;
दरअसल, उन्हें यह हिंदुओं से पहले मिल गया था। मैंने बड़ौदा में मुसलमानों से भी मुलाकात की।
जिसने भी यही बात कही। एक तरह से, इससे आपका मनोबल थोड़ा गिर जाता है।
क्योंकि आप क्रोध की हवा में सवार हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आपका
यह आक्रोश 2002 की यादों पर आधारित है। जमीनी हकीकत बदल चुकी थी। बाढ़-
प्रभावित मुसलमानों को वही राशन और आर्थिक सहायता दी गई जो दूसरों को मिल गया। मुझे याद है मैंने रजत शर्मा से कहा था, कृपया श्री मोदी को बता दीजिए कि मुझे मिल गया है।
मैंने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। 2002 में, मैंने एक पूर्ण परिवर्तन देखा।
अहमदाबाद में कानून-व्यवस्था चरमरा गई थी और मुसलमान रह रहे थे।
आतंक में। इस बार, मैंने प्राकृतिक आपदा के दौरान मुसलमानों के चेहरे पर बहुत आशा की झलक देखी।

आपदा। सत्ता प्रतिष्ठान ने उनके साथ करुणा और देखभाल का व्यवहार किया।
इससे मुझे उम्मीद मिली कि नदी अपना रास्ता बदल रही है। दुर्भाग्यवश, कुछ संघर्ष उद्यमी संघर्षों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे
यदि मानवीय घृणा समाप्त हो जाए तो युद्ध उद्योग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, संघर्ष
उद्यमियों ने इस नफरत में बहुत बड़ा निवेश किया है। इस राक्षस को जीवित रखने के लिए।
अपने ईश्वर को जीवित रखना ही उनका उद्देश्य है। वे इस घृणा से ही पोषण प्राप्त करते हैं।
धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करने वालों को महात्मा गांधी का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि
महात्मा गांधी के ग्रंथों में क्षत्र (शत्रु) की कोई अवधारणा नहीं है।
मोदी विरोधी खेमे में महेश भट्ट ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन तथ्यों को सच्चाई से स्वीकार किया है। हालांकि, वे भी अपने वैचारिक पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकल पाए हैं और टीवी चैनलों पर मोदी पर हमले जारी रखे हुए हैं। ज़फ़र के बयान को आगे बढ़ाते हुए:
यह आरोप कि मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, या उन्होंने चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाए, ये दोनों आरोप निराधार हैं।
सर्वोच्च स्तर की जांचों से यह साबित हो चुका है कि चुनाव पूरी तरह से फर्जी हैं।
अदालत। दशकों से बार-बार होने वाले राजनीतिक रूप से नियोजित सांप्रदायिक दंगों के कारण

पिछली सरकारों के दौरान, गुजरात पुलिस और प्रशासन भी भारी रूप से प्रभावित थे।
सांप्रदायिक रंग में रंग दिया गया। फिर भी, मोदी ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर इसे नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की।
तीन दिनों के भीतर स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए।
इस दंगे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह भाजपा बनाम भाजपा का मामला इतना सरल नहीं था।
मुसलमान या सिर्फ वीएचपी बनाम मुसलमान। कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी उतने ही सहमत थे।
इसमें शामिल हैं। इनमें से कुछ श्रमिकों को दोषी भी ठहराया जा चुका है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।
कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दंगों में सक्रिय रूप से भाग लिया। यहां तक कि बाहर भी
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 41

एहसान जाफरी के घर पर, हत्या करने वालों में कई कांग्रेसी भी शामिल थे।
भीड़। गुलबर्ग सोसाइटी में हत्याओं के दोषी पाए गए लोगों में कांग्रेसी भी शामिल हैं।
जाफरी की हत्या में शामिल कांग्रेसियों में सबसे प्रमुख नाम हिम्मत का है।
उस समय अहमदाबाद के मेयर सिंह पटेल थे। यह एक घोर अन्याय है। न्याय के नाम पर उसे सजा नहीं मिली। तीस्ता उसका नाम कभी नहीं लेगी।
अहमदाबाद में वली दखनी का एक बहुत प्रसिद्ध मकबरा था, जो कि
18 वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि। सुभाष ब्रिज के पास स्थित यह समाधि स्थल।

पाल्दी में दंगाइयों ने एक मस्जिद के साथ-साथ इसे भी अपवित्र कर दिया था। उस समय,
हिम्मत सिंह पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस का अहमदाबाद में नियंत्रण था।
नगर निगम (एएमसी)। एएमसी ने रातोंरात पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मकबरे की जगह, उस जमीन पर बुलडोजर चलाया और उस पर सड़क बनाई। दंगाइयों ने केवल तोड़फोड़ की थी, एएमसी ने इसके सारे निशान पूरी तरह मिटा दिए थे।
mazaar . Such a hue and cry was raised over Babri Masjid. Wali Dakhani’s
मजार भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। जब उन्होंने कोशिश की तब बाबरी मस्जिद जर्जर हालत में थी।
उस पर मंदिर बनाने का काम चल रहा था। लेकिन यहाँ उन्होंने एक लोकप्रिय मजार पर बुलडोजर चला दिए।
साथ ही पास की मस्जिद के ऊपर से भी ज़मीन खोदी और दोनों के ऊपर एक सड़क का निर्माण किया।
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल विरोध जताने के लिए महापौर हिम्मत सिंह पटेल के पास गए।
और उसने उससे कहा, “हिंसक भीड़ ने केवल कुछ नुकसान पहुंचाया है। ऐसा क्यों हुआ?”
क्या आप उन दो पवित्र संरचनाओं को ध्वस्त कर देंगे? हमें उन्हें पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहिए।
मजार।” उनका जवाब था, “मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता।” इस पर, हमारे एक साथी ने कहा, “मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता।” सदस्यों ने कहा, “तो फिर आपमें और वीएचपी में क्या अंतर है? यह तो होगा ही।”

ऐसा प्रतीत हो जैसे आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हों। उन्होंने कहा, "आप व्याख्या कर सकते हैं।"
"इसे जैसे चाहो वैसे करो।" उसने इतनी धृष्टता दिखाई कि हमारे मुंह पर यह बात कह दी। ज़रा सोचो!
कांग्रेस का अहंकार! जब मुसलमानों ने इसी तरह की शिकायतें उठाईं तो
नरेंद्र मोदी के मामले में प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने हर एक समस्या का समाधान किया।
हमारी शिकायतों का शीघ्रता से समाधान किया जाएगा।
यह हिम्मत सिंह पटेल सोनिया गांधी का चहेता है। 2007 में,
जब भी सोनिया मैडम गुजरात आती थीं, वह उनके आसपास ही मौजूद रहते थे।
हमारे लिए वह मौत का सौदागर था। मुसलमान
सोनिया गांधी की हिम्मत सिंह से नजदीकी को लेकर वे बेहद नाराज थे। कांग्रेस जानती है कि वह दंगों में शामिल थी। यही कारण है कि... गुजरात में कांग्रेस 2002 का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन लोग उस पर जोर-शोर से चिल्लाते हैं।
केवल राष्ट्रीय टेलीविजन पर। यहां तक कि अब भी जब टीवी चैनलों पर बहसें होती हैं,
कांग्रेस को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं मिलता, जबकि भाजपा को मिलता है।
उनके पक्ष में बोलने के लिए गुजरात से चार से पांच विश्वसनीय मुस्लिम मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि
कांग्रेस को लगता है कि अगर वे मुस्लिम चेहरों को अपना प्रतिनिधि बनने देंगे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा।

वोट तब से ही विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और आरएसएस के एक वर्ग पर निर्भर हैं, जो मोदी, मुसलमानों और मीडिया से जुड़े 42 प्रकार के वोटों की मांग करते हैं।

उन्हें चुनाव लड़ने में मदद करें। कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में सहायक भूमिका निभा रही है।
गुजरात में वीएचपी।
रईस खान, जो 2008 तक तीस्ता सेतलवाद के दाहिने हाथ थे, ने निम्नलिखित विवरण देकर जफर के बयान का समर्थन किया। तीस्ता सेतलवाद, जिन्होंने मोदी विरोधी अभियान का नेतृत्व किया, मुंबई में रहती हैं, जबकि रईस खान को गुजरात में रहने और तीस्ता को दैनिक रिपोर्ट भेजने के साथ-साथ पीड़ितों को उनके मोदी विरोधी अभियान में शामिल होने के लिए जुटाने का काम सौंपा गया था। 2008 में उनका तीस्ता से मतभेद हो गया। एक वीडियो-रिकॉर्डेड साक्षात्कार में उन्होंने कहा:
मैंने तीस्ता सेतलवाद को दंगा करने वाली भीड़ की कई तस्वीरें दी थीं।
उस दौर के दौरान। उनमें पार्टी के जाने-माने कार्यकर्ताओं और नेताओं के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे।
कांग्रेस पार्टी, वीएचपी/बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ। तीस्ता में
उन तस्वीरों को कभी जारी नहीं किया गया जिनसे सांसदों पर आरोप लगते हैं।
तस्वीरें गायब हो गई हैं। उसने मुझे उनकी प्रतियां देने से इनकार कर दिया है।
मैंने उसे घटनास्थल से जो तस्वीरें भेजी थीं, उनका भी वह कभी ज़िक्र नहीं करती या दिखाती नहीं है।

मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले की तस्वीरें
उस दौरान। जब मैंने टीस्टा एंड कंपनी को यह बताना शुरू किया कि वे दंगों की एकतरफा तस्वीर पेश कर रहे थे, और उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया।
उन्होंने हिंदुओं पर हुए हमलों, उन्हें हुए नुकसान और हजारों लोगों की मौत के बारे में बात करने से परहेज किया।
जो लोग बेघर हो गए थे और राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए थे, उसने उन पर अपना गुस्सा निकाला।
एक दुष्प्रचार अभियान जिसमें यह दावा किया गया कि मुझे वीएचपी ने खरीद लिया था। अंततः
मुझे बिना कोई सूचना दिए ही संगठन से निकाल दिया गया।
मुझे अपनी बात समझाने का मौका मिला। इसके अलावा, टीस्टा ने झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाए।
दंगों के पीड़ितों की ओर से। यही कारण है कि कई पीड़ितों ने खुले तौर पर खुद को अलग कर लिया है।
खुद को उससे अलग कर लिया है। केवल वे मुसलमान जो तीस्ता से वेतन लेते हैं, वे ही अब भी उससे अलग हैं।
उसके साथ खड़ी रहती है। वह उन्हें मासिक भत्ता देती है ताकि वे स्तुतिचित्र बने रहें।
गुजरात दंगों के दौरान, उन्होंने प्रशिक्षित गवाहियाँ दीं। 2007 तक, जमीनी स्तर पर
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) के कार्यकर्ता के रूप में, मैं वितरण का प्रभारी था।
इन परिवारों को नकद राशि दी गई - यह सब हवाला के पैसे का हिस्सा था जो तीस्ता को मिलता था।
विभिन्न मुस्लिम देश—जिनमें से अधिकांश उसने अपने पास रखे।

रईस खान इस समय तीस्ता सेतलवाद के खिलाफ अदालती मुकदमे लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने न्यायाधीशों के सामने तीस्ता द्वारा झूठी गवाही देने और अदालतों को गुमराह करने के कई सबूत पेश किए हैं। रईस खान का विस्तृत साक्षात्कार मेरी अगली किताब में प्रकाशित होगा। ज़फ़र के वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए:
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 43

आइए, मैं आपको मोदी और उनके बीच के अंतर का एक और उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस नेताओं। जब एसईबीआई (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) मुझे बहुत परेशानी होने लगी, महेश भट्ट ने सुझाव दिया कि मैं सलमान से संपर्क करूं।
खुर्शीद न केवल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, बल्कि वे सुप्रीम कोर्ट में एक वकील। मैंने महेश भट्ट से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।
निजी एहसान। मैं बस उसे अपने कागजात दिखाना चाहता था। SEBI का फैसला मेरे लिए विनाशकारी साबित होगा।
छोटी कंपनियों ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए।
मुझे, और मेरी बात नहीं सुनी गई। सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों का विधेयक बनाया है।
मंत्रालय को स्पष्ट जनादेश दिया गया है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य
अगर कोई समस्या हो तो सबसे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से संपर्क करना चाहिए।
महेश भट्ट ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया और खुर्शीद ने मुझे आने को कहा।
दिल्ली में, अमुक तिथि को, वर्ष 2009 में।

तो हम उनसे मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली तक गए। उन्होंने मुझे घंटों इंतजार कराया लेकिन मुझे अपनी बात कहने के लिए 15 सेकंड भी नहीं दिए गए। उसने बस इतना कहा...
क्योंकि यह मामला एसईबीआई और वित्त मंत्रालय से संबंधित था,
वह कुछ नहीं कर सका। मैंने उससे कहा कि मुझे किसी तरह की मदद नहीं चाहिए।
लेकिन मंत्री होने के नाते, वे कम से कम मेरी समस्या सुन तो सकते थे। लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया।
मेरी बात सुनो भी। तुम्हारा काम हुआ है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, कम से कम।
आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरी ओर, हमारे पास मोदी साहब हैं—अगर आप उन्हें बुलाते हैं तो।
उनके कार्यालय में जाकर संदेश छोड़ दें, आपको कुछ घंटों में कॉल आ जाएगी।
हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली ने दस वर्षों में हमें कभी निराश नहीं किया है। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए सच है।
सभी के लिए; मुख्यमंत्री कार्यालय आपका नाम और नंबर पूछेगा, और मोदी
हम आपको व्यक्तिगत रूप से कॉल करेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए उनकी एक मानक प्रक्रिया है।
खुर्शीद से हुई उस मुलाकात के बाद, मैं हमारे रिश्ते को लेकर चिंतित था।
इस देश में मुसलमान होने के नाते। जब मेरे साथ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते, ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे
ज़रा सोचिए, एक आम मुसलमान का क्या हाल होगा! हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं—बंद करो।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भंग करो; बस हमें हमारे संवैधानिक अधिकार दे दो।
आम नागरिकों के रूप में। समस्या यह है कि वे मुझे एक नागरिक के रूप में मेरे अधिकार नहीं देते।
आम नागरिक और फिर वे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन करते हैं और
हमें 15 सूत्रीय कार्यक्रम दीजिए, जिसे लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को मेरा संदेश है: मुझे मेरे बुनियादी अधिकार वैसे ही दिए जाएं जैसे मुझे दिए जा रहे हैं।
यह गुजरात सरकार द्वारा किया गया है; हमें कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहिए।
आइए, मोदी की प्रतिक्रियाओं में अंतर का एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
कांग्रेस पार्टी के उच्च और शक्तिशाली लोगों की तुलना में शिकायतों के प्रति अधिक संवेदनशील।
हम मुसलमानों के पुनर्वास कार्यों और कानूनी मामलों में सहायता कर रहे थे,
हमने फैसला किया कि न्याय व्यवस्था अपना काम तो करेगी ही, लेकिन हमारा मुख्य काम
हमारा लक्ष्य अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए हमें यह करना होगा...
शिक्षा के लिए जिहाद शुरू करो। 2001-02 तक, केवल तीन मुस्लिम थे। 44 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

इस शहर में कई मुस्लिम स्कूल हैं। आज अकेले अहमदाबाद में ही 17 मुस्लिम स्कूल हैं।

कई मुस्लिम कॉलेज भी हैं। जमालपुर में एफडी कॉलेज है, जहाँ 100 से अधिक छात्र पढ़ते हैं।
1,000 लड़कियां पढ़ रही हैं। मेरी भाभी और मेरी बहन एक गरीब इलाके में स्कूल चलाती हैं।
शाहपुर का वह इलाका, जहां 650 से अधिक लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं। हम
मैं चाहता हूं कि इस काम को प्राथमिकता मिले—सिर्फ किसी टेलीविजन चैनल पर न दिखाया जाए।
मोदी की निंदा करो और धर्मनिरपेक्ष नायक बनो।
जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, लाइसेंस राज भारत में कहीं भी स्कूलों के लिए बहुत बुरा है।
लेकिन गुजरात में मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं।
मोदी के सत्ता संभालने के बाद ही स्थिति में सुधार आया। कुछ साल पहले तक एक अलिखित समझौता था।
ऐसा कानून बनाया गया कि मुस्लिम स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए,
किसी मुसलमान ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। जब आपको पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसका क्या मतलब था?
आपने कितनी भी कोशिश की, अनुमति नहीं मिली? अब हालात बदल गए हैं। अलग-अलग तरह के विकल्प मौजूद हैं—अगर आप चाहें तो सरकार से आपको काफी प्रोत्साहन मिलता है।
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी करना।
हमने श्री मोदी से कहा कि हमें उनसे केवल दो चीजें चाहिए: रसद संबंधी सहायता।
समर्थन और यह वादा कि प्रशासन इसमें बाधा नहीं डालेगा

हमारे वाहन। सरकार के रसद संबंधी सहयोग के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है।
आप जहां चाहें वहां स्कूल शुरू नहीं कर सकते। मोदी ने वाकई में सही बात कही है।
उस आश्वासन के प्रति। प्रशासन आज बहुत ही तत्पर है।
मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक पहल।
गुजरात सरकार द्वारा एक पारदर्शी और नियम-आधारित प्रणाली स्थापित करने से स्कूल खोलना आसान हो गया है, जिससे मनमाने ढंग से अनुमति अस्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। शिक्षा विभाग ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं और आवेदन स्वीकार किए जाने से पहले पूरी की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताओं की सूची दी है। यह सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे, साथ ही भूमि स्वामित्व प्रमाण और स्कूल भवन निर्माण पूरा होने जैसे दस्तावेजी प्रमाण भी देने होंगे। स्वीकृति देने वाली समिति को आवेदन केवल बैठक के दिन ही देखने को मिलते हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने वालों को अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, और आवश्यकताओं को पूरा न करने वालों को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभाग को अस्वीकृति के कारणों को ऑनलाइन प्रकाशित करना होगा। यदि फिर भी किसी को कोई शिकायत है, तो वह शिकायत निवारण की सुव्यवस्थित 'स्वागत' प्रणाली का उपयोग कर सकता है, जो व्यवस्थित पहुँच और मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करती है। इसी से रिश्वतखोरी वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का अंत हुआ है, जिसने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को भी निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति दी थी। मोदी प्रशासन को नियंत्रित नहीं करते।
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 45

मुख्यमंत्री-केंद्रित प्रणाली उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेपों पर निर्भर करती है; इससे वह गति और निष्पक्षता प्राप्त नहीं हो पाती जो नियम-आधारित पारदर्शी प्रणाली से संभव है। इसके अलावा, विभाग को स्कूलों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व दिया गया है, न कि अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करने का।
हालांकि, कई बार मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। ज़फ़र बताते हैं कि मोदी ऐसी स्थितियों को कैसे संभालते हैं:
मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे मोदी चीजों को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
उदाहरण के लिए, हिंदू ट्रस्ट द्वारा संचालित नूतन स्कूल बापू नगर में स्थित था।
जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मध्य में स्थित है। लेकिन, जब मुसलमानों की संख्या
जब इनकी संख्या बढ़ी, तो उन्होंने इसे एक मुस्लिम प्रबंधन को बेच दिया। इसमें 1,400 मुस्लिम लड़कियां हैं।
सुबह की शिफ्ट में 1,400 लड़के पढ़ रहे थे, और दोपहर की शिफ्ट में 1,400 लड़के थे। एक रात,
अचानक एक रविवार को रात 10:30 बजे मुझे एक फोन आया।
स्कूल चलाने वाले सज्जन ने कहा, "जफर मियां, एक बड़ी समस्या है।" हमारे स्कूल की इमारत को गिराया जाने वाला है। पुलिस पहले से ही यहाँ मौजूद है और
वे इसे सुबह दस बजे गिराने की योजना बना रहे हैं। मोदी के अलावा कोई इसे बचा नहीं सकता।
हमारा स्कूल।" मैंने मजाक में जवाब दिया कि अब तुम्हारे लिए सिर्फ मोदी ही हैं, मानो
अल्लाह मियां गायब हो गया है। मानो मोदी ही भगवान हों! अब रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं कैसे करूँ?

इतनी देर रात मोदी को फोन करना? उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उन्हें उसी समय फोन करूं।
यह घटना 2007 में घटी थी। आपको विश्वास नहीं होगा, रात के 10:45 बजे मैंने फोन किया।
मोदी अपने आवास पर थे। उनके सचिव ने मुझे बताया, “साहब बाहर गए हैं।” मैंने उन्हें बताया।
कृपया मोदी साहब से कहें कि वे कल सुबह सात बजे से पहले मुझे फोन करें।
सुबह 6:59 बजे मोदी ने मुझे फोन किया और कहा, "तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते थे?"
मुझे सुबह-सुबह?” मैंने कहा, “सर, बापू नगर में एक मुस्लिम स्कूल है—मुझे नहीं पता।”
मुझे नहीं पता कि यह इमारत अवैध है या वैध। मुझे बस इतना पता है कि नगरपालिका
इसे गिराने वाले हैं। लेकिन आपको इसे बचाना होगा। उन्होंने कहा, "आप लोगों ने मुझे इसमें डाल दिया है।"
यह एक मुश्किल स्थिति है। यह एक अवैध ढांचा है और उच्च न्यायालय का आदेश है कि
नगर निगम को सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त करना होगा।” मैंने यह बात कही।
अगर यह किसी स्कूल से संबंधित है, तो आपको मदद करनी होगी। मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया, "अगर
स्कूल ध्वस्त हो जाता है, उससे निपटने का सिरदर्द शुरू हो जाता है।
आखिरकार 2,800 बच्चे भी मेरे सिर पर बोझ बनेंगे! इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा।

उस दिन मोदी ने तोड़फोड़ रोक दी। बाद में, उनके अधिकारियों ने सलाह दी
हमें बताएं कि स्कूल को कानूनी मान्यता कैसे दिलाई जाए।
एक और घटना है जिसे याद करना उचित है। 2005 में, तीन प्रमुख मुस्लिम
गोधरा हत्याकांड के सिलसिले में विद्वानों के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे।
उनके घरों पर वारंट पहले ही चिपका दिए गए थे। वे लोग मेरे पास आए। और उन्होंने कहा, “अहमदभाई दिल्ली के एक प्रमुख मुस्लिम नेता हैं; हम उन्हें फोन करेंगे।”
मैंने उनसे मदद मांगी।” मैंने उनसे कहा, भले ही आप उन्हें फोन करें, लेकिन वह शासन करने वाले 46 मोदी, मुसलमान और मीडिया नहीं हैं।

यहां। इन विद्वानों की मदद के लिए आपको अंततः मोदी से बात करनी होगी।'
उन्होंने कहा, “नहीं, हम अपने अहमदभाई से बात करेंगे।” उन्होंने चार अलग-अलग फोन पर कॉल किया।
उन्होंने कई बार नंबर डाले लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने अपने फोन नंबर छोड़ दिए।
उन्होंने अपने कार्यालय में कहा, "हमें पूरा यकीन है कि वह आज रात तक हमें वापस फोन करेंगे।" अगले दिन
उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, "उन्होंने हमारे फोन का जवाब नहीं दिया।" तभी मैंने उन्हें यह प्रस्ताव दिया।
मोदी के कार्यालय में फोन करने के लिए।
संयोगवश, मोदी साहब उस समय अपने कार्यालय में ही थे। वे आए थे...

मैंने तुरंत उससे संपर्क किया। मैंने उसे तीनों विद्वानों के बारे में बताया और कहा कि मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ।
मैं उनके बारे में भी उतना ही अच्छा सोचता था जितना मैं अपने पिता के बारे में सोच सकता था। वे बहुत सम्मानित व्यक्ति थे।
और फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। मोदी ने कहा, "मुझे उनके नाम बताओ।" ऐसा लगा जैसे उन्होंने लिखा हो।
जैसे-जैसे मैं उनके विवरण देता गया, उसने खुद ही नाम लिख लिए। यह बातचीत चल रही थी।
तभी एक मौलाना ने मुझे एक नोट दिया जिस पर लिखा था कि फलां मौलाना का...
पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। इसलिए मैंने मोदी जी से कहा, महोदय, पासपोर्ट का मामला है।
उन्होंने आगे कहा, “इस व्यक्ति से कहो कि जब उसे विदेश जाना हो, तो यह मेरी गारंटी है।”
हम उसे पासपोर्ट देंगे।
इस फोन कॉल के आठ घंटे के भीतर, उप आयुक्त गए और
मौलानाओं के घरों पर चिपकाए गए समन को हटा दिया गया।
और आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिए गए। लेकिन यह सिर्फ सुल्तानी स्तर पर ही नहीं हुआ था।
मोदी के फरमान पर। उन्होंने मामले की जांच करवाई और उनकी पुष्टि की।
कलेक्टर द्वारा आदेश वापस लेने से पहले निर्दोषता साबित करने के मामले भी थे। इसी तरह, अन्य मामले भी थे।
धारा 268 के तहत आरोपित मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया था। वे दस साल से बाहर नहीं आए थे।
कई साल बीत गए। हम मोदी के पास गए और उन्होंने मानवीय सहायता के तहत ऐसे पांच लड़कों को बाहर जाने की अनुमति दी।

उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही।
आइए, मैं आपको कार्यप्रणाली में अंतर का एक और उदाहरण देता हूँ।
स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष राजनेताओं और मोदी के बारे में। जब महेश भट्ट की फिल्म
जिस्म 2 रिलीज होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पार्टी कार्यकर्ता, जो गठबंधन सहयोगी है
कांग्रेस पार्टी ने धमकी दी कि जो भी थिएटर फिल्म रिलीज करने की हिम्मत करेगा, उस पर हमला किया जाएगा।
उन्होंने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और फिल्म के प्रचार होर्डिंग्स को विरूपित कर दिया, यह कहते हुए कि वे
ऐसी अश्लील फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही राष्ट्रीय
सेंसर बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी दे दी थी, लेकिन एनसीपी की नैतिक पुलिस अड़ी हुई थी। इसलिए
महेश भट्ट ने एनसीपी के सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार को फोन किया और उनसे कहा
उन्हें बताया गया कि गुजरात में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सिनेमा हॉलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे।
वे लोग फिल्म की स्क्रीनिंग करने वाले थे। जब वह बातचीत हुई तब मैं वहां मौजूद था।
शरद पवार हँसे और बोले, “क्या आप चाहते हैं कि मैं सुरक्षा की गुहार लगाऊँ?”
क्या नरेंद्र मोदी, भले ही मैं उनका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हूँ? चिंता मत करो।
ऐसा कुछ नहीं होगा।” लेकिन दो दिन बाद मुझे महेश का फोन आया।

भट्ट ने कहा कि एनसीपी कार्यकर्ताओं की धमकियां वास्तव में बढ़ गई हैं।
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 47

मैंने भट्ट साहब को आश्वासन दिया कि मैं उनकी ओर से मोदी से बात करूंगा। हालांकि भट्ट
मोदी के कट्टर दुश्मन बने रहने पर भी, मोदी की प्रतिक्रिया स्पष्ट और खरी थी।
सरकार द्वारा किसी को भी इस पर अशांति फैलाने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
मुद्दा। कानून का शासन कायम रहेगा। चूंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी दे दी है,
किसी को भी गैरकानूनी कृत्यों के माध्यम से इसकी स्क्रीनिंग में बाधा डालने का अधिकार नहीं है।” उन्होंने कहा।
मुझे भट्ट साहब से यह कहना है कि वे चैन से सो सकें क्योंकि सरकार गुंडागर्दी की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस बातचीत के कुछ ही मिनटों बाद भट्ट साहब ने मुझे फोन किया और कहा,
“बड़ौदा के पुलिस आयुक्त, जिस शहर में एनसीपी कार्यकर्ता थे
सबसे आक्रामक, मुझे यह आश्वासन देने के लिए फोन किया कि सरकार प्रतिबद्ध है
किसी भी प्रकार की उपद्रवी गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जब मैंने पुलिस को बताया
आयुक्त का कहना है कि थिएटर मालिक भयभीत हैं और इसलिए अनिच्छुक हैं।
फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए, पुलिस आयुक्त स्वयं गए और मालिकों से मिले।

उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।" और वास्तव में, फिल्म ने देखा
एक शांतिपूर्ण रिहाई। भट्ट साहब ने मुझसे कहा, “यार, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।”
किसी भी राजनेता या मुख्यमंत्री के लिए इतनी तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना कितना मुश्किल होता है!
भारत में कहीं और नहीं।" उन्होंने फिल्म फेडरेशन में मोदी के आचरण की खुले तौर पर प्रशंसा की।
बैठक में उन्होंने कहा, “भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता।”
कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता।"
मैंने महेश भट्ट से इन तथ्यों की पुष्टि की। उन्होंने माना कि मोदी ने 'जिस्म 2' की शांतिपूर्ण रिहाई सुनिश्चित की थी। लेकिन वे 'जिस्म 1' के विवादों में घिरने और अपने बेटे को डेविड कोलमैन हेडली के साथ कथित तौर पर निर्दोष मित्रता या संबंध के कारण कठिनाइयों का सामना करने को लेकर अभी भी नाराज़ थे। डेविड कोलमैन हेडली शिकागो का एक पाकिस्तानी-अमेरिकी था जिसने लश्कर-ए-तैबा समूह और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर मुंबई में कई आतंकी हमले किए और अन्य आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मोदी का उनके बेटे के मामले से क्या लेना- देना है, जबकि डेविड हेडली का मामला केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संभाला जा रहा है।
मैंने ज़फ़र से पूछा कि जब वीएचपी के लोगों ने बड़ौदा में एक पेंटिंग प्रदर्शनी के खिलाफ इसी तरह का हंगामा किया था या जब फिल्म 'परज़ानिया' की रिलीज़ रोक दी गई थी, तब मोदी ने ऐसा दृढ़ संकल्प क्यों नहीं दिखाया था? तो फिर यह बदलाव क्यों? ज़फ़र ने जवाब दिया:

मोदी ने स्वीकार किया कि गुजरात में फना या परज़ानिया को चुनाव न लड़ने देना एक गलती थी।
या तो थिएटरों को बंद कर दें या बड़ौदा कला महाविद्यालय में उपद्रव मचाने वाले बदमाशों को छूट दे दें।
प्रदर्शनी में। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि ने उनके लिए काफी परेशानी खड़ी की थी।
उस समय। इसलिए, उन्होंने फैसला किया था कि अब से कानून का शासन कायम रहेगा, नंबर 48 मोदी, मुसलमान और मीडिया

चाहे राजनीतिक कीमत कुछ भी हो। मेरा मानना है कि वे घटनाएँ घटीं।
जब गुजरात अभी भी विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नियंत्रण में था, तब परज़ानिया की घटना घटी।
2003 में जब मोदी का राज्य प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था।
उस समय पुलिस बल अभी भी पूर्व शासनों के प्रभाव में था।
शासन व्यवस्था को पटरी पर लाने में उन्हें 2-3 साल लग गए। अब मोदी का शासन पर पूरा नियंत्रण है।
प्रशासन। यहां तक कि पुलिस भी जानती है कि वह निगरानी रख रही है, और मोदी ऐसा नहीं करेंगे।
किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपातपूर्ण आचरण को नजरअंदाज करें। यही कारण है कि आज
गुजरात में मुसलमान बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
उनके साथ क्या किया जाए। सैकड़ों मुस्लिम समूहों ने विभिन्न मुद्दों पर उनसे मुलाकात की है।
उन सभी को सम्मानपूर्वक सुने जाने और समान अनुभव प्राप्त हुआ है।
उनकी शिकायतों का शीघ्रता से समाधान किया गया। मोदी अपने वादों को पूरा करते हैं।

चूंकि ज़फ़र का बयान मोदी की बदनाम छवि से बिल्कुल अलग था, इसलिए मैंने उनके साथ काम कर चुके अधिकारियों सहित कई लोगों से दोबारा पुष्टि की। जिन लोगों ने वास्तव में मोदी के सामने कोई गंभीर मुद्दा उठाया था, उन सभी की कहानी एक जैसी थी। केरल के वी.वी. ऑगस्टीन का बयान बेहद महत्वपूर्ण था, जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी के साथ अक्सर बातचीत की थी:
इस दुष्प्रचार के विपरीत कि मोदी जी अल्पसंख्यक विरोधी हैं, मेरा मेरा अनुभव यह है कि मोदी अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत ही मित्रवत व्यक्ति हैं। जब मैं सदस्य था
अल्पसंख्यक आयोग के वापी जिले के ईसाई समुदाय के
गुजरात ने मेरे ध्यान में एक गंभीर मुद्दा लाया। वहां उनकी संख्या लगभग 7,000 है।
वापी क्षेत्र में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के कई चर्च हैं। जिनमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, सीरियाई ईसाई और कई अन्य शामिल हैं।
पिछले 40 वर्षों से वे बिना किसी सफलता के एक
उन्होंने मृतकों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान बनाने हेतु जमीन का एक टुकड़ा मांगा था। उन्होंने इसके लिए संपर्क भी किया था। केंद्र सरकार ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने में मदद की, जिसके लिए वे
वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार थे। लेकिन प्रशासन इस मामले को टालता रहा।
दशकों तक। इससे भारी असुविधा हुई क्योंकि उन्हें मृतकों को ले जाना पड़ता था।
वापी से 40 मील दूर शवों को दफनाने के लिए भेजा गया। सामूहिक रूप से पैरवी करने के लिए, उन्होंने एक संगठन बनाया।

वापी क्रिश्चियन एसोसिएशन के एक सदस्य ने मुझसे मदद के लिए संपर्क किया।
अल्पसंख्यक आयोग।
मैंने उनसे कलेक्टर को संबोधित एक और नया आवेदन लिखने को कहा।
जिले में। मैं कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से मिलने गया और उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा, "यह
यह सरकार का निर्णय होना चाहिए क्योंकि स्थानीय लोगों को इससे समस्या है।
उनके बीचोंबीच कब्रिस्तान है। कृपया संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
‘संघर्ष उद्यमियों’ द्वारा निर्मित मोदी मिथक 49

इसलिए मैंने सीधे मोदी जी से बात करने का फैसला किया और उन्हें मामला समझाया।
उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, "हाँ, आपके पास एक वास्तविक प्रतिभा है।"
समस्या। मुझे बताओ, क्या तुमने कोई ज़मीन का टुकड़ा चुना है जो तुम चाहते हो?” मैंने उसे बताया कि हम
हमारे पास जगह तो है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अधिग्रहित करने का विरोध कर रहे हैं। मोदी ने कहा, “वह
यह आपकी समस्या नहीं है; यह मेरी समस्या है। बस मुझे बता दीजिए कि आपको ज़मीन कहाँ चाहिए और मैं
रिपोर्ट मंगवाएंगे।" कुछ ही घंटों के भीतर, उन्हें पूरी रिपोर्ट मिल गई।
कलेक्टर ने उसे बताया कि चूंकि वह विशेष भूमि का टुकड़ा ठीक उसी क्षेत्र में स्थित था

कस्बे के बीचोंबीच, स्थानीय लोग वहां कब्रिस्तान बनाए जाने का विरोध कर रहे थे।
इसके बाद मोदी ने कलेक्टर को वापी के साथ समन्वय में काम करने के लिए कहा।
ईसाई संघ से संपर्क करें और उपयुक्त भूमि का पता लगाएं। देखते ही देखते,
कस्बे के बाहरी इलाके में जमीन की पहचान की गई और ईसाई समुदाय राज्य सरकार द्वारा उन्हें डेढ़ एकड़ जमीन मुफ्त में उपहार स्वरूप दी गई थी।
तब से मैंने उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की है, और हमेशा
मैंने उन्हें बेहद मददगार और सहयोगी पाया। उदाहरण के लिए, डांग जनजाति में।
इन क्षेत्रों में नव-ईसाइयों की बस्तियाँ हैं। वीएचपी बहुत सक्रिय हो गई थी।
क्षेत्र में सक्रियता के कारण काफी तनाव पैदा हो गया। जब उन्होंने एक आयोजन करने की योजना बनाई,
2006 में उस क्षेत्र में आयोजित विशाल शबरी कुंभ मेले के दौरान, ईसाई समुदाय के लोग अत्यधिक रूप से प्रभावित हुए।
वे घबराए हुए थे और उन्हें डर था कि उस दौरान उन पर हमला हो सकता है। हम चले गए।
हमने अपनी आशंकाओं से मोदी को अवगत कराया। ईसाई संगठनों ने प्रतिबंध लगाने की मांग की।
शबरी मेला। मोदी ने मेले पर प्रतिबंध नहीं लगाया क्योंकि ऐसा करने से
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने यह बहाना बनाकर हंगामा खड़ा कर दिया कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है।

ईसाइयों के आग्रह से तनाव और बढ़ गया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई भी
उन्हें हिंसा या अन्य प्रकार के गैरकानूनी व्यवहार में लिप्त होने की अनुमति दी जाएगी
और उन्होंने इलाके के पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश जारी किए। दरअसल,
यह मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, हालांकि 2002 के दौरान गैर-
ईसाई कबायलियों ने ईसाई बस्तियों पर हमला किया था, जिसके कारण बहुत कुछ हुआ।
आपसी शत्रुता और संदेह का। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश ईसाई इसके लिए मतदान करते हैं।
मोदी। उन्होंने कभी उनके शासनकाल के खिलाफ शिकायत नहीं की है।
जब मैं छोटी-छोटी बातों पर भी मोदी से मिला, तो उन्होंने सभी जायज मांगों का समर्थन किया।
एक अन्य घटना में, एक छोटे से इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद हो गया।
2004 में बड़ौदा के पास एक गांव में। उन्होंने मुझे मध्यस्थ के रूप में काम करने की पूरी छूट दी थी।
मैंने एक संयुक्त बैठक बुलाई। व्यापारिक विवाद के चलते एक मुस्लिम ने एक हिंदू की हत्या कर दी थी।
हिंदुओं ने जवाबी कार्रवाई की। वे बातचीत तक नहीं कर रहे थे।
लेकिन मैं उन्हें ले आया।
उन्होंने दोनों को एक साथ बिठाया और मीडिया को दूर रखते हुए उन्हें आपस में बात करने के लिए कहा।
मोदी जी ने कलेक्टर को भी पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए थे।

हमने सांप्रदायिक सद्भाव लाने के लिए शांति बैठकें आयोजित कीं।
गुजरात
अखबारों ने 'ऑगस्टाइन मिशन' को प्रमुखता से कवर किया।
यह मिशन सफल रहा। लेकिन अगर 50 मोदी, मुस्लिम और मीडिया शामिल नहीं होते तो शांति मिशन सफल नहीं हो सकता था।

प्रशासन ने पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया था। अफवाह फैलाने वाले लोग
यह कहना कि मोदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, उनके अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।
अनुभव बिल्कुल अलग है। वह बहुत ध्यान से सुनता है और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
वास्तविक समस्याओं का मामला।
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में, मैंने कई राज्यों के साथ काम किया।
ओडिशा और मध्य प्रदेश की सरकारें भी अच्छी रही हैं। लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं।
मंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जितने ही अच्छे, मजबूत और दृढ़ निश्चयी हैं। एक बार जब वे कोई पदभार ग्रहण कर लेते हैं,
वह इस मुद्दे को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाता है।
अब तो मुसलमान भी यह समझने लगे हैं कि मोदी उनके लिए अच्छे हैं। दो प्रकार के लोग हैं।
गुजरात में मुसलमानों के बीच - अमीर और गरीब दोनों। मेरे अनुभव से पता चलता है कि गरीब
मुसलमान मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं क्योंकि गुजरात दंगा- मुक्त है और एक पुनर्जीवित देश है।

नई संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्था ने इन गरीब मुसलमानों को काफी लाभ पहुंचाया है।
और भी नाटकीय रूप से। इसने उन्हें ऊपर उठने के रास्ते प्रदान किए हैं। मैं प्रशंसा करता हूँ।
मोदी और मैं चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बनें। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित जानकारी का ही उपयोग करता हूं।
अल्पसंख्यकों के साथ हुए अन्याय से ग्रस्त लोगों को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए:
अल्पसंख्यकों को पूर्ण अधिकार किसने दिए हैं? हिंदू बहुसंख्यकों ने। किसने लिखा?
संविधान? अधिकतर हिंदू! हमें इसके लिए हिंदुओं की सराहना करनी चाहिए और
उन्हें उनका उचित श्रेय दें।
कुछ महीनों बाद, मैंने वापी और डांग क्षेत्र की यात्रा की ताकि ईसाई समुदाय के नेताओं से ऑगस्टीन के वृत्तांत की पुष्टि कर सकूँ। उन्होंने कब्रिस्तान और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में ऑगस्टीन के कथनों का समर्थन किया। हालाँकि, उनकी प्रतिक्रियाएँ ऑगस्टीन की प्रतिक्रिया से कहीं अधिक जटिल थीं। मैं अपनी अगली पुस्तक में उस बातचीत का विस्तृत विवरण दूंगा।

अध्याय 3

नरेंद्र मोदी को हवाई जहाज से उतारा गया
अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में
नमो का गुजरात की जनता के नाम पहला संदेश

मेरी संपूर्ण कार्यशैली का मूलमंत्र है 'हमारा गुजरात'। 'हमारा होना' की यह भावना मेरे लिए सर्वोपरि है—'हमारा गुजरात, अनूठा गुजरात'। हम गुजरात की विविधता को और अधिक कैसे उजागर कर सकते हैं, इसे और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं, और 'हमारा होना' की भावना को कैसे मजबूत कर सकते हैं?
7 अक्टूबर, 2001 को मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद नामो का पहला बयान।

7 अक्टूबर 2001 को, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कभी सरपंच का पद भी नहीं संभाला था, अचानक एक ऐसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए जो विभिन्न मोर्चों पर गंभीर संकट से जूझ रहा था।
उन्होंने न तो स्वयं कोई चुनाव लड़ा था और न ही सरकार में कोई पद संभाला था। भाजपा में संगठनात्मक भूमिका निभाने के बावजूद, उन्हें नौकरशाही और प्रशासन प्रणाली की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। मोदी कहते हैं कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में पार्टी के महासचिव रहते हुए भी उन्होंने कभी मुख्यमंत्री कक्ष में कदम नहीं रखा। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के कुछ समय के दौरान मोदी भाजपा के महासचिव के रूप में दिल्ली में थे। वे कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तभी देखा जब उन्हें पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। उस समय

उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में रहना आवश्यक था क्योंकि उन्हें प्रतिदिन मीडिया को जानकारी देनी होती थी।
मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापन काफी नाटकीय था। कई वर्षों तक पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद, जिसने भाजपा को सत्ता में आने में मदद की, तत्कालीन राज्य भाजपा अध्यक्ष संजय जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात राज्य भाजपा ने मोदी को गुजरात से निष्कासित कर दिया। छह वर्षों तक, मोदी को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, यहां तक कि जब वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव थे तब भी। राजकोट से उनके पुराने सहयोगी विजय रूपाणी कहते हैं, "52 मोदी, मुस्लिम और मीडिया"

मोदी इस बारे में मजाक में कहते थे, "मैं गुजरात को छोड़कर पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं।"
इसलिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति मोदी के लिए उतनी ही चौंकाने वाली थी जितनी उनके विरोधियों के लिए। उन्हें केशूभाई की जगह भेजा गया था क्योंकि गुजरात सरकार पूरी तरह से अस्त-व्यस्त थी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2002 के अंत में होने वाले थे। इससे भाजपा के केंद्रीय नेता घबरा गए थे। गुजरात में हार का मतलब केंद्र में वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा झटका होता। नरेंद्र मोदी को केशूभाई की जगह मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर कैसे मिली, इसका विस्तृत वर्णन एम.वी. कामथ और कालिंदी रंदेरी ने किया है।
यह मैदान उनके [मोदी के] उन पूर्व सहयोगियों के लिए खुला छोड़ दिया गया था जो...
आपसी कलह और तुच्छ राजनीति में लिप्त रहना... 1995 से 2001 तक, सिवाय उस दौरान जब...

1999 के चुनावों के दौरान, गुजरात हर तरह से नरेंद्र के लिए वर्जित क्षेत्र था।
पार्टी के महासचिव के रूप में उनके काम के चलते उन्हें दिल्ली में रहना पड़ता था… [मोदी] ने अपना अधिकांश समय दिल्ली में बिताया। उस समय का अधिकांश हिस्सा संगठनात्मक कार्यों के लिए पूरे भारत में यात्रा करने में व्यतीत होता था…
राजनीतिक रूप से गुजरात संकट में था। भाजपा सरकार और पार्टी
वे दो अलग-अलग संस्थाओं की तरह व्यवहार कर रहे थे और एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे।
दूसरे तब जब वे अपना वादा निभाने में विफल रहे। गुजरात की जनता, जिन्होंने
भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद ठगा हुआ महसूस हुआ। और जनता को भी ठगा हुआ महसूस हुआ,
ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री और नेता अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करना जारी रखे हुए हैं।
गुजरात में भाजपा को अनुशासन की भावना को फिर से स्थापित करने के लिए किसी की जरूरत थी।
और संगठन के प्रति एकता… वास्तव में, स्थिति इस हद तक बिगड़ गई थी।
एक ऐसा दौर जिसमें पार्टी पूरे एक साल (2000-01) में एक भी सीट नहीं जीत सकी।
राज्य में उपचुनाव। प्रतिष्ठित साबरमती विधानसभा सीट हारना, साबरकांठा लोकसभा सीट, और सभी स्थानीय स्वशासन, तालुका, नगर पालिका (नगर निगम) चुनावों में कांग्रेस की जीत एक तरह से चेतावनी के रूप में आई।
भाजपा को बुलावा आया। उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। और एकमात्र व्यक्ति, के अनुसार...

नरेंद्र पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे जो मामलों को सुलझा सकते थे।
उन्हें तत्काल आदेश दिया गया कि वे अहमदाबाद जाकर सत्ता की बागडोर संभालें।
केशूभाई पटेल से मुख्यमंत्री के रूप में।
यह घटना कुछ अप्रत्याशित ढंग से घटी। माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर, 2001 को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके साथ यात्रा कर रहे चार पत्रकार भी उस दुर्घटना में मारे गए। उनमें एक कैमरामैन भी शामिल था।
1 एम.वी. कामथ और कालिंदी रांदेरी, नरेंद्र मोदी: आधुनिक राज्य के वास्तुकार,
नई दिल्ली: रूपा एंड कंपनी, 2009, पृ. 80-1.
नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में हवाई जहाज से उतारा गया था।

आज तक के गोपाल, जिन्हें मोदी अच्छी तरह जानते थे। 1 अक्टूबर, 2001 को मोदी गोपाल के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली गए थे, तभी उन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, जिन्होंने मोदी को शाम को उनसे मिलने के लिए कहा।
जब वाजपेयी ने मोदी को गुजरात जाकर वहां काम करने के लिए कहा, तो मोदी ने सोचा कि उन्हें संगठनात्मक काम के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या वे सिर्फ गुजरात के प्रभारी होंगे या किसी और राज्य के भी? लेकिन अटलजी ने कहा, “नहीं, नहीं, आपको चुनाव लड़ना होगा। आपने अब तक दूसरों को चुनाव लड़ने में मदद की है। अब आपको खुद चुनाव लड़ना होगा।” जब उन्हें पता चला कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जा रहा है, तो उन्होंने अटलजी से कहा, “यह मेरा काम नहीं है। मैं छह साल से गुजरात से दूर रहा हूं। मैं

वहां के मुद्दों से परिचित नहीं हूं। मैं वहां क्या करूंगा? यह मेरी पसंद का क्षेत्र नहीं है…”2
लेकिन आडवाणी और वाजपेयी दोनों ने मोदी को यह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। यह चुनाव मोदी पर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने ही पार्टी संगठन को जमीनी स्तर से खड़ा किया था और उसे कई चुनावी जीत दिलाई थीं। केशूभाई और संजय जोशी द्वारा उन्हें गुजरात से निकाले जाने की परिस्थितियों और पार्टी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मोदी जानते थे कि गुजरात में उनका सफर आसान नहीं होगा। गुजरात रवाना होते समय उन्होंने मेरे साथ एक साक्षात्कार में अपने पहले कदमों का वर्णन इस प्रकार किया: गांधीनगर में मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने पार्टी कार्यालय को फोन किया।
और मैंने उनसे सर्किट हाउस में मेरे लिए एक कमरा बुक करने को कहा। मैं नहीं चाहता था
पहले की तरह किसी के भी घर में रहना। सर्किट हाउस में रहना।
इसका मतलब यह भी था कि लोग मुझसे खुलकर मिल सकेंगे। लेकिन मैंने अपने दल को बताया।
सहकर्मियों से अनुरोध है कि वे किसी भी विधायक के नाम पर कमरा बुक न करें क्योंकि इससे समस्या उत्पन्न होती है।
रियायती दर पर। मैंने उनसे कहा कि वे इसे मेरे नाम पर बुक कर दें क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ।
मैंने पूरा भुगतान कर दिया। उस समय मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे कितने दिन लगेंगे।
सर्किट हाउस में रहने के लिए और मुझे क्या-क्या करना होगा क्योंकि मैं वहां नहीं रह सकता था
मुझे सरकारी कामकाज से जुड़ी प्रक्रियाओं की बारीकियों की जानकारी है।

छह साल बाद गुजरात लौटी। मीडिया इन मामलों पर अत्यधिक सक्रिय है।
समस्याएँ सामने आने पर खबर तेजी से फैल गई। मेरी योजना सीधे अपनी माँ से मिलने जाने की थी।
अहमदाबाद में उतरने के बाद। मैंने बिल्कुल यही किया।
पहले दिन से ही, जो लोग सर्किट हाउस में मुझसे मिलने आए थे

2 वही, पृ. 81-2.
54 मोदी, मुसलमान और मीडिया

सभी की एक ही आम शिकायत थी: “मोदी जी, आप यह पद क्यों स्वीकार कर रहे हैं?” पार्टी
गुजरात में इसका पतन हो रहा है और इसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है।" दूसरा संदेश
लोगों ने मुझसे कहा: "क्या आप कोई और सार्थक काम कर पाते हैं या नहीं, यह मायने रखता है।"
चाहे बिजली मिले या न मिले, बस यह सुनिश्चित कर लें कि हमें शाम के भोजन के समय बिजली मिल जाए।
बिजली की कमी के कारण गांवों में बहुत अधिक परेशानी है।
तीसरी बार यही दोहराया गया: “यह अच्छी बात है कि पार्टी ने ऐसा करने का फैसला किया है।”
एक बदलाव। आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या
आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। लेकिन कम से कम आप कोशिश तो करेंगे।
4 अक्टूबर 2001 को नमो भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। हालांकि निवर्तमान मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल ने नमो का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन उन्होंने मोदी के साथ कभी सुलह नहीं की और अपने उत्तराधिकारी को बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास करते

रहे। फिर भी, पार्टी कार्यकर्ताओं में व्यापक उत्साह था। 5 अक्टूबर 2001 को एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की: “भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और आरएसएस के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी, जो रविवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, गुजरात में पार्टी की छवि को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं।”
हालांकि, मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कोई व्यापक बदलाव नहीं किए। उनके पार्टी सहयोगी विजयभाई रूपाणी के शब्दों में:
जब वे पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब मैं गुजरात में भाजपा के मुख्य समूह में था।
राज्य। संजय जोशी हमारे अध्यक्ष थे। उस समय भी नरेंद्रभाई बैठे थे।
उन्होंने पार्टी के सहयोगियों से कहा, "हमें मंत्रालय के बारे में मिलकर फैसला लेना होगा।"
पार्टी के मुख्य समूह को बैठक करके नामों की सूची तैयार करनी चाहिए।
मंत्रिमंडल के लिए।" और उन्होंने ठीक वही नामों की सूची घोषित की जो पहले घोषित की गई थी।
पार्टी ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया था, इस तथ्य के बावजूद कि उसे इस बारे में संदेह था।
3-4 लोगों की ईमानदारी और कार्य क्षमता। उदाहरण के लिए, नरेंद्रभाई
गोरधन ज़ादाफ़िया के बारे में गंभीर आशंकाएँ थीं और उन्होंने हमें इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।
उसका नाम लेकर कहा गया कि वह शरारत कर सकता है। लेकिन हम सभी ने जोर देकर कहा कि वह

party gave for inclusion in his cabinet and said, “Chalo yehi hai agar panchon

नरेंद्रभाई को बदनाम करना चाहते थे। अपने पहले ही टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे नरेंद्रभाई को बदनाम करना चाहते थे।
शपथ ग्रहण समारोह में उनसे पूछा गया कि आप शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए।
इसके जवाब में नरेंद्रभाई पर हर तरह के झूठे आरोप लगाए गए और कहा गया,
“मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगा।” वह पहले दिन से ही नरेंद्रभाई को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगा हुआ था।
और ज़ादाफ़िया ने साबित कर दिया कि मोदी की आशंकाएँ निराधार थीं, क्योंकि 2002 के दंगों के दौरान उन पर हिंसा भड़काने में बेहद अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा था। देखते ही देखते उन्होंने भाजपा छोड़ दी और केशूभाई की अलग हुई पार्टी में शामिल हो गए, जो मोदी को चुनाव दर चुनाव हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है।
जैसा कि अध्याय के उत्तरार्ध में दिए गए विवरण से पता चलता है, मोदी ने न तो नौकरशाही में कोई फेरबदल किया और न ही अपने मंत्रियों को चुना। लेकिन चूंकि पार्टी उच्च कमान द्वारा नमो को दिया गया जनादेश गुजरात भाजपा को गहरे संकट से बाहर निकालना और उसकी सरकार की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना था, इसलिए नमो ने दिल्ली से आने के तुरंत बाद अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं और घोषणा की: “मैं यहां एक दिवसीय मैच खेलने आया हूं। मुझे सीमित ओवरों के खेल में रन बनाने के लिए तेज और अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों की जरूरत है।”3
7 अक्टूबर, 2001 को शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाते समय: जब मोदी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन जाना था, तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों की तरह कोई नई, शानदार कार का इस्तेमाल नहीं किया। वे एक साधारण, अपेक्षाकृत पुरानी गहरे नीले रंग की मारुति

800 में गए, जो उन दिनों भी कारों के सबसे सस्ते मॉडलों में से एक मानी जाती थी।
शपथ ग्रहण समारोह में जाते समय, मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के 5 प्रमुख व्यक्तियों का आशीर्वाद लेने के लिए रुक गए। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मौन प्रार्थना से शुरुआत की, उसके बाद सरदार पटेल और बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर भी इसी तरह पुष्पांजलि अर्पित की और प्रार्थना की।4 इन तीनों हस्तियों ने मोदी पर गहरी छाप छोड़ी है और
3. कामथ और रंदेरी, नरेंद्र मोदी: आधुनिक राज्य के निर्माता, पृष्ठ
83. 4. 7 अक्टूबर, 2001 को नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए, लिंक देखें: http://www.youtube.com/watch?v=jd0Ndc3mQ4Q.
56 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उनकी सोच और कार्ययोजना को आकार देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद, वे रवि शंकर व्यास और विट्ठलभाई झावेरभाई पटेल की प्रतिमाओं पर आशीर्वाद लेने गए। पहले तीन नाम तो सर्वविदित हैं। अन्य दो गुजराती दिग्गजों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। रवि शंकर व्यास (1884-1984), जिन्हें “बोरिनवाला महाराज” और “मुखसेवक” के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल के शुरुआती और सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। 1920 और 1930 के दशक में, वे गुजरात में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन और विद्रोहों के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1960 में गुजरात को एक अलग राज्य के रूप में गठित करने के उद्घाटन के लिए उन्हें ही चुना गया था।

विठ्ठलभाई झावेरभाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विठ्ठलभाई भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया।
ये दोनों दिग्गज गुजरात के सभी वर्गों के लोगों के बीच, राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार करते हुए, सर्वत्र आदरणीय रहे हैं। मैंने नमो से पूछा कि 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दिन वे छोटी मारुति कार में क्यों यात्रा कर रहे थे, जबकि सरकार के आधिकारिक वाहनों के बेड़े में छोटी मारुति कार नहीं है। उन्होंने अपने वाहन के चुनाव के बारे में इस प्रकार स्पष्टीकरण दिया:
जब चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री बने और केशूभाई उनके मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर पर थे,
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे एक तस्वीर याद आई जो मैंने देखी थी।
सभी गुजराती समाचार पत्रों में मंत्रियों के लिए नई कारों के बेड़े की खबर प्रकाशित की गई।
वह इस दृश्य से विचलित हो गया और उसे लगा कि इससे गलत संदेश जा रहा है। हालाँकि
सरकार में ऐसी चीजें आम बात हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीरें लोगों को परेशान करती हैं।
इसलिए मैंने अपने अधिकारियों से कहा, मैं अपने शपथ ग्रहण समारोह के आसपास इतना हंगामा नहीं चाहता।
जब मैं छह साल बाद गांधीनगर लौटा, तो मेरे पास कोई वाहन नहीं था।
मेरी अपनी। इसलिए, मैंने पार्टी से अनुरोध किया कि वे मुझे एक पार्टी कार्यकर्ता की कार भेज दें।
एक ड्राइवर के साथ ताकि मैं आसानी से घूम सकूँ। यही वो कार है जो मुझे ले गई थी।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए।
मुख्यमंत्री बनने पर पहली प्रेस वार्ता: नए मुख्यमंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना प्रथागत है। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने प्रेस को संक्षिप्त बयान दिया, लगभग बुलेट पॉइंट्स में, जिसके बाद उन्होंने कुछ ही सवालों के संक्षिप्त जवाब दिए। हालांकि, इस संक्षिप्त वार्ता में भी उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बताया।
नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में हवाई जहाज से उतारा गया था।

इन बातों को उन्होंने 10 अक्टूबर, 2001 को टीवी के माध्यम से अपने साथी गुजरातियों को दिए गए एक "संदेश" में और विस्तार से बताया है।
मैं आपसे कई वर्षों बाद मिल रहा हूँ और वह भी एक नई भूमिका में… इस साल हम
कृषि की जरूरतों के लिए पर्याप्त बारिश हुई, लेकिन पेयजल संकट बना हुआ है।
वह हमें घूरता रहता है। प्राकृतिक आपदा के कारण, जो हमने झेली है... भूकंप के बाद, गुजरात सरकार के सामने पुनर्वास का विशाल कार्य है। भूकंप पीड़ितों के।
गुजरात के गांवों में रहने वाले मेरे किसान भाइयों को मेरा संदेश यह है कि मैं इस बात से भली-भांति अवगत हूं।
बिजली कटौती के कारण आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में मैं जल्द ही जानकारी दूंगा।
एक ठोस योजना बनाएं और इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाएं।

नई सरकार सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाना चाहती है। शासन को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावशाली। मेरे पास एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसके तहत मैं एक ऐसा संगठन बनाना चाहता हूँ जो... केंद्र-राज्य संघर्षों के समाधान के लिए एक तंत्र। हमारा प्रयास रहेगा कि इसे लागू किया जाए।
कि गुजरात को केंद्र से अधिकतम संभव सहयोग मिले।
मैंने आज अधिसूचना जारी कर दी है कि पंचायत चुनाव यहाँ आयोजित किए जाएँ।
जल्द से जल्द। हमने यह भी तय किया है कि वे सभी गाँव जो अपनी पंचायतें चुनते हैं
पूर्ण सहमति के माध्यम से समरस 5 ग्राम (पारस्परिक सद्भाव) का दर्जा प्राप्त होगा
सरकार गांवों को विशेष प्रोत्साहन देकर उनके विकास में योगदान देगी।
समरस के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें।
इससे गांवों को विभाजनकारी राजनीतिक षड्यंत्रों से ऊपर उठने में मदद मिलेगी।
और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
11 सितंबर 2001 के बाद, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को तेज करने की जरूरत है।
इसलिए, कल से [गुजरात सरकार] ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्य को सतर्क रहने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
आगे किसी भी हमले को रोकने के लिए अग्रिम तैयारियां। आज मैंने पूरा समय इसी में बिताया।

मैंने इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए पूरा दिन बिताया। मैंने सेना और सीमा सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की।
मैंने सेना और वायु सेना दोनों के बारे में भी चर्चा की। मैं एक उच्चस्तरीय समिति के साथ भी बैठा था।
गुजरात की आंतरिक सुरक्षा की जांच कर इस बात पर चर्चा की जा रही है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है।
गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी संकट की स्थिति में, इस पर चर्चा करने के लिए कि क्या किया जा सकता है।
रक्षा और नागरिक अधिकारियों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
राज्य में ताकि हमारे पास एक सतर्क और सक्रिय संस्थागत तंत्र हो।
खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के लिए। हमने इस बात पर चर्चा की है कि गुजरात के सभी विभाग कैसे काम करते हैं।
सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने वाली सरकारों को सतर्क रहना चाहिए...

5. 'सम' का अर्थ है समानता या एक साथ होना और 'रस' का अर्थ है अमृत। इन दोनों शब्दों के साथ
संस्कृत में इन दोनों मूलों को जोड़ने पर साझा भावनाओं, मूल्यों और लक्ष्यों पर आधारित आम सहमति की भावना का अर्थ निकलता है।
58 मोदी, मुसलमान और मीडिया

36 लाख हेक्टेयर की बंजर भूमि के लिए नर्मदा प्रमुख मुद्दा है। गुजरात। नर्मदा करोड़ों मूक, प्यासे जानवरों का सर्वोपरि लक्ष्य है।
5 करोड़ प्यासे गुजरातियों के लिए नर्मदा सर्वोपरि मुद्दा है। उन्होंने प्रेस को बताया कि अगले ही दिन भूकंप पुनर्वास से संबंधित विभागों के साथ उनकी एक लंबी बैठक तय है। इस प्रारंभिक

ब्रीफिंग के बाद वे स्वयं कच्छ जाएंगे। “पुनर्वास कार्य की वर्तमान स्थिति, दिशा और गति को समझने के बाद ही मैं मीडिया से संपर्क करूंगा, जब मेरे पास बताने के लिए कुछ सार्थक होगा और एजेंडा में कुछ ठोस बातें होंगी। इसमें साहस, धैर्य, दयालुता, सौजन्या (क्षमता), ‘हमारी’ भावना की शक्ति प्रदर्शित होनी चाहिए— ये चीजें कल के गुजरात के निर्माण में निर्णायक होंगी…”
जब एक पत्रकार ने मोदी से पूछा कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे राज्य प्रशासन में किस तरह के बदलाव लाना चाहेंगे, तो मोदी का जवाब बहुत ही सटीक था:
मुझे नहीं लगता कि प्रशासन में सब कुछ बदलने की जरूरत है। प्राथमिकताओं में बदलाव का मामला है। गुजरात की सबसे बड़ी जरूरत त्वरित डिलीवरी है।
सेवाओं के संबंध में और मुझे विश्वास है कि गुजरात के सभी अधिकारी और कर्मचारी इन सेवाओं का पालन करेंगे।
गुजरात सरकार सेवा की गति बढ़ाने में मेरा सहयोग करेगी।
और मोदी ने ठीक यही करने का लक्ष्य रखा: कोई निलंबन नहीं, कोई बड़े पैमाने पर तबादले नहीं, कोई बड़ा फेरबदल नहीं और न ही बहुत सारे नए कानून। जैसा कि हम आगे के अध्यायों में देखेंगे, मोदी ने शासन प्रणाली को बदलने के लिए उन्हीं कर्मचारियों और उन्हीं सरकारी नियमों का इस्तेमाल किया, हालांकि उन्होंने इस दौरान कई पुराने नियमों में बदलाव किया। लेकिन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, उन्होंने नए विचारों और ऊर्जा को लाने के लिए सरकारी व्यवस्था से बाहर के कई पेशेवर प्रतिभाओं को भी शामिल किया।
उस अवसर के वीडियो फुटेज में मोदी बेहद सतर्क और स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी बात को एकरस स्वर में कह रहे हैं। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने इसे इस प्रकार समझाया:

जब पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, उसी शाम को वे... मीडियाकर्मियों के साथ विशेष बैठकें हुईं—कुछ ने तो कक्षों का दौरा भी किया।
अखबार के संपादकों। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, इसका कारण यह था कि
मैं छह साल बाद गुजरात लौटा था। मुझे इस प्राणी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
‘सरकार।’ इसके अलावा, मुझे पहले से ही शत्रुतापूर्ण माहौल की जानकारी थी।
नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में हवाई जहाज से उतारा गया था।

मेरे खिलाफ। मुझे आशंका और चिंता थी कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूँ,
मैं शब्दों के जाल में फंस सकता हूँ।
मुझे मीडिया से बात करने में असहजता हो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरी छवि खराब कर दी थी।
बिना किसी कारण के। वैसे भी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ऐसा नहीं कर सकता था।
मैंने बड़े-बड़े बयान इसलिए दिए क्योंकि मेरी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था।
इसके अलावा, मुझे वह पद किसी और को हटाने के बाद दिया गया था। एक ढीला
अगर मैंने एक शब्द भी कह दिया होता तो हंगामा मच जाता। इससे स्थिति और बिगड़ जाती।
इससे मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचा। ये सारी चिंताएं मेरे मन पर हावी थीं।

मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का गुजरातियों के नाम पहला संदेश: प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय, 10 अक्टूबर, 2001 को मोदी ने गुजरात की जनता को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए निम्नलिखित संदेश दिया। इसमें कोई शेखी नहीं, कोई विभाजनकारी बयानबाजी नहीं, कोई सांप्रदायिक अपील नहीं:
मुझे नहीं पता कि लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं
मैं पूरी ईमानदारी से गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित हूं। मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है।
आप सबके बीच एक बिल्कुल नई भूमिका में आने का यह अवसर। अभी भी ये दो शब्द—“नरेंद्र मोदी” और “मुख्यमंत्री”—एक साथ ठीक नहीं बैठते।
मेरे कई मित्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जो चाहते हैं कि मैं यह जिम्मेदारी ग्रहण करूँ,
शासन का प्रभार मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे मुझे एक बार फिर से यह अवसर मिला है।
मुझे एक बार फिर अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि की सेवा करने का अवसर मिला है।
(कर्म की भूमि), और गुजरात के लोग एक नई भूमिका में।
हालांकि, मुझे एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। मैं पूरी तैयारी के साथ आपके पास आया हूँ।
श्रद्धा (विश्वास) कि आपके प्रेम से मैं अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होऊंगा
इस कर्तव्य को पूरा करके मैं अपना नाम रोशन करूंगा। यह मेरे राजनीतिक जीवन में एक बिलकुल नया काम है…
मैं इस उत्कंठ (उत्सुकता), उत्साह (उत्साह) और प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा।

मुझे गुजरात के लोगों से प्यार मिला है। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा।
आप मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपका निरंतर सहयोग मुझे सक्षम बनाएगा।
प्रगति के पथ पर विचरण करें…
चाहे वह मुझे सम्मानित करने का समारोह हो या पिछले सप्ताह का शपथ ग्रहण समारोह,
मैं जहाँ भी गया, मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया जा रहा है वह संयुक्त है।
इस उम्मीद के साथ… मैं गुजरात के लोगों को अपना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं।
साथ ही आपमें से वे लोग भी जो राज्य के बाहर साझेदार के रूप में बस गए हैं
मैंने एक नई जिम्मेदारी संभाली है।
“अद्वितीय गुजरात” के लिए “अपनी पहचान” का बोध: पिछले छह वर्षों से, मैं
मैं गुजरात से दूर रहा लेकिन मैंने धूप पर कड़ी नजर रखी है और राज्य में हो रहे घटनाक्रमों की झलक के साथ-साथ वहां के लोगों की आकांक्षाओं पर भी इसका प्रभाव दिखता है।
गुजरात में विकास की अपार संभावनाएं हैं और गुजरात के लोगों में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं।
अनंत कार्यशक्ति (असीमित कार्य क्षमता) होना। यही 60 मोदी, मुसलमानों और मीडिया की विशिष्टता है।

गुजरात। मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुजरात की क्षमता 'एकता की शक्ति' में निहित है।
(apnepan ki shakti).

इसलिए, मैं पुरुषार्थ (पहल और) के मंत्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके सामने कड़ी मेहनत करने की क्षमता है। मेरी पूरी कार्यशैली का मूलमंत्र है...
‘हमारा गुजरात’। ‘अपनापन’ की यह भावना मेरे लिए सब कुछ है—‘हमारा गुजरात’
'अद्वितीय गुजरात'। हम गुजरात की विविधता को और अधिक कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे...
इसे और अधिक चमकीला कैसे बनाएं, हम 'अपनेपन' की भावना को कैसे मजबूत कर सकते हैं?
‘हमारा गुजरात, अनूठा गुजरात’ किसी राजनीतिक एजेंडा या मुख्यमंत्री का नारा नहीं है।
मंत्री जी। प्रत्येक गुजराती के लिए पुरुषार्थ की यह आंतरिक पुकार है कि वह इस भावना को महसूस करे।
हमें अपनी मातृभूमि और अपने समाज पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी...
आप भी इस भावना से सहमत होंगे।
इसमें उद्यमशीलता की असीम क्षमता है; इसमें उत्कंठ (उत्सुकता) है और
ज्ञान, करुणा के संस्कार, आपसी सहयोग से प्राप्त असीम शक्ति सहयोग, संवाद की इच्छा, शांति और सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता, और एक
समृद्धि और विकास की अदम्य इच्छा। हमारा गुजरात एक रचनात्मक देश है।
इन सभी सामाजिक मूल्यों का मिश्रण…
‘अद्वितीय गुजरात’ का अर्थ है कि हममें से प्रत्येक इन सभी संस्कारों को आत्मसात करे।

हमें किसी का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है; न ही हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारा गुजरात
वह एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहता है जिसका अनुसरण और पालन करना अन्य लोग चाहें। यही वह उद्देश्य है।
हम किस तरह का गुजरात बनाने जा रहे हैं? मुझे समस्याओं की पूरी जानकारी है और
मेरे प्रशासन के सामने चुनौतियाँ हैं। लेकिन उनका सामना करना मेरे स्वभाव में है।
समस्याओं का डटकर सामना करना; चुनौतियों का सामना करना मेरी प्रकृति है। मैं चढ़ाई को अच्छी तरह जानता हूँ।
यह कठिन है, लेकिन मेरी राजनीतिक इच्छाशक्ति और गुजरात की जनता का समर्थन इसे सुनिश्चित करेगा।
मेरे लक्ष्य और उद्देश्य ऊँचे बने रहें। सामान्यतः, लोकतंत्र में, एक पार्टी को
पांच साल का शासनकाल। इनमें से साढ़े तीन साल पहले ही बीत चुके हैं।
बीत गया और अब हमारे पास केवल डेढ़ साल बचे हैं। मैं इसे गिन रहा हूँ।
मेरे पास 12,000 घंटे से भी कम समय उपलब्ध है। मेरी इच्छा और मेरा लक्ष्य है...
गुजरात की जनता की अपनी पूरी क्षमता से सेवा करना।
मैंने लोगों की मौजूदा भावनाओं का विश्लेषण किया है और सुधारात्मक उपायों पर विचार किया है।
इनकी आवश्यकता है। सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे, जिनमें से सभी
हमें तत्काल समाधान की आवश्यकता है। मैं लोगों की अपेक्षाओं से अवगत हूं।

प्रशासन और सरकार की ओर से।
जनहितैषी शासन की ओर: विनाशकारी भूकंप,
पिछले दो वर्षों के लगातार सूखे और अंतरराष्ट्रीय मंदी ने
इससे लोगों के जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
प्रभावित। केवल तभी जब पुनर्निर्माण प्रक्रिया गति और गति प्रदर्शित करती है।
पुरुषार्थ प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से गुजरात को हुए नुकसान को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इन त्रासदियों के बाद, क्या गुजरात की जनता का अपनी सरकार पर विश्वास बहाल हो पाएगा?
नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में हवाई जहाज से उतारा गया था।

विभिन्न लोगों का विश्वास बहाल करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सभी स्तरों पर प्रशासन। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन
स्वच्छ छवि बनाने की दिशा में काम करें। सरकारी तंत्र को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
यदि जनता की नज़र में इसकी छवि धूमिल होती है तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी होगी।
प्रशासन के अधीन रहते हुए, मैं अपने अधिकार क्षेत्र में जरा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं करूंगा।
जिम्मेदारी संभालने के पहले ही दिन से मैंने निर्णायक निर्णय लेना शुरू कर दिया है।

वे चाहते हैं कि अधिकारी निर्णय लेने के किसी भी चरण में असफल हो जाएं।
भ्रष्टाचार से मुकाबला: भ्रष्टाचार वातावरण को प्रदूषित करता है और
इससे प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचता है, जिसका दोष पूरी तरह से इस पर आता है।
सरकार। किसी को भी बचाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, खासकर जब मुझे इसके बारे में पता चलता है।
भ्रष्टाचार का जरा सा भी संकेत मिला तो मैं प्रशासन को निर्णायक संदेश दे रहा हूं।
मेरी आकांक्षा एक सर्वांगीण, प्रभावी और प्रगतिशील प्रणाली प्रदान करने की है।
प्रशासन।
मेरी सरकार को कई सार्वजनिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है, और ये
इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए
ध्यान रहे, मेरी पहली प्राथमिकता प्रशासनिक तंत्र को योग्य बनाना होगी।
सामने मौजूद कार्यों में से।
भूकंप से हुए नुकसान को कम करना हमारी पहली प्राथमिकता है।
हाल ही में आए भूकंप से हुई अभूतपूर्व तबाही के कारण लोगों की जान चली गई।
मैंने त्वरित और निर्णायक समाधान के लिए तंत्र बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है।
पुनर्वास, उठाए जा रहे उपायों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए [द्वारा]

सरकार] और यह सुनिश्चित करना कि यह सब समन्वय के माध्यम से लागू हो।
प्रशासन और जन पहल (पुरुषार्थ) का समन्वय। 62 मोदी, मुसलमान और मीडिया

हमारी मुख्य चिंता प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
हाल ही में आए भूकंप के पीड़ित। प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याएं।
ये किसी भी समाज के लिए एक कसौटी का काम भी करते हैं। हाल ही में हुई शुरुआती बारिश से पानी तो आया लेकिन
पेयजल संकट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।
ऐसे दीर्घकालिक उपायों की ओर जो जल संकट को स्थायी रूप से दूर कर देंगे।
किसानों की चिंताएं, एजेंडा में सबसे ऊपर: दूसरी बड़ी समस्या गुजरात में किसानों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की कमी है। मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ।
और हमारे किसानों का दर्द, जिनकी फसलें उनकी तमाम मेहनत के बावजूद मुरझा रही हैं।
क्योंकि हमारे पास सिंचाई के लिए पानी पंप करने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं है।
जब तक हम चिंताओं में भागीदार नहीं बन जाते, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी।
और हमारे किसानों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि

वर्तमान में उपलब्ध सीमित बिजली का अधिकतम संभव हिस्सा किसे मिलता है?
कृषि। हम इसके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणामोन्मुखी व्यवस्था करेंगे।
निर्धारित समय - सीमा।
मैं नर्मदा परियोजना को गुजरात के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानता हूं।
सरदार सरोवर परियोजना न केवल मेरी प्राथमिकता है बल्कि यह सर्वोपरि है।
पांच करोड़ लोगों, करोड़ों जानवरों, पक्षियों और लाखों हेक्टेयर भूमि का एजेंडा
गुजरात की सूखी धरती। हम सबने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाने का संकल्प लिया है।
और पुरुषार्थ को निर्धारित समय सीमा के भीतर नर्मदा योजना को पूरा करना होगा।
सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना: मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि
सीमावर्ती राज्य होने के नाते, गुजरात एक संवेदनशील जिम्मेदारी निभा रहा है। अमेरिका
अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। कोई भी संभवतः
इस युद्ध के परिणामों से बच निकलें। भारत के नागरिक होने के नाते, हम सभी इस बात से ओतप्रोत हैं कि...
देशभक्ति की भावना के साथ। हमारे सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिक और अधिकारी।
गुजरात की अंतरराष्ट्रीय सीमा की देखभाल की जा रही है। लेकिन आंतरिक मामलों का दायरा

सुरक्षा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि राष्ट्र और समाज शक्तिशाली और पूर्ण रूप से संपन्न हैं, तो सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्कता बरती जाए, तो कोई भी सीमा रेखा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा।
आंतरिक सुरक्षा। भले ही हमें युद्ध के प्रत्यक्ष परिणामों का सामना न करना पड़े, फिर भी
सुरक्षा के आंतरिक पहलुओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। नागरिकों की सतर्कता
यह समय की मांग है। लोगों को डरना या घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपील करता हूं कि
आपको हर तरह से सतर्क रहना होगा। सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रहने के लिए कहें।
हमारा मूलमंत्र होना चाहिए: 'सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है।' लोक सेवा की संस्कृति: मैं आम लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ।
लोगों। मैंने नागरिकों की शक्ति की असीमित क्षमता का अनुभव किया है। गुजरात में
मानवता की सेवा की उच्च परंपराओं की स्थापना की। स्वयंसेवी संगठनों
और सामाजिक सेवा संस्थानों ने लोक सेवा (लोगों की सेवा) का मार्ग दिखाया है।
लोगों)। मेरी यह आकांक्षा है कि सरकार को एक माध्यम बनाया जाए जो लोगों की आवाज़ को प्रसारित करे।
विकास में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए लोगों की सहज पहल नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में हवाई जहाज से उतारा गया था।

प्रक्रिया। गुजरात की क्षमता तभी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी जब हममें से प्रत्येक, चाहे किसान हों या
कर्मचारी हों, व्यापारी हों या उद्योगपति, मजदूर हों या सामाजिक कार्यकर्ता, सभी प्रेरित होते हैं।
अपना कर्तव्य निभाने के लिए। यह सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक लोगों को यह एहसास नहीं हो जाता।
कि यह उनकी सरकार है। अगर मैं इसे 'हमारी सरकार' बनाने में सफल हो जाता हूँ, अगर यह
जब सरकार पांच करोड़ गुजरातियों की सरकार बन जाएगी, तभी हम इस पर विचार कर सकते हैं।
यह सफल रहा।
बेरोजगारी और गरीबी पर: मैंने मुख्य मुद्दों का गहन अध्ययन शुरू कर दिया है।
गुजरात के सामने आने वाली समस्याएं—बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं—
किसी भी समाज को नष्ट करना और पूर्ण शून्यवाद का वातावरण बनाना... मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ।
मेरा ध्यान उन कार्यक्रमों पर है जो इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस संदर्भ में,
मैं केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भरता की मानसिकता से अवगत हूं।
इस संबंध में। मेरा संकल्प है कि मैं वर्तमान माहौल को समाप्त कर दूंगा।
ठोस संस्थागत व्यवस्थाएँ बनाकर मनोबल को कम किया जा सकेगा।
सरकार में विश्वास जगाना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा।
गुजरात के दीर्घकालिक विकास के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।
जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हैं, उनका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो आज सबसे अधिक प्रभावित हैं।
समाज के सबसे हाशिये पर रहने वाले लोग।
ग्राम शक्ति को संगठित करना: इस समय मैं प्रशासन को मार्गदर्शन दे रहा हूँ।
विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के मौजूदा कार्यान्वयन में तेजी लाना लोगों के लाभ के लिए। हालाँकि, मैं आपके समक्ष एक दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करने के लिए पुनः उपस्थित होऊंगा।
दृष्टि और दिशा।
मुझे पता है कि मौजूदा अशांत परिस्थितियों के कारण ग्राम पंचायत चुनाव स्थगित हो गए हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करना मेरा प्रयास रहेगा।
मैं जल्द से जल्द व्यायाम शुरू करूंगा। इसके अलावा, मैं नई ताकत पैदा करने का प्रयास करूंगा।
राजनीतिक षड्यंत्रों की संस्कृति से लड़ने के लिए ग्राम शक्ति (गांव की शक्ति)।
ग्राम राजनीति में शत्रुता और आपसी ईर्ष्या। इसीलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आपके समक्ष समरस पंचायतों का प्रस्ताव है।
कोई भी गाँव जो आम सहमति से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है इसे समरस गांव का दर्जा दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं

समरस गांवों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा कर रहा हूं ताकि तेजी से विकास हो सके।
ऐसे गांवों का विकास। मेरी यह आकांक्षा है कि ये समरस गांव विकसित हों।
सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में उभरे और ग्राम राज से राम राज की ओर बढ़े और
विकास के नए क्षितिज तलाशें।
सत्ता की बागडोर 5 करोड़ गुजरातियों के हाथों में: सत्ता संभालने के बाद,
मैंने इसे प्रशासनिक तंत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया है। लेकिन,
सरकार का हस्तक्षेप केवल प्रेरक भूमिका तक ही सीमित रहेगा। मैं चाहता हूँ
नागरिकों की पहल की शक्ति को और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं। हम 64 मोदी, मुस्लिम और मीडिया का निर्माण करना चाहते हैं।

एक ऐसा गुजरात जहां नागरिक निडर तो है, लेकिन सामाजिक मुद्दों के प्रति उदासीन नहीं है।
अच्छा है; युवा उत्साह से भरे हुए हैं और बेरोजगारी से निराश नहीं हैं;
जहां महिलाएं समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेंगी और पीछे नहीं रहेंगी
अशिक्षित; जहाँ प्रशासन पारदर्शी और ऊर्जावान हो; जहाँ नागरिक अपने अधिकारों को लेकर असहाय महसूस न करें। प्रशासन संवेदनशील रहेगा।
और जनकेंद्रित; प्रत्येक गुजराती अपने पूरे दिल से राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा।

सिर ऊंचा करके। हम आपको कभी असहाय महसूस नहीं होने देंगे। बागडोर (लगाम)
विकास का आंदोलन पांच करोड़ गुजरातियों के हाथों में होगा। हमारा गुजरात एक अनूठा गुजरात होगा। मैं आप सभी को भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
in this. Jai Jai Garvi Gujarat, Vande Matram, Jai Hind!
मोदी के एकतावादी एजेंडे ने कांग्रेस को भयभीत कर दिया है। मैंने 8 अक्टूबर, 2001 को मोदी के पहले बयान और 10 अक्टूबर, 2001 को दूरदर्शन पर गुजरात की जनता के नाम उनके पहले सार्वजनिक संदेश का लगभग पूर्ण अनुवाद गुजराती से किया है, ताकि पाठकों को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के पहले दिन से ही मोदी द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण और एजेंडे की प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके। मैं लोगों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों द्वारा गढ़ी गई उस भयावह रूढ़ि को समर्थन देने वाली एक भी पंक्ति बताएं, जो मोदी को एक विभाजनकारी, ध्रुवीकरण करने वाले राजनेता के रूप में पेश करते हैं, जिन्होंने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदल दिया है—वह हिंदुत्व जिसे कांग्रेस और उसके वामपंथी धर्मनिरपेक्ष सहयोगी मूल रूप से हिटलरवादी और फासीवादी विचारधारा वाला मानते हैं।
इसके विपरीत, विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देने के बजाय, पदभार संभालने के पहले ही दिन से नमो ने गुजरात के पांच करोड़ लोगों को संबोधित किया, जिनमें स्पष्ट रूप से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सभी वर्ग और जातियां शामिल हैं। किसी भी जाति, वर्ग या धार्मिक समुदाय के प्रति संकीर्ण राष्ट्रवादी भावना का कोई संकेत नहीं मिलता। उनका दृष्टिकोण विकासोन्मुखी है और उनका ध्यान सरकार को लोगों पर प्रभुत्व जमाने के बजाय उनकी सेवा करने का एक ईमानदार और सक्षम साधन बनाने पर केंद्रित है।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

और चूंकि नामो ने अपने वादों को गंभीरता से लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी पार्टी और विपक्ष के उन सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया, जिनकी नज़र में सत्ता का मतलब लूट और भ्रष्टाचार है। यही वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें निरंकुश और तानाशाह माना। मोदी की मुश्किलें विभाजनकारी एजेंडा लेकर आने के कारण नहीं, बल्कि फूट डालो और राज करो की राजनीति को समाप्त करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली खामियों को दूर करने के कारण पैदा हुईं। उन्होंने भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगह दुश्मन बना लिए क्योंकि उन्होंने प्रशासन को राजनेताओं और उनके पक्षपातपूर्ण एजेंडा का बंधक बनने के बजाय जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास किया।
अगले अध्यायों में यह वर्णन किया गया है कि कैसे उनके विरोधियों ने उन्हें उनके एजेंडे से भटकाने और उन्हें एक विभाजनकारी, ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, जबकि वे राजनीतिक रूप से रची गई गोधरा नरसंहार और उसके बाद हुए दंगों के बावजूद अपने दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता में अडिग रहे।
मोदी को बदनाम करने का अभियान 2002 के दंगों से शुरू नहीं हुआ था। "मोदी को बदनाम करने का अभियान" पहले दिन से ही चल रहा था और इसे उसी कर-करो वाली भावना से अंजाम दिया गया था, जैसा कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर करने की कोशिश में देखा जा रहा है। फरवरी 2002 में राजकोट से मोदी के पहले चुनाव पर आधारित अध्याय में यह बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

6 अध्याय 9, “कीचड़ फेंकना और कमल खिलना” देखें।

अध्याय 4

शासन के तौर-तरीके सीखना
नौसिखिया NaMo की नौकरशाहों के साथ पहली बातचीत

जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मुझे लगा कि सरकार की मूलभूत समस्याओं में से एक है अलग-अलग हिस्सों में सोचने की आदत और समन्वय का अभाव। समन्वय समय की मांग है... जब मैंने पहली बार सरकार में कार्यभार संभाला, तो अधिकारी इतने गुप्त थे कि वे नीति-निर्माण की फाइलों को किसी के साथ साझा नहीं करते थे, यह सोचकर कि उन्हें "लीक" होने से बचाया जा सके। मैंने उनसे पूछा कि नीति-निर्माण को सार्वजनिक जानकारी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? मैंने प्रत्येक नीति मसौदे को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर देकर गोपनीयता की संस्कृति को समाप्त कर दिया। मेरा विचार था कि इससे हमें प्रारंभिक चरण में ही अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी... खुलापन स्वतः ही पारदर्शिता लाता है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम के वादे से कहीं आगे है।
नरेंद्र मोदी का निजी साक्षात्कार, 2013

मैंने नरेंद्र मोदी के अधिकारियों से नौकरशाहों के साथ उनकी पहली मुलाकातों के बारे में कई दिलचस्प कहानियां सुनीं। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री के रूप में उनके शुरुआती दिनों के बारे में खुद नरेंद्र मोदी का नज़रिया भी जानने का फैसला किया। उनसे मिलने वाले पहले अधिकारी श्री अशोक भाटिया थे, जो उस समय सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव थे। उस मुलाकात के बारे में नरेंद्र मोदी के बयान के अनुसार:

जब मैं सर्किट हाउस में था, तभी एक पार्टी कार्यकर्ता ने घोषणा की कि जीएडी के सीएस
मुझसे मिलने आया है। मैंने इसे ईश्वर के रूप में सुना और मान लिया कि यह कोई पवित्र व्यक्ति है या
कोई संत मुझसे मिलने आए हैं। इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आश्चर्यचकित रह गया।
यह देखकर कि दरवाजे से अंदर आने वाला व्यक्ति पैंट और कोट पहने हुए था और
अपना परिचय श्री भाटिया के रूप में दिया। [अशोक भाटिया अतिरिक्त प्रमुख थे]
उस समय के जीएडी के सचिव]
मैंने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब तक मैं नहीं बैठा, वह नहीं बैठा क्योंकि
सरकारी अधिकारी एक विशेष अनुशासन का पालन करते हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने मुझे बताया,
“सर, जीएडी की आवश्यकताओं को देखना मेरा काम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बताएं।”
शासन के तौर-तरीके सीखना 67

मुख्यमंत्री के कक्ष में कोई बदलाव हुआ है क्या?” मैंने उनसे कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा।
मुख्यमंत्री का कक्ष। मैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कैसे करवा सकता हूँ?
जब तक मैं दिल्ली में रही, मेरे पास सिर्फ एक खाट और एक तांबे का बर्तन था।
पानी जमा करने के लिए। जनरल बनने के बाद भी यही मेरी जीवनशैली बनी रही।

तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के सचिव। इसलिए जब श्री भाटिया ने मुझसे पूछा कि किस तरह का
मैंने कहा, मुख्यमंत्री के कक्ष में वह जो बदलाव चाहते हैं, मैंने सुना है कि केशूभाई
मैं एक बहुत ही शाही, महाराजाओं जैसी कुर्सी पर बैठता था। देखिए, क्या आप इसे बदल सकते हैं?
लेकिन नई कुर्सी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोई भी साधारण कुर्सी ले आइए जो काम आ सके।
सचिवालय में फालतू पड़ा हो सकता है।
ऐसा लगता है कि सचिवालय में यह खबर फैलने में एक घंटा भी नहीं लगा। सभी हैरान थे कि नए मुख्यमंत्री ने अपने लिए कोई अतिरिक्त खर्च न करने की बात कही, जबकि वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। एक तरह से यही मोदी का प्रशासन को पहला संदेश था: फिजूलखर्ची नहीं। आज तक यही बात कायम है। उनके अधिकारी बताते हैं कि उनका निजी जीवन बेहद सादगीपूर्ण है; वे जनता के धन के प्रति सजग हैं और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्कता बरतते हैं।
मोदी और तत्कालीन मुख्य सचिव सुब्बा राव के बीच हुई पहली बातचीत मोदी की कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ मोदी का अपना पक्ष है, जिसकी मैंने सुब्बा राव से भी पुष्टि की है:
जब मुख्य सचिव सुब्बा राव मुझसे मिलने आए, तो उनका पहला सवाल था मेरा सवाल यह था कि मैं किन अधिकारियों को मुख्यमंत्री के स्टाफ के हिस्से के रूप में तैनात करवाना चाहता था।
वह सचमुच हैरान था और उसने उससे पूछा: क्या आपके पास पहले से ही कुछ अधिकारी नहीं हैं?
मुख्यमंत्री कार्यालय? राव ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मुख्यमंत्री को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है।
उनकी पसंद के कुछ निश्चित संख्या में अधिकारी।

मैंने उनसे कहा: देखिए, मैं किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं जानता। आप खुद फैसला कीजिए।
और आप जिन अधिकारियों को उपयुक्त समझते हैं, उन्हें तैनात करें।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखें।
निम्नलिखित मानदंड:
• आपके द्वारा चुने गए अधिकारी निर्विवाद सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होने चाहिए।
• उनमें लंबे समय तक काम करने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि मैं काम के प्रति बेहद समर्पित हूं।
• उन्हें तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए क्योंकि मैं इसका काफी उपयोग करने का इरादा रखता हूँ।
शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी।
• उनमें टीम वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए।
आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में मेरा पूरा जीवन मानव संसाधन को समर्पित रहा।
प्रबंधन। यहां तक कि जब मैं भाजपा में आया, तब भी मैं इन बातों पर जोर देता था।
कार्यकर्ताओं को तैयार करने, टीमें बनाने और उन्हें काम पर लगाने, आदि पहलुओं पर विचार करें।
प्रत्येक कर्मचारी को उसकी अपनी योग्यताओं के अनुरूप कार्य सौंपे जाते हैं। मेरा बुनियादी प्रशिक्षण 68 मोदी, मुसलमानों और मीडिया से संबंधित रहा है।

लोगों का आकलन करें, उनकी कठिनाइयों को समझें और उन्हें आवश्यकतानुसार कार्य सौंपें।
उनकी क्षमताओं के अनुसार। चूंकि मैं मूल रूप से आरएसएस द्वारा पोषित हूं जहां टीम वर्क होता है।

सुब्बा राव कहते हैं, “जब वे मुख्यमंत्री बने, तो मैं उनके आरएसएस पृष्ठभूमि के कारण बहुत चिंतित था। इसलिए जब मैं उनसे सर्किट हाउस में मिला, तो मैंने उनसे कहा, ‘महोदय, कृपया कानून या संविधान के विरुद्ध कुछ भी न कहें।’ लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि वे बहुत सतर्क हैं और कभी भी अपनी सीमा या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते। वे न तो लोकलुभावन भाषणबाजी करते हैं और न ही गैरजिम्मेदाराना और विचारहीन बयान देते हैं।”
मोदी की सुरक्षा में तैनात तीन अधिकारियों में से एक पी.के. मिश्रा थे, जो कद में छोटे और विनम्र दिखने वाले व्यक्ति थे और जिन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। वे चीजों को आसानी और शांति से निपटाने में माहिर माने जाते थे। इस ईमानदार अधिकारी ने मोदी को प्रशासन की बारीकियां सिखाईं, फाइलों की जांच कैसे करनी है, हस्ताक्षर कहां करने हैं और यहां तक कि हस्ताक्षर के लिए किस रंग की स्याही का उपयोग करना है जैसी छोटी- छोटी बातें भी बताईं। मोदी कहते हैं कि मिश्रा ने उन्हें आधिकारिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण ऐसे दिया जैसे किसी बच्चे को सिखाया जाता है। जब मैंने उनसे पूछा
शासन के तौर-तरीके सीखना 69

जब मोदी से यह पूछा गया कि सुब्बा राव द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारी सही विकल्प साबित हुए या नहीं, तो उनका जवाब काफी खुलासा करने वाला था:
मैंने कभी इस बात का विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाई। मेरा मानना है कि मुझे अपने अनुभव से जो मिलता है, वह काफी है।
अधिकारी मुझ पर निर्भर हैं। मैंने कभी अपने चपरासी, ड्राइवर या किसी और को नहीं बदला है।

मैं एक पदाधिकारी हूँ। मेरा काम है कि मुझे जो भी काम सौंपा जाए, मैं उसे पूरा करवाऊँ।
सरकार। यह कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि मुझे फलां अधिकारी दे दो।
उन्होंने मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक को भी नहीं बदला और उन्हीं अधिकारियों, कर्मचारियों, ड्राइवर और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ काम करते रहे जो केशूभाई की सेवा में थे। यह मोदी प्रशासन की पहचान बन गई - वे किसी गुट को बढ़ावा नहीं देते, न ही ऐसे किसी को जो मोदी का इतना करीबी होने का दावा कर सके कि उनके माध्यम से अपनी मनचाही चीजें करवा सके। जैसे ही कोई अधिकारी ऐसा करने की कोशिश करता है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है।
नौकरशाही में तालमेल बिठाना
अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करवाने के लिए नौकरशाही को एक नई कार्य संस्कृति का निर्माण करना आवश्यक था। संयोगवश, कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) का वार्षिक सम्मेलन मोदी के सत्ता में आने के पहले 3-4 हफ्तों के भीतर ही आयोजित होने वाला था। जब मुख्य सचिव सुब्बा राव उन्हें यह सूचित करने आए कि उन्हें सम्मेलन का उद्घाटन करना है, तो मोदी ने उनसे पूछा, "साहब, मुझे उस समारोह में क्या करना है?" सुब्बा राव ने उन्हें बताया, "महोदय, आप आइए और उद्घाटन दीप प्रज्वलित कीजिए तथा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनके लिए अपने सुझाव दीजिए। इसके बाद आप जा सकते हैं और हम सम्मेलन का शेष भाग संचालित करेंगे।"
जब मोदी ने उनसे पूछा कि सम्मेलन में वास्तव में क्या होता है, तो राव ने कहा, "हम कलेक्टरों और डीडीओ के अधीन प्रत्येक विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हैं।" मोदी आने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अपने कार्यालय को उस पूरे दिन को अन्य सभी कार्यों से मुक्त रखने का निर्देश दिया।

दीप प्रज्ज्वलन और स्वागत समारोह के बाद, यह घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। मोदी ने सबको चौंकाते हुए कहा, “मैं इस पद पर नया हूँ और मुझे आप लोगों से सीखना है। मैं आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ? आप अपनी सभा जारी रखिए। मैं थोड़ी देर बैठकर सुनना चाहता हूँ।”
पहले यह प्रथा थी कि कलेक्टरों और डीडीओ की वार्षिक समीक्षा सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू होती थी और दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाती थी। उन सभी अधिकारियों में 70 मोदी, मुस्लिम और मीडिया शामिल थे।

विभिन्न जिलों से सैकड़ों मील की यात्रा करके आए अधिकारी दोपहर के भोजन के बाद अपने-अपने जिलों में लौट जाते थे। प्रत्येक विभाग का सचिव—चाहे वह शिक्षा, कृषि, परिवहन, स्वच्छता हो—उस समय आता था जब जिला अधिकारियों को उस विभाग के कार्यों पर रिपोर्ट देनी होती थी। वह उनकी बात सुनता, कुछ सवाल पूछता, किसी बात पर उन्हें टोकता और चला जाता। उस दिन मोदी को इन बैठकों के संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें पता था कि ये महज़ औपचारिक प्रक्रियाएं हैं जो साल दर साल चलती रहती हैं।
लेकिन चूंकि मोदी पूरी बैठक में बैठे रहे, इसलिए कोई भी सचिव बैठक छोड़कर नहीं जा सका। हर वरिष्ठ अधिकारी को उतने ही समय तक बैठना पड़ा जितना मोदी बैठे रहे। जैसे ही प्रत्येक कलेक्टर और डीडीओ ने अपनी-अपनी प्रस्तुति दी, मोदी ने ध्यान से सुना और प्रत्येक जिले में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए नोट्स बनाए। इस तरह, उन्होंने इस एक बैठक को अपने सभी अधिकारियों को जानने और उनके काम की दिशा का आकलन करने के एक त्वरित प्रशिक्षण में बदल दिया। दोपहर के भोजन का समय होने पर, उन्होंने उनसे कहा, "हम दोपहर के भोजन के बाद बैठक जारी रखेंगे।" पूरे दिन वे एक शब्द भी नहीं बोले और बैठक

रात 11 बजे तक चलती रही। उन्होंने रात के खाने की भी पहले से व्यवस्था नहीं की थी और उन्हें मौके पर ही कुछ बनाना पड़ा।
रात 11 बजे, उन्होंने बैठक को इतना लंबा खींचने के लिए माफी मांगी और उनसे कहा, “मुझे खेद है; मैंने आपके कार्यक्रम में बाधा डाली, लेकिन मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। आप सभी जो काम करते हैं और जिस बारीकी से काम करते हैं, उसके लिए मेरी सराहना स्वीकार करें। अब हम बैठक समाप्त कर सकते हैं।” लेकिन अधिकारियों ने जोर दिया कि वे उन्हें संबोधित करें। जब मैंने मोदी से इस बैठक और उन्होंने अधिकारियों से क्या कहा, इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा:
मैंने उनसे कहा कि अब तक मैंने सरकार को केवल एक
बाहरी व्यक्ति। पहली बार मुझे अंदरूनी चीजों के बारे में बारीकियाँ पता चल रही थीं।
सरकार का कामकाज। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो यह
यह हमेशा एक सुखद अनुभव होता है।
मुझे पता था कि ये वही लोग हैं जिनके माध्यम से मुझे काम करवाना है।
मानव संसाधन प्रबंधन का संस्कार (दर्शन) कहता है कि मुझे अवश्य ही उन्हें प्रोत्साहन दें—चाहे वे अच्छे हों या बुरे, चाहे उन्होंने
चाहे वे मुझे समझाने में कामयाब हुए हों या नहीं। मेरा काम उनकी सराहना करके उन्हें प्रोत्साहित करना था।
उनका काम। मैंने उनसे कहा, मैं काम का दीवाना हूँ और बहुत सारे दौरे करने वाला हूँ। इसे समझ लो।
मैं संभवतः महीने में दो बार प्रत्येक जिले का दौरा करूंगा।
लेकिन मेरी एक सरल विनती है कि

जब मैं मिलने आऊं, तो कृपया अधिकारियों के पूरे काफिले को इकट्ठा न करें।
अपने जिले के। दूसरे, अपने जिले की समस्याओं को ठीक करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें।
सर्किट हाउस में नए पर्दे या नए बाथरूम फिटिंग लाने, दोबारा पेंट करने आदि का काम किया जाता है।
मेरे लिए कमरा ठीक कर दो या फिर यह या वह काम करवा दो।
शासन के तौर-तरीके सीखना 71

मैंने यह सब इसलिए कहा क्योंकि पहले पंद्रह दिनों में मैंने देखा था कि मेरे अधिकारी कैसे काम करते हैं।
मेरे लिए बहुत सी नई चीजें लेकर आया था - नए नल, नई बाल्टियाँ, और इसी तरह की चीजें।
तो मैंने उनसे कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और वर्तमान स्थिति में ही अपना गुजारा कर सकता हूँ।
कृपया मेरे लिए अतिरिक्त पैसे खर्च न करें। मुझे बस स्वच्छता चाहिए।
जिस जगह मैं रहता हूँ, वहाँ। तीसरी बात, मैं भव्य लंच में शामिल नहीं होने वाला हूँ। मैं
मैं अपना लंच बॉक्स खुद लेकर चलूंगा। अंत में, विशेष वाहनों की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मेरे लिए- मैं नहीं चाहता कि आप गांधीनगर से विशेष काफिले भेजें मुझे घुमाने ले जाइए। आपके विभाग में जो भी वाहन उपलब्ध हो।
ठीक है। आपकी नियमित व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त है। इसके बाद, मैंने पूछा
उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि वे मेरे लिए स्थानीय लोगों से मिलने का समय निकालें।

विधायकों और अन्य निर्वाचित अधिकारियों। मेरा मानना है कि लोगों को समय देना मेरा कर्तव्य है।
प्रतिनिधियों।
पहली ही बैठक में दिए गए ऐसे असामान्य निर्देशों ने अधिकारियों को आगाह कर दिया कि वे एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो लीक से हटकर काम करता है। पिछले एक साल में मैं गुजरात सरकार के जितने भी अधिकारियों से मिला हूँ, चाहे वरिष्ठ हों या कनिष्ठ, सभी ने इस बात की गवाही दी कि चुपचाप सुनना केवल उस पहली बैठक तक ही सीमित नहीं था। यह उनकी नियमित और विशिष्ट शैली है। वे अपने अधिकारियों, राजनीतिक सहयोगियों और सुझावों के साथ आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही वे किसी निर्णय पर पहुंचते हैं।
बेहतर समन्वय के लिए विकेंद्रीकरण तोड़ना: इसके बाद एक और असामान्य कदम उठाया गया। उन्होंने सभी वरिष्ठ सचिवों के एक साथ बैठकर एक-दूसरे की कार्य योजनाओं को सुनने की प्रथा शुरू की, ताकि विकेंद्रीकरण को तोड़ा जा सके और समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। मोदी ने इस कदम के पीछे का उद्देश्य इस प्रकार समझाया:
जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मुझे लगा कि सरकार की मूलभूत समस्याओं में से एक यह है कि
यह खंडित सोच की आदत और समन्वय की कमी है।
अभिसरण समय की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हमारे देश की 30 प्रतिशत आबादी...
अभिसरण लाकर ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों को योजना बनाने में शामिल करना और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
प्रक्रियाओं को एक साथ करने से गोपनीयता की संस्कृति से भी मुकाबला होता है जो गहराई से व्याप्त है।

सरकारों में गहराई से जमे हुए। जब मैंने पहली बार सरकार में काम करना शुरू किया, तो अधिकारियों ने
वे इतने गुप्त थे कि नीति-निर्माण की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करते थे।
इस धारणा पर फाइलें कि वे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थीं
"लीक हो गया"। मैंने उनसे पूछा कि नीति निर्माण को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण बताएं।
ज्ञान? मैंने प्रत्येक नीति पर जोर देकर गोपनीयता की संस्कृति को समाप्त कर दिया। 72 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मसौदे को ऑनलाइन डाल दिया जाए ताकि यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। मेरा विचार यह था कि
इससे हमें प्रारंभिक चरण में ही अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। पहले तो सब चौंक गए। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह कैसे खुलता है।
इसने नए विचारों के द्वार खोले और हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद की जो
सरकार की चिंतन प्रक्रिया में अंतर्निहित। इसका एक अन्य लाभकारी प्रभाव।
इस खुलेपन का फायदा यह था कि इससे निहित स्वार्थों की हेरफेर करने की शक्ति पर अंकुश लग गया।
उनके पक्ष में सरकारी नीतियां। एक बार सार्वजनिक होने पर, न केवल न केवल व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी, बल्कि आम नागरिक भी अवांछित प्रभावों को उजागर कर सकते हैं।
विशिष्ट नीतियों पर। इस तरह हमने सुधारात्मक तंत्र विकसित किए ताकि उनका समाधान किया जा सके।

नीति के प्रारंभिक चरण में ही उसकी खामियों और सीमाओं का पता चल जाता है। इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है।
लंबे समय में भरपूर लाभ मिलेगा। जब से हमने जनता से सुझाव लेना शुरू किया है और
कार्ययोजना तैयार करते समय जहाज पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, कुल मिलाकर
सरकारी नीतियों के संबंध में बहुत कम विरोध और विवाद हैं। गुजरात में। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी सभी नीतियां एकदम सही हैं, लेकिन चूंकि वे बनाई गई हैं
खुले और पारदर्शी तरीके से, वे विवाद का कारण नहीं बनते।
उदाहरण के लिए, सामान्यतः, विकास योजनाएँ (डीपी) या नगर नियोजन योजनाएँ
(टीपीएस) राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए धन कमाने के अवसर प्रदान करते हैं।
मैंने डीपी और टीपीएस को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया है। पहले जब भी डीपी और टीपीएस उपलब्ध होते थे,
टीपी योजनाएं बाजार में आने पर हजारों शिकायतें आती थीं।
उनके खिलाफ। लेकिन हमें 300 से 400 से अधिक शिकायतें नहीं मिलतीं और वे भी
वास्तविक लाभ – निहित स्वार्थों से प्रेरित नहीं। पारदर्शिता स्वतः लाभ लाती है।
पारदर्शिता। यह सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा किए गए वादों से एक कदम आगे है।
उस दौरान मोदी के साथ मिलकर काम करने वाले पी.के. मिश्रा कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके तहत सप्ताह में दो या तीन बार शाम छह बजे,

सभी विभागों के प्रमुखों और सचिवों के साथ-साथ मंत्रियों को भी उपस्थित होना होगा।
उनसे मिलना था। और हर दिन किसी न किसी विभाग को प्रस्तुति देनी होती थी।
अगले छह महीने या एक वर्ष के लिए गतिविधियों और कार्य योजना के बारे में।
इससे मुख्यमंत्री को काफी जानकारी मिली। अधिकारियों को भी लगा कि पहली बार उन्हें आंतरिक भाग की इतनी व्यापक तस्वीर मिल रही थी। सरकार की कार्यप्रणाली।
कई अन्य नौकरशाहों ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि इससे टीम वर्क की भावना पैदा करने में मदद मिली। प्रत्येक विभाग को दूसरे विभागों के बारे में जानकारी मिली और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। चूंकि एजेंडा सामूहिक रूप से तय किए जाते थे, इसलिए प्रत्येक विभाग के सचिव को अन्य विभागों को सुझाव देने का अवसर दिया गया ताकि एजेंडा में सुधार किया जा सके।
शासन के तौर-तरीके सीखना 73

विचारों के आदान-प्रदान के बारे में। इससे तालमेल भी बढ़ा क्योंकि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और लक्ष्य सर्वसम्मति से निर्धारित किए जाते थे। इसने आपसी टकरावों को नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी एक-दूसरे के काम में बाधा न डालें, जैसा कि अक्सर सरकारी विभागों में होता है। विचार-विमर्श सत्र लंबे, गंभीर और गहन होते थे। मोदी प्रत्येक अधिकारी की बात ध्यान से सुनते थे और चर्चा के लिए अपने सुझाव भी रखते थे। मिश्रा कहते हैं:
उन दिनों मुख्यमंत्री का मुख्य ध्यान सेवाओं के वितरण में तेजी लाने और उसे सुव्यवस्थित करने पर था।

आईएएस अधिकारी थे - और उन सभी का एक साथ तबादला कर उन्हें महत्वहीन पदों पर भेज दिया।
यह एक बड़ा धमाका साबित हुआ क्योंकि इन अधिकारियों ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा था; उनका इतना दबदबा था कि उन पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद किसी ने भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की थी। इससे यह स्पष्ट संदेश मिला कि मोदी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देंगे। इसलिए, उनमें से कुछ ने सरकार छोड़कर अन्य पदों पर काम करने का फैसला किया। उन्हें सम्मानजनक विदाई दी गई। मैंने जिन लगभग सभी नौकरशाहों से बात की, उन्होंने कहा कि मोदी अधिकारियों को अनुशासित करने के लिए सजा, निलंबन या बर्खास्तगी जैसी धमकियों का इस्तेमाल करने से बचते हैं। जब मैंने मोदी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा: “मैं लोगों को सुधार का मौका देने में विश्वास रखता हूँ, यही मेरा मूल संस्कार है।” उनके अधिकारियों ने मुझे बताया कि दंडात्मक उपायों से बचने की इस प्रवृत्ति की वजह से उन्हें कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके विरोधियों के सहयोगी बन गए और मोदी विरोधी गुटों में शामिल हो गए।
कुल मिलाकर, भले ही मोदी ने अपने मंत्रिमंडल या नौकरशाही टीम की संरचना में कोई नाटकीय बदलाव या फेरबदल नहीं किया, लेकिन उनकी कार्यशैली और सरकार को आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त साधन बनाने के उनके दृढ़ संकल्प ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के भीतर कई लोगों को नाराज कर दिया।

अध्याय 5

मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह
“Sabka Saath, Sabka Vikas” in Action

जब सच्चर समिति के सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की और पूछा, “श्री मोदी, आपने गुजरात के मुसलमानों के लिए क्या किया है?” तो मैंने उनसे कहा: कुछ नहीं, मैंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि मैंने हिंदुओं, जैनियों या सिखों के लिए भी कुछ नहीं किया है। मैं 55 करोड़ गुजरातियों के लिए जिम्मेदार हूं और मैं जो कुछ भी करता हूं, उसका उद्देश्य मेरे राज्य के इन सभी 55 करोड़ लोगों के हितों की सेवा करना है। जब हमारी नदी जोड़ने की परियोजना के कारण नर्मदा का शुद्ध जल साबरमती में बहता है, तो क्या आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं यह मापूं कि हिंदुओं द्वारा कितने लीटर पानी का उपयोग किया जाता है और कितना पानी मुस्लिम घरों में जाता है? मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति मिले। कृपया मुझसे आपकी विभाजनकारी शब्दावली और दृष्टिकोण को अपनाने की अपेक्षा न करें। - नरेंद्र मोदी, व्यक्तिगत साक्षात्कार, 2013

कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर एक दुष्परिणाम गढ़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के क्षण से ही उन्होंने गुजरात को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का अभियान शुरू कर दिया और हिंदू वोटों को एकजुट करने और मुसलमानों को आतंकित द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में जीने के लिए मजबूर करने के लिए 2002 के दंगों को अंजाम दिया।

यहां तक कि जो लोग मोदी के सुशासन और विकास कार्यों का सम्मान करते हैं, उनका भी यही मानना है कि मोदी ने विकासोन्मुखी रुख तभी अपनाया जब उन्होंने सफलतापूर्वक एक मजबूत हिंदू वोट बैंक हासिल कर लिया था।
इस अध्ययन को शुरू करने से पहले, मैं भी यही सोचता था कि मोदी ने 2002 के बाद गुजरात को दंगों से मुक्त इसलिए रखा क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि 2002 के दंगों का उल्टा असर उन पर ही पड़ा है। हालांकि, जब मैंने 7 अक्टूबर, 2001 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के क्षण से लेकर मोदी के कार्यकाल का बारीकी से अध्ययन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था।
मोदी को गहराई से समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को यह देखना होगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को कैसे परिभाषित किया, अपनी प्राथमिकताओं को कैसे निर्धारित किया और 76 वर्षों में उन्होंने कौन से कार्यक्रम और सुधार शुरू किए। मोदी, मुसलमान और मीडिया

गोधरा हत्याकांड और उसके बाद की हिंसा से पहले उनके कार्यकाल के लगभग 19 सप्ताह बीत चुके थे। यही वह महत्वपूर्ण समय था जब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें उपचुनाव (फरवरी 2002) जीतना आवश्यक था। राजनेता आमतौर पर चुनाव के समय लोकलुभावन भाषणबाजी करने लगते हैं। लेकिन मोदी का चुनाव अभियान, जिसका विस्तृत वर्णन अध्याय 8 में किया गया है, आक्रामक या कटु नहीं था। इस अध्याय में, मैं मोदी द्वारा अपने कार्यकाल के पहले चार महीनों में अपनाई गई प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता हूँ।
मोदी ने बार-बार दोहराया है कि उनका मूल मंत्र है “सबका साथ, सबका विकास”। उनके अधिकारियों और राजनीतिक सहयोगियों के अनुसार, मोदी की शासन शैली की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वे किसी भी परियोजना

भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास में ही मोदी का काफी समय लगा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बार-बार उन क्षेत्रों का दौरा किया। पहले 19 हफ्तों के दौरान,
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 77

उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 20 से अधिक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें और कई जिला स्तरीय बैठकें आयोजित कीं। एक सामान्य समय विश्लेषण से भी पता चलता है कि मोदी का 60 प्रतिशत समय भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने में व्यतीत हुआ; शेष समय प्रशासनिक कार्यों को सीखने में लगा।
इस बेहद कठिन दौर में एक नई शासन शैली की शुरुआत की गई, जिसने लोगों को विकास में सक्रिय भागीदार बनाया। परिणामस्वरूप, भूकंप से तबाह और पिछड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र कच्छ, उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाला जिला बनकर उभरा। अपनी अगली पुस्तक में, मैं उन दूरगामी व्यवस्थागत सुधारों का भी वर्णन करूँगा जिन्हें मोदी ने गुजरात को उसके चिरस्थायी जल संकट से उबारने के लिए इन शुरुआती कुछ हफ्तों में शुरू किया था।
ग्राम राज्य और समरस पंचायतें: मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद जो पहला निर्णय लिया, वह था पंचायतों को ग्रामीण विकास का प्रमुख साधन बनाना। 11 अक्टूबर को, यानी शपथ ग्रहण के चार दिनों के भीतर— और गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे) के जन्मदिन पर—उन्होंने समरस गांवों के निर्माण के लिए समरस पंचायत योजना की घोषणा की। आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, मोदी ने जेपी के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने 'समरस' को 'एकजुट और एकजुट' के रूप में परिभाषित किया। समरस गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां पंचायत का गठन

[illegible]
[illegible]
[illegible]

प्रशासन में फेरबदल शुरू कर दिया और यथासंभव अधिक से अधिक समरस चुनाव सुनिश्चित किए। ग्राम सभाओं का पहला चरण 11 अक्टूबर, 2001 को आयोजित किया गया था। मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए यह संदेश दिया कि लोकतंत्र को जन-केंद्रित बनाने के लिए ग्राम सभा को लोकसभा (संसद) के समान महत्व दिया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं को दिए गए महत्व को उजागर करने के लिए, मोदी ने इन सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की पूरी शक्ति का उपयोग किया। स्वयं मोदी ने ग्राम सभाओं में शारीरिक रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेना शुरू किया। उनके सभी मंत्रिमंडल मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों को भी ग्राम सभाओं में उपस्थित होने के लिए कहा गया। यह परंपरा आज तक जारी है। प्रत्येक गांव में प्रतिवर्ष कम से कम छह ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं।
मोदी के सत्ता में आने के पहले कुछ हफ्तों के भीतर ही 18,000 से अधिक गांवों में ग्राम सभाओं का गठन किया गया। अक्टूबर 2001 से 2008 के बीच, उन्होंने बुनियादी ढांचे, सामाजिक संघर्षों के समाधान, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसार आदि से संबंधित कुल शिकायतों और विवादों में से 92 प्रतिशत का निपटारा किया। इसी अवधि के दौरान, जिन ग्राम पंचायतों में चुनाव निर्धारित थे, उनमें से 7,793 पंचायतों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और उन्हें 'समरा' घोषित किया गया। सरकार ने इन समरा गांवों को प्रोत्साहन के रूप में 65.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
2013 में, मैंने कई ऐसे गाँवों का दौरा किया जहाँ निर्वाचित समरस पंचायतें थीं। वे उन गाँवों की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय रूप से काम कर रही थीं जहाँ चुनाव में कड़े मुकाबले हुए थे। आज गुजरात के गाँवों में असंतुष्ट लोगों की संख्या कम होने का एक कारण यह है कि ग्राम सभाओं को अपने गाँव के कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने

के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। नौकरशाहों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि न तो वे, न ही विधायक और न ही मंत्री ग्राम सभाओं द्वारा विकास कार्यों के संबंध में लिए गए निर्णयों को पलटें। इससे विकास प्रक्रियाएँ राजनेताओं, विशेषकर सत्ताधारी दल के नेताओं के चंगुल से मुक्त हो गईं।
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 79

विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले राजनेता के रूप में बदनाम मोदी द्वारा समरस की अवधारणा को प्राथमिकता देना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा समरस की राजनीति पर किए गए हमलों के जवाब में, मोदी ने विधानसभा में उन्हें याद दिलाया कि वे इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रहे हैं।
राज्यसभा चुनावों के लिए, इस सदन के किसी भी सदस्य को मतदान नहीं करना पड़ा।
अपना वोट डालने की परेशानी। चार सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए।
मैं आप सभी की ओर से उन्हें राज्यसभा के लिए बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं।
कि वे गुजरात की भलाई के लिए निरंतर और ईमानदारी से प्रयास करेंगे।
मैं अपने उन कांग्रेस सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सिद्धांत का विरोध करने के बावजूद,
ग्राम पंचायतों के लिए गठित समरस ने राज्यसभा के लिए भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया।
इससे यह संकेत मिलता है कि मोदी कांग्रेस पार्टी से भी टकराव नहीं चाहते थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठना पसंद करते थे। अपनी अगली पुस्तक में, मैं उदाहरण दूंगा कि कैसे आज भी मोदी ग्रामीण राजनीति में समरसता को प्रोत्साहित करते

हैं और कांग्रेस-प्रभुत्व वाले नगर निगमों और पंचायतों की जरूरतों को उतनी ही तत्परता से पूरा करते हैं जितनी भाजपा- प्रभुत्व वाली पंचायतों की।1
लोक कल्याण मेले: जनता के घर तक सरकार की सेवाएं। मोदी द्वारा शुरू किए गए शुरुआती महत्वपूर्ण कदमों में से एक गरीबों को उनके घर पर ही सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्थापित करना और साथ ही इन सेवाओं के वितरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाना था। भारत में प्रत्येक राज्य सरकार के पास गरीबों के लिए अनगिनत सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं—गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति से लेकर विधवाओं के लिए पेंशन, घर या शौचालय निर्माण के लिए सब्सिडी तक। दुर्भाग्य से, गरीबों का एक बड़ा वर्ग न तो इन योजनाओं के बारे में जान पाता है और न ही उन्हें इनका लाभ उठाने का तरीका पता होता है। यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है और नौकरशाही गरीबों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग करती है।
मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद, मोदी ने अपने अधिकारियों को गरीबों के लिए मौजूद सभी कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी की एक विस्तृत सूची बनाने का आदेश दिया था। जब सूची उनके सामने पेश की गई, तो उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या वे उन्हें स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि एक वृद्ध, अशिक्षित विधवा या गरीब परिवार का कोई विकलांग व्यक्ति अपने हक का दावा कैसे कर सकता है। जाहिर है, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इसका सटीक जवाब नहीं दे सका।
1. अध्याय 22 में, “ट्रस्टीशिप, धर्म और करुणा” विषय पर, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
उन्होंने समरसता पर जोर देने के पीछे की प्रेरणा के स्रोत को स्पष्ट किया।
80 मोदी, मुसलमान और मीडिया

स्पष्ट उत्तर क्योंकि ऐसे मामले आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारियों की मनमानी पर छोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने उनसे कहा, “यदि हम जैसे योजनाएँ बनाने वाले ही किसी व्यक्ति को सरकार से मिलने वाले कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने का सही तरीका नहीं बता सकते, तो हम गरीबों और जरूरतमंदों से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे स्वयं इनका लाभ उठाएँगे? इसलिए, अब से किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने लिए घोषित लाभों के लिए भीख माँगने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार हर साल उनके घर जाकर उन्हें ये लाभ एक साथ प्रदान करेगी।”
इस संकल्प के परिणामस्वरूप लोक कल्याण मेलों (जन कल्याण मेलों) को संस्थागत रूप दिया गया। ये मेले सबसे लोकप्रिय और नवोन्मेषी कार्यक्रमों में से एक साबित हुए, जिन्होंने न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया बल्कि लोगों के घर-घर तक सरकारी सेवाओं की डिलीवरी की अवधारणा को भी पेश किया।
लेकिन इसके लिए पहले से ही सक्रिय संपर्क और उचित सर्वेक्षणों के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों की पहचान करना आवश्यक हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रक्रिया की सीधी निगरानी की। कल्याणकारी योजनाओं के संभावित लाभार्थियों की सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों का दौरा किया और चयनित व्यक्तियों को चेक या वस्तु के रूप में कल्याणकारी लाभ सौंपे। यह सब सुगठित सार्वजनिक समारोहों में हुआ। इससे स्वतः पारदर्शिता आई और मनमानी चयन प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए।
जिन लोगों को चेक या अन्य लाभ प्राप्त करने थे, उन्हें सबके सामने पेश होना पड़ता था। पूरी जनता देखती थी कि लाभ सही व्यक्ति को मिला या नहीं। इससे अयोग्य लोगों द्वारा गरीबों के लिए बने लाभों

पर कब्ज़ा करने या भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा फर्जी लाभार्थियों को दिखाकर धन हड़पने की संभावना बहुत कम हो गई। यह त्वरित सार्वजनिक लेखापरीक्षा का एक बेहतर तरीका साबित हुआ, उन तरीकों की तुलना में जिनमें धन की चोरी होने के बहुत बाद भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है।
पूर्व मुख्य सचिव सुब्बा राव कहते हैं कि जब फरवरी 2002 के पहले सप्ताह से लोक कल्याण मेलों का पहला दौर आयोजित किया गया, तो मोदी ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे जनभागीदारी चाहते हैं ताकि सभी को यह स्पष्ट संदेश मिले कि सरकार उनके पास आएगी, न कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अधिकारी बहुत हैरान थे क्योंकि उनका मानना था कि बड़ी जनसभाओं का आयोजन करना राजनेताओं का काम है, नौकरशाहों का नहीं।
पहला लोक कल्याण मेला डीसा में आयोजित किया गया था। सरकारी कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। 5 जनवरी, 2002 को द हिंदू में प्रकाशित निम्नलिखित रिपोर्ट के अनुसार,
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 81

संवाददाता मानस दासगुप्ता ने 4 जनवरी को बनासकांठा के आदिवासी जिले में आयोजित पहले लोक कल्याण मेले का वर्णन किया:
केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री, जोएल ओरम ने आज एक घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को कल्याणकारी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की विशेष मंजूरी।
राज्य के आदिवासियों के बारे में। यह घोषणा अभूतपूर्व समय पर की गई।
राज्य में पहली बार आयोजित लोक कल्याण मेला, और शायद

देश के किसी भी हिस्से में, सीमावर्ती जिले के सुदूर कस्बे डीसा में
उत्तर गुजरात में बनासकांठा का.
यह आयोजन न केवल लाभार्थियों को एक साथ लाने के मामले में अद्वितीय था, बल्कि
विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाएं सीधे तौर पर संपर्क में हैं
प्रशासन के अनुसार, लगभग 1,300 स्थानों से तीन लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति रही।
जिले के गांवों और कस्बों ने सभी मामूली अनुमानों को पार कर लिया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित यह 'मेला' उन लोगों को बेनकाब करने के उद्देश्य से बनाया गया है जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना चाहते हैं।
प्रशासन को जनता तक पहुंचाना और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनपढ़ ग्रामीणों को जानकारी देना।
वे किन क्षेत्रों में कार्यरत लोग अधिकारियों से किन लाभों की अपेक्षा कर सकते हैं और उनकी मांग कर सकते हैं, यह सब उन पर निर्भर करता है।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य है
राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक बार इसका आयोजन किया जाएगा। विभिन्न स्टालों पर जानकारी देने वाले स्टॉलों का दौरा करते समय बड़ी संख्या में लोग...
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें इस बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी।
कई योजनाओं में भाग लिया गया है, और अब तक लाभ प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इनसे। यह पहली बार था कि कई कल्याणकारी योजनाओं ने सीमित कर दिया था।
कानून की किताबों को सबके सामने लाया गया और लोगों को शिक्षित किया गया।
इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के तरीके के बारे में।
इसके अतिरिक्त, 54,721 लाभार्थियों को मौके पर ही 10 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई।
94 कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनुदान के रूप में 49.75 करोड़ रुपये दिए गए। यह जानकर वे आश्चर्यचकित रह गए।
इसके अलावा सरकारों द्वारा लगभग 200 अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई थीं।
जिसके तहत पात्र लोग लाभ का दावा कर सकते थे। इसके अलावा और भी कई अच्छी तरह से स्थापित व्यवस्थाएँ थीं।
सरदार पटेल और डॉ. अंबेडकर आवास योजनाओं जैसी प्रसिद्ध योजनाएं, बीमा सुरक्षा, बैंक योग्य योजनाएं, ऋण, छात्रवृत्तियां,
और अन्य बातें जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी लेकिन वे उनका लाभ नहीं उठा सके।
प्रक्रियात्मक उलझनें।
मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद, श्री मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था।
प्रत्येक जिले में इस तरह के मेले आयोजित करने का विचार लोगों को एक साथ लाने और
प्रशासन को एक-दूसरे के करीब लाना होगा। 'अब प्रशासन को जाने का समय आ गया है।'
श्री मोदी ने कहा, 'लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, न कि इसके विपरीत।'
82 मोदी, मुसलमान और मीडिया

लोक कल्याण मेले अब तक वर्षों से जारी हैं। इनसे भले ही अचूक परिणाम न मिले हों, लेकिन इन्होंने निश्चित रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) निधि के दुरुपयोग को रोका है और एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो पारदर्शिता और निरंतर सुधार की अनुमति देती है। कुछ मायनों में, राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि बीपीएल मानदंड केंद्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनमें कई अंतर्निहित कमियां हैं।
अधिकांश राज्यों में, सरपंचों द्वारा बीपीएल परिवारों को चुन-चुनकर उनका इस्तेमाल वास्तव में गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने के लिए किया जाता है। लेकिन गुजरात में, लाभार्थियों की पहचान के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण हर साल एक निश्चित तिथि तक एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। मोदी, अपने पूरे मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हर साल पूर्व निर्धारित तिथियों पर गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं।
ये मेले भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी तंत्र की बुनियादी दिशा को जन-केंद्रित बनाने के लिए मोदी के विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मोदी अधिकारियों को दंडित करने के लिए दंडात्मक या नाटकीय तरीकों—जैसे स्टिंग ऑपरेशन, निलंबन, बर्खास्तगी की धमकी — से बचते हैं। इसके बजाय, सुविचारित संस्थागत तंत्रों के माध्यम से ऐसी प्रणालियाँ स्थापित की जाती हैं जो पारदर्शिता लाती हैं और ऐसे कोषों को नियंत्रित करने वाले नौकरशाहों की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाती हैं। इन प्रणालियों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी की जाती है ताकि खामियों या नई चुनौतियों के सामने आने पर उनमें और सुधार किया जा सके।

कन्या केलवानी और शाला उत्सव कार्यक्रम: मोदी के कार्यकाल के पहले तीन महीनों में शुरू किए गए इन पूरक कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करना है, ताकि स्कूल में दाखिले का अनुभव बच्चों के लिए सुखद और यादगार बन सके। इन कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सत्ता संभालने के एक महीने के भीतर ही मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या केलवानी योजना नामक एक विशेष कोष स्थापित किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक प्राप्त और भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी उपहारों को सरकारी खजाने में जमा करके बालिका शिक्षा को व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाएगी। इन उपहारों की नीलामी की जाएगी और प्राप्त राशि कन्या केलवानी कोष में दी जाएगी, जिससे राज्य के 100 पिछड़े तालुकों के सबसे गरीब जिलों की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी। मोदी के शब्दों में:
आज लाभ पंचमी है। मैंने सोचा कि इस शुभ दिन पर गुजरात में
राजकोष को मेरे माध्यम से कुछ लाभ (मुनाफा) मिलना चाहिए। मुखिया बनने के बाद
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 83

मंत्री जी, मैं भी सरकारी संपत्ति हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में, जहाँ कहीं भी
मैं गया था, मुझे कोई न कोई उपहार दिया गया था। वो चीजें मायने नहीं रखतीं।
ये मेरे हैं; ये गुजरात की जनता के हैं। इसीलिए मैंने सोचा।
इन सभी को सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए। मैंने अनुरोध किया है।

सरकार से अनुरोध है कि मैं आपको जो कुछ भी दे रहा हूं, उसे सर्वोत्तम मूल्य पर नीलाम किया जाए।
संभावित कीमत और एकत्रित की गई सारी धनराशि लड़कियों और उनके लिए जानी चाहिए।
महिलाओं की शिक्षा। अगर इस पैसे का इस्तेमाल महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाता है, तो इससे
इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली। सरकार जल्द ही व्यवस्था करेगी। इस सुझाव को लागू करने के लिए।
जब एक पत्रकार ने पूछा कि इन वस्तुओं की कीमत कैसे तय की जाएगी, तो मोदी ने जवाब दिया, “मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं खरीदीं। न ही मैंने कभी उन्हें उस नजरिए से देखा है। जब लोग सार्वजनिक समारोहों में आपको उपहार देते हैं, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। मैं इन्हें सड़कों पर बांट सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इन्हें सरकारी खजाने में देना ही बेहतर है।”
एक अन्य पत्रकार ने टिप्पणी की, "हमें बताया गया है कि 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना के बाद से राज्य के खजाने में कुल 164 वस्तुएं जमा की गई हैं, लेकिन आपने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के एक महीने के भीतर ही 165 वस्तुएं जमा कर दी हैं।"
मोदी का जवाब था: “मैं अपने से पहले जो कुछ हुआ है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं श्रेष्ठता की होड़ में विश्वास नहीं करता। मैं यह इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी और ने ऐसा नहीं किया है। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है। जैसा कि मैंने अभी कहा, महात्मा गांधी का न्यास का सिद्धांत ही मुझे प्रेरित करता है। इसीलिए मैं यह कर रहा हूं।”2 मोदी के उपहारों की पहली नीलामी से 17,00,000 रुपये जुटाए गए। तब से उस कोष में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य के उपहार और धन जमा हो चुके हैं, और यह लगातार बढ़ रहा है—यह सब ऐसे देश में हो रहा है जहां

ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने राज्य के खजाने से कीमती प्राचीन वस्तुएं चुराई हैं।
मोदी 2002 से हर साल कन्या केलवानी और शाला उत्सव अभियान का नेतृत्व करते आ रहे हैं। स्कूलों में वार्षिक प्रवेश से ठीक पहले, विभिन्न जिलों के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने गांवों और कस्बों में जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय अधिकारी और ग्राम पंचायत सदस्य स्कूल में दाखिले की उम्र के सभी बच्चों के परिवारों से संपर्क करें, खासकर गरीब और वंचित समूहों के बच्चों से, और उन्हें अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए राजी करें। फिर, चिलचिलाती गर्मी में तीन दिनों तक,
2. महात्मा गांधी के न्यास के विचार से नमो के जुड़ाव के बारे में अधिक जानने के लिए, अध्याय पढ़ें।
22.

84 मोदी, मुसलमान और मीडिया

जून माह में, वर्ष 2002 से हर साल, मुख्यमंत्री, उनके सभी मंत्रिमंडल मंत्री, वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अधिकारी और अन्य राज्य सरकारी अधिकारी विभिन्न गांवों में आयोजित होने वाले भव्य सार्वजनिक समारोहों में भाग लेते हैं, जहां नए स्कूली बच्चों को धूमधाम से जुलूस के साथ एक उत्सवपूर्ण जनसभा में लाया जाता है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, एक स्कूल किट (जिसमें बैग, किताबें, पेंसिल, रंग के डिब्बे, विशेष रूप से तैयार की गई पौष्टिक चॉकलेट जिसे 'बाल भोग' कहा जाता है) और खिलौने दिए जाते हैं। प्रत्येक बालिका को उसके नाम पर 1,000 रुपये का नर्मदा बांड भी दिया जाता है, जिसे सातवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर भुनाया जा सकता है।

नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों को शामिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
2013 में, मैंने कन्या केलवानी की कई सभाओं में भाग लेने के लिए यात्रा की, जिन्हें मोदी ने स्वयं 14 से 16 जून तक संबोधित किया, जब तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। इन सभाओं में उनका प्रेरणादायक भाषण, जिसमें उन्होंने सभी अभिभावकों और पंचायतों से सभी बच्चों को उचित शिक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया, सभी स्कूलों में प्रसारित किया जाता है। इन सभाओं की उल्लेखनीय बातों में से एक यह है कि आम किसान, दुकानदार, दूध उत्पादक, टैक्सी चालक आदि मोदी के कन्या केलवानी कोष में दान करते हैं, जो इस अभियान के लिए बढ़ते जनसमर्थन को दर्शाता है। उनके द्वारा दान किए गए धन का सदुपयोग करते हुए, मैंने अधिकांश स्थानों पर लोगों को उन्हें चांदी की मोटी चूड़ी भेंट करते देखा, संभवतः इसलिए कि इसे भुनाना आसान होता है। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, स्कूलों में ड्रॉपआउट दर, जो 2002-2004 में 17.83 प्रतिशत थी, 2012-2013 में घटकर 2 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर 57.80 प्रतिशत से बढ़कर 70.73 प्रतिशत हो गई है।
शत प्रतिशत नामांकन और छात्रों के स्कूल में बने रहने के इस लक्ष्य को स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षकों के प्रदर्शन में हुए महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन प्राप्त है। मैं इस पहलू पर अपनी अगली पुस्तक में विस्तार से चर्चा करूंगा।
प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों के बिना स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं था। मोदी के सत्ता संभालने के तुरंत बाद, सरकार ने एक ही बार में 1,20,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती की। पिछली सरकारों की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा

सकता है कि पिछले दस वर्षों में एक भी नए शिक्षक की भर्ती नहीं हुई थी। तब से, शिक्षकों की भर्ती और तबादलों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थागत बदलाव किए गए हैं, जिनमें योग्यता आधारित चयन और तबादलों की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना शामिल है। अपनी अगली पुस्तक में, मैं ग्रामीण और शहरी दोनों विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करूंगा।
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 85

शाला उत्सव कार्यक्रमों में मैंने मोदी को प्रत्येक गाँव को एक बड़ा दूध का डिब्बा भेंट करते हुए देखा। उन्होंने अपील की कि जिन परिवारों के पास पशु हैं, वे अपने दैनिक दूध उत्पादन का एक छोटा हिस्सा उस डिब्बे में डालें और स्थानीय आंगनवाड़ी (ग्राम पंचायतों के माध्यम से बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिशुगृह) में आने वाले बच्चों के लिए स्वैच्छिक दान के रूप में दें। यह डिब्बा प्रत्येक गाँव के सहकारी दूध खरीद केंद्र पर रणनीतिक रूप से रखा गया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि सरकार इन आंगनवाड़ियों में आने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं कराती है। गुजरात की ग्रामीण और शहरी दोनों आंगनवाड़ियाँ देश की सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ियों में से हैं। यह मोदी का हर सामाजिक विकास उपाय को जन आंदोलन में बदलने का तरीका है, जिसके तहत वे गाँव के प्रत्येक परिवार को गाँव के सभी बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ज़िम्मेदार महसूस कराते हैं। यह अपील व्यर्थ नहीं गई है। मोदी के आह्वान पर, धनी व्यक्तियों और कॉरपोरेट घरानों ने भी इनमें से कई आंगनवाड़ियों को गोद लिया है। यहाँ तक कि आंगनवाड़ियों के लिए उनका खिलौना संग्रह अभियान भी एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से घर-घर

जाकर खिलौने दान में इकट्ठा करने को कहा। वे चाहें तो किसी धनी उद्योगपति से भी बड़ी मात्रा में खिलौने दान करने को कह सकते थे, लेकिन लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मध्यमवर्गीय परिवारों को शामिल करके वे वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे।
मैंने गांवों में स्थित कई आंगनवाड़ियों का अचानक दौरा किया: भोजन की गुणवत्ता या सामान्य बुनियादी ढांचे के मामले में उनमें से कोई भी निराशाजनक नहीं निकला। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में मैं इस मुद्दे पर और अधिक विस्तृत अध्ययन करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, 25 दिसंबर 2001 को महिला एवं बाल कल्याण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई। ऐसे विभाग लगभग हर राज्य में आम हैं। हालांकि, अधिकांश अन्य राज्यों के विपरीत, गुजरात का महिला एवं बाल कल्याण विभाग एक सुस्त और निष्क्रिय नौकरशाही संस्था नहीं है। इसे कमजोर महिलाओं और बच्चों की सेवा के लिए कई विशेष और लक्षित उपाय करने हेतु एक सक्रिय और सक्षम साधन बनने के लिए मजबूर किया गया है। अधिकांश अन्य मुख्यमंत्रियों के विपरीत, जो इसे एक महत्वहीन और मामूली विभाग मानते हैं, मोदी की कार्ययोजना में यह उनके विकास मॉडल का केंद्रबिंदु है। यहां तक कि एक सामान्य समय विश्लेषण से भी पता चलता है कि मोदी राज्य की औद्योगिक नीतियों से निपटने की तुलना में इस विभाग से जुड़े कार्यक्रमों पर प्रति वर्ष अधिक समय व्यतीत करते हैं।
86 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मोदी की कुछ सबसे प्रभावी पहल और अभियान, जैसे ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए 50,000 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन; महिला कैदियों के लिए कारावास की अवधि में राहत का प्रावधान;

और 'बालिका बचाओ ' अभियान , फरवरी 2002 में ही परिकल्पित और शुरू किए
गए थे। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए , गुजरात सरकार
ने चिरंजीवी योजना शुरू की। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए इसे
एशिया इनोवेटिव अवार्ड मिला। इसके अलावा , गुजरात ने कई
महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं : 1.25 करोड़ छात्रों को आकस्मिक
मृत्यु के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करना
विद्या -दीप योजना।
 1 करोड़ बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ , जिनमें स्वास्थ्य
जांच और उपचार शामिल हैं
गंभीर बीमारियों और चिकित्सा सुविधाओं , जिनमें महंगी सर्जरी भी
शामिल हैं , के बारे में। चिकित्सा , अग्निशमन और पुलिस विभागों
को एकीकृत करके ,
गुजरात व्यापक आपातकालीन व्यवस्था लागू करने में अग्रणी बन गया।
प्रबंधन। आपदा प्रबंधन प्रणालियों के हिस्से के रूप में , यह शुरू
हुआ।
एक कुशल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने की प्रक्रिया समर्थित
अस्पताल सेवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों द्वारा।

आज,
गुजरात का सबसे दूरस्थ गाँव , एक अच्छी तरह से सुसज्जित ,
वातानुकूलित
उचित सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस सेवा
प्रसव सहित आपातकालीन सेवाएं नि :शुल्क उपलब्ध हैं।
आईटी विभाग के माध्यम से इसकी कड़ी निगरानी की जाती है ताकि यह
सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें अधिक समय न लगे।
सबसे दूरस्थ गांवों तक पहुंचने में भी आधे घंटे से भी कम समय लगता
है। यह प्रणाली

अब इसका लक्ष्य प्रतिक्रिया समय को घटाकर 20 मिनट करना है। हर छोटी सी बात
गुजरात में स्कूल जाने वाला बच्चा जानता है कि किसी भी आपात स्थिति में 108 डायल करना चाहिए।
एम्बुलेंस को बुलाना।
सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जुड़ाव
मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर, मोदी ने कच्छ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बाड़बंदी और गश्त की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कदम उठाए।
साथ ही, उन्होंने तटीय क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएँ बनाईं। मैं अपनी अगली पुस्तक में इनमें से कुछ का वर्णन करूँगा। लेकिन ये दौरे केवल "राष्ट्रीय सुरक्षा" के मुद्दों तक ही सीमित नहीं थे - ये पाकिस्तान की सीमा से लगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के कल्याण से भी संबंधित थे, जो इस प्रकार बेहद प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में काम कर रहे थे। मोदी के शब्दों में:
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 87

मुख्यमंत्री के रूप में अपने शुरुआती कुछ हफ्तों में, मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करने गया था।
रक्षा बलों के सदस्यों को, क्योंकि मुझे लगा कि उन्हें यह बताना मेरा कर्तव्य है।
मैं उनकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वहां मौजूद हूं। मेरा मानना है कि भले ही रक्षा कर्मी—सेना, नौसेना या वायु सेना— तैनात हों

मेरे राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी देखभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है।
उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकि राज्य सरकार के साथ उनका अच्छा समन्वय हो सके।
सीमा पर तैनात हमारे जवानों को जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक गंभीर समस्या है।
गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र रेगिस्तानी होने के कारण पानी की कमी है। सीमावर्ती क्षेत्र
सुरक्षा बलों (बीएसएफ) को परिवहन के लिए लगभग 900 ऊंट तैनात करने पड़े।
विभिन्न रक्षा चौकियों को पानी की आपूर्ति। लेकिन, जैसे ही हमने नया जल ग्रिड बनाया,
अगले वर्षों में, हमने नर्मदा के जल की पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति करके एक रास्ता खोज निकाला।
इन सीमा चौकियों तक। उन मुलाकातों के दौरान मुझे पता चला कि उन्हें यह ठीक लगता है।
ताजी सब्जियां मिलना मुश्किल है। सब्जियां लाने का परिवहन खर्च बहुत अधिक है।
सब्जियों की वास्तविक लागत से कहीं अधिक खर्च हो रहा था। इसलिए, हमने बनाया
आसपास सब्जियां उगाने के लिए पानी की नियमित आपूर्ति सहित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
उनकी अपनी सीमा चौकियाँ थीं। उन्हें टेलीफोन तक पहुँचने में भी बड़ी समस्या थी। यदि
उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, वे पाकिस्तानी टावरों से जुड़ गए। हमें नशा हो गया।

गुजरात सीमा पर बिजली के टेलीफोन टावर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे सैनिक उनका उपयोग कर सकें।
अपने परिवारों से जुड़े रहें। पहले, हमारे सैनिक केवल प्राप्त कर सकते थे
पाकिस्तानी टीवी, क्योंकि भारतीय टीवी चैनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंचते। लेकिन हम
उन्हें डिश टीवी उपलब्ध कराए गए।
इसी तरह, जब मोदी को पता चला कि भीषण गर्मी में सेना के जवानों के पास भोजन भंडारण के लिए रेफ्रिजरेटर तक नहीं हैं, तो वे वापस आए और उनके लिए रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की। सैनिकों की जरूरतों का आकलन करने के लिए मोदी का सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा साल दर साल जारी रहा है।
15 अगस्त 2013 को, मैं सीमा चौकियों पर तैनात सैनिकों के साथ उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी था। उन्होंने एक जल आपूर्ति प्रणाली का उद्घाटन किया, जिससे नर्मदा का ताज़ा पानी सबसे दूरस्थ सीमा चौकी तक पहुँचा। इसके अलावा, उन्होंने कच्छ सीमा पर, ब्रिटिश शासन के बाद के भारत में निर्मित सैनिकों के लिए पहले स्मारक का भी उद्घाटन किया। इंडिया गेट पर बना स्मारक अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। भारत सरकार ने चंदवा के नीचे केवल 'अमर जवान ज्योति' लिख दी है। मोदी का कहना है कि उन्हें यह अपर्याप्त लगा, क्योंकि उनके विचार में, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वालों को बेहतर सम्मान मिलना चाहिए।
मोदी के कार्यकाल के पहले कुछ हफ्तों के भीतर ही, तटीय क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए उपाय किए गए, जिनमें तटरक्षक बल के साथ संयुक्त गश्त भी शामिल है। 88 मोदी, मुसलमान और मीडिया

विकास के पाँच अमृत
नमो ने अपनी शुरुआती घोषणाओं में से एक में कहा था कि उनके विकास एजेंडा का मार्गदर्शक सिद्धांत पंचामृत योजना या 'विकास के पांच अमृत' होंगे। इन्हें जल शक्ति, जन शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति और रक्षा शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था।
जल शक्ति में जल संसाधनों का विकास और संरक्षण शामिल है। गुजरात का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी क्षेत्र में आता है, इसलिए मोदी को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जहां हमेशा जल संकट बना रहता है। उन्होंने घोषणा की थी कि नर्मदा परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पहले 18 हफ्तों में, उन्होंने इसकी प्रगति की समीक्षा करने और इसे गति देने तथा पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नौ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। कांग्रेस पार्टी समर्थित मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा किए गए दृढ़ अवरोधों के बावजूद, मोदी ने नर्मदा परियोजना को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है।
लेकिन जल सुरक्षा को एक जन आंदोलन के रूप में उठाया गया। मोदी के सत्ता में आने के पहले तीन महीनों के भीतर ही जल संसाधनों और स्वच्छता के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए WASMO (जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन) नामक एक विशेष प्रयोजन संगठन का गठन किया गया—यह सशक्त जल समितियों के गठन के माध्यम से किया गया। आज, रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घर पर पाइप से पानी की आपूर्ति मिल रही है, जबकि गुजरात 100 प्रतिशत कवरेज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी ने किस प्रकार ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल दोहन पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए—एक ऐसी प्रथा जिसने जल स्तर को खतरनाक स्तर तक नीचे कर दिया था—इसकी विस्तृत कहानी मेरी अगली पुस्तक में बताई जाएगी। लेकिन मोदी द्वारा पहले कुछ हफ्तों में उठाए गए कदमों ने

स्थायी बदलावों की नींव रखी। जल संचयन, जिसे मोदी के कार्यकाल के पहले कुछ महीनों में एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, के परिणामस्वरूप लाखों खेत तालाबों और चेक डैमों का निर्माण हुआ है। परिणामस्वरूप, गुजरात उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ वर्षा की कमी वाले क्षेत्र होने के बावजूद भूजल स्तर बढ़ रहा है। 2011 तक, राज्यव्यापी भूजल स्तर में औसत वृद्धि 3.62 मीटर थी।
यह प्रयोग जल संसाधनों की कमी वाले देशों के लिए एक वैश्विक आदर्श बन गया है। पेयजल आपूर्ति प्रबंधन की सहभागी प्रणाली को 2009 में संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार मिला।
जनशक्ति (मानव संसाधनों और समाज की आंतरिक शक्ति को संगठित करना): मोदी की कार्यशैली पर सरसरी नजर डालने से ही पता चलता है कि वे हर चीज को, चाहे वह स्कूल नामांकन कार्यक्रम हो या जल नीति सुधार, एक जन आंदोलन में बदल देते हैं, जो इस दृढ़ विश्वास से उपजा है कि बिना जनशक्ति के
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 89

प्रजाशक्ति या जनशक्ति (नागरिकों की शक्ति) के बिना राजशक्ति वैधता प्राप्त नहीं कर सकती और न ही प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर आधारित अध्याय छह और सात इस दर्शन को व्यवहार में दर्शाते हैं। इसी का एक परिणाम 'गरवी गुजरात अभियान' था, जिसका उद्देश्य गुजरात की विरासत, संस्कृति, खान-पान और शिल्पकला को प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देना था। योजना गुजरात को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना था, जहाँ पहले इसकी उपस्थिति लगभग न के बराबर थी। बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'गरबा महोत्सव' को पुनर्जीवित किया गया, क्रूज सेवाएं शुरू की गईं और साहसिक एवं पर्यावरण पर्यटन को प्राथमिकता दी गई। सोमनाथ और द्वारका को

[illegible]

[illegible] (Закон об охране и использовании недр):

- в 2001 году [illegible] 11 [illegible] из 44 [illegible]

मुस्लिम महिलाओं सहित महिलाओं में शिक्षा का प्रसार इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि परिवारों
अगर वे लड़कियों को मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में भेजने के लिए कहीं अधिक इच्छुक हों तो
इसमें उन्हें घर से दूर स्थानों पर भेजना शामिल नहीं है। उच्चतर गुजरात में निजी संस्थानों में भी शिक्षा कहीं अधिक सस्ती है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में, जहाँ भारी मात्रा में धन की मांग की जाती है, यहाँ ऐसा नहीं है।
सीटों की कमी के कारण प्रति व्यक्ति शुल्क में वृद्धि हुई है। ऊर्जा शक्ति (ऊर्जा का दोहन और संरक्षण): इसी के फलस्वरूप ज्योति ग्राम योजना शुरू हुई, जिसके तहत हर गांव और हर घर में (शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, यहां तक कि दूरदराज के आदिवासी इलाकों में भी) चौबीसों घंटे सातों दिन तीन फेज की बिजली आपूर्ति होती है। इस उपाय के साथ-साथ पानी की बेहतर उपलब्धता ने गुजरात के गांवों और छोटे कस्बों को लघु उद्योग के केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों को कृषि कार्यों के लिए प्रतिदिन निश्चित घंटों के लिए अलग लाइनों के माध्यम से सुनिश्चित बिजली मिलती है। गुजरात न केवल बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली अधिशेष वाले राज्य में परिवर्तित हुआ है, बल्कि पवन, बायोमास और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी अग्रणी बन गया है। यह कैसे हुआ और इससे जो परिवर्तन आया है, उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है।
रक्षा शक्ति: इसका व्यापक अर्थ है बीमारी, आपदाओं, असामाजिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से सुरक्षा। इसमें हर गांव और कस्बे में निवारक और चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, सुसज्जित अस्पताल, प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली और असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए मजबूत कानून

[illegible] [illegible] [illegible] [

500 करोड़ रुपये (102 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश। रॉयल डच
शेल कंपनी ने 5,000 रुपये के निवेश की घोषणा की।
हाजिरा बंदरगाह और एलएनजी टर्मिनल में करोड़ों (1 अरब अमेरिकी
डॉलर) का निवेश किया गया है। बिरला कॉपर की एक इकाई , इंडो गल्फ
कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रक्रिया शुरू की।
भरूच में विश्व स्तरीय तांबा गलाने का संयंत्र स्थापित करने के
संबंध में। देश में एक व्यापक नीति , स्थापना के संबंध में
विशेष आर्थिक क्षेत्रों की घोषणा की गई।
 एक उच्चशक्तिशाली गुजरात औद्योगिक संवर्धन बोर्ड (जीआईपीबी) के
नेतृत्व में
मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित प्रक्रिया और एकल -खिड़की सुविधा
प्रदान करने के लिए गठित किया गया था।
बड़ी औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी।
 मेसर्स केयर्न के बीच गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए समझौते पर
हस्ताक्षर किए गए
ऊर्जा (CEIL) और गुजरात समुद्री बोर्ड (3.4 मिलियन घन मीटर)
गैस का उत्पादन और वितरण 10 लाख डॉलर से अधिक के निवेश के साथ किया
जाएगा।
(600 करोड़ रुपये)।
 पुनरुत्थानशील गुजरात मेगा इवेंट का आयोजन फरवरी 2002 में किया
गया था।
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
देने के लिए
इस क्षेत्र की जलवायु।
सहकारी समितियों के लिए नीति और नियमों में प्रमुख सुधार किए गए।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और उनके कामकाज को और अधिक सुचारू
बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पारदर्शिता बनाए रखें और अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रणों को हटा दें। मीडिया में नई पहलों की रिपोर्ट इसी प्रकार प्रकाशित हुई। टाइम्स न्यूज़ सर्विस ने 11 फरवरी, 2002 को प्रकाशित किया: "संभावित निवेशक फिर से संपर्क कर रहे हैं।" आगे इसमें कहा गया है: जब अर्थव्यवस्था कमजोर और भविष्य अंधकारमय दिखाई दे तो क्या होता है?
सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तत्काल उपाय किए हैं। मोदी सरकार अपने तीन दिवसीय अभियान में ठीक यही लक्ष्य हासिल करना चाहती है।
पुनर्जीवित गुजरात कार्यक्रम। और यूनाइटेड किंगडम के 92 वें राष्ट्रपति बनने के साथ, मोदी, मुसलमान और मीडिया

शीर्ष कॉरपोरेट कंपनियों के साथ 'साझेदार देश' के रूप में, राज्य को उम्मीद हो सकती है कि...
कुछ सकारात्मक संभावनाएं हैं। विदेशी (मुख्य रूप से यूके) प्रतिनिधिमंडलों के अलावा,
कई ऐसे अनिवासी गुजराती (एनआरजी) और एनआरआई थे जिन्होंने पाया कि पूरा अनुभव बेहद रोमांचक रहा…पुनरुत्थान गुजरात - व्यापार साझेदारी बैठक-2002 का आयोजन औद्योगिक विस्तार ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
गुजरात सरकार, विदेश मंत्रालय, सरकार
भारत, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल हो गया था।
एक साझेदार देश के रूप में।
प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या।

भारत भर के विभिन्न उद्योगों के लोग, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल, प्रमुख व्यवसायी और उद्योगपति
भारत ने उस आयोजन में भाग लिया। पुनरुत्थानशील गुजरात - व्यावसायिक साझेदारी
यह बैठक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स की नींव साबित हुई।
अब तक आयोजित पांच द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनों ने गुजरात को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है, जो भारत के अन्य राज्यों के मुसलमानों सहित, रहने और व्यापार करने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है। सूखे और भूकंप से तबाह गुजरात में हो रहे तीव्र परिवर्तन का अंदाजा 5 फरवरी, 2002 को प्रकाशित टाइम्स न्यूज नेटवर्क की निम्नलिखित रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है:
कंपनियां कच्छ की ओर रुख कर रही हैं: गुजरात कच्छ में वही कर रहा है जो वह खुद कर रहा है।
यह सबसे अच्छा काम करता है—औद्योगीकरण के माध्यम से अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजने का।
और धन सृजन। आधिकारिक हलकों में यह भावना प्रबल है कि
भूकंप से कच्छ का पुनर्निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका उद्योग में नए निवेश करना है।
मलबे के बीच, सरकार के लिए यह जानकर खुशी हुई है कि 34 निवेशकों ने पहले ही निवेश कर दिया है।
768.87 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया गया, जो कि किए गए निवेश से अधिक है।
जिले में पिछले 50 वर्षों में जो हुआ है, वह बहुत तीव्र है। और यह तो बस एक तीव्र बदलाव की शुरुआत हो सकती है।

कच्छ में औद्योगीकरण की प्रक्रिया बिक्री कर और उत्पाद शुल्क के सहारे आगे बढ़ रही है।
राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। सूत्रों के अनुसार निवेश
आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में यह आंकड़ा 3,000 रुपये तक पहुंच सकता है या इससे भी अधिक हो सकता है।
करोड़ों का आंकड़ा। कॉर्पोरेट जगत के बड़े नाम जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
पांच साल की टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए। लगभग 300 पूछताछों में से
अब तक किए गए प्रयासों में से 13 ने अपने ज्ञापन दाखिल किए हैं, दस ने भूमि अधिग्रहण किया है और आठ ने भूमि अधिग्रहण किया है।
वे ऐसी कंपनियां हैं जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हैं। 2,000 रुपये का निवेश।
करोड़ों रुपये रिलायंस, एलजी और एक्सेल जैसे जाने-माने घरानों से आएंगे, जबकि
बाकी कार्य छोटे और मध्यम स्तर पर होंगे।
मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 93

भूकंप प्रभावित जिले का औद्योगिक विकास प्रमुख केंद्रबिंदु होगा।
उद्योग एवं खान विभाग के प्रधान सचिव का कहना है कि गुजरात पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है।
आई. मानसिंह. गुजरात सरकार के प्रधान औद्योगिक सलाहकार आर.जे. कच्छ में निवेश का समन्वय कर रहे शाह कहते हैं, 'हमने मंजूरी दे दी है।'

शासित राज्यों में ये नीतियां घोटालों और देरी से घिरी हुई हैं। इसके विपरीत, गुजरात में मोदी के विकास मॉडल को लेकर अपेक्षाकृत कम विवाद हैं। यही कारण है कि कांग्रेस गुजरात में मोदी के आर्थिक एजेंडे के खिलाफ पर्याप्त विरोध जुटाने में सफल नहीं हो पाई है। प्रमुख निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई
मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए और उन्हें शीघ्रता से लागू किया गया:
पारदर्शी और कुशल प्रशासन के लिए ई-गवर्नेंस: सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर, मोदी ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक जिले के प्रशासन की समीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से राज्य के प्रत्येक जिले का दौरा किया। सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के नए विभाग 1994 अक्टूबर को स्थापित किए गए। मोदी, मुस्लिम और मीडिया

27, 2001 को, सुगम और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया शुरू की गई। गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (जीएसडब्ल्यूएएन), जो विश्व का सबसे बड़ा आईपी-आधारित ई-गवर्नेंस नेटवर्क है, राज्य के 25 जिलों को सचिवालय और गांधीनगर से जोड़ता है और 225 तालुकों को इन जिलों से जोड़ता है, को परिचालन में लाया गया। सैटेलाइट संचार स्थापित किए गए, जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग संभव हुआ।
पारदर्शिता लाने और मनमानी ठेकों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी ठेकों की खरीद हेतु निविदाओं को ऑनलाइन प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद, गुजरात ने भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति या नए स्कूल खोलने की अनुमति जैसे विभिन्न क्षेत्रों

में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की, जो अन्य राज्यों में केवल रिश्वत और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से ही संभव हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का पुनर्गठन: मोदी ने ग्रामीण आबादी और शहरी गरीबों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी विभागों की व्यापक समीक्षा बैठकें कीं। इस प्रयास से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुव्यवस्थित करने, भ्रष्टाचार को रोकने और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करने में मदद मिली।
जन सेवा केंद्र: सभी सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण शुरू हुआ और ई-गवर्नेंस की नींव रखी गई। शुरू की गई प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप जन सेवा केंद्रों (लोक सेवा केंद्रों) का तेजी से निर्माण हुआ, जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, भूमि पंजीकरण से लेकर होटल लाइसेंस आदि लगभग 72 सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं, ताकि नागरिकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय न भटकना पड़े। इन उपायों से भारत में आम नागरिकों को लाइसेंस या सेवाएं प्रदान करने वाले छोटे अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन झेलनी पड़ने वाली उत्पीड़न और जबरन वसूली की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई।
टेली फरियाद: एक शिकायत पंजीकरण प्रणाली को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया, जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों के लोग टेलीफोन के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे।
शिकायत निवारण तंत्र: स्वागत (स्वागत) नामक एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई, जिसके तहत निर्धारित दिनों और समय पर मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित नागरिकों की शिकायतें सुनते थे। यह प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक सुव्यवस्थित ई-गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाती थी। यह उल्लेखनीय है कि मोदी ने इंदिरा गांधी द्वारा आयोजित किए जाने

वाले भव्य जनता दरबार या लालू यादव और नीतीश कुमार द्वारा लोकप्रिय किए गए सामंती तमाशों का विकल्प नहीं चुना। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 95

स्वागत प्रणाली की शुरुआत तालुका और जिला स्तर पर शिकायत निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुव्यवस्थित तंत्र से हुई। यदि किसी व्यक्ति को इन स्तरों पर न्याय नहीं मिलता, तो वे मुख्यमंत्री के स्वागत पोर्टल पर लिख सकते हैं। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। यदि मामला सुलझ नहीं पाता, तो मुख्यमंत्री टेली-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी दोनों की बात सुनते हैं। अक्सर, मौके पर ही निर्णय लिए जाते हैं या समस्या के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसमें उन पुराने नियमों में बदलाव या संशोधन शामिल हो सकते हैं जो किसी अधिकारी को शिकायत निवारण में बाधा डालते हैं। लोग बताते हैं कि जब नागरिकों को कभी-कभार अभद्र अधिकारियों का सामना करना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री के स्वागत पोर्टल का उपयोग करने की बात कहने मात्र से ही मामला आगे बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री की भागीदारी अनियमित नहीं है; यह वर्षों से निरंतर और सुव्यवस्थित रही है। इसलिए, यह प्रणाली छोटी-मोटी शिकायतों से भरी नहीं है। यह खुली और पारदर्शी है, और कुछ चुनिंदा अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर दूसरों को डराने से बचती है। साथ ही, यह ईमानदार अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से भी बचाता है। इस प्रणाली को 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला था।
आर्थिक अपराधों से निपटने के उपाय: संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (जीयूजेसीओसी) को और अधिक सख्ती और गंभीरता से लागू किया जाने लगा। आम निवेशकों के

हितों की सुरक्षा के लिए गुजरात जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अध्यादेशों के माध्यम से सहकारी समितियों के कामकाज में गुणात्मक और प्रशासनिक परिवर्तन लाए गए।
आपदा निवारण योजना: 12 फरवरी, 2002 को गुजरात सरकार ने अगले दो वर्षों में एक व्यापक आपदा निवारण योजना के कार्यान्वयन हेतु 350 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया। तब से, राज्य सरकार ने न केवल सभी स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम शामिल किए हैं, बल्कि भूकंप, आग, दुर्घटनाओं और बाढ़ जैसी विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए एक सक्षम आपदा प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की है। इसने इस क्षेत्र में नए ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने और विकसित करने के लिए नए संस्थान भी स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ पर कच्छ में भूकंप पुनर्वास संबंधी अध्यायों में चर्चा की जाएगी।
भूमि हड़पने वालों के खिलाफ PASA: 7 नवंबर, 2001 को सरकार ने घोषणा की कि वह व्यावसायिक उद्देश्यों और उद्योगों के संचालन के लिए अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (PASA) लागू करेगी। यह उल्लेखनीय है कि इसमें गरीब झुग्गीवासियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों का कोई उल्लेख नहीं है। जिला कलेक्टर 96 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

दिसंबर तक चेतावनी का पालन न करने पर भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था। यह घोषणा की गई कि यदि राजनेता भी भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, तो उन्हें भी कानून के शिकंजे से नहीं बख्शा जाएगा।
तब तक PASA का इस्तेमाल ज़मीन हड़पने वालों के खिलाफ़ बहुत कम किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों को संरक्षण से वंचित कर दिया गया। इससे

स्वाभाविक रूप से मोदी अपने ही दल के सहयोगियों सहित कुछ खास तरह के राजनेताओं के बीच अलोकप्रिय हो गए।
मोदी के विकास एजेंडे पर मीडिया की चुप्पी: मैंने ऊपर नरेंद्र मोदी द्वारा गोधरा हिंसा से महज 19 सप्ताह पहले शुरू किए गए कई शासन सुधार उपायों और विकास कार्यक्रमों की संक्षिप्त झलकियाँ दी हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य समावेशी विकास है। ऐसे सभी कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने वाला मुख्यमंत्री अपने राज्य में दंगे होने की संभावना सबसे कम ही रखेगा।
मोदी के नारे, 'सबका साथ, सबका विकास' के परिणाम ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे थे। उदाहरण के लिए, जब हर गाँव के घर में 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम गाँव या घर इससे वंचित रह गए हों। यदि कन्या केलवानी और शाला उत्सव कार्यक्रमों का उद्देश्य 100 प्रतिशत बच्चों का स्कूल में नामांकन और स्कूल में बने रहना है, यदि मुफ्त वर्दी, स्कूल की किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रत्येक स्कूली बच्चे के लिए हैं, तो मुस्लिम बच्चों को पीछे छोड़ना संभव नहीं है। यदि आंगनवाड़ियाँ सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती हैं, तो मुस्लिम बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं रह सकते। चूंकि ऐसे प्रत्येक विकास कार्यक्रम में 100 प्रतिशत कवरेज की प्रतिबद्धता है, इसलिए इसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कोटा की राजनीति है जिसमें भेदभाव अंतर्निहित है। शुरुआत से ही, मोदी का प्रयास उन कमियों को दूर करना रहा है जो कोटा की राजनीति और कमजोर समूहों के हाशिए पर धकेलने का कारण बनती हैं।
कांग्रेस पार्टी में दहशत फैल गई क्योंकि मोदी ने कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की उस नकारात्मक छवि को गलत साबित करने से इनकार कर दिया, जो मुसलमानों या ईसाइयों पर आग बरसाता था। वे न तो उग्र राष्ट्रवाद की भाषा बोल रहे थे और न ही किसी जाति या समुदाय

के वोट बैंक को लामबंद कर रहे थे। पारदर्शिता लाने के उनके तरीके ने उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या अक्षमता का आरोप लगाना मुश्किल बना दिया। दरअसल, मोदी के विकास एजेंडे ने गुजरात की राजनीति को ध्रुवीकरण से मुक्त कर दिया था। अपने हर भाषण में, अपने हर कार्यक्रम में, उन्होंने धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना गुजरात के सभी पांच करोड़ लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह 97

इसके बावजूद, राष्ट्रीय मीडिया के सभी माध्यमों, चाहे प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन, ने कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थन में अपनी सेवाएं दीं ताकि गैर सरकारी संगठनों द्वारा मोदी के खिलाफ फैलाई गई गलत सूचनाओं की सुनामी लाई जा सके और उन्हें नफरत का पात्र बनाया जा सके। भाजपा समेत किसी ने भी मोदी का खुलकर बचाव करने की हिम्मत नहीं की। उनके सभी अच्छे कार्यों को उनके द्वारा गढ़े गए झूठ के ढेर के नीचे दबा दिया गया। कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुजरात में कृषि क्षेत्र के विकास पर शोध और लेखन करने वाले अशोक गुलाटी जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर, शिक्षाविदों में से बहुत कम, या शायद ही किसी ने, गुजरात में शोध करने की जहमत उठाई। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के भी इस दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा बनने के कारण, युवा विद्वान भी राज्य से दूर रहे, जबकि राज्य में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे थे। इसी तरह अल्पसंख्यकों के बचाव के बहाने गैर सरकारी संगठनों द्वारा बुना गया धोखे का जाल न केवल प्रमुख बल्कि मोदी और 2002 के दंगों पर एकमात्र स्वीकार्य कथा बन गया।

अध्याय 6

आपदा को अवसर में बदलना
भूकंप से तबाह गुजरात का कायापलट

पूरा कच्छ गहरे शोक में डूबा हुआ था। सबकी आँखों में आँसू थे। हमारे 150 घरों वाले छोटे से गाँव में 35 लोगों की मौत हो गई थी। मोदी जी से पहले, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई मंत्री हमारे आँसू पोंछने आया था। हमारा पूरा गाँव मलबे से ढका हुआ था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ढह चुके घरों के मलबे पर से होकर गुजरना पड़ता था। राहत कार्य के पहले कुछ हफ्तों के बाद, सबने हमें छोड़ दिया था... तीन साल के भीतर मोदी ने कच्छ का जीर्णोद्धार कर दिया। हमारे घर को ही देख लीजिए—इसमें दो हवादार, अच्छी तरह से बने कमरे हैं, एक रसोईघर, स्नानघर और एक बड़ा आँगन है। यह भूकंपरोधी घर है। पार्वतीबेन, ट्राम्बो गाँव, कच्छ।

कभी उपेक्षित रहे कच्छ में नई समृद्धि के सबसे पुख्ता संकेतों में से एक है जमीन की कीमतों में आसमान छूती हुई बढ़ोतरी। पार्वतीबेन ने जो जमीन 30 साल पहले महज 500 रुपये में खरीदी थी, आज उसकी कीमत 30 लाख रुपये प्रति एकड़ है।
26 जनवरी 2001 को जब गुजरात में भूकंप आया, तब मोदी न तो गुजरात में रहते थे और न ही वहां के मुख्यमंत्री थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 थी और यह पिछले 180 वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंपों में से एक था—लातूर, कोबे या मैक्सिको में आए भूकंपों से भी कहीं अधिक विनाशकारी। इसका केंद्र भुज से 30 किलोमीटर दूर चोबारी गांव के पास था। भूकंप की लहरों ने एक ही झटके में व्यापक तबाही मचा दी, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें, चोटें और विनाश हुआ।

मोदी की पहली प्रतिक्रिया अपनी मां को फोन करना थी, जो वे शायद ही कभी करते थे। उनकी मां ने उन्हें बताया कि वड़नगर में उनका कच्चा मिट्टी का घर भी भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। एक साक्षात्कार के दौरान, मोदी ने बताया कि कैसे केशूभाई द्वारा राजनीतिक रूप से राज्य से बहिष्कृत किए जाने के बावजूद, भूकंप के बारे में सुनकर वे गुजरात जाने से खुद को रोक नहीं पाए।
भूकंप की खबर ने मुझे बहुत गहराई से झकझोर दिया। इसलिए, मैंने अपनी पहल पर,
मैं तुरंत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो गया। अटल जी वहीं थे।
आपदा को अवसर में बदलना 99

उस समय दिल्ली में 26 जनवरी की परेड चल रही थी। परेड खत्म होते ही, उसने
मुझे फोन आया और पूछा कि क्या मुझे भूकंप के बारे में कोई खबर है। मैंने कहा कि मुझे बस इतना ही पता है...
मेरी माँ ने गाँव से फोन पर मुझे जो बताया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं
मुझे गुजरात के लिए रवाना होना चाहिए। वह सहमत हो गए और कहा कि मुझे जाना चाहिए। आडवाणी जी
मैं भी गुजरात जा रहा था। इसलिए मैं उनके साथ उनके विमान में सवार होकर सीधे उनके लिए रवाना हो गया।
कच्छ के लिए।
उस समय केशूभाई के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। मेरी यात्रा गुजरात की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इतनी सारी मौतों की खबरें सुनकर...

इतनी तबाही थी कि मैं लोगों से संपर्क करने से खुद को रोक नहीं पाई।
प्रभावित क्षेत्र।
मैं लगभग एक महीने तक कच्छ के गांवों में रहा और मैंने जो भी थोड़ा-बहुत किया, वह किया।
मैं अपने दम पर कर सकता था। उदाहरण के लिए, मैंने देखा कि बहुत से लोगों को गंभीर समस्याएँ थीं।
चोटें आईं। बहुत ठंड भी थी। मैंने लोगों को एक सरल सुझाव दिया कि रात में
उन्हें आसपास पड़े बेकार पदार्थों का उपयोग करके कुछ पानी गर्म करना चाहिए और उसे भर देना चाहिए।
इसे खाली बिसलेरी की बोतलों में भरें। जब आप गर्म पानी की बोतल को अपने कंबल में रखें तो उसे कंबल में रख दें।
सोने की तैयारी करें। इससे आपकी चोटों को आराम मिलेगा और आपको नींद भी आएगी।
आपको गर्मी लगती है। यह बात सचमुच लोकप्रिय हो गई, और पूरे क्षेत्र में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे।
इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उनके घर ढह गए थे। वे खुले में सो रहे थे।
जिनके घर अभी भी खड़े थे, वे भी घर के अंदर सोने की हिम्मत नहीं करते थे।
लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के कारण।
मैंने यह भी देखा कि वहां कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे। यह तब की बात है जब हजारों लोग
कई लोगों की हड्डियां टूट गई थीं। इसलिए, मैंने सरकारी टीमों को सलाह दी जो इस पर काम कर रही थीं।

एनसीसी के सभी छात्रों को प्राथमिक फिजियोथेरेपी सिखाने के लिए राहत प्रदान की गई। उन्होंने इसे लागू किया।
इस सुझाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। बुनियादी उपचार के बाद, चोटिल व्यक्ति
कुछ बुनियादी अभ्यासों का अभ्यास करने की आवश्यकता थी, जिन्हें आसानी से किया जा सकता था।
मैंने जिन नए शौकिया फिजियोथेरेपिस्टों को प्रशिक्षित करने में मदद की, उनकी मदद से मुझे यह सब सीखने को मिला।
7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास और तबाह क्षेत्रों का पुनर्निर्माण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वे कहते हैं, “मुझे इस बात का गहरा नैतिक बोझ महसूस हुआ कि लोगों के पास अभी भी घर नहीं थे। वे फुटपाथों पर या खेतों में रह रहे थे। सर्दी आ रही थी और कच्छ में सर्दियाँ बहुत भीषण होती हैं। लोग क्या करेंगे? यह चिंता मुझे सता रही थी। इसलिए मैंने तबाह क्षेत्रों में नई जान फूंकने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया।”
जो कोई भी मोदी के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, उसे यह अध्ययन करना होगा कि उन्होंने भूकंप प्रभावित लोगों से किए गए अपने वादे को अक्षरशः और भावपूर्वक कैसे निभाया। कच्छ और अन्य सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 100 मोदी, मुसलमान और मीडिया

गुजरात के सबसे पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में से एक, कच्छ, संकटग्रस्त पलायन, जल संकट और दीर्घकालिक सूखे के लिए जाना जाता है। मोदी ने इन उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रों को जीवंत औद्योगिक केंद्रों में बदल दिया और साथ ही कृषि क्षेत्र में भी तेजी से विकास किया। कच्छ, मोदी के जन-केंद्रित विकास मॉडल और जनता के

[illegible] [illegible] [illegible] [

बुनियादी ढांचा बदहाल था। सड़कें, रेलवे ट्रैक, पानी और बिजली सब ठप थे।
आपूर्ति नेटवर्क ध्वस्त हो गए थे। कुल 592 सार्वजनिक भवन प्रभावित हुए थे।
पूरी तरह से नष्ट हो गया; 8,131 इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। गुजरात सरकार और विश्व समुदाय ने तत्काल राहत सामग्री और बचाव दल भेजने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय राहत दल के चले जाने के बाद, सरकार ने पुनर्वास के मोर्चे पर बेहद खराब प्रदर्शन किया। केशूभाई ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) की स्थापना की थी, जो भूकंप से उबरने के व्यापक कार्यक्रम के समन्वय और पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन पहलों के संचालन के लिए समर्पित एक एजेंसी थी। लेकिन वे इसे अपने वादे के अनुरूप पूरा नहीं कर सके।
अहमदाबाद के रहने वाले मुस्लिम टैक्सी सेवा मालिक और राजनीति के बहुत ही तीक्ष्ण विश्लेषक राजुभाई ने 2013 में कच्छ की मेरी एक यात्रा के दौरान मुझसे यह बात कही थी, जब हम उस क्षेत्र के गांवों से गुजर रहे थे:
आपदा को अवसर में बदलने का पहला सबक

भूकंप के बाद मैंने कच्छ की कई यात्राएँ कीं क्योंकि मैं अक्सर अपने साथ कुछ सामान ले जाता था।
मेरी टैक्सी में पत्रकार, एनजीओ कार्यकर्ता आदि बैठे थे। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई।
केशूभाई और उनके मंत्रियों ने किस प्रकार खुलेआम लूटपाट की और यहाँ तक कि चोरी भी कर ली।
भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री आई थी। यहां तक कि संग्रहकर्ताओं ने भी।

उस समय राहत सामग्री के वितरण में काफी पक्षपात किया गया था।
उदाहरण के लिए, एक दिन मैं व्यापारियों के एक संघ के साथ मालिया गांव गया था।
उन्हें राहत सामग्री के वितरण के लिए देवड़िया गांव सौंपा गया था।
वे अपने साथ लाए थे। ठीक हमारे सामने, मालिया में, एक बड़ा कोल्ड-चेन
विदेशी चॉकलेट और अन्य कई खाद्य पदार्थों से भरा एक कंटेनर आया। राहत सामग्री के रूप में लाई गई सामग्री जिला कलेक्टर के पास गई, जिन्होंने बदले में उसे आवंटित किया।
किसी अधिकारी को उस गांव का नाम बताना था जहां उन खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाना था।
जो लोग चोरी करने के इच्छुक थे, उन्होंने कलेक्टर के कार्यालय में ही ऐसा किया।
उस खास दिन, विदेशी खाद्य पदार्थों से भरे इस बड़े कंटेनर के तुरंत बाद
केशूभाई अपनी सिएलो कार में पूरे दल के साथ मालिया पहुंचे। वाहनों का काफिला। उसने कंटेनर के अंदर रखी सामग्री के बारे में पूछताछ की। जब
जब उसे पता चला कि इसमें विदेशी चॉकलेट और अन्य ऐसी ही स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं, तो उसने ऑर्डर कर दिया।
अधिकारियों को बक्से निकालकर उसकी कार में रखने को कहा गया। बिल्कुल हमारे सामने।
उसने अपनी सिएलो कार में विदेशी चॉकलेट के जितने कार्टन भर सकता था, उतने भर लिए और
गाड़ी गांधीनगर की ओर चली गई। लोग इस सब की बेशर्मी देखकर स्तब्ध रह गए।

कलेक्टर कार्यालय में पहरा दे रहे पुलिस कांस्टेबल ने टिप्पणी की,
"ये राजनेता सोचते हैं कि जो कुछ भी होता है उस पर पहला अधिकार उन्हीं का है।"
मैंने यह भी देखा कि रनपुर के मूल निवासी सांसद रतिलाल वर्मा ने कैसे बाजी मारी।
भूकंप के लिए पाकिस्तान से आए हरे रंग के आकर्षक तंबू
राहत मिली। उन्हें ये तंबू इतने पसंद आए कि उन्होंने जाकर अपने घर पर भी ऐसा ही एक तंबू लगा दिया।
लोगों को दिखाने के लिए पेट्रोल पंप पर। यह शर्मनाक तस्वीर भी कुछ समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी। उस समय पड़ोसी राज्यों के भिखारी भीख मांगते थे।
भूकंप पीड़ितों के लिए आई राहत सामग्री को इकट्ठा करने के लिए वे कच्छ भी पहुंचे।
पीड़ित तो थे ही। लेकिन सबसे बेशर्म भीख मांगने वाले हमारे ही कुछ राजनेता थे।
उन्होंने सचमुच बेशर्मी से लूटपाट की। कई अच्छे गैर सरकारी संगठन भी आए थे और
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनमें से कुछ के साथ यात्रा भी की। उनमें से कुछ
जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उनमें सिख गुरुद्वारे, मुरारी बापू का एनजीओ और शामिल थे।
organisation of Dangre ji Maharaj.
उतना ही महत्वपूर्ण यह था कि आम तौर पर गुजराती लोग और विदेशों में बसे कच्छ के लोग प्रभावित क्षेत्र के तबाह परिवारों की मदद के लिए भरपूर आगे आए थे। भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आर.के. समा, जिन्होंने गैर सरकारी संगठनों के साथ राहत कार्य में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस घटना का एक अंतर्दृष्टिपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं:
102 मोदी, मुसलमान और मीडिया

कच्छियों में कुछ खास बात होती है; यहां तक कि जो लोग दूसरे देशों में चले गए हैं, उनमें भी यही बात है।
कच्छ के निवासी तीन पीढ़ियों से अपनी मातृभूमि से बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं और
उनके गांवों में। एक कच्छी चाहे कितना भी धनी और अच्छी तरह से बसा हुआ क्यों न हो,
चाहे वह सुदूर अमेरिका हो या यूरोप, वह हमेशा अपने पैतृक घर में एक घर बनाए रखेगा।
गांव में रहें और कच्छ की घटनाओं से जुड़े रहें। वे सिर्फ गांव ही नहीं हैं।
वे बातें करने में माहिर होते हैं, लेकिन काम करने में बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूँ। एक बहुत ही
ओमान में स्थित धनी कच्छी व्यापारी घराने, खिमजी एंड संस, के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं।
दुबई और ओमान के सबसे अमीर व्यक्ति। वह अपने निजी विमान से यात्रा करते थे। चूंकि मैं एनजीओ
राहत सामग्री की सूची तैयार करने का काम कर रहा था जो प्राप्त हो रही थी।
जो कुछ आवश्यक था, उसके साथ-साथ उन्होंने हमसे आवश्यक वस्तुओं की सूची भी मांगी।
तुरंत। हमने जल्दी से उन चीजों की सूची तैयार कर ली जो हमें आवश्यक लगीं।

अन्य फोन लाइनें बंद थीं लेकिन उनके पास एक सैटेलाइट फोन था। चार के भीतर
कुछ घंटों बाद उन्होंने हमें बताया कि हमने जो मांगा था वह पहले ही दुबई से निकल चुका था, और यह कि
अगली सुबह जहाज कांडला बंदरगाह पर उतरेगा। हमें ध्यान रखने के लिए कहा गया था।
सीमा शुल्क निकासी। कुछ हफ़्ते बाद जब हमने मूल्य का आकलन किया उन्होंने हमें जो राहत सामग्री भेजी थी, उससे हमें पता चला कि उसकी कुल कीमत 85 करोड़ रुपये थी।
खरीददारी और डिलीवरी चार घंटे के भीतर हो गई। उस दिन मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी।
सबक: जो व्यक्ति दान नहीं कर सकता, उसे धनी नहीं माना जा सकता। दान करने की आदत
इसे समय के साथ लगातार विकसित करना पड़ता है, और यही वह चीज है जिसे कुच्ची परिवार करता है।
प्रचुर मात्रा में। जब मैंने अपनी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त किया
खिमजी की उदारता के लिए उन्होंने उत्तर दिया: “कृपया मुझे शर्मिंदा न करें। कोई समस्या नहीं है।”
इसमें धन्यवाद देने का स्थान है। दरअसल, मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
आप मुझे बताइए कि और क्या चाहिए। आपको जो भी चाहिए, मैं भेजने के लिए तैयार हूं।
एक और घटना है, जो कुच्ची चरित्र के बारे में बहुत कुछ उजागर करती है।
एक दिन हमने 4,000 खाने के पैकेट तैयार किए और उन्हें जवाहर नगर ले गए, जो कि

सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में। जब हमने इसे बांटने की कोशिश की, तो वहां के लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “हमें हमारा हिस्सा मिल गया है। कृपया अगले गाँव जाइए क्योंकि वहाँ
उन्हें अपना हिस्सा नहीं मिला है।" नागरिकों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना
दरअसल, सरकारी प्रयासों की तुलना में इसका कहीं अधिक महत्व है। कई अंतरराष्ट्रीय
राहत कार्य के लिए एजेंसियां भी आईं और हम गैर सरकारी संगठनों ने भी इसमें अच्छा काम किया।
एक संयुक्त मंच बनाकर समन्वित तरीके से। फिर भी, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर
जहां योग्य अधिकारियों ने व्यक्तिगत पहल की, वहां सरकार के पुनर्वास कार्य में तेजी आई।
केशूभाई के नेतृत्व में स्थिति अराजक, अस्थिर और अव्यवस्थित थी। मोदी के कार्यभार संभालने के बाद
मोदी की पहली आधिकारिक बैठक भूकंप राहत कार्य से संबंधित थी। इसकी शुरुआत विभिन्न जिलों में चल रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा से हुई। अगले दिन वे कच्छ के लिए रवाना हो गए। मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने एक नई योजना को गति प्रदान की।
आपदा को अवसर में बदलना 103

उन्होंने सरकार की कार्य संस्कृति पर प्रकाश डाला और लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का भाव व्यक्त करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली ही कच्छ यात्रा पर, मैं वहां लगातार तीन दिन रुका।

मैंने प्रत्येक प्रभावित गांव और कस्बे का दौरा किया और लोगों से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है।
त्रासदी के आठ महीने बाद भी उनके लिए हालात बेहद दयनीय थे।
हड़ताल हुई। लेकिन मैंने किसी भी आधिकारिक या निजी स्वागत समारोह की अनुमति नहीं दी।
स्थानीय प्रशासन को पहले ही निर्देश दे दिया गया था कि वे कोई आदेश जारी न करें।
मेरा स्वागत करने के लिए केवल एक विज्ञापन।
इस यात्रा में मोदी के साथ गए कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया कि नौकरशाही को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मोदी ने बहुत ही सख्त अनुशासन का पालन किया। पहले, अगर कोई मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे बैठक का समय तय करता था, तो वह शायद ही कभी 12 बजे से पहले आता था। मोदी तो ऐसे हैं जो सुबह 9:45 बजे ही पहुँच जाते हैं। इसलिए अधिकारियों को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ा।
मोदी के व्यक्तिगत आचरण ने छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से अहम संदेश दिए। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने अधिकारियों को अपने लिए भोजन की व्यवस्था न करने का निर्देश दिया। आम तौर पर जब वे दौरे पर जाते हैं, तो वे विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपने लिए आयोजित होने वाले दोपहर के भोजन से बचते हैं। इसका कारण यह है कि यदि जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन करना पड़ता है, तो वे पूरे सरकारी परिवार को आमंत्रित कर देते हैं और अंततः यह 500-600 लोगों के लिए एक भव्य दावत बन जाती है। वे जानते हैं कि उनके पास ऐसी दावतों के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। इसलिए, अधिकारी किसी व्यापारी से भोजन प्रायोजित करने का अनुरोध करके व्यक्तिगत दायित्व निभाते हैं। इस तरह का दायित्व निभाना भी भ्रष्टाचार के समान है। इसलिए, उन्होंने अपने

अधिकारियों को ऐसा न करने का निर्देश दिया। वे अपना लंच बॉक्स स्वयं लेकर गए। इससे काफी समय की भी बचत हुई क्योंकि बड़े दोपहर के भोजन में घंटों लग जाते हैं और उस दौरान पूरा प्रशासन ठप्प हो जाता है।
अपनी पहली ही यात्रा में उन्होंने एक और बदलाव किया, और ज़िला प्रशासन को यह स्पष्ट कर दिया कि वे अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को उनके आसपास इकट्ठा न करें। आम तौर पर ऐसा होता था कि जब मुख्यमंत्री किसी दौरे पर जाते थे, तो सभी अधिकारी फाइलों का ढेर लिए इधर-उधर घूमते रहते थे, यह जाने बिना कि मुख्यमंत्री किस विभाग से क्या सवाल पूछेंगे। ऐसे दौरों के दौरान एक तरह का डर का माहौल रहता था। मोदी ने उनसे कहा, “मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मुझे किस विभाग से जवाब चाहिए। तब भी, केवल विभाग प्रमुख ही मौजूद रहें। उस विभाग के पूरे दल को इधर-उधर भटकने और अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”
104 मोदी, मुसलमान और मीडिया

एक और घटना जिसने मुख्यमंत्री के रूप में उनके एजेंडे के बारे में एक मजबूत संदेश दिया, वह यह थी कि पदभार संभालने के तीन-चार दिनों के भीतर ही भूकंप से तबाह कच्छ के अपने पहले ही दौरे पर उन्होंने राहत कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ दागी सरपंचों और अधिकारियों को निलंबित कर दिया। वे कहते हैं:
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैंने वह फैसला कैसे लिया क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो सोच-समझकर काम करता हो।
रॉबिन हुड की तरह। लेकिन इस मामले ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। इससे एक स्पष्ट संदेश मिला।

पूरे प्रशासन को यह संदेश दिया जाए कि ऐसे मानवीय मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मेरी मूल प्राथमिकता जनता का सशक्तिकरण थी।
कच्छ की अपनी पहली तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, मैंने यह समझने की कोशिश की कि देरी किस वजह से हो रही है।
पुनर्वास कार्य। मुझे बताया गया: “सर, यह नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है।”
क्योंकि नियमों के अनुसार XYZ की अनुमति नहीं है।
वापस लौटने पर, मोदी ने संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन सभी विभागों के सचिव शामिल थे, जिन्हें भूकंप पुनर्वास कार्य में किसी न किसी रूप में योगदान देना था—चाहे वह सिंचाई, आवास, बिजली आपूर्ति, सड़कें या भवन निर्माण हो। उन्होंने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारी अत्यधिक नौकरशाही बाधाओं की शिकायत कर रहे थे, जिसके कारण उनके लिए जमीनी स्तर पर परिणाम देना असंभव हो गया था। फिर उन्होंने पुनर्वास विभागों के प्रभारी राज्य सरकार के अधिकारियों से पूछा कि वे उस समय वास्तव में किस स्थिति में थे। उनकी कार्ययोजना क्या थी? मोदी ने उस पहली बैठक का वर्णन इस प्रकार किया:
उनकी प्रस्तुति उन सभी बातों पर केंद्रित थी जो वे अंत तक देने की योजना बना रहे थे।
वित्तीय वर्ष के, यानी 31 मार्च, 2002 को। मैंने उनसे कहा कि उन्हें चाहिए
इस वित्तीय वर्ष के चक्कर को अपने दिमाग से निकाल दें क्योंकि 26 जनवरी को...
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया कच्छ में उतरकर गुजरात को निशाना बनाएगी।

गहन जांच के दायरे में। ऐसी स्थिति में, हमें उन सभी आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से पूरा करना पड़ा।
ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया के सामने अपनी अच्छी छवि पेश कर सकें।
अधिकारियों से मार्च की योजनाओं को आगे बढ़ाने और मुझे यह बताने के लिए कहा गया कि क्या
वे 31 दिसंबर तक डिलीवरी कर सकते थे। हर एक ने एक नया शेड्यूल पेश किया।
और एक नई लक्ष्य तिथि। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वे दो दिनों में कितना काम पूरा कर पाएंगे।
अक्टूबर में हमारी यह बैठक होने वाली थी, तब से डेढ़ महीने बीत चुके हैं। जैसा कि मेरा भी है।
आदत की वजह से, ये सारी समस्याएं मेरे दिमाग में तब भी घूमती रहती थीं जब मैं रात को घर लौटता था।
मैंने सुबह-सुबह मुख्य सचिव को फोन किया और उनसे सुबह 9 बजे मुझसे मिलने के लिए कहा।
जब वह आया, तो मैंने उसे प्रभावित तालुकों की सूची बनाने को कहा। कुल
संख्या 38 थी। मैंने उसे सबसे अधिक प्रभावित तालुकों को लिखने के लिए कहा।
आपदा को अवसर में बदलना 105

शीर्ष स्थान पर मौजूद खिलाड़ियों को चुनें और विनाश के स्तर के अनुसार उन्हें ए, बी, सी और डी ग्रेड दें।
वह लगभग एक घंटे में वह सूची लेकर आया। फिर मैंने उससे नाम बताने को कहा।

मैं सबसे कुशल अधिकारियों में से उन्हें चुन सकूं ताकि उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बनाया जा सके।
सबसे ज्यादा प्रभावित तालुकों में। फिर मैंने उन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें बताया।
उस दिन से उनमें से प्रत्येक को स्वयं को
उन्हें सौंपे गए तालुका के मुख्यमंत्री। उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त होगा।
उन्हें इस संबंध में जो भी निर्णय आवश्यक लगे, लेने का अधिकार है। उन क्षेत्रों में। उन्हें तुरंत, मौके पर ही निर्णय लेने में संकोच न करने के लिए कहा गया था।
और वे वही करें जो उन्हें सही लगे, और मैं उनका पूरा समर्थन करूंगा, भले ही वे
इस प्रक्रिया में अनजाने में कुछ गलतियाँ हो गईं। आपको आश्चर्य होगा।
यह जानने के लिए कि इससे अधिकारियों को कितना जोश मिला। उन्हें जाने के लिए कहा गया और
वे प्रत्येक शुक्रवार से रविवार तक अपने प्रभार वाले तालुका में रहते हैं। 'सी' ग्रेड
जिन गांवों पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा था, उन्हें इस तरह के गहन उपचार की आवश्यकता नहीं थी।
निगरानी की जा रही थी। इसलिए उनके साथ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार किया गया।
इनमें से प्रत्येक अधिकारी ने सप्ताहांत में तीन दिन अपने-अपने स्थानों पर बिताए।
मैंने और जिन तालुकों को कार्यभार सौंपा गया था, उनके साथ सोमवार को सुबह 11 बजे एक समीक्षा बैठक की।

पहले ही सोमवार की समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "क्षमा कीजिए महोदय, कुछ नहीं किया जा सकता।"
"हमें वास्तव में बदलाव करना पड़ा क्योंकि हमने पहले गलत नियम लागू किए थे।" उन्होंने स्वीकार किया कि
पुनर्वास उपायों से संबंधित नियमों और विनियमों को सूचीबद्ध करने वाले परिपत्र
गांधीनगर से जारी किए गए आदेश ऐसे थे कि नेक इरादे वाले अधिकारी भी उन्हें आसानी से समझ सकते थे।
उन परिस्थितियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी ऐसी ही बातें सुनी थीं।
स्थानीय लोगों और जिला अधिकारियों से पता चलता है कि सरकारी नियम बाधा उत्पन्न करते हैं।
काम को सुगम बनाने के बजाय। उदाहरण के लिए, लोगों से XYZ उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती थी।
राहत का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र या दस्तावेजी सबूत।
अधिकांश लोगों के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेजी सबूत नहीं था।
क्योंकि उनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, इसलिए उन्हें दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ी।
सभी सरकारों की मूल प्रकृति यही है कि वे समाधान तलाशती रहें। लोगों को उनका हक न देना। मैंने पहले ही इस तरह की सारी शिकायतें सुन ली थीं।
और मैं एक जवाब की तलाश में था। इसलिए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं हर एक बनाता हूँ
आपमें से कोई एक, उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री या सीईओ, उन्होंने स्वयं पहचान की है।

समस्या को सही ढंग से समझा और स्वीकार किया कि उनके पहले के जीआर (सरकारी आदेश)
नियम-कानून पूरी तरह गलत थे। वे बाधा डालने और वंचित करने के लिए बनाए गए थे।
मैंने कहा, अब जब आपको पता चल गया है कि दिक्कत कहाँ है, तो...
आपके द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन करना आपका कर्तव्य है।
कृपया गुरुवार तक मुझसे संपर्क करें।
आप अपनी आवश्यकतानुसार सभी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपके संशोधनों के साथ।
यह हमारी मूलभूत नीतियों के विपरीत नहीं होना चाहिए।
उन सभी ने गुरुवार को सरकार में आवश्यक बदलावों के बारे में रिपोर्ट दी।
नियमों का पालन करें। मैंने उनसे कहा कि आज के अंत तक, हम नए जीआर जारी कर दें ताकि वे
वे शुक्रवार तक जाकर इन्हें लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके तालुका 106 में होने थे। मोदी, मुस्लिम और मीडिया

शुक्रवार से रविवार तक। जब वे सोमवार को अपने फील्ड ट्रिप से वापस आए,
उन सभी ने आत्मविश्वास से कहा, "सर, अब हमें पूरा भरोसा है कि हम अपना वादा पूरा कर लेंगे।"
तो इस तरह, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर, हमने एक संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया।
नई व्यवस्था। मैं 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बना था और 15 अक्टूबर तक मैं पहले ही
सरकार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया। और इन सभी अधिकारियों ने अपना समय व्यतीत किया।

इस भावनात्मक हावभाव का उद्देश्य यह संदेश देना था कि उनका दर्द हमारा दर्द है।
दर्द। इसी तरह हम लोगों के दुख को व्यक्त करते थे। हालांकि, नवरात्रि के दौरान,
जो दिवाली से पहले आते हैं, उनकी मदद के लिए मैंने थोड़ा अलग तरीका अपनाया था।
लोग सदमे और दुख से उबर रहे हैं। मैंने कलेक्टरों और जिला अधिकारियों से पूछा।
उन क्षेत्रों के विकास अधिकारियों (डीडीओ) को विशेष व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
नवरात्रि का उत्सव मनाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है क्योंकि नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक है।
गुजरातियों के जीवन में दिवाली का बहुत गहरा महत्व है। प्रत्येक गुजराती परिवार में दिवाली मनाई जाती है।
व्यक्तिगत परिवार। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, वे एक ऐसी स्थिति में थे।
आपदा को अवसर में बदलना 107

वे शोक में डूबे हुए थे और अपने घरों में किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाना चाहते थे।
लेकिन नवरात्रि सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से मनाई जाती है। इसीलिए मैं
उन्होंने कहा कि मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगा। मैं जाकर मातम में शामिल होऊंगा।
परिवारों के साथ खाना खाया। हम वहां दो दिन रुके। एक बार जब उन्हें लगा कि

सरकार ने वाकई परवाह की, उन्होंने अपनी सारी शिकायतें भुला दीं और साथ जुड़ गए।
इस त्रासदी को भुलाने में वे हमारा साथ दें।
मैंने उन कुछ गांवों का दौरा किया जहां मोदी 2001 में दिवाली के अवसर पर गए थे। यहां दो सबसे अधिक प्रभावित गांवों - चोबारी और ट्राम्बो - का विवरण दिया गया है।
मोदी का शोकग्रस्त चोबारी गांव का दौरा: चोबारी 1 विनाशकारी भूकंप का केंद्र था। यहां 5,000 की कुल आबादी में से 555 लोग (दस प्रतिशत) उस भयावह दिन अपनी जान गंवा बैठे। 550 से अधिक मृतकों के अलावा, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे - कुछ के पैर टूट गए थे, तो कुछ ने अपने अंग खो दिए थे। भूकंप के तुरंत बाद, उन्हें हवाई मार्ग से मुंबई और अहमदाबाद के अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उसके बाद केशूभाई सरकार के तहत चल रहे पुनर्वास कार्य अधर में लटक गए। सभी घर, दुकानें और इमारतें ढह गईं और मलबे में तब्दील हो गईं। लेकिन चमत्कारिक रूप से, गांव का स्वागत द्वार सुरक्षित रहा। आज, चोबारी में 80 मुस्लिम परिवार, 1,600 अहीर परिवार, 400 रबारी और 300 दलित परिवार हैं। इसके अलावा, यहां वानिया, लोहना आदि समुदाय के लगभग 500-500 परिवार भी हैं। यह उन गांवों में से एक था जहां मोदी ने 14 नवंबर, 2001 को दिवाली के अवसर पर काफी समय बिताया था। भुज में सूचना विभाग के उप निदेशक एस.के. सोनी, जो उस यात्रा के प्रत्यक्षदर्शी थे, कहते हैं:
मुख्यमंत्री गांव के चौक पर बैठे और प्रार्थना सभा में शामिल हुए।
हालांकि लोग सरकार से बहुत नाराज थे, फिर भी कोई
मोदी के दौरे के दौरान उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन या नारेबाज़ी हुई।

इन गांवों में। चोबारी में उनकी प्रार्थना सभा के लिए 3,000 से अधिक लोग एकत्र हुए।

1. चोबारी नाम एक प्राचीन और अद्वितीय आयताकार कुएं से आया है जो शहर के भीतर स्थित है।
एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर का परिसर। लोककथाओं के अनुसार, यह मंदिर महाभारत काल का है और इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। मंदिर परिसर में प्राचीन सती प्रतिमाओं और अन्य नक्काशी का अद्भुत संग्रह मौजूद है।
108 मोदी, मुसलमान और मीडिया

वातावरण एकदम शांत था—आम तौर पर होने वाली चहल-पहल से बिलकुल अलग।
आधिकारिक यात्राओं की पहचान।
चौबारी के स्थानीय ज्योतिषी भरतभाई जोशी कहते हैं:
जब हमें पता चला कि मुख्यमंत्री चोबारी आ रहे हैं, तो हमें आश्चर्य हुआ।
हमारी मौजूदा अव्यवस्थित स्थिति को देखते हुए हम उस बैठक को किस स्थान पर आयोजित कर सकते थे?
फिर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह शिव मंदिर में होगा। यह परिसर पूरे गांव का था और इसमें बड़े लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती थी।
बैठक में आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या।
गुजरात में हिंदू-मुस्लिम विभाजन के बारे में लगातार दुष्प्रचार सुनकर, मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही थी कि मैंने कहा, "लेकिन मुसलमान तो मंदिर नहीं आते? आपने मंदिर परिसर को ही क्यों निशाना बनाया?" जैसे ही ये शब्द मेरे मुँह से निकले, उनके चेहरों पर

अविश्वास के भाव देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। गाँव के एक व्यक्ति ने मुझसे पलटवार करते हुए पूछा, "मुसलमान मंदिर क्यों नहीं आएंगे? इस गाँव में लोग ऐसे नहीं रहते। हम सब मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी।"
भरतभाई ने बताया कि उनके गांव के मुसलमान भी अभिवादन के लिए ‘राम राम’ का इस्तेमाल करते हैं। मुझे और शर्मिंदा करते हुए उन्होंने कहा, “आप लोग इस तरह की फूट डालने वाली भाषा क्यों बोलते हैं? हमें हैरानी होती है कि आप दिल्ली वाले इस तरह सोचते हैं।” चोबारी गांव के निवासियों का एक-दूसरे के घरों में बेझिझक आना-जाना, गांव के प्रमुख हिंदुओं का मुझे देर रात मुसलमानों के घरों तक ले जाना, ये सब इस बात का पर्याप्त सबूत था कि उनके गांव में भाईचारे के पुराने बंधन आज भी कायम हैं।
हालांकि उस गांव का ऐतिहासिक शिव मंदिर ढह गया था, लेकिन शिवलिंग पूरी तरह सुरक्षित था। मोदी आए, मंदिर में शिव पूजा की और मंदिर परिसर में प्रार्थना सभा आयोजित की। जिस स्थान पर मोदी ने शिव पूजा की, वह गांव के लिए एक और यादगार जगह बन गया है। उन्होंने दलित और मुस्लिम परिवारों से विशेष रूप से मुलाकात की, जबकि मंदिर परिसर में आयोजित मोदी की प्रार्थना सभा में इन दोनों समुदायों के लोग समान रूप से उपस्थित थे। उन्होंने क्षतिग्रस्त खेतों, बोरवेल आदि का निरीक्षण किया और अकेले इस गांव में आधे दिन से अधिक समय बिताया। उन्होंने मृतकों की याद में चौक में एक दीपक भी जलाया। इसलिए यह कोई क्षणिक वीआईपी दौरा नहीं था।
2001 में 5,000 से अधिक की आबादी वाले चोबारी में आज 10,000 निवासी हैं। रामजी मारिया, एक युवा और उद्यमी दलित किसान, जो एक अर्ध-पेशेवर फोटोग्राफर भी हैं, यहाँ के सबसे मुखर लोगों में से एक थे।
आपदा को अवसर में बदलना 109

उन्होंने बताया कि मोदी की यात्रा का गांव पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुझे मोदी की यात्रा की कई तस्वीरें दिखाईं जो उन्होंने खुद ली थीं और निम्नलिखित विवरण दिया:
उस बैठक के दौरान जिसमें मोदी ने स्थानीय लोगों की बात सुनी
भाषण देने के बजाय, आज तक टीवी के संवाददाता धीमंत पुरोहित ने चैनल ने मोदी से पूछा, “आज पूरा देश दीये जलाकर जश्न मना रहा है।” “दिवाली है, लेकिन आप यहां आए हैं। लोगों के लिए आपका क्या संदेश है?” उन्होंने पूछा।
इस प्रश्न को तीन बार दोहराया गया। लेकिन मोदी अपने जवाब में वाक्य पूरा नहीं कर सके।
धीमंत का सवाल सुनकर उसका गला आंसुओं से भर गया। नरेंद्रभाई ने बात शुरू की।
तीन बार यह कहते हुए, "जबकि देश के बाकी हिस्सों में दीये जलाए जा रहे हैं, इतने सारे लोग
"इस गांव के दीये बुझ गए हैं।" यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसकी आँखें नीचे झुकी हुई थीं और वह एक और वाक्य नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वह बहुत दुखी था।
अपने आसपास के शोक से वह अभिभूत हो गया था।
वह लोगों की समस्याओं को सुनने में घंटों बिताता था और उनके साथ घूमता रहता था।
गांव के विभिन्न वर्गों, जिनमें दलित और मुस्लिम परिवार शामिल हैं।
उन्होंने महिलाओं की बातों पर विशेष ध्यान दिया और उनका आकलन किया।

उसके लिए समग्र स्थिति। चोबारी में, हम अलग-थलग बस्तियों में नहीं रहते हैं।
सभी जातियों और समुदायों के लोग आपस में स्वतंत्र रूप से घुलमिलकर रहते हैं।
हालांकि कुछ इलाकों में इनकी संख्या अधिक है, फिर भी आस-पड़ोस में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है।
किसी न किसी जाति या समुदाय का।
उन्होंने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में यह कहा, जिनसे पुनर्निर्माण में तेजी लाने में मदद मिली:
मोदी जी के आने से पहले पूरा गांव सदमे और शोक की स्थिति में था। सबसे पहले उन्होंने गांव को टीलों से मुक्त कराने पर ध्यान केंद्रित किया।
मलबे के ढेर अभी भी इधर-उधर पड़े हुए थे, जो उस त्रासदी की दैनिक याद दिलाते थे।
तब तक, इस दिशा में केवल नगण्य मात्रा में ही काम शुरू हुआ था।
पुनर्वास। मोदी जी ने स्वयं इस क्षेत्र की हर गली-गली का निरीक्षण किया।
गांव। उसने पूरी व्यवस्था को काम पर लगाकर सब कुछ तेजी से निपटा दिया।
आपातकालीन स्थिति में। हमें तुरंत ठोस अस्थायी सहायता प्रदान की गई।
सर्दियों की ठंड से बचने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए थे। तब तक हम खुले में रह रहे थे।
ऊपर आसमान ही हमारी छत थी। तब तक कई लोगों के पास टेंट भी नहीं थे।
उन्हें भोजन, कपड़े और कुछ नकद राशि के रूप में पर्याप्त राहत मिली थी।

हमें सरकारी सहायता तो मिल रही थी, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई वास्तविक आश्रय नहीं था।
कई ग्रामीणों ने बताया कि उस बैठक में सभी लोग रो रहे थे और मोदी भी उनके साथ रोए। ग्रामीणों की बात कई मिनट तक सुनने के बाद, मोदी, मुसलमानों और मीडिया ने

कुछ घंटों बाद उनका संदेश था: “निराशावाद के आगे मत झुकिए। आपका गाँव फिर से उठ खड़ा होगा और आप पहले से कहीं अधिक समृद्ध होंगे।” ट्राम्बो की महिलाओं ने मोदी की दिवाली यात्रा का ब्यौरा दिया। 2001 की दिवाली पर मोदी द्वारा दौरा किया गया एक अन्य गाँव ट्राम्बो था, जो भूकंप का केंद्र भी था। इस गाँव के 450 घरों में से 400 पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि शेष घरों को अलग-अलग स्तर की क्षति पहुँची।
जिन पहले लोगों से मैंने विस्तार से बात की, उनमें से एक पार्वतीबेन थीं, क्योंकि गाँव के लोगों ने मुझे उनके घर का पता बताया था, क्योंकि वे गाँव की सम्मानित मुखिया थीं। भूकंप में उनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उन्होंने भी उपेक्षा की वैसी ही कहानियाँ सुनाईं जैसी मैंने चोबारी में सुनी थीं। भूकंप को नौ महीने बीत चुके थे, लेकिन वे अब भी तंबुओं या अस्थायी आश्रयों में रह रहे थे। यह आपदा उनके लिए दोहरी मार थी क्योंकि वे 40 साल पहले विधवा हो गई थीं और उन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण अकेले ही किया था। हालांकि, उनके लिए उस आपदा की दर्दनाक यादें नरेंद्र मोदी के उनके अस्थायी आश्रय में आने और उनकी पड़ोसी द्वारा पकाई गई बाजरे की रोटी और मिर्च का सादा भोजन करने की गर्व भरी यादों के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी सबसे कीमती चीजों में से एक नरेंद्र मोदी की धुंधली हो चुकी अखबार की तस्वीर है जिसमें वे वही खाना खा रहे हैं जो उन्होंने उन्हें परोसा था।

तस्वीर के नीचे कैप्शन इस प्रकार है: तुम चिंता न करो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। (कृपया चिंता न करें; पूरा देश आपके साथ है)। वह कहती हैं:
पूरा कच्छ गहरे शोक में डूबा हुआ था। हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं।
150 घरों वाले उस छोटे से गाँव में 35 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले कोई मुखिया नहीं था।
मंत्री जी, कोई भी मंत्री हमारे आंसू पोंछने नहीं आया। सिर्फ नरेंद्र मोदी आए।
हमारा पूरा गांव अभी भी मलबे से ढका हुआ था और उसे उस पर से चलकर जाना पड़ा।
ढह चुके घरों के मलबे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना।
राहत कार्य के पहले कुछ हफ्तों में, सबने हमें छोड़ दिया था। केवल वही लोग थे जो...
राम रहीम संत (सच्चा सौदा) के स्वयंसेवक मदद के लिए आए थे।
पंजाब का एक संप्रदाय)। इन्हीं लोगों ने हमें भीषण सर्दी से बचाया।
हमें टेंट उपलब्ध कराए गए और साथ ही तीन महीने का राशन भी दिया गया। हमें यह भी मिला
मुंबई में बसे इस इलाके के लोगों से हमें मदद मिली। उन्होंने हमें ट्रक भर-भरकर सामान भेजा था।
राहत सामग्री, जिसमें भोजन भी शामिल है, हमें पर्याप्त मात्रा में राशन आदि प्राप्त हुआ।
पुनर्वास और हमें नए सिरे से जीवन शुरू करने में मदद करने का कार्य यहीं से शुरू हुआ।
नरेंद्र मोदी का आगमन।

आपदा को अवसर में बदलना 111

वह गांव में घूमा और उसे एहसास हुआ कि घर नहीं हो सकते।
पुराने गांव में अत्यधिक घनी आबादी होने के कारण इसे उसी स्थान पर पुनर्निर्मित किया गया।
स्थित। वह इन गांवों का पुनर्निर्माण करवाना चाहता था ताकि उन्हें लाभ मिल सके।
सभी संभावित नागरिक सुविधाओं से युक्त सुनियोजित विकास - पाइप से पानी की आपूर्ति,
स्वच्छता, खुले स्थान, सामुदायिक केंद्र, उचित आंगनवाड़ी और विद्यालय
खेल के मैदानों के साथ-साथ बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
मोदी जी के दौरे के 15 दिनों के भीतर ही बुलडोजर आए और मालबा को साफ कर दिया गया।
जब हमारे घरों और गांवों का नए सिरे से पुनर्निर्माण किया जा रहा था, तब सरकार
हमें टिन की छतें मुहैया कराई गईं। मोदी ने स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को देने का आदेश दिया।
पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पहली प्राथमिकता। इसके बाद प्राथमिकता प्रदान करना था।
उचित जल आपूर्ति प्रणाली। बोरवेल खोदे गए और पानी के टैंकर चलने लगे।
हर गाँव तक पहुँचने के लिए। प्रत्येक परिवार को प्रति माह 100 रुपये का नकद अनुदान मिलना शुरू हुआ।
2,000.

हमारे गाँव के एक बूढ़े हरिजन ने अपने परिवार के चार सदस्यों को खो दिया था—उनका
बेटा, उसके भाई का बेटा, पत्नी और बेटी। वह पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि
उनके बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन भूकंप में उन्होंने अपने दोनों पोतों को खो दिया।
लेकिन मोदी जी उनके साथ उसी पलंग पर बैठ गए और बोले, “बापू, डरो मत, मैं हूँ।”
और तुम्हारा बेटा भी।" ऐसा वाक्य केवल वही व्यक्ति बोल सकता है और समझ सकता है।
नरेंद्र मोदी की तरह। और उन्होंने अपना वादा निभाया, न केवल उस बूढ़े आदमी से किया,
लेकिन हम सभी के लिए। वह बूढ़ा आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसका परिवार पास के रापर में रहता है।
जब हमने उसे खाना दिया, तो उसने बाजरे के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया।
roti, mirchi, and chhachh. We had prepared dhokla, etc. but he only had roti
और छाछ। [पार्वतीबेन के तम्बू में मोदी ने जो खाना खाया था, वह वास्तव में पकाया गया था।]
पार्वतीबेन की पड़ोसी एक हरिजन महिला थी। मेरी पड़ोसी की पत्नी के पास...
मैंने उसके लिए कुछ पेड़े बनाए, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं। उसने उन्हें भी मना कर दिया।
उन्होंने हमें दूध पीने दिया और रोटी पर घी भी नहीं लगाने दिया— उन्होंने सादी रोटी ही खाई।

बाजरा, लाल मिर्च और छाछ। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मरहम लगाने आया था।
हमारे घावों पर ध्यान दिया और समझा कि हम सभी शोक में थे और यह सही समय नहीं था।
मिठाई खाने के लिए।
उसी दिन मैंने मन ही मन कहा था, ऐसा मुख्यमंत्री भगवान के समान है।
तीन साल के भीतर ही उन्होंने कच्छ का जीर्णोद्धार कर दिया। देखिए हमारे अपने घर में—इसमें दो हवादार, अच्छी तरह से बने कमरे हैं और एक रसोईघर है।
बाथरूम और एक बड़ा आंगन। यह भूकंपरोधी है। पहले हम इसमें रहते थे।
मिट्टी के घर। 1998 में भी भूकंप आया था। उस समय किसी के पास भी नहीं था।
उन्होंने हमारी तरफ देखने या यह पता लगाने की जहमत भी नहीं उठाई कि कितने लोग मरे। लेकिन इस बार परिवारों ने ऐसा किया।
मृत सदस्यों के साथ-साथ घायल सदस्यों के लिए भी उचित मौद्रिक मुआवजा प्राप्त हुआ।
घायल हो गए। मेरे चार बेटे हैं और उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग घर मिले हैं।
उनके परिवार।
112 मोदी, मुसलमान और मीडिया

समाज की आंतरिक शक्ति को संगठित करना: मोदी ने न केवल नौकरशाही को पुनर्गठित और पुनर्जीवित किया, बल्कि अन्य सभी चीजों की तरह, उन्होंने अपने गुजराती समाज की आंतरिक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा का भी उपयोग किया। उनके शब्दों में:
इसके बाद जो पुनर्निर्माण कार्य करना पड़ा, वह बहुत विशाल पैमाने का था।

मैं राहत कार्य के दिनों की एक रोचक घटना सुनाऊंगा।
त्रासदी के तत्काल बाद की स्थिति। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
हमारे समाज की प्रकृति। राहत कार्य के लिए बहुत सारे विदेशी आए थे।
वे सुव्यवस्थित थे और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करते थे। शाम पांच से छह बजे के बीच,
वे दिन भर का काम समाप्त करते, स्नान करते और अपने तंबुओं में लौट जाते। इसलिए मैं
दिन भर का काम खत्म होने के बाद उनसे जाकर बातचीत किया करता था। कई अन्य कहानियों के अलावा, उन्होंने मेरे साथ ये दो अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा,
हम दुनिया के कई देशों की यात्रा करते हैं। उन सभी जगहों पर राहत कार्य जारी है।
आम तौर पर रेड क्रॉस और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठनों तक ही सीमित। हमें आश्चर्य है।
यह जानकर हैरानी होती है कि गुजरात में हर गली, हर मोहल्ले में एक स्वयंसेवी संगठन है।
कुछ लोग दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं, कुछ दूध बांट रहे हैं। हम ऐसे दृश्य देख रहे हैं।
पहली बार किसी समाज में; हमें यहाँ बहुत कम काम करना है क्योंकि लोग
वे आवश्यक कार्यों का अधिकांश हिस्सा स्वयं ही कर रहे हैं।"
यही हमारे समाज की आंतरिक शक्ति है। हमें इसे समझना होगा।
और इस शक्ति का उपयोग करें। जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में लौटा, तो यह विचार मेरे मन में बना रहा।

इन छह सदस्यीय ग्राम समितियों में सरपंच, एक शिक्षक और अन्य सदस्य शामिल थे।
गांव द्वारा चुने गए अन्य सदस्यों को हमने स्कूल के लिए पैसे सौंप दिए।
उन्हें मुफ्त निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा, पुनर्निर्माण कार्य भी किया जाएगा।
आपदा को अवसर में बदलना 113

ग्राम समितियों को पूर्ण अधिकार दिए गए थे, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था कि वे ऐसा करें।
यह एक अच्छा काम था क्योंकि यह सब उनके अपने बच्चों के लिए था।
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये स्कूल भवन उम्मीद से कहीं अधिक सफल साबित हुए।
सरकार द्वारा निर्मित की जा सकने वाली चीज़ से बेहतर।
निविदाओं, नियमों, विनियमों और ठेकेदारों की सामान्य प्रक्रिया।
जहाँ हम
एक कमरे के निर्माण की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने दो कमरे बना लिए। जहाँ कमी थी, वहाँ उन्होंने काम किया।
जगह की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्वेच्छा से नए स्कूलों के लिए जमीन दान कर दी।
ग्राम समितियों द्वारा निर्मित संरचनाएं गुणवत्ता के मामले में अन्य संरचनाओं की तुलना में कहीं बेहतर होती हैं।
पहले सरकार द्वारा निर्मित स्कूल। इस तरह हमने कच्छ को परिवर्तित किया।
त्रासदी को अवसर में बदलें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गाँव समितियों ने इस काम को इतनी ईमानदारी से किया कि उनमें से कई ने इसे वापस कर दिया।

सरकार को अतिरिक्त धन मिलना। यह अपने आप में बेहद मार्मिक था।
यह हमारी मूल संस्कृति है, और यदि हम इसका लाभ उठा सकें, तो हम बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इस प्रकार, जनवरी तक, हम एक उपलब्धि हासिल करने में सफल हो गए थे।
जमीनी हालात में बड़ा बदलाव आया। तभी मैंने फैसला किया कि... वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक व्यापक प्रस्तुति दें। कॉन्फ्रेंसिंग। जैसा कि आप जानते हैं, उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना मेरी आदत है।
तकनीक। इसलिए मैंने अपनी प्रस्तुति उसी के अनुसार तैयार की। इसके बाद, मैंने सभी को आमंत्रित किया।
23 और 24 जनवरी की रात को दिल्ली स्थित दूतावासों में जाकर उन्हें सूचना दी गई।
हमें उपलब्ध कराए गए धन या सामग्री का हमने किस प्रकार उपयोग किया, इसका विस्तृत विवरण।
मैंने प्रत्येक देश के प्रति अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त किया। और हमने उन्हें उन सभी बातों के बारे में बताया जो हम उनकी मदद से हासिल कर पाए थे।
26 जनवरी को पूरे देश का मीडिया गुजरात में था और एक साल बाद, उन्होंने वास्तव में सरकार के काम की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि
काम सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, हालांकि कुछ मामूली कमियां हो सकती थीं।
कुछ छोटी-मोटी चूकें हुईं। इससे हमारे आत्मविश्वास को काफी बढ़ावा मिला।
अधिकारियों को पहले आठ महीनों में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सकारात्मक

उन्हें जो प्रतिक्रिया और प्रशंसा मिली, उससे उन्हें और अधिक मेहनत करने की शक्ति मिली। उन्होंने देखा
मार्च से लेकर दिसंबर के अंत तक आगे बढ़ने और एक कदम उठाने की रणनीति
अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने में अपनाई गई सक्रिय रणनीति काफी कारगर साबित हुई।
सामाजिक संगठनों का रचनात्मक उपयोग: पी.के. मिश्रा, एक आईएएस अधिकारी, जिन्हें कच्छ पुनर्वास के अपने अनुभव के कारण आज आपदा प्रबंधन पर एक अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त है, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अभियान नामक गैर सरकारी संगठनों के एक संयुक्त मंच ने भूकंप राहत और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 25 गांवों के प्रत्येक समूह के लिए सेतु (पुल) नामक संसाधन केंद्र स्थापित किए ताकि 114 मोदी, मुसलमानों और मीडिया के बीच सूचना का आदान-प्रदान सुगम हो सके।

गुजरात सरकार और स्थानीय समुदायों के सहयोग से गठित सेतुओं ने अपने अधीन गांवों से जानकारी एकत्र की और सप्ताह में एक बार या पखवाड़े में एक बार अभियान को भेजी। अभियान ने सेतुओं को आवश्यक मार्गदर्शन और समाधान प्रदान किए। जहां भी आवश्यक हुआ, जानकारी सरकार को भी भेजी गई ताकि संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान हो सके। पुनर्निर्माण कार्य के चरम पर, 33 सेतुओं ने 400 गांवों को कवर किया।
भुज में, भुज विकास परिषद नामक एक गैर सरकारी संगठन ने नगर नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने शहर की चारदीवारी के भीतर आठ स्थानों पर कर्मचारियों और कंप्यूटरों से सुसज्जित छोटे कार्यालय स्थापित किए और अपनी योजनाएँ प्रदर्शित कीं। प्रभावित लोग आपत्तियाँ दर्ज करा सकते थे और सुझाव दे सकते थे। यह

गैर सरकारी संगठन नियोजन सलाहकारों और सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहा। भाचाऊ और अंजार में भी इसी तरह के प्रयास किए गए।2
आईएएस अधिकारी मानसिंह, जिन्हें सचिव (पुनर्वास) नियुक्त किया गया था, ने गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न धार्मिक-सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे अस्सी संगठनों ने पांच जिलों के 285 गांवों को गृह निर्माण के लिए गोद लिया। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी आर.के. समा ने भी कच्छ में पुनर्वास कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई। वे निम्नलिखित जानकारीपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं:
मैंने मानसिंह के आग्रह पर ही यह जिम्मेदारी स्वीकार की थी। हालांकि मुझे पुनर्वास कार्य का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने मुझे मना लिया।
मैंने उनसे कहा, “आपने राहत कार्य में अच्छा काम किया है। अगर आप एक मॉडल स्थापित करने में मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।”
गैर सरकारी संगठनों को प्रभावी पुनर्वास करने के तरीके के बारे में जानकारी देने से इसकी गुणवत्ता में सुधार होगा।
उनके काम के बारे में। चूंकि आप हाल ही में सरकार से सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए आप
सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करें।” मैंने श्रीमान से कहा।
मानसिंह से मैंने कहा कि मैं केवल उतना ही काम करूंगा जिसके लिए मुझे पैसा मिलेगा।
मुझे चार-पांच दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। और मुझे आश्चर्य हुआ जब

हमें चार-पांच दिनों के भीतर ही फंड से लगभग 80 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए।
जो एचडीएफसी, हिंदुस्तान लीवर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य स्रोतों से आया था।
इजरायल सरकार।
मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे नीतियों को तेजी से संशोधित किया गया और
मोदी के आने के बाद इसमें सुधार हुआ। केशूभाई के समय में, यह बहुत दोषपूर्ण था।
2 प्रमोद के. मिश्रा, कच्छ भूकंप 2001: यादें, सबक और अंतर्दृष्टि (नई दिल्ली: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 2004), पृष्ठ 163। आपदा को अवसर में बदलना 115

यह नीतिगत निर्णय लिया गया था कि पुनर्निर्मित किए जा रहे नए गांवों में,
परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार भूखंडों का आकार आवंटित किया जाएगा।
जिनके पास अधिक भू-जोत थी, उन्हें जमीन का बड़ा टुकड़ा दिया जाना था।
एक सरकारी आदेश के माध्यम से चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई गईं। मैं इस सरकारी आदेश के खिलाफ था।
शुरू से ही, इसका सीधा सा कारण यह है कि उन लोगों की आजीविका
कृषि पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा था। ग्रामीणों को केवल
उन्होंने अपने घर खो दिए, खेत नहीं। मेरा मानना था कि हर परिवार उन्हें उचित आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए, आकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

भूखंड का या नवनिर्मित आवासीय इकाई के आकार का। जैसे ही
मामला नरेंद्र मोदी तक पहुंचा, तुरंत एक नया सरकारी आदेश जारी किया गया और नीति में बदलाव किया गया।
शीघ्रता से संशोधित किया गया।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमें आवश्यक बुनियादी ढांचागत सहायता मिले।
जैसे कि गांवों में घर बनाने के लिए पानी और बिजली।
आईएएस अधिकारी श्री महेश्वर साहू के नेतृत्व में स्थानीय समन्वय उत्कृष्ट था।
मुझे 52 गांवों के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, जिसका मतलब लगभग 10,000 घर थे।
साहू सप्ताह में दो बार सभी गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय बैठकें करते थे।
यदि कोई समस्या या अड़चन उत्पन्न होती, तो उसे मौके पर ही हल कर दिया जाता और एक नया जीआर जारी किया जाता।
24 घंटे के भीतर जारी किया गया। मोदी साहब ने आदेश दिया था कि जो भी निर्णय लिया जाए।
प्रभावित लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा यह कदम उठाया गया।
राज्य की राजधानी से लोगों का तुरंत जीआर में अनुवाद किया जाएगा। दो वरिष्ठ
इस कार्य के प्रभारी अधिकारी श्री मानसिंह और श्री महेश्वर साहू ने
विलंब से बचने के लिए तत्काल निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार—केवल यही कि आदेश
इसे स्थानीय कलेक्टर के कार्यालय से जारी करवाना पड़ता था। सब कुछ इसी तरह होता था।

त्वरित प्रक्रिया में लगाया गया। वास्तविक सत्ता हस्तांतरण के कारण घनिष्ठ समन्वय संभव हो सका।
शक्तियों के उपयोग के परिणामस्वरूप गुजरात ने जापान की तुलना में भी तेजी से पुनर्वास किया।
विश्व बैंक के अनुसार, किसी देश को सामान्यतः सात वर्ष लगते हैं इतनी भीषण त्रासदी से तबाह हुए क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना।
लेकिन गुजरात सरकार ने केवल कदम उठाए।
पुनर्निर्माण कार्य में तीन से चार साल लगने का अनुमान है, जो इस संबंध में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा।
मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ; मैंने खुद से एक वादा किया था, साथ ही, मेरे संगठन को भी, 52 के पुनर्निर्माण के अपने सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए।
डेढ़ किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों, जिनमें घर और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल हैं,
वर्षों बाद, वे गांधीनगर लौट आए। पुनर्निर्माण कार्य में सड़क निर्माण कार्य भी शामिल था।
कनेक्टिविटी, बिजली और पानी के कनेक्शन। यकीन मानिए, सब कुछ ठीक था।
निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम खातों सहित सभी कार्य पूरे कर लिए गए।
भुगतान निपटान, दस्तावेज़ीकरण और बाकी सभी आवश्यक सामग्री। मेरे पास थी
इंजीनियरों, राजमिस्त्रियों और ऐसे कार्यों के लिए आवश्यक श्रमिकों की पूरी टीम की भर्ती करना।
बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण। मैंने जिन 52 गांवों का पुनर्निर्माण किया, उनमें से प्रत्येक की आबादी 100 से 150 थी।

एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर। और फिर भी, हम निर्धारित समय के अनुसार काम पूरा कर सके। 116 मोदी, मुसलमान और मीडिया

क्योंकि सरकार ने काम को धीमा करने के बजाय उसे तेजी से पूरा करने में मदद की।
जैसा कि आमतौर पर नौकरशाही में होता है।
एक अच्छा आदर्श बनाने के लिए मेरे हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि
बिजली के तारों को भूमिगत बिछाने पर जोर दिया जा रहा था। मैंने तर्क दिया कि
अगर यह अहमदाबाद में हो सकता है, तो कच्छ में क्यों नहीं? इसी से एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ।
विवाद। लोगों ने कहा कि इतने बिखरे हुए स्थान पर ऐसा करना संभव नहीं था।
दूर-दराज के गाँव। इसमें बहुत खर्च आएगा, इत्यादि। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और
उन्होंने कहा कि जब हम पूरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण कर रहे थे, तो क्यों न हम इस ओर रुख करें?
सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा? मुख्यमंत्री ने मेरे विचार का पूरा समर्थन किया और,
उनके आग्रह पर, उन्होंने दो बड़े गांवों में भूमिगत बिजली केबल बिछा दीं।
परीक्षण के आधार पर। इसके पूरा होने पर, परिणाम की बहुत सराहना की गई।
सभी ने इस विचार को अपनाया। यह विचार लोकप्रिय हो गया और भूमिगत केबलों को स्वीकार्यता मिल गई।

अन्य गांवों के लिए भी। इससे गांवों में चौबीसों घंटे सातों दिन स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है।
सबसे दूरस्थ गांव।
मुझे लगता है कि पुनर्वास और व्यवस्थापन का इतना शानदार काम करना सराहनीय है।
गति में विश्व रिकॉर्ड ने मोदी साहब को न केवल बहुत आत्मविश्वास दिया, बल्कि
न केवल स्वयं में बल्कि उनकी नौकरशाही की कार्यकुशलता और क्षमता में भी।
चोबारी और ट्राम्बो आज
आज, न्यू ट्राम्बो में प्रवेश करते ही गाँव की ओर जाने वाली सड़क पर ही बड़े-बड़े आधुनिक बंगले दिखाई देते हैं। हालाँकि ट्राम्बो के अधिकांश निवासी अनुसूचित जाति और गरीब मुस्लिम थे, जो दिहाड़ी मजदूरी और अन्य कम वेतन वाले ग्रामीण कामों से अपना जीवन यापन करते थे, फिर भी सरकार द्वारा पुनर्वास पैकेज के तहत बनाए गए घर आज मध्यम वर्गीय घरों जैसे दिखते हैं। चूंकि सभी को समान व्यवहार मिला और घर बनाने के लिए समान आर्थिक और भौतिक सहायता प्रदान की गई, इसलिए समता की एक नई संस्कृति पनपी। अमीर और गरीब, दलित या उच्च जाति, हिंदू या मुस्लिम, के आवास की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं था। हर मोहल्ले में एक जैसी नागरिक बुनियादी सुविधाएँ थीं— चौड़ी पक्की सड़कें, 24x7 बिजली, हर घर में नल से पानी की एक जैसी व्यवस्था। हर परिवार—चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो— को एक ही तरह का घर और एक ही आकार का भूखंड मिला। हर घर में दो कमरे, एक रसोईघर और एक बाथरूम के साथ एक छोटा बरामदा और एक बड़ा चारदीवारी वाला आंगन है। आने वाले वर्षों में आय बढ़ने के साथ, कई लोगों ने इन घरों में और सुधार और विस्तार किया। लेकिन मूल सिद्धांत अभी भी समतावादी है।

भूकंप से पहले, कच्छ में ज़मीन के बड़े-बड़े हिस्से बंजर पड़े थे और लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे क्योंकि ज़मीन खेती योग्य नहीं थी।
आपदा को अवसर में बदलना 117

इस क्षेत्र की विरल आबादी का भी भरण-पोषण करना मुश्किल था। लेकिन अब कृषि में व्यापक सुधार, पानी की उपलब्धता, चौबीसों घंटे बिजली और उत्कृष्ट सड़क संपर्क के कारण जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। विशेष रूप से, मैंने उस हरिजन व्यक्ति के घर का दौरा किया, जिससे मोदी ने कहा था, “चिंता मत करो; मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे।” उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि वह मोदी से एक शब्द भी नहीं बोल पाईं क्योंकि भूकंप में उनके परिवार के चार वयस्क सदस्यों की मृत्यु हो जाने के कारण वह लगातार रो रही थीं।
गांव के युवा मुस्लिम, जो पार्वतीबेन के साथ थे जब मोदी ने उनके तंबू में दोपहर का भोजन किया था, ने कहा कि सरकार ने मोदी जी के हर वादे को निभाया। प्रत्येक परिवार को यह विकल्प दिया गया था कि वे पूरी सहायता नकद में लेना चाहते हैं या सरकारी गोदामों से निर्माण सामग्री लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यामीन के परिवार ने घर के पुनर्निर्माण में सहायता के बजाय नकद सहायता लेना चुना। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार मुसलमानों, हरिजनों या अन्य किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है।
इन सभी हरिजन और मुस्लिम घरों की पूरी कतार पर एक रसीद लगी हुई थी जिसमें लिखा था कि इनका निर्माण केयर इंडिया ने गुजरात सरकार और ट्राम्बो ग्राम समुदाय के सहयोग से किया है। प्रत्येक परिवार ने किश्तों में धन प्राप्त करके अपने घर के निर्माण में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, स्वीकृत कुल राशि 90,000 रुपये थी; परिवार को

पहली किश्त में 20,000 रुपये मिले। वे सरकारी डिपो से आवश्यक निर्माण सामग्री ला सकते थे और जैसे-जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ता गया, उन्हें शेष किश्तें मिलती रहीं। किसी भी परिवार ने भुगतान में देरी या बकाया राशि प्राप्त करने में नौकरशाही की परेशानी की शिकायत नहीं की।
इसी तरह, चोबारी में रामजी मारिया कहते हैं, “जब मोदी ने निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई डिपो स्थापित किए, तभी पुनर्वास कार्य में तेज़ी आई। इंजीनियर हर चरण में आकर निर्माण कार्य की जाँच करते थे और सरकार हमें उसी के अनुसार भुगतान करती थी। ये ‘सामग्री भंडार’ दो-तीन गाँवों के समूहों के बीच सुविधाजनक रूप से स्थित थे ताकि ग्रामीणों को सामग्री प्राप्त करने के लिए दूर न जाना पड़े। स्कूल आदि के निर्माण के लिए, ग्राम समिति द्वारा एक ठेकेदार नियुक्त किया जाता था, जिसका पूर्ण पर्यवेक्षण नियंत्रण होता था। सरकार, नागरिकों और सामाजिक कार्य संगठनों के बीच बेहतर समन्वय ने ही पूरे पुनर्वास कार्यक्रम को गति प्रदान की।” भरतभाई, जिन्होंने भूकंप में अपना सब कुछ खो दिया, कहते हैं, “गांव के सुनियोजित पुनर्विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, कई नए आवास 118 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

एन्क्लेव बनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप हम अब पहले की तरह भीड़भाड़ वाले पुराने गांव में नहीं रहते। हमारे पास अच्छी चौड़ी सड़कें और गलियां हैं। आज गांव में दस विस्तार (सेक्टर) हैं। इसका मतलब है कि भौगोलिक रूप से इसका कई गुना विस्तार हुआ है। मोदी 14 नवंबर, 2001 की यात्रा के बाद कई बार चोबारी का दौरा कर चुके हैं। उन्हें हमारी पूर्व सरपंच पूर्वीबेन का नाम भी याद है। उन्होंने एक बार विधानसभा में बताया था कि चोबारी का मावा (दूध से बना

व्यंजन) पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा है। एक बार वे चोबारी से मिल्क केक लेकर विधानसभा में विधायकों को बांटे थे।
रामजी मारिया ने आगे कहा, “दरअसल, मोदी के सत्ता में आने के बाद दलितों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं। उनसे पहले किसी ने भी बाबासाहेब अंबेडकर को उतना महत्व नहीं दिया जितना मोदी देते हैं। उदाहरण के लिए, अंबेडकर आवास योजना (अंबेडकर के नाम पर आवास योजना) और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए कई अन्य योजनाएँ हैं। उन्होंने दलित बस्तियों में शौचालय बनवाने की योजना शुरू की है। गुजरात सरकार दलितों के मुद्दों के प्रति बेहद संवेदनशील रही है— गुजरात में आपको उनके खिलाफ भेदभाव का कोई सबूत नहीं मिलेगा।”
फिर वह मुझे अपने घर ले गए, जिसका बाहरी हिस्सा पूरे गाँव में सबसे खूबसूरती से सजा हुआ था। यह एक छोटा सा बंगला था, जो सुंदर पौधों और फूलों के पेड़ों से भरा हुआ था, जिससे यह किसी भारतीय गाँव के घर की बजाय किसी यूरोपीय गाँव की आलीशान कुटिया जैसा दिखता था। रामजी के घर की निर्माण गुणवत्ता, साथ ही मैंने जिन अन्य घरों का दौरा किया, उन सभी की गुणवत्ता एक समान रूप से अच्छी थी क्योंकि सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली भूकंपरोधी सामग्री और डिज़ाइन उपलब्ध कराए थे। रामजी ने बताया कि भूकंप के बाद बने उनके घर रिक्टर स्केल पर पाँच से छह झटकों को झेल चुके थे। हालांकि, बाद के झटकों से रामजी के घर में कुछ छोटी दरारें आ गई थीं, लेकिन उनसे घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने जिनसे भी बात की, लगभग सभी ने कहा कि मोदी द्वारा किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि इस क्षेत्र में निर्मित प्रत्येक घर और इमारत भूकंपरोधी हो। अगर सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीशियनों के माध्यम से निर्माण की निगरानी नहीं करती, तो यह कभी संभव नहीं होता।

चोबारी की कुल आबादी में दलितों की संख्या 30 प्रतिशत है, लेकिन उनके घर भी उतने ही अच्छे और विशाल थे जितने कि अन्य लोगों के। चूंकि मैं रामजी और अन्य लोगों से पुनर्वास कार्य में दलितों और मुसलमानों के साथ हुए भेदभाव के संभावित उदाहरणों को याद करने के लिए बार-बार आग्रह करता रहा, तो रामजी ने एक बार फिर मुझसे कहा: “हमें आश्चर्य है कि आप इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठा रहे हैं। मेरे घर के आसपास 100 अन्य दलितों के घर थे। वे सभी दलितों के लिए बनाए गए नए योजनाबद्ध आवासीय क्षेत्र में चले गए हैं।”
आपदा को अवसर में बदलना 119

भूकंप के बाद हम वहां से चले गए थे। लेकिन मैंने यहीं रहने का फैसला किया। मेरे आस-पास गैर-दलित परिवार रहते हैं। लेकिन उनके रवैये में मुझे कभी भी जरा सा भी भेदभाव नहीं दिखा। आप खुद जाकर दलितों के नए बने घर देख लीजिए। हमारी पंचायत ने यह सुनिश्चित किया कि सबसे पहले उन्हें ही चौड़ी कंक्रीट की सड़कें, स्ट्रीटलाइट, पानी की सप्लाई, जल निकासी आदि सुविधाएं मिलें। मैं आपको खुद उस इलाके का दौरा कराऊंगा।
जब मैंने उस इलाके का दौरा किया, तो मैंने साफ-सुथरी और चौड़ी कंक्रीट की गलियाँ, बड़ी चारदीवारी वाले परिसर और हवादार घरों की सुव्यवस्थित कतारें देखीं। हर परिसर में इतना खाली स्थान था कि परिवार के बढ़ने पर घर का विस्तार किया जा सके। चोबारी अब पुराने जमाने के भीड़भाड़ वाले गाँव की जगह एक सुनियोजित छोटे कस्बे का रूप ले चुका है। पिछले आठ-दस वर्षों में आय में तेजी से वृद्धि के साथ, इन परिवारों के जीवन स्तर में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। इन दूरदराज के गाँवों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति होने के कारण, मैंने जिन परिवारों से मुलाकात की, उन सभी के पास फ्रिज,

टीवी सेट और शहरी मध्यमवर्गीय घरों में पाए जाने वाले अन्य उपकरण मौजूद थे।
चोबारी के बेलजी मारिया एक और युवा दलित हैं जिन्होंने भूकंप में अपनी बेटी और दादी को खो दिया। गांव में उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान है। परिवार के पास कुछ जमीन है, लेकिन वह सिंचाई योग्य नहीं है। उन्होंने भी पुनर्वास उपायों पर संतोष व्यक्त किया। सीमेंट ब्लॉक बनाने का काम करने वाले अरविंद मेरिया ने रामजी की बात की पुष्टि की कि दलित बस्ती गांव की पहली बस्ती थी जहां बिजली, नई जल आपूर्ति प्रणाली और कंक्रीट की सड़कें बनीं।
चोबारी के पूर्व सरपंच नामेरीभाई जेठा ने बताया कि उन्होंने मोदी सरकार की अंगभूत योजना के तहत दलित बस्तियों में ये सभी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस योजना के अंतर्गत दलित बस्तियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में प्राथमिकता दी गई है। अंगभूत योजना दलित समुदायों को कई सकारात्मक उपाय और अन्य लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है।
इसके बाद मैंने पुनर्वास के दौरान बनाए गए नए इलाके में बसे कुछ मुस्लिम परिवारों से मुलाकात की। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख सदस्यों में से एक सुलेमानभाई हैं। दलित बस्ती की तरह ही, नए मुस्लिम इलाके के घर भी अच्छी तरह से बने हुए, विशाल और एक बड़े परिसर से घिरे हुए हैं।
सुलेमानभाई एक किसान हैं और उनके परिवार के पास दस एकड़ जमीन है। उनके परिवार के दो घर थे। लेकिन भूकंप में दोनों ही नष्ट हो गए, जिसमें सुलेमानभाई के पिता की भी मृत्यु हो गई। वे बताते हैं कि उन्हें दोनों घरों के लिए मुआवजा मिला, जिससे उन्होंने अपने नए घर बनाए। सरकार ने प्रत्येक घर के लिए 90,000 रुपये का अनुदान दिया। हर कोई, 120 मोदी, मुसलमान और मीडिया

सुलेमान समेत अन्य लोगों ने बताया कि सरकारी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की प्रणाली बेहद किफायती साबित हुई, इसलिए बाथरूम, शौचालय और रसोईघर वाले गुणवत्तापूर्ण घर बनाने के लिए यह धनराशि पर्याप्त थी। सुलेमान ने तत्कालीन ग्राम सरपंच निमेरीभाई की खूब प्रशंसा की, जिन्होंने गांव के पुनर्वास और विकास के लिए अथक परिश्रम और लगन से काम किया। सुलेमान ने कहा, “उन्होंने हमें सर्वोत्तम सुविधाएं दिलाने का वादा किया था और उन्होंने अपना वादा बखूबी निभाया। हमें पानी, बिजली, अच्छी सड़कें और बाकी सभी सुविधाएं मिलीं।”
नए मुस्लिम बस्ती के अधिकांश घर पुराने गांव के अपेक्षाकृत भीड़भाड़ वाले भीतरी इलाकों से दूर स्थित हैं। आज प्रत्येक मुस्लिम परिवार के पास कोई न कोई मोटर वाहन है, साथ ही टीवी और रेफ्रिजरेटर भी हैं - ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें डेढ़ दशक पहले इस क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए पहुंच से बाहर माना जाता था।
सुलेमान ने बेहतर जल प्रबंधन, आसपास के क्षेत्र में 50-60 बांधों के निर्माण और सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब के निर्माण के कारण गांव में कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि के बारे में भी बताया। कई अन्य लोगों की तरह, उन्होंने भी गांव में आपसी सहयोग और अंतर-सामुदायिक सद्भाव की संस्कृति की सराहना की।
समरास का दृष्टिकोण व्यवहार में
चोबारी की मेरी यात्रा का समापन नामेरीभाई जेठा अहीर के घर देर रात हुई मुलाकात के साथ हुआ, जो नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समय गांव के सरपंच थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा और इस क्षेत्र के कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ से भाजपा के गढ़ में बदलने की कहानी सुनाई।

भूकंप के समय मैं एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता था। मैंने कभी कोई पदभार ग्रहण नहीं किया था।
मैंने तब तक न तो कोई पद संभाला था और न ही कोई चुनाव लड़ा था।
लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान इसी काम में लगाया।
भूकंप के बाद अपने गांव के लोगों की सेवा करने के लिए ऊर्जा।
चुनाव के समय
समय आ गया, मेरे गांव वालों ने मुझसे नामांकन फॉर्म भरने पर जोर दिया।
सरपंच पद के लिए। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मना लिया।
चुनाव लड़ना था। मुझे समरसता (सर्वसम्मति से) के आधार पर चुना जाना था।
(विकल्प)। लेकिन, अंतिम क्षण में, कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया।
तो हमारे यहाँ चुनाव हुए और मैंने कुल मतदान में 1,000 वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की।
3,000 लोगों की सूची। मेरे प्रतिद्वंदी को केवल दस प्रतिशत वोट मिले। यह पहले ऐसा हुआ करता था।
यह पूरी तरह से कांग्रेस समर्थक गांव है, फिर भी इसने एक भाजपा कार्यकर्ता को ऐसे उम्मीदवार के रूप में चुना है।
भारी बहुमत। चुनाव के बाद, मैंने एक बैठक बुलाई और आश्वासन दिया। लोगों को भरोसा है कि इस गांव में किसी चीज की कमी नहीं होगी—चाहे वह सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो या स्वास्थ्य।
आपदा को अवसर में बदलना 121

सुविधाओं, या अन्य विकास कार्यों के लिए। अगले चार वर्षों के लिए, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया।

गांव के सर्वांगीण विकास में ऊर्जा का निवेश करना।
बाद में, मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा और जीता। लोगों ने देखा था मेरे सरपंच के रूप में किए गए अच्छे कार्यों के कारण कई मंत्री यहाँ आए थे।
गांव को इसके पुनर्निर्माण की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया और जिला प्रशासन ने सहयोग किया।
हमारी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हुए। मैंने जिला चुनाव भी जीता।
शानदार नेतृत्व। जिला पंचायत सदस्य के रूप में, मैं उच्चतर सुनिश्चित कर सकता था।
हमारे गांव को आर्थिक सहायता मिली। इससे भी गांव के तीव्र विकास में मदद मिली।
जब मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, तो मैंने सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया।
गाँव। लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि एक योग्य व्यक्ति निर्विरोध मेरे उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाए।
समरस प्रक्रिया के माध्यम से। बारह महीने बाद, जब नियमित चुनाव होंगे।
जब मैं आया, तब तक मैं भाजपा का तालुका अध्यक्ष बन चुका था। उस समय मैंने राजी किया...
अपने ही ग्रामीणों से एक बुजुर्ग कांग्रेसी नेता को समरस सरपंच के रूप में निर्विरोध चुनने का आग्रह किया।
हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे एक अच्छे और ईमानदार इंसान हैं और जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
सभी लोग दलगत विचारों से ऊपर उठकर साथ चल रहे थे। मुझे लगा कि अगर एक तालुका के रूप में

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ही गाँव में समरसता नहीं ला सका, तो कैसे ला पाऊँगा?
क्या कोई मुझ पर भरोसा करता है कि मैं समरस की भावना के साथ काम करूँ (आम सहमति बनाना, आगे बढ़ना)?
क्या तालुका स्तर पर सभी लोग साथ होंगे?
लेकिन तीसरे चुनाव में कई उम्मीदवार थे। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सके।
समरस चुनाव हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इसके लिए आने वाली धनराशि में काफी वृद्धि हुई है।
गांवों में विकास कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। ये अनुदान गांवों को प्राप्त होते हैं।
सरपंच के खाते में यही बात है। इसलिए, इस पद को लेकर अब और भी ज्यादा खींचतान चल रही है।
लेकिन, इन चुनावी लड़ाइयों के बावजूद, हमारे गाँव में हम उस भावना को बनाए रखते हैं
समरसता। यह कच्छ की एक पुरानी परंपरा है। हमारे बीच बहुत गहरी जड़ें हैं।
समुदाय की सद्भावना और पारस्परिक सहयोगात्मक संबंधों की परंपरा में
हमारे गाँव में। इसका एक उदाहरण वार्षिक पदेलसा पीर मेला है, जो संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
सभी समुदायों द्वारा आयोजित। हर साल, 50,000 से 100,000 लोग— दोनों
हिंदू और मुसलमान मार्च महीने में उस मेले के लिए एकत्रित होते हैं।

आर्थिक पुनरुत्थान के तरीके और कारण: एक ग्राम बुजुर्ग, जिनका नाम मैं दर्ज करना भूल गया, ने पूर्व में दरिद्र क्षेत्र में आई नई समृद्धि का निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण दिया:
पहले कच्छ में केवल कुछ इलाकों में ही वर्षा आधारित कृषि होती थी। इस क्षेत्र के लिए हालात अनुकूल नहीं रहे थे। लेकिन पिछले दस वर्षों में, कृषि में भी सुधार हुआ है।
यह जादुई रूप से बदल गया है, जैसा कि इज़राइल के रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ था। कोई भी
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कच्छ में सिर्फ बारिश के पानी से ही कृषि का विकास हो सकता है।
कटाई। मोदी ने इस संदेश पर जोर दिया है कि बारिश की एक बूंद भी नहीं - 122 मोदी, मुसलमान और मीडिया

पानी को बर्बाद होने देना चाहिए। उन्होंने किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी।
उन्हें अपनी भूमि पर चेक-डैम और तलवाड़ी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि
बारिश के रूप में आने वाली पानी की हर बूंद को रोक लिया जाता है और उसे बहने नहीं दिया जाता।
बाहर बहने के लिए। उन्होंने सभी पुराने बांधों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य भी अपने हाथ में लिया।
जो वर्षों से प्रशासनिक उपेक्षा के कारण निष्क्रिय हो गया था। ऐसा माना जाता था कि चूंकि प्रकृति ने कच्छ पर अपना कहर बरपाया था, इसलिए हमें या तो
या तो इसे स्वीकार करो या बेहतर जीवन के अवसरों की तलाश में पलायन करो। लेकिन ऐसा नहीं है।

और भी। कच्छ में हरे-भरे भूभाग के बड़े-बड़े हिस्से हैं और कृषि तेजी से बढ़ रही है।
दुग्ध उत्पादन। यह मोदी जी द्वारा वन योजना शुरू करने के कारण संभव हो पाया।
महोत्सव (वनों का त्योहार), पशु महोत्सव और जल महोत्सव। कोई नहीं मैंने पहले कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था। विभिन्न वन महोत्सवों के दौरान
विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण भी शामिल है।
सड़क के दोनों ओर पेड़।
बागवानी के विकास में भारी निवेश किया गया है। किसानों को उन्हें सुनिश्चित बिजली आपूर्ति दी जाती है; उन्हें रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक दिए जाते हैं।
साधारण लोगों द्वारा बनाए जा रहे हरे-भरे घरों और सफेद जालीदार घरों की कल्पना की जा सकती थी।
क्या कच्छ के किसान कृषि में नए प्रयोग करेंगे? सरकार
अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक किसानों से न केवल व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, बल्कि
वार्षिक कृषि मेले के समय के साथ-साथ नियमित रूप से भी।
आधार।
इस क्षेत्र के पशुपालकों ने अपनी सदियों पुरानी पशुपालन पद्धति को छोड़ना शुरू कर दिया था।
विपणन और अन्य सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण व्यवसाय बाधित है।
लेकिन हाल के वर्षों में दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। क्योंकि किसानों को अपने मवेशियों की नस्ल सुधारने में मदद मिल रही है। किफायती

सरकार द्वारा कुशल पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं।
दूध के विपणन के विभिन्न माध्यम। इसी प्रकार इस पारंपरिक उत्पाद में लोगों की रुचि बढ़ती है।
व्यवसाय फिर से शुरू हो गया है और इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है।
आय स्तर। कच्छ के विकास की कहानी में जो बात उल्लेखनीय है, वह यह है कि
कृषि और पशुपालन में वृद्धि लगभग बराबर है।
औद्योगिक विकास।
निमेरीभाई के अनुसार, पिछले दस वर्षों में उनके क्षेत्र में कृषि उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गाँव में जीवन स्तर में स्पष्ट सुधार, चोबारी में दिखाई देने वाले नए मोटर वाहनों और ट्रैक्टरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह दावा खोखला नहीं लगता था। निमेरीभाई ने कृषि क्षेत्र में इस बढ़ती समृद्धि का श्रेय निम्नलिखित कारकों को दिया:
आपदा को अवसर में बदलना 123

कृषि उत्पादन में भारी सुधार का एक प्रमुख कारण यह है कि...
कृषि उत्सवों (कृषि) के माध्यम से सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण
उत्सव)। गर्मी के महीनों में, फसल कटाई से पहले, अधिकारी इससे जुड़े होते हैं।
कृषि संबंधी मुद्दों के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिक भी व्यापक यात्रा करते हैं।
वे एक गाँव से दूसरे गाँव जाकर कृषि मेले आयोजित करते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि...

आज गांव में कई परिवारों के पास अपने ट्रैक्टर हैं।
पिछले छह-सात वर्षों में सैकड़ों ट्रैक्टर खरीदे गए हैं। यह क्योंकि कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है और श्रम की कमी हो गई है।
ट्रैक्टर की हॉर्सपावर के आधार पर, प्रत्येक किसान को सब्सिडी मिलती है।
45,000-60,000 रुपये। इस गांव में लगभग 2,500 परिवार हैं और इससे अधिक लोग रहते हैं।
400 ट्रैक्टर। लेकिन 2,500 परिवारों में से हर एक के पास ज़मीन नहीं है। इसलिए अनुपात
जमीन मालिकों से लेकर ट्रैक्टर मालिकों तक का अनुपात बहुत अधिक है। अब सरकार ने कदम उठाया है।
दस अतिरिक्त वस्तुओं पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है।
कृषि उपकरण, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली, हैरो, कल्टीवेटर आदि।
कुल मिलाकर इनकी लागत 15 लाख रुपये है। यह सब्सिडी चार वर्षों में वितरित की जाएगी।
ताकि किसान उन्हें आसानी से खरीद सकें।
सरकार ने जल संचयन संरचनाओं में भी भारी निवेश किया है।
इन सब बातों ने खेती में नई रुचि पैदा कर दी है। मेरे अपने बेटे ने भी, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, खेती में रुचि विकसित कर ली है।
बारहवीं कक्षा का छात्र खेती करने और उसे एक उच्च तकनीक वाले उद्यम में बदलने पर जोर देता है।
नामेरीभाई के किशोर बेटे धर्मेंद्र ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कच्छी की पिछली पीढ़ी के विपरीत, जिन्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए पलायन करना पड़ता था, अब बहुत कम युवा अपने गांवों को

छोड़ना चाहते हैं। “मैं पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे की पढ़ाई करूंगा, लेकिन मेरे 124 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

“वास्तविक रुचि अत्याधुनिक कृषि में है,” उन्होंने कहा। धर्मेंद्र पहले ही आनंद स्थित कृषि विश्वविद्यालय का दौरा कर वहां चल रहे शोध से अवगत हो चुके हैं। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों को देखते हुए, कृषि विश्वविद्यालय ऐसे दौरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिला पंचायतें भी सक्रिय रूप से ऐसे दौरों का प्रायोजन कर रही हैं।
इस क्षेत्र के कई किसान ड्रिप फार्मिंग और शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्य नवीनतम तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए सरकारी सहायता से इज़राइल जा चुके हैं। नामेरीभाई ने बताया कि हाल के वर्षों में उनके क्षेत्र में जीरा जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती शुरू हो गई है। उन्होंने कपास की खेती भी शुरू कर दी है, जो पहले असंभव थी। अरंडी की खेती यहाँ पहले से होती थी, लेकिन इसके उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। किसानों ने खजूर और अनार जैसे उच्च मूल्य वाले फलों के साथ भी प्रयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मृदा परीक्षण से पता चला है कि उनकी भूमि इन दोनों फलों के लिए उपयुक्त है। सरकार ने सबसे पहले इज़राइल से खजूर के पौधे आयात किए और गुजरात के अपने कृषि विश्वविद्यालयों में उन्नत किस्में भी विकसित कीं। नामेरीभाई कहते हैं:
नरेंद्रभाई की एक और महत्वपूर्ण पहल यह है कि उन्होंने पुनर्जीवित किया है और
इससे कच्छ के डेयरी उद्योग को नई ऊर्जा मिली, जो पहले से ही शुरू हो चुका था।

अस्वीकार कर दिया। मैंने उनसे संकेत लिया और निर्णय लिया कि हमारे गाँव और तालुका को
साथ ही, हम अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैंने एक छोटी सी दूध मंडली शुरू की।
लगभग एक दर्जन पशुपालकों से संपर्क किया और धीरे-धीरे कई और लोगों को शामिल किया। फिर हमें एक
इंजीनियरिंग स्नातक वल्लभजीभाई, अखिल कच्छ सहकारी समिति की स्थापना करेंगे।
दूध उत्पादक। जब मुख्यमंत्री को हमारी सहकारी समिति के बारे में पता चला,
उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि ली क्योंकि इससे पशुधन की संपत्ति में वृद्धि होगी।
और दूध उत्पादन उनके दिल के बेहद करीब है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमारा
सहकारी संस्था का पंजीकरण दस दिनों के भीतर हो गया।
हालांकि, जब हमने 11 सदस्यों के साथ अपनी पहली सहकारी मंडली शुरू की,
हमारे पास आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। हमने शुरुआत की।
इस क्षेत्र के तीन गांवों से दूध एकत्र करके और उसे डांगड्रा को आपूर्ति करके।
धीरे-धीरे, हमें रापार में एक प्रशीतन प्रणाली मिली और हमने इसे धीरे-धीरे प्रत्येक क्षेत्र में फैला दिया।
गांव। इसकी शुरुआत मात्र 30 लीटर दूध की आपूर्ति से हुई थी और आज हम
दूध की आपूर्ति प्रतिदिन 2 लाख लीटर तक पहुंच गई है। गर्मी के महीनों में दूध की आपूर्ति कम हो जाती है।

यह घटकर आधा हो जाता है, लेकिन ठंडे महीनों में यह 2,00,000 लीटर प्रति दिन होता है। यह अपने आप में ही
इससे हमारे गांवों में करोड़ों रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है। जब हमने अपनी सहकारी संस्था शुरू की थी, तब दूध 15 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। अब इसकी कीमत काफी अधिक है।
वसा की मात्रा के आधार पर कीमत 40-50 रुपये तक हो सकती है।
आपदा को अवसर में बदलना 125

कृषि मेलों में भी वे किसानों को मवेशियों को स्वस्थ रखने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करते हैं और
दूध उत्पादन बढ़ाएँ। पशु चिकित्सक केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं।
हमारे क्षेत्र में दस गाँव शामिल हैं। वह घर-घर जाकर सेवाएँ देने के लिए मामूली शुल्क लेते हैं।
उसके आने-जाने के खर्चों को कवर करें। लेकिन अगर कोई किसान जानवर को पशु चिकित्सक के पास ले जाता है तो
उनकी सेवाएं निःशुल्क हैं। पशु चिकित्सा विभाग को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
हम अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से ऑपरेशन और अन्य जटिल सर्जरी करने जा रहे हैं।
पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। यह सेवा कई जगहों पर पहले से ही मौजूद है।
कुछ क्षेत्रों में पशुओं के लिए नियमित दवाइयाँ और टीके निःशुल्क हैं। लेकिन गंभीर मामलों में, पशुओं के लिए दवाइयाँ और टीके निःशुल्क हैं।
जिन बीमारियों के लिए विशेष दवाओं की आवश्यकता होती है, उनके इलाज का खर्च पशुपालक को वहन करना पड़ता है।

अध्याय 7

भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ
एक जीवित बचे व्यक्ति का वृत्तांत

मैं कच्छ के लोगों से कह रहा हूँ, अपनी ज़मीन का एक इंच भी मत बेचो; आपका कच्छ ऐसा नंदनवन बनने जा रहा है कि आपको अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने का हमेशा अफ़सोस रहेगा। इसलिए कृपया बेचने के लालच से बचें, क्योंकि यह ज़मीन बहुत कीमती होने वाली है। - नरेंद्र मोदी ने 2002 में कच्छ के लोगों से कहा था।

26 जनवरी 2001 को आए अभूतपूर्व भूकंप ने गुजरात को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इससे पहले लातूर या चमोली जैसे जिलों में आए भूकंपों ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही प्रभावित किया था। लेकिन इस भूकंप में कच्छ के सभी शहर - भुज, अंजार और बाछौ - भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे।
इन कस्बों के पुनर्जीवन की अनेक कहानियों में से, कच्छ व्यापार मंडल के वर्तमान अध्यक्ष राजेश भट्ट की कहानी एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो उनकी व्यक्तिगत त्रासदी और उससे उबरने से कहीं आगे बढ़कर भुज के राख से फीनिक्स पक्षी की तरह पुनरुत्थान की कहानी बयां करती है। कई अन्य लोगों की तरह, उनका 12 सदस्यीय परिवार भी तबाह हो गया था। 16 अगस्त, 2013 को उनके वीडियो-रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार पर आधारित एक विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:
मैं 1995 तक देना बैंक में मैनेजर था और उसके बाद मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया।
निर्माण मशीनरी और बिजली जनरेटरों का व्यापार। लेकिन, 24x7 बिजली की सुविधा के साथ।

गुजरात में बिजली आपूर्ति में कमी के कारण बिजली उत्पादन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है।
2001 में जब भूकंप आया, तो मेरे 13 बेडरूम वाले तीन मंजिला घर की दो मंजिलें गिर गईं।
बंगला पूरी तरह ढह गया और घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। तीसरी मंजिल एक तरफ झुक गई।
45 डिग्री के कोण पर। संयोगवश, मैं तीसरी तारीख को अपने बेडरूम में था।
यह तल से लगभग 40 फीट ऊपर था। लेकिन, जब नीचे के दो तल थे।
जब इमारत ढह गई, तो तीसरी मंजिल जमीन से महज 3 फीट ऊपर लटकी रह गई।
तभी
मैं सड़क पर कूद गया। मेरे घर के बगल वाली इमारत में 10 मंजिलें थीं।
वह जगह ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसमें 170 से अधिक लोग मारे गए।
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 127

उस त्रासदी में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब भूकंप के झटके आए, तब वह पूजा कर रही थी।
भूतल। मैं घर पर था क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश था। बीच में
नीचे फर्श पर, मेरे पिता, छोटा भाई और भतीजी गणतंत्र दिवस देख रहे थे।
टीवी पर दिल्ली की परेड। भूकंप की तीव्रता 100 ट्रेनों के बराबर थी।
100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपस में टकराना। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि पाकिस्तान के पास

हमने भुज पर कुछ मिसाइलें दागीं क्योंकि दो दिन पहले तक हमें सफलता मिल रही थी।
सीमा पर झड़पों की खबरें आ रही थीं। लेकिन, जब मैं गाड़ी से कूदकर चारों ओर देखने लगा,
मैंने अकल्पनीय तबाही देखी।
सच तो यह है कि केशूभाई ने उस आपात स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाला।
इसमें देखभाल और प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। इसलिए नागरिक वास्तव में आक्रोशित थे।
सरकार के खिलाफ। कच्छ में जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है और यहाँ तक कि
धनवान लोगों ने सब कुछ खो दिया था। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुख खोने का था।
हमारे प्रियजन। ऐसे परिवार भी थे जिनमें 10 में से 9 लोग मारे गए थे।
ऐसे लोग गहरे सदमे में थे और उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
उनके आसपास यही सब घट रहा था।
सरकार ने प्रत्येक मृतक के लिए 100,000 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की। लेकिन,
बचे हुए लोगों के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने जीने की इच्छा खो दी थी।
जहां तक मेरी बात है, हमारा परिवार उस दौरान कम से कम दो महीने तक खुले आसमान के नीचे रहा।
कड़ाके की ठंड थी। मैंने 25 जनवरी को जो कपड़े पहने थे, वही कपड़े मैंने भी पहन रखे थे।

हम सब खुले में लेटे हुए थे तभी हमें बताया गया कि एक वाहन सामान बांट रहा है।
रोटी। मेरी बेटी और मुझे एक-दो रोटी पाने के लिए उस गाड़ी के पीछे दौड़ना पड़ा।
रोटी के टुकड़े, जिन्हें वे लोगों पर फेंक रहे थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि कैसे पकाना है।
उस अराजकता के बीच व्यवस्थित वितरण की व्यवस्था करना।
उस रात, मेरे 91 वर्षीय गुरुजी ने मुझे फोन किया और कहा कि यह सब एक नाटक था।
उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और मुझसे आशा न छोड़ने को कहा, साथ ही यह भी कहा कि मैं इस स्थिति में अकेला नहीं हूँ।
उन्होंने मुझे यह आश्वासन भी दिया कि हम इस त्रासदी से बहुत जल्द उबर जाएंगे।
और आने वाले वर्षों में कच्छ की प्रगति सौ गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वह
उन्होंने मुझे सख्त सलाह दी कि मुझे किसी से भी आर्थिक सहायता नहीं लेनी चाहिए।
अगर मुझे दान में मिले भोजन से भोजन लेना पड़े।
मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी सलाह मानूंगा, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे
भविष्य के बारे में ये आश्वासन सिर्फ मुझे दिलासा देने के लिए थे। जब मेरा भाई-
मेरे ससुर, जो अहमदाबाद में डॉक्टर हैं, मेरी मदद करने आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया।
अपना स्टेथोस्कोप पीछे छोड़ जाने के लिए। मैं स्टेथोस्कोप पहनकर इधर-उधर घूमता था।

शिविरों में डॉक्टर होने का नाटक कर रहे थे। आपदा आने से पहले, हमारे पास तीन थे।
कारें और एक दोपहिया वाहन, ये सभी भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। मेरे एक दोस्त ने बताया कि...
एक दिन वह आया और हमें अपनी बस्ती में ले गया। उनका घर भी ढह गया था। लेकिन
उनके घर के पास कुछ खुली जगह थी। हमारा पूरा परिवार वहीं रुका। उस खुले मैदान में, जहाँ रात में तापमान शून्य डिग्री तक गिर जाता है। 128 मोदी, मुसलमान और मीडिया

हमारे पास न तो पहनने के लिए गर्म कपड़े थे और न ही खाने के लिए भोजन। मैंने अपना स्टेथोस्कोप पहन रखा था।
और लकड़ी मांगने के लिए श्मशान घाट गया। दिखावा करते हुए
मैंने एक डॉक्टर से झूठ बोला कि खुले में कई लाशें पड़ी हुई हैं। हमारे इलाके में और मुझे उन्हें वहीं जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी क्योंकि मेरे पास
उन शवों को श्मशान घाट तक ले जाने का कोई साधन नहीं था। इसीलिए मैंने यह कदम उठाया।
उनसे कुछ लकड़ी मिल गई। उस लकड़ी से हमने आग जलाई ताकि गर्मी बनी रहे।
उन बर्फीली रातों में खुद को गर्म रखने के लिए। मेरे पिता और भाई दोनों के पास
उनके दोनों पैर टूट गए थे। उनका इलाज करने के लिए कोई अस्पताल नहीं था और मेरे पास कोई सहायता नहीं थी।
दूसरा विकल्प यही है कि उनकी टांगों के चारों ओर लकड़ी के सीधे टुकड़े बांधकर उन्हें सुरक्षित रखा जाए।
टूटी हुई हड्डियाँ।

हर सुबह मुझे उन दोनों को उठाकर शौच के लिए ले जाना पड़ता था।
कई दिनों तक मैं सुबह-सुबह उनकी देखभाल करता था और सुबह 6 बजे तक वापस लौट जाता था।
मैं अपनी पत्नी को खोजने के लिए अपने ही मोहल्ले में जाता था। मैं जाकर सभी से विनती करता था।
मानवीय संगठन जो मेरी तलाश में मेरी मदद करने के लिए भुज आए थे
या तो पत्नी मिल जाए या उसका शव। लेकिन वे भी बेबस थे क्योंकि सब कुछ
बड़े-बड़े पत्थरों और टन भर मलबे के नीचे दब गया।
उस समय तीन संगठनों ने सराहनीय कार्य किया—भारतीय सेना,
आरएसएस और अंतरराष्ट्रीय बचाव दल। विदेशी टीमें इनके साथ आईं। नवीनतम उपकरण। उनके पास खोजी कुत्ते, स्निफर डॉग, आरसीसी कटर, जनरेटर आदि थे।
और मलबे को हटाने और दबे हुए लोगों को बचाने के लिए कई तरह के उपकरण।
उस समय सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं था। मैं दस दिनों तक वहीं मंडराता रहा।
मैं उस जगह के आसपास हर किसी से गुहार लगा रहा था कि मेरी पत्नी को बचाने या उसे वापस लाने में मेरी मदद करें।
मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि वह मेरे ढह चुके शरीर के ठीक नीचे दफ़न थी।
घर। लोग मुझसे कहते रहे कि उसे किसी दूसरे शहर ले जाया गया होगा। मुझे अन्य घायल लोगों के साथ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चूंकि मेरे गुरुजी ने कहा था
मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसे यहीं पाऊंगा। जब सब कुछ विफल हो गया, तो मेरे बहनोई और मैंने सोचा कि हम बन जाएंगे

हमारे अपने खोजी कुत्ते। जैसे-जैसे हम सूंघते हुए आगे बढ़े, हमें एक दुर्गंध महसूस हुई।
एक खास जगह से आवाज आ रही थी। लेकिन, वह आवाज 25-30 फीट नीचे से आ रही थी।
संयोगवश, जहाज तोड़ने वाले कारखाने से नौसेना की एक टीम वहाँ से गुजर रही थी।
उस समय उस स्थान पर। मुझे अभी भी याद है कि द्विवेदी नाम का एक अधिकारी था, जो
मेरे चेहरे पर हताशा और अवसाद के स्पष्ट भाव देखकर, उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई
मेरे एक रिश्तेदार मलबे के नीचे दब गए थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ...
उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी जीवित होती, तो उनकी टीम उसका शव बरामद कर लेती।
उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की है। मैंने कहा, इसे मेरा लगाव कह लो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ।
उसका चेहरा, भले ही वह अब इस दुनिया में न हो। उन्होंने कहा, "अगर हम अपने कर्मचारियों को बता दें कि वह मर चुकी है,
वे मशीनों का इस्तेमाल करेंगे और उसका शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ निकलेगा। लेकिन, अगर आप
उन्हें बताएं कि आपने दो घंटे पहले अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी, वे इस पर काम करेंगे।
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 129

उसे सही सलामत बाहर निकालने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहा था।
मैंने कहा, मैं झूठ बोलने को तैयार हूँ, और उससे विनती की।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसका शव बरामद करने में मदद करें।

इसलिए, उन लोगों ने अगले पांच-छह घंटों तक पूरी ऊर्जा और लगन से खुदाई की।
जब वे 20-22 फीट की दूरी पर पहुँचे, तो मैंने उसका पैर देखा और लगभग बेहोश हो गई।
मेरे जीवन का सबसे बुरा क्षण। जब उसका शव बाहर निकाला गया, तो मेरे जीजाजी ने...
कानून ने मुझे उसका चेहरा देखने से मना किया, क्योंकि वह बुरी तरह से क्षत-विक्षत था। मैं तो देख भी नहीं सकता था।
उस महिला के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें जिसने मुझे इतना समर्थन दिया था।
हमारे वैवाहिक जीवन के दौरान। हमें उसके शरीर को एक गंदे गद्दे पर रखना पड़ा, जो
मलबे में पड़ा हुआ था। हम उसे बांधने के लिए रस्सी ढूंढ रहे थे। उसके शरीर को उस गद्दे पर दबाते हुए, हमें कुछ टूटे हुए टेलीफोन और बिजली के तार मिले।
उसे बांधने के लिए उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए, हमें श्मशान घाट तक पहुंचने में तीन घंटे लग गए।
मैं राजेशभाई नाम के एक व्यक्ति को जानता था जो श्मशान घाट में काम करता था। उसने मुझे बताया
“आपकी पत्नी की मृत्यु ईश्वर की इच्छा है। यह भावुकता व्यक्त करने का समय या स्थान नहीं है।
इस समय सभी अनुष्ठान करना संभव नहीं है। कृपया उनका पार्थिव शरीर ले जाएं।
इसे पहली मंजिल पर ले जाकर वहां चल रहे सामूहिक दाह संस्कार में फेंक दो।
मेरे पास वहां जाकर अपनी पत्नी के शव को जलती हुई आग में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था।

नीचे जहां लगभग 300 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा था।
मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है।
अपने अंतिम संस्कारों को ठीक से संपन्न न कर पाने के दुःख के कारण हिंदू अनुष्ठानों के लिए।
कड़वा सच यह है कि तत्कालीन सरकार ने हमें कोई मदद नहीं दी।
चाहे कुछ भी हो जाए। यह हर मोर्चे पर विफल रहा। पूरे एक साल तक हम भिखारियों की तरह रहे।
और हमने धर्मार्थ संगठनों द्वारा दी गई हर चीज खाई। सरकार
उस एक साल में उन्होंने एक भी राहत शिविर नहीं चलाया और न ही किसी को राशन मुहैया कराया।
परिवार। यह सारा काम धार्मिक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया गया था।
NGOs. Sikh gurudwaras, Swaminarayan Sect, Murari Bapu, RSS, and other
गैर सरकारी संगठनों ने हमें जीवित रखा। हमारे स्वामीनारायण गुरु जी ने प्रतिदिन 5,000 लोगों के लिए लंगर चलाया।
लोगों को भोजन कराया गया। ठीक पीछे ध्यान स्वामी जी ने भी लगभग उतने ही लोगों को भोजन कराया।
कलेक्टर का कार्यालय। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को भी वहीं खाना पड़ता था।
मेरे परिवार सहित अधिकांश सक्षम बचे हुए लोग भी सेवा कार्य में शामिल हो गए।
इन धार्मिक संगठनों में शामिल होना। वैसे भी, और कोई चारा नहीं था।
सेवा ने हमारे सामूहिक दुःख से कुछ राहत प्रदान की। पूरे एक साल तक, हम सभी

हमने उन लंगरों में भोजन किया। बाद में, हमारे गुरुजी ने हमें अस्थायी आश्रय प्रदान किया।
जब तक हम अपना घर दोबारा नहीं बना लेते।
लेकिन पुनर्निर्माण और पुनर्वास की जिस पैमाने पर आवश्यकता थी यह कार्य केवल धर्मार्थ संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता था। जहाँ तक केशूभाई की बात है...
सरकार चिंतित थी, वह ईमानदारी से काम करने के लिए एकजुट नहीं हो पा रही थी।
यहां तक कि चारों ओर फैले करोड़ों टन मलबे को हटाने का काम भी एक चुनौती है।
लगभग। प्रक्रिया बेहद धीमी और अक्षम थी। इससे भी बुरी बात यह है कि 130 मोदी, मुसलमान और मीडिया

कि इतनी पीड़ा के समय में भी, वे धोखाधड़ी में लिप्त रहे।
मलबा। अधिकारियों और राजनेताओं ने ठेकेदारों के साथ मिलकर साजिश रची और मनमानी की।
मलबे को हटाने में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में। उदाहरण के लिए, अगर मेरे घर का मलबा
दस ट्रक भरकर माल का उत्पादन करने पर, इन ठेकेदारों ने आंकड़ों को दस गुना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।
खूब मुनाफा कमाने के लिए। जाहिर है, लूटी गई संपत्ति नेताओं और बाबुओं के साथ बांटी गई।
उन्होंने मुआवजे की राशि के मामले में भी गड़बड़ी की जो उन्हें दी जानी थी।
मृतकों के परिवारों के नाम पर अधिकारियों ने फर्जी दावा पत्र तैयार किए।

पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर। उनके कार्यभार संभालने के तीन महीने के भीतर, भुज
मलबे को अत्यंत पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से पूरी तरह से साफ कर दिया गया था।
उन्होंने गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज को सुव्यवस्थित किया।
(जीडीएमए) ने अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को भुज के पुनर्निर्माण का जिम्मा सौंपा और
पीड़ितों का पुनर्वास। हमने देखा कि कैसे उसी संगठन ने एक नया अधिग्रहण किया।
व्यक्तित्व। वही कार्य जो जीडीएमए ने 6-7 महीनों में किए थे, अब होने लगे।
मोदी के कार्यभार संभालने के दस दिनों के भीतर ही यह काम हो जाना चाहिए था। इतनी तेज़ी से और
नए मुख्यमंत्री ने कच्छ के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा लाई, वह सराहनीय थी।
बेघर लोगों के लिए घर बनाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया।
आपदा को अवसर में बदलने के उनके वादे पर। गुजरात शहरी
उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए विकास प्राधिकरण (जीयूडीए) का पुनर्गठन किया गया।
सभी तबाह हुए कस्बों में नागरिक बुनियादी ढांचा। उदाहरण के लिए, जिस क्षेत्र का मैंने उपयोग किया
पहले यहाँ रहने के लिए सड़क की अधिकतम चौड़ाई तीन मीटर थी। आज यहाँ कोई सड़क नहीं है।
भुज में एक ऐसी सड़क है जिसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम है।

हम सभी यह सोचकर हैरान रह गए कि इतनी बड़ी टास्क फोर्स कहाँ से आई थी।
वही सरकारी तंत्र, वही अधिकारी और वही ठेकेदार,
लेकिन उनके काम करने का तरीका मानो किसी जादुई छड़ी से बदल गया था।
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 131

काम में तेजी आई, पुनर्वास कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ। नाटकीय रूप से, और लोगों में आशा की लहर दौड़ गई।
मोदी के सत्ता संभालने के बाद ही नीतिगत घोषणा की गई थी कि
जिनके घर नष्ट हो गए हैं, उन सभी को स्थानांतरित किया जाएगा और उन्हें 120 का मुफ्त आवास दिया जाएगा।
सभी नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित वर्ग गज का भूखंड—बिजली, जल निकासी,
पानी का कनेक्शन आदि।
सभी को 120 वर्ग गज का एक भूखंड मुफ्त मिला—चाहे उनके पास एक साधारण सी झोपड़ी हो या
2 करोड़ रुपये का एक बड़ा बंगला। इससे भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई।
यदि लोगों को अलग-अलग आकार के भूखंड दिए गए होते, तो राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग
वे बड़े भूखंडों का प्रबंधन कर सकते थे। इसके अलावा, सरकार ने नकद राशि भी दी।
प्रत्येक परिवार को अपना घर बनाने के लिए 150,000 रुपये का अनुदान।
सामग्री को 'सामग्री बैंकों' से बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर प्राप्त किया जा सकता था।

सरकार द्वारा स्थापित। उस समय, धनराशि पर्याप्त से अधिक साबित हुई।
अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए क्योंकि हमें अच्छी गुणवत्ता का निर्माण मिल सकता था
इन सरकारी डिपो से बहुत कम कीमतों पर सामग्री प्राप्त करें। सबसे अच्छी बात यह थी कि योजनाओं की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच कोई अंतराल नहीं था।
वितरण प्रक्रिया का प्रारंभ। अधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था।
सभी वादों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मौके पर ही निर्णय लिए गए।
भूखंडों का आवंटन बिजली की गति से हुआ। अधिकारियों की बड़ी-बड़ी टीमें मौजूद थीं।
प्रत्येक भवन को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उन्हें बुलाया गया था।
लोगों पर भरोसा करने और हमेशा की तरह अड़चन डालने वाले रवैये को त्यागने का निर्देश दिया गया।
या फिर लालफीताशाही। उदाहरण के लिए, हमारे इलाके में आए अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि...
मुझे अपने घर के भूखंड के स्वामित्व का प्रमाण राशन कार्ड के रूप में देना होगा।
पासपोर्ट, बिजली का बिल या कोई अन्य दस्तावेज़। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास बस यही बचा है:
कुछ नहीं—कोई लिखित सबूत नहीं था क्योंकि हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते थे।
हम उन्हीं कपड़ों में भाग निकले थे जो हमने पहन रखे थे। उन्होंने हमारे बयानों पर विश्वास कर लिया।

उन्होंने कहा कि हमें बस स्थानीय नगर परिषद के पास जाना होगा।
और हमें इस बात का प्रमाण पत्र मिल जाए कि हम उस क्षेत्र के निवासी थे। उस प्रमाण पत्र में यह भी लिखा हो कि...
यह आसानी से हो गया। नागरिकों पर भरोसा करने का यह दृष्टिकोण, उन्हें एक तरह से
संभावित गुंडों ने हमारे घावों पर मरहम का काम किया।
व्यवस्था स्थापित करना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना: अनिल दास, जो एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 2001 में गुजरात सरकार के साथ पुनर्वास कार्य में हाथ मिलाया था, कहते हैं:
मोदी ने मलबा हटाने की प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित किया, इसके बावजूद
लोगों को उचित अस्थायी आश्रय प्रदान किए गए ताकि वे 132 मोदी, मुसलमानों और मीडिया की कड़ाके की ठंड से बच सकें।

कच्छ में किए गए और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी, जो उनकी सबसे नाटकीय उपलब्धियों में से एक है।
और विवादास्पद कदमों में सभी आवास और
सार्वजनिक भवनों का पुनर्निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था और
विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के तरीके में कुप्रबंधन
और सरकार के भीतर और बाहर निहित स्वार्थों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया।
मैंने शुरू में सभी प्रकार के आवास निर्माण को रोकने के इस कदम का विरोध किया था। लेकिन, एक बार
उन्होंने इसे समझाया, और मुझे यकीन हो गया कि उन्होंने सही काम किया है।

इन और अन्य प्रोत्साहनों के चलते, श्रमिक इस क्षेत्र में आने लगे। स्थानीय
लोगों को रोजगार भी मिला, सरकार ने इसमें भारी निवेश किया।
नए बुनियादी ढांचे का विकास, विश्व स्तरीय सड़कें, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति,
स्वच्छता और बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाएं।
मुझे भी अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला।
सौभाग्यवश, 1998 में।
जब इस इलाके में एक बड़ा चक्रवात आया था, तब मैंने एक पूरी तरह से तबाह व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी।
एक अजनबी, जिसका जनरेटर, जिसे उसने मेरे माध्यम से खरीदा था, चक्रवात में बह गया। संयोगवश मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने भूकंप देखा।
मैंने एक कंपनी के लिए प्रतिरोध आधारित पूर्वनिर्मित मॉडल घर का डिज़ाइन और निर्माण किया था।
हमारे गुरुजी द्वारा आवास परियोजना चलाई जा रही है।
अगले दिन, वह आदमी मेरे घर आया और बोला, "क्या आप और 100 बना सकते हैं?"
"क्या ये घर वैसे ही हैं जैसे आपने मुझे मॉडल हाउस दिखाया था?" उन्होंने कहा कि काम सार्थक था।
उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपये दिए और काम देने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था।
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 133

ईमानदारी। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास व्यवसाय में निवेश करने के लिए आवश्यक पूंजी नहीं है।

तो, अगले ही दिन उन्होंने मेरे बैंक खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए—यह
उस समय जब मेरा कार्यालय भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन्होंने कहा, "आपके पास था
उन्होंने संकट के समय मेरी मदद की। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूँ ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
एक बार फिर पैर जमाओ।"
राजेश भट्ट ने पर्यावरण के अनुकूल फ्लाई ऐश ईंटों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और इस उद्योग में विश्व के अग्रणी बन गए। भट्ट ने अपने फ्लाई ऐश प्रयोग को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के ध्यान में लाया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी सराहना की।
फ्लाई ऐश की 50 लाख ईंटों का पहला ऑर्डर गुजरात शहरी विकास बोर्ड से आया। उनकी पर्यावरण-अनुकूल ईंटें, पर्यावरण के लिए हानिकारक लाल ईंटों की तुलना में मैनहोल की लाइनिंग के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हुईं। उत्पादन शुरू करने के लिए, उन्होंने और उनके दो इंजीनियर भाइयों ने लगभग 10 लाख रुपये का बैंक ऋण लिया। यह भी संभव हो पाया क्योंकि गुजरात सरकार ने कच्छ में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था, ताकि वहां की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को नई दिशा और ऊर्जा दी जा सके। बहुत जल्द, उन्होंने अपना खुद का अत्याधुनिक स्वचालित फ्लाई ऐश निर्माण संयंत्र विकसित कर लिया। आज, उन्हें कम लागत वाले आवास के क्षेत्र में एक अग्रणी विशेषज्ञ माना जाता है और गुजरात सरकार ने उन्हें अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए इटली, अमेरिका, ब्रिटेन और कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में भेजा है। वे कहते हैं: भूकंप से पहले कच्छ में व्यापार और उद्योग की कोई संभावना नहीं थी।

वह भी बिजली जनरेटर बेच रहा था, किसी चीज का निर्माण नहीं कर रहा था। लेकिन, क्योंकि
मोदी ने कच्छ में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए लाल कालीन बिछाया।
कर छूट की घोषणा करना और बड़े और छोटे दोनों प्रकार के गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराना
यहां छोटे उद्योग तेजी से विकसित हुए हैं और फल-फूल रहे हैं। चूंकि पहले
उस समय केंद्र में एनडीए सरकार थी, इसलिए हमें भी छूट दी गई थी। उत्पाद शुल्क और अन्य केंद्रीय कर। राज्य सरकार ने वैट भी माफ कर दिया।
अन्य स्थानीय कर। इस शुष्क क्षेत्र में उद्योग के तीव्र विकास ने उत्पन्न किया है
बड़े पैमाने पर रोजगार।
मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के एक साल के भीतर ही मोदी ने कच्छ में भाषण देते हुए कहा,
मैं कच्छ के लोगों से कह रहा हूँ, अपनी ज़मीन का एक इंच भी मत बेचो; कच्छ ऐसा नंदनवन बनने जा रहा है कि आपको हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा।
आपने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। इसलिए कृपया बेचने के प्रलोभन से बचें।
क्योंकि यह जमीन बेहद मूल्यवान होने वाली है।"
134 मोदी, मुसलमान और मीडिया

नियम आधारित, जनहितैषी नीतियां
कृषि से उद्योग में भूमि हस्तांतरण के संबंध में अन्य राज्य सरकारों के तौर-तरीकों से यह दृष्टिकोण पूरी तरह अलग है। भारत के

अधिकारी भी इस प्रक्रिया में फंस गए क्योंकि वरिष्ठ होने के नाते शर्मा ने उनसे मनगढ़ंत खातों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। भविष्योन्मुखी योजना के चलते कच्छ सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
भट्ट की उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए जिसमें बताया गया है कि कैसे मोदी की दूरदर्शी नीतियों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे कभी पिछड़े रहे भीतरी इलाकों को बदल दिया:

1 For details of Pradeep Sharma’s case, see: Madhu P. Kishwar, “Ulta Chor Kotwal Ko
दांते: आरोपित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा का नरेंद्र मोदी के खिलाफ जवाबी हमला, 3 दिसंबर 2013, वेब। http://www.manushi.in/articles.php?articleId=1738#. Uv3tQUKSxJP.
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 135

मैं कच्छ चैंबर ऑफ कॉमर्स का तीन बार अध्यक्ष रह चुका हूं। लेकिन, मोदी ने हमारी सभा को संबोधित करते हुए अपनी पहली ही बैठक में हमें बताया कि कच्छ
यह उद्योग, बंदरगाहों, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनने जा रहा था।
ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और बिजली उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश। उन्होंने मुझसे कहा, “राजेश, मैं
मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी सलाह मानते हैं या मेरी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं, वही कहता हूं।
मेरा सपना है कि गुजरात 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करे।

कच्छ के विशाल तटीय क्षेत्र को देखते हुए, मैं 10,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने जा रहा हूँ।
सबसे सस्ते स्रोतों से कोयला आयात करके अकेले कच्छ में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।"
प्रमुख व्यापारियों और कॉरपोरेट जगत के बड़े-बड़े अधिकारियों समेत सभी लोग हंस पड़े।
यह सुनकर, सांसदों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। अगले ही दिन, सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर खबर छापी कि मोदी पागल हो गए हैं; उसे मेगावाट और किलोवाट के बीच का अंतर भी नहीं पता था।
आज उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया है। कच्छ अब अपने अधिशेष की आपूर्ति कर रहा है।
कई पड़ोसी राज्यों को सत्ता सौंप दी है। टाटा और अडानी दोनों ने प्रत्येक परियोजना 4000 मेगावाट की है। टाटा पावर परियोजना अभी भी निर्माणाधीन है।
क्रियान्वयन में देरी हुई है, लेकिन अदानी पावर प्रोजेक्ट कुछ वर्षों से चालू है।
अब, पूरे गुजरात में बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
कच्छ में पवन ऊर्जा का भी भारी उत्पादन हो रहा है। यह क्षेत्र यहां हवा की गति हमेशा से तेज रही है, लेकिन मोदी से पहले किसी ने भी इसका दोहन करने के बारे में नहीं सोचा था।
हम कच्छी लोगों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह एक ऐसी संपत्ति हो सकती है जिसका उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में बंजर भूमि के विशाल भूभाग हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है।
कृषि के लिए उपयुक्त। उस बंजर भूमि का राज्य द्वारा सदुपयोग किया गया है।

सरकार निवेशकों को पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज,
ये पूरे तटीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि...
हालात प्रतिकूल हैं, लेकिन कोयले की आपूर्ति एक दिन खत्म हो जाएगी, जबकि पवन ऊर्जा
अक्षय है।
दूसरे, कच्छ में साल में 300 दिन धूप रहती है। हममें से किसी ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया।
इससे बिजली उत्पादन की कितनी संभावनाएं पैदा हुईं, इस पर ध्यान दिया गया। लेकिन मोदी
उन्होंने कच्छ और गुजरात को सौर ऊर्जा के दोहन में अग्रणी बनाया। यही कारण है कि उन्होंने
उनका मतलब यही था जब उन्होंने कहा कि हम भूकंप को एक अवसर में बदल देंगे।
पुनर्निर्माण का कार्य करते समय मोदी दूरदर्शी योजना बना सकते हैं।
कुच मलबे से इसलिए उभरे क्योंकि उनकी सोच बड़ी है और उनका दूरगामी दृष्टिकोण है जो किसी और का नहीं है।
अल्पकालिक चुनावी विचारों से बाधित। यहां तक कि हमारे बिजली के तार भी।
अब इसे जमीन के नीचे बिछाया जा रहा है। हमारी सभी स्ट्रीटलाइटें सौर ऊर्जा से चलती हैं।
यहां खुले में सीवेज की व्यवस्था नहीं है। गुजरात के पुराने गांवों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
स्वच्छ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में भूमिगत सीवेज प्रणाली को अपनाएं।

नर्मदा जल का जादू: दशकों तक, विभिन्न सरकारों ने इसे छिपाए रखा।
हमें आश्वासन दिया गया कि नर्मदा नदी का जल कच्छ तक लाया जाएगा।
136 मोदी, मुसलमान और मीडिया

लेकिन कुछ नहीं हुआ। कच्छी लोग हमेशा पानी की कमी से जूझते रहे। लेकिन मोदी ने...
वह आया और अपने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि
स्वच्छ पेयजल एक वर्ष के भीतर कच्छ के सुदूरतम छोर तक पहुँच जाता है। और यह
ऐसा हुआ। आज हमें नर्मदा से शून्य टीडीएस वाला पीने का पानी मिलता है। टीडीएस एक
पानी की कठोरता मापने की इकाई। मोदी से पहले के दिनों में, हम 1700 ग्राम पानी पी रहे थे।
अब हमारा पानी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली विशाल पाइपों के माध्यम से आता है जो टीडीएस नहीं दर्शाती हैं।
जंग लगना। इसके अलावा, सरकार ने हर जगह जल शोधक संयंत्र स्थापित किए हैं।
नर्मदा पेयजल आपूर्ति निगम (एनडीडब्ल्यूएससी) के माध्यम से गांव को जल आपूर्ति की जाती है।
15 साल पहले कच्छ के लोग ऐसी किसी चीज का सपना भी नहीं देख सकते थे।
अब सरकार ने नर्मदा नदी के जल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नहरों का निर्माण शुरू कर दिया है।
सिंचाई के लिए भी पानी। अगर संघर्ष न होता तो यह पहले ही हो चुका होता।

नए रोजगार और व्यावसायिक अवसर—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। शहरी
मोदी द्वारा कच्छ के लिए अपनाई गई योजना का मॉडल जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था।
किसी आपदा पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय, इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी योजना बनाई।
बहुमूल्य विरासत का संरक्षण: आइए मैं आपको यह भी बता दूं कि मोदी कितने रचनात्मक हैं।
विरासत संबंधी मुद्दों से निपटने में। भुज के ठीक बीचोंबीच एक पुराना किला है।
आजादी के बाद से ही इस पर सेना का कब्जा था। हमारे मुख्यमंत्री ने लंबे समय से
सेना के साथ बातचीत की और उन्हें किला खाली करने के लिए राजी करने में सफल रहा।
उन्हें उन सुविधाओं के लिए वैकल्पिक स्थान दिया गया जिन्हें उन्हें स्थानांतरित करना पड़ा था।
सरकार ने स्मृति वन (स्मारक उद्यान) बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए।
भूकंप में जान गंवाने वालों की याद में। यह स्मृति वन फैला हुआ है।
लगभग 60-70 एकड़ जमीन। सेना ने एक साल पहले ही किले को खाली किया था, लेकिन काम जारी है।
इस स्मारक के विकास का काम पहले से ही तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार ने
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 137

भुज कलेक्टर को चीन और यूरोप भेजा गया ताकि वे ऐसे स्मारकों का अध्ययन कर सकें।
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की एक टीम के साथ ताकि वे न केवल नुकसान की भरपाई कर सकें
सर्वोत्तम रचनात्मक विचारों के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि स्मारक भूकंप-रोधी हो।
प्रतिरोधी। हमारे स्थानीय वास्तुकारों में से एक, बालकृष्ण जोशी, जिन्होंने इस विषय को प्रस्तुत किया।
इस स्मारक के निर्माता भी इस अध्ययन दल का हिस्सा थे।
उपेक्षित कच्छ को पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना: हालांकि, अमिताभ बच्चन को लाना
बच्चन को कच्छ का ब्रांड एंबेसडर बनाना मोदी का मास्टरस्ट्रोक था। वह यह बात अच्छी तरह जानते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। बच्चन एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं।
एक ऐसी शख्सियत जिसे पांच साल की उम्र से लेकर सभी आयु वर्ग के लोग प्यार और सम्मान देते हैं।
एक 75 वर्षीय व्यक्ति के लिए एक छोटे बच्चे की तरह। ऐसे महान व्यक्तित्व को प्रचार के लिए लाना।
कच्छ अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, बच्चन साहब ने कहा, “नरेंद्र
मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं कि गुजरात को बढ़ावा देने के लिए मैं जो कुछ भी करूंगा, वह सराहनीय होगा।
नि:शुल्क।" आपको विश्वास नहीं होगा, विज्ञापन अभियान का नारा था: कच्छ
nahin dekha to kuchh nahin dekha (If you haven’t seen Kutch, you haven’t

(मैंने कुछ भी देखा है?), ने इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में अद्भुत काम किया है। लेकिन
मोदी जी ने पहले आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने और निवेश करने में बुद्धिमत्ता दिखाई।
विज्ञापन अभियान शुरू करने से पहले अब तक उपेक्षित विरासत को ठीक करने में।
इसी वजह से यहाँ पर्यटकों का निरंतर प्रवाह बना हुआ है और कच्छ एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है।
यह एक पर्यटन स्थल बन सकता है, हालांकि एक दशक पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था।
एक संभावित पर्यटन केंद्र के रूप में।
रण उत्सव का उदाहरण लीजिए। जब मोदी जी ने इसे पहली बार शुरू किया था, तब हमारे व्यवसाय
चैंबर लोगों से आने की गुहार लगाता था क्योंकि इसके बाद से कोई नहीं आया था।
इसे एक पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था। अब रण उत्सव 90 किलोमीटर तक चलता है।
टेंटों के लिए ऑनलाइन वैश्विक बुकिंग तीन महीने पहले से शुरू हो जाती है।
बुकिंग की इतनी अधिक मांग है कि कई लोगों को मना करना पड़ता है।
यही उनकी खास प्रतिभा है। वे जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ को कैसे बाहर लाया जाए।
हर परिस्थिति का सामना करना, चाहे वह कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो।
बहु-खतरा प्रतिरोधी निर्माण: घरों का पुनर्निर्माण, जो मालिकों द्वारा संचालित था, संभवतः गुजरात पुनर्निर्माण कार्यक्रम का सबसे नवीन पहलू था। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि

पुनर्निर्माण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो, और वास्तविक हितधारक इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाएं।
लेकिन, उस भागीदारी को सार्थक और रचनात्मक बनाने के लिए, लोगों को भूकंपरोधी और गुणवत्तापूर्ण घर बनाने के तरीके के बारे में शिक्षित करना भी आवश्यक था। इसलिए, सरकार ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान को पूरी ताकत से चलाया। 138 मोदी, मुसलमान और मीडिया

कच्छ के लोगों को भूकंपरोधी गुणवत्तापूर्ण निर्माण की बुनियादी बातों का प्रशिक्षण देना। अनिल दास कहते हैं:
जन संपर्क अभियान इतना गहन और व्यापक था कि गांवों के लोग भी इससे प्रभावित हुए।
बच्चों को आवश्यक जानकारी से परिचित कराया गया। उन वर्षों में, प्रत्येक
सड़क के हर कोने पर, हर बस स्टॉप पर, हर सार्वजनिक इमारत और हर जगह बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हुए थे।
नागरिकों के लिए उपयोगी सूचनाओं के संक्षिप्त रूप और आकर्षक चित्र उपलब्ध कराना।
और आरेख। हमने आकलन के लिए 'शेक-टेबल टेस्ट' के वीडियो बनाए।
किसी भी इमारत की भूकंपरोधी क्षमता। वीडियो कैमरों से लैस कई टाटा सूमो वाहन।
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में प्रोजेक्टर लेकर घूमे गए।
उस अवधि के दौरान जब लोगों को आवश्यकता थी, साल में कई बार ऐसा हुआ।
उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि किस प्रकार का निर्माण भविष्य में उन्हें सुरक्षित रखेगा।

देखरेख कर रहा था। सरकार ने इस देखरेख का खर्च वहन किया, लेकिन निर्माण गुणवत्ता में सुधार के रूप में मिले तत्काल लाभों की तुलना में यह लागत बहुत कम थी।
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 139

और इसी के साथ, प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक बहुत बड़ा भंडार भी तैयार हो गया। आज, वे सभी तकनीशियन न केवल गुजरात में, बल्कि पूरे भारत में निर्माण उद्योग में अच्छी तरह से कार्यरत हैं।
अनिल दास कहते हैं, “मोदी ने इस आधार को लगातार मजबूत किया है और आपदा प्रबंधन के अध्ययन और अभ्यास के लिए विशेष संस्थान बनाकर इसे और बेहतर बनाया है। उदाहरण के लिए, व्यापक क्षति और विनाश के कारण राजमिस्त्रियों की भारी मांग थी। वे पड़ोसी क्षेत्रों और राज्यों से आए। लेकिन अधिकांश राजमिस्त्री आपदा-प्रतिरोधी निर्माण और मरम्मत से परिचित नहीं थे। इसलिए, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण युद्धस्तर पर चलाया गया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 29,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को यात्रा और भोजन का खर्च दिया गया और अंत में एक मुफ्त टूल किट प्रदान की गई। इस प्रक्रिया में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, एनसीसीबीएम (सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद) और विभिन्न गैर सरकारी संगठन शामिल थे।”
इसी प्रकार, सरकारी इंजीनियरों के लिए भूकंपरोधी रेट्रोफिटिंग, कंक्रीट और चिनाई संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन और पुलों के भूकंपरोधी डिजाइन पर छह सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। राजकोट, गांधीनगर और भुज में संचालित ये पाठ्यक्रम IIT पवई और IIT कानपुर द्वारा संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, वास्तुकारों के लिए भूकंप इंजीनियरिंग पर एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रकार कठोर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से कौशल विकास ने गुजरात में गहरी जड़ें जमा ली हैं और शिक्षा का स्वरूप बदल दिया है। मोदी को सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और युवा पीढ़ी को अत्याधुनिक कौशल प्रदान करने का गहरा जुनून है, ताकि हमारे युवा विश्व के सर्वश्रेष्ठ युवाओं में गिने जा सकें।
शहरी पुनर्निर्माण के नए दृष्टिकोण: आम तौर पर, नगर नियोजन का काम सरकारी एजेंसियां करती हैं। लेकिन हमारे अधिकांश नगर निगम, जो हमारे कस्बों और शहरों के मामलों का प्रबंधन करते हैं, शहरी केंद्रों की नागरिक और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की योजना बनाने या प्रबंधन करने में विशेषज्ञता की कमी से जूझ रहे हैं। यदि इन कस्बों के पुनर्निर्माण का काम सरकारी योजनाकारों पर छोड़ दिया जाता, तो इसमें कहीं अधिक समय लगता और परिणाम घटिया होता। हालांकि, नौकरशाही नियमों में ढील देकर, मोदी ने कई निजी सलाहकारों, वास्तुकारों और शहरी योजनाकारों को कच्छ के तबाह हुए कस्बों का तेजी से पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। उनका दायित्व था कि वे 140 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

इससे इन पुराने, जीर्ण-शीर्ण कस्बों का चेहरा बदल जाएगा और उन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे की सर्वोत्तम सुविधाएं मिलेंगी।
भूकंप राहत कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में एक नाम पी.के. मिश्रा का है, जो एक विनम्र और अब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के समय वे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। उन्हें जीएसडीएमए का सीईओ नियुक्त किया गया था। कच्छ के पुनर्निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण आज वे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों में से एक बन गए हैं।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] 75 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
2 [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] 2001: [illegible], [illegible] [illegible], (Ann Arbor: [illegible] [illegible] [illegible], 2004), [illegible]. 148-60.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 141

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

तैयार होने के बाद, हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। इसे एक वैधानिक आवश्यकता बना दिया गया।
बड़े पैमाने पर किए गए कार्यों के कारण स्वाभाविक रूप से शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में लोग अपनी संपत्ति का स्वामित्व और/या निवास प्रमाण साबित नहीं कर सके। एक और बड़ी चुनौती उन लोगों को समायोजित करना था जो किराएदार के रूप में रह रहे थे या जिन्होंने दुकानें किराए पर ली थीं; वे उनके मालिक नहीं थे। पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 20 तालुकों में लगभग 1,800 कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया। कुछ मामलों में, उन्हें इंदिरा आवास योजना3 जैसी मौजूदा योजनाओं के माध्यम से समायोजित किया गया। लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला न्यायाधीश को शिकायतें और याचिकाएं प्राप्त करने के लिए लोकपाल घोषित किया गया। मिश्रा कहते हैं कि अक्टूबर 2003 तक, लोकपाल को विभिन्न जिलों से 47,156 याचिकाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 46,182 (99 प्रतिशत) का निपटारा 2004 तक कर दिया गया था।4
सरकार के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों और आपत्तियों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय के माध्यम से राज्य स्तरीय लोकपाल भी नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि यदि कोई नागरिक
3 वही, पृष्ठ 150.
4 वही, पृष्ठ 123.
142 मोदी, मुसलमान और मीडिया

यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या राजनेता के विरुद्ध लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराता है, तो सरकार को उस अधिकारी के बचाव में

वकील उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। सरकार की ओर से कोई तर्क नहीं दिया जाएगा। यदि लोकपाल यह निर्णय लेता है कि सरकार को शिकायतकर्ता को इस प्रकार से मुआवजा देना होगा, तो सरकार बिना किसी आपत्ति के फैसले का पालन करेगी। यह निर्णय मोदी के मुख्यमंत्री बनने के पहले कुछ हफ्तों के भीतर ही लिया गया था।
मोदी कहते हैं, “हमने उस प्रक्रिया के माध्यम से 33,000 समस्याओं का समाधान किया। यह पुनर्निर्माण का इतना विशाल कार्य था कि अंत में हमें शिकायत का एक भी मामला नहीं मिला। संभव है कि जिन लोगों को मुआवजे के रूप में X राशि चाहिए थी, उन्हें केवल Y राशि ही मिली हो। सरकारी योजनाओं में 100 प्रतिशत मुआवजा देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, हम केवल वही दे सके जो स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमत था। किसी ने भी यह शिकायत नहीं की कि उन्हें वादा किया गया मुआवजा नहीं मिला। लेकिन अंत में, ऐसा एक भी मामला नहीं था जहां X राशि पाने के हकदार व्यक्ति को उसका हक न मिला हो।”
गुजरात सरकार ने कच्छ में न केवल आपदा के तुरंत बाद किए गए पुनर्वास कार्यों के लिए, बल्कि कच्छ को एक आकर्षक पर्यटन और निवेश स्थल में बदलने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार और भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार शामिल हैं।
निर्माण का स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण पुनर्निर्माण कार्यक्रम की एक और दिलचस्प विशेषता यह थी कि घरों का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट और गुणवत्ता नियंत्रण तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, ताकि वे आपदा-प्रतिरोधी मानकों के अनुरूप हों। तीन एजेंसियां थीं, अर्थात् एनसीसीबीएम, केंद्रीय भवन अनुसंधान

संस्थान (सीबीआरआई) और आईआईटी पवई, जिन्होंने पुनर्निर्मित भवनों पर गुणवत्ता जांच के लिए एक नियमावली विकसित की। उन्होंने इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किया, जिन्हें साइट पर गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदान की गईं।5 अनिल दास कहते हैं:
शुरुआत में, एक्शन एड हो या स्थानीय संगठन, कई गैर सरकारी संगठन इसके विरोध में थे।
इस बाहरी निगरानी के लिए। उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए और कहा कि उन्हें इसकी आवश्यकता है।
उन्हें निर्माण परियोजनाओं को अपनी इच्छानुसार लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
5 वही, पृष्ठ 151.
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 143

प्रारंभिक चरणों में, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियमों का अत्यधिक उल्लंघन किया गया था।
लेकिन मोदी ने इस अहंकार का मुकाबला करने के लिए एक और चतुर कदम उठाया। उन्होंने पूरी तरह से
जीएसडीएमए को इनकार करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान करना।
प्रत्येक चूककर्ता को उचित सूचना देने के बाद, निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना।
और सुधार का अवसर।
GSDMA द्वारा कानून ध्वस्त किए जाने के बाद अनुपालन ग्राफ में नाटकीय रूप से सुधार हुआ।
5-6 घर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में खरे नहीं उतरे। इससे एक बहुत ही मजबूत प्रतिक्रिया मिली।

संदेश भेजा गया और निर्माण की गुणवत्ता में अचानक सुधार हुआ। साथ ही भूकंपरोधी अनुपालन भी। इसके अलावा, एक बार हर परिवार को मिल जाने के बाद।
उनके पास आवश्यक पर्यवेक्षण कौशल थे और वे जानते थे कि सरकार उनका समर्थन करती है, इसलिए उन्होंने
साथ ही अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया।
मिश्रा कहते हैं, “जनवरी 2004 के अंत तक, 928,369 घरों में से 901,150 घरों की मरम्मत हो चुकी थी और 215,255 घरों में से 186,967 घरों का पुनर्निर्माण पूरा हो गया था। कुल मिलाकर, जनवरी तक 95 प्रतिशत घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम पूरा हो गया था। कुछ मामलों में, राज्य से बाहर रहने वाले मकान मालिकों ने पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। इसलिए पूरे लक्ष्य तक पहुँचने में कुछ कमी रह गई।”6
सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि पुनर्निर्मित सभी घरों का बीमा कराया जाएगा। जीएसडीएमए ने गारंटीड इन्वेस्टमेंट फंड्स (जीआईएफ) के साथ सह-बीमा करने के इच्छुक बीमा कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए। पांच बीमा कंपनियों का चयन किया गया, जिनमें से आईएफएफसीओ-टोकियो एक निजी कंपनी है और अन्य चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां हैं। घरों के बीमा के लिए कंपनियों को अलग-अलग जिले या जिलों के हिस्से आवंटित किए गए।
इस बीमा में आग, भूकंप, विस्फोट, चक्रवात और बाढ़ सहित 14 प्रकार के जोखिम शामिल हैं। यह बीमा दस वर्षों की अवधि के लिए है। सभी घरों का बीमा कराना अनिवार्य था, जबकि अन्य श्रेणियों के घरों के लिए यह वैकल्पिक था। टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा 1 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए प्रीमियम दर 349.10 रुपये निर्धारित की गई थी। लाभार्थी को तीसरी किस्त का भुगतान करते समय प्रीमियम राशि काट

ली जाती थी। आवास इकाई के आकार और स्थान को ध्यान में रखते हुए, बीमा राशि 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक थी।
6 वही, पृष्ठ 126.
144 मोदी, मुसलमान और मीडिया

ग्रामीण या शहरी। जोखिम को कम करने के लिए, अलग-अलग कंपनियों को अलग-अलग जिले/उप-जिले आवंटित किए गए थे।
ग्रामवार बीमित व्यक्तियों की सूचियाँ तैयार की गईं और उन्हें सामूहिक बीमा के रूप में प्रदान किया गया। बीमित व्यक्तियों की सूची तालुका कार्यालय में रखी जाती है और प्रत्येक लाभार्थी को उसके घर के बीमा का प्रमाण पत्र दिया गया है। बीमा प्रमाण पत्र खो जाने पर भी, बीमित व्यक्ति तालुका कार्यालय में उपलब्ध सामूहिक बीमा प्रमाण पत्र के आधार पर अपना दावा कर सकता है। बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली किसी आपदा की स्थिति में, तालुका विकास अधिकारी (टीडीओ) से बीमा दावों से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।7
सरकार ने गुजरात में प्रत्येक छात्र और परिवार के लिए शत प्रतिशत शिक्षा बीमा कवर की व्यवस्था की है। इसके लिए पूरी आबादी के लिए थोक बीमा पॉलिसियां खरीदी गईं, ताकि किसी दुर्घटना में यदि किसी छात्र के माता-पिता का निधन हो जाता है, तो उसकी शिक्षा पूरी तरह से बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो सके। इसका अर्थ यह भी है कि यदि किसी का घर किसी आपदा में नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह भी इस बीमा के अंतर्गत कवर होगा।
कच्छ पुनर्निर्माण: एक वैश्विक आदर्श उदाहरण। बिहार के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों में भी काम कर चुके अनिल दास कहते हैं:

मोदी द्वारा कच्छ पुनर्निर्माण का प्रबंधन बाकी देशों के लिए एक आदर्श बन गया है।
दुनिया का। इसके विपरीत, कोसी के बाद घरों के पुनर्निर्माण का वादा किया गया था।
बाढ़ की तबाही को पांच साल बीत जाने के बावजूद इसका असर अभी भी बरकरार है।
इस क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने बिहार को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया।
काम चल रहा है। आज तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर बिना खर्च किए पड़े हैं और इसे लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
यह आकलन करें कि अब तक उपयोग किए गए धन का कितना सदुपयोग हुआ है।
नीतीश एक नियंत्रक हैं।
वह सनकी इसलिए है क्योंकि वह सत्ता का भूखा है, परिणाम का नहीं।
उसके पास कोई वास्तविक समझ नहीं है।
वह अपने काम को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, और अपने अधिकारियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है।
परिणामस्वरूप,
बिहार की शासन व्यवस्था संकट में है। उसके अधिकारियों को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है।
लोग मोदी पर नियंत्रण के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का आरोप लगाते हैं। लेकिन उनके नियंत्रण तंत्र
वह परिणामों और समयसीमाओं को लेकर अत्यधिक सचेत रहता है, इसलिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते।
और वह उन पर बहुत बारीकी से नज़र रखता है। हालाँकि, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद वह चला जाता है।
उसके नौकरशाहों को सहमत कार्यों को अपने तरीके से लागू करने की पूरी छूट है।

सर्वश्रेष्ठ खोजें। मोदी उन्हें काफी छूट देते हैं और उन्हें सफल होने के लिए पूरी स्वतंत्रता और समर्थन प्रदान करते हैं।
वह नवाचारी हैं। साथ ही, वह स्थायी संस्थागत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार से प्रयास किए जाएं ताकि गुजरात में व्यवस्थित परिवर्तन हो सके।
7 वही, पृष्ठ 153.
भुज कैसे अपनी राख से पुनर्जीवित हुआ 145

आपदा प्रबंधन को संस्थागत रूप देना: लेकिन मोदी केवल उस एक आपदा को अच्छी तरह से संभालने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन की एक सक्षम प्रणाली को संस्थागत रूप दिया, जिसे वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह लगातार अपनी क्षमताओं को उन्नत करती रहती है।
गुजरात की आपदा प्रबंधन प्रणाली की कार्यक्षमता की परीक्षा 2005 में सूरत में आई भीषण बाढ़ के दौरान हुई। उनकी आपातकालीन टीम ने बिजली की गति से कार्रवाई की। गुजरात में स्थापित आपदा प्रबंधन संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक माना जाता है। मोदी कहते हैं:
अटल जी की सरकार के दौरान, हमें आपदा राहत के लिए 200 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था।
प्रबंधन संस्थान। लेकिन यूपीए सरकार, जो सत्ता में आई।
बाद में, उन्होंने उस वादे का पालन नहीं किया। इसलिए, हमने इसे अपने द्वारा बनाया।
अपनी ताकत से। हमने इस विषय पर पहले ही पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित कर ली थी।
दुनिया के बाकी हिस्सों को व्याख्यान देना और पढ़ाना।

उदाहरण के लिए, भारत के कई राज्यों को यह पता ही नहीं था कि वे किस श्रेणी में आते हैं।
जी5 जोन भूकंप के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील है।
इसलिए, हमने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया ताकि उन्हें शिक्षित किया जा सके। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी दी है। यह केवल
उस कार्यशाला के बाद विभिन्न महानगरों के प्रशासनों ने कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए।
इस दिशा में रचनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
जब नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, तब मैंने उनसे कहा था
उन्हें यह बताया गया कि हम रेलवे कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में रेलवे की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन, जब अटल
जी की सरकार बदली, सब कुछ ध्वस्त हो गया। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण मॉड्यूल
हमने जो प्रबंधन प्रणाली विकसित की थी, उसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता था। लेकिन,
पिछले नौ वर्षों से यूपीए सरकार ने इसे सेवा करने की अनुमति नहीं दी है।
क्योंकि वे गुजरात को शत्रु राज्य मानते हैं।
हालांकि, यूपीए सरकार ने नकल करके हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा दी।
गुजरात आपदा प्रबंधन कानून को राष्ट्रीय कानून बनाए बिना लागू करने का प्रावधान है।

पूर्ण विराम या अल्पविराम में बदलाव करना। उनकी टीम मुझसे कुछ बार मिलने आई थी।
जब 2004 में दक्षिण भारत में सुनामी आई, तो उनकी आपदा प्रबंधन टीम ने
हमारे पुनर्निर्माण मॉडल से सीखने के लिए वे गुजरात में 15 दिन बिताने भी आए थे।
जीवन तहस-नहस हो गए।
चूंकि गुजरात ने आपदा प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता को लगातार निखारा है, इसलिए भारत या विश्व स्तर पर कहीं भी आपातकालीन स्थिति आने पर यह बहुत काम आती है। जब जापान में भीषण सुनामी आई, तब गुजरात ने 146 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

भारत सरकार ने जापान को सबसे पहले सूचित किया कि वे सहायता दल भेजने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसे दल विदेशी देशों में केवल भारत सरकार के माध्यम से ही जा सकते हैं और गुजरात यूपीए की योजनाओं में फिट नहीं बैठता था। जापान में एक भीषण परमाणु आपदा हुई थी। यदि गुजरात के दल को जाने की अनुमति मिल जाती, तो वे ऐसी आपदाओं से खुद को बचाने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते थे। लेकिन भारत सरकार को गुजरात का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उनके दल को जाने की अनुमति नहीं दी गई।
गुजरात भारत का पहला राज्य था जिसने किसी स्थान पर त्रासदी होने की स्थिति में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, यह निर्धारित करने के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया। राज्य ने विद्यालयों की सुरक्षा का पूर्ण ऑडिट भी किया। इसने बच्चों को क्षेत्र में किसी अन्य आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया। क्षमता निर्माण की प्रक्रिया सतत है। प्रत्येक नगर पालिका के अग्निशमन विभाग के पास अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण हैं। आज भी, सभी स्कूली

बच्चों के लिए आग दुर्घटनाओं सहित वार्षिक प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। क्षमता निर्माण के लिए, गुजरात ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें चपरासी और चालक भी शामिल हैं, को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया है। इसकी टीमों ने आपदा प्रबंधन प्रणालियों का अध्ययन करने और उन्हें अपने देश में लागू करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की है। आज गुजरात में आपदा प्रबंधन के लिए बेहतरीन उपकरण मौजूद हैं, जिनमें स्लैब कटर और अन्य सभी उपकरण शामिल हैं। लेकिन, इन सबके साथ-साथ मोदी जी की त्वरित प्रतिक्रिया भी एक अहम भूमिका निभाती है। मुझे याद है, जब मैं वापी जिले से गुजर रहा था, तब राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हो गई थी। लेकिन जिस कलेक्टर से मेरी मुलाकात तय थी, उन्होंने अपना सारा काम रद्द कर दिया और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए ताकि वे गांधीनगर को पीड़ितों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की प्रत्यक्ष रिपोर्ट दे सकें।
मोदी, जो आपदा प्रबंधन प्रणाली को इस क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अनुरूप बनाए रखने में व्यक्तिगत रूप से काफी रुचि रखते हैं, कहते हैं:
इस आपदा को आकार देने में गुजरात सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। श्रीलंका द्वारा तैयार किया गया प्रबंधन मॉड्यूल। इसी तरह, ईरान ने 50-60 प्रतिशत लिया।
भूकंप के बाद उनके पुनर्वास उपायों के लिए हमारे मॉड्यूल का प्रतिशत
इस क्षेत्र में। अफगानिस्तान में तालिबान-बाद के पुनर्वास कार्य इसी पर आधारित थे।
गुजरात सरकार के एक अधिकारी द्वारा तैयार की गई योजना के आधार पर। तालिबान ने

कई घर नष्ट हो गए और हमारे एक अधिकारी ने कार्रवाई की योजना तैयार की।
उनके प्रभावी पुनर्वास के लिए। यहां तक कि चीनी सरकार ने भी एक भेजा।
हाल ही में एक टीम ने गुजरात मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया।
भुज कैसे अपनी ही राख से पुनर्जीवित हुआ 147

गुजरात टीम के साथ अपने-अपने अनुभव साझा करने के लिए।
आपदा प्रबंधन संस्थान ने वैश्विक ख्याति अर्जित की है। इस विषय में
इसे सभी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।
गुजरात में। प्रत्येक संकाय चाहे जिस भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो, उन्हें उसमें शामिल करना होगा।
आपदा प्रबंधन को एक अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया गया है।
राज्य ने यह कार्य अपने हाथ में लिया है।
इसके लिए गहन मानव संसाधन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
यह एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। हम चल रहे नए घटनाक्रमों का अध्ययन करते हैं।
घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखें और उन्हें अपनी प्रणाली में शामिल करने का प्रयास करें। जब भी
दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आए, गुजरात उन पहले राज्यों में से एक है जिन्हें मदद मिलती है।
उनके पास सबसे आधुनिक तकनीक और उचित व्यवस्था होने के कारण उन्हें बेहतर जानकारी प्राप्त होती है।
एक प्रणाली लागू है, जो 24x7 चालू रहती है।

मोदी कहते हैं कि 2003 में उन्होंने सभी राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते गुजरात में दो पीएचडी छात्रों को शोध के लिए भेजें—ताकि भूकंप के बाद के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सके—शुरुआती बचाव कार्य से लेकर बाद में राहत और पुनर्वास तक। किसी भी अन्य देश में इस विषय पर 100 पीएचडी शोध हो चुके होते। वे कहते हैं, “मैंने उन छात्रों के दो साल के रहने-सहने सहित पूरे खर्च की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी। मेरा विचार था कि अगर ऐसा शोध होता, तो हमें पूरी प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझने का अवसर मिलता। सकारात्मक पहलू दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते; और अगर हमें नकारात्मक पहलू मिलते, तो वे भविष्य में आवश्यक सुधार करने में हमारी मदद करते। मुझे यह कहते हुए खेद है कि कोई नहीं आया। किसी भी राज्यपाल ने इसे प्राथमिकता का मुद्दा नहीं माना।”
मोदी के विरोधियों ने आश्वासन दिया है कि गुजरात के बाहर इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। चूंकि हमारे शिक्षा जगत और सामाजिक विज्ञान समुदाय ने मोदी-विरोधी प्रचार को गहराई से आत्मसात कर लिया है, इसलिए किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक ने कच्छ के अपने ही अवशेषों से उठकर एक निर्वाह अर्थव्यवस्था से भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की कहानी का अध्ययन करने की जहमत नहीं उठाई। दुर्भाग्य से, भाजपा ने भी इस कहानी को बाकी भारत तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई।

अध्याय 8

कांग्रेस में "तूफान" को लेकर दहशत
NaMo के लिए मुस्लिम समर्थन
फरवरी 2002 में राजकोट से मोदी का पहला चुनाव।

समाज के कल्याण के लिए अच्छा काम करने वाले माने जाने वाले 28 मुस्लिम संगठनों द्वारा भाजपा को समर्थन देने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर शोक का माहौल है।
9 फरवरी, 2002, सांझ टाइम्स
कांग्रेस नेता किस चेहरे के साथ मुस्लिम समुदाय से वोट मांगेंगे? अगर उन्होंने पिछले 35 सालों में मुस्लिम समाज के लिए एक भी काम किया है, तो उन्हें दो दिनों के भीतर उसका हिसाब देना चाहिए। राजकोट का राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय भाजपा सरकार द्वारा राजकोट के मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए अच्छे कामों से भली-भांति परिचित है। कांग्रेस नेताओं को अब यह एहसास हो गया है कि जब वे मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसंपर्क के लिए जाते हैं, तो मुस्लिम समुदाय उनका किसी भी तरह से स्वागत नहीं करता।
कादरभाई सालोट ने सांझ टाइम्स, फरवरी 11, 2002 में उद्धृत किया जिन बूथों पर 70 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोट हैं, वहां भाजपा काफी आगे है... ऐसा लगता है कि विधानसभा उपचुनाव में नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का बड़ा हाथ रहा है। 25 फरवरी 2002 को मोदी की चुनावी जीत पर सांझ टाइम्स की रिपोर्ट

जो लोग कांग्रेस और वामपंथी दुष्प्रचार पर विश्वास करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी एक "ध्रुवीकरणकारी" व्यक्ति हैं और उन्हें गुजरात में आक्रामक उग्रवादी हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदलने

के लिए भेजा गया था—जिसमें अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों का व्यवस्थित क्रूर दमन शामिल है—उन्हें 4 अक्टूबर, 2001 को मुख्यमंत्री नियुक्त होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर गुजरात विधानसभा के लिए उनके चुनाव अभियान की रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी, 2002 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और पहली बार चुनाव लड़ा।
NaMo को मिल रहे मुस्लिम समर्थन की "तेजी से बढ़ती लहर" पर कांग्रेस में दहशत 149

राजकोट से चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने पहले ही इतने शासन सुधार शुरू कर दिए थे कि विभिन्न स्वार्थी तत्वों के लिए वे एक खतरा बन गए थे। इसलिए इन सभी ताकतों ने मोदी को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया। आगे का विवरण यह स्पष्ट करेगा कि उनके खिलाफ चलाया गया अभियान, प्रधानमंत्री पद की दौड़ से मोदी को बाहर करने के लिए चलाए जा रहे वर्तमान घिनौने अभियान से बिल्कुल अलग नहीं था। कांग्रेस ने मोदी को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए 'करो या मरो' का अभियान चलाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कई नए रिकॉर्ड बनाए थे, खासकर भूकंप पुनर्वास के क्षेत्र में। उनकी हताशा तब चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने देखा कि मुसलमान भी कांग्रेस छोड़कर मोदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
नामांकन दाखिल करने से पहले, मोदी ने राजकोट के लोगों से आह्वान किया कि वे उन पर जताए गए भरोसे पर खरे उतरेंगे। कांग्रेस द्वारा उन पर लगाए गए विभिन्न आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मैं लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं। हम ऐसा नहीं करते।

नकारात्मकता में विश्वास रखें। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कांग्रेस हार नहीं मान सकती।
इसकी नकारात्मकता। यह केवल हमला करना और विरोध करना जानता है— उन्होंने विरोध किया है।
आतंकवाद निवारण अध्यादेश (POTO) की शुरुआत के बाद, उन्होंने
लोक कल्याण मेलों का विरोध किया, समरस गाँव का विरोध किया, सुदृढ़ीकरण का विरोध किया
ग्राम सभाओं के बारे में। क्या ऐसी नकारात्मकता गुजरात के लिए अच्छी होगी? क्या यह अपराध है?
क्या सरकार को सक्रिय होकर कुशलतापूर्वक काम करना चाहिए? मतदाताओं को यह मौका देना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब... मैं राजकोट के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि
आप मुझे जो भी कार्य सौंपेंगे, मैं उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
परिणाम...
अपनी यात्राओं के दौरान मैंने कई जानकार मुसलमानों से सुना था कि मोदी के कई मुस्लिम संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध हैं। लेकिन नकारात्मक प्रचार से प्रभावित होने के कारण, मैं उनके पहले चुनाव अभियान की खबरों से उभरने वाली बिल्कुल अलग तस्वीर के लिए तैयार नहीं था। विरोध का सामना करने के बजाय, वास्तव में विभिन्न मुस्लिम समूहों और संगठनों के बीच नरेंद्र मोदी के समर्थन की एक विशाल लहर थी। इससे कांग्रेसियों में घोर दहशत फैल गई क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी से उसका सबसे वफादार और स्थायी वोट बैंक छीन रहे थे। मोदी ने वह कर दिखाया जो भाजपा के सबसे उदार चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए थे। हालांकि मुसलमान वाजपेयी को व्यक्तिगत रूप से पसंद

करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें या उनके नेतृत्व वाली भाजपा को वोट नहीं दिया।
150 मोदी, मुसलमान और मीडिया

कांग्रेस में अपना पूरा जीवन बिताने वाले सम्मानित मुस्लिम नेताओं ने मोदी के मुख्यमंत्री बनने पर पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल होने लगे। इसलिए, कांग्रेस नेताओं ने मोदी को हराने के लिए अभूतपूर्व आक्रोश और हताशा के साथ प्रतिक्रिया दी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस कहानी पर आऊं, आइए उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके तहत मोदी अपने पहले चुनावी मुकाबले के लिए राजकोट पहुंचे।
राजकोट निवासी विजयभाई रूपाणी, जो वर्तमान में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के सचिव हैं, ने नरेंद्र मोदी के पहले चुनाव अभियान के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे मोदी को तब से अच्छी तरह जानते हैं जब मोदी गुजरात में भाजपा के महासचिव थे। नरेंद्र मोदी के पहले चुनाव के बारे में उन्होंने मुझे जो जानकारी दी, वह इस प्रकार है।
नरेंद्रभाई को बिना किसी पूर्व अनुभव के गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था।
कोई भी चुनाव लड़ने के बावजूद। लेकिन उन्हें किसी न किसी जगह से चुनाव जीतना ही था।
दूसरा छह महीने के भीतर। इसलिए हमारी पार्टी में इस बारे में चर्चा हुई।
नरेंद्रभाई को उम्मीदवार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। कई लोग थे।
जो चाहते थे कि वह उनके संबंधित ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ें। लेकिन

पार्टी उनके लिए एक प्रमुख शहरी निर्वाचन क्षेत्र चाहती थी। हमारी पहली पसंद थी
अहमदाबाद शहर।
मैंने रूपाणी से पूछा कि क्या मोदी के विरोधियों द्वारा लगाए गए इस आरोप में कोई सच्चाई है कि मोदी और हरेन पांड्या के बीच मतभेद इसलिए हुआ क्योंकि पांड्या ने मोदी के लिए अपनी सीट खाली करने से इनकार कर दिया था? यह विजयभाई का बयान है, जिसकी पुष्टि कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी की है:
यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि नरेंद्रभाई ने जबरदस्ती करने की कोशिश की।
हरेन पांड्या बाहर। नरेंद्रभाई ने साफ कर दिया कि वह किसी से कुछ नहीं पूछने वाले।
उन्होंने पांड्या से कभी भी अपनी सुरक्षित सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा।
उनके लिए। एलिस ब्रिज से मोदी को मैदान में उतारने का फैसला संयुक्त रूप से लिया गया था।
भाजपा और आरएसएस, क्योंकि इसे पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था।
मुझे लगा कि चूंकि नरेंद्रभाई अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे, वह भी मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए
उन्हें सुरक्षित सीट दी जानी चाहिए।
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही इस फैसले की जानकारी पंड्या को दी थी।
नरेंद्रभाई ने अहमदाबाद के एलिस ब्रिज में कई वर्षों तक काम किया था।
अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहते हुए उनके वहां के कई लोगों से घनिष्ठ संबंध थे।

NaMo 151

शहर में हर किसी को लगता था कि उन्हें मोदी जी के लिए अपना योगदान देना चाहिए था। पूरी पार्टी,
नरेंद्र भाई समेत कई लोगों ने उनसे विनती की। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
नरेंद्रभाई के खिलाफ पहले दिन से ही। वास्तव में, उन्होंने उन्हें भड़काने के लिए हर संभव प्रयास किया।
उन्होंने अपने पूरे पटेल समुदाय को मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ नष्ट कर देंगे।
पटेलों का प्रभाव। लेकिन पटेलों का एक बड़ा वर्ग नरेंद्रभाई का समर्थक था।
क्योंकि उन्होंने जातिगत मुद्दा उठाने से परहेज किया और सामूहिक कल्याण की बात की।
हम सभी गुजराती हैं। 2012 के चुनाव में भी हमें बड़ा समर्थन मिला था।
सौराष्ट्र के पटेल।
152 मोदी, मुसलमान और मीडिया

15 फरवरी, 2002 को सांझ टाइम्स में एक समाचार रिपोर्ट में लिखा गया: “मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से नाराज केशूभाई पटेल का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है… भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें मनाने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने टस से मस होने से इनकार कर दिया…” रूपाणी के विवरण को आगे बढ़ाते हुए:
चुनाव फरवरी 2002 में हुए थे और यही वह महीना है जिसमें...
गोधरा हत्याकांड हुआ। मुस्लिम समुदाय के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे।
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्रभाई ने कई विशाल सभाओं को संबोधित किया था।

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बैठकें। राजकोट में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है।
दाऊदी बोरा जो हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। दाऊदी बोरा युवाओं ने नरेंद्रभाई के समर्थन में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया।
वे अपने पारंपरिक परिधानों में पूरे शहर में घूम-घूमकर लोगों से वोट देने का आग्रह कर रहे थे।
नरेंद्रभाई... और निश्चित रूप से उन्हें मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिला।
नरेंद्रभाई के चुनाव प्रचार अभियान की एक और उल्लेखनीय बात यह थी कि उसमें
इसमें कोई नकारात्मकता नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला भी नहीं किया। वास्तव में, उन्होंने
मैं शुरुआत में कहता, “मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ आया हूँ।”
मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चुनाव केवल जीत या हार का मामला नहीं है।
हारना। लेकिन चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है।
इसीलिए मैं इस चुनाव में लड़ने आया हूँ। मैं यहाँ हराने या बर्बाद करने नहीं आया हूँ।
किसी का भी भाग्य बदल सकता है। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि यदि राजकोट के लोग वोट देंगे तो
मैं तुम्हें कभी भी मेरी वजह से शर्म से सिर झुकाने नहीं दूंगा। उन्होंने उस चुनाव के दौरान बहुत ही समवेदांशी भाषण दिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

नरेंद्रभाई किसी भी समुदाय पर हमला कर रहे हैं या मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी दोहराया कि वे न तो धार्मिक आधार पर ऐसा करेंगे और न ही सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करेंगे।
not will he let anyone do it (mein khata nahin hoon aur na kisi ko khane
डूंगा)। उस समय उन्होंने आम जनता के सामने जो छवि प्रस्तुत की, वह यह है कि
आज तक बरकरार है।
लेकिन वे चुनाव प्रचार के लिए चार दिनों से अधिक का समय नहीं दे सके।
राजकोट। वह सप्ताह में एक बार एक दिन के लिए आते थे। वह इससे अधिक समय नहीं दे सकते थे।
समय की कमी के कारण क्योंकि वह कच्छ और अन्य क्षेत्रों में भूकंप पुनर्वास कार्यों में व्यस्त थे।
सरकारी काम।
विजयभाई रूपाणी का यह विवरण मेरे अब तक के विश्वास से इतना भिन्न था कि मैंने स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समकालीन समाचार रिपोर्टों की जाँच करने का निर्णय लिया, जिनमें उस अभियान के दिन-प्रतिदिन के घटनाक्रमों का विवरण दिया गया था। ये रिपोर्टें मोदी को बदनाम करने के उस अभियान की उत्पत्ति और मूल कारणों का बहुत ही गहन विश्लेषण प्रदान करती हैं, जो आज तक जारी है।
NaMo 153 के लिए मुसलमानों के "तेजी से बढ़ते" समर्थन पर कांग्रेस में दहशत

प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने मोदी के लिए प्रचार किया। राजकोट के एक प्रमुख मुस्लिम नेता कादरभाई सलोट ने मोदी के लिए मुस्लिम समूहों का समर्थन जुटाने और मुस्लिम वोटों की दिशा उनके पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, राजकोट के एक समाचार पत्र, सांझ टाइम्स ने 6 फरवरी, 2002 को अपने पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित समाचार प्रकाशित किया: “कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों के कारण, कादरभाई सलोट और उनके सहयोगियों ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी के 200 से अधिक मुस्लिम कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। समय की कमी के बावजूद कादरभाई नए हंगामे के मूड में हैं।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है:
गुजरात राज्य के उपाध्यक्ष कादरभाई सलोट के प्रयासों के कारण अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजकोट के महासचिव, ऐजाज़ बापू बुखारी और अल्ताफभाई सुमा - और अधिक
200 से अधिक युवा मुस्लिम केसरिया (भगवा) रंग में रंग गए... कादरभाई
वह कम समय में कुछ बड़े काम करने के मूड में है।
भाजपा में शामिल हुए 200 मुसलमानों का स्वागत और अभिनंदन किया गया।
विजयभाई रूपानी सहित वरिष्ठ नेता।
यह उल्लेखनीय है कि मोदी द्वारा राजकोट से नामांकन पत्र दाखिल करने के 5 दिनों के भीतर ही कांग्रेस से मुसलमानों का पहला पलायन हुआ। 9 फरवरी, 2002 को सांझ टाइम्स ने अपने पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित समाचार प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था: “मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 सामाजिक सेवा उन्मुख मुस्लिम संगठनों का समर्थन मिला: मुस्लिम संगठनों के इस समर्थन को लेकर कांग्रेस पार्टी में गहरी हलचल।” आगे इसमें कहा गया है:

कांग्रेस पार्टी के भीतर शोक का माहौल है।
28 मुस्लिम संगठनों द्वारा भाजपा को समर्थन की घोषणा, जो कि कथित तौर पर
अपने समाज के कल्याण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। [यह घटना] एक बैठक में घटी।
यह आयोजन मुस्लिम समुदाय के एक बेहद लोकप्रिय नेता कादरभाई के आवास पर हुआ।
सलोट, जो गुजरात राज्य अल्पसंख्यक वित्त समिति के उपाध्यक्ष भी हैं,
विकास विभाग।
पिछले तीन दिनों से कांग्रेस नेता मुस्लिम समुदायों में जा रहे हैं
लोगों से संपर्क करने के लिए मोहल्लों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इस तथ्य से चिंतित है।
मुस्लिम समुदाय उन्हें अच्छा प्रतिसाद नहीं दे रहा है। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि इस बार उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलने वाला है।
मुस्लिम समुदाय द्वारा नरेंद्रभाई को दिए गए समर्थन की घोषणा में,
हुसैन कमेटी, हैदर सबील कमेटी, जाम जाम सबील कमेटी, एकता
वार्ड नंबर 1 की कमेटी, हुसैनी आवाज कमेटी, जाम जाम सबील 154 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

पंजीताल सबील कमेटी, आशिक हुसैन नियाज कमेटी,
वार्ड नंबर 14, यूनिट ब्लड डोनेशन कमेटी, मंज़ूर का युवा मुस्लिम। हुसैन वॉयस कमेटी, ख्वाजा गरीब-ए-नवाज कमेटी, एकता समूह

वार्ड संख्या 11 और वार्ड संख्या 16 की लग्नोत्सव आयोजन समिति के साथ-साथ
कई अन्य समितियां भी एक विशाल सभा में शामिल हुईं।
इस बैठक में उन सदस्यों ने भाग लिया जिन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपना समर्थन घोषित किया।
नरेंद्र मोदी ने भाजपा द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के बारे में जानकारी साझा की।
इसके कार्यकर्ता मुस्लिम मोहल्लों में घर-घर जाकर सहायता प्रदान करते हैं।
उनके लिए हज की उचित व्यवस्था की गई है। [इसके अलावा, भाजपा ने] अल्पसंख्यकों के बोर्ड को निगम में परिवर्तित किया गया, और कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई।
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, 571 मुसलमानों की मदद के लिए करोड़ों रुपये के ऋण प्रदान किए गए।
अपने पैरों पर खड़े होने के लिए।
[मुस्लिम नेताओं] ने सार्वजनिक रूप से सदस्यों को ले जाने की जिम्मेदारी ली
मुस्लिम समुदाय को उनके क्षेत्र के मतदान केंद्रों तक ले जाएं। कादरभाई सलोट
उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी मुसलमान भाजपा को वोट देंगे; और यह बात साबित हो जाएगी।
जब उन वार्डों में वोटों की गिनती हो जाती है। इसी तरह राजकोट का नाम सामने आता है।
और मुस्लिम समाज रोशन होगा।
11 फरवरी 2002 को सांझ टाइम्स ने खबर दी कि कादरभाई सलोट ने कांग्रेस पार्टी को यह चुनौती दी: “अगर राजकोट के कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम समाज के लिए एक भी काम किया है, तो वे दो दिनों के भीतर

इसकी घोषणा करें, अन्यथा मैं भाजपा द्वारा किए गए [अच्छे] कार्यों की घोषणा कर दूंगा।” रिपोर्ट में कादरभाई के हवाले से कहा गया है: गुजरात राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास के उपाध्यक्ष
विभाग के कादरभाई सलोट ने कांग्रेस से तीखा सवाल पूछा है। राजकोट के नेताओं का कहना है, “कांग्रेस नेता किस मुंह से यह मांग करेंगे?”
मुस्लिम समुदाय के वोट? अगर उन्होंने एक भी काम किया है तो... पिछले 35 वर्षों में मुस्लिम समाज को अपने कार्यों का हिसाब दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए।
मैं कांग्रेस के उन नेताओं को चेतावनी देता हूं, जो शुभचिंतक/सहानुभूतिवादी होने का दिखावा करते हैं।
मुस्लिम समुदाय के बारे में, कि राजकोट का राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय अच्छी स्थिति में है
भाजपा सरकार द्वारा उनके लिए किए गए अच्छे कार्यों की मात्रा से अवगत।
राजकोट। कांग्रेस नेताओं को अब यह एहसास हो गया है कि जब वे जनसंपर्क के लिए जाते हैं तो
मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम समुदाय उनका किसी भी तरह से स्वागत नहीं कर रहा है।
इसे देखकर कांग्रेस नेताओं को यह सीख लेनी चाहिए कि उनकी कोई भी रणनीति कारगर नहीं है।
मुसलमानों के बीच सफलता मिलने वाली है।"
NaMo 155 के लिए मुसलमानों के "तेजी से बढ़ते" समर्थन पर कांग्रेस में दहशत

कांग्रेस के लिए "भूकंप जैसी" स्थिति: जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोदी भूकंप से प्रभावित

लोगों के पुनर्वास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को जनता की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में पूरी तरह से व्यस्त थे, इसलिए वे राजकोट में चुनाव प्रचार के लिए केवल सप्ताहांत में ही आते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने पक्ष में जबरदस्त जनसमर्थन का माहौल बना दिया। यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं भी सार्वजनिक सभाओं में उनका समर्थन करने के लिए शामिल हुईं। 11 फरवरी, 2002 को सांझ टाइम्स ने इस बारे में यह लिखा था:
राजकोट विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर माहौल गरमा रहा है। शनिवार और रविवार को चुनाव प्रचार का दूसरा चरण। भाजपा उम्मीदवार और
मुख्यमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने लोगों के बीच उत्साह की लहर फैलाई।
राजकोट के प्रबुद्ध मतदाता। प्रत्येक छोटे 12-14 वार्ड बैठकों में और
सामुदायिक बैठकों में बुद्धिमान और प्रबुद्ध जनता उपस्थित थी। उन्होंने एक
कमल के लिए मतदान का संकेत और मुख्य उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीत दिलाना
मंत्री जी ने सोनी समाज की सभाओं में तूफानी प्रचार करते हुए कहा, मोदी ने दर्जी समाज, क्षत्रियों, बुद्धिजीवियों आदि से अपील की कि वे
भाजपा को विजयी बनाएं।
पहली बार बोहरा मुस्लिम बहनों ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
और लोगों से देश के प्रति वफादार रहने की अपील की।
13 फरवरी को उसी अखबार में निम्नलिखित शीर्षक के साथ एक समाचार प्रकाशित हुआ: “मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक बड़ा

मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस सम्मेलन को रोकने के सभी प्रयास विफल रहे। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे 50 मुस्लिम नेता भाजपा में शामिल हो गए।” समाचार में आगे कहा गया है:
रामनाथपाड़ा में घांची समाज का वाड़ा में विशाल सम्मेलन
आयोजित किया गया। विभिन्न मुस्लिम समुदायों के प्रमुखों की उपस्थिति में और
मुस्लिम समाज के सम्मानित नेताओं और हजारों युवा मुसलमानों ने इस सम्मेलन ने कांग्रेस के भीतर भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी।
इसका आयोजन गुजरात माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष कादरभाई सलोत ने किया था
वित्त एवं विकास विभाग। [मेरे द्वारा ज़ोर दिया गया]
इस सम्मेलन में कई मुस्लिम नेता शामिल हुए, जिनका 40 वर्षों से लंबा संबंध रहा है।
कांग्रेस से अलग होकर, उन्होंने विभाजनकारी नीतियों के कारण पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
कांग्रेस पार्टी की राजनीति। इन नेताओं ने दशकों तक 156 मोदी, मुसलमानों और मीडिया को लामबंद किया था।

मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। भाजपा में शामिल होने वालों ने एक अपील जारी की है।
मुसलमानों से आगामी चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करने का आह्वान किया और संकल्प लिया कि
भाजपा को वोट दें। इस पर बैठक में मौजूद मुसलमानों ने बहिष्कार की घोषणा कर दी।

जोरदार तालियों और नारों के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया गया...
मोदी के वादे और मुस्लिम प्रतिक्रिया: मैंने पहले ही नरेंद्र मोदी के उस संदेश का उल्लेख किया है जो उन्होंने नामांकन दाखिल करने के दिन राजकोट के लोगों को दिया था। उसमें जरा भी नकारात्मकता नहीं थी। यहां तक कि अपने बाद के भाषणों में भी उनका ध्यान विकास के मुद्दों और समावेशी विकास एजेंडा पर केंद्रित था। धार्मिक या किसी अन्य प्रकार के ध्रुवीकरण की वकालत करने के बजाय, मोदी ने या तो अपने द्वारा शुरू किए गए नए शासन एजेंडा की बात की या फिर गर्वित गुजरात के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया।
14 फरवरी, 2002 के संझ टाइम्स ने उस सप्ताहांत उनके भाषण की रिपोर्ट इस प्रकार प्रकाशित की: “नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गुजरात को नंदनवन (वह पौराणिक वन जहाँ कृष्ण ने लीला की थी) बनाया जाएगा।” समाचार रिपोर्ट में आगे कहा गया है:
राजकोट से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्रभाई मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
वार्ड संख्या 16 में आयोजित एक विशाल जनसभा (मानव समन्वय) के बीच, उन्होंने संबोधित किया।
पोपटपरा चौक पर आयोजित एक भव्य सभा में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि गुजरात की सूखी भूमि, प्यासे लोगों, जानवरों और पक्षियों के लिए
गुजरात के लिए, "नर्मदा का नीर" (नर्मदा का जल) आदर्श समाधान है। गुजरात के 5 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए मैं सिर झुकाकर भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता हूँ।
अन्य बातें मेरे लिए गर्व का विषय होंगी। यह कहते हुए उन्होंने व्यापकता की बात की।

गुजरात का सर्वांगीण विकास। इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 45 वर्षों में जो करने में विफल रही,
भाजपा ने 45 दिनों में यह कर दिखाया है। बिछोलिया प्रथा (परंपरा) का त्याग कर।
कांग्रेस सरकार के दौरान दलाली के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि
लोक कल्याण मेलों के माध्यम से लोगों तक पूरा भुगतान पहुंचता है.... हम नहीं देखेंगे
गुजरात के समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में हम पीछे हट रहे हैं। यह कहते हुए
भाजपा के हाथों में गुजरात का भविष्य अत्यंत गौरवशाली है। मुख्यमंत्री ने अपने विशिष्ट अंदाज में कहा कि भाजपा सरकार ने सिखाया है
षड्यंत्रकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए यह एक उपयुक्त सबक है...
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा नीर गुजरात का सपना है। मध्य प्रदेश सरकार फैसले लेने में आनाकानी कर रही है।
यह मुद्दा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर नर्मदा का पानी गुजरात में आ जाता है, तो भाजपा
सरकार को मजबूती मिलेगी... लेकिन इस बार आदरणीय अटल जी के हस्तक्षेप से।
कांग्रेस में NaMo को मिल रहे मुस्लिम समर्थन की "तेजी से बढ़ती लहर" पर दहशत फैल गई 157

और गुजरात को साकार करने में मदद करने के लिए नर्मदा के संबंध में उन्होंने जो उल्लेखनीय निर्णय लिया।

इस राज्य को नंदनवन में बदलने के उसके सपने ने वाकई एक बड़ा बदलाव ला दिया है...
16 फरवरी को, सांझ टाइम्स ने एक शीर्षक में यह घोषणा करके कांग्रेस के घावों पर और नमक छिड़का: “नरेंद्रभाई के लिए समर्थन सभा - मुस्लिम समुदाय ने एक शक्तिशाली जनसभा का आयोजन किया।” इस सभा में मुस्लिम नेताओं ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय की लंबे समय से लंबित मांगों, जैसे कि अतिरिक्त कब्रिस्तान के लिए भूमि और मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उपायों को कितनी तेजी से पूरा किया है। रिपोर्ट से उद्धृत:
मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के समर्थन में, मुस्लिम भाइयों और बहनों
एक विशाल मुस्लिम सम्मेलन (सार्वजनिक सभा) के लिए एकत्रित हुए भोमेश्वर, कादरभाई सलोट के प्रमुख क्षेत्र में, उपाध्यक्ष
राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग।
इस सम्मेलन में कादरभाई ने वहां मौजूद मुसलमानों से कहा कि भाजपा सरकार ने प्रत्येक हज यात्री को 20,000 रुपये की सब्सिडी दी है और इसके बजाय अहमदाबाद से सीधे जेद्दा के लिए उड़ानों की व्यवस्था की जाए।
हाजियों को मुंबई होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा, मुस्लिम महिलाओं को भी
15 अलग-अलग केंद्रों में सिलाई, जरी के काम आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इस सम्मेलन में मीर जमात के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
और उन्होंने नरेंद्रभाई के प्रति खुले तौर पर समर्थन व्यक्त किया।

18 फरवरी 2002 को सांझ टाइम्स की हेडलाइन थी: "सदर जोन में भाजपा के समर्थन में मुसलमानों का एक विशाल सम्मेलन।"
वजुभाई वाडा की अध्यक्षता में मुसलमानों की एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई।
सदर जोन में मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
मोदी। इस बैठक में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे।
गुजरात राज्य पर्यटन समिति की अध्यक्ष ने मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा:
विभाग की वासुबेन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने योगदान दिया है।
मुस्लिम महिलाएं निरक्षर और पिछड़ी हैं जबकि भाजपा सरकार की अल्पसंख्यक
वित्त एवं विकास विभाग ने सिलाई, कढ़ाई और
जरी केंद्र।
इस सम्मेलन में वंजीभाई बाड़ा की उपस्थिति देखकर मुस्लिम नेताओं ने
वह बहुत भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने घर में लाइटें लगवाने के लिए 60,000 रुपये दिए थे।
सदर में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान। अतिरिक्त 7 एकड़ जमीन देने का निर्णय, 158 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

कब्रिस्तान के लिए जमीन भी [भाजपा सरकार द्वारा] ले ली गई थी।
लेकिन
सांसदों के विरोध के कारण प्रक्रिया ठप हो गई है।
मुस्लिम नेताओं ने वंजीभाई को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया।

रिपोर्ट में आगे बशीरभाई मेमन द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित कई मुस्लिम नेताओं के नामों की सूची दी गई है।
मैं शासक नहीं, सेवक हूँ।
मोदी के चुनाव अभियान का लहजा और शैली 19 फरवरी, 2002 को सांझ टाइम्स में प्रकाशित मोदी के भाषण की रिपोर्ट से भी स्पष्ट होती है, जिसका शीर्षक था: "मैं गुजरात का नाथ (शासक) नहीं, मैं दास (सेवक) हूँ।" यह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनके इस वादे के अनुरूप है कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ओर से एक 'चौकीदार' (सुरक्षा गार्ड) के रूप में वोट दें, जो किसी भी भ्रष्ट हाथ को सार्वजनिक खजाने या सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने नहीं देगा। समाचार रिपोर्ट में मोदी के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने अपने मतदाताओं से निम्नलिखित वादे किए थे:
मैं किसी को हराने या नीचा दिखाने नहीं आया हूँ… मैं लोगों का दिल जीतने आया हूँ।
राजकोट के लोगों का। लोगों को कांग्रेसियों के चरित्र को पहचानना चाहिए।
जो राजकोट के लोगों को पानी से वंचित करते हैं।"
मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदी, जिन्होंने स्वयं को एक स्थापित नेता के रूप में स्थापित किया है
भाजपा के विजयी उम्मीदवार ने पहले ही जनता के बीच अपनी अटूट जगह बना ली है।
राजकोट के लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। आज उन्होंने बेहद कोमल हृदय का परिचय दिया।
उन्होंने राजकोट के लोगों को संदेश देते हुए कहा, “मैं गुजरात का शासक नहीं हूं।”

मैं गुजरात का सेवक हूँ। जिस वातावरण में मैं पला-बढ़ा हूँ, वहाँ सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है।
"धर्म के रूप में, शक्ति के रूप में नहीं।" उन्होंने कहा, "मेरे पूरे जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है।"
जब मुझे किसी से भीख मांगनी पड़ती थी। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि
राजकोट: मुझे आपसे वोट मांगने का अवसर मिला है। मैं राजकोट के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं
राजकोट के लोग मुझे जो कुछ भी देंगे, मैं उसे ब्याज सहित लौटा दूंगा।
अपने स्वभाव के बारे में बात करते हुए श्री नरेंद्रभाई मोदी ने कहा, “मित्रों,
मैं यहां किसी को हराने नहीं आया हूं; मैं यहां किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूं।
मैं राजकोट के लोगों का दिल जीतने और उनके बीच रहने के लिए यहाँ आया हूँ।
दिलों में।” राजकोट के लिए अपने विकास परिप्रेक्ष्य को समझाते हुए, श्री नरेंद्रभाई
मोदी ने कहा, “राजकोट में विकास के कई अवसर हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में विकास के अनेक अवसर हैं। गुजरात के बाद भूकंप के लिए हमने भूकंप प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है।
गुजरात में इस कार्य से संबंधित एक विभाग की स्थापना की जाएगी।
राजकोट। मैं चाहता हूँ कि राजकोट शिक्षा धाम बने।
कांग्रेस में NaMo को मिल रहे मुस्लिम समर्थन की "तेजी से बढ़ती लहर" पर दहशत फैल गई 159

और इस क्षेत्र के लोगों के लिए आशा का केंद्र है। राजकोट को यह विशिष्टता प्राप्त है कि...
सौराष्ट्र के सबसे प्रमुख शहर के रूप में माना जाता है। यह बात कौन नहीं जानता?
उस दिशा में कार्य करने के लिए, नर्मदा प्रगति का स्रोत होगी। सिर्फ राजकोट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सौराष्ट्र और कच्छ के लिए?
प्रस्तुत है ‘नर्मदा सर्वदे’ (नर्मदा, सभी का उत्थान) श्रृंखला। जनता के सामने विचार करते हुए, श्री नरेंद्रभाई मोदी ने कहा कि यदि नर्मदा
यदि परियोजना लागू हो जाती है, तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, चारा उपलब्ध होगा।
खूब फसल होगी, गोधन (पशुधन) प्रचुर मात्रा में होगा, और नदियाँ दूध और दही की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। इसके बावजूद, कांग्रेस पार्टी,
जिसने 1961 में नर्मदा परियोजना की आधारशिला रखी थी, उसने ऐसा नहीं किया।
मध्य प्रदेश द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण इसे पूरा करने में 40 साल लग गए।
प्रदेश कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार में कमी है
राजकोट में पानी की समस्या। राजकोट के समझदार नागरिकों को कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है?
क्या आप मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना को रोकने के लिए बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं?
क्या इसे लागू होने से रोका जा सकता है?
कांग्रेस ने शिकायत की है कि भाजपा सरकार के बंद करने के आदेश से अवैध कसाईखानों का संचालन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था।

इस संदर्भ में श्री नरेंद्रभाई मोदी ने कहा, “कृपया कांग्रेसियों से पूछें।”
क्या उनके उम्मीदवार अवैध कसाईखानों को चलाने के पक्ष में हैं? वे बेचारे जानवरों की रक्षा करना चाहते हैं या कसाइयों की?
अंत में, लोगों से अपील की गई कि वे अपने वोटों को पूजा के फूलों की तरह ग्रहण करें।
21 फरवरी को लोकशाहिका मंदिर में, ताकि
भाजपा को चुनावी समर्थन देने के संबंध में श्री नरेंद्रभाई मोदी ने कहा, “मैं यहाँ आया हूँ
इस चुनाव में रचनात्मक एजेंडा अपनाकर लड़ें। रचनात्मक होना मेरी कार्यशैली का हिस्सा है।
प्रकृति। मुझे विश्वास है कि मेरे रचनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए, लोग
राजकोट बहुत बारीकी से आकलन करेगा, सावधानीपूर्वक तौलेगा, सटीक रूप से मापेगा और
मुझे इस अग्निपरीक्षा (अग्नि परीक्षा) में सफल घोषित करें।
20 फरवरी 2002 को सांझ टाइम्स ने राजकोट में मोदी के चुनावी भाषण का निम्नलिखित सारांश प्रकाशित किया। शीर्षक था: "नरेंद्रभाई मोदी द्वारा राजकोट की जनता के लिए स्नेह से भरा संदेश।"
समाज सेवा और राष्ट्र सेवा ही राष्ट्र की सेवा है।
मेरे जीवन का महामंत्र। यह आगे बढ़ने की नींव रखेगा।
गुजरात नई ऊंचाइयों को छुए। मेरी यही कामना है कि नर्मदा का जल राजकोट तक पहुंचे।
सौराष्ट्र। मैं आपसे मतदान के माध्यम से अपना बहुमूल्य सहयोग चाहता/चाहती हूँ।
इसके गंतव्य के प्रति मेरी श्रद्धा (विश्वास)।
160 मोदी, मुसलमान और मीडिया

समाज के लिए कुछ करना मेरी तमन्ना (गहरी इच्छा) है; मैं प्रेरित हूं।
अपने देश के लिए जीने और मरने की इच्छा से प्रेरित होकर; …मैं चाहता हूँ कि गुजरात का गौरव सभी तक पहुँचे।
पूरी दुनिया में... मैंने लोकप्रेम (लोगों के प्रति प्रेम) के मंत्र का प्रयोग किया है।
सरकार द्वारा आयोजित लोक कल्याण मेले प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं।
मशीनरी लोकसेवा (जनसेवा) का एक साधन है। 4 से कम समय में
कुछ महीनों से, मैंने रूस के मॉस्को स्थित एस्ट्रा माइंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
गुजरात को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। पूरी सरकार को समर्पित करना।
नर्मदा और अन्य कानूनों को लागू करने और लोगों की सेवा के लिए मशीनरी
प्रमुख योजनाएँ... मेरा प्रत्यक्ष प्रयास रहा है।
यह मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के मेरे प्रयासों की शुरुआत है।
भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सत्ता सौंपी है। मुझे जनता के सहयोग की आवश्यकता है।
गुजरात के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए राजकोट के लिए। आपका वोट
आप भावी गुजरात के लिए अमूल्य हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारे लिए यह संभव कर पाएंगे।
भाजपा को वोट देकर और अपने राज्य को प्रगतिशील गुजरात की ओर अग्रानी बनाकर, हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

विजय। हमें ईमानदारी के माध्यम से गुजरात का समग्र विकास करना होगा।
कड़ी मेहनत। इस प्रयास में आपका वोट एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा।
मुझमें। आपने हमेशा भाजपा पर भरोसा किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति मिले।
अपने धर्म के अनुरूप जीवन जीना। राजकोट के बुद्धिमान नागरिकों से मुझे बस यही कहना है।
कांग्रेस के निराधार दुष्प्रचार के जवाब में मुझे बस इतना ही कहना है: “हे
Prabhu!, kuprachar karne walon ko subuddhi dena aur sadvichar karne wale
ko shakti dena. Aur bus Rajkot ki janata matraroopi shakti Bhajpa ko degi,
aisi meri shraddha hai.” (Oh lord! Please give wisdom to those indulging in
बुराई फैलाने वालों को शक्ति प्रदान करें और अच्छाई और पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों को बल दें।
(विचार)। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकोट के लोग भाजपा को ही अपना वोट देंगे।
नरेंद्र मोदी ने राजकोट के नागरिकों को प्रणाम किया।
उसी पृष्ठ पर एक बॉक्स आइटम में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए लिखा: “कांग्रेसियों, जो आज सत्ता में आने के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं, वे उस समय कहां थे जब भूकंप के बाद गुजरात पर मौत का साया छा गया था?” बॉक्स आइटम में मोदी द्वारा किए गए निम्नलिखित वादे भी शामिल थे। उनके हवाले से कहा गया है, “मैं ये करूंगा:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"
NaMo 161 [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आज़मी का भव्य स्वागत किया। इन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और यूरोपीय वित्तीय एजेंसियों के भरपूर समर्थन से नर्मदा विरोधी आंदोलन को राजनीतिक रूप से लोकप्रिय बनाया। कांग्रेस पार्टी के ठोस, हालांकि गुप्त समर्थन के बावजूद, मेधा ने गुजरात में विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं की।
राजकोट चुनाव की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, 19 फरवरी, 2002 को, सांझ टाइम्स ने एक बार फिर भाजपा के लिए बढ़ते मुस्लिम समर्थन पर रिपोर्ट दी।
राजकोट के इतिहास में पहली बार भगवा रंग का वातावरण बनाया गया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने के लिए शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को लक्षित किया जाता है।
भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए एकजुट हुए। वार्ड नंबर 1 में जहां हैं
more than 4000 Muslims voters, at 10 am, Anjaliben Rupani, Kheruben Salot
और भावनगर की भावी महापौर विभारीबेन दवे के नेतृत्व में मंजुलाबेन जोशी, 200 से अधिक शिक्षित मुस्लिम महिलाओं के साथ आईं।
मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील करना और
भाजपा के नरेंद्रभाई मोदी के लिए वोट जुटाना।
यह सब देखकर जिला और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता भागने लगे।
आज दोपहर में ये महिलाएं इधर-उधर घूमेंगी।
पूरे इलाके में और मोची बाजार में, और 20 तारीख को वे नेहरू के आसपास घूमेंगे।
नगर, बजरंगबाड़ी, रुखदिया, माफतियापारा, पोपटपारा क्षेत्रों में जीत हासिल करनी होगी

21 फरवरी को मुस्लिम समुदाय ने भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वोट दिया। 162 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

25 फरवरी 2002 को, सांझ टाइम्स की एक हेडलाइन ने मोदी की जीत की घोषणा इस प्रकार की: “70 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोट वाले बूथों में भाजपा काफी आगे है... मुस्लिम युवा नेता मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों ने विधानसभा उपचुनाव में नरेंद्र मोदी जी की इस बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है: कांग्रेस के लिए मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने के लिए, राज्य और राज्य दोनों
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी थे।
राजकोट में पिछले 10 दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन ये सभी नेता असफल रहे।
मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलते हैं जबकि मुस्लिम नेता कादरभाई सलोट,
गुजरात राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास समिति के उपाध्यक्ष विभाग ने राजकोट के विभिन्न क्षेत्रों में तीन विशाल रैलियों का आयोजन किया था।
साथ ही भाजपा उम्मीदवार नरेंद्रभाई के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं की एक रैली भी आयोजित की गई।
मोदी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 13 अलग-अलग समूह बैठकें भी आयोजित कीं। मदद के लिए
भाजपा को मुस्लिम वोट मिले, विजयभाई रूपाणी ने इसके लिए बहुत मेहनत की।

कादरभाई। परिणामस्वरूप , 70 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बहुमत वाले
चुनाव बूथों पर भी यही स्थिति रही।
जनसंख्या के आधार पर भाजपा को बड़ी बढ़त मिली।
मोदी ने मुस्लिम वोटों में इतनी बड़ी जीत क्यों हासिल की ?
मोदी के पक्ष में मुस्लिम वोटों के इस अभूतपूर्व बदलाव में
निम्नलिखित कारकों का योगदान रहा :
□ उनके द्वारा प्रस्तुत जनहितैषी शासन मॉडल स्वाभाविक रूप से
inclusive – Sabka saath sabka vikas was being demonstrated on the
मैदान।
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य को
कुशलतापूर्वक संभालने के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।
इन क्षेत्रों ने ठोस कार्यों के माध्यम से यह भी प्रदर्शित किया
कि मुसलमान
नए विकास मॉडल से सभी को समान रूप से लाभ हुआ। □ मोदी के कई लोगों
के साथ दशकों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध थे।
आम मुसलमान और साथ ही समुदाय के नेता जिन्होंने खुलकर हिस्सा
लिया
उनका समर्थन।
राजकोट में ही उन्होंने विशिष्ट आवश्यकताओं का जवाब दिया था।
मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान की जमीन की मांग तेजी से कर रहा है।
ये अनुरोध , जो दशकों से अनसुलझे रहे थे ,
मोदी के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के भीतर इन मुद्दों को
संबोधित किया गया। □ उन्होंने अल्पसंख्यक बोर्डों को पूर्ण
निगमों में अपग्रेड कर दिया था।
नए उद्यमशीलता गतिविधियों और कौशल विकास में सहायता करने के
उद्देश्य से
मुसलमानों के बीच विकास संबंधी पहल।

NaMo 163 के लिए मुसलमानों के "तेजी से बढ़ते" समर्थन पर कांग्रेस में दहशत

फिर भी, मोदी ने मुसलमानों को कभी अलग वोट बैंक के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काए बिना, नागरिकों के रूप में उनकी जायज़ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं का रचनात्मक ढंग से समाधान किया। इस दृष्टिकोण ने कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। स्वाभाविक रूप से, कांग्रेस पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया।
अगले अध्याय में मोदी के पहले ही चुनाव में कांग्रेस द्वारा आयोजित अनैतिक और गैरकानूनी चुनाव अभियान का वर्णन किया गया है।

अध्याय 9

कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में
मोदी के गोधरा-पूर्व चुनाव में कांग्रेस का कानूनविहीन और घिनौना अभियान

यह नरेंद्र मोदी कांग्रेस को करारा झटका देने वाले हैं। वे प्रतिभा और योग्यता के धनी हैं। वे कांग्रेस पार्टी के लिए चक्रवात साबित होंगे।
कांग्रेस नेता, अश्विनभाई कोटवाल से भाजपा नेता विजयभाई रूपाणी तक, 7 अक्टूबर 2001
मेरी विचारधारा यह है कि मुझ पर फेंके गए पत्थरों का उपयोग करके मैं अपने लिए एक पुल बनाऊं; मैं अपने काम के माध्यम से अपने आलोचकों को गलत साबित करने में विश्वास रखता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जितना अधिक कीचड़ आप मुझ पर फेंकेंगे, भाजपा का कमल उतना ही अधिक खिलेगा। यही कमल का स्वभाव है, वह कीचड़ से निकलकर अद्भुत सुंदरता का सृजन करता है। - नरेंद्र मोदी, निजी साक्षात्कार, 2013

फरवरी 2002 में राजकोट से लड़े गए उनके पहले ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मोदी के प्रति गहरी नफरत साफ झलक गई। गोधरा कांड से बहुत पहले ही उनके खिलाफ चलाए गए अनैतिक और मानहानिकारक अभियान से यह बात साबित होती है। उनकी यह बेचैनी इस तथ्य से उपजी थी कि अब तक उनके वश में रहे मुस्लिम वोट बैंक ने खुलेआम और बेखौफ होकर नरेंद्र मोदी का साथ दिया था। मोदी को हराने की अपनी बेताबी में उन्होंने उन्हें चुनाव से बाहर करने के लिए निर्लज्जतापूर्वक गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया।

राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, कांग्रेस की शत्रुता के कारण मोदी को जिन अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वह उस दौर की समाचार रिपोर्टों से स्पष्ट होता है। इसके अलावा, मोदी के भाजपा के पुराने सहयोगी विजयभाई रूपाणी, जो 2002 में नव नियुक्त मुख्यमंत्री के राजकोट चुनाव अभियान के प्रभारी थे, ने इस बात पर दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान की कि कांग्रेस और उसके गैर सरकारी संगठनों के सहयोगियों ने पहले दिन से ही मोदी को एकतरफा जुनून के साथ क्यों निशाना बनाया।
कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 165

आइए मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया।
पार्टी मोदी को खत्म करने के लिए इतनी बेताब थी। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विनभाई,
नरेंद्रभाई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति मेरे निजी मित्र हैं।
नरेंद्रभाई ने 7 अक्टूबर, 2001 को अपने पद की पहली शपथ ली थी।
8 अक्टूबर, मेरे बेटे के जन्मदिन पर, अजीत रूपानी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई।
उनके नाम पर एक बाल संगम का आयोजन किया गया था। हम गरीब बच्चों की देखभाल करते हैं।
यह पारिवारिक ट्रस्ट। उस समय अश्विनभाई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि
आगामी चुनाव में उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से होगा; मेरा भी यही मानना था।
मैंने अश्विनभाई को अपने समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था।

कार्यक्रम के दौरान, अश्विनभाई और मैं बातचीत करने के लिए बैठ गए। मुझे उनकी बातें अच्छी तरह याद हैं।
उस शाम की भविष्यवाणी। उन्होंने कहा, "अगर केशूभाई को अपना खेल पूरा करने दिया जाता तो..."
उनके पांच साल के कार्यकाल में, कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में वापस आ जाती।
Gujarat. Yeh Narendra Modi bhari pad jayega Congress ko. Yeh bahut kshamata
wala aadmi hai. Yeh toh Congress Party ke liye bilkul cyclone siddh hoga.” (This
नरेंद्र मोदी कांग्रेस को करारा झटका देने वाले हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो
वह असाधारण प्रतिभा और योग्यता के धनी हैं। वह आने वाले समय में तूफान साबित होंगे।
(कांग्रेस पार्टी)। मुझे याद है कि अश्विनभाई ने बिल्कुल यही शब्द कहे थे।
उन्होंने नरेंद्रभाई का इतना सटीक आकलन इसलिए किया क्योंकि उनका उनसे घनिष्ठ संपर्क था।
उनके साथ काम किया था और उनकी संगठनात्मक प्रतिभा से परिचित थे। कांग्रेस पार्टी ने आकलन किया कि...
उन्होंने उसकी क्षमता का बहुत सटीक आकलन किया और इसलिए उसे हराने के लिए हर संभव प्रयास किया।
उन्हें उनके पहले ही चुनाव में। कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता डेरा डाले हुए थे।
नरेंद्रभाई के खिलाफ प्रचार करने के लिए करीब 10 दिनों तक राजकोट में कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया।
कमल समेत दिल्ली के नेता भी मोदी के खिलाफ प्रचार करने आए थे।

नाथ और मनमोहन सिंह। उन्होंने उन्हें जमकर बदनाम किया और गाली- गलौज की।
कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा के केशूभाई समूह के साथ मिलकर चलाया गया सुनियोजित मानहानि अभियान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का घोर उल्लंघन था। लेकिन, राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, न तो शक्तिशाली चुनाव आयोग और न ही राजकोट पुलिस ने मोदी की मदद की। रूपाणी ने उस समय पार्टी को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उनका वर्णन किया है:
नरेंद्रभाई को अनगिनत अपमान सहने पड़े, यहाँ तक कि उनके हाथों भी। प्रशासन में नए होने के कारण उन्हें नौकरशाही और पुलिस से काफी अनुभव प्राप्त हुआ।
कांग्रेस से संबद्ध पुलिस और नौकरशाही ने खुलेआम कार्रवाई की।
नए मुख्यमंत्री के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके अपनाए जा रहे हैं।
भाजपा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि यह मानहानिकारक अभियान चलाया जा रहा है।
प्रिंट में प्रकाशित सामग्री चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विरुद्ध थी। इससे पहले 166 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

हमने देखा था कि कैसे शंकर सिंह वाघेला ने उस स्थान से चुनाव लड़ा था।
उसी क्षेत्र में, पुलिस खुलेआम उसके लिए काम करती थी और वस्तुतः उसके चुनाव अभियान का संचालन करती थी।
सरकार की पूरी मशीनरी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके अधीन कर दी जाती थी।
विजय।

लेकिन मोदी के मामले में, पुलिस आयुक्त ने हमारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात है – यह तब की बात है जब नरेंद्रभाई थे।
मुख्यमंत्री के प्रति हमने नरेंद्रभाई से पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में शिकायत की थी।
पुलिस आयुक्त के आचरण पर उन्होंने कहा, "हम उसे नहीं उठाएंगे।" पुलिस के खिलाफ लाठीचार्ज मत करो। उन्हें जो करना है करने दो। मैं नहीं चाहता...
एक ऐसी मिसाल कायम करना कि पुलिस आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को मेरी बात मानो। तुम अभियान को यथासंभव अच्छे से संभालो और सच्चाई प्रस्तुत करो।
जनता के सामने तथ्य।
प्रशासन की शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि जब हमने होर्डिंग्स लगाए शहर में, नगर आयुक्त ने उन्हें जबरन हटवा दिया; यह घोषणा करते हुए कि
होर्डिंग लगाना चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है।
यह पूरी तरह से बकवास था क्योंकि हर पार्टी लोगों तक पहुंचने के लिए होर्डिंग लगाती है।
लोगों को इसके बारे में बताया जाता है और इस पर कभी कोई समस्या नहीं हुई है।
नरेंद्रभाई के होर्डिंग्स पहले ही दिन हटा दिए गए। हम ऊपर गए। हमने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हमने चुनाव आयोग से भी संपर्क किया।
पुलिस आयुक्त की कार्रवाई के खिलाफ। लेकिन नरेंद्रभाई ने जोर देकर कहा कि

हमें प्रशासन के खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए। इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी।
मुख्यमंत्री की अधिकारियों को धमकाने की कोशिश करते हुए तस्वीर।
उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है करने दो।
हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को खुद फैसला करने देना चाहिए।
राजकोट प्रशासन ने कांग्रेस के इशारे पर काम किया। ज़िला प्रशासन ने कांग्रेस के साथ अपने पुराने संबंधों और पूर्व मुख्यमंत्रियों केशूभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के निरंतर प्रभाव के कारण कांग्रेस की चाल में साथ दिया। उदाहरण के लिए, 4 फरवरी, 2002 को सांझ समाचार ने रिपोर्ट किया कि कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद, शहर प्रशासन ने भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार के तहत लगाए गए होर्डिंग्स को विरूपित कर दिया था।
कल चुनाव आयोग के आदेशानुसार पानी का छिड़काव किया गया।
शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे भाजपा के होर्डिंग्स को विरूपित करना।
विजयभाई रूपाणी ने कहा, “चूंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं राजकोट से भाजपा ने यह सुनिश्चित किया है कि आचार संहिता का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए।
चुनाव अभियान के हर चरण में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ पालन किया गया।
आचार संहिता के नियमों के अनुसार, चुनाव के दौरान होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते।
कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 167

स्थानीय प्रशासन संस्थानों की दीवारों पर इन्हें लगाया जाए। हमने इन्हें सम्मानित किया।

यह घोषित किया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाना आचार संहिता का उल्लंघन है।
आचरण का....
भाजपा की इस दलील को उचित सुनवाई दिए बिना कि यह दायरे में था होर्डिंग्स और सरकारी तंत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के लिए कानून
उन्होंने रातोंरात सभी होर्डिंग्स हटा दिए, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन,
केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब भाजपा को अनुमति दे दी है।
और उसने 28-01-1998 के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया। यह एक जीत के समान था।
भाजपा के लिए।
रूपाणी ने यह भी बताया कि जब शंकर सिंह वाघेला प्रमुख बने तो क्या हुआ।
मंत्री बनने के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा और खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया।
आचार संहिता। हालांकि, इस बार भाजपा सरकार होने के बावजूद। राज्य में और स्वयं मुख्यमंत्री राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं।
भाजपा और मुख्यमंत्री दोनों ही 168 के दायरे में रहने के लिए प्रतिबद्ध थे। मोदी, मुस्लिम और मीडिया

आचार संहिता द्वारा निर्धारित मर्यादा (सीमाओं) का पालन करें और उसके सभी नियमों का अनुपालन करें।
अपने चुनाव अभियान के दौरान सख्ती से…
2002 का बदनामी अभियान मौजूदा रणनीति की झलक दिखाता है। मोदी के चुनाव अभियान में बाधा डालने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के अलावा, कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ एक व्यापक

सामने लाया गया… राजकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए बहुत कम दिन बचे हैं।
ऐसे समय में भारी मात्रा में आपत्तिजनक साहित्य का प्रकाशन हुआ। मुख्यमंत्री के खिलाफ विषैले दुष्प्रचार में लिप्त होकर
उनके निजी जीवन पर अपमानजनक हमले करना, आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचरण संबंधी मानदंडों ने भाजपा हलकों में गंभीर नाराजगी पैदा कर दी थी…
अचानक, हर गली में मानहानिकारक और विषैले संदेशों वाले पर्चे दिखाई देने लगे।
कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 169

नरेंद्रभाई के खिलाफ हमलों को बेचा जा रहा था। इससे काफी हंगामा मच गया था।
भाजपा खेमे में... यह सूचना मिलते ही पुलिस ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
Kawada Road. But it went deep into thought (soch mein doob gayi) since no
वाहन उस तरफ से गुजरा।
ये ट्रक मानो हवा में गायब हो गए थे, लेकिन राजकोट में मानहानिकारक साहित्य उतारे बिना नहीं, क्योंकि उसी शाम राजकोट के हर गली-नुक्कड़ पर यह साहित्य बांटा जा रहा था। इससे भी पुलिस की मिलीभगत का संकेत मिलता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले अपेक्षाकृत कम ज्ञात अखबार 'बिंदु पत्रिका' का प्रसार अचानक बहुत बढ़ गया, क्योंकि इसमें मोदी के खिलाफ बेहद निंदनीय सामग्री प्रकाशित की गई थी।

बिंदु के प्रचलन में हुई विशेष वृद्धि का श्रेय विचित्रता को दिया गया।
विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित समाचार क्लिप, चित्र और सूचना क्लिप का संकलन
समाचार पत्रों के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, इस दैनिक समाचार पत्र की लाखों प्रतियां बिकती हैं।
अहमदाबाद से जारी संदेश पूरे शहर [राजकोट] में प्रसारित किए गए हैं... इसके बाद
कांग्रेस पार्टी की 16 फरवरी को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी शामिल थी।
मुख्यमंत्री के निजी जीवन से संबंधित पर्चे विभिन्न माध्यमों पर भेजे गए।
राजकोट में कार्यालय।
भाजपा से शिकायतें मिलने पर, पुलिस ने विभिन्न गुजराती समाचार पत्रों में "प्रथम श्रेणी की जमात" शीर्षक से प्रकाशित मानहानिकारक विज्ञापन की जांच का बहाना बनाया। लेकिन चूंकि यह केवल एक बहाना था, इसलिए वास्तव में इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 17 फरवरी, 2002 को सांझ टाइम्स ने लिखा:
आपत्तिजनक सामग्री के वितरण को लेकर तनाव के बावजूद भी
दैनिक समाचार पत्र में अभी शांति नहीं आई थी, रंग-बिरंगे विज्ञापनों का वितरण जारी था।
देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ पर्चे बांटे गए।
शहर में काफी हलचल मच गई... राजकोट उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुँच गया है।
बढ़ते तनाव के बीच, एक भाजपा कार्यकर्ता का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ टकराव हो गया, जो विरोध पत्र बांट रहे थे।

मोदी के खिलाफ मानहानिकारक साहित्य। पुलिस ने इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की।
इसके मोबाइल वैन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उमेश राजगुरु, कश्यप शुक्ला,
और कई अन्य लोग चौक की ओर दौड़ पड़े… जिससे माहौल और भी गरमा गया। आगे …
कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस जीप के बोनट पर चढ़ गए। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
लाठीचार्ज नहीं किया गया। इसके बजाय इसने इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं, 170 मोदी, मुसलमानों और मीडिया से निपटा।

विनम्रता के साथ। … यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों ने
पार्टी के सदस्य रेस कोर्स क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से इन पर्चों का वितरण कर रहे थे।
वहाँ तीन-चार अलग-अलग प्रकार के पर्चे बाँटे जा रहे थे।
कांग्रेस पार्टी, जिसमें पटेल समुदाय को संबोधित एक पत्र भी शामिल है
पंचायत उपाध्यक्ष ललितभाई कागथरा और वजुभाई बोड़ा की....बीजेपी इन पर्चों के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस पर दबाव डालने की कोशिश की गई।
लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनमें नाम नहीं है।
प्रिंटर या प्रकाशक को यह पता नहीं था कि पैम्फलेट केवल कॉपी- पेस्ट किया गया था।
पुरानी रिपोर्टें, समाचारों की कतरनें और लेख। ये पर्चे लगातार प्रकाशित होते रहे।

देर शाम तक वितरित किया गया।
कांग्रेस के साथ पुलिस की मिलीभगत
सांझ टाइम्स की रिपोर्टों में इन रंगीन पुस्तिकाओं को विकृत तरीके से छपी (विकृत मानसिकता से प्रकाशित) बताया गया था। अखबार की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि पुलिस भाजपा उम्मीदवार के लिए हंगामा करने वाले कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति नरमी बरतकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही थी। इससे मोदी के सत्ता संभालने के समय गुजरात में पुलिस व्यवस्था की स्थिति और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पुलिस के पक्षपातपूर्ण आचरण का अंदाजा लगता है।
17 फरवरी को राजकोट के एक अन्य स्थानीय दैनिक अखबार, जयहिंद ने खबर दी कि राजकोट पुलिस आयुक्त द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील पर्चे बांटने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से से उबल रहे थे। यह आदेश चुनाव के अंतिम चरण में जारी किया गया था, जब तक कि आपत्तिजनक साहित्य व्यापक रूप से वितरित हो चुका था।
18 फरवरी को जयहिंद अखबार ने खबर दी कि चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि उनमें से एक बड़ी भीड़ मोदी को निशाना बनाने वाले साहित्य के वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश के विरोध में राजकोट पुलिस आयुक्त के कार्यालय में घुसने पर अड़ी हुई थी। पुलिस आयुक्त के परिसर के अंदर ही उनका व्यवहार इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि, समाचार रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाठीचार्ज हल्का था और इसका उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के बजाय पुलिस आयुक्त के कार्यालय की सुरक्षा करना था।

18 फरवरी को सांझ टाइम्स ने खबर दी कि भाजपा ने बिंदु पत्रिका के प्रकाशक की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसने प्रधानमंत्री वाजपेयी और मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की थी। कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 171

मुख्य मजिस्ट्रेट श्री दवे ने मंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर दिया क्योंकि आईपीसी की जिन धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था, उनमें सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए, गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं किए जा सके।
इससे यह भी संकेत मिलता है कि राजकोट पुलिस जानबूझकर मोदी और यहां तक कि प्रधानमंत्री वाजपेयी के खिलाफ विकृत अभियान चलाने वालों के प्रति नरम रुख अपना रही थी। भाजपा नेताओं के बार-बार पुलिस के दरवाजे खटखटाने पर पुलिस ने जांच का आदेश देने का दिखावा तो किया, लेकिन जैसा कि विजयभाई रूपाणी कहते हैं, उन्होंने मोदी को निराधार आरोपों से बदनाम करने वालों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि देश का कानून और चुनाव आचार संहिता सख्त कार्रवाई की हकदार थी।
19 फरवरी, 2002 को, चुनाव तिथि से ठीक चार दिन पहले, सांझ टाइम्स में निम्नलिखित शीर्षक था: “विवादास्पद पर्चे और व्यक्तिगत हमलों से युक्त अन्य सामग्री वितरित करते हुए दो गिरफ्तार। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। सामग्री वितरित करने वाले कुछ स्थानों से भाग निकले।” इसमें आगे लिखा है:
आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त के बाद उपेंद्र सिंह ने कल रात दो अलग-अलग शिकायतों के संबंध में एक फरमान जारी किया।
मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इस फरमान का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने विवादित वस्तु बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
सौराष्ट्र हाई स्कूल के पास अखबार और रंगीन मुद्रित पर्चा पड़ा था।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का यह दिखावा भी केवल कुछ ही लोगों के खिलाफ किया गया, जो पर्चे बेच रहे थे, अर्थात् निचले स्तर के अधिकारी। पर्चे लिखने या प्रकाशित करने वालों या वास्तव में उनके वितरण के पीछे जो लोग थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को भड़काने में भी सफल रही, जबकि नरेंद्र मोदी प्रशासन को सुव्यवस्थित करने, फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने, भ्रष्टाचार से लड़ने और सुशासन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। 19 फरवरी, 2002 को जयहिंद अखबार ने निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित की:
सरकारी कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे भाजपा के खिलाफ वोट देंगे।
क्योंकि वे उत्पीड़न के विभिन्न उपायों से सचमुच थक चुके हैं। गुजरात सरकार द्वारा किए गए उपायों में 35,000 लंबित आवेदनों को भरने पर रोक लगाना भी शामिल है।
रिक्तियां, महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की कटौती, नई स्थानांतरण नीति जिसके तहत
किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी पद पर भेजा जा सकता है। कांग्रेस सरकार
सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की नीति शुरू की थी। लेकिन 172 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

नई भाजपा सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया है। सरकार के परिवारों ने
दिवाली बोनस न मिलने के कारण कर्मचारी बेहद परेशान हैं।
दूसरी ओर, सरकार लोक कल्याण में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वोट हासिल करने के उद्देश्य से मेलों (जन कल्याण मेलों) का आयोजन किया जाता है। इन कुकर्मों के कारण...
जिला पंचायत के सरकारी और अर्ध-सरकारी दोनों कर्मचारी
स्कूल, कॉलेज और नगर निगम के अधिकारी बहुत नाराज हैं। मुख्यमंत्री को उन कर्मचारियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो काम करते हैं।
हजारों वोट।
अश्लील सामग्री का इस्तेमाल और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भड़काना: भले ही राजकोट से मोदी के नामांकन की घोषणा के दिन से ही जाने-माने कांग्रेसी नेताओं द्वारा उनके खिलाफ मानहानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही थी, फिर भी पुलिस आयुक्त ने मध्य फरवरी में ही चुनाव आयोग द्वारा स्थापित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन, जमीनी स्तर पर पुलिस ने मानहानिकारक सामग्री को रोकने के लिए नाममात्र का ही प्रयास किया। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके प्रतिबंध लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, राजकोट में भाजपा इकाई को इस मामले को उचित प्रक्रिया के तहत निपटाने का निर्देश दिया गया। इसलिए वे संबंधित अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील करते रहे।
19 फरवरी, 2002 को जयहिंद द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने अश्लील साहित्य के प्रसार पर रोक लगाने वाले पुलिस आयुक्त के विलंबित आदेश को "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर

प्रतिबंध" बताते हुए अदालत में चुनौती देने की धृष्टता दिखाई। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पुलिस आयुक्त का आदेश स्वस्थ प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, और यह आदेश केवल झूठी मानहानिकारक सामग्री के प्रसार और प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है। 19 फरवरी को जयहिंद ने एक बार फिर मोदी विरोधी एक और पर्चा छापने में शामिल वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के नाम उजागर किए।
नरेंद्र मोदी के चरित्र का उपहास करते हुए 'नटुमामा' नामक एक पर्चा प्रकाशित किया गया।
गुजरात राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरीश चंद्र द्वारा लिखित पटेल अब कुख्यात हो चुका है। इसने राजकोट में काफी हलचल मचा दी है। यह है
बिंदू साप्ताहिक द्वारा वितरित पहले पैम्फलेट के बाद यह तीसरा ऐसा पैम्फलेट है।
दूसरा यतिन ओझा द्वारा। महेंद्र शाह नाम का एक कांग्रेस कार्यकर्ता।
जब वह इस पर्चे को बांट रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया… इसके बाद, एक
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह पुलिस आयुक्त के कार्यालय की ओर बढ़ा।
और जबरन अंदर घुसने की कोशिश की।
कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 173

रिपोर्ट में कई अन्य कांग्रेसी नेताओं के नाम भी बताए गए हैं जो पुलिस आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये पर्चे बांट रहे थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसी दिन एक अन्य समाचार रिपोर्ट में कहा गया है, "पुलिस पर मुख्यमंत्री के इशारों पर नाचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने

कई पुलिस अधिकारियों के तबादलों की मांग की है।" इसमें आगे कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और नरहरि अमीन समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री लिंगदोह को एक याचिका सौंपी। इन नेताओं ने धमकी दी कि अगर नामित पुलिस अधिकारियों का तबादला नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर चले जाएंगे।
21 फरवरी 2002 को, इसने फिर से खबर दी कि कांग्रेस नेता नरहरि अमीन ने अपने मानहानिकारक साहित्य के प्रसार को रोकने के प्रयास के लिए पुलिस आयुक्त के तबादले की मांग की है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घृणित साहित्य के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस की नाममात्र की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी का आक्रोश यह दर्शाता है कि वे पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने के कितने आदी हो चुके थे।
जैसा कि ऊपर उद्धृत नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों और सार्वजनिक भाषणों से स्पष्ट है, उनमें सांप्रदायिक जहर या मुस्लिम विरोधी भावना का कोई अंश नहीं था। बल्कि, मुसलमानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि भाजपा ने एक पार्टी के रूप में और नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में, समुदाय की विशेष जरूरतों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता को ठोस रूप से प्रदर्शित किया था। इसके बावजूद, कांग्रेस ने ऐसा दुर्भावनापूर्ण माहौल बनाया कि धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़कने की गंभीर आशंकाएं पैदा हो गईं। उदाहरण के लिए:
जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, 19 फरवरी, 2002 को 'जयहिंद' अखबार के बैनर पर यह शीर्षक छपा था: "राजकोट में चुनावी बुखार छाया हुआ है, सांप्रदायिक दंगों का डर है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है:

"उपचुनाव में सिर्फ तीन दिन बचे हैं और शहर में चुनावी बुखार छाया हुआ है। भाजपा के सभी राज्य स्तरीय नेता राजकोट पहुंच चुके हैं। प्रशासन पर दोनों तरफ से भारी दबाव है। आज भाजपा की आखिरी जनसभा है और कल कांग्रेस की रैली को फिल्म स्टार सुनील दत्त संबोधित करेंगे। आने वाले दिनों में शहर के कई इलाकों से आगजनी की घटनाएं सामने आ सकती हैं।"
कांग्रेस और आरएसएस एवं भाजपा के कुछ वर्गों में उनके दुश्मनों द्वारा उनके खिलाफ चलाए गए जानलेवा प्रयासों और भ्रष्ट अभियान के बावजूद, मोदी कांग्रेस के कट्टर दुश्मन क्यों बन गए? 174 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मोदी ने अपना पहला चुनाव आरामदायक अंतर से जीता। लेकिन इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं क्योंकि उनकी हताशा ने खतरनाक रूप ले लिया। अपने पहले चुनाव में भी, पार्टी ने मोदी के खिलाफ मुख्य रूप से बदनामी और दुष्प्रचार को हथियार बनाया। जहाँ उनके भाषण विकास के एजेंडे और सत्ता में आने के लगभग 19 हफ्तों में शुरू की गई रचनात्मक पहलों का ब्योरा देने पर केंद्रित थे, वहीं कांग्रेस का चुनाव प्रचार मोदी के व्यक्तित्व पर केंद्रित था और रचनात्मक आलोचना के बजाय उन पर कीचड़ उछालने पर ही आधारित था। मुस्लिम वोट बैंक के नुकसान ने कांग्रेस को व्याकुल कर दिया और उन्होंने मोदी को नष्ट करने के लिए सबसे भड़काऊ तरीके अपनाने शुरू कर दिए।
आज, मोदी को नीचा दिखाने के लिए, कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी की एक उदारवादी और सर्वसम्मत नेता के रूप में प्रशंसा करने से नहीं थकते। लेकिन वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्हें भी मोदी की तरह ही बेरहमी से निशाना बनाया गया था—सिर्फ फर्क इतना था कि वाजपेयी एक जाने-माने राष्ट्रीय नेता थे, इसलिए मीडिया या आम जनता पर इसका उतना असर नहीं हुआ। इसके विपरीत, मोदी अधिकांश भारतीयों

और मीडियाकर्मियों के लिए अपेक्षाकृत एक गुमनाम क्षेत्रीय नेता थे। इसलिए, राष्ट्रीय मीडिया की मशहूर हस्तियों के सहयोग से, उन्हें हिंदुत्व के उग्र और राक्षसी चेहरे के रूप में पेश करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। उदाहरण के लिए, उसी दौरान जब वाजपेयी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे, 19 फरवरी, 2002 को, जयहिंद ने इस बारे में रिपोर्ट किया कि वाजपेयी को अन्य राज्यों में मुसलमानों के बीच भाजपा विरोधी प्रचार से कैसे निपटना पड़ा: जब अटल बिहारी वाजपेयी वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा।
यह कहना कि, "भले ही मुसलमान भाजपा को वोट न दें, फिर भी भाजपा ही विजयी होगी।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चारों राज्य विधानसभाओं के चुनाव समाप्त होने के बाद,
विपक्ष उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करेगा। जनता को संबोधित करते हुए
उत्तर प्रदेश में हुई बैठक में उन्होंने विपक्ष के इस लक्षण की तुलना एक
बिल्ली जो बेसब्री से मक्खन से भरी मटकी के टूटने का इंतजार कर रही है। उसने कहा
वे इस उम्मीद को पूरा नहीं होने देंगे। “कुछ लोग ऐसे हैं जो
कुछ लोग मुसलमानों को भाजपा को वोट न देने के लिए कह रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा
इसने कभी भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ काम नहीं किया है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं।"
मुसलमानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वह

मुस्लिम विरोधी। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ-साथ भाजपा सरकारों ने भी ऐसा ही किया है।
विभिन्न राज्य मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसलिए, मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है।
भाजपा के खिलाफ जाने का कारण। इसके बावजूद, अगर मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, तो...
भाजपा को अब भी जीत का पूरा भरोसा है।
कीचड़ उछालने और कमल खिलने के बारे में 175

यह उल्लेखनीय है कि तथाकथित उदारवादी वाजपेयी के विपरीत, जिन्हें कांग्रेस और वामपंथी दल भाजपा के अधिक स्वीकार्य और समावेशी चेहरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आक्रामक हिंदुत्व के तथाकथित प्रतीक मोदी ने कभी भी मुस्लिम समर्थन को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र और गुजरात के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से कच्छ में मुसलमानों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, बल्कि अपने पहले ही चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लगभग हर वर्ग से ठोस चुनावी समर्थन प्राप्त किया। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, 70 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बहुल आबादी वाले मतदान केंद्रों ने भाजपा को बड़ी बढ़त दिलाई और मोदी की जीत में सहायक साबित हुए। यही बात उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे गंभीर और शक्तिशाली खतरा बनाती है। मोदी वहां सफल हुए जहां वाजपेयी भी असफल रहे थे!
2002 और 2014 के प्रधानमंत्री चुनाव के बीच समानताएं: 2001 में शुरू हुए चरित्र हनन के दुर्भावनापूर्ण प्रयास आज तक नहीं रुके हैं। आज, मोदी पर शोध-आधारित ग्रंथ लिखने का दावा करने वाले सम्मानित समाजशास्त्री और शोधकर्ता भी इस धंधे को ज़िंदा रखे हुए हैं। इस बेहद लाभदायक धंधे में नवीनतम उदाहरणों में से एक है

निलंजन मुखोपाध्याय की 'नरेंद्र मोदी: द मैन' नामक पुस्तक, जो टाइम्स 1 में प्रकाशित हुई थी। यह मोदी के बारे में कुछ गंदगी खोदने और उनके नाम को किसी न किसी यौन कांड से जोड़ने का उनका नवीनतम साहसिक प्रयास है। लेकिन बेचारे मुखोपाध्याय को गुजरात के पेशेवर मोदी-विरोधी लोगों द्वारा साझा की गई फुसफुसाहटों और अफवाहों के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने भी गुमनाम रहना ही चुना। उन्होंने मोदी की कथित "त्यागी पत्नी" जसोदाबेन से कुछ सनसनीखेज सामग्री प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अन्य सभी की तरह, वे बुरी तरह असफल रहे। इसलिए वे मोदी को उनकी कहीं अधिक उम्र की सहयोगी और वर्तमान राजस्व मंत्री, आनंदीबेन पटेल से जोड़ने वाले चालाक इशारों पर निर्भर हैं। इस तरह के आरोपों का कोई नतीजा नहीं निकला है, फिर भी हर चुनाव से पहले इन्हें फिर से उठाया जाता है। 2014 के संसदीय चुनावों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चरित्र हनन को आपराधिक रंग देने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा का इस्तेमाल करते हुए मोदी और एक युवा महिला वास्तुकार के साथ अश्लील वीडियो रखने के बेबुनियाद आरोप लगाए।2 ऐसा कोई वीडियो पेश नहीं किया गया है।
1 नीलांजन मुखोपाध्याय, नरेंद्र मोदी: द मैन, द टाइम्स (चेन्नई: ट्रेंक्यूबार)
प्रेस, 2013)।
2 For details of Pradeep Sharma’s case, see: Madhu P. Kishwar, “Ulta Chor Kotwal Ko
दांते: आरोपित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा का नरेंद्र मोदी के खिलाफ जवाबी हमला, 3 दिसंबर 2013, वेब। http://www.manushi.in/articles.php?articleId=1738#. Uv3tQUKSxJP.

176 मोदी, मुसलमान और मीडिया

सबूत के तौर पर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं, प्रमुख पत्रकारों, टीवी एंकरों और गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के कई अन्य प्रतिष्ठित लोगों की खुली मिलीभगत से इस कमजोर मामले का इस्तेमाल करते हुए महीनों तक मोदी को बदनाम किया है। कांग्रेस पार्टी ने शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने में भी मदद की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मोदी का एक अश्लील वीडियो उनके पास होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच गठित की है, यह जानते हुए भी कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका मकसद सिर्फ 2014 के संसदीय चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखना है। 2002 की तरह ही, अब भी मोदी ने कोई जवाब या स्पष्टीकरण जारी करने की जहमत नहीं उठाई है।
मेरे एक साक्षात्कार के दौरान, जब मैंने मोदी से पूछा कि वे इन सभी घृणित हमलों का सामना कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा:
यह सुनियोजित अभियान उनकी हताशा को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ा
खामियों को पकड़ना और उन्हें चित्रित करना आसान है। लेकिन, अगर आपको कोई बड़ी खामी नहीं मिलती है तो...
फिर लोग ऐसे आरोप लगाने लगते हैं जिनके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती - इसे कहते हैं
किसी व्यक्ति को अहंकारी कहना, या किसी यौन कांड का आरोप लगाना। मैं ऐसी बातों का खंडन नहीं कर सकता।
आरोप। मेरा सिद्धांत है कि मुझ पर फेंके गए पत्थरों का उपयोग करके एक पुल बनाया जाए।
मैं स्वयं; मेरा मानना है कि मैं अपने काम के माध्यम से अपने आलोचकों को गलत साबित कर सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ,

आप मुझ पर जितना अधिक कीचड़ उछालेंगे, भाजपा का कमल उतना ही अधिक खिलेगा।
कमल का स्वभाव ऐसा है कि वह कीचड़ से निकलकर अद्भुत सुंदरता का सृजन करता है।

अध्याय 10

निर्मल गुजरात की ओर अग्रसर
और “हम यह कर सकते हैं” का जज़्बा
मोदी के गोधरा-पूर्व भाषण

हमारा प्रयास है कि हम ऊँच-नीच, साक्षर-अछूतों के बीच के सभी प्रकार के विभाजनों को दूर करें, साथ ही उन अन्य भेदभावों को भी दूर करें जिन्होंने लोगों के दिलों में संघर्ष भर दिया है और पूरी मानवता को टुकड़ों में बाँट दिया है…ऋषि वाल्मीकि ने हमें सिखाया कि समाज में प्रगति करने के लिए आपको शबरी को साथ लेकर चलना होगा; यदि आप अपने समाज की प्रगति चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वानर भी आपके साथ खड़े हों। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको केवत को अपनाना होगा। …हम यहाँ उनके संदेश का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
1 दिसंबर 2001 को नरेंद्र मोदी
मैं संतों से प्रार्थना करने आया हूँ कि उनके आशीर्वाद से ऐसी रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जिससे 5 करोड़ गुजराती और 10 करोड़ साथी भारतीय इतने आत्मविश्वास से भर जाएँ कि हमारा समाज नकारात्मकता और अपराधबोध से मुक्त हो जाए। - नरेंद्र मोदी, 1 जनवरी 2002

सत्ता संभालने के पहले कुछ हफ्तों के भीतर ही नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी नई पहल शुरू कीं और भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास पर काफी समय व्यतीत किया। इसके बावजूद उन्होंने नागरिकों के कई समूहों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के समूहों की सभाओं को संबोधित किया।

उन्होंने जिन विषयों पर बात की और जिन कार्य योजनाओं की घोषणा की, उन पर उनकी समावेशी राजनीति की छाप स्पष्ट है, जो सबसे वंचितों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देती है।
मैं उनके दो भाषणों के अपने अंग्रेजी अनुवादों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दोनों भाषण हिंदू श्रोताओं को संबोधित हैं—पहला भाषण 1 दिसंबर, 2001 को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर और दूसरा भाषण 1 जनवरी, 2002 को शताब्दी समारोह में दिया गया था। 178 मोदी, मुसलमान और मीडिया

स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी। जैसा कि मैंने पहले उद्धृत किए गए भाषणों में देखा है, इन दोनों भाषणों में या मोदी के गोधरा कांड से पहले के कई अन्य भाषणों में, जिन्हें मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना, विभाजनकारी सांप्रदायिक बयानबाजी का कोई संकेत नहीं मिलता। मैं पाठकों से स्वयं निर्णय लेने का आग्रह करता हूं कि क्या मोदी वास्तव में कांग्रेस पार्टी के प्रचारकों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दंगे भड़काने के लिए उत्सुक व्यक्ति प्रतीत होते हैं।
वाल्मीकि जयंती, 1 दिसंबर 2001 को महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदिकवि या प्रथम कवि के रूप में भी पूजा जाता है, ने रामायण की रचना की, जो भारत के प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि की विरासत का जश्न मनाने के लिए मोदी ने नीचे दिया गया भाषण दिया:
शरद पूर्णिमा तब आती है जब चंद्रमा 16 कलाओं (गुणों) से परिपूर्ण होता है।
जो दिव्यता में पूर्णता लाते हैं)। इसी प्रकार, वाल्मीकि जयंती प्रतिनिधित्व करती है

16 कलाओं की चमक, उस ज्ञान से भरपूर जो हमें प्राप्त हुआ है।
ऋषि वाल्मीकि1 की सांस्कृतिक विरासत। यह वर्तमान पीढ़ी को भी प्रेरित करती है।
ऋषि वाल्मीकि से जुड़ी कई लोकप्रिय मिथक और कहानियां प्रचलित हैं।
जो मौखिक परंपरा के माध्यम से जीवित हैं। हमारे पास यह कहने का कोई आधिकारिक आधार नहीं है।
ऋषि वाल्मीकि ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया? लेकिन उनके दूरदर्शी लेखन के कारण, जीवन
प्रभु राम जी के जीवन ने हजारों वर्षों से असीम प्रेरणा प्रदान की है।
जब भी मन अशांत हो और जीवन में कोई सहारा ढूंढना चाहे, तब
कोई यह जानना चाहता है कि एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच कैसा अंतर्संबंध होना चाहिए।
एक अस्तित्व और दूसरे के बीच, व्यक्तियों और समाज के बीच, मनुष्यों के बीच
और वानर (पशुओं) के बीच, नर (मनुष्यों) और नारायण (ईश्वर) के बीच, क्या है?
हमें जिस प्रकार के सामाजिक संगठन की आवश्यकता है, ऋषिवर ने हमें उसका सर्वोत्तम संभव उदाहरण दिया है।
इन मुद्दों पर साहित्य। उनकी जयंती का शुभ अवसर है।
ऋषि वाल्मीकि के प्रति अपना ऋण चुकाने और उनके समक्ष नतमस्तक होने का यह उचित समय है।
और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुसार जीवन व्यतीत करें।
इस अवसर पर, मैं आप सभी के साथ मिलकर अपना नमन (श्रद्धांजलि) अर्पित करता हूँ।

ऋषिवर वाल्मीकि का अनुसरण करते हुए समरस्त की स्थापना के मार्ग पर चलें। सरकार
1. वाल्मीकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन-पोषण एक सफाईकर्मी महिला ने किया। वे एक पथिक बन गए।
अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए उन्होंने एक डाकू के रूप में काम किया, जब तक कि उनका ऋषि नारद से मिलन नहीं हुआ। रामनाम का जाप करने से उन्हें महर्षि का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। तपस्या के दौरान उनके शरीर पर एक दीमक का टीला उग आया था, इसलिए वे वाल्मीकि के नाम से जाने जाने लगे। हाल की शताब्दियों में जिन जातियों और समुदायों को मानव मल-मूत्र साफ करने का काम सौंपा गया है और जिन्हें अछूत माना जाता है, वे ऋषि वाल्मीकि से अपनी वंशावली का दावा करते हैं।
निर्मल गुजरात और "हम कर सकते हैं" की भावना का लक्ष्य रखते हुए 179

गुजरात सरकार प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
गुजरात के समुदाय, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, इस मार्ग के अनुसार
ऋषि वाल्मीकि ने हमें यह दिखाया था।
ऋषि वाल्मीकि ने सत्य की शक्ति को जागृत करने पर केंद्रीय ध्यान केंद्रित किया ताकि
बुराई का नाश करना। उसने केवल राक्षसी शक्तियों के संहार की इच्छा या कल्पना नहीं की थी।
युद्ध की शक्ति के माध्यम से। उन्होंने एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

असुरी (राक्षसी) शक्तियों को पराजित करने के लिए समाज का गठन प्रभु रामचंद्र ने किया था।
अपने शत्रु [रावण] से स्वयं निपटने में सक्षम। लेकिन ऋषि वाल्मीकि इससे उन्हें संपूर्ण शक्ति को एकजुट करने और आगे ले जाने की प्रेरणा मिली।
वनजीवन (वन जीवन), जिसमें वानर (बंदर) भी शामिल हैं, में दिव्य ऊर्जा को प्रज्वलित करने के लिए।
समाज में उभरती हुई विध्वंसक शक्तियों को नष्ट करने के उद्देश्य से उनका उपयोग किया जाता है।
असुरों (राक्षसों) के रूप में। अच्छाई के इस सामाजिक लामबंदी में शामिल थे
रावण के सगे भाई और पुत्र ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार। ऋषि वाल्मीकि
इसने हमें सकारात्मक ऊर्जाओं को सक्रिय करके और उन्हें एक साथ लाकर जीना सिखाया है।
आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए समाज।
उन्होंने हमें सिखाया कि समाज में प्रगति करने के लिए, आपको सबको साथ लेकर चलना होगा।
शबरी2, मैं आपसे सहमत हूँ; यदि आप अपने समाज की प्रगति चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि
वानर भी आपके साथ खड़े हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उन्हें अपनाना होगा।
केवट 3. ऋषि वाल्मीकि ने ये सभी संदेश दिए। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं।
यह वह स्थान है जहां हम उनके संदेश का पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकते हैं।

जब मैं सामाजिक विज्ञान का छात्र था, तब मैंने पढ़ा था कि वहाँ लोग थे
इस देश ने हमारे वाल्मीकि भाइयों को अपनी कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया।
अपने पड़ोस या गली से गुजरते समय, ताकि कोई निशान न छूटे।

2. शबरी, एक विनम्र वनवासी, भगवान राम के प्रमुख भक्तों में गिनी जाती हैं।
रामायण महाकाव्य में, वनवास के दौरान सीता की खोज करते समय, राम संयोगवश शबरी की कुटिया के पास पहुँचते हैं। राम के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर, वह यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उन्हें केवल वही मीठे जंगली फल मिलें जो उन्होंने जंगल से एकत्र किए थे। इसलिए, वह उन्हें अर्पित करने से पहले स्वयं चखती हैं। शबरी को भक्ति में इतना लीन देखकर, राम प्रेमपूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। शबरी शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गई हैं, जो स्वयं भगवान को भी विनम्र कर देती है। वह भारत के पारंपरिक वनवासी समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें से कुछ को अंग्रेजों द्वारा 'आदिवासी' घोषित किया गया था। यह भ्रामक नामकरण स्वतंत्रता के बाद भी भारत में बरकरार है। मोदी सरकार शबरी को हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिनके विकास को उनकी सरकार प्राथमिकता देने का वादा करती है।
3. रामायण महाकाव्य में, केवट एक साधारण नाविकों के समुदाय को संदर्भित करता है।
यह विशेष घटना गुहा नामक एक नाविक से संबंधित है, जिसने वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराई थी। केवट ने राम के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के कारण उनके हाथों मोक्ष प्राप्त किया, अर्थात् जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई। औपनिवेशिक काल

से शुरू हुए आर्थिक हाशिए पर चले जाने के कारण यह समुदाय भारत की सबसे पिछड़ी जातियों में गिना जाने लगा।
180 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उनके पदचिह्न पीछे छूट गए। इस प्रकार की क्रूरताएँ दोनों पर की गई हैं।
हम अपने और आपके पूर्वजों के पापों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं।
दोस्तों, जब हम अपने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की समस्याओं की परवाह करते हैं, तो
समाज में, यह पार्टी राजनीति (राजकरण) का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाजीकरण का हिस्सा है।
(समाज को सशक्त बनाना)।
वास्तविक शासन में गरीबों का दिल जीतना शामिल है,
बेहद दुखद। इस पाप को पसीने और खून से धोना होगा। बस यही एकमात्र उपाय है।
जब हम अपने पापों को धो लेते हैं, तभी हम लोगों के दिलों को जीतने के योग्य बन जाते हैं।
लोगों की।
हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार के विभाजन को दूर करें—चाहे वह विभाजन किसी भी समुदाय के बीच हो या किसी अन्य समुदाय के बीच। ऊँच-नीच, स्पर्शनीय-अस्पृश्य—साथ ही अन्य पहलू भी
भेदभाव जिसने लोगों के दिलों को संघर्षों से भर दिया है और उन्हें विभाजित कर दिया है।
पूरी मानवता को टुकड़ों में बांट देता है। इससे बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

भारत की प्रगति के लिए। अगर हम इन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो हमें सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।
सामाजिकरण के साथ गंभीरता से।
यह कहना गलत है कि केवल सवर्ण (कुछ उच्च जातियाँ) ही अपराध करते हैं।
हम पर अत्याचार होते हैं। हमारे समाज में अनेक प्रकार के क्षैतिज विभाजन भी मौजूद हैं।
एक समय था जब हम अखबारों में पढ़ते थे कि दलित समुदाय के सभी लोग एक समरूप हैं।
समुदाय। लेकिन, अगर कोई वाल्मीकि से उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में पूछे।
आजादी के 50 साल बाद हमें किस तरह का जवाब मिलने की संभावना है? जब मैंने एक दलित लड़की को इस अवसर पर अपने घर में कुंभ स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया
‘विजय दशमी’ के बारे में, ऐसा इसलिए नहीं है कि किसी ने मुझसे ऐसा करने को कहा। बल्कि इसलिए कि मैं
मेरा मानना है कि इस मानसिकता को बदलना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
यह बीमारी हमारे समाज में इतनी गहराई से जड़ जमा चुकी है कि इससे प्रभावित लोगों की मानसिकता भी बदल गई है।
अच्छी शिक्षा प्राप्त, बुद्धिमान और अंग्रेजी में बातचीत करने में सक्षम होने के मुद्दे पर वास्तव में कोई बदलाव नहीं आया है। हमने वाल्मीकि के अपने भाइयों के लिए 100,000 घर बनाने का निर्णय लिया है।
समाज, जिन्होंने अब तक अपना जीवन झोपड़ियों में बिताया है। इसके अतिरिक्त,

निर्मल गुजरात कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए
इस कार्यक्रम के तहत, हम शहरी क्षेत्रों में 10,000 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं।
हमारा प्रयास उन लोगों को हर संभव सुविधा प्रदान करना है जो यहां रह चुके हैं।
jhopadis thus far.
आज ही ऋषि के कार्यकाल में 10,000 शौचालयों के निर्माण का यह निर्णय लिया गया।
वाल्मीकि का जन्मदिन। हम सफाई कर्मचारी निगम की स्थापना करेंगे। उन लोगों के लाभ के लिए जिनके पूर्वजों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है
गुजरात को स्वच्छ रखना। कड़ी मेहनत करने वालों से प्रेरणा लेना।
समाज में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सदियों से हम निर्मल का झंडा बुलंद करते आ रहे हैं।
गुजरात (स्वच्छ गुजरात)।
यह सरकार गुजरात को नंदनवन में बदलना चाहती है (
निर्मल गुजरात और "हम कर सकते हैं" की भावना का लक्ष्य रखते हुए 181

भगवान कृष्ण से जुड़े पौराणिक रमणीय वन में इस पहल के साथ
और पांच करोड़ गुजरातियों की कड़ी मेहनत। यह सरकार लोगों को जगाना चाहती है।
गुजरात का झंडा बुलंद रखने के लिए पांच करोड़ गुजरातियों की रचनात्मक कल्पनाशीलता
उच्चतर। मैं आप सभी से निर्मल गुजरात को साकार करने का आह्वान करता हूँ…

[illegible]
[illegible]
[illegible]

□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□

□□□□ □□□□ □□ "□□□" □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□

“□□ □□ □□□□ □□□” □□□□, 1 □□□□□, 2002: □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□:

□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□… □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□

□□□□□□ □□□ □□□ (□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□) □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□) □□ □□□□□□□ 182 □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

डिग्री हासिल करने के लिए। इस परंपरा ने मनुष्यों को मानवीय बनना सिखाया।
यह संस्था पुरुषों में मात्र मनुष्य होने से ऊपर उठने की क्षमता विकसित करती है।
दिव्य बनने के लिए (नर से नारायण)।
इस संस्था ने ऐसा वातावरण विकसित किया है जो संस्कारों को बढ़ावा देता है।
अहम (स्वयं) से ऊपर उठकर व्याम (हमारापन) की ओर बढ़ना, जिससे लोग स्वार्थपरक होने से बदलकर स्वाभाविक रूप से समाजोन्मुखी हो जाना।
और लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए सामूहिक संस्कारों (मूल्यों) को शामिल करना।
जीवन की ओर।
यह महान परंपरा छात्रों को अपने गुरुओं का सम्मान करना सिखाती है; यह उन्हें पोषित करती है
संस्कृति के प्रति श्रद्धा और अपना जीवन उसे समर्पित करने की इच्छा
अच्छा कार्य करना, जिससे सब कुछ त्यागने की निरंतर प्रेरणा मिलती रहे।
उत्कृष्टता प्राप्त करना। यह संस्था निरंतर (कभी न खत्म होने वाली) प्रक्रिया का पालन करती है।
इस प्रकार की जीवनशैली को गढ़ने के लिए यज्ञ। गुरुकुल प्रणाली को प्राथमिकता देकर।
स्वामीनारायण परंपरा में, राजकोट की धरती पर जो प्रकाश प्रकट हुआ है
स्वामीनारायण के विशेष रूप से प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन को ही नहीं, बल्कि इसने और भी कई लोगों के जीवन को रोशन किया है।

बल्कि इसने पूरे गुजरात में जागरूकता की एक नई लहर भी पैदा की। इस रोशनी के लिए
सामाजिक पुनर्निर्माण के दीपक के लिए, गुजरात की पूरी जनता ऋणी है।
यह संस्था।
हिंदू समाज की यह विशेष प्रतिभा है कि उसमें प्रतिक्रिया देने की क्षमता है।
बदलते समय और विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य शुरू करना।
आवश्यक बदलाव। एक समय था जब जो लोग इसमें दृढ़ विश्वास रखते थे संस्कृति (संस्कृति) इसी मंत्र के अनुसार जीती थी। हमने पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया।
आर्य। आर्य शब्द का अर्थ धर्म परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है बनना।
सुसंस्कृत (अच्छे सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों में दृढ़ व्यक्ति)। हमने अच्छा दिया
संपूर्ण विश्व के लिए मूल्य। आक्रमणकारियों का सामना करने पर समय बदल गया। रक्षा के लिए
और आक्रमणों से अपनी रक्षा करना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई।
उस समय इस भूमि के संतों ने निर्णय लिया कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे;
हम अपनी भूमि के भीतर जो कुछ भी सुरक्षित रख सकते हैं, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे।
आजादी के बाद समय फिर बदल गया। उस बदलाव के साथ—चाहे वह किसी भी माध्यम से हो

the inspiration of Swami Vivekanand, the Swaminarayan tradition, the Hare
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मानवता का। हमें अपने देश में एक नए विचार आंदोलन की आवश्यकता है जो हमारे समाज को नई दिशा दे सके।
एक नई दिशा
निःसंदेह, व्यसन मुक्ति (हानिकारक व्यसनों से मुक्ति) आवश्यक है। और चरित्र की दृढ़ता आवश्यक है। पिछले 50 वर्षों में, हमने कोशिश की है कि
हम इस भावना को कुछ हद तक 100 करोड़ भारतीयों में भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन, हमारे प्रयास...
हम कई मायनों में पिछड़ गए हैं। 1000 वर्षों की गुलामी के कारण, हम हमने यह मानसिकता विकसित कर ली है कि हम हीन हैं। जिन्होंने हम पर शासन किया है
उन्होंने लगातार वैचारिक हमले किए ताकि हमें यह याद दिलाया जा सके कि हम बेकार हैं।
लोगों के प्रति यह हीन भावना कि हमारे पास खुद का कुछ भी मूल्यवान नहीं है।
और अपराधबोध ने सामाजिक वातावरण को दूषित कर दिया है और हमारी शक्तियों को कमजोर कर दिया है।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश में आत्मविश्वास की भावना को पुनः उत्पन्न करें।
मानवता का सागर 1000 वर्षों के अपराध बोध के बोझ तले जी रहा है।
नकारात्मकता के माहौल में गुलामी की समस्या। इसमें पर्याप्त जागरूकता का अभाव है।
अपनी ही अच्छाई के कारण।
हमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि 100 करोड़ की आबादी वाला यह देश, जो इसमें डूबा हुआ है
निराशा के दलदल में फंसा और अपराधबोध से बोझिल, वास्तव में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है।

समाज। इसमें दुनिया को बहुत सी उत्कृष्टता प्रदान करने की क्षमता है। यह भूमि
इसमें पूरी दुनिया का भला करने की क्षमता है। हमारे पूर्वजों को यही विश्वास था।
हम उस आस्था को फिर से कैसे जगा सकते हैं? किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता है?
हमें क्या बनाना चाहिए? हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम और सिलेबस अपनाना चाहिए?
हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली समाज में इस प्रकार की जागरूकता कैसे लाती है?
ऐसा वातावरण जो नचिकेता भाव (भौतिक वस्तुओं से आसक्ति का अभाव) को बढ़ावा देता है।
हमारे लोगों में आध्यात्मिक विकास के प्रति रुचि और झुकाव पैदा करने में मदद करने के लिए
अपने भीतर 'हम यह कर सकते हैं', 'हम यह करेंगे' की भावना और आत्मविश्वास विकसित करें।
समाज? यह आज एक गंभीर चिंता का विषय है।
मुझे लगता है कि आजादी के बाद हमारा समाज दिशाहीन हो गया। हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस समय लोगों को लगा कि भले ही उन्हें बलिदान देना पड़े, वे ऐसा कर सकते हैं।
उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और स्वतंत्रता हासिल करने तक चैन से नहीं बैठे।
भारत के लिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे नेता हमें सही दिशा नहीं दे सके।
और न ही यह बताया गया कि हमने स्वतंत्रता के लिए क्यों लड़ाई लड़ी। परिणामस्वरूप, कर्तव्य की भावना
समाज का क्षरण होने लगा। अधिकारों की भावना प्रबल होती गई जबकि

कर्तव्य की भावना धीरे-धीरे गायब होने लगी। जिधर भी देखो, वही रवैया नज़र आता है:
“मुझे इससे क्या मिलेगा? मेरा क्या हित है? इसमें मेरे लिए क्या है?” 184 मोदी, मुसलमान और मीडिया

यह ‘अधिकार भाव’ हमें ‘समझ’ के प्रति उदासीन बना रहा है।
कर्तव्य भाव। कोई भी समाज जहाँ कर्तव्य की भावना नष्ट हो जाती है और
अधिकारों की भावना ही एकमात्र विजय है, जो एक अंधकारमय भविष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। कौन जा रहा है?
क्या राजनेताओं के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण की भूमिका निभाना संभव है?
इस कार्य को हमारे राष्ट्र के संतों और गुरुकुल परंपरा के अनुयायियों द्वारा संपन्न किया जाता है।
हमारे राष्ट्र के आचार्यों को नई पीढ़ी का पोषण करना होगा।
जो आत्मविश्वास और कर्तव्यबोध को जोड़ता है। यदि हम इन दोनों को विकसित करें तो...
इन गुणों से उत्पन्न होने वाली शक्ति ही भविष्य के इतिहास को आकार देगी।
हमारा समाज…।
इसके बाद मोदी ने भारत के उन चुनिंदा (दस) देशों में शामिल होने की बात कही।
परमाणु बम बनाने की क्षमता होने के बावजूद, भारतीयों को लगता है कि वे
कुछ भी हासिल नहीं किया।]
हमने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है, फिर भी हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है।

कुछ भी हासिल नहीं हुआ… अमेरिका इतना शक्तिशाली राष्ट्र है; इसकी इतनी प्रभावी क्षमता है।
खुफिया प्रणाली के बावजूद आतंकवादी आए और उन्होंने पेंटागन को उड़ा दिया।
ट्विन टावर्स—अमेरिकी आर्थिक साम्राज्य का केंद्र। अमेरिका कर सकता था
इन दो शक्तिशाली सत्ता केंद्रों को नहीं बचाया जा सकता। इसके विपरीत, भारत के जवान
उन्होंने मौत को गले लगाया और भारतीयों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।
भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े बलिदानों के बाद भी, इस देश का 100 करोड़ रुपये उन साहसी पुरुषों के निस्वार्थ भाव को भुला देते हैं और उन्हें अपने पास रखते हैं।
असफलता के गीत गाना। यह सब अपराधबोध के बोझ तले जीने की आदत के कारण है।
नकारात्मक मानसिकता। कच्छ भूकंप के दौरान, शायद ही कोई
देश का वह क्षेत्र जिसने पीड़ितों की मदद के लिए कुछ ही घंटों के भीतर हाथ नहीं बढ़ाया।
मृत्यु के जबड़े में फंसा एक समाज एक सप्ताह के भीतर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, 'जो भी हो'
ईश्वर की इच्छा से ही यह सब हुआ है…
आज अगर आप भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा
मानव प्रयासों के अनेक मंदिर (पुरुषार्थ)। मैं अधिकारियों को जानता हूँ।

जो किसी और के बच्चे को बचाने के लिए तब निकले जब उनकी अपनी पत्नी खतरे में थी।
मृत। कुछ अधिकारी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे थे।
अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार को पीछे छोड़कर।
क्या यह हमारे समाज की आंतरिक लचीलेपन का संकेत नहीं है? लेकिन, इसे कौन देख रहा है?
इस क्षमता पर? अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक नए 156 मेगावाट बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है।
एक पौधा जिसे मात्र 300 दिनों में तैयार कर लिया गया। ज़रा सोचिए, इसे तैयार करने के लिए कितने कौशल की आवश्यकता होती है!
मैं संतों से प्रार्थना करने आया हूँ कि उनकी कृपा से मुझे लाभ मिले।
वह रचनात्मक ऊर्जा जो 5 करोड़ गुजरातियों और 100 करोड़ साथी भारतीयों को सक्षम बनाती है
इतना आत्मविश्वास हासिल करना कि हमारा समाज नकारात्मकता से मुक्त हो जाए और
अपराधबोध। हम भारतीयों की अपनी सीमाएँ और कमियाँ हैं। फिर भी, हम कर सकते हैं।
निर्मल गुजरात और "हम कर सकते हैं" की भावना का लक्ष्य रखते हुए 185

उन्हें हटाने के लिए सामूहिक रूप से काम करें।
कृपया ऐसा वातावरण बनाने में हमारी मदद करें। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है।
अपने देश की सेवा करें। अपने लोगों में कर्तव्य की इस भावना को जगाने के लिए,

महात्मा गांधी ने एक बार किसी को पत्र लिखा था, जिसके बारे में मुझे लगता है
जैसे कि इस फोरम में इस बारे में बात हो रही है...
इस बिंदु पर मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। हालांकि, ऊपर दिए गए अंशों से हमें उनकी सोच की अच्छी झलक मिलती है। विशिष्ट हिंदू धार्मिक समुदायों से बात करते समय भी मोदी किसी भी प्रकार की संकीर्ण या विभाजनकारी अपील नहीं करते। इन दोनों भाषणों में, और अन्य सभी भाषणों की तरह, मोदी गुजरात के सभी 5 करोड़ (अब 6 करोड़) लोगों और 100 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि शामिल हैं। वे समाज के सभी वर्गों की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग सभी के सामान्य हित के लिए करने पर जोर देते हैं।
भारत पर हुए 1000 वर्षों के आक्रमणों के इतिहास की बात करते हुए भी मोदी मुस्लिम-विरोधी या ईसाई-विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते। वास्तव में, वे आक्रमणकारियों के धर्मों का ज़िक्र तक नहीं करते। उनका मुख्य ध्यान अधिकांश शिक्षित भारतीयों की निराशावादी मानसिकता और आज के भारत की पहचान बन चुकी "नकारात्मकता" और आत्मसम्मान के क्षरण पर केंद्रित है। यह असल में कांग्रेस और वामपंथियों से ज़्यादा आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को निशाना बना रहा है। यह सर्वविदित है कि हिंदुत्व के कई अनुयायी इन विदेशी आक्रमणों के कारण सबसे ज़्यादा "नकारात्मकता" और "सामूहिक अपराधबोध" से ग्रस्त हैं। वे इस सवाल से व्याकुल रहते हैं: हिंदू समाज में ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों के छोटे-छोटे समूह बार-बार स्थानीय शासकों को हराकर इतनी बड़ी आबादी और देश पर सत्ता हासिल करने में सक्षम रहे? आरएसएस और अन्य हिंदुत्व समर्थकों ने ही हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की है कि हिंदुओं को इसलिए दबाया गया क्योंकि

वे सैन्य रूप से कमज़ोर थे और सामाजिक विविधता के कारण सामाजिक रूप से "विभाजित" थे, जबकि यूरोप के राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से समरूप और इसलिए राजनीतिक रूप से "एकजुट" थे। मोदी उस हीन भावना की भी बात कर रहे हैं जो वामपंथियों सहित अधिकांश भारतीयों में पश्चिम के प्रति व्याप्त है, जिसके कारण शिक्षित वर्ग पश्चिम के तौर-तरीकों का अंधाधुंध अनुकरण करता है - चाहे वह राजनीति हो, विद्वत्ता की संस्कृति हो या सामाजिक मानदंड। लेकिन, मोदी उग्र राष्ट्रवाद में लिप्त नहीं हैं और न ही पश्चिम-विरोधी भय को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बजाय, वे एक रचनात्मक साझेदारी का प्रस्ताव रखते हैं और पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष को समाप्त करने की बात करते हैं। (186 मोदी, मुसलमान और मीडिया)

दूसरे व्यक्ति की सर्वोत्तम विशेषताओं को आत्मसात करना।
इन दोनों भाषणों का लहजा और शैली मोदी द्वारा गोधरा कांड से पहले के पूरे काल में दिए गए हर भाषण में व्याप्त है और उनके खिलाफ चलाए गए दुष्प्रचार अभियान के बाद भी जारी रही। यह समझना मुश्किल है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण नए भारत के निर्माण के लिए समरसता और 'एकता' की भाषा बोलता है, उस पर विभाजनकारी होने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है, और तो और गुजरात में रक्तपात की कामना करने का आरोप भी कैसे लगाया जा सकता है। यह सवाल उठता है कि मोदी को विभाजनकारी और हत्यारा राजनेता बताने वाला मिथक कैसे और क्यों गढ़ा गया, जबकि उनके सभी कार्यों ने सर्व धर्म समभाव के आदर्श का समर्थन किया है—अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान करना।

अध्याय 11

गोधरा ट्रेन नरसंहार
दुर्घटना या साजिश?

यदि अंतर-सामुदायिक संघर्ष होने पर हर बार मामले की सच्चाई की परवाह किए बिना बहुसंख्यक वर्ग को ही दोषी ठहराया जाता है… तो पारंपरिक सहिष्णुता के स्रोत सूख जाएंगे।
के.एम. मुंशी, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता, जवाहरलाल नेहरू को
ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मुख्यमंत्री और/या उनके मंत्रिपरिषद के किसी अन्य मंत्री या पुलिस अधिकारियों ने गोधरा घटना में कोई भूमिका निभाई थी या सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सुरक्षा, राहत प्रदान करने के मामले में या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और निर्देशों का पालन न करने के मामले में उनकी ओर से कोई चूक हुई थी।
Justice Nanavati Commission Report, September 2008

कांग्रेस और उसके वामपंथी सहयोगियों द्वारा गोधरा नरसंहार में किए गए चौंकाने वाले विकृतियों से, जिसके कारण 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रही 59 महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को जिंदा जला दिया गया था, यह स्पष्ट रूप से उस भयावह त्रासदी में उनके निहित स्वार्थ की ओर इशारा करता है।
इस घटना को जानबूझकर विवादास्पद बनाया गया है, जबकि घटना के कुछ ही दिनों के भीतर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती की अध्यक्षता वाले एक जांच आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

शहर, जो बार-बार दंगों के गवाह रहे, बारूद के ढेर की तरह थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से सौराष्ट्र और कच्छ में, अहमदाबाद या सूरत जैसी दंगे या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं थी।
गोधरा का विघ्न इतिहास
पंचमहल जिले का गोधरा कस्बा गुजरात के बाहर के लोगों के लिए शायद उतना जाना-पहचाना नाम न हो, लेकिन राज्य के भीतर इसका सांप्रदायिक हिंसा और हिंदू-मुस्लिम संबंधों में तनावपूर्ण इतिहास रहा है। यहां के गुजराती हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा सिंधी मूल का है; वे विभाजन के समय गोधरा में आकर बस गए थे। गोधरा दंगों की जांच के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति नानावती की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट की शुरुआत इस टिप्पणी से की है:
गोधरा शहर एक बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ मुस्लिम आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है।
जिले के विभिन्न स्थानों में जनसंख्या प्रभावित हुई थी। सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
गोधरा में वर्ष 1925, 1928, 1946, 1948, 1950, 1953, 1980, 1981, 1985 में

1 Justice G.T. Nanavati and Justice Akshay H. Mehta, “Part I: Sabarmati Express
"गोधरा की ट्रेन दुर्घटना," जांच आयोग की रिपोर्ट, अहमदाबाद (18 सितंबर, 2008), वेब।
गोधरा ट्रेन नरसंहार 189

1986, 1988, 1989, 1990, 1991 और 1992 में हुए सांप्रदायिक दंगे।

1948 में हालात बेहद गंभीर थे। शुरुआत में मुसलमानों ने 869 घर जला दिए थे।
हिंदुओं के। इसके बाद, हिंदुओं ने मुसलमानों के 3,071 घर जला दिए... 2
गुजरात: द मेकिंग ऑफ ए ट्रेजेडी3 नामक पुस्तक में, धर्मनिरपेक्ष खेमे की अग्रणी सदस्य और तीस्ता सेतलवाद की करीबी सहयोगी पत्रकार ज्योति पुनवानी लिखती हैं:
समुदायों के बारे में रूढ़िवादिता फैलाना न केवल सांप्रदायिक है बल्कि भ्रामक भी है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, गोधरा के घन्चियों के कुछ विशिष्ट गुण इस प्रकार हैं।
गोधरा और उसके बाहर हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच ज्ञात हैं, शायद
इनमें से अधिकांश पर लागू माना जाता है। वे आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं।
अफगान सैनिकों और भील महिलाओं के वंशज, एक आवेगशील समुदाय।
वे पहले तेल के संग्राहक और व्यापारी थे और बाद में किसान बन गए।
आज
वे परिवहन व्यवसाय में हैं। वे अधिकतर निरक्षर और गरीब हैं।
उनमें शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है। घांची परिवार का लंबा इतिहास रहा है।
स्वतंत्रता से पहले और बाद में गोधरा के हिंदुओं के साथ हुए हिंसक संघर्षों का इतिहास।
समुदायों के बारे में रूढ़िवादिता फैलाना वाकई हानिकारक है। लेकिन ये रूढ़िवादिता तभी सच साबित होती है जब वास्तविकता किसी हद तक उसे पुष्ट करती हो। गोधरा के मुसलमानों में बहुसंख्यक घांची मुस्लिम समुदाय से गैर-घांची मुसलमान भी डरते और अविश्वास

करते थे। चूंकि उनमें से कई मोटर वाहन मरम्मत कार्यशालाओं के मालिक हैं, इसलिए एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर चोरी के मोटर वाहनों को पुर्जों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अलग करने में शामिल है। उनका पड़ोसी जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ी की चोरी का भी इतिहास रहा है। यहां तक कि बोहरा मुसलमान भी पहले घांची मुस्लिम इलाकों में जाने से बचते थे। अधिकांश पुलिस और आईएएस अधिकारी हाल तक इसे एक "कठिन" पोस्टिंग बताते थे।
बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में हुए सांप्रदायिक हत्याकांड और हमलों की यादें आज भी लोगों के मन में ताज़ा हैं, फिर भी गोधरा में निम्नलिखित घटना हिंदुओं के बीच डर का कारण बन गई है: नवंबर में गोधरा के वोरवाड़ा इलाके के सैफिया मदरसा में बदमाशों ने दो महिला शिक्षकों सहित चार हिंदू शिक्षकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

2. न्यायमूर्ति नानावती और न्यायमूर्ति मेहता, “भाग I: साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना”
गोधरा”, पृ. 12-3.
3 ज्योति पुनवानी, “गोधरा में नरसंहार,” गुजरात: एक त्रासदी का निर्माण, संपादक।
सिद्धार्थ वरदराजन (नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया, 2002), पी. 67.
190 मोदी, मुसलमान और मीडिया

20, 1990 को बच्चों के सामने एक हिंदू दर्जी की भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यह सब कथित तौर पर इलाके के कांग्रेस विधायक के इशारे पर असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था।

सौभाग्य से, पिछले दस वर्षों में, क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक एवं शैक्षिक बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधारों के साथ, गोधरा के घांची समुदाय की सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। कानून-व्यवस्था के कड़े प्रवर्तन और इस कभी पिछड़े समुदाय के लिए नए आर्थिक अवसरों के खुलने से आपराधिक तत्व हाशिए पर चले गए हैं। इससे घांची समुदाय के आत्म-दृष्टिकोण और आकांक्षाओं के साथ-साथ गैर-घांची (हिंदू और मुसलमान दोनों) की नजरों में उनकी छवि में भी बदलाव आना शुरू हो गया है। लेकिन यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी के सभी घावों को भरने और सांप्रदायिक विभाजन को पाटने के दृढ़ प्रयासों के बिना संभव नहीं हो पाता। मेरी आगामी पुस्तक सरकार द्वारा शुरू की गई इस उपचार प्रक्रिया के परिणामों को कवर करेगी, जो 2011 में मोदी की सद्भावना यात्रा में परिणत हुई।
गोधरा हत्याकांड की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया। 27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से 2,000 से अधिक कारसेवकों को लेकर खचाखच भरी साबरमती एक्सप्रेस सुबह 7.47 बजे गोधरा स्टेशन पहुंची, जो अपने निर्धारित समय से लगभग पांच घंटे विलंबित थी। स्टेशन से निकलते ही और सिग्नल फालिया स्टेशन से कुछ मीटर दूर रुकते ही मुसलमानों की भीड़ ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इसके बाद, यात्रियों के फंसे होने के बावजूद एक डिब्बे में आग लगा दी गई। इस घटना में 59 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भयावह मौत हो गई। मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित इस घटना ने पूरे देश में सदमे की लहर फैला दी। अधिकांश गुजरातियों का मानना है कि गोधरा हत्याकांड ने गुजरात के कई हिस्सों में प्रतिशोधात्मक हिंसा की एक भयावह श्रृंखला को जन्म दिया।
6 मार्च 2002 को, गुजरात सरकार ने गोधरा हत्याकांड की पूर्व नियोजित साजिश का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति के.जी. शाह को एक

सदस्यीय जांच आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। आयोग के दायित्व में गोधरा में हुई अशांति और उसके बाद राज्य में हुई अशांति को रोकने और उससे निपटने के लिए उठाए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता का आकलन करना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना शामिल था।
लेकिन अपनी नियुक्ति के पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी गैर सरकारी संगठनों ने आयोग पर हमला किया और नियुक्त न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गोधरा कांड सरकार की विफलता या मिलीभगत के कारण हुआ था, न कि मुसलमानों द्वारा सुनियोजित हमले के कारण। आयोग का पुनर्गठन किया गया और नए सदस्यों द्वारा इसे उच्च शक्तियां प्रदान की गईं। गोधरा ट्रेन नरसंहार 191

21 मई, 2002 की अधिसूचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती ने इस दो सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी।
कांग्रेस और उसके सहयोगी गैर सरकारी संगठनों के लगातार हमलों के जवाब में, 20 जुलाई, 2004 को सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए गोधरा हत्याकांड के साथ-साथ गोधरा के बाद हुए दंगों से निपटने में तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल मंत्रियों, पुलिस अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों और संगठनों की भूमिका और आचरण की भी जांच शुरू कर दी।
लेकिन न्यायमूर्ति नानावती की नियुक्ति भी कांग्रेस समर्थित गैर सरकारी संगठनों के बेबुनियाद आरोपों का निशाना बन गई, जबकि न्यायाधीश का चयन मोदी ने मनमाने ढंग से नहीं किया था। मोदी ने आयोग के प्रमुख के रूप में नानावती के चयन को इस प्रकार समझाया:

मेरा उद्देश्य निर्णय लेने के दौरान हुई सभी कमियों को उजागर करना था।
इन दोनों ही मामलों में आदेश जारी करने या उन्हें लागू करने में। ऐसा होगा
हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करें। न्यायमूर्ति नानावती सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
सर्वोच्च न्यायालय। मैंने उन्हें स्वयं नहीं चुना, लेकिन मैंने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि
नामों का सुझाव दिया गया। उन्होंने नानावती का नाम लिया क्योंकि उन्होंने आयोग की अध्यक्षता की थी।
1984 के दंगों की जांच समिति के। मैं व्यक्तिगत रूप से न्यायमूर्ति नानावती को नहीं जानता था। मैंने लिया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी नाम सुझाया गया हो, क्योंकि मैं यही चाहता था।
मामले की जांच उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए।
दरअसल, मैंने तो इसके संदर्भ की शर्तों में यह भी जोड़ दिया था कि मेरे खिलाफ सभी आरोप
इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर मैं जांच से बचना चाहता, तो मैं नियुक्ति क्यों करता?
मेरे खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक आयोग? उन्होंने एक ज्ञापन दिया था।
मेरे खिलाफ राष्ट्रपति को। मैंने नानावती आयोग को सौंप दिया।
उन्होंने अपने ज्ञापन में आरोपों की पूरी सूची सूचीबद्ध की थी।
फिर भी, वे आगे बढ़ गए।
मुझ पर हथौड़ा और चिमटा चलाओ।

छह साल तक चली इस जांच के दौरान आयोग ने कई प्रत्यक्षदर्शियों, दस्तावेजी साक्ष्यों और फोरेंसिक रिपोर्टों की जांच की, साथ ही जांच अधिकारियों द्वारा जुटाए गए तथ्यों और आंकड़ों का भी अध्ययन किया। आयोग को 44,475 व्यक्तियों के आवेदन और हलफनामे तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा दायर 2,019 बयान और हलफनामे प्राप्त हुए। सभी गवाहों से वकीलों द्वारा विधिवत जिरह की गई। जिन लोगों ने गुजरात सरकार के इस दावे का विरोध किया कि ट्रेन हत्याकांड गुजरात की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, उन्हें भी गवाहों से जिरह करने और जवाबी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। नानावती आयोग की रिपोर्ट का पहला भाग 25 सितंबर, 2008 को गुजरात विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। 192 मोदी, मुसलमान और मीडिया

नानावती आयोग द्वारा स्थापित तथ्य: विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के तत्वावधान में लगभग 2,000-2,200 कारसेवक अयोध्या में ट्रेन में सवार हुए, जहां से वे कुछ हिंदू संगठनों द्वारा अपने 'राम मंदिर निर्माण' कार्यक्रम के तहत आयोजित पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेने के बाद लौट रहे थे। राम मंदिर निर्माण के इस आंदोलन के कारण पहले 6 दिसंबर, 1992 को इन्हीं संगठनों के कुछ सदस्यों द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया था। हालांकि, बाबरी मस्जिद विध्वंस के विपरीत, पूर्णाहुति यज्ञ शांतिपूर्ण रहा। देश के सभी हिस्सों से लोग अयोध्या गए, यज्ञ में भाग लिया और फरवरी के मध्य से फरवरी 2002 के अंत तक वापस लौटने लगे।
यह बात स्पष्ट है कि अयोध्या में कारसेवा के लिए गए परिवारों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और यह तथ्य इस तथ्य से साबित होता है कि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) कार्यकर्ताओं सहित ये कारसेवक

दंगा भड़काने के इरादे से नहीं निकले थे। यह सर्वविदित तथ्य है कि पुरुष दंगे भड़काने के लिए निकलते समय अपने परिवार की युवा लड़कियों, महिलाओं और बच्चों को शायद ही कभी साथ ले जाते हैं। यह भी साबित हो चुका है कि साबरमती एक्सप्रेस के सभी यात्री विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) कार्यकर्ता नहीं थे। उस ट्रेन में कई आम यात्री भी थे, जो इतनी भरी हुई थी कि लोग फर्श पर और यहां तक कि ट्रेन के शौचालयों के बाहर भी बैठे थे। रेलवे चेकिंग स्टाफ डिब्बों में प्रवेश करके बिना टिकट वाले यात्रियों की जांच नहीं कर पाया था।
सुबह 7:47 बजे गोधरा स्टेशन पर निर्धारित पांच मिनट के ठहराव के बाद जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, तो कुछ उपद्रवियों ने आपातकालीन चेन खींच दी, जिससे ट्रेन सिग्नल फालिया में रुक गई, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह इलाका घांची मुस्लिम बस्तियों से घिरा हुआ है। ट्रेन के रुकते ही, लगभग 1,500 लोगों की भीड़ ने ट्रेन पर इतनी बेरहमी से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया कि लोगों को खिड़कियों के शटर गिराने और खचाखच भरी ट्रेन के दरवाजे बंद करने पड़े। कई यात्री पत्थरों और आग के गोलों से बचने के लिए ऊपरी बर्थों पर शरण लेने या निचली बर्थों के नीचे रेंगने लगे। पत्थर और आग के गोले इतनी बेरहमी से फेंके गए कि कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। पत्थरों के अलावा, हमलावर भीड़ ने पेट्रोल में भीगे हुए जलते हुए कपड़े भी फेंके। ट्रेन पर दोनों तरफ से हमला किया गया, जिसके कारण यात्री पत्थरों और आग के गोलों से खुद को बचाने के लिए बाहर नहीं निकल सके।
पत्थर फेंकने वाली भीड़ में से कुछ लोगों ने S/6 कोच का कैनवास फाड़ दिया, जिससे वह बगल वाले कोच S/7 से अलग हो गया। उस छेद से आग लगाने वाले पेट्रोल से भरे कारबॉय लेकर कोच पर चढ़ गए। उन्होंने पेट्रोल डाला।

गोधरा ट्रेन नरसंहार 193

कोच एस/7 की ओर जाने वाले इंटरकनेक्टिंग दरवाजे को जबरदस्ती खोलने के बाद कोच एस/6 के अंदर भारी मात्रा में ज्वलनशील तरल पदार्थ पाया गया।
इसके चलते आग और धुआं तेजी से फैल गया, जिससे कोच के अंदर फंसे यात्री जलकर मर गए। 59 पुरुष, महिलाएं और बच्चे झुलस कर मर गए। भागने की कोशिश में कई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, बचे हुए लोगों के बयान और चश्मदीदों, जिनमें ट्रेन का चालक, ट्रेन गार्ड, गोधरा रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी, गोधरा प्लेटफार्म पर विक्रेता, दमकल चालक और हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी शामिल हैं, साथ ही कुछ आरोपियों के इकबालिया बयान—ये सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गोधरा घटना पूर्व नियोजित थी और यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसमें गोधरा के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल थे। जस्टिस तेवतिया समिति ने तो यहां तक कहा, “योजना 27 फरवरी, 2002 की तड़के दो हजार से अधिक यात्रियों वाली पूरी ट्रेन को जलाने की थी। यह एक आतंकवादी कार्रवाई की योजना थी जो आंशिक रूप से विफल रही। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को गोधरा से सक्रिय जिहादी तत्वों का समर्थन प्राप्त था। इनमें नगर पालिका के कुछ कांग्रेस सदस्य भी शामिल थे।”4 इस संबंध में सबसे प्रमुख नाम गोधरा नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन कलोटा का है।
कलोटा ने छह साल तक गोधरा में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेतृत्व किया और उनके तबलीगी जमात और हरकत-उल-मुजाहिदीन से संबंध थे, जो कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान स्थित संगठन है। इस संगठन ने 7 सितंबर, 2011 को दिल्ली में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ईमेल के जरिए ली थी। हालांकि, सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया

गया था। अन्य आरोपी कांग्रेसियों में नगर पार्षद हाजी बिलाल, फारुख भाना, अब्दुल रहमान घंटिया, सलीम अब्दुल गफ्फार शेख, अयूब पटलिया, इरफान कलंदर, मेबूब पोपा, शंकट पटड़िया और सिद्दीक वोहरा शामिल थे। दो अन्य - इब्राहिम धंतिया और सलीम पनवाला - कथित तौर पर पाकिस्तान भाग गए हैं।
इस योजना को अंजाम देने वाले दो मुख्य व्यक्ति राजक कुरकुर और सलीम पनवाला थे, जिन्होंने इसे "आतंक फैलाने और प्रशासन को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश" के हिस्से के रूप में अंजाम दिया।5
इस खूनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक टेम्पो (अस्थाई वाहन) का इंतजाम किया था।

4. न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया, डॉ. जे.सी. बत्रा, आदि, गोधरा नरसंहार-न्यायमूर्ति तेवतिया रिपोर्ट,
अंतर्राष्ट्रीय मामलों और मानवाधिकार परिषद, दिल्ली, अप्रैल 2002, पृ. 35-6.
5. न्यायमूर्ति नानावती और न्यायमूर्ति मेहता, “भाग I: साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना”
गोधरा,” पृष्ठ 159.
194 मोदी, मुसलमान और मीडिया

26 फरवरी, 2002 को रात लगभग 9:30 बजे, कलाभाई पेट्रोल स्टेशन से 20 लीटर के सात या आठ कारबॉय (कुल 140 लीटर से अधिक) पेट्रोल भरवाकर (माल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी डिलीवरी वैन) लुटेरे सिग्नल फालिया के पास घांची मुस्लिम इलाके में स्थित अमन गेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए, ट्रेन को दोनों तरफ से घेर लिया और डिब्बों पर इतनी भारी पथराव किया कि यात्री बाहर नहीं निकल सके। यह

साबरमती एक्सप्रेस के एस/6 डिब्बे में आग लगाने के दौरान अधिकतम हताहतों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
भीड़ का सामूहिक नरसंहार करने का दृढ़ संकल्प पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बी.आर. सिम्पी (गवाह-25) के बयान से स्पष्ट है। जब वे सुबह लगभग 11 बजे वडोदरा से दुर्घटनास्थल पर पहुँचे, तो उन्होंने अली मस्जिद के पास लगभग 2,000 से 2,500 लोगों की भीड़ देखी। उन्होंने गवाही दी कि वे "ऐसे नारे लगा रहे थे जिनसे दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही थी" और उन्होंने अली मस्जिद के लाउडस्पीकरों से "इस्लाम खतरे में है, मारो, काटो" जैसे नारे सुने। अधिक हिंदुओं की हत्या का आह्वान कर रही इस आक्रामक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। यह भीड़ मांग कर रही थी कि पुलिस द्वारा पहले हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, वे "मार डालो, काट डालो" के नारे लगाते हुए ट्रेन और फंसे हुए यात्रियों पर पत्थर फेंकते रहे। पत्थर फेंकने वाली भीड़ के हमले में छह पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ट्रेन और यात्रियों पर एक और हमले की आशंका से डीएसपी सिम्पी ने पुलिस कांस्टेबल मानसिंह को हवा में एक गोली चलाने का निर्देश दिया था। इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए तीन और गोलियां चलाई गईं।7
इसी तरह, पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) गढ़वी ने अपनी रिवॉल्वर से दो राउंड फायर किए। हवा में फायरिंग करने से वांछित प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने जवानों को भीड़ में मौजूद लोगों की कमर के नीचे गोली चलाने का निर्देश दिया। भीड़ में से दो लोग घायल हो गए। जब दूसरी तरफ से आ रही भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू किया, तो एक और गोली चलाई गई, जो एक व्यक्ति को लगी। तब तक रिजर्व पुलिस फोर्स (आरपीएफ) कमांडेंट पांडे भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने जवानों को फायरिंग का आदेश दिया…

सीआईडी क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर महबूब बेग मिर्जा (डब्ल्यू-19) वडोदरा से सुबह करीब 11:15 बजे गोधरा पहुंचे। डीएसपी सिम्पी ने उन्हें यात्रियों को ट्रेन में बैठाने के लिए कहा। जब वे ऐसा कर रहे थे, तभी सिग्नल फालिया से करीब 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ आ गई।
6 वही, पृ. 159-60.
7 वही, पृष्ठ 123.
गोधरा ट्रेन नरसंहार 195

एक तरफ। वहां मौजूद लोग "छोड़ दो, मार डालो, काट डालो" के नारे लगाते हुए पत्थर फेंक रहे थे। डीएसपी सिम्पी और आरपीएफ कमांडेंट ने पहले उन्हें चेतावनी दी और फिर फायरिंग का आदेश दिया। इसी दौरान हिंसक भीड़ में से कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया।8 साबरमती एक्सप्रेस पर दो बार हमला हुआ—पहली बार सिग्नल फालिया पर जब उसे रोका गया; दूसरी बार पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के लगभग तीन घंटे बाद, जब प्रभावित दो डिब्बों को अलग करने के लिए ट्रेन को शंट किया जा रहा था। पुलिस के बयानों के अनुसार, भीड़ के दो समूहों ने यार्ड में ट्रेन के अहमदाबाद के लिए आगे की यात्रा फिर से शुरू करने का इंतजार कर रहे बचे हुए यात्रियों पर फिर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, शेष यात्रियों को दोपहर 12.40 बजे साढ़े चार घंटे के भीतर उनके गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि गोधरा स्टेशन हजारों चिंतित रिश्तेदारों से भर न जाए और सामान्य रेल यातायात लंबे समय तक बाधित न हो।
आयोग की 176 पृष्ठों की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि गोधरा ट्रेन हत्याकांड एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसे

हत्याकांड से एक दिन पहले रचा गया था। इसका उद्देश्य प्रशासन में भय का माहौल पैदा करना था। आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि: “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुख्यमंत्री और/या उनके मंत्रिपरिषद के किसी अन्य मंत्री या पुलिस अधिकारियों ने गोधरा घटना में कोई भूमिका निभाई थी या सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सुरक्षा, राहत और पुनर्वास प्रदान करने में या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और निर्देशों का पालन न करने में उनकी ओर से कोई चूक हुई थी।”9
यह महत्वपूर्ण है कि नानावती आयोग को रेल मंत्रालय के विचित्र और कपटपूर्ण आचरण को दर्ज करने के लिए विवश होना पड़ा:
हैरानी की बात यह है कि गोधरा में रेलवे और उसके कर्मचारियों ने इस संबंध में कोई बयान दर्ज नहीं कराया।
वे स्वयं कोई भी ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, जिससे आयोग को सहायता मिल सकती थी।
गोधरा घटना वास्तव में कैसे घटी, यह पता लगाने में, भले ही
यह घटना गोधरा रेलवे यार्ड के अंदर घटी, वहां आग लग गई थी।
ट्रेन दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।
चोटें आईं और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे पुलिस को गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा।
नुकसान हुआ। आयोग को संबंधित रेलवे कर्मचारियों को समन जारी करना पड़ा।
8 वही, पृष्ठ 125.
9 वही, पृष्ठ 175.
196 मोदी, मुसलमान और मीडिया

आयोग के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करना। आयोग

[illegible]
[illegible]10
[illegible] 2002 [illegible] 2004 [illegible]
[illegible]:
[illegible]
[illegible]:
[illegible], 2004 [illegible]

1952 की धारा 3(ख) के प्रावधान के अनुसार, एक बार किसी राज्य सरकार द्वारा किसी मामले की जांच के लिए आयोग नियुक्त किए जाने के बाद, केंद्र सरकार उसी मामले की जांच के लिए दूसरा आयोग नियुक्त नहीं कर सकती। इस प्रकार, यू.सी. बनर्जी समिति की नियुक्ति असंवैधानिक होने के साथ-साथ सरकार के अपने नियमों और विनियमों के भी विरुद्ध थी।
बनर्जी समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका स्पष्ट उद्देश्य लालू की पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटों को एकजुट करना था।
10 वही, पृष्ठ 7.
गोधरा ट्रेन नरसंहार 197

दल और उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी। अब तक सभी सबूतों से यही पता चला था कि मुस्लिम भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस पर हमला कर उसमें आग लगा दी थी। लेकिन न्यायमूर्ति बनर्जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग "दुर्घटना" थी और ट्रेन पर बाहर से हमला नहीं किया गया था।11 लालू यादव ने वास्तव में बिहार में 2005 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले समिति की अंतरिम रिपोर्ट जारी करने में जल्दबाजी की। गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 मार्च, 2006 को एक आदेश पारित कर रेल मंत्रालय और अन्य सभी को रेल मंत्रालय समिति को आगे कोई प्रचार न देने और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। रेल मंत्रालय ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने बदले में गुजरात उच्च न्यायालय को मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया।
13 अक्टूबर 2006 को गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बनर्जी समिति को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय ने

केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा बनर्जी समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव से पहले अंतरिम रिपोर्ट जारी करना दुर्भावनापूर्ण कृत्य था।
गोधरा के आरोपियों के बचाव में दिए गए विचित्र तर्क: गोधरा के आरोपियों का बचाव जमीयत उलेमा-ए-हिंद, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस समर्थित गैर सरकारी संगठन जन संघर्ष मंच ने किया। बदमाशों के एक समूह (जिनमें से कुछ के कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट संबंध थे) द्वारा पूर्व नियोजित हमले के आरोप को खारिज करने के लिए उन्होंने जो तर्क दिए, वे न केवल जले पर नमक छिड़कने जैसे थे, बल्कि यह भी उजागर करते हैं कि सामूहिक हत्या के दोषियों का बचाव करने में कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकती है।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 जुलाई, 2002 को अपने तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अमरसिंह भीलाभाई द्वारा हस्ताक्षरित बयान-सह-शपथपत्र में जो आरोप लगाए थे, उनमें से एक सबसे विचित्र आरोप यह था कि नरेंद्र मोदी ने एक राज्य मंत्री की मदद से गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इस नरसंहार की साजिश रची और उसे उकसाया था। इसकी बेतुकी बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि इससे ठीक तीन दिन पहले, मोदी ने मुस्लिम समुदाय के भारी समर्थन से राजकोट से अपना पहला चुनाव जीता था।

11 डीएनए प्रेस, “न्यायमूर्ति यू सी बनर्जी समिति रिपोर्ट से अंश,” डीएनए इंडिया,
3 मार्च, 2006, वेब. http://www.dnaindia.com/india/report-excerpts-from-the-justice-u-c-banerjee-committee-report-1016092.
198 मोदी, मुसलमान और मीडिया

राजकोट में, जिसने कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करते हुए मोदी को वोट दिया।12 इसके अलावा, 27 फरवरी, 2002 को मोदी को अपना पहला बजट पेश करना था। कोई भी मुख्यमंत्री इतने महत्वपूर्ण दिन पर इस तरह की बाधा उत्पन्न करने की योजना नहीं बनाएगा।
कांग्रेस के सहयोगियों द्वारा फैलाई गई शरारती कहानियाँ: नानावती आयोग ने नोट किया है कि, “जुलाई 2002 तक न तो जन संघर्ष मंच, न ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और न ही किसी और ने यह सुझाव दिया था कि गोधरा घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए और राज्य सरकार तथा संबंधित रेलवे कर्मियों और यात्रियों सहित अन्य लोगों द्वारा बताए गए तरीके से नहीं हुई थी...”13
क्या मुस्लिम लड़की के अपहरण ने मुसलमानों को भड़काया? जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जेयूएच) द्वारा फैलाई गई भ्रामक कहानियों में से एक यह थी कि एक कारसेवक ने एक मुस्लिम लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया था और ट्रेन पर हमला करने वाली मुस्लिम भीड़ का इरादा केवल लड़की को छुड़ाना था। 27 दिसंबर, 2002 को, जेयूएच के वकील ने सोफियाबानू को आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाने का आवेदन दिया। 13 जनवरी, 2003 को उनकी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि वह वडोदरा की निवासी हैं और सिग्नल फालिया स्थित अपनी मौसी जैतुनबीबी से मिलने आई थीं। 27 फरवरी को सुबह लगभग 7:30 बजे, वह अपनी मां और बहन के साथ वडोदरा जाने वाली ट्रेन पकड़ने गई थीं। अचानक, 'जय बजरंग' के नारे लगाते हुए कुछ कारसेवक प्लेटफार्म पर आ गए। "भगवा रंग की बेल्ट पहने एक व्यक्ति ने उसका मुंह पकड़ लिया और उसे खींचकर ट्रेन की ओर ले जाने की कोशिश की। उसके चिल्लाने पर उसने उसे छोड़ दिया।"
नानावती आयोग ने निम्नलिखित कारणों से इस कहानी को बाद में गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज कर दिया:

उसके साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि
उसके द्वारा दिया गया विवरण सत्य प्रतीत नहीं होता… कथित प्रयास उसका अपहरण तब हुआ जब वे किताबों की दुकान के पास थे। इसका मतलब यह होगा कि
वे प्लेटफार्म के ढके हुए हिस्से के लगभग बीच में थे और बहुत रेलवे कर्मचारियों के कार्यालयों के निकट। साक्ष्यों से पता चलता है कि वहाँ थे।
प्लेटफ़ॉर्म पर कई लोग मौजूद थे। यात्रियों के अलावा, कई मुस्लिम विक्रेता भी थे।

12 अध्याय 8 देखें।
13 न्यायमूर्ति नानावती और न्यायमूर्ति मेहता, “भाग I: साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना”
गोधरा,” पृष्ठ 136.
गोधरा ट्रेन नरसंहार 199

वहाँ मौजूद थे। रेलवे कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित थे। कुछ पुलिसकर्मी भी थे।
वे भी मौजूद थे। अगर उसने उसे बचाने के लिए चिल्लाया होता तो वे भी मौजूद होते।
आस-पास मौजूद कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। लेकिन किसी भी विक्रेता ने नहीं।
या फिर कोई और उसके बयान का समर्थन करने के लिए आगे आया है। उसके अनुसार
सबूत इकट्ठा करने के बाद, वे बुकिंग क्लर्क के कार्यालय के अंदर चले गए।

वहाँ किसी को भी इस बारे में सूचित न करना कि क्या हुआ था... उसका स्पष्टीकरण यह था कि
वह बहुत डरी हुई थी और उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया था
उस दिन वडोदरा वापस न जाना, सच नहीं लगता...
यह मानना भी मुश्किल है कि किसी रामसेवक ने किसी का अपहरण करने का प्रयास किया हो।
गोधरा रेलवे स्टेशन की एक घांची मुस्लिम लड़की, और वह भी सबके सामने।
इतने सारे व्यक्तियों का। ऐसे कृत्य के संभावित परिणामों से लोगों को रोका जा सकता था।
किसी भी रामसेवक को ऐसा करने से रोका। उसका साक्ष्य यह है कि वे वहां से चले गए थे।
रेलवे स्टेशन पर उस समय साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली थी।
उस समय तक, अधिकांश रामसेवक ट्रेन के अंदर चले गए होंगे।
जब भी उसने इस घटना के बारे में किसी से बात की, तो उसने कहा कि तीन घटना के चार दिन बाद, उसे एक राहत शिविर में ले जाया गया जिसे स्थापित किया गया था।
वह इकबाल स्कूल में थी और वहां कुछ प्रेस रिपोर्टरों ने उससे पूछताछ की। इसके बाद
लगभग एक महीने तक रेलवे पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। पुलिस रिपोर्ट में उसके बयान के अनुसार,
उसने अपने बयान में कहा था कि लगभग पांच या छह दिनों के बाद किसी रिश्तेदार ने
उनकी जाति के कारण उसे इकबाल स्कूल में भेज दिया गया था। चूंकि उसने कुछ भी नहीं बताया था,
इस घटना के बारे में तब तक किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चला था।

वही। इन परिस्थितियों में, यह संदेह और शंका का विषय बन जाता है कि ऐसा क्यों है।
लगभग पांच दिन बाद किसी ने उससे संपर्क किया और उसे राहत गृह ले गया।
शिविर में, और वह भी उस समय जब प्रेस रिपोर्टर मौजूद थे।
साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने से पहले सलीम पनवाला चिल्लाते हुए भाग गया था।
थाने से खबर आई कि एक घांची मुस्लिम लड़की का अपहरण किया जा रहा है।
कारसेवकों द्वारा। सलीम पनवाला उस स्थान के पास मौजूद नहीं थे और सोफियाबानू के अपहरण के कथित प्रयास को न देखने के बावजूद उन्होंने यह मुद्दा उठाया था।
यह सूचना मिली कि कारसेवकों द्वारा एक घांची मुस्लिम लड़की का अपहरण किया जा रहा है।
इस साक्ष्य से पता चलता है कि सलीम पनवाला उस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए थे।
लगभग उसी समय जब मोहम्मद लतिका और सिदिक बकर चले गए थे
इंजन की तरफ खुले स्थान के पास दौड़ना। इन सभी कारणों से
आयोग इस मत को मानने के लिए इच्छुक है कि वास्तव में ऐसी घटना घटी थी।
ऐसा नहीं हुआ और शायद सोफियाबानू ने जो कहा वह उस समय की बात है। सलीम पनवाला का, जिसने ऐसी झूठी अफवाह फैलाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक
झूठी अफवाह को सच साबित करने का प्रयास। अगर सलीम पनवाला ने जो कहा था, वह सच है।
अगर यह सच होता, तो 200 मोदी, मुसलमानों और मीडिया के दौरान उसकी तलाश करने का प्रयास किया गया होता।

इसके बाद ट्रेन लगभग आठ से दस मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही।
ऐसा किसी ने नहीं किया था।14
क्या यात्रियों ने चेन खींची थी, न कि उपद्रवियों ने? आयोग ने कांग्रेस और जन संघर्ष मंच द्वारा फैलाई गई इस कहानी को भी खारिज कर दिया कि सिग्नल फालिया के पास ट्रेन को रोकने के लिए दो बार चेन खींचने का काम पीछे छूट गए यात्रियों ने किया था, न कि उपद्रवियों ने।15
जांच आयोग के अनुसार, यह उन लोगों द्वारा पूर्वनियोजित कदम था जिन्होंने ट्रेन पर हमला करने की साजिश रची थी ताकि उसे सिग्नल फालिया में फंसाया जा सके क्योंकि यह एक घांची मुस्लिम बस्ती से घिरा हुआ था जहां दंगाइयों को स्टेशन के विपरीत पूरी छूट मिल जाती, जहां कम से कम पुलिस की सांकेतिक उपस्थिति और कई अन्य गवाह मौजूद थे।
क्या कारसेवकों ने चाय विक्रेता पर हमला करके मौत को न्योता दिया? आरोपियों का बचाव करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद और जन संघर्ष मंच ने शुरू में तर्क दिया था कि इस ट्रेन से यात्रा कर रहे रामसेवकों का उज्जैन और रुदौली स्टेशनों पर कुछ मुस्लिम विक्रेताओं से झगड़ा हुआ था, और इसलिए प्रतिशोध के रूप में गोधरा में यह घटना घटी। चूंकि इसकी खबर गोधरा पहुंच गई थी, इसलिए मुसलमान पहले से ही नाराज थे। गोधरा में, कारसेवकों ने फिर से विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे कहासुनी हो गई। लेकिन रेलवे कर्मचारियों सहित सभी गवाहों ने उज्जैन में ऐसी किसी घटना से इनकार किया। अगर उज्जैन या रुदौली में किसी सड़क विक्रेता के साथ किसी तरह की बहस या झगड़े की थोड़ी सी भी सच्चाई होती, तो उज्जैन के एक सड़क विक्रेता द्वारा सैकड़ों मील दूर एक रेलवे कोच को जलाने के लिए 1,500 या उससे अधिक लोगों की भीड़ जुटाना, केवल "क्रिया-

प्रतिक्रिया" की कहानी के बजाय एक काउंटी-व्यापी आपराधिक माफिया नेटवर्क के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। रतलाम स्थित रेलवे के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ने अपने बयान में कहा था कि ट्रेन दाहोद तक शांतिपूर्वक चली।
इस मामले में एकमात्र अन्य साक्ष्य दाहोद रेलवे चौकी के सहायक सब-इंस्पेक्टर रत्नाभाई और हेड कांस्टेबल लखाभाई का है। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ रामसेवक पानी, चाय आदि लेने के लिए प्लेटफार्म पर उतरे और उन्होंने "जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम का नाम बढ़ाएंगे" के नारे लगाए। (हम इसी स्थान पर मंदिर बनाएंगे और राम का नाम गौरवान्वित करेंगे)। चूंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को देखा,
14 वही, पृ. 48-50.
15 वही, पृष्ठ 106.
गोधरा ट्रेन नरसंहार 201

उस ट्रेन में यात्रा कर रहे रामसेवकों ने इस बारे में गोधरा रेलवे पुलिस को सूचित करना उचित समझा था।
आयोग के समक्ष दिए गए बयानों, जिनमें रेलवे कर्मचारियों के बयान भी शामिल हैं, से यह साबित हुआ कि ट्रेन क्षमता से कहीं अधिक भरी होने के बावजूद, पिछले किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई कहा-सुनी या लड़ाई नहीं हुई थी। आयोग ने पाया कि सभी विवरणों के अनुसार, कारसेवकों ने ज़्यादा से ज़्यादा रामधुन और अन्य भजन गाए। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में नारे भी लगाए। लेकिन इनमें से किसी भी बात के कारण पिछले किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई कहा-सुनी या लड़ाई नहीं हुई।16 इसलिए, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है:

लाइसेंस-कोटा राज की एक आम कहानी है, जो जहां भी इसे लागू किया जाता है, वहां माफियाओं को जन्म देता है।
चाय विक्रेताओं में से एक के कर्मचारी अजय कनुभाई ने अपने बयान में उस सुनियोजित रैकेट का खुलासा किया, जिसके माध्यम से एक छोटा समूह विक्रेताओं के स्टेशन तक पहुंच को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी विक्रेता जो अपनी चाय बेचते हैं,
16 वही, पृ. 38-40.
17 वही, पृष्ठ 41.
202 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उनके जैसे कर्मचारियों के माध्यम से प्लेटफार्म पर सामान बेचने वाले घांची मुस्लिम थे, जिनके नेता सलीम पनवाला और रजाक कुरकुर थे। दोनों अच्छे दोस्त और व्यापारिक साझेदार थे। वे सभी विक्रेताओं को नियंत्रित करते थे, जिन्हें रजाक कुरकुर के नकली मिनरल वाटर पाउच, नकली एयरेटेड ड्रिंक्स और अन्य सामान बेचने के लिए मजबूर या प्रेरित किया जाता था। सभी विक्रेता सलीम पनवाला और रजाक कुरकुर से डरते थे। विक्रेता स्वयं भी दृढ़ निश्चयी थे, और न तो रेलवे कर्मचारी और न ही रेलवे पुलिसकर्मी उन्हें नियंत्रित कर पाते थे।18
गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के पांच मिनट के ठहराव के दौरान, कुछ यात्री चाय पीने के लिए बाहर निकले। बताया जाता है कि चाय विक्रेता सिदिक बाहर का रामसेवकों के साथ चाय के भुगतान को लेकर झगड़ा हो गया। रामसेवकों ने कहा कि उन्होंने भुगतान कर दिया था, जबकि बाकर ने कहा कि उन्होंने भुगतान नहीं किया था। इस झगड़े में, कुछ रामसेवकों ने कथित तौर पर सिदिक बाकर को लाठी से दो बार मारा। 19 लेकिन पुलिस के पास जाने के बजाय, दोनों मुस्लिम विक्रेता

(लतीका और सिदिक बाकर) सिग्नल फालिया की ओर भागे और वहाँ भीड़ जमा हो गई जिसने ट्रेन पर पथराव किया।20
इस घटना का इस्तेमाल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जन संघर्ष मंच और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यह तर्क देने के लिए किया कि कारसेवकों ने अपने आक्रामक व्यवहार से ट्रेन पर हमले को "भड़काया" था। इस सिद्धांत को तीस्ता सेतलवाद के एनजीओ ने भी एक मुस्लिम लड़की के अपहरण के प्रयास की झूठी कहानी के साथ खुलकर फैलाया। उन्होंने बेशर्मी से कहा कि कारसेवकों को "निर्दोष यात्री" कहना मुश्किल है क्योंकि वे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अभियान का हिस्सा थे। अब यह वाम-कांग्रेस के इस तर्क का हिस्सा बन गया है कि कारसेवकों ने खुद ही मुसीबत मोल ली थी।
एक या दो यात्रियों की चायवाले से कथित झड़प के आधार पर रेलगाड़ी के पूरे डिब्बे को जिंदा जला देने के इस विकृत तर्क का तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि गुजरात के बाकी हिस्सों में हुई जवाबी हिंसा भी जायज है। किसी भी मामले में, यह अकल्पनीय है कि स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन पर हमला करने के लिए दो-तीन मिनट के भीतर 1,500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है और यह भीड़ उस छोटी सी घटना से इतनी प्रेरित हो सकती है कि बदला लेने के लिए पुलिस के साथ भीषण झड़प करे। बाकी परिस्थितिजन्य तथ्यों को देखते हुए,

18 वही, पृष्ठ 42
19 वही, पृ. 43-4
20 वही, पृष्ठ 46
गोधरा ट्रेन नरसंहार 203

सबूतों से यह अत्यधिक संभावना प्रतीत होती है कि यह झड़प भी उन लोगों द्वारा रची गई एक सुनियोजित घटना थी जिन्होंने पहले से ही ट्रेन को जलाने की योजना बना रखी थी।
क्या कारसेवक चूल्हे पर खाना बना रहे थे जिससे आग लगी? जन संघर्ष मंच और कांग्रेस पार्टी के वकीलों द्वारा अदालत में पेश किया गया एक और बेतुका तर्क कोच एस/6 में आग लगाने वाली भीड़ के अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है और तर्क देता है कि आग दुर्घटना थी - चलती ट्रेन में खाना पकाने का चूल्हा पलट जाने के कारण लगी थी।
आयोग ने इस बात को यह कहकर खारिज कर दिया कि कोच एस/6 समेत पूरी ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई थी कि लोग फर्श पर बैठे थे, बर्थ के नीचे लेटे थे, शौचालय के बाहर बैठे थे और निकास व प्रवेश द्वारों का रास्ता अवरुद्ध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में यह सोचना बेतुका है कि लोग ताजा भोजन पकाने के लिए अस्थायी रसोई बनाने की जगह ढूंढ लेंगे।
दूसरे, अगर एक छोर पर चूल्हे में आग लग जाती, तो लोग दूसरे छोर से आसानी से ट्रेन से बाहर निकल सकते थे। शरारती तत्वों द्वारा दरवाजों को बाहर से बंद कर देना, खिड़कियों के शीशे तोड़ देना और ट्रेन पर पत्थरबाजी के स्पष्ट निशान यह साबित करते हैं कि यह कहानी मनगढ़ंत थी।
तीसरी बात, जब तक ट्रेन में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ नहीं फेंके गए होते, तब तक जलने की चोटें इतनी गंभीर नहीं हो सकती थीं, और चूल्हे से एक लीटर केरोसिन के कारण डिब्बे का फर्श धंसना संभव नहीं था।
क्या बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी? एस/6 कोच की बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के इस कमजोर तर्क को नानावती आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में यात्री आश्रय के लिए ऊपर की बर्थों पर नहीं चढ़ते, क्योंकि

सभी बिजली की वायरिंग डिब्बे की छत के पास स्थित होती है। इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग एक मिनट के भीतर पूरे कोच को धुएं और लपटों में नहीं घेर सकती थी। इससे यात्रियों को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता।
दुर्भाग्य से, कोच में स्वतः प्रज्वलन की इन विचित्र कहानियों को तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने तब मान्यता दी, जब उन्होंने सितंबर 2004 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेन का डिब्बा जमीन से इतनी ऊंचाई पर होने के कारण बाहरी हमलावरों द्वारा आग लगाना संभव नहीं था और यह एक दुर्घटना थी। बनर्जी समिति ने यह भी तर्क दिया कि सिग्नल फालिया में मौजूद भीड़ में "निर्दोष" लोग शामिल थे और आग या तो चूल्हे के फटने या बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है।
204 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मीडिया का दुष्प्रचार: रामसेवकों ने खुद मुसीबत मोल ली। जिस तेज़ी से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी गैर सरकारी संगठनों ने गोधरा नरसंहार का पक्षपातपूर्ण संस्करण एक सरल मीडिया को परोसा, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक पूर्व नियोजित योजना थी। अपनी पुस्तक 'गोधरा: द मिसिंग रेज'21 में एस.के. मोदी कहते हैं: टेलीविजन समाचार चैनलों ने जलते हुए एस/6 कोच की तस्वीरें दिखाईं।
और दिनभर लाशें पड़ी रहीं। लेकिन कुछ तो गायब था।
क्रोध गायब था… आक्रोश का कोई नामोनिशान नहीं था… कुछ दिनों बाद समता पार्टी की जया जेटली ने इस घटना के बारे में लिखा: "...गोदरा पर...

जब सत्ता पक्ष ने विपक्ष से शामिल होने की गुहार लगाई तो सन्नाटा पसरा रहा।
इस घटना की सर्वसम्मति से निंदा करते हुए... सोनिया गांधी को ऐसा महसूस नहीं हुआ।
27 फरवरी को प्रधानमंत्री से मिलने की जरूरत है… फरवरी को चुप्पी छाई हुई है
27, 2002 का दिन बेहद भयावह था। उदासीनता पूर्ण थी। असंवेदनशीलता चरम पर थी।
बेहद गुस्सा दिलाने वाला।
कई पत्रकारों ने कांग्रेस के सहयोगियों द्वारा दिए गए इस दृष्टिकोण को दोहराया कि कारसेवकों ने ही मुसीबत को न्योता दिया था; उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही था क्योंकि उन्हें हिंदू संगठनों द्वारा संगठित किया गया था और वे ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने पर तुले हुए थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे कट्टर मुखपत्र एनडीटीवी ने उस समय अपनी प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए गोधरा हत्याकांड पर एक विकृत विमर्श तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 27 फरवरी को गोधरा घटना का इसका शुद्धीकृत संस्करण, गोधरा के बाद के दंगों के इसके उन्मादी कवरेज के बिल्कुल विपरीत, अन्य सभी के लिए मानक टेम्पलेट बन गया। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कम से कम 57 लोगों के मारे जाने और 43 लोगों के घायल होने की आशंका है।
सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन की चार बोगियों पर हमला कर उनमें आग लगा दी गई।
गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास कारसेवक। [मेरे द्वारा ज़ोर दिया गया]

एनडीटीवी द्वारा हमलावरों को "अज्ञात व्यक्ति" कहना, जबकि गोधरा की जनता को भीड़ हिंसा के नेताओं के बारे में पहले दिन से ही जानकारी थी, भ्रामक जानकारी देने के इरादे को दर्शाता है।
28 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर की हेडलाइन थी: "गुजरात में भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया, 55 लोगों की मौत।" इस रिपोर्ट के लेखक, सज्जाद शेख ने अफवाहों के आधार पर इस सामूहिक हत्याकांड को लगभग जायज ठहराया।
21 एस.के. मोदी, गोधरा: द मिसिंग रेज (नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, 2004), पृष्ठ 26-9।
गोधरा ट्रेन नरसंहार 205

हिंसा के दोषियों के बारे में उन्होंने कहा, “ट्रेन में मौजूद कारसेवकों ने सिग्नल फालिया की कुछ धोबिनों के साथ दुर्व्यवहार किया।” उन्होंने गोधरा घटना के कारणों में से एक के रूप में “दाहोद में एक धार्मिक स्थल पर हमले की अफवाह” का भी हवाला दिया। इसका तात्पर्य यह है कि 55 लोगों को जिंदा जलाना किसी हद तक समझ में आता है, क्योंकि कारसेवकों ने कथित तौर पर मुसीबत को न्योता दिया था।
द हिंदू ने 28 फरवरी, 2002 के अंक में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित की: “गुजरात में भीड़ द्वारा ट्रेन में आग लगाने से 57 लोग मारे गए।” इस रिपोर्ट के लेखक, मानस दासगुप्ता, बताते हैं कि “प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन में लगभग 1,200 रामसेवक यात्रा कर रहे थे। मुस्लिम बहुल गोधरा कस्बे के स्थानीय लोग कुछ दिन पहले उसी ट्रेन से अयोध्या जाते समय रामसेवकों द्वारा इस्तेमाल की गई अपशब्दों से ‘आक्रोशित’ थे। बताया जाता है कि आज सुबह वापसी यात्रा पर ट्रेन के गोधरा पहुँचने पर उन्होंने नारे लगाए।” इससे एक बार फिर यह संकेत मिलता है कि रामसेवकों ने अपने

नारों से हिंसा भड़काई थी। इस रिपोर्ट का सबसे अजीब पहलू यह है कि इसमें यह संकेत दिया गया है कि गोधरा के विक्रेताओं ने अयोध्या जाते समय रामसेवकों द्वारा कथित तौर पर किए गए अपशब्दों का बदला लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार किया था।
हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर यह शीर्षक छापा: "गुजरात अयोध्या के प्रकोप की चपेट में।" यह भी अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेन में आग लगाने वालों की कार्रवाई को जायज ठहराता है।
जैसे ही गुजरात के बाकी हिस्सों में जवाबी हिंसा भड़की, गोधरा हत्याकांड को दबा दिया गया और उसे जनमानस से मिटाने की कोशिश की गई, मानो उसका बाद में हुए दंगों से कोई संबंध ही न हो। दूसरी ओर, प्रिंट मीडिया और टीवी में खबरें यह दोहराने लगीं कि यह राम मंदिर आंदोलन का स्वाभाविक परिणाम था। उदाहरण के लिए, द हिंदू ने 1 मार्च, 2002 के अंक में लिखा:
बुधवार को गोधरा में हुई भीषण आगजनी की घटना में लगभग 50 यात्रियों की जान चली गई।
साबरमती एक्सप्रेस में मरने वालों में से अधिकांश कारसेवक थे जो वापस लौट रहे थे।
अयोध्या और अन्य जगहों पर इसके कारण भड़की अंधाधुंध हिंसा की प्रतिक्रिया
राज्य में, हिंसक भीड़ ने अल्पसंख्यकों पर जवाबी हमले करते हुए हिंसक झड़पें कीं।
समुदाय और उसकी संपत्तियां, विस्फोटक स्थिति की ओर स्पष्ट और चिंताजनक संकेत देती हैं।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है।
राम मंदिर के निर्माण के लिए उत्तेजक और विनाशकारी अभियान अयोध्या में। गोधरा में क्या हुआ, जिसके बारे में अलग-अलग मत हैं।

और परस्पर विरोधी बयान देना एक घिनौना कृत्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
स्पष्ट रूप से।
206 मोदी, मुसलमान और मीडिया

इसके बावजूद, इस बात की कठोर वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस तरह की घटनाओं का परिणाम क्या होता है...
गोधरा की भयावहता, घायलों के परिणामस्वरूप, दुखद रूप से पूर्वानुमेय थी।
और वीएचपी का आक्रामक सांप्रदायिक अभियान। यह निर्दयतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।
मंदिर निर्माण का कार्य 15 मार्च को शुरू करने के अपने एजेंडे पर वह अडिग है, चाहे कुछ भी हो जाए।
जन लामबंदी के माध्यम से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना और देशभर में लगभग दस लाख रामसेवक। [मेरे द्वारा ज़ोर दिया गया] टाइम्स ऑफ इंडिया के 1 मार्च के अंक में सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा, “हालांकि आधिकारिक जांच से यह पता चलेगा कि साबरमती एक्सप्रेस पर हमला किस हद तक पूर्व नियोजित था, लेकिन गुरुवार (28 फरवरी) को गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ निर्देशित हिंसा की सुनियोजित प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता।” www.gujaratriots.com22 टीम द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार: उनकी रिपोर्ट से दोहरा मापदंड स्पष्ट है, जो भेदभाव करती है।
27 फरवरी की घटनाओं की तुलना 28 फरवरी की घटनाओं से करते समय। उनका कहना है कि 27 फरवरी को हुए गोधरा हमलों के पीछे पूर्व नियोजित साजिश थी।
यह "सरकारी जांच" ही तय करेगी कि कारसेवकों पर हमला हुआ था या नहीं।

यह पूर्व नियोजित था या नहीं। लेकिन जब हिंदुओं की हिंसक प्रतिक्रिया की बात आती है तो
28 फरवरी को, वह हमलों के संबंध में फैसला सुनाने का जिम्मा खुद अपने हाथों में लेता है।
गुजरात के मुसलमानों पर हिंदुओं द्वारा किए गए हमले "पूर्व नियोजित" प्रकृति के थे...
यह समाचार रिपोर्ट गोधरा नरसंहार के ठीक दो दिन बाद प्रकाशित हुई थी।
450 से अधिक शब्दों के इस लेख में कारसेवकों की जघन्य हत्या का उल्लेख केवल एक बार किया गया है।
रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ हुए अत्याचारों का भयावह वर्णन है।
इस घटना के बाद लोगों की बेरहमी से हत्या की जा रही है।
विदेशी संवाददाताओं की रिपोर्टें भी कांग्रेस से संबद्ध गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचारित संस्करण पर आधारित थीं। लेकिन 20 मार्च, 2002 को ब्रिटिश अखबार 'द इंडिपेंडेंट' में पीटर पोफम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की नवीनता की बराबरी कुछ ही कर पाईं। …कार S/6 में जो हुआ वह एक भयावह अंत था। कहानी लगभग 36 साल पहले शुरू हुई थी।
कुछ घंटे पहले। उनमें से कई लोग नशे में थे या ड्रग्स के असर में थे, या ऐसा करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस थे:
लचीले और सहिष्णु हिंदू धर्म में ऐसी चीजों के बारे में कोई कठोर नियम नहीं हैं। और
वे गुजरात लौट रहे थे, जो भारतीय संघ का एकमात्र राज्य है।
22 “गोधरा में हुई पूरी घटना: नरसंहार कैसे हुआ,” गुजरात दंगे: सच्ची कहानी, 22 मई, 2008, वेब. http://www.gujaratriots.com/index.php/page/3/?s.

गोधरा ट्रेन नरसंहार 207

अभी भी 'सूखा' है। इसलिए एक-दो बोतलें छिपाकर रखना और भी ज़रूरी है। … ट्रेन
देरी हो रही थी: डेढ़ दिन बाद, यह साढ़े चार घंटे पीछे चल रही थी। इसीलिए यह गोधरा में निर्धारित समय के अनुसार सुबह 2.55 बजे नहीं, बल्कि
सुबह 7:15 बजे तक, कारसेवकों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मुसीबत यह यात्रा दाहोद स्टेशन से शुरू हुई थी, जो रेलवे ट्रैक पर लगभग एक घंटे और 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ट्रेन सुबह करीब 6 बजे दाहोद पहुंची और कई कारसेवक ट्रेन से उतर गए।
डिब्बे S/6 के यात्री प्लेटफार्म पर एक स्टॉल पर चाय और नाश्ता करने जाएंगे।
वे नशे में धुत और उद्दंड थे। हिंदुओं और उनके बीच बहस छिड़ गई।
एक विवरण के अनुसार, चाय की दुकान चलाने वाले मुस्लिम व्यक्ति ने मना कर दिया।
उसे 'जय श्री राम' का जाप करने पर ही भुगतान करना होगा, जो भगवान राम के भक्तों का मंत्र है।
उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने वापस जाने से पहले उसकी दुकान को तोड़ना शुरू कर दिया।
डिब्बे में घुसने के बाद, दुकानदार ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
नानावती जांच आयोग को ऐसी किसी शिकायत का कोई सबूत नहीं मिला।
और दाहोद।]
अचानक, विवाद ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया: कारसेवकों ने मोर्चा संभाल लिया।

एक मुस्लिम महिला की कहानी। उसकी पहचान और वह इसमें कैसे शामिल हुई, यह रहस्य बना हुआ है।
अस्पष्ट है लेकिन चार अलग-अलग गवाह इस घटना का जिक्र करते हैं। एक का कहना है कि यह
पीड़ित चाय विक्रेता की 16 वर्षीय बेटी ने आगे आकर कोशिश की। अपने पिता को बचाने के लिए।’ एक अन्य कहानी में रेलवे ट्रैक के किनारे कपड़े धो रही एक महिला का जिक्र है।
रस्सी को खींचकर ले जाया जा रहा है। एक तीसरी घटना में बताया गया है कि कैसे बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की...
और स्टेशन प्लेटफॉर्म से होकर स्कूल जाने का शॉर्टकट लेने पर उन पर हमला कर दिया गया।
और उसे गाड़ी में घसीटकर ले जाया गया। सभी इस बात से सहमत हैं कि एक मुस्लिम महिला को घसीटा गया था।
कारसेवकों ने गाड़ी में प्रवेश किया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया और किसी को अंदर नहीं जाने दिया।
उसे जाने दो। नाम न बताने की शर्त पर एक स्थानीय पुलिसकर्मी ने इस कहानी की पुष्टि की।
और अचानक, जो महज एक छोटी-सी बदसूरत झड़प, एक नशे में धुत लोगों का तमाशा था, वह बदल गया।
सत्ता और अधीनता का मुद्दा कहीं अधिक विस्फोटक बन गया। कारसेवकों वे अपनी जान की ज़ुल्म के लिए हद से ज़्यादा नशे में थे, वरना वे कोई और रास्ता चुन लेते।
ऐसा स्टंट करने के लिए उपयुक्त स्थान। क्योंकि अब सामाजिक भूगोल गोधरा की भूमिका सामने आई। [मेरे द्वारा ज़ोर दिया गया]
हिंदुओं के लिए खेद की बात यह है कि गोधरा स्टेशन एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो

अब पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय का केंद्र बन गया। और मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायों का एक समूह उभर कर सामने आया।
रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झोपड़ियों में, जिनमें से कई मोटर-मरम्मत के कारखाने हैं। यह छोटा सा
सिग्नल फालिया के नाम से जानी जाने वाली इस झुग्गी बस्ती में दंगे के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां मौजूद हैं: ढेर सारे
ईंटें, पेट्रोल, पैराफिन और कैलोरी गैस सिलेंडर। लेकिन इसमें आवश्यक सामग्रियां भी थीं।
मानव सामग्री: एक गरीब, कड़वाहट से ग्रस्त और जीवित समुदाय। अपराध की सीमाएँ।
कारसेवकों द्वारा पकड़ी गई महिला को डिब्बे S/6 में घसीटकर ले जाया गया, और 208 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

जो कुछ हुआ था उसकी खबर फैलने लगी। लड़की चीखने लगी।
'मदद करो,' अहमद ने कहा, जो लकड़ी का व्यापारी था और दूसरी तरफ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था।
रास्ता। ट्रेन में सफर कर रहे मुसलमान उतर गए। लोग बाहर निकलने लगे।
उसे बचाने की कोशिश में मैं प्लेटफार्म पर चढ़ गया। मैं घर की ओर भागा - मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है।
शराब बनाना...
ट्रेन चल पड़ी और जमा हुई भीड़ ने डिब्बे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
ईंटें। ट्रेन के अंदर, किसी ने आपातकालीन रस्सी खींची; ट्रेन रुक गई।
फिर गाड़ी दोबारा चलने लगी; स्टेशन से एक किलोमीटर दूर जाकर रस्सी को फिर से खींचा गया।

और इस बार ट्रेन रुक गई और रुकी ही रही। ‘आसपास के लोग...
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, ‘लोग ट्रेन के पास इकट्ठा होने लगे। भीड़ ने... अनुरोध किया कि
कारसेवकों ने लड़की को लौटा दिया। लेकिन लड़की को लौटाने के बजाय, उन्होंने शुरू कर दिया।
उन्होंने अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। इससे भीड़ भड़क उठी...
यह झड़प एक लड़ाई में बदल गई, जिसमें कारसेवक अपनी तलवारों के साथ कूद पड़े।
और लाठियाँ, और अब कहा जा रहा है कि 1,000 लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
झुग्गी बस्ती में, पेट्रोल, गैस, चिथड़े-चिट्ठे - जलने वाली कोई भी चीज़ लेकर आते थे। उनके गैस सिलेंडर भी साथ लाते थे।
खिड़कियों की सलाखें टूट गईं और अंदर विस्फोट हो गया; पेट्रोल बम हवा में उड़ने लगे।
और उसने गद्दी और अंदर फंसे लोगों को आग लगा दी।
एक घंटे बाद जब पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची, तब तक वहां कुछ भी नहीं था।
बच जाओ…
दुर्भाग्यवश, द इंडिपेंडेंट में कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश करने से यह "धर्मनिरपेक्षतावादियों" का पसंदीदा संस्करण बन गया और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरस की तरह फैल गया। गुजरात को थोड़ा- बहुत भी जानने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि शराबबंदी का उल्लंघन करके शराब पीने वाले गुजराती भी ऐसा कभी सार्वजनिक रूप से नहीं करते, खासकर महिलाओं और बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं - और वह भी धार्मिक यात्रा से लौटते समय तो बिल्कुल नहीं।
लेकिन इन सभी कुटिल व्याख्याओं का मूल स्रोत तीस्ता सेतलवाद थीं। उन्होंने इस बात को राजनीतिक रूप से प्रचलित कर दिया कि गोधरा

ट्रेन हत्याकांड में मारे गए हिंदू "उग्रवादी कारसेवक" थे, इसलिए उन्हें "निर्दोष यात्री कहना असंभव है"। इसका अर्थ यह है कि वे कत्लेआम के पात्र थे। आज भी, सांप्रदायिकता विरोधी संगठन की वेबसाइट इसी पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रही है, जबकि नानावती आयोग ने दर्ज किया है कि कारसेवकों ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उनका कत्लेआम हो।
उस समय, हिंदुस्तान टाइम्स के मुख्य संपादक वीर संघवी उन कुछ पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने औचित्य साबित करने की प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी दी थी।
गोधरा ट्रेन नरसंहार 209

ट्रेन नरसंहार। 27 फरवरी, 2002 को पक्षपातपूर्ण टीवी कवरेज के जवाब में लिखे गए उनके लेख 23 में कहा गया है:
संभावित प्रतिक्रिया में कुछ बेहद चिंताजनक बात है।
गोधरा नरसंहार के लिए धर्मनिरपेक्ष प्रतिष्ठान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है...
कुछ संस्करणों में कहा गया है कि कारसेवकों ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए; जबकि अन्य संस्करणों में कहा गया है कि...
उन्होंने मुस्लिम यात्रियों को ताने मारे और परेशान किया। इन विवरणों के अनुसार,
मुस्लिम यात्री गोधरा में उतरे और अपने समुदाय के सदस्यों से अपील की।
मदद के लिए समुदाय से गुहार लगाई। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि नारे ही लोगों को भड़काने के लिए काफी थे।
स्थानीय मुसलमानों और इस हमले के बदले की भावना से किए गए हमले... यह वाकई असाधारण लगता है।
चलती ट्रेन से या रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगाए गए नारे,

स्थानीय मुसलमानों को इतना गुस्सा दिलाने के लिए काफी था कि उनमें से 2,000 लोगों ने ऐसा किया।
सुबह आठ बजे जल्दी से इकट्ठा हो गए, क्योंकि पहले ही व्यवस्था कर ली गई थी।
पेट्रोल बम और एसिड बम।
दुर्भाग्यवश, गुजरात दंगों की कवरेज में, हिंदुस्तान टाइम्स और अधिकांश अन्य समाचार पत्रों ने अपनी सभी रिपोर्टिंग में कांग्रेस पार्टी के पूर्वाग्रह को पूरी निष्ठा से हावी होने दिया। परिणामस्वरूप, बहुत कम लोग जानते हैं कि नानावती आयोग और अदालतों ने गोधरा हिंसा को कांग्रेस पार्टी के भीतर के कुछ शरारती तत्वों का काम माना था, जिनके कथित तौर पर पाकिस्तानी संगठनों से भी संबंध थे। जब मैंने मोदी से पूछा कि क्या स्थानीय कांग्रेस नेताओं के अलावा, दिल्ली स्थित कोई नेता गोधरा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, तो उन्होंने कहा:
हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया जो उचित जांच के बाद दोषी पाए गए और
जांच-पड़ताल। नानावती आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का एक हिस्सा यह है कि
पहले ही रिहा कर दिया गया था। उसके बाद, एसआईटी ने अपनी जांच की और हम आगे बढ़े।
उन्हीं के आधार पर। अगर मैं गोधरा कांड में पार्टी की राजनीति को घसीटता हूँ, तो
इससे आने वाले वर्षों में गुजरात को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। मुझे चाहिए
इन मामलों में मैं अपनी निजी राय नहीं दूंगा। ऐसी बातें
इसका पेशेवर तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। सरकारी एजेंसियां ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

[illegible] - [illegible]
[illegible]
23 [illegible], [illegible]: [illegible] 23 [illegible], 2011, [illegible]. http://virsanghvi.com/Article-Details.aspx?Key=611. ([illegible] 2002 [illegible])[illegible]
210 [illegible], [illegible]

[illegible] "[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] (1887-1971) [illegible] (1889-1964) [illegible] "[illegible]-[illegible]" [illegible]

सच्चाई की परवाह किए बिना, बहुसंख्यक को ही दोषी ठहराया जाता है… तो पारंपरिक सहिष्णुता के स्रोत सूख जाएंगे।”24
इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करने के बहाने, कांग्रेस पार्टी ने बहुसंख्यक वर्ग को बदनाम करना अपना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में ऐसी विकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

24. के.एम. मुंशी, भारतीय संवैधानिक दस्तावेज: स्वतंत्रता की तीर्थयात्रा, 1902-1950, द्वितीय संस्करण
ed. (Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, 2012), p. 312.

अध्याय 12

गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी जरूरत थी?
कांग्रेस या नरेंद्र मोदी?

क्या आपको गुजरात में पुलिस की कुल संख्या का पता है? पुलिस एक साथ कितने स्थानों पर लोगों को बचा सकती थी? वे सेना और अर्धसैनिक बलों की भूमिका के बारे में बात क्यों नहीं करते? वे समय पर कार्रवाई से बचाई गई जिंदगियों के बारे में कभी बात क्यों नहीं करते? केवल मृतकों की ही बात क्यों करते हैं?... यदि ऐसे प्रत्येक स्थान पर 10,000 से 15,000 लोगों की भीड़ हो और स्थानीय थाने में केवल 10-20 पुलिसकर्मी हों, तो पुलिस क्या कर सकती है, खासकर तब जब इन 20 में से शायद केवल पाँच के पास राइफलें हों और एक के पास पिस्तौल हो... अधिकांश पुलिसकर्मी केवल डंडा लेकर चलते हैं। ऐसा पुलिसकर्मी पत्थरबाजी कर रही 10,000 लोगों की क्रोधित भीड़ का सामना कैसे करेगा?... हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने अपना गुस्सा निकाला। कई स्थानों पर मुसलमान असुरक्षित साबित हुए, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर हिंदू कमजोर समूह बन गए। रईस खान, जो 2002 से 2008 तक तीस्ता सेतलवाद के दाहिने हाथ थे।

2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा को लगातार "नरसंहार" और भाजपा द्वारा प्रायोजित "मुसलमानों का नरसंहार" बताया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। यह एक ऐसा स्थापित नैरेटिव बन गया है कि जो कोई भी इस विकृत संस्करण को चुनौती देने की हिम्मत करता है, उसे तुरंत हिटलरवादी फासीवादी राजनीति का समर्थक करार दिया जाता है और वह घृणा के अंधाधुंध अभियान का निशाना बन जाता है।

दंगे और नरसंहार में अंतर: कई दंगों को व्यक्तिगत रूप से कवर करने वाले व्यक्ति के रूप में, मेरा मानना है कि अंतर-सामुदायिक हिंसा की प्रकृति को समझने और दंगे तथा नरसंहार के बीच अंतर करने के लिए कुछ बुनियादी नियम आवश्यक हैं। 'नरसंहार' को किसी जातीय या धार्मिक समूह के हिंसक नरसंहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से रूस और पूर्वी यूरोप के ईसाइयों द्वारा यहूदियों पर किए गए एकतरफा, बिना उकसावे वाले हमलों के संदर्भ में किया जाता था। यहूदी एक क्रूर रूप से उत्पीड़ित और नफरत का शिकार अल्पसंख्यक बने रहे, जिन्होंने 212 मोदी, मुस्लिम और मीडिया में अंतहीन हिंसा का सामना किया।

यूरोप और रूस भर में ईसाइयों के हाथों हुए अत्याचारों का अंत हिटलर के जर्मनी में एक व्यापक नरसंहार के रूप में हुआ। भारत में मुसलमानों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सदियों तक हिंदू बहुसंख्यक आबादी पर मुस्लिम आक्रमणकारियों और सम्राटों का शासन रहा। इनमें से कई मुस्लिम शासक अपने हिंदू प्रजाजनों पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार करते थे।
इसी प्रकार, 'नरसंहार' को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक समुदाय या समूह को दूसरे द्वारा मार डाला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अपराधी पक्ष बल पर पूर्ण नियंत्रण में है, जबकि पीड़ित समूह पूरी तरह से अपने हमलावरों की दया पर निर्भर है।
नवंबर 1984 में, कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों में सिखों की हत्याओं को पूरी तरह से नरसंहार कहा जा सकता है क्योंकि ये हत्याएं पूरी तरह से एकतरफा थीं। यह हिंदू-सिख दंगा नहीं था। वास्तव में, हिंदू समुदाय भी इन हिंसक भीड़ से उतना ही स्तब्ध था जितना सिख। कांग्रेस पार्टी ने गुंडों को किराए पर

लिया था जिन्होंने उन्माद का नाटक किया और अकेले दिल्ली में 3,000 से अधिक सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी। उत्तर भारत के कई शहरों में हजारों और लोगों को मार डाला गया या जिंदा जला दिया गया। मरने वाले सभी सिख थे; केवल सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। सिखों द्वारा हिंदुओं की हत्या करने या किसी अन्य समुदाय की महिलाओं का अपहरण करने की एक भी घटना नहीं हुई। सिख आम तौर पर असहाय समुदाय नहीं हैं और न ही वे उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। हालांकि, चूंकि कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं द्वारा हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जानबूझकर कानून व्यवस्था को निष्क्रिय करने की बात ज्ञात है, इसलिए हत्यारों और आगजनी करने वालों को तीन-चार दिनों तक खुली छूट मिल गई।
दिल्ली छावनी में सेना की तैनाती पूरी तरह से तैयार थी, फिर भी तीन दिनों तक स्थिति नियंत्रण में आने तक उसे नहीं बुलाया गया। पुलिस ने हिंसक भीड़ पर एक भी गोली नहीं चलाई। उन्हें या तो अनदेखी करने या फिर हत्यारी भीड़ की सक्रिय रूप से सहायता करने का आदेश दिया गया था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का भी कोई मामला सामने नहीं आया। उन दिनों आगजनी करने वालों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। 31 अक्टूबर, 1984 से 3 नवंबर, 1984 तक अराजकता का माहौल बना रहा। संपत्ति का नुकसान भी एकतरफा था। केवल सिखों के घरों में आग लगाई गई; भीड़ ने केवल सिखों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों को लूटा। किसी भी सिख ने लूटपाट नहीं की। हालांकि, गुजरात में गोधरा कांड और उसके बाद की हिंसा में स्थिति काफी अलग थी। इसकी शुरुआत राजनीतिक रूप से उकसाई गई मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं पर किए गए एकतरफा, पूर्व नियोजित और बिना किसी उकसावे के हमले से हुई। गोधरा कांड के बाद की हिंसा में भी न तो

हत्याएं हुईं और न ही घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाना और लूटना एकतरफा था।
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी? 213

2002 के दंगों के बारे में तथ्यों को चुनिंदा तरीके से पेश करने और रिपोर्टिंग के माध्यम से जैसा दिखाया गया, वैसा पक्षपातपूर्ण नहीं था। इसका यह अर्थ नहीं है कि गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा में मुसलमानों को जान-माल का भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। साथ ही, यह भी सच है कि कई मामलों में प्रमुख राजनेताओं ने जन आक्रोश को भड़काया और उसका फायदा उठाया, और कई मौकों पर पुलिस ने तब तक आंखें मूंद रखीं जब तक भीड़ ने उत्पात मचाना जारी रखा।
हालांकि, स्पष्ट विफलताओं और चूकों के बावजूद—कुछ जानबूझकर और कई अनजाने में—बाद की जांचों से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने समग्र रूप से अनदेखी नहीं की। मुख्यमंत्री ने तेजी और दृढ़ता से कार्रवाई की, जबकि उनके कुछ मंत्रिमंडल और पार्टी सहयोगियों ने ऐसे काम किए जिनसे आग में घी डाला गया। 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के विपरीत, जो कांग्रेस पार्टी की एकतरफा कार्रवाई थी, 2002 के गुजरात दंगों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने समान भूमिका निभाई। गुजरात के अधिकांश लोग कहते हैं कि उन उन्मादी दिनों में, अधिकांश लोग यह भूल गए कि वे किस पार्टी से संबंधित हैं और इसके बजाय हिंदू या मुस्लिम दंगाई बनकर व्यवहार किया।
उदाहरण के लिए, 2003 में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना मदनी, जो कि कांग्रेस समर्थक और भाजपा विरोधी मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते हैं, ने सार्वजनिक रूप से दंगों में कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप लगाया था और कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी लिए थे जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के राजेश

रामचंद्रन की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो 9 अगस्त, 2003 को टाइम्स न्यूज सर्विस पर प्रकाशित हुई थी:
कांग्रेस बेस्ट बेकरी और अन्य मामलों को लेकर जमकर हंगामा कर रही है।
नरेंद्र मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी हिंसा में संलिप्तता के संबंध में,
जिसने पिछले साल गुजरात को हिलाकर रख दिया था। लेकिन, जब इसकी संलिप्तता की बात आती है
हत्याओं में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता के बावजूद, 10 जनपथ ने सन्नाटा पसरा रखा है।
जेयूएच के अनुसार, "अधिकांश कांग्रेस पार्षदों" और कुछ कांग्रेस सदस्यों ने
गुजरात के नेताओं ने पिछले साल के दंगों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। महमूद असद
जेयूएच के महासचिव मदानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया: “हमने पत्र लिखे थे
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसमें शामिल कांग्रेस नेताओं की सूची दी।
दंगों के दौरान, उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अप्रैल में
उदाहरण के लिए, 29, 2002 को, जेयूएच को अपने संगठन से 25 कांग्रेस नेताओं की एक सूची प्राप्त हुई।
गुजरात चैप्टर की रिपोर्ट तुरंत उन्हें भेज दी गई। इसमें एक पूर्व सदस्य भी शामिल थे।
कांग्रेस मंत्री, एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व सांसद।
फिर 20 अगस्त को मदानी ने गांधीजी को याद दिलाया, “इसी प्रकार हमारी अपील भी है।”

कांग्रेस विधायकों, पार्षदों, 214 मोदी, मुसलमानों और मीडिया की संलिप्तता के संबंध में आपको अग्रेषित किया गया।

गुजरात नरसंहार में शामिल श्रमिकों और दोषियों के नामों की सूची।
इसे नजरअंदाज किया जाता रहा है।
जेयूएच का कहना है कि उसके पास जमीनी स्तर से सटीक जानकारी थी।
उदाहरण के लिए,
इसकी गुजरात शाखा ने वडोदरा शहर के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा था।
21 मार्च को, “गोधरा घटना के बाद कार्यकर्ताओं की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी।”
भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल की बैठक योगेश के नेतृत्व में हुई।
पटेल (विधायक) और चिम्मनगांधी (कांग्रेस पार्षद)। उन्होंने ही ये आवंटन किए थे।
कार्यकर्ताओं को उनके काम सौंपे गए, एक योजना बनाई गई और कार्यकर्ताओं को यह काम करने के निर्देश दिए गए।
बिना किसी डर के और उन्हें बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा।
गुजरात जेयूएच ने जिला स्तर पर भी कांग्रेस नेतृत्व का नक्शा तैयार कर लिया था।
मेहसाना और पाटन जिलों की सूची में कांग्रेस नेताओं के आठ नाम हैं।
स्थानीय सांसद आत्माराम पटेल को भी "नकारात्मक भूमिका" निभाने का दोषी ठहराया गया है। एक फैक्स
मेहसाना से 1 मई को भेजे गए संदेश में पटेल के कॉलम के विरुद्ध यह टिप्पणी है: “अभी भी

मुसलमानों की मदद करने नहीं आया है; एक अपराधी व्यक्ति का पक्ष ले रहा है
सरदारपुर और लाडोई गांव।"
आनंद से 15 लोगों की सूची का नेतृत्व गुजरात युवा संगठन के एक सचिव कर रहे हैं।
कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस और जेयूएच के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए, रिपोर्ट पूरी तरह से प्रशंसात्मक है।
पाटन के सांसद प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा निभाई गई 'सकारात्मक भूमिका' के लिए।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव एन.ए. फारूकी कहते हैं, “कांग्रेस ने दंगों के दौरान चूक और जानबूझकर दोनों तरह के पाप किए। पूर्व सांसद
एहसान जाफरी ने सोनिया गांधी से मदद मांगी थी। उन्होंने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया।
गुजरात की अपनी अगली यात्रा में। स्थानीय निकायों का नेतृत्व अधिकतर इनके द्वारा किया जाता था।
कांग्रेस राहत और पुनर्वास के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
सब कुछ गैर सरकारी संगठनों पर छोड़ दिया गया है।"
2002 में ही, मैंने कई लोगों को, जिनमें कुछ वामपंथी गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल थे, निजी बातचीत में यह कहते सुना था कि दंगों के बाद अहमदाबाद की अपनी पहली यात्रा पर सोनिया गांधी ने ज़किया जाफरी से मिलने से इसलिए परहेज किया क्योंकि उन्हें पता था कि ज़किया उन्हें गुलबर्ग सोसाइटी पर हुए हमले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भूमिका के बारे में खरी-खोटी सुना देंगी, जिसके कारण उनके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि कई स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा और विश्व हिंदू

[illegible] 28 [illegible]

[illegible]

[illegible]? 215

[illegible]? [illegible] 2002 [illegible]

27 [illegible], 2002 [illegible] 8 [illegible] 24 [illegible], 2002 [illegible] 7 [illegible] 27 [illegible]: [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जरा सा भी सबूत मिल जाता, तो अब तक उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके होते। हालांकि, आज तक न तो कांग्रेस पार्टी और न ही उसके सहयोगी गैर-सरकारी संगठन मोदी के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज करा पाए हैं।
गोधरा ट्रेन त्रासदी पर मोदी की प्रतिक्रिया: 27 फरवरी, 2002 को सुबह लगभग 8 बजे गोधरा रेलवे स्टेशन से निकलते ही साबरमती एक्सप्रेस पर हमला हुआ और कुछ ही मिनटों में 59 पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिंदा जल गए, जबकि कई अन्य भागने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री को इस नरसंहार की सूचना सुबह लगभग 9 बजे मिली। मोदी ने अपनी स्थिति और तत्काल प्रतिक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया:
24 फरवरी को मुझे अपने चुनाव परिणाम मिले। मैंने चुनाव में भाग लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था।
विधायक चुने जाने के बाद ही विधानसभा में काम करने का मौका मिला। इसीलिए मैंने विधानसभा की समस्या ठीक की।
26 फरवरी के सत्र के लिए। 27 तारीख को मुझे अपना पहला बजट प्रस्तुत करना था। मुझे मिल गया।
गोधरा घटना की खबर सुबह करीब 9 बजे मिली, लेकिन गोधरा के लिए रवाना नहीं हो सका।
क्योंकि विधानसभा की बैठक दोपहर में होनी थी, इसलिए इसे तुरंत रद्द करना पड़ा।
सदन में जाने से पहले, मैंने एक छोटी सी बैठक बुलाई और पूछताछ की।
हालाँकि, उस बैठक से पहले ही मैंने निर्देश दे दिए थे।
गोधरा के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि बाकी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
और ट्रेनों को जल्द से जल्द अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी चाहिए अन्यथा 218 मोदी, मुस्लिम और मीडिया जैसी स्थिति हो जाएगी

गोधरा में हजारों यात्री फंसे हुए हैं... इसलिए मेरी सलाह यह थी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन के शेष यात्रियों को उनके संबंधित स्थानों पर भेज दिया जाना चाहिए।
गंतव्य तक यथाशीघ्र पहुंचाना। हमारा प्रयास शीघ्रता सुनिश्चित करना था।
सामान्य स्थिति की वापसी।
जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, बचे हुए यात्रियों को लेकर ट्रेन दोपहर 12.40 बजे के आसपास गोधरा से रवाना हुई, यानी हमले के साढ़े चार घंटे के भीतर। यह आपातकाल के समय त्वरित कार्रवाई करने और आगे अराजकता से बचने के मोदी के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह ईश्वर की कृपा थी या जो भी हो, कि मैंने उचित सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश दिया।
अन्य स्टेशनों में आगे संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर उपाय किए जाएंगे।
मार्ग। यह तथ्य अभी तक कहीं भी सामने नहीं आया है। मैंने यह भी निर्देश दिया था कि जब
यदि जीवित बचे यात्री अहमदाबाद पहुँचते हैं, तो उन्हें सीधे एस्कॉर्ट किया जाना चाहिए।
उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए—रास्ते में कोई नारेबाजी न हो।
मेरे अधिकारियों की तत्काल प्रतिक्रिया थी, "नहीं महोदय, अब और कोई गड़बड़ी नहीं होगी।"
ऐसा होने की संभावना है।" फिर भी, मैंने जोर दिया कि वे अग्रिम भुगतान करें।

तैयारी कर लें और किसी भी बात को हल्के में न लें। फिर भी, जब वह ट्रेन पहुंची तो...
आनंद स्टेशन पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। तभी मेरे अधिकारियों ने मुझसे कहा, “सर,
आपका आकलन बिल्कुल सही था।
बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचने पर मोदी ने सदन को इस त्रासदी के बारे में सूचित किया और मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। उनके बयान का आगे का भाग इस प्रकार है:
विधानसभा में फोन सिग्नल नहीं मिलते। बजट का काम खत्म हो गया। दोपहर करीब 3 या 3:30 बजे तक, हमें पता चला कि स्थिति और भी खराब हो गई थी।
टीवी चैनल लाइव कवरेज दिखा रहे थे। मुझे बड़ौदा के लिए निकलना था। गोधरा। हमारा अपना हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। इसलिए हमने एक निजी कंपनी से मदद मांगी।
उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, "हमारे पास डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर नहीं है।"
और हमें एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर में वीआईपी को ले जाने की अनुमति नहीं है।” मैंने उनसे कहा,
मैंने उनसे कहा, “मैं वीआईपी नहीं हूँ,” और उन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मैंने उनसे कहा कि
मैं उन्हें लिखित में दे दूंगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर यात्रा कर रहा हूं।
सरकार ने गोधरा में सुबह 9:45 बजे कर्फ्यू लगा दिया और भीड़ हिंसा में लिप्त पाए जाने वालों के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। नानावती आयोग ने दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे पुलिस

ने गोधरा में हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने और तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी? 219

यहां कुछ समाचार रिपोर्टों के उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी। द हिंदू ने लिखा, “मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधरा में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए” (28 फरवरी, 2002)। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही खबर दी: “गुजरात सरकार ने गोधरा में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए, जब भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी, जिसमें 57 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। गोधरा स्टेशन पर उपद्रवियों ने ट्रेन के चार डिब्बों में आग लगा दी…”
यह रिपोर्ट 27 फरवरी को दोपहर 1.37 बजे ही प्रकाशित की गई थी, जिससे पता चलता है कि कर्फ्यू तुरंत लागू कर दिया गया था। द ट्रिब्यून (चंडीगढ़ से प्रकाशित) ने 28 फरवरी को रिपोर्ट किया: “घटना के तुरंत बाद गोधरा कस्बे में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए...” (ध्यान दें ‘तुरंत बाद’ शब्द पर)।
अगले दिन सभी अंग्रेजी दैनिकों ने, जिनमें कई विदेशी समाचार पत्र भी शामिल थे, इसी तरह की खबरें छापीं। अमेरिकी समाचार पत्र सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने 27 फरवरी को ऑनलाइन लिखा: “इस हमले से सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका से भारतीय अधिकारियों ने इस विशाल, धार्मिक रूप से विभाजित राष्ट्र में तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। प्रधानमंत्री ने हिंदुओं से जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया…”

मोदी शाम करीब 4:30 बजे गोधरा पहुंचे और आग लगाई गई रेल बोगियों का निरीक्षण करने गए। उन्होंने कहा:
जब मैं गोधरा पहुंचा, तो मुझे तुरंत यह अहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारे छायांतकार हैं।
(विध्वंसक) तत्व पहले से ही अति सक्रिय थे। हमें इसकी पूरी भयावहता का एहसास हुआ।
उस साजिश का पता बहुत बाद में चला। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर एक ईमेल भेजा गया।
एक पत्रकार के नाम से प्रसारित हो रही जानकारी में यह कहानी फैलाई गई थी कि कुछ
कारसेवकों में से एक ने एक मुस्लिम लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। मीडिया ने भी इस मामले को आसानी से दबा दिया।
उस ईमेल के कुछ ही मिनटों के भीतर उस कहानी को खूब उछाला गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है।
शरारती तत्वों ने कितनी सटीक योजना बनाई थी, क्योंकि इस तरह का काम करना
घटना के एक या दो घंटे के भीतर खबर फैलाना इतना आसान नहीं है।
मीडिया में से कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता।
विशेषज्ञों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि लड़की कौन थी या क्या किसी ने उसे देखा था।
एक घटना घटित हो रही है।
रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाने के बाद जब मैंने मीडिया से मुलाकात की तो...
मैंने अपने बयान में कहा था कि जिस अस्पताल में मृतकों और घायलों को ले जाया गया था, वहां मैंने यह बात कही थी।
दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा, ताकि लोग शांति बनाए रखें।

[illegible]

[illegible]

220 [illegible]

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]

27, 2002 [illegible]

[illegible]

 गुजरात भर में 70,000 पुलिसकर्मियों की पूरी टुकड़ी तैनात की गई
थी।
एक भी जवाबी दंगा होने से पहले ही। पूरी पुलिस
अहमदाबाद के संवेदनशील इलाकों में 6,000 जवानों की तैनाती की गई
थी।
पहले ही दिन। हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ (ब्रिटेन का) और
अन्य।
अखबारों ने 28 फरवरी को अपने संस्करणों में पुष्टि की कि इससे
अधिक
27 फरवरी को गुजरात में 70,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई
थी।
द टेलीग्राफ 1 और अन्य विदेशी समाचार पत्रों ने भी रिपोर्ट किया
था कि सुरक्षा
गुजरात में ही नहीं, बल्कि उन सभी जगहों पर सख्ती बरती गई थी जहां
काफी संख्या में लोग रहते थे।
भारत में मुस्लिम आबादी।
 उसी दिन, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की सभी कंपनियों ने
राज्य के जवानों को अहमदाबाद, गोधरा और अन्य संभावित क्षेत्रों
में तैनात किया गया था।
'संवेदनशील'। सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) की
इकाइयां भी शामिल थीं।
तैनात किया गया। उसी दिन, अहमदाबाद में आरएएफ को भी भेजा गया।
और अन्य संवेदनशील क्षेत्र।
 टाइम्स ऑफ इंडिया ने 27 फरवरी को ऑनलाइन रिपोर्ट किया कि गुजरात
सरकार ने केंद्र से सीआरपीएफ की दस कंपनियां भेजने का अनुरोध
किया था।
जिन्हें भेजा गया था।

 मोदी ने स्वयं शांति और सद्भाव के लिए एक से अधिक बार अपील जारी
की।
जिसका प्रसारण 27 फरवरी को ही दूरदर्शन पर किया गया था और जिसे
दोहराया गया था।
1. राहुल बेदी, "ज्वलित ट्रेन में हिंदुओं का नरसंहार," द
टेलीग्राफ, 28 फरवरी, 2002।
वेब.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/1386341/Hindus-massacred-on-blazing-train.html.
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी? 221

अगले दिनों में। अगला अध्याय विश्लेषण करता है कि मीडिया
जानबूझकर कैसे
उन्होंने उनके बयानों और भाषणों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया।
 27 फरवरी को ही 217 निवारक गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें से
इनमें से 137 हिंदू और 80 मुसलमान थे। नौ हिंदुओं को गिरफ्तार
किया गया।
हिंसा की घटनाएं। इस तथ्य के बावजूद कि कई भाजपा (और कई कांग्रेस)
यदि नेता सक्रिय रूप से अशांति फैला रहे थे, तो उनके खिलाफ
कार्रवाई का आदेश दिया गया।
सभी अपराधी।
 जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि
जब मृतकों को
गोधरा से शव अपने-अपने पैतृक स्थानों पर पहुँचते हैं,
सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए, पुलिस बंदोबस्त
किया गया।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

स्थिति की आपातकालीन समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की, जिसमें गृह और पुलिस विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। मोदी के शब्दों में:
222 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उसी रात मैंने उनसे सेना को सूचित करने को कहा। मुझे बताया गया कि सेना मौके पर मौजूद है।
पाकिस्तान द्वारा प्रेरित ऑपरेशन पराक्रम के बाद जोधपुर सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
भारतीय संसद पर हमला। देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
इसलिए, गुजरात स्थित सैन्य इकाइयों को सीमा से वापस नहीं बुलाया जा सका।
मैंने कहा, कृपया उन्हें समझाएं कि भले ही उनके पास उचित सैन्य इकाइयाँ न हों,
उन्हें अपने धोबी, रसोइये, नाई को सेना की वर्दी में भेजने दो और ले जाओ
उन्हें वाहनों में घुमाया जाता है। सेना की वर्दी पहने पुरुषों की उपस्थिति मात्र से ही एक
मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सेना से कम से कम इतना करने को कहें, जबकि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह ऐसा करे।
अन्य व्यवस्थाएँ। लोग सेना का सम्मान भी करते हैं और उससे डरते भी हैं।
सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देर रात बुलाई गई इस बैठक में मौजूद सभी लोगों ने एसआईटी को बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने पर जोर दिया। उसी बैठक में मोदी ने अपने अधिकारियों को

स्थानीय सेना मुख्यालय से सेना की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेने का निर्देश दिया।

शवों के भड़काऊ प्रदर्शन के संबंध में आरोप : 27 तारीख को चाकूबाजी की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थीं , लेकिन असली हिंसा 28 फरवरी की दोपहर के आसपास भड़की। आरोप लगाया गया है कि मोदी दंगों में शामिल थे क्योंकि : मोदी ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाए गए बंद को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए कुछ नहीं किया।

28 फरवरी को गोधरा नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य था

दंगों को भड़काया गया और राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मोदी सरकार ने गोधरा से शवों को लाने की अनुमति दी।

अहमदाबाद में प्रवेश किया और मुस्लिम विरोधी भावनाएँ भड़काने के लिए शहर में 'जुलूस ' निकाली।

हिंदुओं की भावनाओं में उबाल आया , जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। मोदी ने पुलिस को दंगाई भीड़ को नजरअंदाज करने और हिंदुओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने देने का आदेश दिया।

गोधरा हत्याकांड का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर उनका 'गुस्सा ', जो बदले में

इसका श्रेय भी मोदी को दिया जा रहा है।

इस मामले की गहन जांच के बाद एसआईटी ने इसे खारिज कर दिया है और सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

 शव परीक्षण गोधरा अस्पताल में ही किया गया। गोधरा में परिजनों द्वारा दावा किए गए सभी शवों को सौंप दिया गया।

उसी कस्बे में। केवल अज्ञात शव और वे लोग जिनके अहमदाबाद और उसके आसपास रहने वाले परिवारों को अहमदाबाद भेजा गया था।

भारी पुलिस सुरक्षा के बीच। शेष शवों को पुलिस सुरक्षा के तहत
भेजा गया।
सुबह करीब 3:30 बजे भारी पुलिस सुरक्षा के साथ।
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी ? 223

 उस असमय समय में लोगों को दंगा भड़काने के लिए लामबंद नहीं किया
जा सकता।
इसके अलावा , सिविल अस्पताल के विपरीत , जो शहर के मध्य में स्थित है
अहमदाबाद में स्थित सोला अस्पताल मुस्लिम बस्तियों से घिरा हुआ
है और यहीं पर स्थित है।
अहमदाबाद के बाहरी इलाके जहां शायद ही कोई मुसलमान रहता था
दिन।
 चूंकि कारसेवक वीएचपी नेताओं के आह्वान पर अयोध्या गए थे , इसलिए
उनमें से कुछ ने शवों को ले जा रहे पुलिस वाहनों का भी पीछा किया।
 अज्ञात पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार श्मशान घाट में किया
गया।
सोला अस्पताल के ठीक पीछे। मौके पर मौजूद वीएचपी नेता भी।
पीड़ितों के परिजनों को इस बात के लिए राजी करने को कहा गया कि वे
यह कार्य करने के लिए सहमत हों।
उन शवों का अंतिम संस्कार पास के श्मशान घाट में किया गया।
हालाँकि ,
इस प्रस्ताव से पहले से ही नाराज रिश्तेदारों में और भी आक्रोश
फैल गया।
उन्होंने उचित अंतिम संस्कार के लिए उन्हें उनके संबंधित घरों
में ले जाने पर जोर दिया। 2 इस प्रकार मोदी ने अहमदाबाद में कुछ
शवों को लाने के अपने निर्णय और कानून -व्यवस्था की स्थिति को

बिगड़ने से बचाने के लिए उठाए गए एहतियाती कदमों के बारे में बताया:
अहमदाबाद का मुख्य सिविल अस्पताल, जहाँ गोधरा पीड़ितों का इलाज किया जाता था
सामान्य तरीके से पहुँचने पर मैं शहर के बीचोंबीच पहुँच गया। मैंने जो भी अच्छा लगा उसका इस्तेमाल किया।
ईश्वर ने मुझे जो विवेक दिया है, उसी के अनुसार मैं उन्हें सोला अस्पताल लाने का आदेश देता हूँ, जो कि
उन दिनों वह अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक आभासी जंगल के बीचोंबीच स्थित था।
उस क्षेत्र का विकास पिछले दस वर्षों में ही हुआ है। जब से ट्रेन आ रही थी
अहमदाबाद के शवों को साबरमती लाना पड़ा।
वापस शहर। अगर हमने मारे गए सभी लोगों के परिजनों को जाकर वसूली करने के लिए कहा होता।
गोधरा से उनके शवों को लादकर हजारों लोग वहाँ पहुँच गए होंगे।
पहले से ही तनावपूर्ण शहर में स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती थी।
अगर ऐसा होता तो...
क्रोधित होकर गोधरा गए रिश्तेदारों ने गोधरा निवासियों पर हमला कर दिया था।
इससे और अधिक परेशानी खड़ी हो जाती।
इसलिए, सामान्य ज्ञान ने हमें बताया कि शवों को हटा देना चाहिए।
उन्हें जल्द से जल्द गोधरा ले जाया गया और उनके घरों तक पहुंचाया गया। हम उन सभी को सोला ले आए।
अस्पताल में लगभग 30 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
सोला अस्पताल के बगल में स्थित श्मशान घाट।
अगर कोई ईमानदारी से जांच करे तो उसे पता चलेगा कि

उस विस्फोटक स्थिति को संभालने में गुजरात ने प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग किया।
और शांति बहाल करने के लिए हमारे पास जो भी बल उपलब्ध था, उसका उपयोग किया गया। एक दिन
2 उदय माहुरकर और शिशिर गुप्ता, “मोदी के पाप,” इंडिया टुडे, 18 मार्च 2002,
वेब. http://www.indiatoday.com/itoday/20020318/cover.shtml.
224 मोदी, मुसलमान और मीडिया

गुजरात को उस विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में याद किया जा सकता है।
दुर्भाग्यवश, 2002 की गुजरात त्रासदी को आज तक भुलाया नहीं जा सका है।
कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से या न्याय और सामाजिक दृष्टिकोण से
सामंजस्य। इसके बजाय, इसका इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए किया जा रहा है और वह भी
सिर्फ एक आदमी को फंसाने का इरादा।
इन सावधानियों के बावजूद, अहमदाबाद ही नहीं बल्कि गुजरात के कई शहरों, कस्बों और जिलों में भयंकर दंगे भड़क उठे, क्योंकि गोधरा नरसंहार का सीधा प्रसारण उस पूरे दिन राष्ट्रीय और स्थानीय टीवी चैनलों पर किया गया था। इसने अभूतपूर्व पैमाने पर जन हिंसा को जन्म दिया। हर लिहाज से, यह एक जन आंदोलन था, जिसका भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कांग्रेस के बेईमान राजनेताओं ने बखूबी फायदा उठाया।
कुछ जानबूझकर अनदेखी किए गए तथ्य

इंडिया टुडे के संवाददाता उदय माहुरकर, जिन्होंने उन भयावह दिनों के दौरान कुछ सबसे मार्मिक और गहन रिपोर्टें लिखीं, ने मुझे एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में बताया:
दंगे 28 फरवरी की सुबह शुरू नहीं हुए थे। हिंदुओं ने इसकी शुरुआत की थी।
नरोदा पाटिया इलाके में मुस्लिम घरों पर पत्थरबाजी की घटना हुई। मुसलमानों ने भी
उन्होंने पत्थरों से जवाबी हमला किया।
सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच, रंजीत वंजारा नाम का एक ऑटो चालक था।
नरोदा पाटिया में एक मस्जिद के पास खड़ी गाड़ी में। मुसलमानों के एक समूह ने उसे घसीटकर अंदर ले गए।
मस्जिद के पास वाली गली में। यह देखकर हिंदू मदद के लिए चिल्लाने लगे।
पुलिस 20 मिनट के भीतर आ गई। जब वे गली में गए, तो उन्हें यह मिला... मस्जिद के बाहर वंजारा का शव पड़ा था। उसकी आंखें निकाल दी गई थीं।
इससे हिंदू भड़क उठे और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया। इस मामले में भी
मामला अदालत में दर्ज है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
इस मामले पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक हिंदू हत्या का मामला है।
दूसरी घटना सुबह करीब 11 बजे घटी। एक मुस्लिम आइशर कार मालिक के साथ यह घटना हुई।
ट्रक को हिंदू भीड़ ने घेर लिया था। घबराहट में उसने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी।

एक व्यक्ति कुचलकर मर गया। इससे भी भीड़ भड़क उठी और वे हिंसक हो गए।
हिंसक उत्पात मचाते हुए।
नरोदा गांव में हुई तीसरी घटना में, मुसलमानों के एक समूह ने एक हिंदू की हत्या कर दी।
साइकिल चालक। इस प्रकार, फरवरी में भीड़ हिंसा में मारे गए पहले तीन व्यक्ति।
उनमें से 28 हिंदू थे। इसलिए, यह सिद्धांत कि 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगे
भाजपा की सुनियोजित साजिश का हिस्सा होने की बात पूरी तरह बकवास है। और ये बातें इतनी एकतरफा भी नहीं थीं।
जैसे-जैसे उन्हें प्रक्षेपित किया जाने लगा।
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी? 225

इन तीनों घटनाओं की रिपोर्ट इंडिया टुडे3 में छपी है। मैंने गुजरात सरकार के गृह विभाग से भी इनकी पुष्टि की है। हालांकि, यह कहना कि पहली तीन मौतें हिंदुओं की थीं, किसी भी तरह से जवाबी हिंसा को जायज़ नहीं ठहराता—चाहे वह गोधरा हत्याकांड के जवाब में हो या इन तीनों हत्याओं के जवाब में। कोई भी सभ्य समाज भीड़ हिंसा को अन्याय का निवारण करने का साधन नहीं मान सकता। न ही इसका मतलब इस तथ्य को कम आंकना है कि गुजरात में कई जगहों पर क्रोधित हिंदू भीड़ जमा हुई थी, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से ऐसी घबराहट भरी प्रतिक्रिया हुई होगी जिसके परिणामस्वरूप भीड़ द्वारा उत्तेजित मुस्लिम ट्रक चालक ने हिंदुओं को कुचल दिया। इन तीनों हत्याओं का उल्लेख करने का उद्देश्य केवल इस तथ्य को उजागर करना है कि हमारे खुले तौर पर पक्षपाती मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिंसा के इन और अन्य हिंदू पीड़ितों के प्रति कोई परवाह या

[illegible]
[illegible]
[illegible]

3 Uday Mahurkar, “Naroda Patiya case: Mayaben Kodnani’s Fate Hangs in Balance,” India
आज, 25 मई, 2013, वेब . http://indiatoday.intoday.in/story/naroda-patiya-case-mayaben-kodnani-judgement-narendra-modi-gujarat-riots/1/273065.html.

226 मोदी , मुसलमान और मीडिया

पराक्रम चल रहा था जिसमें आमने -सामने की बहस शामिल थी।
भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद , एक उच्च स्तरीय बैठक की
आवश्यकता थी।
केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय।
 लगभग उसी समय, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने भेजा
केंद्रीय रक्षा सचिव से सेना को मजबूत बनाने के लिए एक आधिकारिक
अनुरोध।
गुजरात में आंतरिक सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक
हुई।
अध्यक्षता। इसने सैनिकों की तत्काल तैनाती को मंजूरी दी।
अहमदाबाद और गुजरात के अन्य हिस्सों में। वाजपेयी ने तत्कालीन
रक्षा मंत्रालय को तैनात किया था।
मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस सैनिकों की तैनाती की निगरानी करेंगे।
शाम 4 बजे , मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस निर्णय की घोषणा
की।
राज्य सरकार सेना को बुलाएगी। 28 फरवरी को ही फर्नांडीस
अहमदाबाद पहुंचे और देर रात नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके
बाद

सुबह , फर्नांडीस सड़कों पर निकले और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण
किया।
सशस्त्र बलों की तैनाती। उन्होंने कई दंगा प्रभावित क्षेत्रों का
दौरा किया।
उन्होंने बहुत बड़ा व्यक्तिगत जोखिम उठाया और स्थिति का
व्यक्तिगत रूप से जायजा लिया। सेना के जवानों को 40 विमानों में
अहमदाबाद ले जाया गया।
देश की सीमा के अग्रिम मोर्चों पर वे पहुंचने लगे और वे आने लगे।
28 फरवरी की मध्यरात्रि को पहला विमान अहमदाबाद में उतरा।
28 फरवरी की मध्यरात्रि तक और आखिरी विमान रात 11 बजे तक।
1 मार्च , 2002।
 सेना की तैनाती 1 मार्च , 2002 को सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी।
मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के साथ एक उच्च स्तरीय
बैठक
मंत्री के साथ सेना और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रशासन भी आयोजित किया गया। अहमदाबाद में कुल नौ कॉलम
सेना की टुकड़ियों को 1 मार्च को ही अधिकांश संवेदनशील क्षेत्रों
में तैनात कर दिया गया था। सेना के लिए आवश्यक सहायक बुनियादी
ढांचा और कर्मी उपलब्ध कराए गए थे।
राज्य सरकार द्वारा युद्धस्तर पर प्रभावी ढंग से कार्य करने के
लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गईं।
इसमें उनके आवागमन के लिए 131 वाहन शामिल थे। इसके अतिरिक्त , सात
सुबह 7:30 बजे तक सेना को कार्यकारी मजिस्ट्रेट उपलब्ध करा दिए
गए।
तीन और नियुक्त किए गए। कुल 32 कार्यकारी मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराए
गए।

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

फरवरी में केवल 28 दिन थे। इस प्रकार 1 मार्च की कार्रवाई का मतलब दंगों के भड़कने के ठीक अगले दिन की कार्रवाई है, न कि दो-तीन दिन के अंतराल के बाद, जैसा कि 30 या 31 दिनों वाले महीनों में होता है।
कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों ने सहायता देने से इनकार कर दिया हिंसा के प्रसार को देखते हुए, 1 मार्च, 2002 को ही गुजरात सरकार ने पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से कुछ अतिरिक्त बल प्रदान करने का अनुरोध किया।
228 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उस समय तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे— मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत और महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख। फैक्स का पूरा पाठ बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जो तात्कालिकता को दर्शाता है। फैक्स द्वारा भेजा गया अनुरोध इस प्रकार है:
महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, विमान में 58 यात्रियों के जलकर मर जाने की भयावह घटना हुई थी।
27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला था।
गुजरात में स्थिति। आगजनी, लूटपाट, हत्या और हिंसा की व्यापक घटनाएं।
कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों से हिंसा की अन्य घटनाएं सामने आई हैं।
राज्य सरकार अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की पूरी कोशिश कर रही है।
संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ-साथ भारत सरकार से अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनशक्ति। हालाँकि, भारत सरकार
अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए, अधिक अर्धसैनिक बलों को उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।
अन्य जगहों पर भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। चूंकि यह स्थिति गांवों तक फैल रही है और प्रमुख राजमार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। अवरुद्ध होने के कारण, हमारे संसाधन अधिकतम सीमा तक सीमित हो गए हैं। हमें लगता है कि
आपके जैसे पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त बलों की सेवाएं मददगार साबित होंगी।
राज्य सरकार इस नाजुक कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में सक्षम है।
अतः हम आपसे निरोधक करने के हमारे अनुरोध पर सहर्ष विचार करने का अनुरोध करते हैं।
सरकार को इस स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए आपकी सशस्त्र पुलिस की दस कंपनियों को भेजा जाना चाहिए।
कानून व्यवस्था की स्थिति। हस्ताक्षर: के. नित्यानंदम, सरकार के सचिव
गुजरात, गृह विभाग।
महाराष्ट्र सरकार ने कुछ सैन्य सहायता प्रदान की, जबकि दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश) और अशोक गहलोत (राजस्थान) दोनों ने गुजरात की सहायता करने से इनकार कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध को ठुकराने में 13 दिन का समय लिया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13 मार्च, 2002 को दिए गए और 'गुप्त' चिह्नित उत्तर का सटीक पाठ नीचे दिया गया है:
कृपया दिनांक 1 मार्च, 2002 के पत्र संख्या एसबी.वी/एमएमएम/102002/769 का संदर्भ लें।

उपरोक्त विषय के संबंध में। खेद है कि अत्यधिक व्यस्तताओं के कारण...

राज्य के भीतर एमपीएसएएफ की तैनाती को देखते हुए, इस समय बल को अलग रखना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार के सचिव आर.सी. अरोरा द्वारा हस्ताक्षरित।

क्या ये पत्र गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर से दंगों को शांत करने की तत्परता को दर्शाते हैं, या क्या वे नरेंद्र मोदी को आधुनिक युग के "नीरो" के रूप में चित्रित करते हैं, जिन्होंने गुजरात के जलने के दौरान कोई ध्यान नहीं दिया?

गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी? 229

यह बात समझ से परे है कि मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया को "गुप्त" क्यों कहा गया, जबकि गुजरात सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। आज दिग्विजय सिंह 2002 के दंगों में मोदी की कथित "मिलीभगत" के लिए उनके सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। हालांकि, जब मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में दिग्विजय सिंह को याद दिलाया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अतिरिक्त बलों की मांग को ठुकरा दिया था, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था।

2 मार्च, 2002: शांति समितियाँ सक्रिय हुईं। अन्य दिनों की तरह, सुबह मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कानून और व्यवस्था समीक्षा बैठक में, पिछले दिन की घटनाओं और की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई और निम्नलिखित घटनाक्रमों की रिपोर्ट दी गई: □ निवारक गिरफ्तारियाँ: 573 (477 हिंदू, 96 मुस्लिम) □ अपराधों के लिए गिरफ्तारियाँ: 711 (482 हिंदू, 229 मुस्लिम) □ पुलिस फायरिंग में मृत्यु: 16 (12 हिंदू, 4 मुस्लिम) □ एसआरपीएफ (राज्य आरक्षित पुलिस बल) की 64 कंपनियाँ और 24 कंपनियाँ

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) की तैनाती की गई। दूसरा दौर
शुरू किया गया।
जिला अधिकारियों को आधिकारिक संदेश भेजा गया था ताकि वे सक्रिय
हो सकें और
जिला और नगर एकता समितियों की बैठकों के आयोजन की व्यवस्था करना।
शांति समितियों और मोहल्ला समितियों का गठन करना और सामाजिक
भागीदारी सुनिश्चित करना।
सभी समुदायों के नेताओं, प्रमुख सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों
ने
प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की
समीक्षा बैठक की।
अधिकारियों ने रात 8.30 बजे।
3 मार्च 2002: और अधिक गिरफ्तारियां और पुलिस फायरिंग।
मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया और सर्किट
हाउस और हवाई अड्डे जाते समय शहर का भ्रमण किया। उन्होंने
केंद्रीय गृह मंत्री एल.के. आडवाणी के साथ गोधरा की यात्रा भी की।
निम्नलिखित आंकड़े स्वयं ही सब कुछ बयां करते हैं:
 निवारक गिरफ्तारियां: 363 (280 हिंदू, 83 मुस्लिम) अपराध के
लिए गिरफ्तारियां: 589 (416 हिंदू, 173 मुस्लिम) पुलिस फायरिंग
में मारे गए: 10 (सभी हिंदू)
पुलिस की विफलता और मिलीभगत
7 मार्च 2002 को ही स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देने लगा,
तब पंचमहल जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सेना को 10 मार्च को
बैरकों में वापस भेजने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, 230 मोदी,
मुसलमानों और मीडिया के कारण

अयोध्या विवाद और उससे जुड़े त्योहारों को लेकर जारी अशांति के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया था। बाद में, वडोदरा और सूरत में कुछ घटनाओं की सूचना मिलने पर सेना को फिर से तैनात किया गया। 15 मार्च को स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद सेना को फ्लैग मार्च के लिए इस्तेमाल किया गया।
सेना की तैनाती के दो दिनों के भीतर ही स्थिति नियंत्रण में आ गई। अगले तीन हफ्तों में कुछ उकसाने वाले तत्वों द्वारा छिटपुट घटनाएं हुईं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक चलने नहीं दिया गया और फैलने से तुरंत रोक दिया गया।
उदय माहुरकर ने पाक्षिक पत्रिका इंडिया टुडे के 18 मार्च, 2002 के अंक में हिंसा की प्रकृति और पुलिस की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था।
यह स्पष्ट है कि [28 फरवरी को] पुलिस अप्रभावी थी। लेकिन क्या यह क्या यह जानबूझकर किया गया था? अहमदाबाद में 6,000 पुलिसकर्मियों का बल है, जिनमें 1,500 सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल हैं।
कर्मियों की संख्या। इसके अलावा, पूरे राज्य में केवल चार कंपनियां (530 जवान) हैं।
रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की, जिसमें से केवल एक कंपनी को ही भेजा जा सका।
अहमदाबाद के लिए। यह देखते हुए कि भीड़ एक साथ सामने आई थी
लगभग आधा दर्जन स्थानों पर, जिनकी संख्या 2,000 से 10,000 के बीच थी, बलों ने साबित कर दिया।
बेहद अपर्याप्त। एक समय, 28 फरवरी को कम से कम 25,000 लोग थे।
लोग सिर्फ अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बना रहे हैं।
इसके अलावा, पुलिस को अहमदाबाद के चारदीवारी वाले शहर में गड़बड़ी की आशंका थी।

जो पिछले दो वर्षों में हर दंगे में सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र रहा है।
दशकों तक। लेकिन इस बार मुसीबतों की शुरुआत किलेबंद शहर से नहीं हुई।
सबसे भीषण नरसंहार स्थल नरोदा पाटिया में पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी।
सुबह भीड़ को इकट्ठा होने और जाने से रोकने के लिए यह नाम के लायक है।
हिंसक उत्पात मचा रहे थे। कम से कम 4,000 से 5,000 लोगों के तीन समूह थे, जिनमें से प्रत्येक हमला कर रहा था।
मुसलमान। इनमें चारा नामक जनजाति के सदस्य भी शामिल थे, जिनके पास एक
नारोदा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बस्ती। अब तक, चरा जनजाति चोरी के लिए जानी जाती थी।
और अवैध शराब का व्यापार। पिछले गुरुवार [यानी 28 फरवरी] को उन्होंने एक प्रतिष्ठा अर्जित की।
दंगों के लिए भी।
चमनपुरा इलाके में, जहां पूर्व कांग्रेस सदस्यों समेत लगभग 40 लोग शामिल हैं,
सांसद एहसान जाफरी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई, मरने वालों की संख्या मात्र कुछ ही थी।
भीड़ जमा होने पर सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए। बाद में अतिरिक्त बल भी पहुंचे।
लेकिन तब तक भीड़ बढ़कर 10,000 हो चुकी थी और पुलिस की गोलीबारी के बावजूद भी भीड़ ने विरोध जारी रखा।
कम से कम पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई—कुल मिलाकर पुलिस फायरिंग में 40 लोगों की मौत हुई।

अकेले अहमदाबाद में हिंसा नहीं रुकी। स्थिति और बिगड़ गई।
इसके अलावा, जाफरी ने भीड़ पर अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई, जिसमें सात लोग घायल हो गए। अन्य लोग भी घायल हुए।
बताया जा रहा है कि उस आवासीय परिसर से एसिड वाले बल्ब भी फेंके गए थे।
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी आवश्यकता थी? 231

पिछले गुरुवार [28 फरवरी] को अहमदाबाद पुलिस को कम से कम 3,500 शिकायतें प्राप्त हुईं।
डर से त्रस्त निवासियों, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, ने मदद की गुहार लगाई।
सामान्य औसत 200 है। दमकल विभाग के पास इससे निपटने की क्षमता है। अहमदाबाद पुलिस के अनुसार, 28 फरवरी को आग लगने की 100 कॉल आईं और कुल 400 कॉल प्राप्त हुईं।
आयुक्त पी.सी. पांडे: “अपने 32 साल के करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।”
कुछ ऐसा ही। यह एक अभूतपूर्व, अजेय और अभूतपूर्व उभार था।
एक ऐसी स्थिति आ गई जब पुलिस के लिए भीड़ से निपटना शारीरिक रूप से असंभव हो गया।
हजारों की संख्या में: गुजरात के अन्य हिस्सों में, समस्या व्यापक रूप से थी
इसी तरह। राज्य पुलिस बल में लगभग 43,000 जवान हैं, हालांकि उनमें से केवल 12,000 ही कार्यरत हैं।
वे सशस्त्र हैं। एसआरपी की संख्या 14,000 है। मुसलमानों को निशाना बनाने वाली भीड़।
ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 500 से लेकर 10,000 तक थी।

तीस्ता के दाहिने हाथ के आदमी ने खुलकर अपनी बात रखी: तीस्ता सेतलवाद के अब अलग हो चुके पूर्व सहयोगी रईस खान, जिन्होंने उनके संगठन के लिए घटनास्थल से पूरे दंगे की रिपोर्टिंग की थी, ने मेरे साथ एक वीडियो-रिकॉर्डेड साक्षात्कार में इसी तरह की टिप्पणियां कीं:
उस समय मैंने दंगों को अपनी आँखों से देखा था। मैं उस जीप में अकेले जाया करता था।
मैंने कई जगहों पर देखा कि कैसे भीड़ उन जगहों पर इकट्ठा हो गई थी जहाँ कुछ भी नहीं था।
कोई पुलिस नहीं थी। कई जगहों पर पुलिस बल इतना छोटा था कि बड़ी समस्या से निपटना संभव नहीं था।
कई अलग-अलग स्थानों पर जमा हुई भीड़। यहां तक कि अपनी एफआईआर में भी,
पीड़ितों ने 10,000 से 15,000 लोगों की भीड़ का जिक्र किया है। क्या आपको कुल संख्या पता है?
गुजरात में पुलिस बल की संख्या कितनी है? पुलिस कितने स्थानों पर बचाव कार्य कर सकती थी?
क्या लोग एक साथ? वे सेना की भूमिका के बारे में बात क्यों नहीं करते?
अर्धसैनिक बलों की बात करें तो? वे कभी इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि कितने लोगों की जान गई?
समय पर की गई कार्रवाई से क्या जान बच गई? केवल मारे गए लोगों की ही बात क्यों?
अगर पुलिस ने सेना की ठीक से मदद नहीं की होती, तो और भी बहुत से लोग मारे जाते।
कई हिस्सों में एक साथ दंगे फैलने के कारण लोगों की मौत हुई है।
गुजरात में। अगर इतने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दंगे हो रहे हैं।

एक दूसरे से बहुत दूर स्थित स्थानों में आप सेना को कैसे बना सकते हैं और
क्या पुलिस इन सभी स्थानों पर तुरंत पहुंचती है? पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी है?
एक सामान्य थाने में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सीमित होती है। पुलिस किसी स्थान पर तभी पहुंच सकती है जब...
जैसे ही उन्हें सूचना मिली, भीड़ से जुड़ी एक घटना घटित हुई है। फलां-फलां स्थानों पर एकत्र होना। यदि प्रत्येक स्थान पर भीड़ हो स्थानीय थाने में केवल 10-20 पुलिसकर्मी होते हैं, तो 10,000 से 15,000 रुपये तक कितना खर्च आएगा?
पुलिस क्या कर सकती है, खासकर तब जब इन 20 में से शायद केवल पांच के पास ही राइफलें हों?
और उनमें से एक के पास पिस्तौल है। वे भी इंसान हैं और अपनी जान को लेकर डर सकते हैं।
क्रोधित भीड़ का सामना करते समय सुरक्षा! अधिकांश पुलिसकर्मी केवल डंडा रखते हैं। 232 मोदी, मुसलमान और मीडिया

(कर्मचारी)। ऐसा पुलिसकर्मी 10,000 लोगों की क्रोधित भीड़ का सामना कैसे करेगा?
क्या वे पत्थर फेंक रहे हैं?
दिल्ली में, इंडिया गेट पर, बलात्कार विरोधी आंदोलन के समय, पुलिस भारी संख्या में उपस्थित लोग थे जबकि प्रदर्शनकारियों की संख्या केवल कुछ ही थी।
हज़ार। पुलिस ने गोलाबारी को छोड़कर सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया। फिर भी, यह
भीड़ ने पुलिस के लिए अफरा-तफरी मचा दी और यहां तक कि कड़ी सुरक्षा वाले परिसर में भी घुस गई।

राष्ट्रपति भवन में। इसके विपरीत, गुजरात में भीड़ उग्र थी और सड़कों पर उतर आई थी।
हत्याओं का सिलसिला। कुछ पुलिसकर्मी भला कैसे इन सबको काबू में कर सकते थे?
क्या एक ही समय पर? दोनों पक्ष मोबाइल फोन के जरिए घातक अफवाहें फैला रहे थे।
ये अफवाहें काफी हद तक भीड़ हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार थीं।
हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कई
कुछ स्थानों पर मुसलमान कमजोर पक्ष साबित हुए जबकि कुछ अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ।
अन्य स्थानों पर, हिंदू कमजोर समूह के रूप में उभरे। आप इसकी जांच कर सकते हैं।
आप स्वयं दस्तावेजों को देखकर यह जान सकते हैं कि कई स्थानों पर हिंदुओं को भी नुकसान उठाना पड़ा।
मुख्य अंतर यह है कि हिंदू बहुल क्षेत्र आकार में काफी बड़े हैं जबकि कई अन्य क्षेत्र
मुस्लिम बस्तियाँ छोटी और बिखरी हुई होती हैं। एक मुस्लिम क्षेत्र में हो सकता है
हिंदू बहुल बस्तियों से घिरी कुछ गलियों में 500 घर।
यदि वे आने वालों पर पत्थर फेंककर अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं
उन पर हमला करने के लिए, उनकी संख्या कम होने की संभावना है। इसमें कुछ समय लगेगा।
पुलिस को ऐसे इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि हर गली और सड़क तक पहुंचना संभव नहीं है।

कई अधिकारियों ने लंबे साक्षात्कारों में मुझे बताया है कि मोदी इस स्थिति से पूरी तरह से अचंभित रह गए थे क्योंकि उन्होंने इस तरह की गंभीर स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी।
गोधरा दंगों के बाद किसे इसकी ज़रूरत थी? 233

न तो उनका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था और न ही वे हिंसक उग्रता से जूझ रहे थे। उन्हें पद संभाले चार महीने से भी कम समय हुआ था। इन कुछ हफ्तों में, तमाम मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने सरकार को नागरिकों की सेवा का एक वास्तविक साधन बनाने के लिए व्यापक प्रशासनिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया था। वे कानून-व्यवस्था तंत्र की पेचीदगियों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। फिर भी, उन्होंने जल्दी ही स्थिति को संभाला और दंगों के पहले ही दिन सेना को बुला लिया। परिणामस्वरूप, यह गुजरात के उन कुछ बड़े दंगों में से एक था, जिन्हें तीन दिनों के भीतर दबा दिया गया। इससे पहले के दंगों में हिंसा जारी रहती थी और कर्फ्यू हफ्तों या महीनों तक लागू रहता था।
गुजरात में दंगे हुए थे, नरसंहार नहीं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि यह नरसंहार होता तो 2002 के दंगों में केवल मुसलमान ही मारे जाते। गोधरा में मारे गए 59 हिंदुओं के अलावा, निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि हिंदू दंगाइयों को बरी नहीं किया गया था: दंगों में कुल 262 हिंदू और 863 मुसलमान मारे गए, जिनमें शामिल हैं:
पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोग।
हिंसा के पहले तीन दिनों में पुलिस की गोलीबारी में 61 हिंदू और 40 लोग मारे गए।
मुसलमान अपनी जान गंवा रहे हैं।

 पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों की कुल संख्या : 10,500 आंसू गैस के गोलों की संख्या : 15,000 दंगा संबंधी आरोपियों की कुल पहचान : 25,486 (17,489 हिंदू)
और 7,997 मुसलमान)
गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या : 26,997, जिनमें से 19,198 थे हिंदू।
 गुजरात पुलिस ने कुल 4,274 मामले दर्ज किए थे। 31 तारीख तक जनवरी 2012 में , 246 हिंदू और 92 मुस्लिम आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। यह वास्तव में एकतरफा हिंसा नहीं थी , जैसा कि कांग्रेस और
इसके सहयोगी। 5 मार्च , 2002 को ही , 98 राहत शिविरों में से 85 शिविर इसके लिए थे।
13 सीटें मुसलमानों के लिए और 13 सीटें हिंदुओं के लिए थीं। एक समय में , 40,000 हिंदू थे।
शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। इसके अलावा , पहली गंभीर उकसाहट गोधरा नरसंहार के रूप में मुसलमानों से ही ये बातें सामने आईं।
हमें यह पूछने की ज़रूरत है : अल्पसंख्यक अधिकारों के स्वघोषित संरक्षक इन तथ्यों को सामने क्यों नहीं आने देना चाहते ? गोधरा और गोधरा के बाद हुए दंगों की विकृत तस्वीर क्यों फैलाई गई है ? इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जब 25 सितंबर 2008 को गुजरात विधानसभा में नानावती आयोग की रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया गया , तो तीस्ता सेतलवाद के एनजीओ ने साहस दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रिपोर्ट के प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। याचिका में उन्होंने यह निराधार तर्क दिया कि राज्य सरकार इसका इस्तेमाल गोधरा कांड के बाद के दंगों के आरोपी

234 मोदी , मुसलमान और मीडिया

हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए करेगी। तीस्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी ने मुसलमानों को झूठा फंसाने के लिए नानावती आयोग में नरम न्यायाधीशों की नियुक्ति की, और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि न्यायमूर्ति नानावती का नाम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
सौभाग्यवश, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नानावती आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन, इससे मोदी विरोधी गैर सरकारी संगठनों को गोधरा और गोधरा के बाद की हिंसा के बारे में वही पुराने झूठ फैलाने से नहीं रोका जा सका है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और उनसे संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों ने मुसलमानों के बीच स्थायी पीड़ित होने की भावना और घेराबंदी की मानसिकता पैदा करने में निहित स्वार्थ प्राप्त कर लिया है ताकि उन्हें एक बंधक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

अध्याय 13

आतंकवादियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
मोदी ने कांग्रेस को हताशा की ओर क्यों धकेल दिया?

गुजरात पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के ज़रिए सीमा पार से अन्य राज्यों में तस्करी करके लाए जा रहे नशीले पदार्थों को पकड़ा है। गुजरात ने नकली नोटों और फर्जी स्टांप कागज़ छापने के रैकेट के ज़रिए हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके एक राष्ट्रव्यापी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने माफिया डॉन छोटा शकील के गिरोहों पर कार्रवाई करके उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। इतना ही नहीं, हमने प्रतिबंधित राष्ट्रविरोधी संगठन SIMI की नापाक योजनाओं और गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया है। हमने सूरत में गुप्त रूप से इकट्ठा हुए SIMI के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पूरे भारत से गिरफ्तार किया है।
मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के कारण, दुबई का गिरोह, विभिन्न आतंकवादी संगठन और गुजरात में उन्हें संरक्षण और पनाह देने वाले तत्व आक्रोशित हैं और गुजरात से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है और हमें उनकी चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदर्शित करनी होगी।
मार्च 2002 में गुजरात विधानसभा में नरेंद्र मोदी

‘मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के पहले 19 सप्ताह’ और ‘राजकोट में मोदी का पहला चुनाव’ नामक पिछले अध्यायों में, मैंने विस्तार से बताया है कि मोदी ने कैसे:

• उन्होंने पहले दिन से ही एक स्पष्ट विकास एजेंडा निर्धारित किया; • उन्होंने किसी भी वर्ग को भेदकर अपील नहीं की; उन्होंने हर दिन पांच करोड़ गुजरातियों की बात की।
मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल एक बार; यहां तक कि अपने चुनावी भाषणों में भी,
संदेश हमेशा समावेशी था;
• उन्होंने अपने पहले चुनाव में भारी मुस्लिम वोटों के साथ जीत हासिल की।
मुस्लिम नेता कांग्रेस पार्टी की खुलेआम अवहेलना करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
मोदी, क्योंकि उन्होंने ठोस प्रयासों के माध्यम से अपनी सद्भावना प्रदर्शित की थी। 236 मोदी, मुसलमान और मीडिया

पहचान के अस्वस्थ पहलुओं को बढ़ावा देने से बचते हुए कार्य करना राजनीति;
• उन्होंने जिस समावेशी और जनहितैषी विकास मॉडल का वादा किया था, वह
कच्छ भूकंप के पुनर्निर्माण में परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं और पुनर्वास;
• गोधरा नरसंहार को उन्होंने शांत धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ संभाला।
इस झूठे प्रचार के विपरीत कि उन्होंने त्रासदी का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए किया; • हिंसा को सख्ती से दबाने के लिए सेना को बुलाया और कार्रवाई की।
भाजपा और उसके कुछ वर्गों के विरोध के बावजूद, 72 घंटों के भीतर दंगे नियंत्रण में आ गए।
कांग्रेस अशांत जल में तेल डालने का काम कर रही है;

पिछले पांच-छह महीनों में मेरी सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों और दुष्टतापूर्ण गतिविधियों में शामिल राष्ट्रविरोधी तत्वों पर नकेल कसें।
राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के संबंध में हमने सख्त कदम भी उठाए हैं।
उन आपराधिक माफियाओं के खिलाफ जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं।
वे अन्य राज्यों में स्थित अपने ठिकानों से भी गुजरात में आतंक फैला रहे हैं।
हमने जो कदम उठाए हैं, उनसे ठोस परिणाम मिले हैं। मैं प्रदान करना चाहता हूँ।
इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पाटन से ही मिले हैं, जैसे कि AK-47 राइफलें, मैगज़ीनें, आदि।
आतंकवादियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 237

पिस्तौलें, लगभग 100 गोलियां, आरडीएक्स, रेडियो सेट, रिमोट कंट्रोल
मेरे पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर ही प्रणालियाँ आदि जब्त कर ली गईं।
राष्ट्रविरोधी तत्वों को यह समझ आ गया कि सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। 17 दिसंबर 2001 को पिस्तौल, रॉकेट लॉन्चर आदि बरामद किए गए।
आरडीएक्स, हथगोले, राइफलें और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई।
वही जगह। उन्हें फिर से यह संदेश मिला कि सत्ता की बागडोर अब उनके हाथों में है।

उन लोगों के हाथों में जो अब उन्हें बख्शेंगे नहीं।
इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा के एम. शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया।
भाजपा सरकार। उनकी गिरफ्तारी के बाद, एके-56 राइफलें, मैगज़ीन के लिए गोला-बारूद बरामद किया गया।
कारतूस और बीस किलोग्राम से अधिक आरडीएक्स जब्त किया गया।
जब्त किए गए इन विस्फोटकों में पांच गांधीनगरों को उड़ाने की क्षमता थी।
जब्त किए गए डेटोनेटर और नवीनतम तकनीक से लैस आयातित रिमोट कंट्रोल
(विस्फोट करने के लिए)।
नवसारी जिले से डाभेल मदरसा के मौलवी को गिरफ्तार किया गया।
घातक तोपें और विस्फोटक, संवेदनशील नक्शे और आपत्तिजनक साहित्य। हम इस घटना को एक सामान्य मामला मानकर नहीं गुजर सकते। इसी तरह, अशरफ
जैश-ए-मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया और आसिफ रजा खान मारा गया। वे सभी
राष्ट्रविरोधी तत्व और अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोहों का हिस्सा इसमें शामिल हैं।
हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से आपराधिक साजिशें।
और जैश-ए-मोहम्मद। उन्हें हथियार और गोला-बारूद मिल रहे थे, जिनमें शामिल हैं:
आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए बम, आरडीएक्स और अन्य सामूहिक हत्या के हथियार।
और उन आतंकवादी संगठनों की मदद से अन्य विध्वंसक गतिविधियाँ।
इन घटनाओं के बाद, दुबई के अंडरवर्ल्ड ने चर्चा और पड़ताल शुरू कर दी।

गुजरात पुलिस को दूर रखते हुए सक्रिय रहने के तरीके। इसीलिए उन्होंने कोलकाता स्थित अमेरिकी केंद्र पर हमला किया। उन्होंने खुलेआम भी हमला किया।
उन्होंने गुजरात को नष्ट करने की धमकी दी। यह घटनाओं की एक बहुत ही गंभीर श्रृंखला है।
कोलकाता और दुबई दोनों जगह से यह घोषणा की गई कि वे बदला लेंगे।
गुजरात में भीषण तबाही मचाकर।
ये सामान्य धमकियाँ नहीं हैं। आतंकवाद के अनेक रूप और चेहरे होते हैं।
गुजरात पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करके लाई जा रही नशीले पदार्थों को पकड़ा है।
आतंकी नेटवर्क के माध्यम से अन्य राज्यों में वितरण के लिए।
गुजरात में भी इसका खुलासा हुआ।
देशव्यापी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन लोगों को पकड़ना होगा जो इन नापाक प्रयासों के पीछे हैं।
नकली नोटों और रैकेट के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाना
नकली स्टांप पेपर छापें। पुलिस ने आपराधिक गिरोहों को भी निष्क्रिय कर दिया।
माफिया डॉन छोटा शकील के नेटवर्क पर नकेल कसने से न केवल उसे रोका जा सकेगा।
हमने प्रतिबंधित राष्ट्रविरोधी संगठन की नापाक योजनाओं और गतिविधियों का पर्दाफाश किया।
हमने पूरे भारत से एसआईएमआई संगठन के 100 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
सूरत में गुप्त रूप से एकत्रित हुए लोग। ये लोग अब सलाखों के पीछे बंद हैं। 238 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के कारण
दुबई के अंडरवर्ल्ड, विभिन्न आतंकवादी संगठनों आदि के तत्व गुजरात में वे तत्व जो उन्हें संरक्षण और आश्रय प्रदान कर रहे थे, वे आक्रोशित हैं और गुजरात से बदला लेने के दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं।
यह बहुत गंभीर मामला है और हमें अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
उन्हें अपनी चुनौती का सामना करना होगा।
गुजरात पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रही है।
ऐसे तत्वों को पकड़ना। ऐसे समय में, उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय, उनके काम की सराहना करने के बावजूद, पूरा पुलिस विभाग हतोत्साहित हो रहा है।
हर तरफ से हमले करके। उनके विनाश के इस प्रयास के पीछे क्या कारण है?
मनोबल? ये वही गुजरात पुलिस है, जिसने आपमें से जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनके साथ काम किया था।
आज विपक्ष में बैठे लोगों को राजनीतिक रंग में रंगने की ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं?
मैं केवल इस सदन में जो हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ प्रयास किए जा रहे हैं
राजनीतिक प्रतिवाद निपटाने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। लेकिन मुझे इसके व्यापक प्रभाव को लेकर चिंता है।
इसके निहितार्थों को लेकर गुजरात पुलिस ने एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं।

और उन्हें बदनाम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ अपराध हुए हैं
मैंने ये अपराध किए हैं। मैं इन सभी अपराधों की ज़िम्मेदारी खुद लेने को तैयार हूँ। और अगर वे
अगर मैं उन्हें फांसी पर चढ़ते देखना चाहता हूं, तो मैं खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। लेकिन मैं
मैं सरकारी अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं क्योंकि उन्होंने ये सब किया है।
गुजरात में शांति बहाल करने के लिए सार्थक परिणाम प्राप्त हुए। राजनीतिक संघर्ष (दांव पेच) का अपना स्थान है। लेकिन हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
ऐसे तरीके जो समाज की सेवा करने वाले लोगों का मनोबल गिराते हैं, भले ही वे अपना काम अच्छे से कर रहे हों।
आतंकवादियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 239

राज्य में जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के अपने समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप, मोदी ने पुलिस का बचाव इसलिए नहीं किया कि वे उनमें से दोषी या अक्षम लोगों को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे समझते थे कि पुलिस पर व्यापक हमला उसे और भी अधिक निष्क्रिय और दिशाहीन बना देगा। कारगिल युद्ध और आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर किया गया आतंकवादी हमला, ये सभी हाल की घटनाएं थीं।
सांप्रदायिक हिंसा, तस्करी माफियाओं और अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोहों के लंबे इतिहास वाले सीमावर्ती राज्य गुजरात में पुलिस बल का मनोबल गिराने की स्थिति असहनीय थी। यहां तक कि पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता भी थी, ताकि इसे आतंक और अत्याचार का स्रोत बनने के बजाय अधिक जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनाया जा सके।

इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मियों का समर्थन करना, भ्रष्ट और कानून तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को दरकिनार करना और उनमें आत्मसम्मान का संचार करना आवश्यक था। पुलिस पर अंधाधुंध हमला अच्छे अधिकारियों का भी मनोबल गिरा देता है, और जब पुलिस बल में अपराध का बोलबाला हो तो कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाना केवल बल को एकजुट करता है और सुधार के सभी प्रयासों को विफल कर देता है। मोदी मानते हैं कि पुलिस का पुनर्गठन करना सबसे कठिन, जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। लेकिन यह काम जारी है। अपराध नियंत्रण और जनता के साथ व्यवहार के मामले में गुजरात पुलिस आज अन्य राज्यों से कहीं आगे है। गुजरात के पुलिस स्टेशन, यहां तक कि दूरदराज के इलाकों में भी, भारत के अधिकांश राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर सुसज्जित और संगठित हैं। वे अधिक नागरिक-हितैषी भी लगते हैं।
लेकिन मोदी के पुलिस सुधार के प्रयासों का समर्थन करने के बजाय, कांग्रेस पार्टी, जिसका गुजरात पुलिस के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हमेशा से ही घनिष्ठ संबंध रहा है, ने इसके खिलाफ जमकर हमला बोला, मानो मोदी किसी दूसरे ग्रह से नए रंगरूटों को लेकर आए हों। जिस तरह उन्होंने गोधरा में ट्रेन यात्रियों को जिंदा जलाने के दोषी पाए गए लोगों के बचाव में आवाज उठाई थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने तब से गुजरात पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव किया है और उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि वे मोदी के खिलाफ गए और मोदी विरोधी गैर सरकारी संगठनों के साथ एकजुट हो गए।1 कांग्रेस
1. ऐसे दो अधिकारियों, संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार के विवरण के लिए देखें: मधु पी.
किश्वर, “धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड के नायक: संजीव भट्ट के कुकर्मों की एक झलक,” मानुषी, 2 मई, 2013, वेब.

http://www.manushi.in/articles.php?articleId= 1703&ptype=campaigns&pgno=1#.Uvya3kKSxJM; और,
“RB Shreekumar: Hero No. 2 of Secular Brigade - Part I,” Post Godhra Gujarat and
मोदिनामा, 16 नवंबर 2013, वेब. http://www.manushi.in/articles.php? articleId =1730&ptype=campaigns#.UvybEkKSxJM.
240 मोदी, मुसलमान और मीडिया

पार्टी ने कुख्यात आतंकवादियों का भी इस तरह बचाव किया है मानो वे इस्लाम के सबसे पवित्र प्रतीक और मुस्लिम समुदाय के मसीहा हों। हाल के वर्षों में कांग्रेस शासित सभी राज्यों के साथ-साथ बिहार के नीतीश कुमार, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जैसे कांग्रेस के सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी सैकड़ों मुठभेड़ों में मारे गए लोग शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस ने केवल उन्हीं मुठभेड़ों को गंभीरता से लिया है जिनमें सोहराबुद्दीन, जावेद शेख, जीशान जौहर और अमजद अली राणा जैसे कुख्यात आतंकवादी मारे गए, जिन्हें पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने खुलेआम स्वीकार किया है।
आरोप है कि कांग्रेस ने इन आतंकवादियों के परिवारों को बेहतरीन वकील मुहैया कराए, वहीं दूसरी ओर अमित शाह को निशाना बनाया, जिनके गृह मंत्री रहते हुए ये मुठभेड़ें हुईं। असल निशाना मोदी हैं, शाह नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने यह दावा खड़ा कर दिया है कि इन कथित फर्जी मुठभेड़ों का आदेश मोदी ने दिया था। जबकि ये हत्याएं भारत सरकार के खुफिया ब्यूरो की सक्रिय संलिप्तता से हुईं, जिसने गुजरात पुलिस को सूचना दी थी कि ये लोग राज्य में आतंकी मिशन पर थे।

अध्याय 14

किसने इस काम को जारी रखा?
गोधरा दंगों के बाद के चार चरण

श्री मोदी से मिलने के बाद, मैं उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उन्हें निष्पक्ष पाया और
दंगों को समाप्त करने के अपने इरादे में वे ईमानदार थे। वे चिंतित और दुखी लग रहे थे क्योंकि उनकी पुलिस इस हिंसा को समाप्त करने में विफल रही थी; वे चाहते थे कि मैं इस हिंसा को समाप्त करने के लिए जो भी कदम उचित समझूं, उठाऊं और उन्होंने मुझे पूरे दिल से समर्थन का आश्वासन दिया… मुझे एहसास हुआ कि सभी राजनीतिक दलों के लोग, जो मोदी विरोधी और भाजपा विरोधी थे, इस अराजकता का फायदा उठा रहे थे और किसी न किसी तरह से मोदी को बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे।
के.पी.एस. गिल को केंद्र सरकार द्वारा मई 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया था।
...अन्य कारकों के साथ-साथ, मोदी का ओबीसी जाति से संबंध उनके विरुद्ध गया। गुजरात में यह एक स्थापित परंपरा थी कि केवल पटेल ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चूंकि उन्हें केशूभाई पटेल के स्थान पर भेजा गया था, इसलिए केशूभाई के करीबी लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी उनका साथ दिया और अपने समुदाय को भड़काया।
ए.आई. सैयद, गुजरात पुलिस के पूर्व एडीजी

हालांकि कांग्रेस भाजपा को "सांप्रदायिक" और "अल्पसंख्यक-विरोधी पार्टी" बताकर बदनाम करने से कभी नहीं थकती, लेकिन वास्तविकता में, भाजपा के शासनकाल में वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए जातिगत और सांप्रदायिक दंगों की एक श्रृंखला देखने को मिली। वे इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि मार्च 2002 के बाद गुजरात में यह विभाजनकारी राजनीति कारगर साबित नहीं हुई। निम्नलिखित विवरण में मोदी सरकार द्वारा हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और मोदी के विरोधियों की गतिविधियों का वर्णन किया गया है।
हिंसा भड़कने और घटने के चार अलग-अलग चरण हैं।
2002 के गुजरात दंगों के दौरान ही इसका खुलासा हुआ था। हिंसक घटनाओं के समय और उनके कारणों का विश्लेषण मीडिया द्वारा अब तक प्रचारित की गई साजिश और पैटर्न से बिल्कुल अलग एक भयावह साजिश और पैटर्न को दर्शाता है।
किसने इस काम को जारी रखा? 243

हिंसा का पहला चरण 28 फरवरी, 2002 को शुरू हुआ और चला...
3 मार्च 2002 तक का समय गोधरा ट्रेन कांड को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जन आक्रोश का फायदा उठाते हुए हर तरह के असामाजिक राजनेताओं द्वारा सरासर बाधित रहा। हालांकि, सेना की त्वरित तैनाती के कारण 72 घंटों के भीतर ही स्थिति नियंत्रण में आ गई। मार्च के मध्य तक हालात सामान्य होने लगे। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान सामान्य रूप से काम करने लगे थे।
हिंसा की छिटपुट घटनाओं का दूसरा चरण, 18 मार्च से शुरू होकर...
28 मार्च की घटना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उपद्रवियों द्वारा विभिन्न केंद्रों पर 18 मार्च, 2002 से शुरू हुई बोर्ड परीक्षाओं

को बाधित करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थी। यह सब माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखने के लिए किया गया था।
17 अप्रैल से शुरू होने वाला तीसरा चरण भी शरारती तत्वों द्वारा ही अंजाम दिया गया था।
बोर्ड परीक्षाओं के दूसरे चरण की पूर्व संध्या पर, सामान्य स्थिति की बहाली को बाधित करने के लिए ये घटनाएँ रची गईं, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि मोदी हिंसा को नियंत्रित करने में अनिच्छुक और अक्षम हैं। लेकिन मोदी सरकार अब अधिक समझदार हो चुकी थी और उसने इन घटनाओं को 28 फरवरी की तरह बढ़ने नहीं दिया, जब सरकार अप्रत्याशित परिस्थितियों में फंस गई थी।
5 मई से शुरू हुई हिंसा के चौथे चरण में हिंदुओं पर हमले हुए। उपद्रवी तत्वों द्वारा पड़ोस में घुसपैठ कर लोगों को भड़काने का इरादा था। उनका मकसद अगले दिन राज्यसभा के समापन सत्र में गुजरात पर होने वाली निर्धारित चर्चा को प्रभावित करना था।
ये सुनियोजित दंगे संसद को गुमराह करने के उद्देश्य से किए गए थे। साथ ही बाहरी दुनिया को भी यह विश्वास दिलाने के लिए कि गुजरात में स्थिति गंभीर थी और नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द एक राष्ट्रीय उन्माद पैदा करने के लिए ताकि प्रधानमंत्री वाजपेयी को मोदी को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया जा सके।
हालांकि, निशाना सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं थे—निशाना तो और भी बहुत से लोग थे।
अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भाजपा के सर्वमान्य "उदारवादी चेहरे" के रूप में वाजपेयी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में कई सहयोगियों को आकर्षित करके भाजपा के राजनीतिक अलगाव को समाप्त कर दिया था, जिससे कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी की संभावना बेहद धूमिल हो गई थी। वाजपेयी न केवल एक लोकप्रिय जन नेता थे, बल्कि उदारीकरण

के अपने एजेंडे के माध्यम से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में भी सक्षम थे। वाजपेयी की एनडीए सरकार की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए उसकी राजनीतिक वैधता को नष्ट करना आवश्यक था। कांग्रेस पार्टी को भाजपा शासित राज्यों, विशेषकर गुजरात में सांप्रदायिक दंगों की सख्त जरूरत थी, ताकि भाजपा की कथित राक्षसी, अल्पसंख्यक-विरोधी छवि को लेकर उन्माद पैदा किया जा सके और तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे भाजपा के स्वघोषित 'धर्मनिरपेक्ष' सहयोगियों को अपना समर्थन वापस लेने और भाजपा को अछूत घोषित करने के लिए मजबूर किया जा सके।
244 मोदी, मुसलमान और मीडिया

यह रणनीति पूरी तरह कारगर साबित हुई क्योंकि टीडीपी, बीजेडी और तृणमूल ने सत्ता छोड़ दी।
मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी साख बनाए रखने के लिए एनडीए गठबंधन बनाया गया था। इसी ने सोनिया गांधी की कांग्रेस को 2004 में वाजपेयी को सत्ता से बेदखल करने में मदद की। हालांकि हर लिहाज से देखा जाए तो वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक शिष्टाचार और सम्मान का व्यवहार किया, लेकिन गुजरात दंगों को एनडीए के "धर्मनिरपेक्ष" सहयोगियों को भाजपा से दूर करने और उसे अलग-थलग करने के लिए एक सुविधाजनक बहाना बना दिया गया। भाजपा को एक बार फिर उन्हीं सहयोगियों द्वारा राजनीतिक रूप से "अछूत" करार दिया गया, जो 1999 में भाजपा के सत्ता में आने पर खुशी-खुशी एनडीए के साथ जुड़ गए थे। परिणामस्वरूप वाजपेयी सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन मोदी सत्ता में बने रहे क्योंकि वे वाजपेयी समेत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से कहीं बेहतर तरीके से राजनीति को समझते थे।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], 28 [illegible], 2002 [illegible] [illegible] [illegible]

फायरिंग में 101 लोगों की मौत इस बात का प्रमाण है कि पुलिस पूरी तरह से मिलीभगत या निष्क्रिय नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों में से 61 हिंदू और 40 मुसलमान थे। अन्य ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौत हुई हो।
किसने इस काम को जारी रखा? 245

भारत के अन्य राज्यों में दंगों के दौरान बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं हो रही हैं।
हिंसा का दूसरा चरण: सरकार ने हज यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी चरण में हज से लौट रहे 6,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक का गुजरात पुलिस ने प्रवेश द्वार पर स्वागत किया और प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को गुजरात के कस्बों और गांवों में स्थित 400 अलग-अलग स्थानों पर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान, राजकोट के मुस्लिम नेताओं ने हज यात्रियों के लिए कांग्रेस की तुलना में बेहतर व्यवस्था करने के लिए नए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया था। जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है, दंगों के भड़कने के बाद मोदी के कार्यालय से जारी पहले निर्देशों में से एक यह था कि पुलिस को गुजरात से हज पर गए 6,000 मुस्लिम तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। 20 मार्च, 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले की रिपोर्ट इस प्रकार की:
गुजरात से हज यात्रियों का पहला जत्था, 287 हज यात्री, लगभग 55 दिनों की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मंगलवार को घर लौट आए। उनकी सुरक्षा के लिए करीब 150 सशस्त्र पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस उपायुक्त प्रवीण गोंदिया के अनुसार, यात्रियों को हवाई अड्डे से 19 जिलों में स्थित उनके विभिन्न

परीक्षाओं के आयोजन का पुरजोर विरोध किया गया, मानो यह मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने के लिए किया जा रहा हो। उन्होंने यह बहाना बनाया कि मुस्लिम बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरा समुदाय आतंकित है। सरकार ने तर्क दिया कि 469 पुलिस जिलों में से केवल 163 जिलों में दंगे हुए थे। दंगों के चरम पर भी, केवल 95 पुलिस जिले ही सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। परीक्षाओं को स्थगित करने का मतलब होगा कि राज्य भर के लाखों छात्रों का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। यह निराशा युवाओं को सामान्य दिनचर्या में लौटने से भी रोकेगी। लेकिन मोदी विरोधी समूह झुकने को तैयार नहीं थे।
कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी गैर सरकारी संगठन इतने हताश थे कि
सामान्य स्थिति बहाल होने से रोकने के लिए उन्होंने परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया—वे उन युवाओं के मन पर पड़ने वाले अशांत प्रभाव से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, जिनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता। हालांकि, सरकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद, उच्च न्यायालय ने उन्हें पर्याप्त पाया। इसलिए, रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया गया। परीक्षाओं का पहला चरण 18 मार्च से शुरू हुआ, सिवाय कुछ राज्यों के।
अहमदाबाद और वडोदरा शहरों के पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों में हिंसा भड़की। लेकिन परीक्षाओं में बाधा डालने के लिए उपद्रवियों को खुला छोड़ दिया गया, जिन्होंने समूह संघर्ष, आगजनी और हत्याएं कीं। 20 मार्च, 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा का दूसरा चरण अहमदाबाद, भरूच, गोधरा, मोडासा और हिम्मत नगर के चारदीवारी वाले इलाकों तक ही सीमित रहा। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं के बाद साबरकांठा जिले के हिम्मत नगर कस्बे

में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। अफवाहों के बाद कस्बे में तनाव बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।
द हिंदू ने 20 मार्च 2002 को रिपोर्ट किया कि हिंसा के बाद,
भरूच और मोडासा दोनों शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते अधिकारियों को इन शहरों में चल रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा अहमदाबाद और बड़ौदा में भी अशांति की स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं पहले ही स्थगित कर दी गई थीं।
किसने इस मामले को गरमागरम बनाए रखा? 247

दंगे आसपास के इलाकों में भी फैल गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी।
22 मार्च, 2002 को यह खबर फैली कि पड़ोसी मोदासा में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद हिम्मत नगर में तनाव का माहौल था, जहां दो लोगों की मौत हो गई थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब खरीदारी करने आए एक कच्छी पटेल का बेटा लापता हो गया। एक निवासी ने बताया, “स्थानीय विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और भाजपा सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय को दोषी ठहराया। उन्होंने पुलिस को दोपहर 2 बजे तक लड़के को लाने का समय दिया था।” प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 1,500 से अधिक लोगों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और लड़के की बरामदगी की मांग की। जल्द ही आगजनी और हिंसा भड़क उठी और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं। हालांकि, उपद्रवियों के अथक प्रयासों के बावजूद, स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रण में कर लिया गया। राज्य के बाकी हिस्सों में वैसे भी शांति बनी रही और इसलिए, राज्य के अधिकांश हिस्सों में बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हुईं।

एनएचआरसी टीम को प्रभावित करने के लिए हिंसा को भड़काया गया: ये घटनाएँ थीं
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वर्मा की गुजरात यात्रा को ध्यान में रखते हुए यह सब सुनियोजित ढंग से किया गया था। उनके गोधरा जाने के दिन ही नई हिंसा भड़क उठी। यह अहमदाबाद में हुई घटनाओं के अतिरिक्त थी। मानस दासगुप्ता ने 22 मार्च, 2002 को द हिंदू में रिपोर्ट किया:
आज दोपहर से अहमदाबाद में हिंसा भड़क उठी, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए, जिनमें से पांच पुलिस फायरिंग में और दो चाकूबाजी की घटनाओं में मारे गए। वहीं गुजरात के अधिकांश हिस्सों में आज शांति बनी रही। हिंसा से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों से चाकूबाजी, बड़े पैमाने पर आगजनी और पत्थरबाजी की कम से कम छह घटनाओं की सूचना मिलने के बाद शाम को कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर और करंज पुलिस थाना क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया। इन क्षेत्रों से कर्फ्यू कल ही हटाया गया था। सेना को एक बार फिर फ्लैग मार्च के लिए बुलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। सिंधी बाजार क्षेत्र में चाकूबाजी की खबरों के बाद आज दोपहर भीड़ ने कम से कम 100 दुकानों में आग लगा दी, जिससे वे नष्ट हो गईं। कालूपुर क्षेत्र के सकारिया-नी-पोल के पास दो समुदायों के लोगों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
इन गड़बड़ियों को अंजाम देने वालों का एक स्पष्ट एजेंडा था— एनएचआरसी टीम को यह संदेश देना कि गुजरात अभी भी जल रहा है और नरेंद्र मोदी ही इसके मुख्य दोषी हैं। एनएचआरसी द्वारा नरेंद्र मोदी पर किसी भी प्रकार की कड़ी टिप्पणी से उनके मोदी-विरोधी अभियान को काफी वैधता मिली। जब तक एनएचआरसी टीम 248 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

गुजरात में रहने के दौरान, अहमदाबाद, गोधरा और वडोदरा के कुछ हिस्सों में हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की छिटपुट घटनाएं जारी रहीं और अफवाहें 'जंगल की आग की तरह फैलती रहीं'। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 24 मार्च, 2002 को रिपोर्ट किया:
राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) की एक टीम गोधरा में डेरा डाले हुए थी और शहर का दौरा कर रही थी, तभी शुक्रवार को यहाँ फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो घायल हो गए। शहर के छह पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया। … चाकूबाजी की घटनाओं के बाद लोग सड़कों पर उतरने लगे और शहर की चारदीवारी वाले इलाकों में बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच झड़पों की छोटी-मोटी घटनाएं भी सामने आईं।
सरकार ने मुहर्रम और होली के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित किया: तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 25 मार्च, 2002, यानी मुहर्रम के दिन कोई अप्रिय घटना न हो। यह मुख्य रूप से कड़ी पुलिस बंदोबस्त के कारण संभव हुआ। पिछले वर्षों में, मुहर्रम के दिन दंगे आम बात थे। 29 मार्च, 2002 को द हिंदू ने रिपोर्ट किया, “गुजरात सरकार कल होली के त्योहार के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। छिटपुट हिंसा जारी रहने के बावजूद, त्योहार और भड़काऊ पर्चों के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जो लोगों को ‘गुजरात को बचाने’ के लिए हिंसा के लिए उकसा रहे थे। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है…”
टाइम्स ऑफ इंडिया ने 29 मार्च, 2002 को यह भी रिपोर्ट किया कि "हालांकि कोई
अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए थे और होली के दिन अहमदाबाद में सेना और बीएसएफ ने लगातार गश्त की। एक दिन पहले, सेना ने सरखेज में

ध्वजारोहण किया, जहां आगजनी की घटनाओं के बाद अशांति फैल गई... गुजरात में होली बहुत ही सादगी से, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई और कहीं भी हिंसा की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि, राजनीतिक उपद्रवियों ने सांप्रदायिक झड़पों को भड़काने के लिए लगातार अफवाहें फैलाईं और अफवाहों को पुलिस तैनात करके या लोगों को गिरफ्तार करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
मानस दासगुप्ता ने 2 अप्रैल, 2002 को द हिंदू में रिपोर्ट किया, “पुलिस
कमिश्नर पी.सी. पांडे ने हिंसा के फिर से भड़कने का कारण 'अफवाह फैलाना' बताया और कहा कि पुलिस उपद्रवी भीड़ को सड़कों पर उतरने और प्रतिद्वंद्वी समुदायों में दहशत फैलाने से रोकने के लिए नए तरीके अपना रही है... वीडियो कैमरों से लैस मोबाइल वैन शहर में घूमकर भीड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में उपद्रवियों की पहचान की जा सके... प्रधानमंत्री वाजपेयी को घेरने की कोशिश: प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पद से ठीक एक दिन पहले...
गुजरात की यात्रा के दौरान, राज्य में हिंसा की विचित्र घटनाएं भड़क उठीं।
किसने इस काम को जारी रखा? 249

विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। 3 अप्रैल, 2002 को द हिंदू ने खबर दी कि वडोदरा के पुलिस आयुक्त दीन दयाल तुतेजा उस समय घायल हो गए जब उपद्रवियों ने उन पर पेट्रोल बम फेंका। एक अन्य घटना में, दक्षिण गुजरात के अंकलेश्वर में पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने गोली चलाई, जबकि कच्छ जिले के आदिपुर-गांधीधाम में भी तनाव व्याप्त था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 अप्रैल, 2002 को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राज्य प्रशासन की चिंता पर

रिपोर्ट दी, “प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आगमन की पूर्व संध्या पर गुजरात, विशेषकर कच्छ क्षेत्र में, जो अब तक सांप्रदायिक उन्माद से बचा हुआ था, हिंसा की ताजा लहर ने राज्य प्रशासन को झकझोर दिया है, जबकि अधिकारी दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे...”
द हिंदू ने 4 अप्रैल, 2002 को रिपोर्ट किया कि कम से कम नौ व्यक्ति थे
वाजपेयी की यात्रा की पूर्व संध्या पर हिंसक घटनाओं में कई लोग मारे गए। इनमें से छह लोगों को अहमदाबाद जिले के अबासाना गांव में जिंदा जला दिया गया। इस क्रूरता के पीछे का मकसद स्पष्ट था: वाजपेयी के सामने ऐसी भयावह छवि पेश करना कि वे मोदी को बर्खास्त करने के लिए विवश हो जाएं। लेकिन बाद के चरणों में, राज्य सरकार ने कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं बरती।
7 अप्रैल 2002 को द हिंदू ने रिपोर्ट किया, “पुलिस ने सेना से मदद मांगी थी।”
घोडासर में अशांति को शांत करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जहां एक भीड़ ने कुछ आवासीय कॉलोनियों पर हमला किया, बिजली आपूर्ति काटकर पेट्रोल बम और जलते हुए कपड़े फेंके। पुलिस ने 80 राउंड फायरिंग की, जिसमें दो लोग मारे गए और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दर्जनों आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने 3 अप्रैल को अहमदाबाद जिले के देट्रोज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अबासाना गांव में एक अल्पसंख्यक परिवार के पांच लोगों को जिंदा जलाने के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए: इन विध्वंसों से बेपरवाह,
मोदी ने लोगों की ऊर्जा को रचनात्मक राजनीति की ओर निर्देशित करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। इसलिए, उन्होंने यह सुनिश्चित

किया कि पंचायत चुनाव घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न हों। यह भारत के कई मुख्यमंत्रियों द्वारा पंचायत चुनावों को अनिश्चित काल तक टालने के बहाने के रूप में "अशांत परिस्थितियों" का उपयोग करने के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि इससे उन्हें राज्य की राजधानी में सारी शक्ति केंद्रित करने का अवसर मिलता है।
8 अप्रैल, 2002 को द हिंदू अखबार ने मतदान के बारे में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित की।
पंचायत चुनावों में: “सरकार के एक प्रवक्ता ने लगभग 1,060 ग्राम पंचायत चुनावों में शांतिपूर्ण मतदान को राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी का संकेत बताया। अनुमानतः 55 से 60 प्रतिशत मतदाताओं ने ग्राम पंचायत चुनावों में अपने मत डाले, जो विभिन्न कारणों से दिसंबर में नहीं हो सके थे। 250 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

मतदान [मार्च में] होने वाला था, लेकिन हिंसा के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।
कानून व्यवस्था में सुधार के साथ, राज्य माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भी सुधार हुआ है।
माध्यमिक परीक्षा बोर्ड ने सिफारिश की है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का दूसरा चरण 14 अप्रैल के बाद कभी भी आयोजित किया जाए।
सरकार द्वारा 18 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाओं के दूसरे चरण को आयोजित करने के निर्णय के बाद, सुनियोजित हिंसा का तीसरा चरण शुरू हुआ। मोदी विरोधी गैर सरकारी संगठनों के समर्थन से कई मुस्लिम संगठनों ने मुस्लिम छात्रों से परीक्षा बहिष्कार का आह्वान किया। लेकिन छात्रों ने हिंसा की धमकियों के बावजूद बहिष्कार का विरोध किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 17 अप्रैल, 2002 को रिपोर्ट किया:

18 अप्रैल से शुरू होने वाली माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए 'असुरक्षित' केंद्रों का हवाला देते हुए, एक मुस्लिम समूह ने मंगलवार रात को समुदाय से संबंधित छात्रों से कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया। 'अहमदाबाद के प्रभावित नागरिकों' के तत्वावधान में आयोजित एक बैठक में यह संकल्प लिया गया कि 'अल्पसंख्यक समुदाय 18 अप्रैल से शुरू होने वाली कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं में भाग नहीं लेगा।' ...अल्पसंख्यक समुदाय परीक्षाओं में भाग नहीं लेगा... इस बीच, मुख्यमंत्री मोदी ने छात्रों से 'बिना किसी तनाव के' परीक्षा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम छात्रों ने परीक्षा बहिष्कार के आह्वान का विरोध किया: सरकार ने अशांत क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को परीक्षा देने में सुविधा प्रदान करने के लिए नियमों में ढील दी। आवश्यकता के आधार पर छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र आरक्षित किए गए; परीक्षा में देर से प्रवेश की अनुमति दी गई, और जिन छात्रों की प्रवेश पर्ची खो गई थी, उन्हें भी परीक्षा देने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की सुरक्षा के साथ-साथ परीक्षा कक्षों तक आने-जाने के लिए पुलिस सुरक्षा वाली बसों की व्यवस्था करके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। मानस दासगुप्ता ने 20 अप्रैल, 2002 को द हिंदू में यह रिपोर्ट प्रकाशित की।
गुजरात सरकार और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के प्रयासों के फलस्वरूप आज बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि राज्य में चल रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में मुस्लिम समुदाय के अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं।
किसने इस काम को जारी रखा? 251

मुस्लिम छात्रों की भारी संख्या में उपस्थिति ने तत्काल प्रभाव दिखाया।
परीक्षाओं में उपस्थिति के कुल प्रतिशत में सुधार हुआ है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार को उपस्थिति 93 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 96.16 प्रतिशत हो गई, जो सामान्य उपस्थिति (लगभग 98 प्रतिशत) से मामूली रूप से कम है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन से उत्साहित होकर, अधिक मुस्लिम अभिभावकों ने अपने बच्चों को परीक्षा में भेजने की सहमति दी है। श्री मोदी के इस आश्वासन से अल्पसंख्यक छात्रों का मनोबल बढ़ा है कि सुरक्षा कारणों से पिछले दो दिनों में परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दंगा प्रभावित मुस्लिम और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बने राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने अभिभावकों को उनके बच्चों की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया। श्री फर्नांडीस, जो राज्य के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के चार दिवसीय दौरे के लिए गुरुवार रात अहमदाबाद पहुंचे, ने सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करने के लिए कुछ परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और छात्रों से बात की। अभिभावकों से उनके अनुरोध का तुरंत समर्थन मिला।
परीक्षा बाधित करने पर आमादा लोगों द्वारा किए गए उत्पीड़न के बारे में मोदी ने यह कहा:
हमने वार्षिक बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, फिर भी इन गैर-सरकारी संगठनों और कांग्रेस पार्टी ने अथाह बाधाएं खड़ी कीं। लेकिन अदालतों ने हमारी मदद की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि जो छात्र किसी कारणवश निर्धारित समय पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए मैं अलग से परीक्षा आयोजित करने को तैयार हूं। लेकिन उन्हें पूरे

उन्होंने परीक्षाओं पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने हमारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की, तो उन्हें संतोषजनक पाया। इसलिए, उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाई। इन सभी उपद्रवी तत्वों के भारी दबाव के बावजूद, मुस्लिम बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। औसत उपस्थिति 98 प्रतिशत थी; उस वर्ष मुस्लिम छात्रों ने और भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए। सामान्यतः, मुस्लिम छात्रों की सफलता दर 60 प्रतिशत हुआ करती थी; उस वर्ष यह बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई। लेकिन ये गैर-सरकारी संगठन केवल एक ही बात दोहराते रहे: मुसलमान मर रहे हैं; उन्हें कुचला और मारा जा रहा है।
जैसे ही हालात सामान्य होने लगे, सेना प्रमुख एस. पद्मनाभन ने मीडिया को बताया कि अब गुजरात से सेना वापस बुलाने का समय आ गया है। लेकिन तभी मानो पहले से तय योजना के तहत अशांति का एक नया दौर शुरू हो गया।
राम नवमी पर जानबूझकर व्यवधान: जब परीक्षाएं
अहमदाबाद में भले ही शांतिपूर्ण शुरुआत हुई थी, लेकिन 21 अप्रैल 2002 को राम नवमी के दिन सुनियोजित हिंसक झड़पों का एक और दौर देखने को मिला। इसी तरह की गड़बड़ी मेहसाना जिले के कढ़ी में भी फैलाई गई। एक महत्वपूर्ण त्योहार के दिन इस तरह की घटनाओं का स्पष्ट उद्देश्य हिंदुओं को भड़काना था। समय ने भी उनके असली मकसद को उजागर कर दिया। संसद का सत्र 22 अप्रैल को फिर से शुरू होना था। हिंसा के इस नए प्रकोप ने कांग्रेस और वामपंथी दलों को केंद्र में वाजपेयी सरकार और गुजरात में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला करने का मौका दिया। 22 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा:
रविवार को गुजरात में हिंसा की एक नई लहर दौड़ गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस

राज्य के 'शांति अभियान' पर थे। मृतकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। राम नवमी के दिन रविवार को अहमदाबाद में हुई हिंसा में मारे गए 12 लोगों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। हिंसा शहर के संवेदनशील इलाकों के साथ-साथ पड़ोसी खेड़ा, वडोदरा और मेहसाना जिलों में भी फैल गई।
शनिवार रात कपडवंज इलाके में पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
खेड़ा जिला। अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में रविवार को हिंसा भड़क उठी, जहां तलवार के घावों से एक कांस्टेबल की मौत हो गई और एक व्यक्ति विस्फोट में मारा गया। शहर में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, पुलिस की गोलियों से एक महिला समेत आठ अन्य लोग शहीद हो गए। दंगाई भीड़ ने बापुनगर इलाके के हरदासनगर में एक पुलिस चौकी को भी आग लगा दी।
किसने इस काम को जारी रखा? 253

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पुलिस के अनुसार, रामधुन कार्यक्रम में एक समूह ने कथित तौर पर श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके, जिससे हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने कम से कम 60 राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें सात लोग घायल हो गए। बीएसएफ और आरएएफ को भी बुलाया गया था। पुलिस ने इस गड़बड़ी के संबंध में 74 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार रात से शुरू हुई पत्थरबाजी, आगजनी, निजी फायरिंग और देसी विस्फोटों के बाद भीड़ के तितर-बितर होने से इनकार करने पर अहमदाबाद के अशांत इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। भीड़ ने शनिवार रात नागपुर वोहरा नी चाली में आग लगा दी और फिर दमकलकर्मियों को वहां पहुंचने से रोक दिया। पुलिस ने दंगाइयों पर गोली चलाई। रविवार को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना को बुलाया गया, जिसके बाद आगजनी और हिंसा आसपास के

अन्य इलाकों में भी फैल गई। इलाके में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अमर सुरेश राव पाटिल की धारदार हथियार से हमले में मौत हो गई।
हालांकि रिपोर्ट में समुदायों का नाम नहीं लिया गया है, फिर भी इसे पढ़ने से
इन पंक्तियों के बीच से यह स्पष्ट होता है कि मुसलमान न केवल पीड़ित हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में हमलावरों में भी शामिल हैं। हालांकि, जब भी आदिवासियों ने हिंसक कृत्यों को अंजाम दिया, उनकी पहचान हमेशा हो गई। उदाहरण के लिए, उसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वडोदरा जिले में, छोटा उदयपुर सहित, कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं, "जहां तीर-धनुष से लैस आदिवासियों ने कथित तौर पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।" द हिंदू ने 23 अप्रैल, 2002 को रिपोर्ट किया:
अहमदाबाद के छावनी क्षेत्र में स्थित बैरकों में लौटी सेना, हिंसा प्रभावित इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल (आरपीएन) के जवानों और पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पर लौट आई और ध्वज मार्च निकाला। इस नए सिरे से भड़की हिंसा का असर चल रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं पर भी पड़ा, जो कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गईं।
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरसिंह चौधरी ने निरंतरता का समर्थन किया।
परीक्षाओं के संबंध में, श्री चौधरी ने अपने कुछ पार्टी सहयोगियों द्वारा अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मिलकर छात्रों से परीक्षा बहिष्कार का आह्वान करने पर गंभीर आपत्ति जताई। आज यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि वे उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगेंगे जिन्होंने बहिष्कार के आह्वान का समर्थन किया था।

परीक्षा बहिष्कार पर कांग्रेस का दोहरा रुख: हालांकि, अखबारों में पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि परीक्षा बहिष्कार के आह्वान में कांग्रेसी लोग गड़बड़ी फैलाने में शामिल थे; 254 मोदी, मुसलमान और मीडिया

विधानसभा में, उसी अमरसिंह चौधरी ने आतंकित मुस्लिम छात्रों पर परीक्षाएं थोपने के लिए नरेंद्र मोदी पर हमला किया। मोदी ने कांग्रेस नेता को उनके दोहरे रवैये की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी:
श्री अमरसिंह ने परीक्षाओं पर लंबा-चौड़ा भाषण दिया। मैं उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं राज्य सरकार को प्राप्त एक फैक्स पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, “राज्य में अशांत परिस्थितियों के बावजूद छात्रों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित करना सही कदम था।” इसमें आगे लिखा है, “छोटा उदयपुर और क्वाट जैसे हमारे अशांत आदिवासी क्षेत्रों में भी परीक्षाएं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित की जा रही हैं। हमें इस बात की खुशी है।” यह फैक्स छोटा उदयपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित विधायक श्री सुखरामभाई राठवा ने भेजा है। इस पत्र पर क्षेत्र के कई लोगों के हस्ताक्षर हैं।
इन सभी वर्षों में, परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत आंकड़ा
97 से 98 प्रतिशत तक। मैं गर्व से कहता हूँ कि आज जहाँ भी परीक्षाएँ हो रही हैं, 98 प्रतिशत छात्र परीक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज़ हैं कि हिंसा को तीन दिनों में काबू कर लिया गया। कुछ लोगों ने ठान लिया है कि वे सरकार को 72 घंटों में दंगे पर काबू पाने का श्रेय नहीं लेने देंगे। इसलिए, वे यह साबित करने

पर तुले हैं कि वे 72 दिनों तक अराजकता जारी रख सकते हैं। ऐसे सपने देखने वाले गलती कर रहे हैं। उनके सपने पूरे नहीं होंगे। यह सरकार शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। तोड़फोड़ के प्रयासों के बावजूद, बोर्ड परीक्षाओं का दूसरा चरण 18 अप्रैल, 2002 से बिना किसी रुकावट के जारी रहा। हालांकि, अप्रत्याशित स्थानों पर छिटपुट घटनाओं ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया। द हिंदू ने 26 अप्रैल, 2002 को रिपोर्ट किया: “दो महीनों में पहली बार, हिंसा से अपेक्षाकृत अछूते रहे सौराष्ट्र क्षेत्र में बुधवार रात से अशांति देखी गई... उपद्रवियों ने दो मंदिरों पर हमला किया और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे विरोधी गुटों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसके चलते पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें छह लोग घायल हो गए...”
सामान्य स्थिति की वापसी को रोकने के लिए किए गए दृढ़ प्रयासों के बावजूद
विपक्ष के विरोध के बावजूद, सरकार ने एक बार फिर सुनियोजित हिंसा के बाद परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले मुस्लिम छात्रों का विशेष ध्यान रखा। सरकार ने घोषणा की कि अप्रैल में परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों के लिए अहमदाबाद और बड़ौदा में पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
किसने इस काम को जारी रखा? 255

टाइम्स ऑफ इंडिया ने 27 अप्रैल, 2002 को लिखा: “सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किरित रावल ने अदालत को आश्वासन दिया कि जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, उन्हें भी पुन: परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे यह वचन दें कि अप्रैल की परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंक रद्द कर दिए जाएंगे…”

लेकिन वडोदरा में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जहां कम से कम दो लोग मारे गए।
19 लोग मारे गए और घायल हुए। द हिंदू ने 28 अप्रैल, 2002 को रिपोर्ट किया, “वादी इलाके में प्रतिद्वंद्वी समुदायों के लोग कल देर रात सड़कों पर उतर आए और एक-दूसरे पर पत्थर और बम फेंके। पुलिस ने कहा कि अशांति का कोई तात्कालिक कारण नहीं था और हिंसा दोनों समुदायों के आपराधिक गिरोहों की करतूत हो सकती है।”
अशांति का चौथा चरण
5 मई से शुरू हुए चौथे चरण में उपद्रवी तत्वों द्वारा और भी अधिक हिंसा देखने को मिली, जिन्हें हिंदू बहुल इलाकों पर हमला करने के लिए उकसाया गया था। इनका स्पष्ट उद्देश्य बड़े पैमाने पर हिंदू- मुस्लिम दंगे भड़काना था। ये हमले जानबूझकर 6 मई को राज्यसभा के समापन सत्र की पूर्व संध्या पर रचे गए थे, ताकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को एनडीए सरकार पर हमला करने का मौका मिल सके। 5 मई, 2002 की सुबह अहमदाबाद शहर के परिक्षित नगर इलाके में संगठित और आक्रामक हमले हुए। इनमें बड़े पैमाने पर आग्नेय शस्त्रों और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। इस हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने बम और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया। इससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और शत्रुता और भी बढ़ गई।
राहत शिविर में कार्यरत चिकित्सा कर्मचारियों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा।
दो समुदायों के बीच आपसी अविश्वास। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 6 मई, 2002 को रिपोर्ट किया:
शनिवार को जब डॉक्टरों की एक टीम शहर के संवेदनशील बापुनगर इलाके में स्थित अमन चौक राहत शिविर में पहुंची, तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। शिविर में मौजूद उनके मरीजों ने उन पर सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाया। जब डॉक्टरों ने शिविर में मौजूद मरीजों को दिए गए

चोट के प्रमाण पत्रों में संशोधन करने से इनकार कर दिया, तो शिविर में मौजूद कुछ लोगों ने धमकी भरे लहजे में कहा, “तुम हिंदू डॉक्टर हो ना? तुम्हारे दिमाग में हमारे लिए जहर भरा हुआ है।”
उनमें से एक ने याद करते हुए बताया कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि हम जल्दबाजी में वहां से भाग गए।
पीछे हटना। 'यह एक भयानक और परेशान करने वाला अनुभव था। इन लोगों ने हम पर आरोप लगाया कि हमने चोट को असलियत से ज़्यादा गंभीर दिखाने वाले प्रमाण पत्र नहीं दिए। 256 मोदी, मुसलमान और मीडिया

डॉक्टर ने सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हमने समझाने की कोशिश की कि अगर किसी व्यक्ति को पत्थर लगता है, तो दिशानिर्देशों के अनुसार उसे केवल दस प्रतिशत चोट का प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया और हम पर सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाने लगे।"
अमन चौक जैसी घटनाओं और धमकियों ने कई लोगों को प्रभावित किया है। राहत शिविरों का दौरा कर रही 50 चिकित्सा टीमें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं… यह सिलसिला अप्रैल की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब जुहापुरा स्थित उनके क्लिनिक में डॉ. अमित मेहता पर चाकू से हमला किया गया, जिससे चिकित्सा जगत में दहशत फैल गई। इसके बाद हुए हमलों और धमकियों ने डॉक्टरों के डर को और पुख्ता कर दिया है। जमालपुर, बहरामपुरा, बापू नगर, गोमतीपुर, शाह आलम, शाहपुर, दरियापुर और जुहापुरा जैसे संवेदनशील इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए भी स्थिति उतनी ही खराब है…
सुपर कॉप के.पी.एस. गिल को हिंसा पर लगाम लगाने के लिए तैनात किया गया। मई 2002 के पहले सप्ताह में, वाजपेयी सरकार ने के.पी.एस. गिल को मुख्यमंत्री का विशेष सलाहकार नियुक्त किया। उनका काम स्थिति की समीक्षा करना, निगरानी करना और पुलिस बल के कुशल संचालन और

प्रबंधन के लिए कदम उठाना था। सभी रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी की नियुक्ति ने एक मजबूत संकेत दिया कि केंद्र में एनडीए सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सांप्रदायिक दंगे भड़काने वालों पर नकेल कसने के लिए गंभीर थीं। के.पी.एस. गिल का एक कुशल, निष्पक्ष पुलिस अधिकारी के रूप में शानदार रिकॉर्ड था, जिन्होंने सांप्रदायिक रूप से विभाजित असम और आतंकवाद से ग्रस्त पंजाब में विस्फोटक स्थितियों को संभालने के लिए प्रशंसा अर्जित की थी। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ उनके व्यापक अभियान के कारण कुछ गैर-सरकारी संगठनों और उग्रवादियों के समर्थकों के बीच वे विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में आम जनता के बीच वे एक अत्यंत सम्मानित और प्रशंसित व्यक्ति हैं। हाल ही में जारी एक जीवनी1 में दर्ज जानकारी के अनुसार, उनके आगमन ने दंगाइयों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी - डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक - यह संदेश दिया कि अब गैरजिम्मेदाराना कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उनके आगमन के कुछ ही दिनों के भीतर, शहर के तीन शीर्ष पुलिस अधिकारियों को
के.आर. कौशिक, नए पुलिस आयुक्त, ने कहा कि गिल ने तुरंत पुलिस को भीड़ में इकट्ठा होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। हालांकि उनके आने के बाद के दो दिनों में 14 लोग मारे गए और हिंसा कम होने के कोई संकेत नहीं दिखे, गिल ने पुलिस प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए तेजी से कदम उठाए। इस चरण में खुलेआम दुर्व्यवहार देखने को मिला।
1. राहुल चंदन, के.पी.एस. गिल: द पैरामाउंट कॉप (नोएडा: मेपल प्रेस, 2013)।
किसने इस काम को जारी रखा? 257

मुसलमानों के बीच उपद्रवियों को आक्रामक होने और अंतर-सामुदायिक संघर्षों को भड़काने के लिए उकसाना।
द हिंदू ने 6 मई, 2002 को रिपोर्ट किया कि हिंसा एक बार फिर भड़क उठी।
आज अहमदाबाद और वडोदरा में हिंसक झड़पों ने दंगाग्रस्त गुजरात में पहले से ही कायम शांति को भंग कर दिया। यूएनआई के अनुसार, हिंसा में छह लोग मारे गए, जिनमें से दो को जिंदा जला दिया गया। अशांत क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया है। वडोदरा से चाकूबाजी की कुछ घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी मृतकों में शामिल था। बहरामपुरा-शाह आलम इलाके में हिंसक भीड़ ने एक कबाड़ बाजार में आग लगा दी, जिससे आसपास के कुछ घर भी जल गए। विरोधी गुट सड़कों पर उतर आए और एक-दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके। आरोप है कि कई बम भी फोड़े गए।
कुछ क्षेत्रों में हिंसा का सिलसिला जारी रहने के कारण, राज्य माध्यमिक और
उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 जून से शुरू होने वाली परीक्षाओं का एक और कार्यक्रम घोषित किया है। 18 अप्रैल से आयोजित परीक्षाओं के दूसरे चरण में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों और राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों (भले ही वे परीक्षाओं के पहले दो चरणों में शामिल हुए हों) को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें तीसरे चरण में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। पहले की तोड़फोड़ की कोशिशों के सिलसिले में, ऐसी खबरें आईं चाकूबाजी, राहगीरों पर भीड़ के हमले और मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस पर हमले जैसी घटनाएं हुईं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 8 मई, 2002 को रिपोर्ट किया: “गुजरात सरकार के अनुरोध को मानते हुए, केंद्र ने सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में राज्य प्रशासन की सहायता के लिए लगभग 200 कमांडो सहित लगभग 2,000 सीआरपीएफ

कर्मियों को भेजने का फैसला किया है।” सीआरपीएफ की आठ कंपनियों को भी देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरात भेजा गया। इसके बावजूद, कुछ चुनिंदा इलाकों में छिटपुट घटनाएं जारी रहीं। द हिंदू ने 9 मई, 2002 को रिपोर्ट किया कि आज रात अहमदाबाद और गुजरात के कुछ अन्य हिस्सों में हुई हिंसा में नौ लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। अशांत क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने शहर से बमों और अन्य हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया और एक पूजा स्थल में छिपे 56 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन्हें गोली चलानी पड़ी।
मणिनगर में भी दोनों समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई।
पुलिस ने बताया कि एक-दूसरे पर बम और अन्य देसी मिसाइलें फेंकने के अलावा "निजी गोलीबारी की बौछार" भी हुई। गोलीबारी की परवाह किए बिना, पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। 258 मोदी, मुसलमान और मीडिया

कई घरों से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। उन्होंने दावा किया कि अगर हथियार और गोला-बारूद बरामद न होते तो मणिनगर में मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी।
द हिंदू ने 10 मई को फिर से खबर दी कि आठ लोग मारे गए थे।
अहमदाबाद में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया और 35 लोग घायल हो गए। गुरुवार देर रात दमकलकर्मियों के तीन कर्मियों की पिटाई और एक एम्बुलेंस को हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाए जाने के बाद दमकल कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल कर दी, जिसके चलते शहर में बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुईं। गायकवाड़ हवेली स्थित पुलिस आवास कॉलोनी पर भी भीड़ ने हमला किया, जिसने एक पुलिस मोटरसाइकिल को आग लगा दी और एक राइफल छीन ली। हालांकि, अपने

घर से घसीटकर निकाले गए एक पुलिस कांस्टेबल ने भागने में कामयाबी हासिल की। जमालपुर और गायकवाड़ हवेली में पुलिस फायरिंग में चार लोग मारे गए, जबकि एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
12 मई 2002 को, द हिंदू ने हिंसा की अंतिम घटनाओं में से एक की रिपोर्ट की:
अहमदाबाद में पुलिस की गोलीबारी, बम विस्फोट और पत्थरबाजी में कम से कम दो लोग मारे गए और 30 घायल हो गए। हालांकि, कानून-व्यवस्था की बागडोर नई पुलिस टीम के संभालने के बाद शहर में हिंसा की तीव्रता में उल्लेखनीय कमी आई है। अहमदाबाद को छोड़कर, दंगाग्रस्त गुजरात के अन्य हिस्सों में स्थिति शांतिपूर्ण थी, जिससे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को अपने घरों में लौटने का प्रोत्साहन मिला।
अशांत क्षेत्रों में सेना और त्वरित कार्रवाई बल द्वारा गश्त। सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस ने कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। दोनों समुदायों के कुख्यात असामाजिक तत्वों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। अहमदाबाद के नए पुलिस आयुक्त के.आर. कौशिक, जो गए थे
शुक्रवार को कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, श्री कौशिक ने अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े राहत शिविर, शाह आलम रोजा शिविर का दौरा करके वहां के निवासियों की समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली। शिविर के आयोजक मोहसिन कादरी ने बताया कि श्री कौशिक द्वारा हिंसक घटनाओं के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के बारे में की गई पूछताछ का निवासियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
सकारात्मक पक्ष की बात करें तो, आपसी सौहार्द के कई उदाहरण देखने को मिले।

गांवों में। मध्य गुजरात के आनंद जिले के कनिज गांव के हिंदू मेहमादाबाद राहत शिविर गए और अपने मुस्लिम साथियों को वापस ले आए… एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू सरपंच ने प्रभावित मुसलमानों को शुरुआती घरेलू सामान उपलब्ध कराने के लिए धन भी जुटाया। इससे कुछ अन्य गांवों के लोगों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिली…
किसने इस काम को जारी रखा? 259

इंडिया टुडे2 में उदय माहुरकर ने चौथे चरण में हिंसा की प्रकृति और उस तबाही के पीछे की कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण दिया है: ...दस सप्ताह से घेराबंदी में जी रहे मुसलमानों की नई आक्रामकता के कारण हिंदू भी पीड़ित होने लगे हैं। मुसलमानों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद कुछ मंत्रियों ने मोदी से पुलिस द्वारा इन शस्त्रागारों को नष्ट करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सवाल किया।
इस नाजुक तनाव को और बढ़ाने वाली बात यह है कि बढ़ते हुए सबूतों से पता चलता है कि
हिंसा एक सुनियोजित तरीके से की जा रही है और आग को बुझने से रोकने का एक मकसद है। मार्च के दूसरे सप्ताह तक हिंसा पर काबू पा लिया गया था, लेकिन राज्य स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं के बीच अहमदाबाद, भरूच और मोडासा में हिंदुओं पर छिटपुट हमलों ने आग को फिर से भड़का दिया। लेकिन राम नवमी के दिन अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या के बाद हिंसा और भड़क उठी। हिंसा का यह अचानक प्रकोप स्थानीय मुस्लिम नेताओं द्वारा समुदाय के छात्रों से पुनर्निर्धारित राज्य स्कूल बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करने के आह्वान के बाद हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाने वालों में

सुरक्षा बलों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का वर्णन करें, जबकि राजनीतिक उपद्रवियों ने शांति की बहाली के प्रयासों को विफल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
केपीएस गिल का फैसला
मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में भी गिल ने बताया कि पहले दिन से ही उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दंगों को दबाने के लिए पूरी तरह से गंभीर थे। लेकिन उनके विरोधियों ने प्रशासन में उनके अनुभवहीन होने का फायदा उठाया। गिल के साथ पहली व्यक्तिगत मुलाकात में मोदी ने उनसे कहा, “एक सच्चे हिंदू और एक राजनेता के रूप में मेरा पहला सिद्धांत है, सर्वे जनः सुखिनो भवन्तु (विश्व के सभी लोग सुखी और शांतिप्रिय हों)। यदि आप इस हिंसा को जल्द से जल्द समाप्त करने में मेरी मदद कर सकें, तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा…” गिल कहते हैं कि दंगों को समाप्त करने के लिए मोदी की ईमानदारी ने उन्हें भावुक कर दिया। वे चिंतित प्रतीत हो रहे थे क्योंकि उनकी पुलिस इस चुनौती का सामना करने में विफल रही थी। मोदी ने इस हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में उनका पूरा समर्थन किया।3
स्थिति का सही आकलन करने के लिए गिल ने दौरा शुरू किया।
उन सभी स्थानों का दौरा किया, जहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और हिंसा के पीड़ितों के साथ-साथ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उन्होंने पाया कि पुलिसकर्मियों का एक बड़ा हिस्सा, साथ ही प्रशासन भी, सांप्रदायिक वायरस से संक्रमित था और गोधरा की भयावह घटना के खिलाफ व्यापक आक्रोश था। चूंकि मोदी इस पद पर नए थे, इसलिए पुलिस बल उनके नियंत्रण में नहीं था। वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे कि "मोदी विरोधी और भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके अनुभवहीनता का फायदा उठा रहे थे।"4

गिल ने सबसे पहले उन अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, जो
अपने-अपने क्षेत्रों में दंगे रोकने में नाकाम रहने पर उन्हें संवेदनशील पदों से हटा दिया गया। निष्पक्षता की उम्मीद रखने वाले अधिकारियों को संवेदनशील पद दिए गए। इससे पुलिस बल सतर्क हो गया कि शीर्ष प्रशासन इस खूनी खेल को खत्म करने के लिए गंभीर है और कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे कहते हैं, “मोदी ने मुझे अक्षम अधिकारियों के तबादले करने और उनकी जगह उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करने की पूरी छूट दी। मैंने मोदी के किसी भी हस्तक्षेप के बिना बल को अनुशासित करने के लिए कई उपाय लागू किए।”
श्री गिल जहाँ भी जाते थे, लोगों को अपना निजी मोबाइल नंबर दे देते थे।
और उन्होंने उनसे कहा कि जरूरत पड़ने पर सीधे उनसे संपर्क करें। जब भी श्री गिल को किसी जरूरतमंद का फोन आता, वे यह सुनिश्चित करते कि उनकी शिकायत का समाधान हो जाए।
3 चंदन, के.पी.एस. गिल: द पैरामाउंट कॉप, पृ. 226. 4 वही, पृ. 227. किसने इस काम को जारी रखा? 261

शिकायत का तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना जो शिकायत का समाधान कर सके।5 के.पी.एस. गिल की मुस्लिम समुदाय में विश्वसनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपना काम पूरा करने के काफी समय बाद भी उन्हें मुसलमानों के लिए पुनर्निर्मित बस्तियों का उद्घाटन करने और मुस्लिम परिवारों में शादियों में शामिल होने के लिए कई निमंत्रण मिले।
अब्दुल्ला इब्राहिम सैयद पुलिस अकादमी के निदेशक थे जब

गुजरात में दंगे हुए। हालांकि, नरेंद्र मोदी ने उन्हें के.पी.एस. गिल के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में चुना था। 2013 की गर्मियों में मेरे साथ एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि गिल ने संवेदनशील पदों पर बेहतर अधिकारियों को लाकर और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को महत्वपूर्ण पदों से स्थानांतरित करके पुलिस में जवाबदेही और व्यावसायिकता की भावना लाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई, ताकि पुलिस के कामकाज में अनुशासन और सुव्यवस्थितता लाई जा सके।
के.पी.एस. गिल एक कुशल पेशेवर थे। जब वे किसी जिले के निरीक्षण के लिए जाते थे, तो स्थानीय अधिकारी पसीने से तरबतर हो जाते थे। मैं उनसे मज़ाक में कहता था, "सर, हमें अपने साथ रुमाल लेकर चलना चाहिए।" गुजरात में अपनी तैनाती के दौरान वे सीआरपीएफ शिविर में रहे। मुझे यह बात दिलचस्प लगी कि कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेता उनसे शिविर में मिलने जाया करते थे। मैंने हरेन पांड्या को भी गिल साहब से मिलते देखा था। वे हमेशा केशूभाई के खास आदमी थे। इन सभी लोगों का एक ही मकसद था - गिल को मोदी के खिलाफ भड़काना ताकि वे प्रधानमंत्री को नुकसानदेह रिपोर्ट दें। लेकिन मोदी ने गिल साहब के काम में कभी दखल नहीं दिया। इसलिए गिल साहब ने मोदी और उनके विरोधियों के आचरण में अंतर खुद देखा था। वैसे भी, उन्होंने स्थानीय लोगों और हर स्तर के पुलिसकर्मियों से व्यापक रूप से बातचीत की थी और इसलिए उनका अपना स्वतंत्र आकलन था।
नरेंद्र मोदी दंगों की राजनीति में शामिल होने वाले अंतिम व्यक्ति हैं।
मेरे गृह जिले से। वह वड़नगर से हैं और मैं पड़ोसी सीतापुर तालुका से। उनके गांव में हमारे कई रिश्तेदार हैं। वे मुझे बताते हैं कि मोदी शुरू से ही मुसलमानों के प्रति हमेशा मददगार रहे हैं - चाहे शिक्षा हो या धार्मिक मुद्दे। दंगे उनके दुश्मनों द्वारा उन्हें

बदनाम करने के लिए रचे गए थे। अन्य कारकों के अलावा, उनका ओबीसी जाति से होना उनके खिलाफ गया। गुजरात में यह एक स्थापित परंपरा थी कि केवल पटेल ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चूंकि उन्हें केशूभाई पटेल के स्थान पर भेजा गया था, इसलिए केशूभाई के करीबी लोग उन्हें गिराने के लिए दृढ़ थे। आरोपियों की सूची में पटेलों की अत्यधिक संख्या से पता चलता है कि इस सब के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन थे। 5 वही, पृ. 233-34.
262 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उन दंगों में, कांग्रेस और भाजपा दोनों में पटेल समर्थक दल मोदी को सत्ता से हटाना चाहते थे। गरीब बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को 500 रुपये और शराब की एक बोतल देकर उत्पात मचाने के लिए उकसाया गया। लेकिन मुझे ऐसे कई उदाहरण भी पता हैं जहां हिंदू बहुल इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को उनके हिंदू पड़ोसियों ने सुरक्षा प्रदान की।
कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी हाथ मिलाया और अपने समुदाय को उकसाया। शिक्षा की कमी के कारण मुसलमानों के कुछ वर्ग आसानी से भड़क उठते हैं। बस किसी को यह अफवाह फैलानी होती है कि फलां दरगाह या मस्जिद जला दी गई है और वे बिना यह पुष्टि किए कि जो उन्हें बताया गया है वह वास्तव में हुआ है या नहीं, जाकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। मुसलमानों को अत्यधिक असहिष्णु और सांप्रदायिक मानसिकता वाला बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
गोधरा कांड के समय मोदी सत्ता में आए हुए चार महीने से भी कम समय हुआ था।
यह घटना घटी। उस समय तक न तो वह पुलिस अधिकारियों को जानता था और न ही उसे पुलिस प्रशासन की कोई जानकारी थी। पिछली सरकारों के प्रति वफादार कुछ अधिकारी उस समय महत्वपूर्ण पदों पर थे। वे मोदी के

दुश्मनों के इशारे पर उन्हें सत्ता से हटाने के लिए काम कर रहे थे। केशूभाई के शासनकाल में तोगड़िया की विश्व हिंदू परिषद का दबदबा था और कांग्रेस सरकारों में भी उसका काफी प्रभाव था। अब कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मोदी गुजरात के हर अधिकारी को, सरपंच स्तर तक, नाम से जानते हैं। गुजरात में उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी है जो उन्हें सही जानकारी देता रहता है।
दुःस्वप्न का अंत और दंगा-मुक्त गुजरात की शुरुआत: तीन महीनों के भीतर, के.पी.एस. गिल कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के अपने मिशन में सफल हो गए थे। तब से मोदी ने इस मामले में पुलिस पर कड़ी लगाम कस रखी है। पुलिस और राजनीतिक तंत्र दोनों के भीतर विघटनकारी ताकतों के लगातार प्रयासों के बावजूद, मोदी जून 2002 से दंगा- मुक्त गुजरात सुनिश्चित करने के अपने मिशन में सफल रहे हैं। 24 सितंबर, 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर पाकिस्तान प्रायोजित हमले के बाद भी राज्य में शांति बनी रही, जिसमें 33 लोग मारे गए और 70 घायल हुए। इसी तरह, 2008 में जब अहमदाबाद और सूरत को जिहादियों द्वारा सिलसिलेवार बम विस्फोटों का निशाना बनाया गया, जिसमें 56 लोग मारे गए और 200 घायल हुए, तब भी मोदी ने किसी भी प्रकार की जवाबी हिंसा की अनुमति नहीं दी।
सोनिया कांग्रेस मोदी के साथ इसलिए संघर्ष कर रही है क्योंकि उन्होंने कभी उनकी बात नहीं मानी।
एल.के. आडवाणी के राम मंदिर अभियान के विपरीत, जिसके कारण बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, कांग्रेस पार्टी को ऐसे विभाजनकारी नेताओं से बहुत फायदा होता है। यही कारण है कि कांग्रेस ने आडवाणी को मोदी के बजाय भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए पुरजोर पैरवी की। मोदी ने कभी हमला नहीं किया। किसने इस काम को जारी रखा? 263

वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।
मोदी को “मौत का सौदागर”, सामूहिक हत्यारा, हिटलर, सांप, बिच्छू, यमदूत और इससे भी बदतर नामों से पुकारा जाने लगा और ये आरोप दिन-ब-दिन और तेज़ होते गए। इन्हें समर्थित गैर-सरकारी संगठनों, चापलूस पत्रकारों और संरक्षण प्राप्त शिक्षाविदों ने और भी हवा दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भाजपा के कई सदस्य भी उन पर लगे आरोपों को सच मानने लगे और यहां तक कि उन्हें बर्खास्त करने की मांग करने लगे। भाजपा के कई सहयोगी दलों ने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया, जिससे दिल्ली में वाजपेयी के नेतृत्व वाली लोकप्रिय एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने में मदद मिली। मोदी विरोधी उन्माद ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कोई उनकी बात न सुने; कोई भी तथ्यों पर गौर करने को तैयार नहीं था। मोदी ने न केवल अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, बल्कि एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में उभरे, जो गुजरात के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने में सक्षम थे, यह गहन अध्ययन का विषय है।

आतंकवादियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 241

मोदी का दृढ़ संकल्प था कि वे अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं और अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोहों को खत्म कर देंगे, जिनके कांग्रेस और कई "धर्मनिरपेक्ष" पार्टियों से गहरे संबंध थे। ऐसे में, उन्हें सत्ता में बने रहने देना या उनकी ताकत बढ़ाना कांग्रेस और इन सभी पार्टियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। कांग्रेस ने सबसे पहले इस खतरे को पहचाना और इसलिए शुरुआत से ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जल्दी ही अन्य सभी समझौतावादी पार्टियों को भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया। जैसा कि हम आगे के अध्यायों में देखेंगे, यह मोदी नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी थी जिसने मोदी के समावेशी विकास एजेंडे को पटरी से उतारने के लिए सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति खेली।
अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने और केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और गुजरात में मोदी को निशाना बनाने के लिए किसी मुद्दे की सख्त जरूरत थी। गोधरा हत्याकांड और उसके बाद हुए दंगे इसी हताशा का नतीजा थे।

अध्याय 15

जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है
राहत शिविरों के संबंध में काम करने वालों और शोर मचाने वालों के विचार

शुरुआती दो-तीन दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया अव्यवस्थित थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक कुशल प्रणाली और आपूर्ति की एक अद्यतन श्रृंखला स्थापित कर ली। इस सरकार का कार्य करने का एक विशिष्ट तरीका है। यदि आज कोई नियम बनाया जाता है, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उसे तुरंत एक उचित, सुस्थापित प्रणाली के माध्यम से लागू कर दिया जाता है। इसी प्रकार, गुजरात सरकार ने एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाई, जो शिविरों के चलने तक, यानी लगभग छह महीने तक, अच्छी तरह से काम करती रही। इनामुल इराकी, जिन्होंने 2002 के दंगों के बाद सबसे बड़े राहत शिविरों में से एक का संचालन किया था।
ये शिविर कुछ गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन स्थल बन गए थे। मीडियाकर्मियों, विशेषकर विदेशी मीडिया को बुलाकर प्रशिक्षित पीड़ितों से बात करवाना एक दैनिक रस्म बन गई थी, जो विदेश से अधिक धन प्राप्त करने के लिए अपनी कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने लगे थे। यहां तक कि सरकार से बातचीत करते समय भी, शिविर के कुछ आयोजकों ने कैदियों की संख्या के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए थे।
के. श्रीनिवास, पूर्व कलेक्टर, अहमदाबाद
राहत शिविर एक बड़ा घोटाला बन गए थे। लोग इनका इस्तेमाल भारत और विदेश से भारी मात्रा में धन जुटाने के लिए करने लगे थे। यह भ्रष्टाचारियों के लिए एक और राजनीतिक मंच बन गया था। उनसे हिसाब

मांगने वाला कोई नहीं था। इसलिए, शिविरों को चलाना कुछ लोगों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय बन गया था। - ए.आई. सैयद, अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, गुजरात

वर्षों से, हमने दूरस्थ गैर सरकारी संगठनों के ऐसे दावे सुने हैं कि गुजरात सरकार ने मुस्लिम दंगा पीड़ितों के साथ पूरी तरह से संवेदनहीनता बरती और राहत शिविरों को समय से पहले बंद करने के लिए मजबूर किया। अब समय आ गया है कि लोग ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक कार्यकर्ताओं का पक्ष सुनें—चाहे वे सरकार के भीतर हों या बाहर।
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 265

सरकार और मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कुछ बेहतरीन राहत शिविरों की स्थापना और प्रबंधन किया।
अपने चरम काल में, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा लगभग 121 राहत शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश 30 जून, 2002 तक बंद हो गए थे, सिवाय अहमदाबाद जिले के 10 शिविरों के। ये 10 शिविर भी 31 दिसंबर, 2002 को या उससे पहले बंद हो गए थे। इसके बावजूद, आज भी मोदी विरोधी गैर सरकारी संगठनों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि हजारों गुजराती मुसलमान अभी भी राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में हैं।
मोदी सरकार द्वारा राहत कार्यों के संचालन की जाँच करने के लिए, मैंने एक अत्यंत सम्मानित सामुदायिक नेता, इनामुल इराकी से बात की, जो सबसे बड़े राहत शिविरों में से एक का संचालन करते थे। वे लोहे के कबाड़ बीनने वाले से एक सफल उद्यमी बने। उनकी गरीबी से अमीरी तक की कहानी का एक हिस्सा अध्याय 17 में है। इराकी उन बढ़ते हुए मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जो गुजरात में भाजपा से

जुड़ रहे हैं। चूंकि वे हमारे मीडिया द्वारा बनाई गई मुसलमानों की रूढ़िवादी छवि से मेल नहीं खाते, इसलिए हम उनकी जैसी समझदार आवाज़ें कभी नहीं सुनते और इसलिए मीडिया उन जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देता। दंगों के पीड़ितों के लिए राहत के प्रति सरकार के रवैये के बारे में उन्होंने जो कहा, वह इस प्रकार है:
पहले तो सरकार इतनी स्तब्ध थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है।
चारों ओर पूर्ण अराजकता फैली हुई थी। लेकिन, सरकार के संभलने के बाद, उन्होंने
उन्होंने हर संभव मदद की। मैंने एक सामुदायिक सेवा संगठन के माध्यम से शिविर स्थापित किया।
अहमदाबाद में स्थित इस शिविर को दरियाखान घुम्मत शिविर कहा जाता था। यह सर्वश्रेष्ठ शिविरों में से एक था।
हमने राहत शिविरों का प्रबंधन किया। कई बार हमारे पास 10,000 तक लोग होते थे। औसतन, हम
लगभग 5,000 कैदी थे। हमने छह महीने तक शिविर चलाया। पहले कुछ महीनों के लिए
कुछ दिनों तक हमें सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा। लेकिन जल्द ही हमें मदद मिलने लगी।
सरकार से। मैं इस्पात उद्योग से जुड़ा एक व्यवसायी हूँ।
और इसलिए, वे इस तरह की सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं।
पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मेरे अनुभव के कारण, मुझे फोन आने लगे।
कई लोगों ने अपने मोहल्लों या घरों पर हमलों की सूचना दी है।
चूंकि मैं
मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैंने सोचा कि मैं उसमें 100-200 लोगों को आश्रय दे सकता हूँ।

घर। इसलिए, मैंने प्रशासन को यह प्रस्ताव दिया। इसके तुरंत बाद, मुझे एक कॉल आया।
सहायक पुलिस आयुक्त श्री झा ने कहा, “बहुत परेशानी है।”
चमनपुरा में। हमने जाफरी साहब के घर बचाव कार्य के लिए दो वाहन भेजे हैं।
लोग। क्या आप उन सभी को संभाल पाएंगे?” मैंने उन सभी की देखभाल करने के लिए सहमति दे दी।
यह 28 फरवरी को दोपहर लगभग 2 बजे की बात है। जैसे ही मैंने इसकी घोषणा की, लोग
लोग लगातार आने लगे। रात 8 बजे तक 2000 लोग आ चुके थे। किसी तरह हमने सब संभाल लिया।
उन सभी के लिए भोजन।
266 मोदी, मुसलमान और मीडिया

भाजपा के लोग चाहते थे कि मैं अपने शिविर को पार्टी द्वारा संचालित शिविर घोषित करूँ, लेकिन मैंने
मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि उस तनावपूर्ण वातावरण में कोई अप्रिय घटना घट जाए।
भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति। यदि किसी को जहर के कारण चोट लगी हो।
अगर माहौल ऐसा होता, तो मुझे ही दोषी ठहराया जाता।
लेकिन, चूंकि जितने लोगों को ठहराया जा सकता था, उससे कहीं अधिक लोग आ चुके थे,
मैंने अपने घर के पास पड़ोस के स्कूल को उनके आश्रय के लिए खुलवा दिया है।
डॉ. अग्रवाल चंद्रमणि नाम का एक मित्र। वह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अध्यक्ष हैं।

क्षेत्र। मैंने फोन किया और उन्हें स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, "यह मेरा कर्तव्य है कि मैं..."
आओ और मानवता को बचाओ। मैं अवश्य आऊंगा।” वह 10 लोगों की एक टीम के साथ आया।
मेरे शिविर में डॉक्टर आए और उन्होंने सुबह 3 बजे तक सभी घायलों का इलाज किया।
मैंने उनसे पूछा कि वीएचपी की छवि कट्टर मुस्लिम विरोधी होने के बावजूद उन्होंने स्थानीय वीएचपी अध्यक्ष को क्यों फोन किया। इराकी का जवाब था:
हम दोस्त हैं; हमारे बीच प्यार है। हमारे बीच गहरे भावनात्मक बंधन हैं (दिली-)
(लगाव)। ये बातें हमारे संबंधित धार्मिक मूल्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
पहचान। मैं आपको कम से कम 10,000 मुसलमानों से मिलवा सकता हूँ, जिनमें से प्रत्येक
मैं आपको बता दूं कि अगर वे आज जीवित हैं, तो यह किसी हिंदू भाई की मदद के कारण है।
और उन्हें बचा लिया। दंगों के दौरान इंसानियत (मानवता) नहीं मरी। आखिरकार,
मैंने अपने शिविर में शरण लेने वाले सभी लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं की।
वे 10,000 लोग मेरे शिविर में केवल इसलिए उतरे क्योंकि कुछ हिंदू भाई
उन्हें बचाया। अगर हत्या करने वाले हिंदू थे, तो उन्हें बचाने वाले भी हिंदू थे।
वे सभी हिंदू थे। बचाए गए हर परिवार ने कहा, “हमारे हिंदू पड़ोसियों ने हमें बचाया।”

या “अमुक हिंदू हमारी मदद के लिए आए।”
These people had come from Chamanpura, Naroda Patia, Meghani Nagar,
गिरधर नगर, काली गांव और आसपास के अन्य इलाकों से। वे ज्यादातर आए थे।
उन इलाकों से जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे। एक ही दिन में 8,000 से मेरे शिविर में 10,000 लोग आ चुके थे।
पहले दो दिनों तक हमने अपने पैसों से खर्च किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और इसलिए, वे जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसके अलावा, मेरे पास 10 लोगों की एक टीम है।
बारह व्यक्तियों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। हमने एक समिति का गठन किया और
शिविर का प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से किया गया। हालाँकि हमारा मूल
हमारी टीम मुस्लिम थी, लेकिन जहां भी हमें जरूरत पड़ी, हिंदू दोस्तों ने भी हमारी मदद की।
उदाहरण के लिए, हमारे इलाके में राशन की दुकानें बहुत कम थीं।
इसलिए, हमने फोन किया
कुछ हिंदू भाइयों ने ट्रक भरकर राशन सामग्री भेजी। उन्होंने जो कुछ भी था, भेज दिया।
मैं पूछा।
मेरे हिंदू भाइयों ने हर तरह से मेरा पूरा समर्थन किया। उदाहरण के लिए,
उस समय अहमदाबाद में बुनकरों का मेला चल रहा था। इसके लिए कई लोगों ने भाग लिया था।
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 267

उस समय एस.के. नंदा साहब सचिव थे और अमरजीत सिंह थे।
अहमदाबाद के कमिश्नर। उन्होंने चड्ढा के नेतृत्व में हमारे शिविर के लिए एक टीम बनाई।
साहब, वह टीम रोज़ाना कैंप का मुआयना करती थी। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती, तो वे कर देते थे।
अगर किसी मरीज को दवाइयों की जरूरत होती या ऑपरेशन की, तो गुजरात सरकार ने व्यवस्था की।
यह सब बिल्कुल मुफ्त है।
जब मैंने इराकी से पूछा कि क्या उस दौरान तीस्ता सेतलवाद, शबनम हाशमी या सरकार की आलोचना करने वाले अन्य गैर सरकारी संगठनों के नेताओं ने उन्हें किसी प्रकार की सहायता की पेशकश की थी, तो उन्होंने यह कहा:
तीस्ता, हाशमी और अन्य लोग हमारे शिविरों में आए थे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया।
एक रुपया भी मदद के रूप में। वे आते, दुख भरी कहानियाँ दर्ज करते। पीड़ितों की तस्वीरें खींची गईं और वे चले गए। उनमें से किसी ने भी मुझसे यह नहीं कहा, "हमारे पास यह है।"
हम आपको कितना पैसा दे सकते हैं, बताइए आप इसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
इस तरह के गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करने में, मुझमें सामाजिक सेवा करने की क्षमता है।
मैंने अपने दम पर गुजरात नाम से अपना खुद का सामाजिक संगठन बनाया है।
सार्वजनिक राहत समिति। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति का वेतन इसमें नहीं लगाते।
एनजीओ के खाते से, यात्रा या अन्य खर्चों का भी भुगतान नहीं होता।
मैं ये सब अपने खर्चे से करता हूँ।

अपनी जेब से। मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है और मुझे इतना सक्षम बनाया है,
मुझे संकट के समय अपने समुदाय की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। 1996-268 में मोदी, मुसलमान और मीडिया

97 में, मैंने भाजपा के लिए उनके वोट मांगे थे। इसलिए, उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य था।
दुःख की इस घड़ी में उनका साथ दें।
जिस तरह मुसलमान मेरे घर पर जमा हुए, उसी तरह हिंदू दंगा पीड़ित भी अंततः वहीं जमा हो गए।
हिंदू समुदाय द्वारा स्थापित राहत शिविरों में। लेकिन, हिंदू शिविर बहुत दूर थे।
संख्या में कम। हमारा संगठन हमारे अपने समुदाय की सेवा के लिए बना है।
हम प्रचार के लिए कुछ नहीं करते और न ही अदालतों के चक्कर लगाते हैं। हम अपना काम करते हैं।
चुपचाप काम करो। मैं हमारे एनजीओ में इकलौता व्यक्ति हूँ जो दाढ़ी नहीं रखता और न ही मास्क पहनता है।
एक टोपी। बाकी सब भी पहनते हैं। वे सब ईश्वर से डरते हैं। हम जो भी करते हैं, करते हैं।
हमारे अल्लाह के लिए।
अहमदाबाद में लगभग 25 अपेक्षाकृत छोटे शिविर थे जिनमें 100 लोग थे।
200 या 500 लोग। हमारा सबसे बड़ा था। सलीम खान और महबूब खान दूसरे बड़े शिविर का संचालन उन्होंने भी किया। उन्होंने भी पहले चरण में अपनी जेब से पैसे खर्च किए।
2-3 दिन। इसके बाद, गुजरात सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की।

राशन और अन्य आपूर्ति। राहत सामग्री की कभी कोई कमी नहीं हुई। सरकार ने हस्तक्षेप किया।
सरकार का पक्ष
के. श्रीनिवास, एक आईएएस अधिकारी, जो अपनी दक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जाने जाते थे, उस समय अहमदाबाद के कलेक्टर थे। इसलिए, वे शहर में राहत कार्यों को संभालने वालों में शामिल थे। राहत कार्य को उन्होंने किस प्रकार संभाला, इसका उनका विवरण इस प्रकार है:
आइए, दंगों के पीड़ितों की सहायता करने के अपने अनुभव से शुरुआत करें।
अहमदाबाद में राहत शिविर पुराने अमन चौक इलाके में स्थापित किया गया था।
शहर। जब स्थानीय पार्षद तौफीक खान ने मुझे फोन करके सूचित किया कि मैंने उस अचानक बने शिविर के बारे में उसे तुरंत बता दिया कि उस शिविर में सरकार की व्यवस्था है।
इसे मंजूरी मिल जाएगी और पूरा समर्थन प्राप्त होगा। हालाँकि, बहुत कम अन्य राजनेता इसे स्वीकार करते हैं।
राहत शिविर स्थापित किए गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक संगठनों ने इसका नेतृत्व किया।
राहत कार्य। उन सभी को तुरंत मंजूरी और सहायता मिली।
राहत शिविर में मेरी पहली यात्रा 2 मार्च को हुई थी, यानी तीसरे दिन।
दंगे हुए। कुछ इलाके इतने बुरी तरह प्रभावित हुए कि वहां सेना भी प्रवेश नहीं कर सकी।
पड़ोस। केवल राजस्व और अहमदाबाद नगर निगम
कर्मचारी उन तक पहुंच सकते थे।

उन शिविरों का दौरा करने पर मुझे एहसास हुआ कि बहुत से परिवार अलग हो गए थे।
उस अफरा-तफरी में। हमने उन सभी लोगों की तस्वीरें लीं जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कुछ खो दिया है।
परिवार के सदस्यों की तस्वीरें सभी शिविरों में चिपका दी गईं। लापता लोगों के मिलने के बाद
जिनकी पहचान हो गई थी, उनके परिवारों को राज्य सुरक्षा के तहत फिर से मिलाया गया। इस प्रकार
बिखरे हुए परिवार के सदस्य जल्दी ही एक हो गए। मेरे एक परिवार के दौरे के दौरान...
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 269

उस दिन शिविरों में, एक बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में मेरे पास आया और बोला: “जैसे
एक नागरिक के रूप में, मैं सरकार से राहत की उम्मीद करता हूं, न कि किसी धार्मिक संस्था से।
"किसी संगठन या गैर सरकारी संगठन से।" मैंने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें यह बात बताई।
that we need to respond to this sentiment. I said, roti honi chahiye sarkar ki,
par jo parose voh aisa ho jis par logon ko bharosa ho. (The food in relief camps
भोजन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन भोजन परोसने वाले लोगों को
वे ऐसे होने चाहिए जो विश्वास जगाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देखभाल करने वाला व्यक्ति सक्षम हो।

सहानुभूतिपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए।" मुख्यमंत्री तुरंत सहमत हो गए और बोले, "हम करेंगे।"
न केवल वस्तु के रूप में राहत प्रदान करना बल्कि प्रत्येक परिवार को कुछ जेब खर्च भी देना।
गैर-खाद्य व्यय।"
पहले 2-3 दिनों को छोड़कर जब धार्मिक और सामुदायिक संगठन उन्होंने संपूर्ण बुनियादी ढांचे, संसाधनों, भोजन और अन्य चीजों का प्रबंधन स्वयं किया।
सरकार द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। पहले दो दिनों में भी, अहमदाबाद नगर निगम ने स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सहायता प्रदान की।
बाद में, जब व्यवस्थाएं लागू की गईं, तो प्रारंभिक व्यय का अधिकांश हिस्सा
गैर सरकारी संगठनों को मुआवजा दिया गया। श्री मोदी जल्दबाजी में कोई काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं।
और अव्यवस्थित तरीके से। इसलिए, हमने राहत की एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित की। लेकिन
देखभालकर्ता एक स्थानीय संगठन था।
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए
दंगा प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त अनाज, अर्थात् गेहूं और चावल वितरित किए गए।
सांप्रदायिक भेदभाव के कारण इन परिवारों को दैनिक रोजगार से वंचित कर दिया गया था।
व्यवधानों के कारण कुल 1,77,519 टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ। मार्च से लेकर मई के मध्य तक, शिविरों का संचालन कुशलतापूर्वक किया गया। हालाँकि, इसके साथ ही

मानसून के आगमन के साथ ही नई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। जिन शिविरों में आवास उपलब्ध नहीं था, उनमें भी समस्याएं पैदा हो गईं। पक्के मकानों को पक्के मकानों में स्थानांतरित करना पड़ा। जहाँ सरकार
इमारतें उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए हमने सामुदायिक स्वामित्व वाली या निजी इमारतों को किराए पर लेने का निर्णय लिया।
इमारतों के बारे में। मैंने लगभग 46 मुस्लिम सामुदायिक संगठनों से संपर्क किया—जिनमें से कई
उनके पास सामुदायिक भवन थे। लेकिन, उनमें से बहुत कम लोग अपना घर देने को तैयार थे।
हम बाजार दर के हिसाब से किराया देने को तैयार थे, फिर भी किराए पर ली गई इमारतों के लिए भी हम तैयार थे।
मुस्लिम जमात से केवल चार बड़ी जगहें ही किराए पर ली जा सकीं।
उस समय उनमें से एक सहयोगी संगठन कुरैश जमात थी।
हमने पर्याप्त शौचालय, रसोईघर, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, आघात नियंत्रण आदि की व्यवस्था की।
देखभाल, आश्रय और यहां तक कि कपड़े भी उपलब्ध कराए गए। स्त्री रोग संबंधी देखभाल, शिशुगृह आदि।
मनोवैज्ञानिक परामर्श भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, हमने आयोजन किया।
मनोचिकित्सकों की एक टीम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। श्री मोदी इस मामले में बेहद सख्त हैं।
व्यवस्थित कार्य। इसलिए, प्रशासन के सदमे से उबरने के बाद।
गोधरा और उसके बाद हुए नरसंहार के दौरान, हमारा राहत कार्य बहुत ही व्यवस्थित था।

राशन उपलब्ध कराने के अलावा, हमने प्रत्येक कैदी को पहचान पत्र भी दिया और 270 मोदी, मुस्लिम और मीडिया कर्मियों को भी पहचान पत्र दिया।

उन्होंने सटीक रिकॉर्ड बनाए रखा। सभी का पंजीकरण मौके पर ही किया गया।
जो लोग काम पर जाना शुरू करना चाहते थे, उन्हें मुफ्त बस पास दिए गए। चिकित्सा अधिकारियों
प्रत्येक शिविर के लिए नियुक्तियां की गईं।
प्रत्येक शिविर का प्रभार एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने
मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन राहत कार्य की समीक्षा की। वास्तव में, यदि आप तुलना करें तो
राहत कार्यों में गुजरात सरकार का रिकॉर्ड, पहले या बाद की सरकारों की तुलना में कैसा है?
दंगों के मामले में, आप पाएंगे कि हमने बाकी सभी से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। दरअसल, ऑक्सफैम ने एक लेख लिखा था।
हमें प्रशंसा पत्र भेजा गया। जो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों का दौरा नहीं किया, उनके लिए
पहले 3-4 दिनों में यह समझना जरूरी है कि उन क्षेत्रों में प्रवेश करना आसान नहीं था।
उस तनावपूर्ण माहौल में। जब सोनिया जी 4 मार्च को अहमदाबाद आईं, 2002 में, हमने उसे भी बताया था कि उसके लिए उन संवेदनशील क्षेत्रों में जाना बहुत असुरक्षित है।
हम उसे दरियाखम गुम्मत ले गए, लेकिन शाह आलम रोजा या अमन नहीं ले गए।

चौक कैंप। लेकिन, मुख्यमंत्री ने 3 मार्च से राहत शिविरों का दौरा करना शुरू कर दिया था।
मुस्लिम अधिकारी को समग्र प्रभार सौंपा गया: मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों का समग्र प्रभार मुस्लिम आईएएस अधिकारी एस.एम.एफ. बुखारी को सौंपा। दंगों के समय वे सेवानिवृत्त ही हुए थे। लेकिन, मुख्यमंत्री मोदी ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभारी बना दिया। कलेक्टर और नगर आयुक्त ने प्रत्येक राहत शिविर की बारीकी से निगरानी की। स्वास्थ्य आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आदि जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित रूप से शिविरों का दौरा कर रहे थे। अन्य जिलों में कलेक्टर और अन्य जिला अधिकारियों ने शिविरों की निगरानी की। जिलों में विशिष्ट राहत शिविरों और अन्य पुनर्वास उपायों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया था।
शिविरों की निगरानी के लिए सर्वदलीय समिति: हालांकि, मीडिया और संसद में गुजरात सरकार पर हमले बढ़ने के साथ ही, राहत कार्यों की निगरानी और दंगा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए गुजरात के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया। इस 13 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री, मोदी के विरोधी सहित कई गैर-सरकारी संगठन, विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता तथा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। राहत राशि का निर्धारण समिति द्वारा किया गया।
राज्यपाल की देखरेख में राहत कार्य: गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार था कि किसी दंगे के बाद किसी राज्य सरकार ने राहत कार्य किया।

जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 271

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल को राहत एवं पुनर्वास कार्यों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि, हमले लगातार जारी रहे और राहत शिविरों से जुड़ी तरह-तरह की भयावह कहानियों से भरे कई दुष्प्रचार पत्र दुनिया भर में प्रसारित किए गए।
शिविरों में पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप: विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने अदालतों और मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि शिविरों में भी सरकार द्वारा दंगा पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया। हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने ऐसी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वास्तव में शिविरों के प्रबंधन में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उस आदेश का एक महत्वपूर्ण अंश यहाँ दिया गया है:
यह कहना जरूरी है कि चूंकि राज्य ने पहले ही श्री एस.एम.एफ. बुखारी को नियुक्त कर दिया है,
एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को राहत और अन्य कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।
विभिन्न शिविरों में पुनर्वास सुविधा…, न्यायालय की राय है कि राज्य ने भी इस समस्या को सुलझाने के प्रयास में कुछ हद तक सावधानी बरती है।
जिसका मुद्दा याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका में उठाया है, और उक्त हावभाव पर
राज्य की भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है।
[गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश - विशेष सीए संख्या: 3773 वर्ष 2002, (3 मई 2002)]
उच्च न्यायालय राहत कार्यों की निगरानी करता रहा, लेकिन गैर सरकारी संगठनों को चैन नहीं आया और उन्होंने शिविरों में पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अपनी शिकायतें उच्च न्यायालय में ले जाने की सलाह दी, जो वैसे भी राहत कार्यों की निगरानी कर रहा था। राहत एवं पुनर्वास मामलों को फिर से खोलने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित करने का एमिकस क्यूरी का सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया सुझाव सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं (महाश्वेता देवी और मल्लिका साराभाई) को गुजरात उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया, जहां इन मामलों की निगरानी की जा रही है। [भारत का सर्वोच्च न्यायालय - डब्लूपीडी (आपराधिक) संख्या 530/2002 और डब्लूपीडी (आपराधिक) संख्या 221/2002, (17 अगस्त 2004)]। लेकिन अंतिम मुस्लिम के सुरक्षित अपने घर लौटने के काफी समय बाद भी गैर सरकारी संगठनों का विरोध जारी रहा।
ज़फ़र सारेशवाला, जिनका परिवार राहत शिविरों में से एक के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था, कहते हैं:
272 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए उपायों का समर्थन करने के बावजूद
गुजरात सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास उपायों के संबंध में, कुछ

इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठन मुसलमानों को शिविरों में रखने के लिए मोदी पर लगातार हमले करते रहते हैं।
अमानवीय परिस्थितियों में। लोगों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं था।
उन राहत शिविरों में। उन्हें केवल पक्षपातपूर्ण दुष्प्रचार ही परोसा गया है। हमारी टीम
मैं हाल ही में असम के शरणार्थी शिविरों में गया था। मेरे भाई ने कहा, “मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।”
क्या भारत में कहीं भी मुसलमान असम के शरणार्थी शिविरों जैसी दयनीय स्थिति में हैं?
शिविर; वहाँ की परिस्थितियाँ कल्पना से परे दयनीय थीं। आज भी 2.5 कांग्रेस शासन के दौरान भी लाखों मुसलमान अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।
[यह बात जनवरी 2013 में कही गई थी]
मेरे भाई ने गुजरात में शरणार्थी शिविर चलाए थे, इसलिए वह तुलना करने में सक्षम थे।
गुजरात के राहत शिविरों का संचालन कहीं बेहतर था और सरकार भी बहुत सक्रिय थी।
सहयोगात्मक। इसका मतलब यह नहीं है कि शरणार्थी शिविर कभी सुखद या रहने के लिए आरामदायक जगह। लेकिन, सरकार ने व्यवस्था की है।
भारत में अधिकांश सरकारों की तुलना में भोजन, चिकित्सा देखभाल और बाकी सभी चीजें बेहतर हैं।
असम के मुसलमान सबसे दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है।
उनमें से कहीं भी नहीं। न तो तीस्ता और न ही शबनम हाशमी के पास उनके लिए ज्यादा समय है।

उनमें से लाखों लोग अभी भी उन शिविरों में हैं, लेकिन क्या आपको कोई खबर मिलती है?
उन शिविरों के बारे में मीडिया में चर्चा? वे तो पहले ही भुला दिए गए हैं, लेकिन
यही लोग गुजरात राहत में मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं।
हालांकि वे शिविर 2002 के मध्य तक, दंगों के चार महीने के भीतर ही बंद हो गए थे।
जहां तक पुनर्वास के लिए सरकार के समर्थन का सवाल है,
किसी भी दंगे में मुआवजे की राशि, हुए नुकसान की तुलना में कुछ भी नहीं होती।
जनता द्वारा। भारत में कहीं भी दंगा पीड़ितों को उनके नुकसान की भरपाई नहीं मिल पाती।
सरकार से आपको मुआवजे के तौर पर मुश्किल से कुछ लाख रुपये ही मिलते हैं। लेकिन,
गुजरात सरकार ने प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया।
जिन लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, उन्हें भी नुकसान हुआ।
धनी मुसलमानों के लिए शायद इसका कोई खास महत्व न हो, लेकिन 1 या 2 लाख रुपये उनके लिए बहुत मायने रखते हैं।
गरीबों के लिए। गुजरात सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था न तो अव्यवस्थित थी और न ही अव्यवस्थित।
न ही अनियमित।
इंडिया टुडे ने 20 मई, 2002 के अंक में यह भी प्रकाशित किया था कि, “मोहसिन कादरी, जो एक प्रमुख वकील और शाह आलम राहत शिविर के मुख्य आयोजक हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा राहत शिविर है और जिसमें 10,000 से अधिक दंगा पीड़ितों को आश्रय दिया गया है, का कहना है कि राज्य

सरकार के अधिकारियों का रवैया संतोषजनक है। ‘फिलहाल हमें कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि पुनर्वास की समस्या हल होने तक राहत शिविर बंद नहीं किए जाएंगे।’”
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 273

ज़फ़र सरेशवाला कहते हैं कि राहत शिविरों का संचालन संतोषजनक ढंग से हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण की बात आने पर, “मुसलमानों ने सरकार से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं की। जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामिया, इमारत-ए-शरिया, हैदराबाद और बिहार के कुछ मुस्लिम गैर-सरकारी संगठनों और कई अन्य गैर-मुस्लिम गैर-सरकारी संगठनों ने दंगा पीड़ितों के लिए घर बनाने के लिए मिलकर काम किया। हमें प्रवासी भारतीयों से बहुत कम मदद मिली। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपये हैं और वह आपको केवल 10 रुपये दान में देता है, तो उसका कोई खास महत्व नहीं है। इंग्लैंड या अमेरिका के लोगों की आर्थिक स्थिति की तुलना में, हमें उनसे बहुत कम मदद मिली। लेकिन, सामुदायिक संगठनों और भारतीय गैर-सरकारी संगठनों - हिंदू और मुस्लिम दोनों - ने मिलकर कुल 15,000 घरों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया। मुझे लगता है कि यह देश में सभी के लिए एक सबक होना चाहिए।”
इनामुल इराकी का संगठन उन संगठनों में से एक था जिसने इस काम का कुछ हिस्सा किया। वह कहते हैं:
हमने दंगा पीड़ितों के लिए लगभग 1,000 घर बनवाए। हर घर में एक
एक कमरा, एक रसोईघर और एक बाथरूम। शहर में स्थित इस अपार्टमेंट के लिए हमें 1.5 लाख रुपये खर्च करने पड़े।
ग्रामीण घरों के लिए 25,000 रुपये से 30,000 रुपये तक और ग्रामीण घरों के लिए 25,000 रुपये से 30,000 रुपये तक। गुजरात
घरों के पुनर्निर्माण के मामले में सरकार कुछ हद तक कमजोर थी।

दंगों के पीड़ितों में से। हमने उन मुसलमानों की पहचान की जो हिंदू बहुल समुदाय में एक छोटी अल्पसंख्यक आबादी थे।
उन्होंने विभिन्न मोहल्लों को अलग-अलग करके उनके लिए बड़े क्षेत्रों में एक समेकित आवास क्षेत्र बनाया।
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया है ताकि भविष्य में वे आसान लक्ष्य न बन सकें। कुल मिलाकर, लगभग 10,000-
गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 15,000 मुस्लिम घरों का पुनर्निर्माण करना पड़ा।
गुजरात सरकार ने भले ही दंगा पीड़ितों के लिए घर नहीं बनाए हों, लेकिन प्रत्येक परिवार को अपने क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी गई।
क्या सरकार ने लोगों को शिविरों से जबरन निकाला? मैंने मोदी से पूछा कि शिविरों को जल्दबाजी में बंद करने के आरोप के बारे में उनका क्या कहना है। मोदी ने जवाब दिया:
पहली बात तो यह है कि राहत शिविरों में केवल मुसलमान ही नहीं थे। वहां कई अन्य लोग भी थे।
हिंदुओं के लिए भी राहत शिविर थे। वे बहुत पहले ही बंद हो गए थे। कई राहत शिविरों का संचालन
स्कूलों में शिविर चलाए जा रहे थे, जिन्हें जून महीने में फिर से खोलना पड़ा था।
क्या समय पर स्कूलों को दोबारा खोलना गलत था?
उदाहरण के लिए, जब सूरत बाढ़ की चपेट में आ गया, तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि हम
झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी लोगों को स्कूल और अन्य सार्वजनिक भवनों में स्थानांतरित करें। लेकिन, 274 मोदी, मुसलमान और मीडिया

बाढ़ का पानी उतरने के बाद, हमने उनसे घर लौटने के लिए कहा ताकि स्कूली बच्चे
शिक्षण कार्य में एक दिन की भी हानि नहीं हुई। इसी प्रकार, 2002 में भी ऐसा ही हुआ।
अगले सत्र के लिए समय पर स्कूल भवनों को खाली कराना महत्वपूर्ण है।
दूसरा, हमें सामान्य स्थिति बहाल करनी थी, जो राहत शिविरों के बंद होने पर संभव नहीं है।
अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।
इनामुल इराकी ने भी इस बात की पुष्टि की कि शिविरों के किसी भी आयोजक पर उन्हें समय से पहले बंद करने का कोई दबाव नहीं था। 2013 की गर्मियों में जमीयत-ए-इस्लामी की एक बैठक में, जहाँ मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, मेजबान संगठन के एक प्रमुख सदस्य ने मंच से कहा कि गुजरात में मुस्लिम दंगा पीड़ित अभी भी राहत शिविरों में सड़ रहे हैं। 26 फरवरी, 2012 को आमिर रजा हुसैन ने राष्ट्रीय टीवी पर भड़काऊ भाषण देते हुए आरोप लगाया कि मोदी के अत्याचार के कारण हजारों दंगा पीड़ित अभी भी शिविरों में दयनीय स्थिति में हैं। मैंने इराकी से पूछा कि क्या यह सच है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अक्टूबर 2002 के बाद राज्य में किसी भी शिविर में एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। मोदी ने राहत शिविरों को अनिश्चित काल तक जारी रखने में आने वाली कुछ अन्य कठिनाइयों का वर्णन किया: ऐसे कई मामले थे जिनमें परिवार किसी विशेष गांव से आए थे।
एक या दो सदस्य शिविर में ही रुक गए, जबकि बाकी चार लौट आए।
मुझे बताइए, इसका तर्क या निहितार्थ क्या है? यह आरोप लगाया जा रहा था कि
मुसलमान डर के मारे गांवों से भागकर अहमदाबाद आ रहे हैं। असल में,

यह कुछ लोगों के लिए अहमदाबाद में प्रवास के लिए पैर जमाने की एक रणनीति बन गई।
परिवार के आधे सदस्य गांव में ही रहे जबकि बाकी आधे सदस्यों ने अन्य साधनों का इस्तेमाल किया।
अहमदाबाद में बसने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राहत शिविर में समय बिताया गया।
लेकिन उन्होंने दंगों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। परिवार के आधे सदस्य कैसे अपना जीवन यापन जारी रख सकते थे?
क्या गांव में शांति होने तक वहां रहना संभव था? उन्हें वापस लौटने के लिए प्रेरित करना पड़ा।
उनके घर। अगर उन्हें कोई समस्या होती, तो हम उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे।
हमने उस वादे को निभाया है। गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। के बाद से।
पांच-पंचियों का भाषण: जब मैंने मोदी से शिविरों को शिशु उत्पादन कारखाने बनाने वाले उनके कुख्यात बयान के बारे में पूछा, तो उन्होंने यह कहा:
“हम पांच, हमारे पच्चीस” वाली एक पंक्ति जो अक्सर उद्धृत की जाती है
मुझे मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करना या यह साबित करना कि मैंने बचपन में राहत शिविरों का उपहास किया था
उत्पादन कारखानों का उपयोग दंगा राहत शिविरों के संदर्भ में कभी नहीं किया गया था।
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 275

वहाँ कई हिंदू शिविर भी थे और मैं वास्तव में उनके लिए व्यवस्था भी कर रहा था।

स्त्री रोग विशेषज्ञों को दोनों प्रकार के शिविरों का दौरा करना होगा क्योंकि यह उनका कर्तव्य है।
गर्भवती महिलाओं की सेवा करें।
यह वाक्यांश केवल राहत शिविरों को निशाना बनाने के लिए नहीं बोला गया था। मैं अब भी यही कहता हूँ।
हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आज अगर किसी किसान के पास पाँच
बेटों, वे जल्द ही मिलकर 25 संतानें पैदा करेंगे। आज आपके पास 5 एकड़ जमीन है।
भूमि। कल्पना कीजिए कि जब इसे पाँच भागों में विभाजित किया जाएगा तो यह किस प्रकार खंडित हो जाएगी।
बेटों! ऐसे माहौल में आप अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे या अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे?
सीमित संसाधन? मैं आज भी लोगों को ये सब समझाता हूँ।
मेरा यह भाषण नवंबर या दिसंबर 2002 में दिया गया था। अधिकांश शिविर तो उससे बहुत पहले ही बंद हो चुके थे। जो लोग इसके लिए मेरी आलोचना करते हैं,
अपने बयान में, इस बात का कभी ज़िक्र न करें कि गोधरा की घटना के कुछ ही महीनों के भीतर वहाँ एक इस्लामी विद्रोह हो गया था। अक्षरधाम पर आतंकवादी समूह का हमला हुआ और फिर भी मेरा गुजरात शांतिपूर्ण बना रहा।
इसके बाद सिलसिलेवार बम धमाके हुए। कोई इस तथ्य के बारे में बात नहीं करता कि हम
उस उकसावे के बाद भी पूर्ण शांति बनाए रखी। कुछ लोगों ने उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए एक व्यक्ति को बदनाम करने का फैसला किया है। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है।

इस आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने भी की। इसने इसे गंभीर ध्यान देने या कार्रवाई के योग्य नहीं पाया, क्योंकि परिवार नियोजन की सर्वोपरि आवश्यकता पर दिया गया भाषण किसी भी समुदाय का नाम लिए बिना दिया गया था और इसके बाद कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगा नहीं हुआ था।1
हालांकि, ज़फ़र सारेशवाला का इस पर थोड़ा अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने मार्च 2013 में मुझे बताया था कि उन्होंने कुछ साल पहले मोदी से इस बेतुकी टिप्पणी के बारे में सवाल किया था। मोदी ने कथित तौर पर कहा था कि चुनाव प्रचार की गहमागहमी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। ज़फ़र का कहना है कि चूंकि मोदी के अन्य सभी कार्यों से मुसलमानों के प्रति वास्तविक चिंता झलकती है, इसलिए इस बेतुकी टिप्पणी को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़फ़र ने इस बात की गहरी समझ दी कि असल में क्या चल रहा था:
इन बातों को दबा दिया जाता है, लेकिन यह टिप्पणी पृष्ठभूमि में की गई थी।
शरणार्थी शिविरों में कुछ अप्रिय घटनाएं हुईं। कई घटनाएं घटीं। बलात्कार, यौन उत्पीड़न और विवाहेतर संबंधों की घटनाओं के परिणामस्वरूप
शिविरों के भीतर गर्भधारण। यह सब समुदाय के भीतर हुआ।
इसीलिए हममें से कई लोग चाहते थे कि ये शिविर जल्द से जल्द बंद हो जाएं और विस्थापित परिवारों को राहत मिले।

1. विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट, दिनांक 12.09.2011 के आदेश के अनुपालन में।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की श्रीमती जकिया नसीम अहसान जाफरी की दिनांक 08.06.2006 की शिकायत में, पृष्ठ 201-02।
276 मोदी, मुसलमान और मीडिया

अपने घरों को लौटें। जब परिवार भीड़भाड़ वाली जगह में एक साथ इकट्ठा होते हैं,
इन चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए दूरदर्शी सामुदायिक नेताओं की आवश्यकता है।
वे चाहते थे कि ये शिविर अनिश्चित काल तक जारी न रहें क्योंकि वहाँ
महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के कई उदाहरण हैं। इसके अलावा, हम नहीं चाहते थे
हमारा समुदाय निर्भरता की संस्कृति में फंसने से बच गया। हम उत्सुक थे।
उन्हें घर वापस जाते हुए देखना और दान पर जीने के बजाय उन्हें अपना जीवन फिर से संवारते हुए देखना।
शिविर। यह किसी भी समुदाय के आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। शिविरों को अनिश्चित काल तक जारी रखने में निहित स्वार्थ: इंडिया टुडे ने 20 मई, 2002 के अपने अंक में समस्या के एक अन्य पहलू की रिपोर्ट की:
अहमदाबाद में सांप्रदायिक तनाव को बनाए रखने वाले कारकों में से कुछ इस प्रकार हैं:
शहर में लगभग 40 राहत शिविर हैं जिनमें 50,000 से अधिक मुसलमान ठहरे हुए हैं।
अन्य 50,000 लोग राज्य भर में फैले शिविरों में रहते हैं। उन पर दबाव बढ़ रहा है।
अपुष्ट रिपोर्टों के बीच सरकार इन राहत शिविरों को बंद करने जा रही है।
इनमें से कम से कम कुछ शिविर मुस्लिम उपद्रवियों के लिए पनाहगाह बन गए हैं।

इंडिया टुडे के संवाददाता उदय माहुरकर ने मेरे साथ एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में इस शरारती तत्व का वर्णन किया:
मैं निम्नलिखित घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। 3 या 4 मार्च को, मैं शाह आलम दरगाह में प्रवेश किया, जिसे शरणार्थी शिविर में परिवर्तित कर दिया गया था।
मेरे साथ फोटोग्राफर बलदीप सिंह थे। दरगाह के एक तरफ एक
एक बड़ा कमरा था जहाँ बेलिम नाम की एक महिला प्रेस को जानकारी दे रही थी और उच्च स्तरीय भाषण दे रही थी।
जो कुछ हुआ था, उसका बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया था। वह बुरी तरह रो रही थी।
पत्रकारों के सामने। जैसे ही मीडियाकर्मी हटे, वह तुरंत उन्होंने चीखना बंद कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सब एक नाटक था। दूसरी ओर
विभाजन के उस पार, कर्नाटक का एक भेंगा आदमी था। एक महिला थी।
टेप रिकॉर्डर लेकर उसके साथ बैठे हुए, कर्नाटक के इस मुस्लिम को पढ़ाते हुए...
कहो, “मैं दंगों से इतना क्रोधित हूँ कि मैं आतंकवादी बनने जा रहा हूँ।” तीस्ता
उसमें एक विकृत प्रवृत्ति है। उसने गवाहों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था।
ऐसा लग रहा था मानो वह इस दंगे के भड़कने का ही इंतजार कर रही थी। के. श्रीनिवास, जो राहत कार्य का विस्तृत हिसाब रखने वालों में से एक थे, ने बताया कि कुछ तत्व शिविरों को बंद करने का विरोध क्यों कर रहे थे:
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 277

आरोप यह है कि मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए राहत शिविरों को बंद करने के लिए मजबूर किया।
वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, यह निराधार है। हमें शिविरों का एकीकरण शुरू करना पड़ा।
क्योंकि मई के मध्य तक, दो कारक सामने आए: शहर के कुछ हिस्सों में हालात शांत हो गए और कई लोग धीरे-धीरे अपने घरों को लौटने लगे। दूसरा कारण जून के पहले सप्ताह में मानसून का आगमन था। लगभग बारिश के साथ
सबसे पहले, निवासियों की सुरक्षा, आराम और स्वास्थ्य मेरी सबसे बड़ी चिंता थी।
तब तक, शिविर के बहुत से निवासी अपनी मर्जी से ही जाने लगे थे। उनके घरों में। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से दो महीने के लिए जारी करने की मंजूरी प्राप्त की।
अपने घरों में वापस लौटने का इरादा रखने वाले प्रत्येक परिवार को अग्रिम रूप से राशन दिया गया।
उन्हें बसने में मदद करने के लिए। जब शिविरों का एकीकरण शुरू हुआ, तब वहाँ
शिविर के कुछ आयोजकों की ओर से काफी प्रतिरोध हुआ, जिन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया था।
वे शिविरों को एक आय-उत्पादक उद्यम के रूप में चला रहे थे। वे इसे जारी रखने में रुचि रखते थे।
शिविरों को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकारी धन का एक हिस्सा हड़पना शुरू कर दिया था।
धन और राहत। शिविरों के अस्तित्व ने उन्हें धन जुटाने की वैधता प्रदान की।
देश के भीतर और विदेश में। इसलिए, वे शिविरों को लंबा खींचना चाहते थे।

जब तक वे कर सकते थे।
ये शिविर कुछ गैर सरकारी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन स्थल भी बन गए थे।
मीडियाकर्मियों, विशेषकर विदेशी मीडियाकर्मियों को लाना एक दैनिक अनुष्ठान बन गया है।
प्रशिक्षित पीड़ितों से बात करने पर, जिन्होंने अपने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया।
विदेश से अधिक धन जुटाने के लिए। यहां तक कि सरकार के साथ व्यवहार में भी,
शिविर के कुछ आयोजकों ने प्रतिभागियों की संख्या के संबंध में आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया था।
कैदियों की संख्या। इसलिए, मैंने यह जांचने के लिए रात में निरीक्षण करना शुरू किया कि कितने कैदी हैं।
लोग सचमुच अभी भी शिविरों में रहते थे। अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करने पर मुझ पर हमला किया गया।
उन्हें।
गुजरात वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अब्दुल्ला इब्राहिम सैयद ने एक निजी साक्षात्कार में इस पहलू का समर्थन करते हुए कहा: “राहत शिविर एक बड़ा घोटाला बन गए थे। लोग इनका इस्तेमाल भारत और विदेश से भारी मात्रा में धन जुटाने के लिए करने लगे थे। यह भ्रष्टाचारियों के लिए एक और राजनीतिक मंच बन गया था। उनसे हिसाब मांगने वाला कोई नहीं था। इसलिए, शिविरों को चलाना कुछ लोगों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय बन गया था।” के. श्रीनिवास के विवरण को आगे बढ़ाते हुए:
1 जुलाई को मुझे राज्य सचिवालय से फोन आया जिसमें बताया गया कि मुझे यात्रा करनी होगी।
दिल्ली में राहत आयुक्त समेत कुछ अन्य अधिकारियों के साथ,

क्योंकि 2 जुलाई को प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा था।
2002 में, राहत शिविरों के बारे में अपनी चिंताओं को उठाने के लिए। प्रधानमंत्री वाजपेयी
उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जिसमें श्री आई.के. मोदी, मुस्लिम और मीडिया जैसे कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे, उन्होंने भाग लिया।

Gujral, former Chief Justice Shri Ahmadi, Swami Agnivesh, Shri Muchkund
दुबे आदि के बारे में मीडिया रिपोर्टों और कुछ सतही दौरे की रिपोर्टों के आधार पर।
एक सदस्य ने हमारे काम के खिलाफ कई आलोचनात्मक बातें कही थीं।
उस समय एक अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी होने के नाते, मुझे वास्तविक स्थिति समझानी पड़ी।
20 मिनट के भीतर वास्तविकता सामने आ गई। इस समय तक, 4 करोड़ रुपये मूल्य का राशन पहले ही वितरित किया जा चुका था।
राहत शिविरों से घर लौट रहे सभी लोगों को वितरित किया गया है।
सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए।
शिविरों में रह रहे लोगों के जीवन को बचाने के लिए हमने कई प्रयास किए थे।
उपायों में से एक की जांच की गई। मुझसे पूछा गया, "लोग कैसे..." क्या वे शिविरों से काम पर जाएंगे? मैंने उन्हें बताया कि हम उन्हें मुफ्त बस सेवा दे रहे हैं।
शिविरों से स्वतंत्र रूप से आने-जाने की सुविधा के लिए तीन महीने की अवधि के लिए पास जारी किए जाते हैं।

कार्यस्थलों पर। इस पर सैयदा हामिद ने एक अजीब आपत्ति जताते हुए कहा,
“Kya hai yeh? Kya bus mein jayenge yeh log?”(What is this? Do you expect
क्या कैदियों को काम पर जाने के लिए बस से यात्रा करनी होगी? इस बिंदु पर, माननीय प्रधान मंत्री
मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा, "अगर बस नहीं तो परिवहन का दूसरा साधन क्या है?"
आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं?
इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि जब मुझे फोन आया तो मुझे कल रात दिल्ली में होने वाली इस बैठक की सूचना मिली, तो मैंने तुरंत अपना संदेश भेज दिया।
लोगों को शिविरों की तस्वीरें लेने के लिए भेजा गया था। मैंने वे नवीनतम तस्वीरें अपने साथ रखी थीं।
शिविरों में मौजूद लोगों की संख्या सुबह 2:30 बजे तक, यानी बैठक से कुछ ही घंटे पहले की थी।
प्रधानमंत्री के साथ। मैंने उनसे तस्वीरें साझा करने की अनुमति मांगी।
वहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ। तस्वीरें देखने और मेरी व्याख्या सुनने के बाद,
प्रधानमंत्री ने दूसरों से कहा, यह अधिकारी सच बोल रहा है और सही जानकारी दे रहा है।
सही तस्वीर। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में, यह मेरे लिए बेहद संतोषजनक क्षण था।
जिस सहानुभूति के साथ राहत कार्य किया गया, जिन साझेदारियों के माध्यम से यह कार्य किया गया

स्थापित किए गए थे, प्रशंसा के पात्र थे। इसके बजाय, सरकार को केवल यही मिला।
आलोचना हुई। हमने बहुत उच्च स्तर की पारदर्शिता के साथ काम किया। अप्रैल में
2 फरवरी, 2002 को हमने भारत के माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को उनकी पहली यात्रा पर भी ले गए थे।
राज्य के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, जैसे कि नरोदा पाटिया, का राजकीय दौरा।
उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ लोगों से मुलाकात की। यह एक चर्चित कार्यक्रम था।
हमने डेढ़ दिन तक विस्तृत चर्चा की और गहन समीक्षा की।
हमारे मुख्यमंत्री का अंदाज़ अलग है; वे किसी को बलि का बकरा नहीं बनाते।
अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में किसी अन्य नौकरी में स्थानांतरित कर दिया जाए।
वह समस्या को स्वीकार करता है और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यह उसकी जिम्मेदारी है।
जिम्मेदारी से बचने का उनका तरीका। वह कभी दूसरों पर दोष नहीं डालते। यही उनकी खासियत है।
कुछ लोगों के लिए वह समस्या का पर्याय क्यों बन जाता है, क्योंकि वे ऐसा नहीं करते।
समाधान का श्रेय उन्हें ही जाता है!
जब त्रासदियों में रोमांच भर दिया जाता है 279

राहत एवं पुनर्वास उपायों पर एक नज़र: राहत कार्य की गंभीरता इस तथ्य से स्पष्ट है कि शुरुआत से ही, राहत सामग्री के वितरण में

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी राहत उपायों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया और कम्प्यूटरीकृत किया गया।

 नकद मुआवजा : मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

दंगों के दौरान हुई क्षति की भरपाई के लिए 1 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए। खाद्यान्न की आपूर्ति : राज्य सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया।

राहत शिविरों के सभी कैदियों को सहायता के साथ -साथ छाया और आश्रय प्रदान करना।

इसका संचालन स्थानीय गैर सरकारी संगठनों , स्वयंसेवी संस्थाओं और सामुदायिक नेताओं द्वारा किया जाता है।

प्रति व्यक्ति प्रति दिन दी जाने वाली सहायता में गेहूं का आटा

(400 ग्राम) और चावल शामिल थे।

(100 ग्राम); खाद्य तेल (50 ग्राम); दालें (50 ग्राम); और दूध पाउडर (50 ग्राम)।

राशन के अलावा , राहत शिविर के आयोजकों को नकद सहायता भी दी गई।

कैदियों के आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 7 रुपये का भुगतान करना होगा।

प्रति व्यक्ति 15 रुपये प्रति दिन की नकद सहायता के अतिरिक्त , एक परिवार में पांच व्यक्ति।

 जल आपूर्ति : पर्याप्त और क्लोरीनयुक्त जल की आपूर्ति की गई कैदियों को। अहमदाबाद शहर में चौबीस टैंकर , 81 सिंटेक्स टैंक।

अन्य जिलों में जल आपूर्ति के लिए 12 टैंकर तैनात किए गए।
स्वच्छता : मौजूदा शौचालय सुविधाओं के अलावा , नए शौचालय बनाए गए।

और 10 शौचालयों वाली मोबाइल वैन चौबीसों घंटे उपलब्ध कराई गईं।
शिविरों में चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार : आवश्यकतानुसार सरकारी रिकॉर्ड , 205 चिकित्सा अधिकारी और 273 पैरामेडिकल स्टाफ

राहत शिविरों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। लगभग 450,596 मामले
उनका इलाज किया गया। दूसरे शब्दों में , शिविर के प्रत्येक रोगी की
जांच की गई।
औसतन 3-4 गुना। परिणामस्वरूप , विभिन्न बीमारियों का प्रसार बढ़
जाता है।
जो बहुत अधिक हो सकता था , उसे नियंत्रण में रखा गया। चिकित्सा
सहायता
इसमें आघात , मानसिक स्वास्थ्य , पोषण, प्रसव और प्रसवपूर्व देखभाल
शामिल हैं।
निवारक , तृतीयक देखभाल और नेत्र जांच। किसी भी शिविर ने रिपोर्ट
नहीं की।
किसी भी महामारी का प्रसार।

- 30 स्त्री रोग विशेषज्ञों , बाल रोग विशेषज्ञों और मानसिक
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीमें
उन्हें बारी-बारी से अलग-अलग शिविरों में भेजा गया। उनकी आंखों की
जांच की गई।
जिसमें 11,624 मरीजों की जांच की गई , 5,050 जोड़ी चश्मे शामिल थे।
वितरित किए गए , और 213 आईओएल (इंट्राओकुलर लेंस) ऑपरेशन किए गए।
शिविरों में प्रदर्शन किया गया। अन्य मानसिक स्वास्थ्य पहलों में
समूह शामिल थे।
परामर्श सत्र , व्यक्तिगत मनोचिकित्सा हस्तक्षेप , और
विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए आघात परामर्श।

280 मोदी , मुसलमान और मीडिया

- गर्भवती माताओं के लिए विशेष प्रसवपूर्व देखभाल : 4,333 गर्भवती
माताएँ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] 127 [illegible] [illegible] [illegible]

2013 में उत्तर प्रदेश में।

□ अनाथ बच्चों और विधवाओं का पुनर्वास : राज्य सरकार ने अनाथों , विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराया।

और शिविरों में रहने वाले बेसहारा लोग। 435 दंगा प्रभावित विधवाएँ थीं।

राज्य सरकार की पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली कुछ महिलाएं।

महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना के तहत भी आवास उपलब्ध कराया गया था।

आजीविका की बहाली ; 5,858 महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई।

तीन स्वाधार गृह स्थापित किए गए , जिन्होंने 196 लोगों को आश्रय प्रदान किया।

बेघर महिलाएं और 148 बच्चे।

□ राहत शिविरों में छात्रों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं : राहत शिविरों में

शिविरों में एसएससी /एचएससी के सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं।

इसके अतिरिक्त , पेन , पेंसिल , नोटबुक , पाठ्यपुस्तकें , संदर्भ सामग्री आदि से युक्त किट उपलब्ध हैं।

किताबें और मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की गई। □ आवास सहायता : सरकार द्वारा 18,037 लोगों को 50,000 रुपये का भुगतान किया गया।

शहरी दंगों से प्रभावित परिवारों को उनके घरों की मरम्मत की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 12.28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इसी तरह , ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही स्थिति रही।

11,204 परिवारों को 17.82 रुपये की आवास सहायता प्रदान की गई।

[illegible] [illegible] [illegible] [

□) □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□,
□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□, 1,510 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ 3.96 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
□□ □□□□□ □□ □□□ 50,000 □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□, □□□□□□ □□ 20 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□
□□□□□ □□□□□ 50,000 □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ 2,083 □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□
□□□□ □□□□□□□□□ □□□ 5.09 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□, □□□□ 545 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ 1.16 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□
□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□-□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□, □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□-□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□, □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□
282 □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□

आतंक की राजनीति का अंत
हालांकि, मोदी सरकार की असली परीक्षा इस बात में निहित है कि 2002 के बाद दंगों के पीड़ितों सहित मुसलमानों की स्थिति कैसी रही है। गुजरात के मुसलमानों का कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की ओर रुख करना इस बात का प्रमाण है कि वे मोदी सरकार में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एस.एम. मुश्रीफ ने 27 मई, 2013 को मिली गजट को दिए एक साक्षात्कार में यही बात कही थी:
…और हैरानी की बात यह है (मेरे मुस्लिम भाई मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे)
इसलिए, आज मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह गुजरात है, केवल इसलिए कि वहां के मुख्यमंत्री
मंत्री नरेंद्र मोदी ने खुफिया ब्यूरो में प्रवेश पर "प्रतिबंध" लगा दिया है।
गुजरात में (आईबी)... आईबी पर 'प्रतिबंध' लगाने के बाद, गुजरात में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गए हैं।
रुक गया। नकलीपन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए यही करना आवश्यक है। मुठभेड़ें, झूठे आतंकी हमले, उनकी मनगढ़ंत जांच और गिरफ्तारियां निर्दोष मुस्लिम लड़के...
मैंने अभी तक आईबी (बौद्धिक संपदा) के पहलू की जांच नहीं की है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों को सुरक्षा का एहसास दिलाने का मतलब पुलिस को बेहतर अनुशासन में लाना भी था। हालांकि, मुशरिफ को गुजरात से अपने समुदाय को खुशखबरी देने के लिए माफी मांगनी पड़ी, इससे हमें कांग्रेस और उसके "धर्मनिरपेक्ष" सहयोगियों द्वारा मुसलमानों के बीच फैलाई जा रही बौद्धिक दहशत का अंदाजा लगता है। कांग्रेस की रणनीति में मुसलमानों को हमेशा पीड़ित के रूप में

पेश होना पड़ता है, अन्यथा उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, जैसा कि सलमान खान के साथ हुआ, जिन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में कुछ हल्के-फुल्के शब्द बोलने की हिम्मत की, या इससे भी बदतर, मौलाना वस्तानवी की तरह उन्हें चुप करा दिया जाता है।

अध्याय 16

खोपड़ी और पिल्लों के बारे में
मीडिया खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है, आग में घी डालता है।

किसी भी मानवतावादी के लिए, ऐसी घटना [गोदरा ट्रेन का जलना] असहनीय दुःख का कारण बनेगी। लेकिन साथ ही, अशांति फैलाना, अनुशासनहीनता करना और आक्रोश व्यक्त करना समाधान नहीं है…क्या आप गुजरात को बचाने में सरकार की मदद नहीं करेंगे? क्या आप शांति और सद्भाव बनाए रखने में हमारी मदद नहीं करेंगे? गुजरात सरकार आपसे शांति और संयम के लिए मदद की अपील करती है…मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने आक्रोश के बीच, गुजरात के 18,000 गाँवों में से केवल कुछ ही गाँवों में अशांति फैली है…मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे को तैसा समाधान नहीं है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता… सरकार आपसे विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को दंडित करने में मदद चाहती है। सरकार आपसे शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद चाहती है ताकि कानून अपना काम कर सके…
जय गरवी गुजरात के नारे को साकार करने के लिए हमें शांति का मार्ग अपनाना होगा…सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव मेरी प्रतिबद्धता है। मेरी सरकार उतनी ही मुसलमानों की है जितनी किसी और की… सभ्य समाज में प्रतिशोधात्मक न्याय का कोई स्थान नहीं है।
नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी, 2002 को अपनी शांति अपील में यह बात कही थी।

एक दिन जब गुजरात दंगों के बारे में निष्पक्ष विवरण लिखे जाने लगेंगे, तो गुजरात के खिलाफ गलत सूचना अभियान चलाने और पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए आग में घी डालने में हमारे

राष्ट्रीय मीडिया, विशेष रूप से इसके कुछ प्रमुख सितारों के आचरण को स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।
2002 के गुजरात दंगे पहले ऐसे दंगे थे जिन्हें टेलीविजन चैनलों ने 24x7 कवर किया था। हमारे कुछ जाने-माने न्यूज़ एंकर, जो उस समय उभरते पत्रकार थे, ने गोधरा दंगों और उसके बाद की हिंसा पर रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारिता की सभी सीमाओं को पार कर दिया। उन्होंने 284 मोदी, मुसलमान और मीडिया

जब आग भड़क रही थी तब भी वे बेकाबू थे—न सिर्फ इसलिए कि उन्हें राष्ट्र के सामने मुस्लिम समुदाय के वीर रक्षक के रूप में खुद को पेश करने और भावुक होने का मौका मिला, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए कि कांग्रेस ने कांग्रेस से संबद्ध गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर खबरों में हेरफेर और तोड़-मरोड़ करने के लिए वफादारों की एक पूरी टीम खड़ी कर रखी थी। चूंकि एनडीटीवी जैसे प्रमुख समाचार चैनलों पर कांग्रेस सरकार का भारी वित्तीय कर्ज था1, इसलिए वे कांग्रेस पार्टी के लिए स्वेच्छा से लाउडस्पीकर बन गए। इतने प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के कांग्रेस पार्टी का निजी चैनल बनने2 के बाद, दूसरों को अपने नियंत्रण में लाना अपेक्षाकृत आसान हो गया। इस प्रक्रिया में, उन्होंने हिंसा को बढ़ाने और हिंदू-मुसलमानों के बीच अलगाव को और गहरा करने में मदद की। अब तक हमने मीडिया में केवल मोदी-विरोधी लोगों का पक्ष सुना है। अब समय आ गया है कि हम मोदी का पक्ष भी सुनें कि कैसे हमारे कुछ टीवी सितारों ने आग में घी डालने का काम किया।
मेरा प्रयास था कि हम जल्द से जल्द शांति बहाल करें। यदि आप आंकड़ों को देखिए, आपको पता चलेगा कि 72 घंटों में हम संक्रमण को रोकने में कामयाब रहे।

दंगों को रोकने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन ये टीवी चैनल लगातार ऐसा करते रहे।
एक ही घटना को बार-बार प्रसारित करना। उस समय, राजदीप
सरदेसाई और बरखा दत्त दोनों ने एनडीटीवी के लिए काम किया। कुछ उदाहरण देने के लिए
उन घटनाओं के दौरान बरखा ने किस प्रकार सबसे गैरजिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार किया, इसके उदाहरण।
तनावपूर्ण दिन: सूरत में सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई थी, सिवाय एक घटना के।
कुछ छोटी-मोटी झड़पें हुईं। हालांकि, बाजार बंद थे। बरखा बीच में खड़ी थी।
बंद दुकानों से चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, “यह सूरत का हीरा बाजार है, लेकिन यहाँ एक भी हीरा नहीं है।”
यहां सिर्फ एक पुलिसवाला है!
मैंने बरखा को फोन किया और पूछा, क्या आप इस पते की जानकारी दे रही हैं?
दंगा करने वाली भीड़ के लिए 'असुरक्षित' बाज़ार? क्या आप उन्हें आने का निमंत्रण दे रहे हैं?
वहाँ हंगामा खड़ा करने के लिए यह कहना कि यहाँ पुलिस नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर मनमानी कर सकते हैं?
अंजर में हुई दूसरी घटना में, उसने हनुमान जी के आगमन की खबर को खूब उछाला।
मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और ढांचा नष्ट कर दिया गया था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है?
आप क्या कर रहे हैं? आप कच्छ में हैं, जो एक सीमावर्ती जिला है। आप वहां दिखा रहे हैं।

एक मंदिर पर हमला और उसे नष्ट करना। क्या आप इसके परिणामों को समझते हैं?
एनडीटीवी से जुड़े शुरुआती घोटालों में से एक के बारे में जानने के लिए, एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस की इस खबर को पढ़ें: "सीबीआई मामला"
प्रणॉय रॉय के विरुद्ध, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 20 जनवरी 1998, वेब.
http://www.financialexpress.com/old/ie/daily/19980120/02051164.h tml.
2 एनडीटीवी के नवीनतम वित्तीय घोटाले के लिए देखें: मधु पूर्णिमा किश्वर, "एनडीटीवी और
“चिदंबरम पर 5500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का आरोप,” मानुषी, 16 जनवरी 2014, वेब. http://www.manushi.in/articles.php? articleId=1751#.Uv8NdUKSxJM.
खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 285

ऐसी खबरें प्रसारित करना? हम अभी भूकंप से उबर भी नहीं पाए हैं। क्या आपने दंगों की सही जांच की है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमारे लिए आग की घटनाओं का प्रसारण कर रहे हैं? पूरे देश में प्रसारण करने में आपको कुछ ही मिनट लगते हैं।
कि फलां स्थान असुरक्षित है या किसी मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन
मुझे पुलिस को एक अशांत स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में घंटों लग जाते हैं।
क्योंकि ये घटनाएं सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर घटित हो रही हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि जब मैंने स्थानीय पुलिस से इस मामले की जांच करवाई, तो हमें पता चला कि

पता चला कि यह एक पेड़ के नीचे बनी एक छोटी, महत्वहीन संरचना थी जो बदमाशों ने इसे थोड़ा-बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन एनडीटीवी ने इसे एक हमले के रूप में पेश किया।
हनुमान मंदिर का दृश्य दिखाया गया और कैमरे पर हनुमान जी की एक धड़ से अलग की गई मूर्ति भी प्रदर्शित की गई।
जी, जब आग भयंकर रूप से भड़क रही थी, तब ये पत्रकार आग में घी डाल रहे थे।
ज्वालाएँ।
राजदीप सरदेसाई उन प्रमुख पत्रकारों में से थे जो इस घटना को कवर कर रहे थे।
अशांति के कारण, मैंने उसे फोन करके कहा कि मुझे उस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना होगा।
यदि आप अपनी भड़काऊ कवरेज जारी रखते हैं तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा।
उस दिन, मैंने टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वे वास्तव में भड़काऊ बातें कर रहे थे।
परेशानी। मैंने उसे बताया कि मीडिया के लिए एक सुस्थापित नियम है।
सांप्रदायिक दंगों के दौरान समुदायों का नाम नहीं लेना चाहिए, न ही किसी क्षतिग्रस्त स्थान की पहचान करनी चाहिए।
किसी स्थान को मंदिर या मस्जिद के रूप में क्यों घोषित किया जा रहा है? आप उस नियम और स्थापित व्यवस्था का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं?
समुदायों का नाम न लेने या पूजा स्थलों की पहचान न बताने से संबंधित प्रोटोकॉल?
आप स्थापित मानदंडों के विरुद्ध जा रहे हैं।

यह बात पहले ही अच्छी तरह से दर्ज हो चुकी है कि कैसे एक गर्भवती मुस्लिम महिला के बारे में झूठी खबरें फैलाई गईं, जिसका कथित तौर पर पेट चीरकर, तलवार से उसका गर्भ निकाल कर आग लगा दी गई थी। बीबीसी ने 6 मार्च, 2002 की अपनी रिपोर्ट में इस अफवाह को विश्वसनीयता प्रदान की। हर्ष मंदर ने 20 मार्च, 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक मार्मिक लेख में इसी कहानी को दोहराया। तहलका वेबसाइट ने यह लिखकर इस अफवाह को और भी पुख्ता किया कि सायरा बानू नाम की एक महिला ने दावा किया था कि उस भयानक घटना की शिकार उसकी भाभी थी।
लेकिन सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अरुंधति रॉय द्वारा उसी कहानी की खून-खराबे वाली रिपोर्टिंग में दिखाई गई शरारत और अहंकार का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने 6 मई, 2002 को आउटलुक पत्रिका में लिखा:
कल रात बड़ौदा से एक दोस्त का फोन आया। वह रो रही थी। उसे बात करने में पंद्रह मिनट लगे।
मुझे बताओ कि मामला क्या था। यह बहुत जटिल नहीं था। बस सईदा,
उसकी एक सहेली को भीड़ ने पकड़ लिया था। बस इतना ही कि उसका पेट 286 मोदी, मुसलमान और मीडिया

उसे चीरकर जलते हुए चिथड़ों से भर दिया गया था। बस इतना ही कि उसकी मृत्यु के बाद, किसी ने
उसने अपने माथे पर ‘ओम’ उकेरा था।3
इस घटना से परेशान होकर भाजपा के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज ने व्यक्तिगत रूप से गुजरात पुलिस से संपर्क किया और उनसे इस कहानी की पुष्टि करने को कहा। स्पष्ट रूप से, गुजरात पुलिस के पास ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, उन्होंने रॉय से पीड़ित परिवार तक पहुंचने और दोषियों को गिरफ्तार करने में मदद करने

3. [illegible], “[illegible]: [illegible],” [illegible], [illegible], [illegible]
6, 2002, [illegible]. http://www.outlookindia.com/article.aspx?215477.
4. [illegible], “[illegible] [illegible] [illegible]” [illegible], 27 [illegible], 2002, [illegible]
http://www.outlookindia.com/feedbacks.aspx?typ=100&val=215477&source=published&commentid=27001#27001.
[illegible] [illegible] [illegible] 287

…[illegible], [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] (6,000 [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

निर्दोष रामसेवकों को ऐसे राक्षस के रूप में देखा जाता है जो जिंदा जलाए जाने के योग्य थे।5
गलत सूचना तंत्र
यहां एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे गोधरा कांड के बाद मोदी द्वारा बोले गए हर शब्द को कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा स्थापित सुनियोजित दुष्प्रचार तंत्र द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। मोदी पर शुरुआती आरोपों में से एक यह था कि गोधरा कांड के बाद जब दंगे भड़के, तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराया और इस प्रकार अपनी संलिप्तता साबित की। यह शरारत ज़ी टीवी पर प्रसारित एक अधूरे बयान से शुरू हुई, जो ज़ी संवाददाता सुधीर चौधरी द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार पर आधारित था। मोदी के सटीक शब्द थे: “क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला चल रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो और न प्रतिक्रिया।” (क्रिया- प्रतिक्रिया की श्रृंखला चल रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो और न प्रतिक्रिया हो)। लेकिन ज़ी टीवी ने जानबूझकर दूसरा वाक्य छोड़ दिया और बयान के पहले भाग को तोड़-मरोड़ कर पेश किया ताकि यह साबित किया जा सके कि मोदी ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को गोधरा में कारसेवकों की हत्याओं के खिलाफ हिंदुओं की जायज प्रतिक्रिया बताया था।
मोदी विरोधी गुटों ने राष्ट्रीय मीडिया की सक्रिय मदद से इस बयान को वायरल किया, जबकि मोदी ने बार-बार विरोध जताया था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देश के प्रमुख समाचार पत्र 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इस बयान के साथ जो किया, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक नया निम्न स्तर था। 3 मार्च, 2002 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने अपने पहले पन्ने पर प्रश्न-उत्तर के रूप में मोदी से जुड़े कुछ मनगढ़ंत बयान प्रकाशित किए, जिनमें वही

"क्रिया-प्रतिक्रिया" वाला बयान भी शामिल था, ताकि यह साबित किया जा सके कि मोदी ने मुस्लिम विरोधी दंगों को जायज ठहराया था।
जब टाइम्स ऑफ इंडिया में मोदी के बयान को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए यह खबर छपी, तो राज्य सरकार ने तुरंत अखबार के संपादक को विरोध पत्र भेजा।
5. बलबीर के. पुंज, “गुजरात की आग में तथ्यों से छेड़छाड़,” आउटलुक इंडिया, 27 मई, 2002।
वेब. http://www.outlookindia.com/printarticle.aspx?215755.
288 मोदी, मुसलमान और मीडिया

अखबार ने दावा किया कि टीओआई ने मुख्यमंत्री का साक्षात्कार नहीं लिया था और न ही उन्होंने अपने नाम से व्यक्त हिंसा को उचित ठहराया था। जब टीओआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सुधार प्रकाशित नहीं किया, तो एक भाजपा नेता टीओआई के संपादक से मिलने गए, जिन्होंने उनसे तथ्यों को लिखित में भेजने को कहा, जो तुरंत भेज दिया गया। लेकिन टीओआई ने फिर भी मोदी द्वारा जारी स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किया। 3 मार्च, 2002 को मूल खबर प्रकाशित होने के पूरे 20 दिन बाद, 23 मार्च को मोदी का स्पष्टीकरण प्रकाशित होने से पहले संपादक के संज्ञान में दो बार लिखित रूप में यह बात लाई गई थी। इससे भी बुरी बात यह है कि जहां मोदी के नाम से उद्धृत भड़काऊ गलत बयान को टीओआई के राष्ट्रीय और अहमदाबाद दोनों संस्करणों के पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा गया, वहीं मोदी कार्यालय का स्पष्टीकरण अखबार के भीतरी पन्नों के एक कोने में प्रकाशित किया गया।
इस बीच, मोदी के नाम से कही गई इस बात को भयावह तथ्यों और खतरनाक व्याख्याओं से भर दिया गया। यह बयान पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैला कि इसने अपना एक अलग ही रूप ले लिया। यहां तक कि 2010-11

में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त और निगरानी की गई विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद भी इसका प्रसार और अंतहीन पुनरावृत्ति नहीं रुकी है।
जब एसआईटी ने तीस्ता सेतलवाद और उनके साथियों द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि के लिए ज़ी टीवी संवाददाता सुधीर चौधरी से पूछताछ की, तो चौधरी ने कहा कि उन्होंने 1 मार्च, 2002 को गांधीनगर के बाहरी इलाके में स्थित सर्किट हाउस में नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और मुख्यमंत्री से एक संक्षिप्त साक्षात्कार का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री सहमत हो गए और उन्होंने लगभग 10 मिनट का साक्षात्कार दिया।6
जब चौधरी ने मुख्यमंत्री से गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड के बारे में सवाल किया, जिसमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 50 से अधिक लोग मारे गए थे, तो मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में उन रिपोर्टों का हवाला दिया कि जाफरी ने पहले हिंसक भीड़ पर गोली चलाई थी, जिससे भीड़ और भड़क उठी। इसके बाद, भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर धावा बोल दिया और उसे आग लगा दी।7
चौधरी के अनुसार, नरेंद्र मोदी ने जाफरी की गोलीबारी को "कार्रवाई" और उसके बाद हुए नरसंहार को "प्रतिक्रिया" बताया। हालांकि, वे इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि ज़ी टीवी पर प्रसारित आखिरी दृश्य में ऐसा क्यों कहा गया।

6. विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट, दिनांक 12.09.2011 के आदेश के अनुपालन में
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती जकिया नसीम अहसान जाफरी की दिनांक 08.06.2006 की शिकायत में, पृष्ठ 188।
7 वही, पृष्ठ 187.
खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 289

line—“Hum chahte hai ki na kriya ho aur na pratikriya”—was deliberately omitted.

[illegible]

व्यक्ति ने उनसे साक्षात्कार के लिए मुलाकात नहीं की थी। टीओआई के पत्रकार ने अपनी अटकलों के आधार पर यह कहानी गढ़ी थी और इसे अखबार के पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा गया था। उनका यह दृढ़ मत था कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्दोषों के खिलाफ भीड़ द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या प्रतिक्रिया को कभी भी उचित नहीं ठहराया और न ही कभी ठहराएंगे।9 इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एसआईटी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची: “नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता क्योंकि यद्यपि दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया और अन्य जगहों पर उपद्रवी भीड़ द्वारा मुसलमानों पर भयानक हिंसक हमले हुए थे, फिर भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए कथित बयान संदर्भ से हटकर उद्धृत किए गए प्रतीत होते हैं।”10
8 वही, पृ. 188-89.
9 वही, पृ. 187-88.
10 वही, पृष्ठ 99.
290 मोदी, मुसलमान और मीडिया

एसआईटी रिपोर्ट का पूरा पाठ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह दोषमुक्ति न केवल उस दिन की विवादास्पद टिप्पणियों की सत्यता की जांच पर आधारित है, बल्कि गोधरा घटना के बाद के दिनों में मोदी द्वारा दिए गए विभिन्न अन्य बयानों और भाषणों की जांच पर भी आधारित है। इसके अलावा, एसआईटी ने राज्य सरकार की वास्तविक कार्रवाइयों की भी जांच की। चूंकि मोदी के बयान को गलत तरीके से उद्धृत करने वाले समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने अपनी गलती सुधारने से इनकार कर दिया, इसलिए शरारती गलत उद्धरण ने अपना महत्व खो दिया और एसआईटी द्वारा इस मामले में मीडिया द्वारा जानबूझकर तोड़-मरोड़ किए जाने की पुष्टि के बाद भी इसे लगातार बदनामी

अभियान के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी, तीस्ता सेतलवाद के 'कम्युनलिज्म कॉम्बैट' की वेबसाइट पर यह आरोप मौजूद है कि:
गुजरात राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोदी का आचरण कुछ इस तरह था:
संवैधानिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री की तुलना में आरएसएस का एक पक्षपाती प्रचारक।
“Har kriya ki pratikriya hoti hai,” he had first said, justifying the premeditated
गोधरा के बाद जो नरसंहार हुआ। “प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत फल होता है।”
प्रतिक्रिया।" वह राज्य के पांच करोड़ लोगों को आश्वस्त करने में पूरी तरह विफल रहे कि वह एक
वे उनके जीवन और संपत्ति के संरक्षक हैं। जिम्मेदारी से जवाब देने के बजाय,
वह लगातार बेपरवाही से यह आश्वासन देता रहा कि सब कुछ सामान्य है। 11
मोदी की शांति की तत्काल अपील
यह बात स्पष्ट है कि मोदी का एसआईटी के समक्ष दिया गया बयान उनकी जान बचाने के लिए मनगढ़ंत नहीं था, यह बात उस दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए कई प्रेस बयानों और दूरदर्शन पर की गई अपीलों से साफ है। जिस तरह 27 फरवरी को गोधरा में हिंदुओं के नरसंहार के बाद मोदी के बयानों में मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयानबाजी का कोई अंश नहीं था12, उसी तरह दंगों के दौरान उनके सभी बयान लोगों के गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से थे, न कि अंतर-सामुदायिक घृणा या शत्रुता को भड़काने के लिए। उदाहरण के लिए, 28 फरवरी, 2002 को नरेंद्र मोदी ने शाम 7 बजे दूरदर्शन पर गुजराती भाषा में

निम्नलिखित व्यक्तिगत शांति अपील जारी की। इसे उसी शाम कई बार प्रसारित किया गया।13
11 “आरोप: गुजरात सरकार,” सांप्रदायिकता से मुकाबला, मार्च-अप्रैल 2002,
पृष्ठ 107.
12 अध्याय 12 देखें।
13 मैंने 28 फरवरी, 2002 को नरेंद्र मोदी की शांति अपील का शब्दशः अनुवाद किया है।
अंग्रेजी। हिंदी संस्करण अंग्रेजी उपशीर्षकों के साथ http://www.youtube.com/watch?v=BIRMR8zW0iI पर उपलब्ध है। (हालांकि समग्र विषयवस्तु में कोई अंतर नहीं है, फिर भी YouTube का अनुवाद शैलीगत रूप से मेरे अनुवाद से थोड़ा भिन्न है।)
खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 291

कल गोधरा में एक अमानवीय त्रासदी घटी। 40 से अधिक महिलाएं और बच्चों की जलकर मौत हो गई। 18 पुरुष भी जिंदा जल गए। कुल मिलाकर 58 लोग मारे गए।
वे रेलगाड़ी के डिब्बे में फंस गए और नरभक्षियों द्वारा बेरहमी से उनका नरसंहार कर दिया गया।
एक जघन्य अपराध सबसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति की आंखों में भी आंसू ला देगा।
गुजरात की धरती पर किया गया यह घिनौना और अमानवीय कृत्य असहनीय है।
किसी भी सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि
गुजरात की जनता को आश्वस्त करें कि इस तरह की कोई भी घटना कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दोषियों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए उचित दंड दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, हम एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा।
ऐसा जघन्य कृत्य करना। गुजरात सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर विनाश करते हैं।
एक सभ्य समाज में निर्दोष लोगों के जीवन का कोई स्थान नहीं है।
मैं इस बात से सहमत हूँ।
गुजरात के लोगों के दुख को और गहरा कर देने वाला। किसी भी मानवतावादी के लिए, ऐसी घटना अत्यंत गंभीर होगी।
अवर्णनीय दुःख। लेकिन साथ ही, अशांति (अशांति) उत्पन्न करना।
अनुशासनहीनता और आक्रोश व्यक्त करना (अक्रोश) समाधान नहीं है।
कानून का उल्लंघन करना और दंगे करके अपना गुस्सा निकालना उचित नहीं है।
किसी भी सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि
आपको यह बताना जरूरी है कि इस समय शांति और आत्मसंयम बनाए रखना आवश्यक है। हम
इस अपराध को करने वालों को दंडित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कोई भी नहीं बचेगा।
उन्हें उनकी उचित सजा मिलनी चाहिए। क्या आप गुजरात को बचाने में सरकार की मदद नहीं करेंगे?
क्या आप शांति और सद्भाव बनाए रखने में हमारी मदद नहीं करेंगे? सरकार
गुजरात आपसे सहायता की गुहार लगाता है, शांति और संयम की गुहार लगाता है।
(संयम/आत्म-अनुशासन)।

इस घोर आक्रोश के बीच, मेरा विनम्र निवेदन है कि
ऐसे कठिन समय में गुजरात आपसे वही अपेक्षा रखता है जिसके लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
गुजरात ने किस प्रकार शांति और सद्भाव बनाए रखा है, इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं।
सबसे कठिन समय के दौरान। मैं आपको इस अनूठी बात की याद दिलाना चाहता हूँ।
गुजरात की विशेषता—संयम दिखाना और शांति बनाए रखना। विपत्तियों के दौरान, आइए शांति और संयम बनाए रखते हुए गुजरात की सेवा करें।
आइए कानून की शक्ति को मजबूत करें। आइए ऐसा वातावरण बनाएं जो सुनिश्चित करे
इस जघन्य अपराध के दोषियों को सबसे कड़ी सजा दी जाए। मैं
मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यह गंभीर अपील आपके दिलों को छू जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।
सरकार में हर कोई आपके द्वारा अनुभव किए गए सदमे और पीड़ा को महसूस करता है।
हमें भी उतना ही दर्द महसूस हो रहा है जितना आपको।
यहां तक कि प्रधानमंत्री [अटल बिहारी वाजपेयी] भी इन बातों से बेहद परेशान हैं।
घटनाक्रम और भारत के गृह मंत्री भी इसी स्थिति में हैं। पूरा देश उन्होंने गुजरात के साथ एकजुटता व्यक्त की और हमारे दुख में शामिल हैं। लेकिन जिम्मेदारी
शांति, सद्भाव और संयम बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। मैं आपका गुस्सा समझता हूँ। 292 मोदी, मुसलमान और मीडिया

और आक्रोश; मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। फिर भी, गुजरात के स्वार्थ में,
और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम गुजरात के भविष्य को खतरे में न डालें, कि गुजरात
इससे न तो इस पर कोई धब्बा लगता है और न ही इस दौर से जुड़ा कोई कलंक लगता है।
सभी 5 करोड़ गुजरातियों को शांत रहने और आत्मसंयम बरतने की जरूरत है।
मैं इस बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी सारी चुनौतियों के बीच भी आपने मेरा साथ दिया।
गुजरात के 18,000 गांवों में से केवल एक गांव में ही अशांति फैली है।
इनमें से कुछ ही जगहों पर। अधिकतर जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल है। हालाँकि,
गुजरात के शहरों में घटी घटनाएं चिंताजनक हैं। यह मेरा
आपसे अपील है, जैसे को तैसा समाधान नहीं है। Ver ver thi shamtu nathi (घृणा
नफरत से कभी जीत नहीं मिलती। मैं आपको उपदेश देने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ
गुजरात का उज्ज्वल भविष्य। इसके लिए, मैं आपसे सरकार की मदद करने का आग्रह करता हूँ।
शांति बनाए रखने में। सरकार दोषियों को दंडित करने में आपकी सहायता चाहती है।
विधिवत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दोषी साबित करें। सरकार आपकी सहायता चाहती है।
शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना ताकि कानून अपना काम कर सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता मेरी अपील पर ध्यान देगी और
हम शांतिपूर्ण गुजरात के लिए मिलकर काम करेंगे। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।
ताकि निर्दोषों को कष्ट न सहना पड़े और न ही उनकी जान जाए। आइए, हम सब मिलकर काम करें।
शांति स्थापित करने के लिए। एक बार फिर, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ और
दर्द। हालाँकि, आइए हम सब मिलकर कानून की शक्ति को मजबूत करें ताकि
दोषियों को उनके लिए उचित सबसे कड़ी सजा दी जाए ताकि एक ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित हो सके।
मैं एक बार फिर गुजरात की जनता से शांति की अपील करता हूँ। जय जय गरवी गुजरात।
mantra jeevant karne ke liye hame shanti ka marg hi chahiye. In order to instill
'जय गरवी गुजरात' के मंत्र में जीवन का संचार करते हुए, हमें शांति के मार्ग पर चलना होगा।
[मैंने इस पर जोर दिया है]
यह समझना मुश्किल है कि कोई इस भाषण में कैसे खामी निकाल सकता है। वीडियो में मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव-भाव भी गंभीर और उदास हैं—उनसे जुड़ी शैतानी प्रतिक्रिया से बिलकुल अलग। शांति अपीलों का अनुवर्ती कार्रवाई
यह सिर्फ एक भाषण की बात नहीं है। मार्च और अप्रैल के महीनों में, मोदी ने लगातार इसी तरह की शांति की अपीलें कीं, चाहे उन्होंने किसी भी मंच से भाषण दिया हो। नीचे राज्य सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों के अंश और उनके भाषणों के प्रमुख अंश दिए गए हैं।

1 मार्च, 2002: “छपने/प्रसारण करने से पहले पुष्टि करें—झूठी खबरें न फैलाएं… स्थापित नियमों के अनुसार समुदायों के नाम न लें।”
खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 293

प्रेस के नैतिक मूल्यों और व्यवहारों का पालन करते हुए हिंसा को रोकने के लिए… मृतकों के दृश्य न दिखाएं ताकि भावनात्मक आवेश भड़कने और हिंसा होने से बचा जा सके… कानून-व्यवस्था की स्थिति में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुजरात की शांति और स्थिरता को असामाजिक तत्वों द्वारा भंग नहीं होने दिया जाएगा जो जनता के गुस्से/भावनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं… शांति बहाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति भंग करने वालों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।” (स्रोत: मुख्यमंत्री की प्रेस विज्ञप्ति) “हिंसा में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं।” (स्रोत: मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति)
2 मार्च, 2002: “गुजरात का हित शांति में निहित है, न कि सांप्रदायिक तनाव या अशांति में… राज्य सरकार जनता के बीच व्याप्त आक्रोश को शांत करने और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है… किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जनता को भड़काने वाले और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले सभी तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं…” (स्रोत: मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति)।
“मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग

करें… सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने नैतिक कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती।” (स्रोत: संदेश/गुजरात समाचार)
3 मार्च, 2002: “मार्च परीक्षाओं का महीना है, इसलिए मैं अभिभावकों, संरक्षकों और शिक्षाविदों से अपील करता हूँ कि वे शांति बहाल करने और माहौल को तनावमुक्त रखने में शीघ्र सहयोग करें ताकि सभी परीक्षाएं समय पर संपन्न हो सकें… पिछले वर्ष आए भूकंप और दंगों के बाद, अब हम राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य निराशा में डूबते हुए नहीं देखना चाहते…” (स्रोत: गुजरात समाचार) “सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने नैतिक कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती… शांति बहाल करने में समाज के सभी वर्गों की भी भूमिका है… मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें…” (स्रोत: मुख्यमंत्री की प्रेस विज्ञप्ति)
6 मार्च, 2002: “प्रतिशोध की भावना और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन के माहौल में समाज प्रगति नहीं कर सकता, चाहे उकसावा कुछ भी हो, क्योंकि यह एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है… सरकार दोषियों को अनुकरणीय दंड देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।” (स्रोत: अहमदाबाद में सामाजिक नेताओं के साथ बैठक में मुख्यमंत्री का भाषण और प्रेस विज्ञप्ति)
294 मोदी, मुसलमान और मीडिया

7 मार्च, 2002: “गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती। गुजरात में इस समय एक-दूसरे के प्रति प्रेम की आवश्यकता है, न कि अफवाहें फैलाने की; जागरूक नागरिकों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।” (स्रोत: मुख्यमंत्री की प्रेस विज्ञप्ति)

8 मार्च, 2002: “राज्य सरकार ने आपसी विश्वास, सुरक्षा और शांति का माहौल बनाने के लिए राज्य भर में शांति रैलियों की योजना बनाई है।” (सूरत के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान दिया गया बयान)
10 मार्च 2002: “यह सरकार शांति भंग करने में शामिल अपराधियों को नहीं बख्शेगी।” (स्रोत: गुजरात समाचार)
“लोगों ने मुझे राज्य को उन तत्वों से मुक्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी है जो गुजरात को सांप्रदायिक अशांति के भंवर में घसीटने का इरादा रखते हैं। मैं दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति से कानून व्यवस्था को मजबूत करूंगा।” (अहमदाबाद के मस्काटी बाजार के कपड़ा व्यापारियों के साथ एक बैठक में। संदेश में प्रकाशित)
14 मार्च, 2002: “मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अफवाहों से प्रभावित न हों और शांति के लिए काम करें।” (स्रोत: मुख्यमंत्री की प्रेस विज्ञप्ति, अहमदाबाद)
18 मार्च, 2002: जब मुख्यमंत्री से पूछा गया, “मुस्लिम समुदाय को आपका व्यक्तिगत आश्वासन क्या है?”, तो उन्होंने उत्तर दिया: “सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव ही मेरा आश्वासन है। मेरी सरकार उतनी ही उनकी है जितनी किसी और की… गोधरा की घटना दुखद थी; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि गोधरा में जो हुआ, उसके जवाब में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है। लोकतंत्र में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के हमेशा तरीके होते हैं, चाहे वे कितनी भी प्रबल क्यों न हों। कानून का शासन सर्वोपरि है… एक सभ्य समाज में प्रतिशोधात्मक न्याय (गोधरा कांड के बाद) के लिए कोई स्थान नहीं है… गोधरा से निकलने से ठीक पहले मैंने हिंसा को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था… धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को अपने समुदायों में आपसी विश्वास बहाल करने के लिए मिलकर काम करना होगा… मैंने एक भी निंदनीय कदम नहीं उठाया

है। जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा, तो वे जान जाएंगे कि मेरी सरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी को भी नहीं बख्शेगी।” (हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली)
22 मार्च, 2002: “अहमदाबाद अब शांति के मार्ग पर लौट रहा है, लेकिन कुछ बुरी ताकतें शहर की शांति भंग करने पर तुली हुई हैं। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि सांप्रदायिक तनाव दोबारा न भड़के, जिसने एक बार फिर अपना कुरूप रूप दिखाया है। शांति भंग करने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं… कानून सबके लिए समान है और कानून की खामियों का फायदा उठाकर कानून तोड़ने वालों को सजा से नहीं बचाया जा सकेगा।” (मुख्यमंत्री की प्रेस विज्ञप्ति)
खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 295

विकृत प्रवचन का निर्माण
गुजरात दंगों पर चर्चा को तोड़-मरोड़कर मोदी को बदनाम करने के तरीके में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। गोधरा कांड के बाद के दंगों पर लिखे गए अध्यायों में उद्धृत द हिंदू और द टेलीग्राफ जैसे समाचार पत्रों की शुरुआती रिपोर्टों में, जब पत्रकार प्रत्यक्षदर्शी विवरण भेज रहे थे, तब नरेंद्र मोदी या गुजरात सरकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे। यहां तक कि दूरदर्शन ने 3 मार्च, 2002 को अपने रात्रि बुलेटिन में रिपोर्ट किया: “अहमदाबाद में हिंसा रिकॉर्ड समय में समाप्त हो गई… केवल 3 दिन… पहले इसमें कई सप्ताह लग जाते थे… आज (रविवार) कर्फ्यू में ढील दी गई, लोगों ने बाजार से सामान खरीदा…”
अखबारों में पुलिस की लापरवाही के साथ-साथ पुलिस या सेना द्वारा जान बचाने के उदाहरणों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने उस जन आक्रोश को संभालने के लिए उपलब्ध पुलिस बल की घोर अपर्याप्तता के बारे में भी बताया, जिसके कारण हजारों लोग - राजनीतिक दलों की

परवाह किए बिना - गोधरा नरसंहार का बदला लेने के लिए एक साथ कई स्थानों पर सड़कों पर उतर आए थे।
लेकिन कुछ ही दिनों में, कहानी को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति नरेंद्र मोदी को इस नरसंहार का शातिर साजिशकर्ता बताकर निशाना बना रही हो। यह तर्क इतना आक्रामक और जड़ जमा चुका था कि जब 2010 में एसआईटी की रिपोर्ट मोदी को निशाना बनाने वाली रिपोर्टों से मेल नहीं खाती थी, तो एसआईटी सदस्यों पर भयंकर व्यक्तिगत हमले और मानहानि के आरोप लगाए गए। उन पर नरेंद्र मोदी द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। तीस्ता एंड कंपनी ने एसआईटी को भंग करने और उसकी जगह नई जांच गठित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया।
यह सवाल उठना लाज़मी है कि एसआईटी रिपोर्ट और एसआईटी से पहले और बाद में आए विभिन्न अदालती आदेशों, जिनमें मोदी का नाम साफ़ हुआ है, ने प्रमुख पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं और उच्च-स्तरीय शिक्षाविदों द्वारा चलाए जा रहे नफ़रत भरे अभियान के लहजे या स्वरूप को क्यों नहीं बदला है? पत्रकार अदालती मामलों के नतीजों और एसआईटी रिपोर्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते हुए मोदी से बार-बार वही सवाल क्यों पूछते रहते हैं और उन्हीं आरोपों को क्यों दोहराते रहते हैं?
खोपड़ी की टोपी विवाद
धर्मनिरपेक्षवादियों द्वारा मोदी की मुसलमानों के प्रति कथित घृणा के बार-बार दोहराए जाने वाले "सबूतों" में से एक यह है कि उन्होंने अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान एक मुस्लिम द्वारा भेंट की गई टोपी को पहनने से इनकार कर दिया था। मीडिया ने इस घटना को तोड़-मरोड़कर पेश करने में किस प्रकार अतिशयोक्ति की, इसका स्पष्टीकरण अहमदाबाद स्थित व्यवसायी जफर सारेवाला ने दिया है। 296 मोदी, मुसलमान और मीडिया

टोपी को लेकर वह विवाद बेतुका था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। मुझे नहीं पता।
मीडिया ऐसे मुद्दों को इतनी अहमियत कैसे दे सकता है और उन्हें इतनी बुरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश कर सकता है।
वैसे भी, उस तरह की टोपी यहूदियों से ज्यादा जुड़ी हुई है, न कि किसी और से।
मुसलमानों के लिए। इस्लाम के दृष्टिकोण से, टोपी का कोई महत्व नहीं है। यदि
आप किसी भी अरब देश में चले जाइए, आपको एक भी मुसलमान टोपी पहने हुए नहीं मिलेगा।
नमाज़ के दौरान। फिर भी, मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने नमाज़ के दौरान टोपी पेश की थी।
उन्होंने सद्भावना की एक सभा में बताया कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था।
me, “Modi ne aise koi utaar nahin di, bola topi mat pehnao, lao shawl de do
"ग्रीन वाली।" (ऐसा नहीं है कि मोदी ने अपने सिर से टोपी उतार दी हो। उन्होंने बस
उसने कहा: मुझे टोपी मत पहनाओ, मुझे वह हरी शॉल दे दो जो तुमने मेरे लिए रखी है।) मैंने आगे कहा
मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या टोपी लेने से इनकार करने पर मोदी ने उसे गाली दी थी। उसने कहा,
नहीं। मोदी ने बस इतना कहा, ‘मुझ पर टोपी मत डालो, मुझे शॉल दे दो।’ भरूच से कांग्रेस पार्टी की पूर्व नेता आसिफा खान, जो दिसंबर 2012 में भाजपा में शामिल हुईं, ने मुझे बताया, “यह शॉल वास्तव में अधिक इस्लामी थी क्योंकि इस पर कुरान की आयतें (कलमा) लिखी हुई थीं।”

मैंने इस तथ्य की पुष्टि कार्यक्रम की तस्वीरों में की। उनमें स्पष्ट रूप से एक मुस्लिम महिला को हरे रंग की शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, जिस पर अरबी में कुरान की आयतें छपी हुई हैं।14 Zafar says, “I did ask Modi, why did you not wear the cap?” He said, “Topi musalmano ka chinh hai ya wo hari shawl? Doosri baat, kya aapko Congress ne topyian kam pehnai har Iftaar parties mein? Iftaari jab hoti hai, har politician topi pehenta hai aur musalman khush ho jaate hain.” (Tell me, is the green shawl with Koranic verses written on it more of a symbol of Islam or the skullcap? Secondly, have the Muslims not had enough of skullcaps being donned by Congressmen during Iftaar parties? During these ceremonial occasions, all the politicians come wearing skullcaps and Muslims feel elated at just that!)
आसिफा खान का कहना है कि उन्होंने एक प्रेस बयान जारी कर घटना का ब्यौरा दिया था, “लेकिन मीडिया मोदी को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले किसी भी तथ्य पर ध्यान देने से इनकार करता है। वे बार-बार उन्हीं तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं और उन पर हमला करते हैं। यही कारण है कि मोदी ने मीडिया की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है।”
14 मैंने नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वे इस्लामी शैली में हरे रंग की शॉल स्वीकार कर रहे हैं।
verses written on it during Sadhbhavana Yatra in my article: Madhu P. Kishwar, “Of Skullcap, Miyan Musharraf and Modi’s Sadbhavana Yatra,” Manushi, April 9, 2013, http://www.manushi.in/articles.php? articleId=1698&ptype=campaigns&pgno=3#. UxBlefSSxJM. खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 297

ज़फ़र ने मोदी से पूछा था कि क्या वे सार्वजनिक रूप से सही बात कह सकते हैं। मोदी ने उनसे कहा, “आप जो चाहें कह सकते हैं। लेकिन मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा क्योंकि मीडिया मेरे हर बयान को तोड़- मरोड़ कर पेश करने पर तुला हुआ है।” ज़फ़र कहते हैं कि उन्होंने टीवी पर यह सब समझाया, लेकिन “वे मेरी बात अनसुनी कर देते हैं और बार-बार वही झूठ दोहराते रहते हैं कि मोदी ने टोपी पहनने से इनकार करके मुसलमानों का अपमान किया।” 12 जून, 2013 को रॉयटर्स 15 को दिए उनके साक्षात्कार के बाद मीडिया द्वारा जानबूझकर की गई तोड़- मरोड़ का यह एक और उदाहरण है, जिसने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। अन्य बातों के अलावा, रिपोर्टर ने मोदी से पूछा:
क्या यह निराशाजनक नहीं है कि बहुत से लोग अभी भी आपको 2002 के संदर्भ में परिभाषित करते हैं?
लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हर किसी को।
उनका अपना नजरिया है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे अपराधबोध होगा। निराशा।
यह तब काम आता है जब आप सोचते हैं, 'मैं पकड़ा गया। मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया।'
यह मेरा मामला नहीं है।
क्या आपको जो हुआ उसका पछतावा है?
मैं आपको बताता हूँ। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक अच्छा न्यायालय माना जाता है।
विश्व। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसने
यह बहुत चमकदार है और इसकी छवि स्पष्ट है। एक और बात, अगर हम कार में हैं... और
अगर कोई और उस कार को चला रहा है और हम पीछे बैठे हैं, तब भी अगर...

अगर पिल्ला गाड़ी के पहिये के नीचे आ जाए, तो क्या उसे दर्द होगा? बिल्कुल होगा।
आखिरकार, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर कहीं कुछ बुरा होता है, तो यह स्वाभाविक है।
दु: खी होना।
इस बयान को सामान्य समझ से पढ़ने पर निम्नलिखित भावना प्रकट होती है: “अगर मैं कार की पिछली सीट पर बैठा हूँ और गलती से कोई छोटा जानवर मेरी कार से घायल हो जाए तो मुझे दुख होगा। इतने सारे निर्दोषों की मौत पर मुझे दुख और पीड़ा क्यों नहीं होगी?” मोदी ने अपनी टिप्पणी पर हुए हंगामे के बाद अपने ट्वीट में इसे स्पष्ट किया: “हमारी संस्कृति में जीवन के हर रूप का सम्मान और पूजा की जाती है। लोग ही सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं।” लेकिन हर टीवी एंकर, हर राजनीतिक टिप्पणीकार ने मुसलमानों को “कुत्ते” कहने पर मोदी की जमकर आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने आडंबरपूर्वक घोषणा की, “यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। यह भारत के विचार के बिल्कुल विपरीत है।” सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने मोदी की ‘इस घटना को उचित ठहराने और तुच्छ बनाने’ के लिए कड़ी निंदा की।
15 भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के साथ साक्षात्कार, रॉयटर्स, 12 जुलाई, 2013, http://blogs.reuters. com/india/2013/07/12/interview-with-bjp-leader-narendra-modi/. 298 मोदी, मुसलमान और मीडिया

2002 के दंगों के लिए खेद व्यक्त करते हुए करात ने कहा कि वे अब भी इसके लिए खेद व्यक्त करने को तैयार नहीं हैं। एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद भी करात ने तीखे शब्दों में कहा, "यह बेहद शर्मनाक है कि वे नरसंहार को उचित ठहरा रहे हैं और इसकी

भयावहता को कमतर आंकने के लिए अनुचित उदाहरणों और उपमाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।"
टीवी और प्रिंट मीडिया में इसे इतनी उग्रता से दोहराया गया कि आज हर मुस्लिम बस्ती में, हर मुस्लिम गांव में, यहां तक कि छोटे मुस्लिम बच्चों के दिमाग में भी यह बात बिठा दी गई है कि मोदी मुसलमानों को कुत्तों से भी बदतर समझते हैं।
मीडिया मॉनिटरों की पक्षपातपूर्ण भूमिका
हमारे राष्ट्रीय मीडिया की पक्षपातपूर्ण भूमिका इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दिलीप पडगांवकर और आकार पटेल के नेतृत्व में एक टीम नियुक्त की, जो मोदी को बदनाम करने वाले अभियान के प्रमुख सदस्य रहे हैं, ताकि दंगों की मीडिया कवरेज का अध्ययन किया जा सके। इस टीम ने अपनी 254 पृष्ठों की रिपोर्ट 16 में कुछ गुजराती समाचार पत्रों, विशेष रूप से संदेश और गुजरात समाचार की, गोधरा घटना और उसके बाद राज्य में हुए दंगों की 'भड़काऊ और गैर-जिम्मेदार' कवरेज के लिए कड़ी आलोचना की। उन्होंने एनडीटीवी टीम द्वारा सामना की गई समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया। लेकिन गिल्ड की टीम ने टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी और राष्ट्रीय मीडिया के कई अन्य लोगों द्वारा आग भड़काने में निभाई गई भड़काऊ भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा।
गिल्ड द्वारा मोदी की निंदा किसी गंभीर जांच पर आधारित नहीं है। हिंसा की हर घटना के लिए मोदी की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि असल में दोषी कांग्रेसी ही हैं। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है: “श्री मोदी के पास मुस्लिम दरगाहों और तीर्थस्थलों के व्यापक विध्वंस का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, और यह भी कि कम से कम एक मामले में मलबा हटाकर उस जगह पर पक्की सड़क कैसे बना दी गई... सड़क बनाना एक बड़ा काम है और इसके लिए संगठन,

यांत्रिक उपकरणों और ऐसे प्रयासों की आवश्यकता होती है जो कुछ गुंडों की क्षमता से परे हैं।”
अगर गिल्ड के सदस्यों ने मामूली सी भी जांच की होती, तो मुसलमान उन्हें बता देते कि यह काम कांग्रेस पार्टी के हिम्मत सिंह पटेल ने किया था, जो उस समय अहमदाबाद के मेयर थे। उन्होंने न केवल भीड़ को मजार और पास की मस्जिद में तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया, बल्कि खुद यह सुनिश्चित किया कि अगले ही दिन एक बुलडोजर इन दोनों धार्मिक ढांचों पर से गुजरकर जमीन को समतल कर दे और उस पर सड़क बना दे।
16 आकार पटेल, दिलीप पडगांवकर और बी.जी. वर्गीस, “एडिटर्स गिल्ड फैक्ट फाइंडिंग”
मिशन रिपोर्ट, "अधिकार और अन्याय: गुजरात के नरसंहार स्थलों में अग्नि परीक्षा, एडिटर्स गिल्ड, नई दिल्ली, 2002।"
खोपड़ी और पिल्लों के बारे में 299

एक ओर जहां गिल्ड की रिपोर्ट दंगों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर चुप्पी साधे हुए है, वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हर गुंडागर्दी को मोदी के खाते में इस तरह डाल दिया गया है मानो वे उनकी निजी सेना हों। एक जिम्मेदार पत्रकार मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के आधिकारिक कार्यों और उनकी पार्टी के कुछ सहयोगियों तथा कुछ मुद्दों पर भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले संगठनों के आचरण के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेगा। सच्चाई यह है कि ये संगठन पिछली कांग्रेस और भाजपा सरकारों के दौरान फले-फूले और नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर मजबूत पकड़ बनाने के बाद ही गुजरात में हाशिए पर चले गए।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17 [illegible] [illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]., [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]. 25-34. 300 [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

पंडितों का कभी समर्थन नहीं करती, जबकि उन्हें हिंसा और आतंक के माध्यम से उनकी मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया था।
मीडिया ने मोदी पर दबाव बनाकर उन्हें गोधरा कांड के बाद हुए दंगों और गोधरा कांड को अलग करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उन्होंने उस दबाव के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए उन्हें एक हिंदू कट्टरपंथी के रूप में चित्रित किया गया।
मोदी के माफी मांगने से इनकार पर मचे बवाल में, मोदी के आलोचकों का एक और पसंदीदा मुद्दा यह है कि उन्होंने दंगों के लिए कभी माफी नहीं मांगी और न ही खेद व्यक्त किया। इसे भी इस बात के "सबूत" के रूप में पेश किया जाता है कि मोदी न केवल 2002 के दंगों के लिए दोषी हैं, बल्कि इसे गर्व की बात मानते हैं। ऊपर उद्धृत सभी बयानों के अलावा, मोदी का भाषण 302 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

मार्च 2002 में हुए पहले विधानसभा सत्र में दंगों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई और चर्चा का केंद्र बिंदु यह था: “क्या हमें आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहिए? चाहे वह गोधरा कांड हो या उसके बाद की स्थिति, इससे किसी भी सभ्य समाज की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होती। दंगे मानवता पर कलंक हैं और किसी को भी गर्व करने का अधिकार नहीं देते। तो फिर मतभेद क्यों है?”
20 मार्च 2004 को एनडीटीवी पर प्रसारित एक साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी ने इंडियन एक्सप्रेस के संपादक शेखर गुप्ता से कहा, “आप सब चाहते थे कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाए। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको अकेले मेरे सिर पर सारे घड़े फोड़ने की इजाजत दी। आप सबने तय कर लिया है कि ये सारे दंगे इसी आदमी (नरेंद्र मोदी) के नेतृत्व में हुए हैं। जब तक इस आदमी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाता, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। आपके इस मिशन में मेरी शुभकामनाएं।”

18 “Chakravyuh with Narendra Modi,” NDTV, May 2, 2009. Web. http://www.ndtv.
com/video/player/chakravyuh/chakravyuh-with-narendra-modi/
72774.
[illegible] 303

[illegible]19
[illegible] 12 [illegible]

[illegible]

19 Anand Bhakto, “Beware of His Chakravyuh,” The Sunday Guardian, December 16, 2011, [illegible]. http://www.thesundayindian.com/article_print.php?article_id=27307.

20 □□□ □□□, “□□□□ □□□□□□□□□,” □□□□□□□, 5 □□ 2009. □□□. <https://www.youtube.com/>
watch?v=voN5iQOPlE0>.

अध्याय 17

क्या मुसलमानों ने डर के मारे भाजपा को वोट दिया?
2012 में?
भारतीय राजनीति में गुजराती मुसलमानों की निर्णायक भूमिका

और हैरानी की बात यह है (मेरे मुस्लिम भाई मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करेंगे), कि आज मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह गुजरात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रवेश पर "प्रतिबंध" लगा दिया है... आईबी पर "प्रतिबंध" लगाने के बाद, गुजरात में मुसलमानों पर अत्याचार बंद हो गए हैं। अगर हम फर्जी मुठभेड़ों, झूठे आतंकी हमलों, उनकी मनगढ़ंत जांचों और निर्दोष मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारी को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं, तो यही करना जरूरी है... एस.एम. मुशरिफ, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक, ने 27 मई, 2013 को मिली गजट में यह जानकारी दी।
कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को दंगे, जुआघर और शराब की तस्करी करने वाले माफियाओं के सिवा कुछ नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमारे समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है कि कांग्रेस शासन में मुसलमान पिछड़े रहे।
अल सैयद, अध्यक्ष, गुजरात वक्फ बोर्ड
आज मुसलमानों को भेदभाव का एहसास नहीं होता, भले ही अल्पसंख्यकों के नाम पर कोई विकास योजना नहीं आई है। सब कुछ गुजरातियों के नाम पर है। लेकिन मुसलमानों को भी उतना ही लाभ मिला है। यही सही मायने में राष्ट्रीय एकता है। भाजपा में शामिल हुए मुसलमान भारत के लिए निर्णायक साबित होंगे।
भरूच से आसिफा खान, प्रवक्ता भाजपा।

मोदी की मुख्यमंत्री नियुक्ति ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था, और फरवरी 2002 के चुनाव में राजकोट में मुस्लिम समुदाय के भारी समर्थन से उनकी जीत को राजकोट और गुजरात के बाहर के मीडिया द्वारा भी देखा जाना चाहिए था। हालांकि, इस ऐतिहासिक चुनाव के कुछ ही दिनों के भीतर मोदी पर "नरसंहार" का आरोप लगाने वाले सभी मीडियाकर्मियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 305

यह कहना कि मुसलमानों से नफरत करना मोदी के स्वभाव का हिस्सा था, राजकोट के मुसलमानों द्वारा मोदी के प्रति दिखाई गई अपार सद्भावना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।1. यह हमारे प्रमुख पत्रकारों की अज्ञानता या चूक का मामला तो बिलकुल नहीं हो सकता। मोदी को भाजपा के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाने में दस साल लग गए, जब उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनावों में 31 प्रतिशत मुस्लिम वोटों के साथ जीत हासिल की। दस साल तक चले राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर चले ज़ोरदार अभियान के बावजूद वे सफल हुए, जिसमें उन्हें फासीवादी, मुसलमानों का हत्यारा और भारतीय राजनीति में स्वाभाविक रूप से "विभाजनकारी" शक्ति बताया गया था। हालांकि, गुजरात में सांप्रदायिक विभाजन के कम होने पर राहत महसूस करने के बजाय, भाजपा के लिए मुस्लिम वोटों में हुई वृद्धि को मोदी-विरोधी लोगों ने तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया, जिनमें मेरे सीएसडीएस (सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी) के सहयोगी योगेंद्र यादव जैसे प्रतिष्ठित राजनीतिक वैज्ञानिक भी शामिल थे। उनका कहना था कि मुसलमानों ने डर के मारे मोदी को वोट दिया था।
मेरी आने वाली किताब में, मैं मुस्लिम गांवों से और भी विस्तृत जानकारी दूंगा कि भाजपा के पक्ष में मुस्लिम वोटों में इतना बड़ा

बदलाव क्यों आया है। लेकिन फिलहाल, भरूच की आसिफा खान की कहानी ही काफी कुछ बयां करती है। आसिफा ने गुजरात में चार साल कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बिताने के बाद 2012 के चुनाव से कुछ सप्ताह पहले भाजपा में शामिल हुईं। इसलिए, उनके भाजपा में शामिल होने से काफी हलचल मच गई। उनका सम्मान न केवल साथी मुसलमानों में है, बल्कि हिंदुओं में भी उनका काफी रुतबा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल द्वारा उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता चुने जाने से पहले, उन्होंने गुजरात में भरूच की पहली मुस्लिम महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, जिन्होंने प्रिंट पत्रकारिता और राष्ट्रीय टेलीविजन दोनों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने उत्साह के साथ कांग्रेस प्रवक्ता का पदभार संभाला, लेकिन वर्षों से पार्टी की अव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस से मुसलमानों का मोहभंग: आसिफा ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया है और बताया है कि क्यों उनके सहित बड़ी संख्या में मुसलमान मोदी की भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं:
एक पत्रकार होने के नाते मुझे कई राजनेताओं से बातचीत करने का मौका मिला और
उद्योगपति। चूंकि मैं भरूच से हूं, और अहमद पटेल साहब भी भरूच से हैं।
उसी जिले में, वह मुझे कई वर्षों से उस क्षेत्र के एक जाने-माने पत्रकार के रूप में जानते थे।
1 अध्याय संख्या 8 और 9 देखें।
306 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मेरी अच्छी प्रतिष्ठा के कारण, उन्होंने 2008 में मुझे प्रवक्ता के रूप में चुना।

गुजरात में कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ अखिल भारतीय मीडिया सेल के संयोजक
भारत महिला कांग्रेस। मुझे याद नहीं कि उन्होंने हमारी ओर से किसी और को चुना हो।
जिले के भीतर किसी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद देना।
बिना कोई चुनाव लड़े और बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के—मैं मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण सदस्य भी नहीं था—मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था
मुझे तुरंत ही एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया।
जिम्मेदारी। मेरा काम पार्टी के लिए मीडिया प्रबंधन था, विशेष रूप से
प्रचार का हिस्सा। लेकिन मुझे मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। मेरा
काम पर्दे के पीछे था। उदाहरण के लिए, जब राहुल गांधी को आना था गुजरात में, मैंने उनके लिए कार्यक्रम तैयार किया। हमने उन्हें अभय की अवधारणा दी।
हमने उन्हें उड़ान (निडर उड़ान) के लिए प्रोत्साहित किया और युवाओं के साथ उनकी बातचीत की व्यवस्था की। हमने उन्हें
उसे काम करने के लिए प्रश्न और उन समस्याओं की संभावित सूची दी गई जिन पर युवाओं को काम करना होगा।
मैं चाहता था कि वह इस विषय पर बोले। मैंने राहुल की यात्रा के हर पहलू की योजना बनाई थी, कि वह क्या करेगा।
हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं और जिन मुद्दों को उजागर करने की आवश्यकता है, उन पर ध्यान कैसे दिलाया जाए।
कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए मैंने जो चार साल बिताए, उस दौरान मैंने यह देखा कि

लोगों की गंभीर समस्याओं और मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा था।
जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस के पास राज्य स्तरीय नेतृत्व की कमी है।
जिसका अर्थ यह है कि उत्पन्न होने वाली कोई भी समस्या स्थानीय स्तर पर हल नहीं होती है।
इसे उच्च अधिकारी या दिल्ली भेजा जाता है, और एक बार मामला दिल्ली पहुँच जाए तो,
जब तक राष्ट्रीय नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तब तक कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी होती है।
जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दे महत्वहीन प्रतीत होते हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा "राष्ट्रीय" की तुलना में महत्वहीन माना जाता है।
समस्याएं। इसलिए, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे एक समस्या उत्पन्न होती है।
जमीनी स्तर पर इसका उल्टा असर होता है क्योंकि लोग अपने देश से निराश महसूस करते हैं।
समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए, जब एक विधवा जिसका पति डाक विभाग में कार्यरत था विभाग मेरे पास एक वास्तविक शिकायत लेकर आया था, जिसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी थे।
इस बात का सबूत है कि डाक अधिकारियों ने उसे कुछ वादे किए थे जो उन्होंने
यदि सम्मान देने से इनकार कर दिया गया, तो इस मुद्दे का समाधान केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही संभव हो सका।
स्तर। वह एक बार, दो बार और तीन बार आई। लेकिन चूंकि हम उसकी समस्या हल नहीं कर सके।

समस्या यह थी कि हम जाकर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। उसने सही ही किया।
यह धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी वादे पूरे नहीं करती।
जब मैं मुसलमानों से बातचीत करने के लिए कच्छ गया, तो उन्होंने कहा कि पहले वे
वे कांग्रेस के साथ थे, लेकिन भाजपा में चले गए थे क्योंकि जब भी वे
किसी भी काम को करवाने के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की थोड़ी सी भी मदद की जरूरत पड़ती थी।
चाहे नौकरशाही बड़ी हो या छोटी, उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई बार तो उन्हें स्थानीय कांग्रेस में मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था।
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 307

नेताओं की बात करें तो, नागरिकों की शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन
भाजपा के नेताओं के मिलनसार और सुलभ होने के कारण उन्हें तुरंत सुनवाई मिलती है।
एक मुस्लिम दुकानदार ने मुझे बताया कि जब उसे नगरपालिका लाइसेंस की आवश्यकता होती थी,
सड़क किनारे एक स्टॉल खोलने पर, उसके एक दोस्त ने उसे एक भाजपा नेता के पास ले जाने की पेशकश की, जिसने
उन्होंने तुरंत अपॉइंटमेंट दिया और समस्या का समाधान कर दिया। उन्होंने कहा, “आज, मैं
मैं भाजपा नेताओं और नगरपालिका की बदौलत अपने परिवार का भरण-पोषण कर पा रहा हूँ।

पार्षद जिन्होंने मुझे आवश्यक लाइसेंस दिलवाकर मेरी आजीविका कमाने में मदद की।
इसीलिए मैंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया।
मेरे गृहनगर में हुई कई अन्य घटनाओं के साथ-साथ एक और उदाहरण यह है कि
एक युवा मुस्लिम लड़के की कहानी, जो एक छोटा सा चीनी खाने का स्टॉल चलाता है। वह इसमें शामिल हो गया।
2006 में भाजपा। मैंने उनसे कारण पूछा और उन्होंने समझाया, "देखिए, मैं
मुझे अपने ठेले के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में समस्या आ रही थी। मैंने कई अलग-अलग जगहों पर जाकर देखा।
पार्षदों समेत कांग्रेस के नेताओं को भी कोई मदद नहीं मिली। मैं अकेला ही घर चलाने वाला हूँ।
छह लोगों के परिवार का कमाने वाला। अंततः, घोर हताशा में, मैंने मदद मांगी।
एक दोस्त ने मुझे भाजपा विधायक से मिलवाया। उस विधायक ने तुरंत मुझे अपने साथ ले लिया।
उन्होंने संबंधित विभाग से संपर्क किया और मुझे लाइसेंस दिलवाकर मेरी समस्या का समाधान किया।
नगर पालिका कार्यालय। अब जब मेरा दोस्त आता है और मुझसे अनुरोध करता है कि मैं एक
मेरी लॉरी पर भाजपा का बैनर लगा है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि...
मेरा दोस्त मुझे एक भाजपा विधायक के पास ले गया था।
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं: जब मुसलमान हज के लिए जाते हैं, तो उन्हें आवश्यकता होती है
किसी सरकारी प्रतिनिधि से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाना।

अधिकार का कार्यालय। लोग अक्सर इसके लिए अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाते हैं। मेरे जिले में,
जब मुसलमान कांग्रेस के मुस्लिम विधायक से मिलने का समय लेने की कोशिश करते हैं, तो वे
उनसे समय नहीं मिल पाता, जबकि जब वे किसी हिंदू भाजपा नेता को फोन करते हैं तो उनसे समय मिल जाता है।
विधायक को तुरंत जवाब मिलता है। उन्हें तुरंत बुलाया जाता है और प्रपत्रों पर तुरंत हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि भाजपा किस प्रकार सिद्ध हो रही है।
जमीनी स्तर पर मुसलमानों के लिए मददगार। वे मुसलमानों तक पहुंच रहे हैं और
वे मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं; वे अहंकारी नहीं हैं। भाजपा नेता आपको
बिना किसी झंझट के अपॉइंटमेंट और बिना किसी भेदभाव के आपकी मदद। भरूच में, 2012 के नगरपालिका चुनाव के दौरान, भाजपा और दोनों ने कांग्रेस ने एक विशेष वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। लेकिन यह
भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा
यह इलाका अहमद रियासत का हिस्सा होने के बावजूद मुसलमानों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है।
पटेल साहब का राजनीतिक आधार मजबूत है। वे एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन उनके पास समय नहीं है।
अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए, जबकि स्थानीय कांग्रेस टीम
ये लोग अव्यवस्थित हैं। जब बड़े राष्ट्रीय नेता आते हैं तो ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही जाते हैं।

वे दिल्ली से आते हैं। वे सिर्फ नाम के नेता हैं। इसीलिए लोग उन पर भरोसा नहीं करते।
चुनावों में उनके लिए मतदान करना।
308 मोदी, मुसलमान और मीडिया

तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस इस राज्य में दिन-ब-दिन हार रही है। क्यों?
क्या वे पिछले 22 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं? आठ नगरपालिकाओं में से
भरूच जिले में निगमों में से सात नगर निगमों का संचालन किया जाता है।
भाजपा। कांग्रेस तो जिला स्तर पर भी ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने बहुत कम जिला परिषदों में जीत हासिल की। बाकी सभी परिषदें भाजपा के पास हैं। आगे पढ़ें
नीचे, ऐसा क्यों है कि गुजरात में वर्तमान तालुका परिषदों में से एक भी नहीं है?
क्या वह कांग्रेस के साथ है? इसका मतलब है कि पार्टी जमीनी स्तर पर खत्म हो चुकी है।
गुजरात में कांग्रेस का एक भी विश्वसनीय चेहरा नहीं है। इसीलिए वे भाजपा के खारिज किए गए नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं। क्या आपने किसी राष्ट्रीय नेता को ऐसा कहते सुना है?
क्या यही वह व्यक्ति है जिसे हम मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा नहीं कहा।
आखिरी क्षण तक चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें।
कांग्रेस का कहना है कि राहुल जी जहां भी गए, उन्होंने वहां की सीटें जीत लीं।

निर्वाचन क्षेत्र। तो फिर उन्हें पूरे गुजरात में ले जाने से किसने रोका? सभी
उनके नेताओं ने घोषणा की कि इस बार वे जीतेंगे क्योंकि चाहे कुछ भी हो
राहुल ने उन्हें सीट दिलवाई। अगर वे इस बार गुजरात में सीट पाने के लिए इतने बेताब थे,
उन्हें 100 या 182 निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाने से किसने रोका? इसका मतलब है
उनके काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। वे उसे केवल ले गए। उन्हें उन जगहों पर ले जाया गया जहां उन्हें लगा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बच जाएगा।
यदि आप अंतिम क्षण में किसी राज्य में पहुँचते हैं, तो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी।
लोगों से जुड़ने और उनका विश्वास जीतने के लिए साल के 365 दिन वहां मौजूद रहना पड़ता है।
लोगों के दिलों में बसे हुए। मोदी जी हर समय जनता के साथ रहते हैं; वे अनेक सार्वजनिक सभाओं में भाग लेते हैं।
वह लगातार लोगों से जुड़ता है, उनकी जरूरतों का जवाब देता है और कार्यक्रमों में भाग लेता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और समाधान निकालता है।
प्रशासन एक उद्देश्य की दिशा में काम करता है। और जब वह वहां होता है और एक
सतर्क निगाहों से देखा जाए तो मंत्रिमंडल भी काम करता है, नौकरशाही भी जवाबदेह है, और
जिला परिषद और नगर परिषदें भी काम करती हैं। वह खुद को 24x7 मुख्यमंत्री कहता है।

साल के 365 दिन। इसीलिए वह इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम रहा है और
गुजरात का चेहरा बदलें।
आसिफा खान ने भाजपा क्यों ज्वाइन की?
आसिफा का कहना है कि उन्होंने अचानक ही भाजपा में शामिल होने का फैसला नहीं किया; उन्होंने इस पर लंबे समय तक विचार किया और मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग से प्रतिक्रिया ली।
एक मुस्लिम होने के नाते, मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि
राज्य में शांति है। 11 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। एक क्षेत्र के रूप में
रिपोर्टर: मैंने दंगों को बहुत करीब से देखा है। वही गुजरात, जो बेकाबू हो गया था।
लगातार हो रहे विस्फोटों को नरेंद्रभाई के नेतृत्व में नियंत्रित करना संभव हो पाया है।
2002 में जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मोदी सरकार
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 309

उस समय वह केवल चार महीने का था और उसे प्रशासनिक रूप से बिल्कुल भी अनुभव नहीं था।
अनुभव। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी यात्रा भारी बोझ के साथ शुरू की।
पूर्व भाजपा सरकारों के प्रति अविश्वास और मोहभंग। अन्य बातों के अलावा
चुनौतियों के अलावा, उन्हें अव्यवस्थित राहत और पुनर्वास से भी निपटना पड़ा।

2001 में आया विनाशकारी भूकंप और दंगों का लंबा सिलसिला।
और फिर भी, 2003 में ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात आंदोलन की शुरुआत की।
पहले दिन से ही उनका दृष्टिकोण विकासोन्मुखी था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहल कीं।
WASMO (जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन) जैसी जल परियोजनाएं।
मुसलमान देख सकते हैं कि उनकी टीम काम कर रही है और उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं है।
इसलिए, वे उसकी ओर आकर्षित होने लगे।
2007 का चुनाव हमारे लिए एक बड़ी परीक्षा का समय था। हमने देखा कि कोई भी सांप्रदायिक
भाजपा ने मुद्दे उठाए। यहां तक कि 2002 के चुनावों में भी मोदी का ध्यान इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित था।
मुख्य रूप से विकास पर केंद्रित। मुसलमानों पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन मीडिया ने हमला किया।
“मियान मुशर्रफ” जैसे वाक्यांश पर अनावश्यक हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी, जिसने सांप्रदायिक नफरत की राजनीति खेलने की कोशिश की,
मोदी जी के लिए ‘मौत का सौदागर’ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। भाजपा ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया।
इस तरह की सांप्रदायिक बयानबाजी। मुसलमान अब इस बात को समझने लगे हैं।
याद रखिए, 1947 से अब तक 11,000 छोटे-बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं।
गुजरात में। क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसी ने सद्भावना का मार्ग अपनाया था?
मिशन (सद्भावना मिशन) या राष्ट्रीय एकता के लिए काम? ध्यान रहे,

मुझसे श्री मोदी की कमियां ढूंढने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं मिली। वास्तव में, मैं
मैंने अपने ही नेताओं में खामियां ढूंढना शुरू कर दिया और सवाल उठाने लगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे।
वही करना जो भाजपा कर रही थी। मैं उनसे पूछता, हम इसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
राष्ट्रीय एकता? हम मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें मोदी, मुसलमानों और मीडिया को 310 के झंडे तले नचाना चाहिए।

ऐसी योजनाएँ लाएँ जिनसे सभी को लाभ हो। हम विभाजनकारी राजनीति क्यों खेल रहे हैं?
जाति या धर्म के आधार पर? यहाँ एक व्यक्ति है जो उदाहरण देकर दिखा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है।
इसके बारे में! मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक होने का लेबल लगाना एक शर्मनाक खेल है। हम होना चाहते हैं
हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। यही हमें अब सुनिश्चित किया जा रहा है। इस मामले में, मैं
कांग्रेस से बार-बार निराशा ही हाथ लगी।
मेरी जगह कोई होता तो उसे कांग्रेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने
मुझे एक अहम पद मिला। सोनिया जी के सबसे करीबी व्यक्ति, उनके शीर्ष राजनीतिक सलाहकार,
वह मेरे गुरु, मेरे संरक्षक थे। मैं शोहरत में डूबा रह सकता था और उसी में लगा रह सकता था।
मेरा जीवन। लेकिन मैंने अपने लोगों की सेवा करने और उनकी सेवा करने के लिए राजनीति को एक माध्यम के रूप में चुना है।

बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। जब मैं बाहर आया और
मैंने अपनी घड़ी देखी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे लगभग एक घंटे से बात कर रहा था।
यही वो क्षण था जब मैंने फैसला किया कि मैं उनके लिए काम करूंगा क्योंकि मुझे लगा कि
उनका रवैया बेहद सकारात्मक था। वैसे भी, वे पहले से ही समय की कसौटी पर खरे उतर चुके थे।
इसलिए मैंने अक्टूबर 2012 में, चुनाव से ठीक एक महीने पहले, भाजपा ज्वाइन कर ली। मुझे बताया गया था
मुझे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही संभालनी थी। उन्होंने यह पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। यहां तक कि अन्य भाजपा सदस्यों ने भी। नेताओं ने मुझे कोई निर्देश नहीं दिए। अगर आप वह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे,
आप स्वयं देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सीधे मेरे दिल से निकला है।
मुझे किसी ने कोई निर्देश नहीं दिए। मुझे मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली। मैंने समझाया।
मोदी सरकार और मीडिया में मुझे जो बात सराहनीय लगी, वह थी स्वतंत्रता।
आप मुझसे जितने चाहें उतने प्रश्न पूछ सकते हैं।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भाजपा के लिए मीडिया का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गया।
यह उल्लेखनीय है कि पार्टी मुख्यालय मुझे उपस्थित होने के लिए कहेगा।

इस या उस मीडिया इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी पर किसी टॉक शो के लिए, मैं तैयार रहता था।
मुझे कभी भी यह या वह बोलना नहीं सिखाया गया था। इतना भरोसा महसूस करना अद्भुत था, खासकर
मेरे जैसे नवागंतुक के लिए, जिसे पार्टी नेताओं द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया था, जिसने
मुझे विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के रुख के बारे में प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मुझे पूरी स्वतंत्रता दी गई थी।
मैंने वही कहा जो मुझे उचित लगा।
चुनाव प्रचार सभाओं के दौरान भी यही कहानी दोहराई गई। उदाहरण के लिए,
जब मोदी जी वागरा आए थे, तब मैंने उनके भाषण से ठीक पहले भाषण दिया था।
यह बहुत बड़ी प्रशंसा है। आपको वह भाषण अवश्य सुनना चाहिए। उन्होंने मुझ पर कितना भरोसा जताया।
इसने मेरे भाषण कौशल को एक नया आयाम दिया। मुझे हर जगह से फोन आने लगे।
देश ने मेरे भाषण की सराहना की। 2012 के चुनाव परिणामों के दिन, भाजपा के लिए वह एक बड़ा दिन था, पार्टी ने मुझे एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने लाइव बैठने के लिए कहा।
टीवी चैनलों की पूरी श्रृंखला। सुबह 8 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, बिना किसी रुकावट के।
किसी भी ब्रेक के दौरान, मैंने बस थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा प्रसाद लिया, जब मैं प्रस्तुति दे रहा था।
उस ऐतिहासिक दिन भाजपा के प्रवक्ता।
कांग्रेस में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे ऐसी जिम्मेदारियां नहीं दी गईं। वे जानते थे।

मैं 17-18 साल तक प्रेस रिपोर्टर और एक सार्वजनिक हस्ती रहा। लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं थी।
मेरी क्षमताओं का उपयोग करने के बजाय, उन्होंने मुझे केवल पर्दे के पीछे के कामों के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद
2012 के चुनावों के दौरान, मुझे कांग्रेस पार्टी से फोन आए और उन्होंने कहा, "आपने कभी ऐसा नहीं किया।"
"हमारे लिए ऐसा काम करो।" मैंने उनसे कहा, आपने मुझसे कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा था;
चार साल तक आपके साथ वही आसिफा खान थी। अगर आप मेरी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें।
मेरी क्षमताओं और प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। मैंने वह सब किया जो आप मुझसे करवाना चाहते थे।
ईमानदारी।
क्योंकि मोदी जी एक नेता के रूप में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उनके अधीन सभी लोग
उनसे प्रेरणा लेकर ही सही। आखिर लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर क्यों निकलेंगे?
भाजपा को वोट देने के लिए? मुसलमानों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनमें सक्रिय रुचि विकसित हुई। 312 मोदी, मुसलमान और मीडिया

शासन में। भरूच में हमारे पास 38 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि वागरा में
जिस निर्वाचन क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहां 44 प्रतिशत मुस्लिम हैं। यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था।
दशकों से। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि अगर वे गुजरात का पूरा हिस्सा भी हार जाते हैं,

[illegible]
[illegible]
Jambusar, Bharuch, and Vagra. The Jaghadia seat went to JDU. Inshallah, in
[illegible]
[illegible]
[illegible]

लगभग 30 से 35 प्रतिशत हिंदू हमेशा कांग्रेस को वोट देते हैं। इसका मतलब है कि मुस्लिम
भाजपा की जीत में मतदान ने अहम भूमिका निभाई। सूरत पूर्व में एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम है
लिंबाय में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन वहां कांग्रेस के उम्मीदवार
40,000 वोटों से हार गए। जबलपुर में, जहां 62 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, 10,000
मुस्लिम वोट भाजपा के उस उम्मीदवार को मिले जो विजयी हुआ। प्रमुख मुस्लिम हस्तियों में शामिल हैं...
मेहबूब अली चिश्ती, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सैयद साहब, आसिफा
हैदराबाद के खान और तैयबा ने मोदी जी के लिए बहुत मेहनत की। कांग्रेस से मुसलमानों का पलायन
भरूच जिले के पूर्व कांग्रेसी नेता और बेहद सम्मानित मुस्लिम नेता सदात बापू, जिन्होंने मोदी के पक्ष में मुस्लिम वोटों को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कहते हैं:
भाजपा मुसलमानों से सक्रिय रूप से संपर्क साध रही है; उन्होंने कई सभाएं आयोजित कीं।
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाएँ, जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। इसके विपरीत
कांग्रेस मुसलमानों को हल्के में लेती है। पहले, जब भाजपा चुनाव प्रचार कर रही थी, तब मुसलमानों को
या तो विरोधी थे या उदासीन। लेकिन 2012 के चुनाव में, भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 313

मुस्लिम बहुल इलाकों में बिना सुरक्षा के बैठकें हो रही हैं।
इसलिए पार्टी को जीत मिल रही है।
समुदाय का विश्वास जीतना और विश्वसनीय एवं प्रतिभाशाली मुसलमानों को आकर्षित करना।
भाजपा में शामिल हुए मुसलमान भारत के लिए निर्णायक साबित होंगे। मेरी आगामी पुस्तक में सदात बापू की भूमिका का अधिक विस्तृत विवरण दिया जाएगा। आसिफा खान वास्तव में उनकी शिष्या हैं। इनामुल इराकी, कांग्रेस की तुलना में भाजपा द्वारा मुसलमानों में कहीं अधिक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के बारे में बापू सदात और जफर के इस बिंदु का समर्थन करते हैं, और 2013 के नगरपालिका चुनावों में उम्मीदवार बनाए गए एडीजी पुलिस सैयद का उदाहरण देते हैं। इराकी के शब्दों में:
जब भाजपा ने पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को उम्मीदवार बनाया था
अब्दुल्ला इब्राहिम सैयद को 2013 में महापौर पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था।
जुहापुरा के मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र से नगरपालिका चुनाव में, इसमें एक
इसका समुदाय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वहां लगभग 35 लाख मुसलमान रहते हैं।
सैयद साहब को 40,000 से अधिक मुस्लिम वोट मिले, हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सके।
चुनाव। यह अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है क्योंकि भाजपा ने कभी भी उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत नहीं की थी।
कांग्रेस जिन मुस्लिम गढ़ों की पूरी लगन से रक्षा करती है, उनसे उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि उन हजारों लोगों ने डर या किसी मजबूरी के कारण वोट दिया हो।
जुहापुरा में भाजपा द्वारा बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें यह देखा गया कि
हर बार हजारों मुसलमानों की भागीदारी होती है।
मुस्लिम मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। कई प्रमुख मुस्लिम कई लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, और भाजपा भी मुसलमानों को अधिक गंभीरता से ले रही है।
हाल के वर्षों में हिंदू-मुस्लिम संबंधों में वास्तव में सुधार हुआ है। हम एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं।
एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। इसका श्रेय काफी हद तक हमारे मुख्यमंत्री को जाता है।
जुहापुरा में कई लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने सैयद साहब को वोट मुख्य रूप से मोदी की वजह से दिया। अगर वे अधिक सक्रिय उम्मीदवार होते, तो वे आसानी से जीत जाते। सैयद साहब बताते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने न केवल भाजपा में शामिल होने का फैसला किया, बल्कि 2012 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार भी किया:
मैंने भाजपा में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी राजनीति में जाति का अत्यधिक वर्चस्व है।
और धर्म। इसमें राष्ट्रीय भावना का समावेश होना चाहिए। मुझे नरेंद्र मिले।
मोदी ठीक यही कर रहे थे। कई ऐसी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के बावजूद।
दंगों के दौरान, कांग्रेसी नेता भाजपा को लेकर मुल्लाओं को डराते रहते हैं। सेवा करते समय
पुलिस में मैंने करीब से देखा था कि कांग्रेस रही है

मुसलमानों को बहुत लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमानों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत थी और
सच कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दंगे, जुआघर, 314 मोदी, मुसलमान और मीडिया के अलावा कुछ नहीं दिया।

और शराब की तस्करी करने वाले माफियाओं से लेकर मुस्लिम समुदाय तक। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ है। इसी कारण मुसलमान पिछड़े रह गए।
कांग्रेस शासन के दौरान।
1985 के दंगों के दौरान मेरी तैनाती अहमदाबाद में उप आयुक्त के पद पर थी।
ये प्रदर्शन कांग्रेस के भीतर पटेल गुट द्वारा माधव को सत्ता से हटाने के लिए आयोजित किए गए थे।
सिंह सोलंकी भी ओबीसी जाति से थे। सोलंकी ने अपना दूसरा चुनाव जीता था।
उन्होंने 148 विधायकों के साथ चुनाव जीता। इसके बावजूद, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी गई।
मंत्री जी। उन्होंने 1985 के जाति-विरोधी दंगों को भड़काने के लिए भाई लोगों और डॉन का इस्तेमाल किया।
जिसमें मुस्लिम समुदाय को बलि का बकरा बना दिया गया।
1985 का दंगा दरियापुर में शुरू हुआ था। जब मैं वहाँ जाँच करने पहुँचा, तो मुझे
मैंने पूछा कि हिंसा किस वजह से भड़की? मुझे बताया गया कि यह सब एक झगड़े के कारण हुआ।
पतंग उड़ाने को लेकर। यह सरासर बकवास था क्योंकि रात में कोई पतंग नहीं उड़ाता।

वे पुलिसवाले तो थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 'हाँ में हाँ मिलाने वाले' बनकर रहने के बजाय बोलने का साहस दिखाया।
उन्होंने कहा, “महोदय, अगर हम सारे हथियार मुख्यालय में जमा कर दें, तो हम उनका प्रबंधन कैसे करेंगे?”
"अगर कहीं हिंसा भड़क जाए तो क्या स्थिति होगी?" कमिश्नर ने जवाब दिया।
पारसी शैली में, "मैं अपनी छड़ी से अहमदाबाद पर नियंत्रण करूँगा!" बेशक, वह 1969 के दंगों को छड़ी से नियंत्रित नहीं कर सकता था! इसीलिए तो बस
रिलीफ रोड पर पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ा मुस्लिम व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थित है।
एडवर्ड वाशिंग कंपनी नामक इमारत जलकर राख हो गई। पुलिस अंदर नहीं जा सकी।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आग का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। 1992 में भी, चिमनभाई
सांप्रदायिक हिंसा भड़काई। मैं जुहापुरा सोसाइटी में रह रहा था जहाँ हम
मैंने एक बैंक में डकैती होते देखी। लेकिन पुलिस उसे रोक नहीं पाई क्योंकि वहाँ
उन्हें गोली चलाने का आदेश नहीं दिया गया था। उस समय जुहापुरा में वही एकमात्र बैंक था।
उस घटना के कारण, जुहापुरा में 15 वर्षों तक किसी अन्य बैंक ने अपनी शाखा नहीं खोली।
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 315

कई साल हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ही दो-तीन नए बैंक सामने आए हैं।

जुहापुरा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था।
आज भी कांग्रेस का नेतृत्व डॉनों के हाथों में है।
उदाहरण के लिए, गुजरात में कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष
last 15 years is a man named Wazir Khan Pathan from Vishnagar, Mehsana
जिले में। वे नाममात्र के लिए बी.ए. एलएल.बी. लिखते हैं और उच्च न्यायालय के सदस्य हैं।
वह बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन मूल रूप से उन्होंने अवैध शराब के व्यापार से पैसा कमाया था।
जब नरेंद्र मोदी ने मुझे वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया, तब उनके
पदभार संभालने के बाद मुझसे पहला वाक्य यही था: "जाओ, अपने समाज की सेवा करो।"
मुझे यह पसंद आया। सबसे अच्छी बात यह है कि वह प्रशासन में कभी दखल नहीं देता, चाहे वह कुछ भी हो।
चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो या सरकार का। फिर भी वो हर चीज पर नजर रखता है।
ताकि लोग अपने पद का दुरुपयोग न करें। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा है।
उन्होंने वक्फ बोर्ड को सेवा का साधन बनाने का आदेश दिया। उन्होंने समुदाय को संस्था का संचालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी।
वक्फ बोर्ड पहले पूरी तरह से निष्क्रिय था। मेरे सामने असली चुनौती यह है कि...
स्थानीय वक्फ ट्रस्टों का नेतृत्व सभी भाई लोग करते हैं और उनमें से 99 प्रतिशत

सांसद। वे समुदाय के लिए चंदा इकट्ठा करके पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं।
कल्याण। मैंने वक्फ बोर्ड के स्थानीय ट्रस्टों को एक भी औषधालय चलाते हुए नहीं देखा है।
या स्कूल। मैं उनके कामकाज में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा हूँ।
आज 70 प्रतिशत मुसलमान मोदी से खुश हैं क्योंकि वह ऐसा नहीं करते हैं।
धर्म या जाति के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना। वह इसका समर्थन करता है।
जो भी व्यक्ति अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है।
वह अपने सभी अधिकारियों से कड़ी मेहनत करवाता है, उन्हें मैदान में भेजता है और लक्ष्य तक पहुंचाता है।
लोगों की सेवा। उनके द्वारा लाई गई स्थिरता से हर कोई खुश है।
गुजरात। उन्होंने दंगा के आरोपियों के मुकदमे में भी हस्तक्षेप नहीं किया है।
कई लोगों को जेल भेजा गया है, कई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब मुसलमान
पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करें।
2013 के नगरपालिका चुनावों में, जब मुझे संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था
अहमदाबाद के मेयर के रूप में, मैंने भाजपा के टिकट पर जुहापुरा से 40,000 वोट हासिल किए।
यह अपने आप में अविश्वसनीय है क्योंकि भाजपा ने इससे पहले यहां कभी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था।
इस मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में। कांग्रेस ने गुजरात की राजनीति को तबाह कर दिया था।

भाई लोग और मुल्ला जिन्होंने अपने ही बीच के गरीब और अशिक्षित लोगों को गुमराह किया
मोदी ने गुजरात में मुस्लिम राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया।
गुजरात भाजपा में मुसलमानों की स्वीकार्यता: आसिफा की भाजपा में इतनी आसानी से स्वीकार्यता की कहानी ने शुरू में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन भरूच जाकर भाजपा के प्रमुख नेताओं से बात करने के बाद मेरा आश्चर्य स्पष्ट हो गया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर मोदी से गठबंधन किया था। जब 316 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मैंने पहली बार फरवरी 2013 में उनका बयान सुना था, तब आसिफा से यह पूछना तर्कसंगत लगा कि क्या उन्हें महिला या मुस्लिम होने के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कोई नाराजगी महसूस होती है, क्या वे उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा:
नहीं। भेदभाव दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार तब होता है जब वे कोशिश करते हैं
आपको इसलिए दबाया जाता है क्योंकि आप एक महिला हैं। अधिकांश पुरुष प्रधान समाजों में
समाजों में, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप
दबा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत, वरिष्ठ नेता खुश थे।
जब भी मुझे तथ्यों या अन्य जानकारी के साथ बैकअप सहायता की आवश्यकता हो, तो मुझे मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए।

जो भी हो। मुझे कभी भी मुसलमान होने के कारण भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा।
या महिला होने के कारण। मुझे एक नई कर्मचारी होने के बावजूद भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा।
न ही मुझे कभी ऐसा लगा कि वे मेरे होने से ईर्ष्या करते थे, और न ही मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि वे मेरे होने के कारण मुझसे ईर्ष्या करते थे।
इसे बहुत ही प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। वास्तव में, ये सभी चीजें मेरे पक्ष में रहीं।
पहले दिन से ही। नरेंद्रभाई ने मेरी क्षमता को पहचाना और मुझ पर भरोसा जताया।
जब हम पहली बार मिले थे, तभी से।
जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें भी जफर सारेवाला की तरह भाजपा में शामिल होने के कारण मुस्लिम समुदाय से किसी प्रकार की शत्रुता का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने यह कहा:
ज़फ़रभाई ने 2002 में मोदी जी से बातचीत शुरू की, जब उनके प्रति घोर पूर्वाग्रह व्याप्त था।
मोदी जी के खिलाफ। उस समय मुसलमान उन्हें ठीक से नहीं जानते थे। अब वे समय की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं।
इसलिए, भाजपा में मेरे शामिल होने पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया यह रही है कि
शानदार! वे बहुत खुश थे। आपको भी उत्साह से भरी बातें देखनी चाहिए।
टीवी फुटेज के माध्यम से मेरी सार्वजनिक सभाओं पर गुजराती मुसलमानों की प्रतिक्रिया
उन दिनों के वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं।

गुजरात की चुनावी राजनीति में मुसलमानों की बदलती भूमिका: राष्ट्रीय मीडिया में हम सिर्फ यही सुनते हैं कि भाजपा मुसलमानों को कैसे दरकिनार करती है और भाजपा मुसलमानों को। 2012 के विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में न उतारे जाने को मोदी की मुसलमानों के प्रति नफरत के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। आरोप लगाया गया कि मोदी ने सार्वजनिक रूप से कसम खाई थी कि अगर एक भी मुस्लिम विधानसभा में दाखिल हुआ, तो वे पूरे परिसर को गंगाजल से धुलवा देंगे। मैंने कई मुसलमानों से पूछा कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। लगभग सभी ने कहा कि यह "बिल्कुल बकवास" है। इस पर जफर सारेवाला का कहना है:
2. आसिफा खान द्वारा एक सार्वजनिक सभा में गुजराती मुसलमानों को संबोधित करते हुए एक वीडियो उपलब्ध है। http://www.youtube.com/watch?v=9fi8Bkh3KvE&feature=youtu.be पर।
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 317

बिलकुल बकवास! इससे पता चलता है कि मोदी के खिलाफ किस तरह के घातक झूठ फैलाए जा रहे हैं।
और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास बनाए रखने के लिए कितनी बेताब है।
कांग्रेस के विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और आरएसएस के साथ गठबंधन करने के कारण मोदी के हाथ बंधे हुए थे।
और बजरंग दल। इस चुनाव में उम्मीदवार की जीत की संभावना एक प्रमुख कारक थी।
आखिर क्यों वे लोग जो मुसलमानों को एक भी टिकट न देने के लिए उनकी आलोचना करते हैं?

2012 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा जब एक
पंचायत चुनावों में भाजपा के टिकट पर अभूतपूर्व संख्या में मुसलमानों ने जीत हासिल की।
नगरपालिका और जिला परिषद चुनाव? अगर मुसलमान वाकई नाराज थे
क्या इस आधार पर वे भाजपा के हिंदू उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कर पाते?
उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ जहां उन्होंने
पर्याप्त प्रतिशत या बहुमत?
जामनगर जिले के हाल ही में हुए सलाया नगर निगम चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भाजपा ने 27 में से 27 सीटें जीती हैं। इनमें से 24 सीटें भाजपा के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीती हैं। जब मैंने ज़फ़र से पूछा कि क्या यह कोई अपवाद है या भाजपा के टिकट पर मुसलमानों की जीत का एक स्थापित चलन है, तो उन्होंने यह जवाब दिया: 2012 के चुनावों में 31 प्रतिशत मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था। आसिफा खान के अनुसार
भरूच क्षेत्र में 35 प्रतिशत से अधिक मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है और यह
यहां तक कि उन जगहों पर भी भाजपा समर्थक मतदान हुआ है जहां कांग्रेस का उम्मीदवार था।
मुस्लिम। कांग्रेस उन जगहों पर भी हार गई है जहां मुस्लिम वोटों का हिस्सा मुस्लिम वोटों के बीच था।
38 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक। ऐसे निर्णायक निर्वाचन क्षेत्रों में, भाजपा के किसी हिंदू उम्मीदवार को जीतना संभव है।
जीत गया। क्यों? मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मीडिया इस बारे में गलत था।

2012 के चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत के कारण। 75 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।
गुजरात में भारी मतदान इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया।
मोदी को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आए।
2012 के विधानसभा चुनाव से पहले, कई मुस्लिम भाजपा के समर्थन से चुनाव जीत चुके थे।
जिला परिषद, नगरपालिका और पंचायत चुनावों में टिकट। सलाया गांव आप जिस क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं वह पश्चिमी तट पर स्थित है। एक समय यह क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध था।
तस्करी एक ऐसा क्षेत्र था जो आर्थिक और
बुनियादी ढांचे के विकास की बात करें तो, वहां बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थीं। मोदी
एक महत्वाकांक्षी तटीय विकास योजना लाई गई। उस क्षेत्र में, एक बहुत सारे मुस्लिम गाँव हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि विकास गतिविधियाँ कैसी हैं।
इस क्षेत्र में मुस्लिम गांव भी शामिल थे।
पिछले नगरपालिका चुनावों में, जब पांच मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी
इस क्षेत्र में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से पूरे समुदाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
उन्हें लगा कि अगर भाजपा इतना आर्थिक विकास ला रही है और साथ ही 318 मोदी, मुस्लिम और मीडिया भी

अगर उन्हें राजनीतिक पद हासिल करने का अवसर दिया जाए, तो फिर उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए?

दूर रहो। यही कारण है कि सलाया मुसलमानों ने भाजपा को सभी 27 सीटों पर जीत दिलाई।
मीडिया ने सैकड़ों लोगों की अभूतपूर्व जीत का कभी जश्न नहीं मनाया।
पंचायत, जिला परिषद और नगर पालिका चुनावों में मुसलमानों का रुझान बीजेपी पर है
टिकट। लेकिन वे मुसलमानों को मैदान में न उतारने को लेकर लगातार हंगामा करते रहते हैं।
विधानसभा चुनाव। गुजरात से बुरी खबर के लिए वे इतने बेताब क्यों हैं? अगर
उन्हें ज़मीनी हकीकत से बुरी खबर नहीं मिलती, वे बस उसे मनगढ़ंत बना देते हैं! फरवरी में
13, 2013, जिस दिन जामनगर के सलाया नगर निगम के नतीजे आये
जब जिलों की घोषणा हुई, तो एनडीटीवी की बरखा दत्त ने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
उनका कार्यक्रम, 'द बक स्टॉप्स हियर'। इसका उद्देश्य जीत पर चर्चा करना था।
सलाया में भाजपा के टिकट पर नगरपालिका चुनावों में सैकड़ों मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
जहां 95 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, वहां सभी 27 सीटें जीती गईं। भाजपा। आम तौर पर मैं अहमदाबाद से ओबी पर उपस्थित होता हूं। लेकिन उस दिन से मैं...
दिल्ली में, मैंने शो के लिए एनडीटीवी स्टूडियो जाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन, आखिरी समय में,
बरखा दत्त ने वह शो रद्द कर दिया। क्या इसकी वजह मीडिया, खासकर चैनल हैं?

एनडीटीवी जैसे लोग गुजरात के बारे में कोई भी अच्छी खबर कभी भी बाहर न आने देने पर तुले हुए हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए?
जिला परिषदों और नगर निगम के मतदान केंद्रों के चुनाव परिणाम
यह दुष्प्रचार कि मोदी की नीतियों से केवल शहरी मुसलमानों को ही लाभ हुआ है
विकास एजेंडा। ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ग्रामीण मुस्लिम
पहले उपेक्षित रहे क्षेत्रों को कहीं अधिक लाभ हुआ है और इसलिए वे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
भाजपा की ओर बड़े पैमाने पर। पंचायत चुनावों में भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती हैं।
कुल सीटों में से 60 प्रतिशत सीटें भाजपा को मिलीं। 76 नगर पालिकाओं में से भाजपा ने 45 में जीत हासिल की। 20 प्रतिशत सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की।
पंचायतों के प्रतिशत में भाजपा और कांग्रेस की हिस्सेदारी 50-50 है। मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मार्केटिंग हथकंडों के जरिए। मुसलमान उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जिसे वे पारंपरिक रूप से समर्थन देते आए हैं।
वे इससे इसलिए बचते हैं क्योंकि वे अपने क्षेत्र में जमीनी हकीकत में नाटकीय बदलाव देखते हैं।
कृपादृष्टि।
जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि केवल धनी या कुलीन मुसलमान ही मोदी की ओर झुक रहे हैं
यह याद रखना चाहिए कि चुनिंदा हिंदुओं में से केवल एक छोटे से अति अभिजात वर्ग के लोग ही ऐसा कर सकते हैं।

मेट्रो मीडिया मोदी को बदनाम कर रहा है। यह सब मीडिया का हेरफेर है। मोदी ने निर्माण कार्य किया है।
गुजरात में विचारशील और सम्मानित मुसलमानों की एक बहुत मजबूत टीम है। हालाँकि,
मेरे विचार में, कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव जीतना काफी हद तक संभव है।
मुस्लिम समुदाय के आर्थिक विकास की तुलना में कम महत्वपूर्ण। कुछ मुस्लिम या अनुसूचित जाति (एससी) के लोग चुनाव जीतते हैं और राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं।
कार्यालय में काम करने से जरूरी नहीं कि पूरे समाज के जीवन स्तर में सुधार हो।
समुदाय, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमारे सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से बहुत से लोग
समुदाय सामाजिक शिष्टाचार की भावना के बिना सुपर महाराजाओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं।
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 319

पूर्व महाराजाओं द्वारा अपनी प्रजा के प्रति निभाई गई जिम्मेदारी।
जब एक निश्चित संख्या में मुस्लिम या अनुसूचित जाति के लोग चुनाव जीतते हैं, तो राजनीतिक शक्ति
कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन समावेशी आर्थिक विकास से आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो जाती है। संपूर्ण समुदाय की स्थिति, जिसके बाद वह इन शक्तियों के साथ बातचीत कर सकता है
सापेक्षिक मजबूती की स्थिति से धारकों को नुकसान हो रहा है। ठीक यही हो रहा है।

गुजरात मेँ।
मोदी को लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहना कम होगा, मोदी की
अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से प्यार करते हैं, कांग्रेस चाहे इसे पसंद करे या न करे। वे सोचते हैं कि वह
bigger hero than Salman Khan (ye Salman Khan ka baap hai). I know some
बहुत से बड़े इस्लामी विद्वानों ने कहा, “मोदी को वोट दें। हमें मोदी की जरूरत है। अल्लाह की कृपा बनी रहे।”
अगर वो हार जाए तो हमें बचाओ! कौन जाने मोदी के हारने पर कौन आएगा! (मोदी को वोट दो!)
Modi chahiye, Allah khair kare,Ye haara kaun aayega pata nahin). जब 2012 के चुनावों में गुजरात के 31 प्रतिशत मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया था,
उन पर डर के मारे भाजपा को वोट देने का आरोप लगाया गया था। 2002 में, गुजरात के मुसलमान
वास्तव में आतंकित होने के बावजूद उन्होंने मोदी के खिलाफ वोट दिया क्योंकि हमारे चुनाव
यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है और इसमें गुप्त मतदान का प्रावधान है। क्या उनका मतलब मुसलमानों से है?
क्या 2012 में आतंकित हुए लोगों ने मोदी को वोट दिया? मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया
क्योंकि उन्होंने मोदी के शासनकाल में आर्थिक प्रगति का स्वाद चखा है।
यह आरोप भी निराधार है कि केवल धनी मुसलमान ही इस ओर बढ़े हैं। मोदी। धनवानों के लिए भाजपा के सत्ता में होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

या फिर कांग्रेस। बड़े उद्योगपति वास्तव में भ्रष्ट सरकार को पसंद करते हैं।
क्योंकि वे इसे अपने फायदे के लिए हेरफेर कर सकते हैं। एक ईमानदार सरकार से लाभ होता है।
इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक और समाज के गरीब वर्ग होते हैं। भले ही
अहमदाबाद में 200 दिनों का कर्फ्यू लगा है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इसकी चिंता नहीं है।
मेरे घर में राशन है या मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं। लेकिन वह गरीब मुसलमान जो
सड़क किनारे ठेला लगाने वाला या रिक्शा चलाने वाला या
टैक्सी चालक के जीवन पर दो दिन के कर्फ्यू के बावजूद भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
उसकी रसोई में कोई राशन नहीं होगा। मुसलमानों का यही वर्ग आकर्षित हुआ है।
मोदी की ओर अधिक संख्या में लोग इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि सुशासन के फल और
दंगा-मुक्त गुजरात से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। भाजपा मुसलमानों को नहीं लेती।
इसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। भाजपा के नेता हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।
जब कोई उम्मीदवार आपके पास आता है और आपकी मदद करने के लिए आपका नाम पुकारता है, तो आपको महत्वपूर्ण महसूस होता है।
वह कंधे पर हाथ रखकर कहता है, "बॉस, मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ।" इससे
समुदाय को केवल दो-तीन होने की तुलना में कहीं अधिक गरिमा का एहसास होता है।

चुनाव के समय नाममात्र के उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं। मैं एक बेईमान मुसलमान की तुलना में एक ईमानदार हिंदू पर अधिक भरोसा करूंगा। हम नहीं चाहते
कांग्रेस ने पार्टी में जिस तरह के मुसलमानों को बढ़ावा दिया है, वे उसी तरह के रबर स्टैंप मुस्लिम हैं। 320 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

आँख बंद करके उसके आदेशों का पालन करना। हम ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो न्याय करता हो, भले ही
वह मुसलमान नहीं भी हो सकता है। पिछले 50 सालों से वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
हमने कुछ चुनिंदा रबर स्टैम्प चुनकर हमें दे दिए। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्या आप अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय चाहते हैं? आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे।
एक नागरिक के रूप में आपको बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन आप मुझसे वह वादा कर रहे हैं जो मेरा हक नहीं है।
मुझे आरक्षण का वादा करें, जो आप संविधान के अनुसार मुझे नहीं दे सकते।
लेकिन जब मैं कहता हूं, कृपया मेरे इलाके में एक छोटा प्राथमिक विद्यालय बनाइए, तो कुछ
आप लोग आसानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप सांसद ऐसा नहीं करते! सच्चाई यह है कि मोदी के कई लोगों के साथ उत्कृष्ट व्यक्तिगत संबंध हैं।
उन्होंने मुसलमानों की एक बहुत मजबूत टीम बनाई है जो उनके साथ मिलकर काम करती है।
वे सुशिक्षित हैं और समाज में उनका सम्मान है।

उन्हें बिकाऊ (बिक्री योग्य) प्रकार का नहीं माना जाता; वे करी बनाने वाले लोग नहीं हैं।
लोग निजी कृपा प्राप्त करते हैं और दरबारी बन जाते हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी...
आज न केवल गुजरात में बल्कि विश्वसनीय मुस्लिम नेताओं की टीम का अभाव है।
भारत के बाकी हिस्सों में भी।
बताइए, क्या आपको राहुल गांधी की टीम में कोई गंभीर मुस्लिम चेहरा नज़र आता है?
क्या कांग्रेस के किसी मुस्लिम सदस्य ने उत्तर प्रदेश या बिहार में उसे सत्ता में लाने में मदद की? मैं
मुझे पूरा विश्वास है कि 2012 के राज्य चुनावों में, जिसमें मुसलमानों ने खुले तौर पर मतदान किया था
मोदी के लिए यह पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर भाजपा मोदी को आगे बढ़ाती है, तो
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी को कोई कठिनाई नहीं होगी।
भारत के बाकी हिस्सों, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, को यह विश्वास दिलाना कि वह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
सत्ता विरोधी लहर का असर कुछ गरीब भाजपा विधायकों पर भी पड़ा। कलाकार। मोदी के खिलाफ कोई सत्ता-विरोधी लहर नहीं थी। कांग्रेस के बाद से
आरएसएस/भाजपा के बागी केशूभाई और वाघेला के साथ हाथ मिलाने के बाद मोदी को सत्ता से हटा दिया गया।
एक कठिन परिस्थिति। अगर उन्होंने इन मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए होते, तो वे

केशूभाई की पार्टी में शामिल होकर उन्होंने भाजपा के वोटों को झटका दिया है। कांग्रेस
इस तरह मोदी को बांधे रखने में कामयाबी मिली। अन्यथा, वह गरीबों को छोड़ देते।
उनके विधायकों और मंत्रियों में प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं।
मोदी के सत्ता में आने से पहले मुसलमानों की स्थिति वास्तव में दयनीय थी।
इस परिदृश्य में, कांग्रेस उन्हें हल्के में लेती थी और उनके लिए कुछ नहीं करती थी।
दूसरी ओर, भाजपा का मानना था कि मुसलमान मतदान नहीं करेंगे।
उनके लिए तो कुछ करना ही क्यों है? लेकिन मोदी ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है।
मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण।
मोदी के आने से पहले, गुजरात में भाजपा का एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था।
आज, इसमें कुछ सबसे सम्मानित मुस्लिम शामिल हैं जो भाजपा के समर्थक के रूप में खड़े होते हैं।
प्रवक्ता। यह कांग्रेस है, जिसने मुस्लिम समर्थन खो दिया है।
और पार्टी का बचाव करने के लिए उनके पास एक भी विश्वसनीय चेहरा नहीं है। उनके पास केवल
क्या मुसलमानों ने 2012 में डर के मारे भाजपा को वोट दिया था? 321

मुंबई और दिल्ली में गैर सरकारी संगठन कांग्रेस के मुखपत्र के रूप में काम करेंगे। गुजरात
मुसलमान आसानी से अन्य राज्यों के मुसलमानों को मोदी की योग्यताओं के बारे में समझा सकते हैं।

क्योंकि उन्होंने परिवर्तन का अनुभव किया है और शांति के फलों को साझा किया है।
आर्थिक विकास।

अध्याय 18

शांति और समृद्धि का
क्या मुसलमान गुजरात के विकास की गाथा का हिस्सा हैं?

समान अवसर केवल एक ईमानदार सरकार ही दे सकती है… अधिकांश मुसलमान इस बात से खुश हैं कि मोदी कभी भी किसी विशेष समुदाय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, को लुभाने के लिए विभाजनकारी रणनीति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा 6 करोड़ गुजरातियों को संबोधित करते हैं… धनवान लोग किसी भी शासन में फलना-फूलना जानते हैं… बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट जगत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश लोकतांत्रिक है या तानाशाही। लेकिन शांति और बहुमुखी शासन के असली लाभार्थी गरीब लोग हैं, जिनके लिए अवसरों के नए द्वार खुलते हैं… मोदी अभाव की राजनीति नहीं खेलते, जो एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। वे प्रचुरता की स्थिति बनाते हैं ताकि हर किसी को बिना किसी से झगड़ा किए अपना हक मिल सके।
जफर सारेवाला, अहमदाबाद स्थित उद्यमी

मोदी सरकार पर बार-बार लगने वाले आरोपों में से एक यह है कि गुजरात में प्रतिकूल राजनीतिक माहौल और भेदभावपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण मुसलमानों को आर्थिक रूप से कुचला जा रहा है। गुजरात की एक पर्यटन यात्रा भी यह दर्शाती है कि वास्तविकता इस दुष्प्रचार से बिल्कुल भिन्न है। होटल व्यवसायी और इस्पात व्यापारी इनामुल इराकी की गरीबी से अमीरी तक की कहानी 2002 के बाद के गुजरात में गुजराती मुसलमानों की तीव्र प्रगति का प्रतीक है।1 इराकी ने अपना जीवन कबाड़ बीनने वाले के रूप में शुरू किया था, जबकि उनके पिता एक गरीब मिल मजदूर थे। उनके शब्दों में:

मेरे पिता जुपिटर मिल में मजदूर थे और हम एक छोटे से मकान में रहते थे।
मुझे पांच रुपये प्रति माह के किराए पर मकान मिला था। मैंने केवल दसवीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है।
मैंने अपना वर्तमान व्यवसाय लगभग 12 साल पहले शुरू किया था।
लेकिन मैंने 15 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था।
1. मैंने गुजरात के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे कई मुसलमानों से मुलाकात की।
अपनी आगामी पुस्तक में, मैं मुस्लिम किसानों, मछुआरा समुदायों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल, मैं शहरी मुसलमानों को उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने दूँगा जिनसे उन्हें समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिली।
शांति और समृद्धि 323

मैं सड़कों से कबाड़ इकट्ठा करता था। मैं छोटी-छोटी चीजें इकट्ठा करने के लिए साइकिल पर घूमता था।
सड़क किनारे पड़े कचरे से लोहे के टुकड़े इकट्ठा करता हूँ, उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में छाँटता हूँ, और
इसे फाउंड्री को बेच दिया। बाद में मैंने एक हाथ से चलने वाली लॉरी का इस्तेमाल करना शुरू किया और अपना कारोबार बढ़ाया।
समय के साथ मेरा व्यवसाय बढ़ता गया। 1992 में, मुझे कच्चा लोहा बेचने की एजेंसी मिल गई।
2003-2004 में, मैंने अपनी खुद की फाउंड्री शुरू की, जिसके बाद राजकोट में दूसरी फाउंड्री खोली।
वर्ष 2006 में। 2009 में, मैंने कुछ होटल खरीदे।

हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमारे पूर्वज इराक से आए थे। लेकिन हमारा परिवार
हम सात पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं। हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं।
हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान को नहीं चुना और हम भारत में ही रहे। मेरे पिता
और उनके तीनों भाई भी स्वतंत्रता सेनानी थे। मूल रूप से मेरा परिवार
वे उत्तर प्रदेश में बस गए। बाद में व्यापारिक अवसरों की तलाश में वे गुजरात चले गए।
वह एक चक्की में काम करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं।
एक व्यवसाय। उस छोटी सी लोहे के कबाड़ की दुकान से शुरुआत करके, मैंने यह व्यवसाय खड़ा किया है।
पिछले कुछ वर्षों में साम्राज्य का विस्तार हुआ है।
2002 में मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालाँकि, वही
2002 के दंगों के समय जिन मुसलमानों के पास केवल 2 रुपये ही थे, आज उनके पास कम से कम 5 रुपये हैं। यानी उनकी आय में काफी वृद्धि हुई है।
गुजराती मुसलमान सक्षम और बुद्धिमान हैं। वे जानते हैं कि कैसे सही दिशा में आगे बढ़ना है।
दिए गए अवसरों के कारण समुदाय ने अभूतपूर्व समृद्धि हासिल की है। गुजराती मुसलमान हमेशा से ही व्यापारोन्मुखी रहे हैं। हम खुले विचारों वाले भी हैं।
दूरदर्शी और बड़ी सोच रखने वाले होते हैं। 2002 के दंगों के बावजूद, मदरसे के प्रतिनिधि

जरूरतमंदों के लिए गुजरात से दान इकट्ठा करने के लिए पूरे भारत से लोग आए।
अन्य राज्यों में मुसलमान हैं। लेकिन देश की राजनीति पर उत्तर प्रदेश का दबदबा है।
बिहार के मुसलमान। उनके पास राजनीति के अलावा कोई और काम नहीं है।
जबकि गुजराती मुसलमान।
हम वास्तविक कार्य में लगे हुए हैं और धन सृजित कर रहे हैं, हमने राजनीति को परिवर्तित नहीं किया है।
व्यवसाय में। दुर्भाग्य से, गुजरात के मुसलमानों का इसमें कोई खास महत्व नहीं है।
राष्ट्रीय राजनीति।
जिस दिन मेरी मुलाकात इनामुल इराकी से हुई, उन्होंने मुझे बताया कि वे कच्छ जा रहे हैं, एक इस्पात संयंत्र को 45 करोड़ रुपये का माल सप्लाई करने के लिए। पिछले दो महीनों में ही उन्होंने उनके साथ 45 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इराकी के अनुसार:
मोदी द्वारा कानून को सख्त करने के कारण गुजरात में मुसलमान समृद्ध हो रहे हैं और
तंत्र को इतने दृढ़ और निष्पक्ष तरीके से व्यवस्थित करें कि उपद्रवी तत्व इसमें बाधा न डाल सकें।
सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं करते। 2002 में, मोदी को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है।
लेकिन अब कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण है। उनका छोटा और
कॉम्पैक्ट कैबिनेट में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो एक समान सोचते हैं और एक समान तरीके से काम करते हैं।
परिवार। इसलिए पार्टी और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। 324 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मुसलमानों का एक वर्ग उनसे नाखुश है क्योंकि यह मुख्यमंत्री उन्हें अनुमति नहीं देता है
उन्हें अशांति फैलाने के बावजूद छूट मिल जाती है। उदाहरण के लिए, इस मुद्दे पर
अमेरिका में पैगंबर का अपमान होने पर, राजनीतिक उपद्रवी तत्व हंगामा खड़ा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे।
दंगा हुआ लेकिन मोदी ने उनसे बहुत सख्ती से निपटा। ऐसे कुटिल तत्व मौजूद हैं
मुसलमान उनसे नाखुश हैं लेकिन पूरा मुस्लिम समुदाय उनसे काफी संतुष्ट है।
मैं उससे खुश हूँ क्योंकि उसने संगठन के भीतर उपद्रवियों को भी दबा दिया है।
हिंदू समुदाय। यदि हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति हंगामा शुरू करता है,
मुस्लिम समुदाय की ओर से भी प्रतिक्रिया आना तय है। इससे विवाद बढ़ेगा।
दोनों तरफ से हमले होंगे तो आग भड़क उठेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री साहब ने यह कहा है।
ऐसे तत्वों को हमेशा सख्ती से दबाने की कोशिश की। उग्र तत्वों हिंदू समुदाय के भीतर के संगठन इस मुख्यमंत्री से खुश नहीं हैं।
वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि 2002 जैसी स्थिति दोबारा न हो।
अगर वह विभाजनकारी किस्म का व्यक्ति होता,
उसे बस इन दोनों समूहों के पेंच ढीले करने थे और हम बच जाते।
बार-बार होने वाले दंगों के दिनों की याद आ गई। कानून और व्यवस्था लागू करने में उनमें अद्भुत क्षमता है।

निष्पक्ष तरीके से। मुसलमानों ने यह समझ लिया है कि उनकी समृद्धि इससे जुड़ी हुई है।
एक दंगा-मुक्त गुजरात के लिए, जिसे केवल इस मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है। असामाजिक गतिविधियों के बाद से
मुसलमानों के बीच मौजूद कुछ तत्वों को दृढ़ता से नियंत्रित किया गया है, इसमें समय लगा है।
इससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो भय था वह दूर हुआ और पूर्वाग्रहों का निवारण हुआ।
इससे दोनों समुदायों के बीच व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ावा मिला।
इसके अलावा, गुजरात सरकार ने लोगों के लिए इसे काफी आसान बना दिया है।
नियमों और विनियमों को सरल बनाकर व्यापार करना और समृद्ध होना, सरकारी नीति कम जटिल और अधिक पारदर्शी है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है।
गुजरात में अच्छा कारोबार करने के लिए राजनीतिक संरक्षकों की आवश्यकता है। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं
ईमानदार व्यवसाय फल-फूल सकता है, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो।
दंगा मुक्त, शिक्षा उन्मुख विकास। इसी तरह, मुझे कच्छ ले जाने वाले मुस्लिम टैक्सी मालिक राजुभाई कहते हैं कि 2001 में उनके पास सिर्फ एक पुरानी टैक्सी थी। आज उनके पास पांच टैक्सियों का बेड़ा है। वे अपने व्यवसाय को इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा सके क्योंकि पर्यटन, जो दस साल पहले तक न के बराबर था, कई गुना बढ़ गया है। गुजरात में पर्यटन और यात्रा सेवाएं चलाने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है। वे कहते हैं:
मैं पिछले 34 सालों से टैक्सी चला रहा हूँ। साल 2000 में, अगर कोई

मैंने अहमदाबाद में घूमने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी, हमें बस कुछ खराब अनुभव हुए।
प्रदर्शन के लिए स्थान बनाए रखे गए थे। यह सब कुछ घंटों में समाप्त हो गया। लेकिन
जिस तरह से मोदी जी ने नई अवसंरचना का निर्माण किया है और विकास किया है
हिंदू और इस्लामी दोनों ऐतिहासिक स्थल न केवल अहमदाबाद को बल्कि पूरे विश्व को ऐतिहासिक बनाते हैं।
शांति और समृद्धि 325

गुजरात, अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित, पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान है। यहाँ देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। अहमदाबाद में ही देखा जा सकता है कि पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और लंबे समय तक ठहरते हैं।
कंकारिया झील इसका एक उदाहरण है। यह एक दुर्गंधयुक्त और सिकुड़ता हुआ तालाब बन गया था।
मोदी जी की सरकार द्वारा इसे पुनर्जीवित करके एक विश्व स्तर पर ले जाने से पहले यह जलमार्ग गंदगी से घिरा हुआ था।
यह एक शानदार पर्यटन स्थल है। परिवार अब इस परिसर में पूरा दिन बिता सकते हैं।
कांग्रेस शासन के दौरान हर साल दंगे होते थे। न तो हिंदू और न ही मुसलमान शांतिपूर्वक अपने सभी त्योहार मना सकते थे। हर समुदाय को ऐसा महसूस हुआ।
त्योहारों के आने पर वे चिंतित और परेशान रहते थे क्योंकि आप कभी भी
दंगा कब भड़केगा, इसका अनुमान लगाया जाता था। लोग जितना हो सके उतना भोजन जमा करने की कोशिश करते थे।

और अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी, दंगे के डर से, जितना हो सके, इकट्ठा कर लिया।
दंगे कभी भी भड़क सकते थे। यह सिर्फ डर का मामला नहीं था - दंगे हमेशा ही भड़क उठते थे।
हर अवसर पर, हिंदू और मुसलमान दोनों ही भय और चिंता की उस स्थिति में रहते थे।
हिंदू त्योहारों के साथ-साथ मुस्लिम त्योहारों पर भी दंगे हुए।
मोहर्रम के दौरान दंगा होता था, रथ यात्रा होती थी तो हंगामा होता था।
दंगा। चाहे ईद हो या दिवाली, ऐसे त्योहारों के साथ हमेशा दंगे होते थे।
हममें से कई लोग भय के साये में जी रहे थे और हर कोई अपने घरों को साफ-सुथरा रखने की कोशिश कर रहा था।
पहले से ही सामान स्टॉक करके रखना चाहिए क्योंकि हर बार दंगे होने पर कर्फ्यू लगाना पड़ता था।
ये कई दिनों तक चलते हैं और कभी-कभी हफ्तों तक भी। इन्होंने सारी बचत खत्म कर दी।
गरीब मुसलमानों की आय में गिरावट आई। 2002 के बाद, मोदी सरकार ने इसने ऐसी शांति (सुकून) ला दी है कि हम सचमुच खुलकर सांस ले पा रहे हैं।
अगर किसी मोहल्ले में कोई छोटी-मोटी घटना हो जाती है, तो दूसरे मोहल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।
इसके बारे में जान लें क्योंकि ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाता है। मोदी
सरकार इस मामले में बेहद सख्त है। नतीजतन, हर कोई रहता है
शांति, सब लोग चैन से सोएं।

मुझे मोदी साहब की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि उन्होंने जबरदस्त प्रोत्साहन दिया है।
गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में आज मुस्लिम समुदाय की लड़कियां न केवल
स्कूल जाने वाले लेकिन बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
इससे मुसलमानों के लिए एक नए प्रकार की सामाजिक उन्नति हुई है। पहले वे
वे अपने बच्चों को 14 या 15 साल की उम्र तक काम पर लगा देते हैं। अब मुस्लिम बच्चे भी काम पर जा रहे हैं।
उच्च शिक्षा के लिए आने वाले छात्रों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
प्रत्येक गाँव और कस्बे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा। आज गुजरात
शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य के रूप में उभर रहा है। मेरे बेटों ने यहीं पढ़ाई की है।
स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की और अच्छा प्रदर्शन किया। एक डेल कंपनी में इंजीनियर है। दूसरा
बेटा भारतीय पुलिस सेवा की तैयारी कर रहा है। तीसरा अभी-अभी उत्तीर्ण हुआ है।
उसकी कक्षा 12 की परीक्षा।
क्योंकि मुस्लिम उद्यम अभूतपूर्व रूप से समृद्ध हो रहे हैं, इसलिए एक बड़ा प्रतिशत
श्रमिक वर्ग का एक हिस्सा सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़कर मध्यम वर्ग बन गया है।
सच्चाई यह है कि जिनके पास 2008 में 20,000 रुपये नहीं थे, आज उनके पास 326 रुपये हैं। मोदी, मुसलमान और मीडिया

20-30 लाख रुपये की कीमत वाले मकान खरीदना। मुझे और क्या सबूत चाहिए?
प्रगति की कमी? यहां तक कि गरीब मुसलमान भी 10 लाख रुपये मूल्य के घर खरीद रहे हैं।
एक ही किस्त में पांच लाख रुपये।
मुस्लिम रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय में दबदबा: गुजरात के हर शहर, कस्बे और गाँव में मुसलमानों की तेज़ी से हो रही प्रगति की ऐसी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण गुजरात के हर राजमार्ग, कस्बे और शहर में मुस्लिम स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट और होटलों की अत्यधिक उच्च संख्या है। ये अधिकतर मेहनती और एकजुट चिलिया मुस्लिम समुदाय के स्वामित्व में हैं, जिनमें से अधिकांश मोदी के अपने शहर वड़नगर और पालनपुर के आसपास के क्षेत्र से आते हैं। उनकी गुजराती बोली को पालनपुरी कहा जाता है।
चिलिया मुस्लिम पारंपरिक रूप से खेती-बाड़ी करते थे और अपने बेटों को मुंबई और पश्चिमी भारत के अन्य शहरों में टैक्सी ड्राइवर या रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करने के लिए भेजते थे। पिछले दस वर्षों में, उनमें से कई अपने गृह राज्य लौट आए हैं और गुजरात के हर राजमार्ग और शहर में रेस्तरां की एक अलग श्रृंखला खोली है, जो अब पड़ोसी राज्यों राजस्थान और महाराष्ट्र में भी फैल रही है। ये आधुनिक, आलीशान भोजनालय हैं, जिनमें वातानुकूलित भोजन कक्ष हैं - ये उत्तर प्रदेश या बिहार में मिलने वाले साधारण ढाबों जैसे नहीं हैं।
चिलिया मुसलमानों को न केवल उनकी आंतरिक एकजुटता और समुदाय के भीतर ऋण जुटाने की क्षमता से मदद मिली है, बल्कि नए उद्यम खोलने के लिए सरकारी नियमों का सरलीकरण और पारदर्शिता भी उनके लिए सहायक

रही है। राजमार्ग पर एक बड़ा रेस्तरां खोलने के लिए न केवल भूमि अधिग्रहण के नियमों में ढील की आवश्यकता होती है, बल्कि भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को भी सरल बनाना पड़ता है। अधिकांश अन्य राज्यों में, इसके लिए राजनीतिक संरक्षण और भारी रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैंने जिन कई चिलिया मुस्लिम रेस्तरां मालिकों से बात की, उन्होंने बताया कि अब भूमि उपयोग परिवर्तन और रेस्तरां लाइसेंस उचित प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ही महीनों में आसानी से मिल जाते हैं।
चूंकि चिलिया के सभी मुस्लिम रेस्तरां केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं, इसलिए मेरे कई वामपंथी मित्रों ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि यह हिंदू कट्टरपंथियों के दबाव के कारण है। चूंकि उन सभी के नाम 'हिंदू जैसे' लगते हैं, इसलिए वामपंथी इसे हिंदू दंगाइयों के हमलों से बचने और पकड़े जाने से बचने का एक बहाना मानते हैं। वास्तव में, जब मैंने पहली बार गोधरा में "तृप्ति" (जिसका अर्थ है 'संतोष') नामक एक मुस्लिम स्वामित्व वाले शाकाहारी रेस्तरां में 90 प्रतिशत से अधिक हिंदू ग्राहकों को देखा, तो मुझे लगा कि यह एक अपवाद है। इसलिए, मैंने ट्विटर पर इस पर अपनी खुशी व्यक्त की।
शांति और समृद्धि 327

एक बार, मुझे आक्रोशित "धर्मनिरपेक्षतावादियों" से कई प्रतिवाद मिले, जिन्होंने कहा कि मैं इस तथ्य के प्रति असंवेदनशील हूं कि मुसलमानों को केवल शाकाहारी भोजन बेचने और 'हिंदू' नामों के पीछे शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था, जो दर्शाता है कि वे अभी भी आतंक के साये में जी रहे हैं।
हालांकि, बाद की यात्राओं के दौरान दर्जनों चिलिया मुस्लिम रेस्तरां और होटल मालिकों से बात करने के बाद, मैंने पाया कि यह

[illegible]
[illegible]
[illegible]

लोग मुफ्त भोजन की उम्मीद में ऐसे रेस्तरांओं पर टूट पड़ते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को 'स्वागत', 'सिद्धि', 'ज्योति', 'पंथी' और 'सर्वोदय' जैसे 'हिंदू' नाम दिए हैं। इस बारे में मैंने जिन रेस्तरां मालिकों से बात की, वे मेरे सवाल पर हैरान दिखे। मुझे जो जवाब मिले, उनका सार यह है: “ये गुजराती शब्द हैं और गुजराती हमारी मातृभाषा है। हम घर पर यही बोलते हैं; स्कूलों और कॉलेजों में यही भाषा पढ़ते हैं। हम न तो उर्दू पढ़ते हैं, न बोलते हैं और न ही इससे हमारा कोई भावनात्मक या बौद्धिक जुड़ाव है। आप गुजराती को हिंदू भाषा क्यों मानते हैं? यह तो सभी गुजरातियों की भाषा है!”
संयोगवश, इन सभी शब्दों की जड़ें संस्कृत में हैं और इसलिए ये गुजराती सहित लगभग सभी भारतीय भाषाओं में आम हैं। चूंकि भाजपा और आरएसएस के कुछ वर्ग संस्कृत को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और इसे अपने स्कूलों में शामिल कर चुके हैं, इसलिए अधिकांश वामपंथियों के लिए संस्कृत का शिक्षण "प्रतिक्रियावादी हिंदुत्व" का पर्याय है। वामपंथियों का "धर्मनिरपेक्ष" एजेंडा 328 मोदी, मुसलमान और मीडिया

अल्पसंख्यकों को 'भिन्नता' का दावा करने के लिए मजबूर करना, भले ही वह मौजूद न हो, और उन्हें उन सभी भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक बंधनों को छोड़ने के लिए प्रेरित करना जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदू बहुसंख्यक वर्ग से जोड़ते हैं, एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों पुराने समरसता और भाईचारे के बंधनों को नष्ट कर रहा है।
मुस्लिम समृद्धि के प्रमुख संकेतक: ज़फ़र सारेवाला, जिनका मैंने पिछले अध्यायों में विस्तार से उल्लेख किया है, को फिर से सुनना

ज़रूरी है। वे सबसे पहले एक व्यवसायी हैं और एक बहुमुखी उद्यमी समुदाय का हिस्सा हैं। इसलिए, गुजरात में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति पर उनकी गहरी नज़र है। वे ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ गुजराती मुसलमानों को आर्थिक रूप से वंचित समुदाय मानने वाली सुस्थापित रूढ़ि को चुनौती देते हैं।
मुसलमान आर्थिक रूप से कभी इतने समृद्ध नहीं रहे जितने वे आज हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
कुछ महत्वपूर्ण संकेत। ज़कात किसी मुसलमान के आचरण को परखने का सबसे आसान पैमाना है।
आपकी आय के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जकात अदा करने के कारण आपकी संपत्ति का प्रोफाइल बेहतर होता है।
ज़कात के रूप में एकत्रित धन का उपयोग मुख्य रूप से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता के लिए किया जाता है।
गरीब परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। मान लीजिए कि इस साल मैंने 2,500 रुपये जकात अदा की, तो आप
मैं तुरंत यह अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी कुल संपत्ति 100,000 रुपये है। अगले साल अगर मैं 100,000 रुपये का भुगतान करता हूँ। 5,000 जकात, इसका मतलब है कि मेरी संपत्ति एक लाख से बढ़कर दो लाख हो गई है।
गुजरात में ज़कात की मात्रा साल दर साल लगातार बढ़ रही है। दरअसल, आप
आपको पता चलेगा कि देश भर के मदरसों की जकात का 50 प्रतिशत हिस्सा आता है।
गुजरात से और शेष 50 प्रतिशत भारत के बाकी हिस्सों से। अगर मोदी ने ऐसा किया होता
मुसलमानों के विनाश के कारण, ज़कात में उनका हिस्सा कम होना चाहिए था। लेकिन पिछले दस वर्षों में

पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों की संपत्ति में वृद्धि हुई है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण संकेतक दूंगा, जो बीएमडब्ल्यू की बिक्री के आंकड़ों से संबंधित है: हम बेचते हैं
बीएमडब्ल्यू कारें। सबसे सस्ती बीएमडब्ल्यू 30 लाख रुपये में उपलब्ध है; सबसे महंगी 30 लाख रुपये तक जाती है।
1.5 करोड़। जब हमने बीएमडब्ल्यू डीलरशिप शुरू की थी, तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम
इन कारों में से दो से पाँच से अधिक कारें मुसलमानों को बेची जा सकती थीं। पिछले साल, 2011 में,
हमने अपनी 11 प्रतिशत बीएमडब्ल्यू कारें मुसलमानों को बेचीं। मुसलमानों की जनसंख्या
गुजरात में यह 9 प्रतिशत है। इस साल भी हमने बिक्री का यह आंकड़ा बरकरार रखा; हमने बिक्री की।
मुसलमानों को लगभग 59 बीएमडब्ल्यू कारें बेची गईं। आखिर इतनी दौलत उनके पास आई कहां से?
अहमदाबाद या भरूच के किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में जाइए, आपको भारी संख्या में मुस्लिम बहुल लोग मिलेंगे।
वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान हाशिए पर हैं, वे गलत हैं।
चाहे वह झुग्गी-झोपड़ी में बसा हो या झुग्गी-झोपड़ी में, यह समझना जरूरी है कि झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में भी घर बनाना मुश्किल होता है।
इस इलाके में आपको पैसे की जरूरत होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीन की कीमतें बेहद बढ़ गई हैं।
किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में आपको 50,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से कम कीमत पर जमीन नहीं मिल सकती।
शांति और समृद्धि के बारे में 329

वर्ग गज; यह किसी भी हिंदू क्षेत्र से अधिक है। पालडी में, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ है
5 करोड़ रुपये से कम में कोई बंगला नहीं मिल रहा है। ये बंगले मुसलमान खरीद रहे हैं।
यह सारा पैसा कहाँ से आया है?
यह आरोप लगाया जाता है कि केवल धनी मुसलमान ही मोदी समर्थक हैं। इसे इस तरह समझिए:
मेरे व्यवसाय से 250 लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, जिनमें से 230 मुसलमान हैं।
इसी तरह लोग कहते हैं कि मोदी ने टाटा को बहुत लाभ पहुंचाया है। लेकिन 10,000
टाटा समूह में प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलता है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार सृजित होता है।
टाटा प्लांट की वजह से। क्या आपको लगता है कि टाटा में सिर्फ हिंदू ही काम करते हैं?
जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन में मोदी गुजरात में नए निवेश लेकर आए। मुझे लगता है
गुजरात के आधे से अधिक परिवारों को इन नए निवेशों से लाभ मिलता है।
समान अवसर केवल एक ईमानदार सरकार द्वारा ही दिए जाते हैं। मोदी के पास एक ईमानदार सरकार है।
व्यापार और उद्योगों के संबंध में सरल नीति, और सब कुछ इसी के इर्द-गिर्द घूमता है।
उस नीति के इर्द-गिर्द। चाहे आप काले हों, गोरे हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, कुछ भी हों,

सरकार द्वारा केवल दो महत्वपूर्ण मापदंडों को ही ध्यान में रखा जाता है:
आपके द्वारा निवेश की गई राशि और आपके द्वारा सृजित की जाने वाली नौकरियों की संख्या के बीच का समीकरण
उत्पन्न करना। उनके द्वारा स्पष्ट एकल खिड़की निकासी नीति लागू करना।
निवेश और उद्यमों के लिए किए गए प्रयासों ने छोटे उद्यमियों को अन्य उद्यमियों की तुलना में कहीं अधिक मदद की है।
बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ। ये कंपनियाँ अपने पक्ष में फैसले मोड़ने में कामयाब हो जाती हैं।
रिश्वतखोरी और भ्रष्ट शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से आसानी। लेकिन
जब भ्रष्टाचार नीतियों और निर्णयों पर हावी हो जाता है तो छोटे व्यवसायी को नुकसान उठाना पड़ता है।
इसीलिए भारत के अधिकांश हिस्सों में लघु एवं मध्यम उद्यम
लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) संकट में हैं और ढह रहे हैं। वहीं गुजरात में वे बढ़ रहे हैं और फल-फूल रहे हैं।
अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लाइसेंस-कोटा के पूर्ण कार्यान्वयन के दौरान भी खूब तरक्की की।
राज और टाटा समूह, दोनों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे विशाल पैमाने पर काम करते हैं और टिके रह सकते हैं।
नौकरशाही की दमनकारी कार्रवाइयां। लेकिन कानून का शासन और एक पारदर्शी नीति जो देती है
सभी के लिए समान अवसर होने से सबसे अधिक लाभ छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को होता है।
यह सर्वविदित है कि अधिकांश मुस्लिम व्यापारी छोटे व्यवसायों में केंद्रित हैं,

मध्यम और सूक्ष्म उद्यम। जबकि कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी हालांकि उनका हिस्सा नौ प्रतिशत है, लेकिन लघु एवं मध्यम उद्यमों में उनका हिस्सा आनुपातिक रूप से कहीं अधिक है, लगभग 22 प्रतिशत। आज गुजरात में मुसलमानों को किसी प्रकार की परेशानी या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है।
गुजरात में उद्यम स्थापित करने के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करना।
अन्यथा मुसलमान इतनी समृद्धि हासिल नहीं कर पाते जितनी उन्होंने की है।
मैं ऐसे कई मुस्लिम उद्यमियों को जानता हूँ जिनकी संपत्ति 50 करोड़ रुपये थी।
2002 में इनकी संपत्ति 500 करोड़ रुपये थी, लेकिन आज यह 500 करोड़ रुपये की है। मुसलमान तेजी से समृद्ध हो रहे हैं।
हिंदुओं की तुलना में उनकी विकास दर अधिक तेज़ है क्योंकि उनके अधिकांश व्यापार और व्यवसाय हिंदुओं से अधिक प्रचलित हैं।
जिन गतिविधियों में वे लगे हुए हैं, वे राजनीतिक स्थिरता और प्रोत्साहन के कारण फल-फूल रही हैं।
छोटे उद्यमी और कृषि। मुसलमानों में कहीं अधिक तेजी से विकास हो रहा है।
हिंदू समकक्षों की तुलना में उनके पास सामाजिक उन्नति के अधिक अवसर होते हैं।
330 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मोदी का एक सरल सूत्र है। कानून के समक्ष सभी समान हैं। अपने अधिकारों का सम्मान करें।
नागरिको। हिंदू या मुसलमान होने के कारण इस या उस रियायत की मांग न करें।

या आपकी जाति या समुदाय के आधार पर।
इससे मुझे कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के उस बयान की याद आ गई, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कहा था कि दूसरे राज्यों के मुसलमान भी गुजरात को निवेश के लिए बेहद अनुकूल पा रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद या मलयाली समुदाय के एक मुसलमान का उदाहरण दिया, जो गुजरात में अपना नया कारोबार शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने के बाद बेहद खुश होकर लौटा था। लेकिन मौलाना मदनी की तरह, अखबारों में छपने पर उन्होंने तुरंत अपना बयान वापस ले लिया, क्योंकि कांग्रेस और अन्य "धर्मनिरपेक्ष" पार्टियों ने तुरंत उनकी आलोचना शुरू कर दी थी। ज़फ़र के विवरण को आगे बढ़ाते हुए:
गुजरात में लघु एवं मध्यम उद्यमों की विकास दर 75% से अधिक रही है।
पिछले दशक में प्रतिशत। मैं आपको इसका कारण समझाऊंगा। छोटा और मध्यम आकार के उद्यम बड़े उद्योगों के आसपास विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब टाटा
जब उन्होंने अपना नैनो कार प्लांट स्थापित किया, तो इससे कई सहायक उद्योगों के लिए जगह बन गई।
टाटा समूह को पुर्जे सप्लाई करने के लिए। एक कार कंपनी मूल रूप से एक असेंबली यूनिट होती है।
उन्हें ब्रेक पैड एक स्रोत से मिलते हैं, वाइपर दूसरे स्रोत से।
उन्हें ज़रूरत है
ऐसे सैकड़ों घटक।
गुजरात का विनिर्माण विकास मॉडल, आईटी विकास मॉडल से बेहतर है।
बेंगलुरु का विकास। आईटी मॉडल में, यदि दस लाख कर्मचारी हैं, तो प्रत्येक
सालाना 30-40 लाख रुपये कमाना—वह वेतन सीधे बैंक में जाता है।

निम्न स्तरों तक काफी हद तक रिसता है; उनकी जीवनशैली से सीमित संख्या में लोगों को ही लाभ होता है।
विनिर्माण क्षेत्र में हर एक नौकरी से दस अतिरिक्त कमाने वालों का सृजन होता है।
इसका असर सबसे निचले स्तर तक पहुंचता है। जब मोदी ने कॉरपोरेट जगत को शामिल किया।
निवेश से सहायक उद्योगों का विकास हुआ और इससे समर्थन मिला। सहायक विकास के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्यम भी आए। गुजरात हमेशा से ही
उद्योग जगत के अनुकूल। मोदी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की; उन्होंने केवल व्यवस्थाओं में सुधार किया।
इसे खिलाने के लिए।
भारत के अधिकांश शहरों में, औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में बहुत ही झुग्गी-झोपड़ियां हैं।
यहां तक कि दिल्ली में भी, ओखला या वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं।
आँखों को चुभने वाली इमारतें, साथ ही श्रमिक वर्ग के लिए दयनीय झुग्गी-झोपड़ियाँ। आज गुजरात का
औद्योगिक विकास से झुग्गी-झोपड़ी जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही हैं। गुजरात
औद्योगिक विकास केंद्र (जीआईडीसी) इन्हें "औद्योगिक क्लस्टर" कहता है।
मोदी के शासनकाल में विकसित की गई नई परियोजनाएं- जैसे कि ऑटोमोबाइल पार्क-
ये विश्व स्तरीय हैं। कृपया जाकर इन्हें देखें। मेरा अपना परिवार भी इसी छोटे समूह से संबंधित है।
शांति और समृद्धि के बारे में 331

और मध्यम उद्यम क्षेत्र। हम वाल्वों के निर्माण में लगे हुए हैं।
कई अन्य सुन्नी बोहरा भी हैं। हम एक छोटे पैमाने के समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
एक उद्योग दूसरे उद्योग को आपूर्ति करता है। बिजली की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है।
गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में समस्या है। सड़कें विश्व स्तरीय हैं और कुल मिलाकर स्थिति बेहतर है।
बुनियादी ढांचा विकास के अनुकूल है। यहां तक कि स्वच्छता भी बहुत अच्छी है।
कुछ खास क्षेत्रों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। मोदी किसी एक या उस छोटे या बड़े निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं।
वह वही कर रहे हैं जिसकी आज भारत को आवश्यकता है।
अधिकांश मुसलमान इस बात से खुश हैं कि मोदी कभी भी विभाजनकारी रणनीति का इस्तेमाल नहीं करते।
किसी विशेष समुदाय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, के लिए यह या वह प्रलोभन
यह हमेशा छह करोड़ गुजरातियों को संबोधित करता है। मुसलमानों की बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
अलग से। मुझे बताइए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं, तो क्या वे संबोधित करते हैं?
अश्वेत, श्वेत, हिस्पैनिक, भारतीय, पाकिस्तानी, चीनी या कोरियाई अलग-अलग? अगर वह ऐसा करता, तो उसे केवल गिनती रखने में ही घंटों लग जाते।
विभिन्न समूहों की बात कर रहे हैं। वे सभी अमेरिकियों की बात कर रहे हैं। मेरे विचार से, यह अच्छी बात है कि मोदी

सभी गुजरातियों की बात करता है और उनके लिए काम करता है। मुसलमान अपने पद को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं।
सभी के लिए सृजित अवसरों में से उचित हिस्सा।
गुजरात शिखर सम्मेलन 2013 में, आपने स्वयं मोदी को इस बारे में विस्तार से बात करते हुए सुना था।
लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना। मोदी जिस लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की बात कर रहे थे, वह है...
यह मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र है। आप पाएंगे कि प्रत्येक सुन्नी बोहरा के पास एक संपत्ति है।
एक लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और मोदी ऐसे और अधिक एसएमई बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में ध्यान केंद्रित किया है।
आईटीआई (भारतीय तकनीकी संस्थान) के विकास पर। मुझे बताएं कि अन्य कौन से प्रमुख
क्या मंत्री जी भी आईटीआई पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना मोदी? वे सभी एक
आईआईएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) या आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी)
या फिर अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज। मोदी इससे कहीं आगे जाते हैं।
और आईटीआई के लिए काम करता है। आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कौन हैं? अधिकतर तो
कारीगर जातियों और वर्गों से आने वाले गरीब मुस्लिम बच्चों को। इसीलिए हम
मोदी से कहिए, कृपया मुसलमानों के नाम पर कुछ भी विशेष न करें, बल्कि

यह सबके लिए करो। हम सुनिश्चित करेंगे कि हम "सब" में शामिल हों और हमें हमारा हिस्सा मिले।
इसी तरह, मैं अपने समुदाय से कहता हूं, अगर आप बस में चढ़ना चाहते हैं तो पहले चढ़ना होगा।
अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। अगर आप बस में नहीं चढ़ेंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे?
आपका गंतव्य स्थान?
मैं सभी मुसलमानों से सीधे तौर पर कहता हूं, यदि आप अपनी प्रतिभाओं को विकसित करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं,
इस दुनिया के अशोक सिंघल जैसे लोग भी आपको आपका हक देंगे। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
उदाहरण: यदि अशोक सिंघल साहब के पास एक हेलीकॉप्टर होता जिसके लिए उन्हें चयन करना होता
दो उपलब्ध पायलटों में से पहला मोहम्मद खान नाम का एक कश्मीरी पायलट है।
जिसके पास 500 घंटे का उड़ान अनुभव है और दूसरा गंगा राम है। उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण जिसके पास मात्र 50 घंटे हैं। आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताइए, कौन
अशोक सिंघल अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए किसे चुनेंगे?
332 मोदी, मुसलमान और मीडिया

जब मैंने इस बीएमडब्ल्यू डीलरशिप को उस समय के अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल में देखा।
गुजरात में, मुझे अपने व्यापारिक भविष्य को लेकर बहुत चिंता थी। हमने सोचा था
कि इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के खरीदार मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू ही होने की संभावना है।

सरकार द्वारा छात्रवृत्ति में मुसलमानों के लिए एक विशेष कोटा निर्धारित करना।
लेकिन मोदी ने जो किया है वह कहीं बेहतर है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार
सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए बहुचर्चित छात्रवृत्ति कोष में दिया गया योगदान
यह राशि 3.75 करोड़ रुपये है, जबकि राज्य का योगदान 1.25 करोड़ रुपये होना चाहिए।
करोड़ों रुपये। यह राशि 55,000 मुस्लिम छात्रों में वितरित की जानी है; यह राशि आती है
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 900 रुपये से थोड़ा अधिक। क्या यह इतना बड़ा लाभ है जिसका ढोल पीटना चाहिए?
इसके विपरीत, गुजरात सरकार की अपनी छात्रवृत्ति योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसके अंतर्गत 63,000 मुस्लिम छात्र शामिल हैं।
प्रत्येक वर्ष लगभग 2,600 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। अधिकांश मुस्लिम
परिवार और स्कूल केंद्र सरकार की योजना में शामिल होने से इनकार करते हैं क्योंकि
इसमें मामूली रकम के लिए अंतहीन कागजी कार्रवाई और नौकरशाही प्रक्रियाएं शामिल हैं।
प्रति वर्ष 900 रुपये। इसके विपरीत, गुजरात सरकार का तीन गुना बड़ा
प्रक्रिया को सरल बना दिए जाने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त करना अब परेशानी मुक्त है।
इसे आसानी से सुलभ बनाएं।

सच्चर समिति द्वारा गुजरात को दिया गया प्रमाण पत्र: यूपीए सरकार द्वारा 2005 में भारत के विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की स्थिति का आकलन करने के लिए नियुक्त की गई सच्चर समिति भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि गुजराती मुसलमान शैक्षिक और आर्थिक रूप से कहीं बेहतर स्थिति में हैं।
शांति और समृद्धि के बारे में 333

भारत के अधिकांश अन्य हिस्सों की तुलना में गुजरात में मुसलमानों की गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता दर अखिल भारतीय आंकड़ों के साथ-साथ कांग्रेस या वामपंथी शासित राज्यों के आंकड़ों से भी काफी कम पाई गई। उदाहरण के लिए, जब केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी दर मात्र एक प्रतिशत है, तो यह दर्शाता है कि मुसलमानों में बेरोजगारी नगण्य है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल आदि राज्यों से लाखों मुसलमान गुजरात में कार्यरत हैं। कोई राज्य प्रवासी श्रमिकों को तभी आकर्षित करना शुरू करता है, जब वह तेजी से विकास कर रहा हो और उसे राज्य के भीतर उपलब्ध श्रमिकों और पेशेवरों से अधिक श्रमिकों और पेशेवरों की आवश्यकता हो।
भारत भर में मुसलमानों की साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत थी, जबकि गुजरात में यह 73.5 प्रतिशत थी। 2006 में शहरी मुसलमानों में साक्षरता दर 76 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में गुजराती मुसलमानों की साक्षरता दर 69 प्रतिशत थी, जबकि अखिल भारतीय औसत 59 प्रतिशत था। तब से स्कूली शिक्षा में सुधार और बच्चों के 100 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए भारी निवेश के कारण इसमें काफी वृद्धि हुई है। आज शायद ही कोई ऐसा गाँव हो जहाँ स्कूल आसानी से न मिल सके। गुजरात

[illegible]

[illegible] 2011-2012 [illegible] 26.9 [illegible] 7.7 [illegible] 28.6 [illegible] 34 [illegible] 40.2 [illegible] 23.9 [illegible] 28.4 [illegible]

2. [illegible]

[illegible] "[illegible]: [illegible]", [illegible] 2009 [illegible]: http://www.india-seminar.com/2009/602/602_d_l_sheth.htm

सरकारी नौकरियों की बात करें तो, गुजरात में 9.1 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के साथ, उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियों में से 7.9 प्रतिशत पर गुजरात के मुसलमानों का कब्जा है। इसके विपरीत, वामपंथी गढ़ केरल में, 24.7 प्रतिशत मुसलमानों के पास उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियों में से केवल 7.3 प्रतिशत हैं; महाराष्ट्र में 10.6 प्रतिशत मुसलमानों के पास केवल 1.9 प्रतिशत हैं; दिल्ली में 11.7 प्रतिशत मुसलमानों के पास मात्र 4 प्रतिशत हैं; कर्नाटक में 12.2 प्रतिशत मुसलमानों के पास 2.1 प्रतिशत हैं; असम में 30.9 प्रतिशत मुसलमानों के पास उच्च स्तरीय सरकारी पदों में से केवल दो प्रतिशत हैं। ये सभी कांग्रेस शासित राज्य हैं।
गुजरात में ग्रामीण मुसलमानों की औसत प्रति व्यक्ति आय 668 रुपये थी, जो ग्रामीण हिंदुओं की औसत प्रति व्यक्ति आय 644 रुपये से अधिक थी। बिहार में यह आंकड़ा 426 रुपये, बंगाल में 501 रुपये, उत्तर प्रदेश में 509 रुपये और आंध्र प्रदेश में 610 रुपये था। इसी प्रकार, गुजरात के शहरी मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय 875 रुपये थी, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी। बंगाल में यह 748 रुपये और बिहार में 551 रुपये थी। सच्चर समिति के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुसलमानों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता गुजरात में अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, साथ ही उद्योग, व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व भी अधिक है।
शहरी मुसलमानों में गरीबी की बात करें तो गुजरात में गरीबी दर देश में पांचवीं सबसे कम है, जहां 14.6 प्रतिशत मुसलमान गरीब श्रेणी में आते हैं। वहीं, दिल्ली में यह दर 33.5 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 15.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 36.4 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में

35.5 प्रतिशत और कर्नाटक में 24.5 प्रतिशत है। बिहार में यह दर सबसे अधिक 51.1 प्रतिशत है। अखिल भारतीय औसत 22.7 प्रतिशत है। कोटा और आरक्षण को निरर्थक बनाना: चूंकि मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिशत हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योगों में लगे कारीगर समुदायों से आता है, इसलिए उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों में सरकार द्वारा किए गए बड़े निवेश से सबसे अधिक लाभ हुआ है। ज़फ़र के कथन को आगे बढ़ाते हुए:
गुजरात सरकार ने 30 छात्रों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की थी।
वर्षों तक कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन मोदी ने कौशल विकास में भारी निवेश किया है।
विकास और उच्च शिक्षा। 2001 में, यहाँ केवल 11 विश्वविद्यालय थे।
गुजरात; आज गुजरात में 44 विश्वविद्यालय हैं। यह दस वर्षों के भीतर हुआ है।
2002 में इंजीनियरिंग के लिए 2,500-3,000 सीटें थीं, अब 55,000 सीटें हैं।
साधारण परिवारों के मुसलमानों समेत, सभी ने तुरंत इस ओर रुख किया है।
उच्च शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों के लिए, भले ही पहले मुस्लिम परिवार
उच्च शिक्षा पर खर्च करने में अनिच्छुक थे। इसका कारण यह है कि उनमें से अधिकांश
नए व्यवसायों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
शांति और समृद्धि के बारे में 335

हाल ही में मेरी मुलाकात एक युवा मुस्लिम से हुई जो आईआईएम से पीएचडी कर रहा है, हालांकि वह

वह एक गरीब परिवार से हैं। उन्होंने कैमरे पर कहा, "मोदी साहब ने शिक्षा को
गरीब गुजरातियों के लिए भी सुलभ। एक समय था जब अहमदाबाद के लोग पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। अब यहाँ दस इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।
अहमदाबाद में ही। इसीलिए मुझे अपने गृह नगर में बहुत आसानी से दाखिला मिल गया।”
परिवार के पास उसे निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे।
किसी अन्य राज्य में।
गुजरात के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस लगभग 15,000 रुपये है।
जबकि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में यह प्रति वर्ष 50,000-55,000 रुपये है।
इससे यह लगभग चार गुना अधिक हो जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कॉलेज।
कर्नाटक आदि तो और भी अधिक महंगे हैं। हर समुदाय को इससे लाभ हुआ है।
शिक्षा के अवसरों में यह व्यापक विस्तार।
जिन छात्रों को दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे, वे अब यहीं रह सकते हैं।
घर पर रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें। हमारे समाज में, चाहे आप हिंदू हों या
मुस्लिम होने के नाते, अधिकांश माता-पिता अपनी बेटियों को छात्रावास में रहने के लिए भेजने से हिचकिचाते हैं।
वे कहते हैं कि अगर आपको शहर के भीतर प्रवेश मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हम

हम आपको दूर-दराज के राज्यों में नहीं भेजना चाहते। अब कई मुस्लिम लड़कियां शुरू हो गई हैं।
वे चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रवेश मिल सकता है।
आज तो निम्न मध्यम वर्ग के मुस्लिम परिवारों के बच्चे भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं।
वे अपने बेटों और बेटियों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा या आईटी की पढ़ाई के लिए भेजते हैं।
चूंकि गुजरात सरकार ने रखरखाव की नीति को समाप्त कर दिया है व्यावसायिक कॉलेजों में सीटों की कमी है, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।
और कोटा। हमारे व्यावसायिक कॉलेजों में इतनी अधिक अतिरिक्त सीटें हैं कि
कई सीटें खाली रह जाती हैं। 2012 में इंजीनियरिंग के लिए 55,000 सीटें थीं।
प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने पर सभी सीटें भर जाने के बाद 5,000 सीटें शेष रह गईं।
गुजरात के निवासियों द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुसलमानों को कहीं बेहतर शिक्षा मिल रही है।
आज गुजरात में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अवसर मौजूद हैं, और इसके लिए कोटा की आवश्यकता भी नहीं है।
मोदी अभाव की राजनीति नहीं खेलते, जो किसी एक समुदाय को निशाना बनाती है।
वह एक दूसरे के विरुद्ध। वह प्रचुरता की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है ताकि हर किसी को उसका हिस्सा मिल सके।
बिना दूसरों से झगड़ा किए अपना कर्तव्य निभाएं।
इसी प्रकार, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वाला गरीब मुसलमान या

गुजरात में दंगा-मुक्त माहौल से सबसे ज्यादा फायदा ऑटो रिक्शा चालक को हुआ है।
कानून का शासन पूरी तरह से स्थापित है।
पिछले 20 वर्षों से सड़क विक्रेताओं को कानूनी दर्जा दिलाने की लड़ाई में शामिल रहने के बाद, गुजरात के कई कस्बों और शहरों में सुरक्षित फेरी लगाने वाले क्षेत्र पाकर मुझे संतोष हुआ। आसिफा ने मुझे अहमदाबाद के मुस्लिम सड़क विक्रेताओं के एक बड़े समूह से मिलवाया, जो 336 मोदी, मुस्लिम और मीडिया के प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए थे।

नरेंद्र मोदी ने उस समय मुलाकात की जब एक प्राचीन मंदिर के आसपास के क्षेत्र का व्यापक सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास किया जाना था, जहां वे अपना व्यवसाय करते हैं। मोदी ने न केवल उन्हें न हटाने का आश्वासन दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि क्षेत्र की विकास योजना में सड़क विक्रेताओं के लिए सम्मानजनक और बेहतर कानूनी स्थान शामिल हों। उन्होंने उनसे कहा कि गुजरात विक्रेताओं के लिए सर्वोत्तम संभव व्यवस्था करेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस वादे के वास्तविक परिणाम का पता चलेगा।
ज़फ़र के वृत्तांत को जारी रखने के लिए:
जो लोग धनी हैं, वे तो वोट डालने भी नहीं जाते, वोट तो गरीब ही डालते हैं।
मोदी को वोट देने वाली 31 प्रतिशत मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से गरीब वर्गों के लिए। धनी मुसलमान अब भी मतदान करने में शर्म महसूस करते हैं।
भाजपा के लिए। हाल ही में, मैंने खुद जाकर देखने का फैसला किया कि वहां क्या हो रहा है।

सौराष्ट्र। मैं और मेरा परिवार गांवों से होते हुए सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए सौराष्ट्र तक पहुंचे।
गिर यात्रा, राजकोट और जामनगर में रुकते हुए। मुझे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक समर्थक है-
विसावदर के केंद्र में स्थित जूनागढ़ में भी मोदी लहर देखी जा रही है, जो मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है।
केशूभाई पटेल की कहानी। एक राजनीतिक नेता आम नागरिकों के लिए नायक बन जाता है।
क्योंकि उसने लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है, उनके जीवन को बेहतर बनाया है, न कि
क्योंकि वह आकर्षक है या मर्दाना है। इलाके की सड़कें खूबसूरत हैं।
इनमें वे सड़कें भी शामिल हैं जो आंतरिक गांवों तक जाती हैं। जूनागढ़ तक छह लेन की सड़कें हैं।
roads. My wife was asking me, “Kache makaan nahi hain yahan par?” Are there no
इन गांवों में मिट्टी के घर?) एक छोटे से गांव के इस बदलाव पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था।
जूनागढ़ जैसा शहर इतने कम समय में इतना विकसित हो गया है कि अब यह काफी समृद्ध हो चुका है।
आपको भारत के छोटे शहरों में पाए जाने वाले आम जर्जर घर यहाँ देखने को नहीं मिलते।
हमें आधुनिक नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित नए, सुदृढ़ रूप से निर्मित घरों की कतारें ही कतारें दिखाई दीं।
मुझे कूड़े के ढेर नहीं दिखे जो कि अधिकांश भारतीय कस्बों और शहरों में आम तौर पर देखने को मिलते हैं।

सक्करबाग चिड़ियाघर की स्थापना जूनागढ़ के पूर्व नवाब ने 1963 में की थी।
एक समय में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन फिर बुरे दिन आने लगे। पिछले दस वर्षों में, यह
चिड़ियाघर को भी उसके पुराने वैभव में बहाल कर दिया गया है। पिछले साल उन्होंने अपनी 150 वीं वर्षगांठ मनाई थी।
सालगिरह। मेरे बच्चे चिड़ियाघर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि
मैंने मुंबई और लंदन के चिड़ियाघर देखे, लेकिन मुझे दोनों में से कोई भी घूमने लायक नहीं लगा।
जब वे जूनागढ़ चिड़ियाघर देखने गए, तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, “पापा,
अविश्वसनीय! हम इतनी असाधारण चीज़ को खो देते और हमें इसका बहुत अफसोस होता।
अगर हम आपके साथ नहीं आए होते तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती।” इसे देखने के बाद ही आप इस पर विश्वास कर पाएंगे। इन्होंने शेरों, बाघों, दरियाई घोड़ों आदि के लिए एक अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।
शुतुरमुर्ग और अन्य जानवर। अब यह जगह साफ-सुथरी और देखने में सुंदर है।
जानवर स्वस्थ हैं क्योंकि उन्हें उचित पेशेवर देखभाल मिलती है। शांति और समृद्धि के बारे में 337

वह दुर्गंध और गंदगी जो आमतौर पर भारतीय चिड़ियाघरों में पाई जाती है। यह इस बात का प्रतिबिंब था कि...
इस जगह के प्रबंधन के लिए चुने गए लोगों का प्रकार। यहां तक कि चिड़ियाघर का गाइड भी।

वह बहुत ही योग्य थे; एक प्रशिक्षित प्राणी विज्ञानी, बहुत ही पेशेवर और बहुत ही कुशल।
जब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कुशल होता है, तो अच्छा प्रशासन नीचे तक प्रभावी होता है।
to the very bottom. I always believe in the dictum, jaisa raja vaisi praja. Jaisa
chief minister ya prime minister, uska reflection hota hai neeche (the quality
नागरिकों की गुणवत्ता शासकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसे हमने गिर यात्रा के लिए ड्राइवर के रूप में किराए पर लिया था, कि ऐसा क्यों था।
वे मोदी समर्थक हैं क्योंकि वह क्षेत्र कभी केशूभाई पटेल का गढ़ हुआ करता था।
उन्होंने जवाब दिया, 'अगर मोदी सत्ता में नहीं आते, तो हम कुचले ही रह जाते।'
उस क्षेत्र में पटेल समुदाय प्रमुख है। बाकी अधिकांश लोग अन्य समुदायों से हैं।
दरबार समुदाय कहीं अधिक गरीब था।
मोदी ने उन लोगों के जीवन में बदलाव लाया है जिनके पास जमीन नहीं थी या
पुराने व्यापारिक नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि मोदी ने उन्हें कोई रियायत दी हो। उदाहरण के लिए, यह
दरबार समुदाय के एक ड्राइवर ने कहा, “पहले मैं जीप चलाता था और कमाता था।”
5,000 रुपये प्रति माह। लेकिन जब से मोदी ने अपनी "खुशबू गुजरात की" योजना शुरू की है...

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है।
हमारे क्षेत्र में भी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मैं और कई अन्य लोग
जो लोग पहले नौकरी की तलाश में गांव से बाहर पलायन करते थे, उन्होंने अब अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर लिया है।
गांव में पर्यटक रिसॉर्ट हैं। आज मुझे थोड़ी-बहुत कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता।
मैं दूसरों के यहाँ काम करता हूँ; मैं अपने फार्म पर एक सफल रिसॉर्ट चलाता हूँ।3
गिर का जंगल सदियों से मौजूद है। लेकिन इसके बारे में कौन जानता था?
मोदी ने आंतरिक क्षेत्रों तक विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण किया, पुराने भवनों का जीर्णोद्धार किया
गुजरात ने स्मारकों का दौरा किया है और एक अभिनव पर्यटन अभियान शुरू किया है।
अचानक एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। आज 50 प्रतिशत पर्यटक
भारत से आने वाले लोगों का प्रवाह गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जहां पहले इसकी उपस्थिति नगण्य थी।
दस साल पहले के पर्यटन मानचित्र में इसका जिक्र है। इससे दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व समृद्धि आई है।
हिंदू और मुसलमान।
धनवान लोग किसी भी शासन व्यवस्था में फलने-फूलने का तरीका जानते हैं। बहु-
राष्ट्रीय निगमों को यह पता है कि दुर्गम क्षेत्रों में भी व्यापार कैसे किया जाता है।

अफ्रीका में गरीब आदमी, छोटा उद्यमी जीवन में तभी आगे बढ़ सकता है जब वह
एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनहितैषी शासन प्रदान करती है और भेदभाव नहीं करती।
नागरिकों के विभिन्न समूहों के बीच। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट जगत को इसकी परवाह नहीं है।
चाहे कोई देश लोकतांत्रिक हो या तानाशाही। लेकिन असली लाभार्थी कौन है?
शांति और बहुमुखी शासन के नए द्वार उन गरीबों के लिए खुले हैं जिनके लिए
अवसर खुलते हैं।
3 मैंने इस कहानी का अनुसरण किया और गिर जंगल में इस और अन्य गांवों का दौरा किया और आशा है कि
मैंने जो देखा और सुना है, उसे मैं एक अन्य पुस्तक में साझा करूंगा।

अध्याय 19

Hindu Hriday Samrat or
भारत के नए महमूद गजनवी?
गुजरात में हिंदू-मुस्लिम संबंधों की मिथक बनाम वास्तविकता

मीडिया उन लोगों से बात करना पसंद करता है जिन्होंने दूसरों की समस्याओं को अपना व्यवसाय बना लिया है। मैं ऐसे लोगों को दुख का सौदागर कहता हूँ – अगर उनकी दुकानें बंद हो जाएँ तो हमारा देश कहीं अधिक शांतिपूर्ण होगा और अंतर-सामुदायिक संबंध फिर से सौहार्दपूर्ण हो जाएँगे।
मुझे मौलाना आजाद के वे शब्द याद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का विकल्प चुनने वाले मुसलमानों से अपनी मातृभूमि, अपने वतन को न छोड़ने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली के बाद कोई भी इस्लाम के आधार पर मुसलमानों को एकजुट करने में सफल नहीं हुआ है। संस्कृति और भाषा धर्म से कहीं अधिक मजबूत बंधनकारी कारक हैं…
Zafar Sareshwala

गुजरात की जनता, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, के बीच मोदी की लोकप्रियता स्पष्ट है, लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि संघ परिवार के भीतर मोदी को भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। अहमदाबाद के व्यवसायी ज़फ़र सरेशवाला बताते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट (हिंदुओं के दिलों के बादशाह) बजरंग दल जैसे संगठनों के सदस्यों, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेताओं और भाजपा और आरएसएस के कुछ वर्गों के बीच इतना आक्रोश क्यों पैदा करते हैं।

मोदी ने पार्टी नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के रवैये में व्यापक बदलाव लाया है।
उन्होंने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है। लेकिन कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं।
भाजपा के कुछ ऐसे तत्व हैं जो इससे खुश नहीं हैं। वही लोग शिकायत कर रहे हैं।
मोदी को तानाशाह कहे जाने का आरोप है। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) का है।
बजरंग दल और आरएसएस के वे वर्ग जो मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 339

कुछ महीने पहले, मैं एक टीवी बहस में था और मैंने देखा कि आरएसएस का पूरा दल बेकाबू होकर चिल्ला रहा था और
मोदी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। फिर अचानक जब मोदी जीत गए, तो उन्होंने कहा कि यही सही तरीका है।
हमारी विचारधारा की जीत। मैंने टीवी पर कहा था, नहीं, यह आपकी जीत नहीं है। यह आपकी जीत नहीं है।
वह विचारधारा जो विजयी हुई। यह मोदी की जीत है। आप उन्हें सत्ता से हटाने के लिए हर हाल में तुले हुए थे।
हार गए! मैंने उनके सामने ही कहा था, तुम लोग उसे नष्ट करने के लिए वहाँ आए थे, तुम
उसके खिलाफ काम कर रहे थे।
आइए मैं आपको आरएसएस के उन तत्वों का एक उदाहरण देता हूं जो मोदी के साथ मतभेद रखते हैं।
मैं पाल्दी में रहता हूँ, जहाँ धनी और प्रतिष्ठित मुसलमानों ने घर खरीदे हैं।

घरों में। हमारी संख्या बहुत कम है, शायद कुल मतदाताओं का पाँच प्रतिशत।
उस क्षेत्र में। यह परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ रहा है और कांग्रेस विरोधी रहा है।
कई वर्षों से। हरेन पंड्या पालडी के एक प्रसिद्ध विधायक थे। इस बार, गुजरात
Parivartan Party (GPP) of Keshubhai Patel (former BJP chief minister and
आरएसएस के एक सदस्य ने हरेन पंड्या की पत्नी जागृति पंड्या को अपना उम्मीदवार बनाया था।
भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ। जीडीपी के पर्चे में पूछा गया: "मोदी के राज में ऐसा कैसे हो सकता है?"
हिंदू बहुल क्षेत्र पाल्दी में मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्यों?
मोदी के राज में पाल्दी में गोमांस और अंडे बेचने वाली दुकानें हैं? ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या मोदी के राज में गायों की हत्या होती है?
मुसलमान मूर्ख नहीं हैं, वे बहुत सोच-समझकर मतदान करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि
कांग्रेस की जीत तोगड़िया शासन की वापसी के बराबर है। अकेले दंगे ही काफी थे।
मुसलमानों के लिए यह एकमात्र परेशानी भरा दौर नहीं था। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ।
1990 के दशक में जब मोदी नहीं थे, तब भाजपा भी नहीं थी। उस समय तोगड़िया
जिसने गुजरात पर राज किया। मुसलमानों की तो बात ही छोड़िए, उस समय कोई भी हिंदू ऐसा नहीं कर सकता था।

गुजरात में एक मांसाहारी रेस्तरां खोलें।
मुसलमान इतने भयभीत थे कि दाढ़ी होने के कारण मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
बोपाल जैसे एक सर्व-हिंदू कुलीन क्षेत्र में। हमें जाने से डर लग रहा था और
हिंदू बहुल इलाकों में स्थित ड्राइव-इन थिएटरों में फिल्म देखना, यहां तक कि
ऐसे दौर भी आए जब कोई दंगे नहीं हुए। कांग्रेस के दौरान माहौल में दहशत का माहौल था।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के प्रभुत्व के कारण शासन व्यवस्था बदल गई।
उस समय मोदी का नामोनिशान भी नहीं था। मुझे हरेन पंड्या की किताब याद है...
चुनावी सभाओं में, वे दो कथनों से शुरुआत करते थे। पहले वे कहते थे,
“ Agar yahan musalman hai to chale jaanye, wo meri baat nahi sun payenge.” (If
इस बैठक में मुसलमान भी हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। वे यहाँ नहीं आ सकेंगे।
(मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे समझो।) वह इसकी शुरुआत इसी से करता और अंत में कहता, "जब
अगर मैं सत्ता में आया, तो मैं सभी मुसलमानों को यहाँ से भगाकर जुहापुरा भेज दूंगा।
मोदी द्वारा किए गए सबसे अच्छे कार्यों में से एक था विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को हाशिए पर धकेलना और उसे कमजोर करना।
बजरंग दल, क्योंकि वे ही मुख्य उपद्रवी थे। मोदी कभी हमला नहीं करते।

उन्हें मौखिक रूप से दंडित किया। लेकिन वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे दंगे करके बच न निकलें।
किसी भी मुद्दे पर अराजकता फैल जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई सरकार 340 मोदी, मुसलमानों और मीडिया को संबोधित करना चाहती है।

विकास कार्य, जैसे सड़कों को चौड़ा करना या जल निकासी की व्यवस्था करना, इनमें से एक है
सबसे बड़ी बाधा सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। इस प्रकार के अतिक्रमणों का एक बड़ा हिस्सा
निहित स्वार्थों द्वारा अतिक्रमण किए जाते हैं जो मंदिर बनाते हैं या स्थापित करते हैं।
सार्वजनिक भूमि पर मजारें खड़ी करना। सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने का यह सबसे आसान तरीका है।
सरकारें धार्मिक स्थलों को छूने से डरती हैं, इसलिए यह प्रतिबंध लागू है। गुजरात में भी यही स्थिति है।
ऐसे सैकड़ों मंदिर थे। अधिकांश सरकारें कार्रवाई करने से डरती हैं।
क्योंकि ऐसे तत्व धार्मिक भावनाओं को भड़का सकते हैं और एक प्रशासन के लिए संकट। 2006-2007 में, जब मोदी सरकार ने शुरुआत की। सड़कों के चौड़ीकरण सहित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
अहमदाबाद समेत कई शहरों में दशकों पुराने अवैध अतिक्रमणों के साथ,
बड़ौदा और सूरत में, कुछ लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर बहुमंजिला इमारतें बना ली थीं।
भूमि। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी इन लोगों को छूने की हिम्मत नहीं की।

लेकिन मोदी ने नगर निगम अधिकारियों को सभी अनधिकृत इमारतों को हटाने का पूरा अधिकार दे दिया।
अतिक्रमण चाहे वो मंदिर हों, दरगाह हों या निजी इमारतें हों। इसलिए वे चले गए।
आगे बढ़कर उन्होंने ऐसे 280 अवैध मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उस समय पांच दरगाहों में
बड़ौदा भी सफाई अभियान में शामिल हुआ। उन दरगाहों को बचाने के लिए, मैंने भी अपना हाथ बटाया।
मुझे मेरे समुदाय के सदस्यों द्वारा मोदी के पास ले जाया गया। मोदी ने एक सरल प्रश्न पूछा।
प्रश्न, "यदि आप कहते हैं कि यह भूमि 100 वर्षों से आपके कानूनी कब्जे में है, तो कृपया
दस्तावेजी सबूत पेश करो।" वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिए, आम सहमति से सहमति से, मुसलमानों ने उस दरगाह को स्वयं ही हटा दिया।
उन दिनों विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रमुख नेताओं ने मोदी को नया नेता बताया था।
महमूद गजनवी जो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने आया है। अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया आदि ने हर जगह मोदी की जमकर आलोचना की। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
उनकी भड़काऊ गालियों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस अपना काम जारी रखा और इसे अनदेखा कर दिया।
अपने दृढ़ कार्यों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि सरकार
कानून और व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ। किसी भी लोकप्रिय प्रतिक्रिया को जगाना। मोदी को अनुशासन बनाए रखने में कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

पहले दो वर्षों में प्रशासन पर उनका अच्छा नियंत्रण था। उसके बाद उन्होंने सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लिया और
वह अपने वादे या निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सका।
इसी प्रकार, जब आडवाणी साहब पाकिस्तान गए और जिन्ना के यहाँ घोषणा की...
जब इस बात पर हंगामा मच गया कि जिन्ना एक "धर्मनिरपेक्ष" नेता थे, तो पूरे भारत में हंगामा मच गया।
गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। जब आडवाणी का गांधीनगर दौरा निर्धारित था,
उनके संसदीय क्षेत्र में, वीएचपी/बजरंग दल ने बड़ी योजनाएँ बनाई थीं।
उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। हालांकि मोदी उनसे सहमत नहीं थे। आडवाणी द्वारा जिन्ना को "धर्मनिरपेक्ष" राजनेता के रूप में प्रमाणित करना और ये विरोध प्रदर्शन
राजनीतिक रूप से जो उनके लिए उपयुक्त था, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वीएचपी के गुंडे अपने इरादों में सफल न हों।
अशांत और कानूनविहीन प्रदर्शन। उनके लिए, यह कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का मामला था।
व्यवस्था बनाए रखने के मामले में, वह अपने ही दल के लोगों को भी नहीं बख्शता। जब कानून के शासन की बात आती है, तो वह अपने ही दल के लोगों को भी नहीं छोड़ता।
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 341

यह मोदी की काबिलियत है कि 2002 के बाद भी, कई उकसाने वाले कदम उठाने के बावजूद, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में अक्षरधाम आतंकवादी हमले जैसी घटनाएं हुईं।

36 हिंदू मारे गए, लेकिन हिंदुओं की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया।
कड़ा रुख अपनाया। उसके बाद, 2006 और 2008 में, सिलसिलेवार बम धमाके हुए।
गुजरात के आठ से दस शहर जिनमें अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा शामिल हैं।
लोगों की जान चली गई लेकिन मोदी ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया।
शरारत
दलालों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। सात-आठ बम धमाके हुए थे।
अहमदाबाद में ही। इससे बड़ा विरोध हो सकता था, लेकिन उन्होंने फिर से सावधानी बरती।
एक बेहद दृढ़ रुख।
रजत शर्मा, जो कभी भाजपा के करीबी थे, लेकिन अब खुद को इससे अलग करने का दावा करते हैं, ने भी यही बात कही:
हालांकि मोदी को हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है, सच्चाई यह है कि
विश्व हिंदू परिषद/आरएसएस मोदी से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति पुलिस को अनुमति नहीं देता है।
उनकी मदद करना या अदालती मामलों को उनके पक्ष में प्रभावित करना। वह उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता।
सत्ता पर काबिज रहने के लिए, वे और दंगे नहीं होने देंगे – वे मुसलमानों पर हमला नहीं कर सकते।
अब और नहीं, फिर भी वह हिंदू हृदय सम्राट बन गया है, जबकि वे
उनके साथ असभ्य व्यवहार किया जाता है। आरएसएस का एक वर्ग उनसे नफरत करता है क्योंकि वे उनके सामने झुकते नहीं हैं।
न तो उन्हें शासन में हस्तक्षेप करने दें और न ही उन्हें शासन व्यवस्था में दखल देने दें।

जफर की उपद्रवियों को निष्क्रिय करने संबंधी दूरदर्शी टिप्पणी का गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के मुसलमानों ने मेरे साथ साक्षात्कार के दौरान समर्थन किया है।
यह उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया अपने सभी लेख इसी आधार पर लिखते हैं।
हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में अभद्र भाषण। इन सभी राज्यों में
इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी और उसके घोषित धर्मनिरपेक्ष सहयोगी दलों का शासन है। ऐसा क्यों नहीं होता?
क्या उनमें गुजरात आकर भाषण देने का साहस था? 2002 से
आज तक गुजरात में किसी ने भी इस तरह का नफरत भरा भाषण देने की हिम्मत नहीं की है।
वह जानता है कि अगर उसने यहां ऐसा कुछ कहा, तो 24 घंटे के भीतर उसे साबरमती जेल में चक्की पीसते देखा गया.
कांग्रेस शासित राज्यों में टोगडिया बिना किसी परिणाम के जहर उगल रहा है।
और उसे अभी तक एक बार भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसकी नफरत को कई महीने बीत चुके हैं।
महाराष्ट्र में भाषण हुए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार का कहना है कि वे
अभी भी उनके कहे की जांच चल रही है। क्या यह जानबूझकर प्रोत्साहन देने का संकेत नहीं है?
कुछ महीने पहले, उर्दू के एक अखबार 'नई दुनिया' में यह खबर छपी थी। following headlines: “Togadia mei himmat ho to jo Hyderabad mein kaha hai 342 Modi, Muslims and Media

wo Ahmedabad mein keh ke dikhaaye, Modi uski taange tod dega.” (If Togadia
अगर उसमें हिम्मत है तो उसे अहमदाबाद जाकर वही बात कहनी चाहिए जो उसने हैदराबाद में कही थी।
मोदी उसकी टांगें तोड़ देगा।
ऐसा नहीं है कि तोगड़िया साहब ने यह पहली बार किया हो। गुजरात में तोगड़िया,
हरेन पंड्या और ज़ादाफ़िया पहले भी नियमित रूप से नफरत भरे भाषण देते थे।
शासन व्यवस्थाएँ। ये तीनों जहर उगलने के लिए मशहूर थे। मोदी ने कभी ऐसा नहीं किया।
ऐसे किसी भी भाषण के बारे में। उनके विरोधी उनके मुस्लिम-विरोधी पूर्वाग्रह को कमजोर सबूतों से साबित करने की कोशिश करते हैं।
उन पर पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति को व्यंग्यात्मक ढंग से संबोधित करने जैसे आरोप लगे।
कारगिल युद्ध के लिए 'मियान मुशर्रफ' को जिम्मेदार ठहराया गया।
लेकिन "मियान" कोई शब्द नहीं है।
दुर्व्यवहार के संदर्भ में, और कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार एक पाकिस्तानी जनरल का जिक्र करते हुए।
व्यंग्य से भरपूर युद्ध कोई बड़ा अपराध नहीं है।
जहां तक गुजराती मुसलमानों का सवाल है, स्थिति बदलने लगी थी।
2007 के बाद मोदी के पक्ष में। लेकिन बहुत कम प्रमुख मुसलमानों ने खुलकर सामने आने की हिम्मत की।
धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड के साथ-साथ कट्टरपंथी लोगों के हमले के डर से खुलेआम बाहर निकलना।
मुस्लिम नेता। सबसे पहले अपनी सीमा से बाहर निकलने वालों में से एक, और मोदी के पक्ष में खड़े होने वालों में से एक।

मौलाना वस्तानवी एक सम्मानित इस्लामी विद्वान और शिक्षाविद थे। यह सर्वविदित है कि मौलाना वस्तानवी के मदरसे में 400 छात्र पढ़ते थे,
मोदी के समय पर हस्तक्षेप के कारण ही यह घटना टल पाई। जैसे ही उन्हें फोन आया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की।
इस मदरसे पर संभावित हमले की आशंका को देखते हुए, मोदी ने सुरक्षा बल भेजे और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी
किसी भी छात्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा, वस्तानवी स्वयं गुजरात से हैं।
इसलिए उन्हें गुजरात की कहानी की प्रत्यक्ष जानकारी है। वे गुजरात से आने वाले पहले व्यक्ति थे।
130 वर्षों में पहली बार किसी को देवबंद विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया।
ऐतिहासिक घटना। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही।
2011 में देवबंद का कार्यभार संभालने के बाद, गुजरात का मुद्दा भी चर्चा में आया।
वास्तनवी से गुजरात में हो रही प्रगति पर टिप्पणी करने को कहा गया।
उन्होंने केवल इतना कहा कि गुजरात अच्छी प्रगति कर रहा है और मुसलमान समान हैं।
राज्य के विकास और उन्नति में भागीदार। संवाददाता ने फिर पूछा उनसे पूछा गया कि क्या लोगों को 2002 के दंगों को भूल जाना चाहिए।
वत्सानवी ने उत्तर दिया कि नौ
दंगों को बीते कई साल हो गए हैं। अब उन्हें भूलकर आगे बढ़ने का समय है।

उन्होंने केवल यही दो बयान दिए। मुझे बताइए, क्या ये तथ्यात्मक रूप से गलत हैं?
और फिर भी मीडिया के साथ-साथ सत्ता प्रतिष्ठान ने भी भारी हंगामा खड़ा कर दिया।
देवबंद। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि देवबंद के कुलपति मोदी के विकास कार्यों की प्रशंसा में एक भी नरम शब्द कहने की हिम्मत करें।
लेकिन, वस्तानवी ने अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें ऐसा करना होगा।
उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए शूरा (शासक परिषद) की बैठक बुलाई गई। वहाँ
शूरा में 13 व्यक्ति थे – छह ने वस्तानवी के खिलाफ वोट दिया, एक व्यक्ति शेष रहा।
एक व्यक्ति तटस्थ था और पांच लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया। वस्तानवी ने मतदान में भाग नहीं लिया।
वस्तानवी के पक्ष में मतदान करने वाले व्यक्ति भारत के शीर्ष उलेमा थे।
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 343

पांच प्रख्यात मुस्लिम विद्वानों ने वस्तानवी के बयान के पक्ष में मतदान किया था।
मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया और केवल वास्तानवी विरोधी उन्माद का ही प्रसारण किया।
वह मूल रूप से एक शिक्षाविद हैं। वह मदरसों की एक श्रृंखला चलाते हैं और प्रत्येक
उनके मदरसे से एक नियमित विद्यालय और तकनीकी संस्थान भी जुड़ा हुआ है।

वह अपने मदरसे में कंप्यूटर के साथ-साथ अंग्रेजी और गणित भी पढ़ाते हैं।
वह एक विज्ञान महाविद्यालय, एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय और एक फार्मेसी महाविद्यालय चलाते हैं।
अब औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। स्थापित संस्थानों में
उनके द्वारा सीधे तौर पर 2 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई। अंततः, उन्होंने मजबूर किया
उन्हें मोदी के बारे में दिए गए अपने बयान को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें देवबंद छोड़ने के लिए विवश किया गया। वस्तानवी का इस्तीफा देवबंद के लिए उनके खुद के इस्तीफे से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। उन्हें मजबूरी में झुकना पड़ा।
कांग्रेस पार्टी की ओर से दबाव क्योंकि उनके सभी शिक्षण संस्थान गुजरात के बाहर या अधिकतर कांग्रेस शासित राज्यों में।
लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सामूहिक प्रयासों के कारण, मुसलमानों के विचारों में एक गंभीर बदलाव आया है। समावेशी विकास मॉडल, एक
मुसलमानों के लिए सुरक्षित वातावरण, आतंक का पूर्ण अभाव, जिसका वे पहले सामना करते थे
सरकार द्वारा कानून के शासन को बरकरार रखने के तहत, दोषसिद्धि की एक श्रृंखला हुई।
दंगों के लिए जिम्मेदार राजनेता, और कई अन्य सक्रिय उपाय किए गए हैं।
इससे मुसलमान भाजपा की ओर आकर्षित हुए।
मुझे लगता है कि मोदी का विरोध करने वाले केवल तीन प्रकार के लोग ही बचे हैं: 1) दूर बैठे हुए, घर बैठे आलोचक - जो गुजरात से बाहर हैं और

उदाहरण के लिए, इंग्लैंड, अमेरिका, दिल्ली आदि। ये लोग सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियां भेजते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर टिप्पणियां पोस्ट करते हैं। लेकिन हमारा मीडिया इन्हें बहुत महत्व देता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड स्थित काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ने अपने संरक्षक लॉर्ड एडम पटेल की मोदी से मुलाकात की निंदा की है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की भी निंदा की क्योंकि ब्रिटिश राजदूत भी मोदी से मिलने आए थे।
देश के बाहर रहने वाले इनमें से अधिकांश लोगों का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है।
भारत के बारे में राय बनाने वाले लोग मीडिया में छपी खबरों के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे लॉर्ड पटेल की तरह नियमित रूप से भारत नहीं आते। न्याय की मांग है कि किसी भी मामले का फैसला उसकी योग्यता के आधार पर किया जाए, न कि पक्षपातपूर्ण प्रचार के आधार पर। भारत ने अजमल कसाब जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी को भी, जिसे मुंबई हमलों के दौरान लोगों का नरसंहार करते हुए कैमरे में कैद किया गया था, हर आरोपी को दिए गए संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हुए अदालत में अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया। लेकिन वे इसके लिए भारत को कभी श्रेय नहीं देंगे।
वे खुद आकर जाँच नहीं करते बल्कि निंदा करने में व्यस्त रहते हैं। मोदी, क्योंकि ऐसा करना राजनीतिक रूप से चलन बन गया है। लेकिन वे मुझसे यह पूछने की जहमत कभी नहीं उठाएंगे कि मैं मोदी से क्यों जुड़ा हुआ हूँ? जब मैं मोदी का विरोध कर रहा था, तब मैं उनका हीरो था। वे मुझे 344 मोदी, मुसलमान और मीडिया का समर्थन क्यों नहीं करते?

क्या आप मुझसे यह पूछने की शिष्टाचार दिखा सकते हैं कि मुझे अपना निर्णय बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? मेरे खिलाफ कई फतवे जारी होने के बाद मैं समाज से बहिष्कृत हो गया हूँ।
2) मोदी के विरोधियों की दूसरी श्रेणी में मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हैं और
भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले स्वघोषित नेता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग खुद को "बुद्धिजीवी" क्यों कहते हैं, लेकिन मोदी के मुसलमानों के साथ संबंधों के खिलाफ बयान देने से पहले कम से कम अहमदाबाद, या पूरे गुजरात का दौरा करने की ईमानदारी भी नहीं दिखाते। वे दिल्ली और मुंबई के टीवी स्टूडियो से हमें गुजराती मुसलमानों को सलाह देते हैं कि हमें गुजरात में अपना कामकाज कैसे चलाना चाहिए। शाहबुद्दीन जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवी मीडिया में सिर्फ 'मोदी को पत्र' छापकर अखबारों के जरिए उपदेश देते हैं! इसके विपरीत, लॉर्ड पटेल मुस्लिम समुदाय से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए मोदी से मिलने गए थे। अगर आप वाकई गुजरात के 75 लाख मुसलमानों के बारे में चिंतित हैं, तो मोदी से मिलिए। आप अखबार में एक पत्र लिखते हैं, टीवी बहसों में आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? (एक खत लिख दिया, टीवी के डिबेट में आ गए और सब गुनाह माफ?)
3) जहां तक तीस्ता सेतलावाद जैसे मोदी विरोधी गैर सरकारी संगठनों के तीसरे समूह का सवाल है
जहां तक शबनम हाशमी का सवाल है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने दुकानें खोली हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया है।
लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 2013 के गुजरात वाइब्रेंट समिट में दुनिया भर के लोगों ने भाग लिया।

121 देशों के नेता भाग लेते हैं और मोदी की प्रशंसा में गीत गाते हैं।
ब्रिटिश सरकार ने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ के नेताओं
उनके करीब आने के तरीके खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी ने किसी को लुभाने की कोशिश नहीं की।
एक। लोग बड़ी संख्या में उसके पास आ रहे हैं। आपने हाल की रिपोर्टें देखी होंगी।
वर्तमान जर्मन राजदूत ने मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राजदूत की जमकर प्रशंसा की।
गुजरात विकास का मॉडल है। लेकिन कुछ साल पहले, एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने
खबरों के मुताबिक, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने गुजरात का दौरा किया।
हमें उस मुलाकात की जरा सी भी आहट नहीं मिली—वे हममें से किसी से भी नहीं मिले।
मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल ने जाकर एक बैठक आयोजित की।
दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में भयानक उत्पीड़न। हमने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, "तुम कौन होते हो मुझे...?"
क्या आप हमारी ओर से बोलेंगे? अगर कोई समस्या है भी, तो वह हमारा आंतरिक मामला है। दरअसल,
आपको हमें स्पष्टीकरण देना होगा; हमें बताएं कि गुजरात आने पर आप किससे मिले थे?
बताइए, गुजरात में रहते हुए आप किन-किन मुस्लिम समूहों से मिले?

क्या आप अहमदाबाद में थे? अगर आप अहमदाबाद में थे, तो हमें, सामुदायिक नेताओं को, क्यों बाहर रखा गया?
हमने उन्हें इन सब बातों का जिक्र करते हुए एक औपचारिक विरोध पत्र लिखा, लेकिन हमें कभी कोई जवाब नहीं मिला।
इसलिए, हमने स्वयं जांच की और पाया कि वे मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।
कुछ मुसलमान हैं। फादर सेड्रिक प्रकाश के नेतृत्व में एक ईसाई समूह भी है।
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 345

जिसने इस प्रतिनिधिमंडल को अहमदाबाद आमंत्रित किया था। कोई हमला नहीं हुआ है।
मोदी के शासनकाल में ईसाइयों पर अत्याचार किया गया। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के कंधों का इस्तेमाल किया।
एक धार्मिक समुदाय ने मोदी पर गोलियां चलाईं। यह समूह धार्मिक मुद्दों पर एक विधेयक से नाराज था।
धर्मांतरण क्योंकि इससे ईसाई मिशनरियों के संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा
धर्मांतरण में शामिल। मोदी सरकार ने कभी भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
ईसाई विद्यालय या अन्य संस्थान।
मैंने तत्कालीन जर्मन राजदूत को एक पत्र लिखकर उनसे पूछा कि क्या प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह जर्मन सरकार का घोषित रुख है।
सरकार। अगर ऐसा है, तो उन्हें हमारी ओर से बोलने का अधिकार किसने दिया है? मत करो

साहब ने उनके साथ अत्यंत स्नेह और आदर का व्यवहार किया, और उनकी अनदेखी की।
लॉर्ड पटेल और उनकी मुस्लिम परिषद द्वारा उन पर किए गए सभी पूर्व हमले।
यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है - पटेल एक बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति हैं और
कोई यह नहीं कह सकता कि वह आदमी "बिका हुआ" है। वह न तो भारत में रहता है और न ही उसके पास...
गुजरात में बचे हुए उनके रिश्तेदारों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है।
हिंदुस्तान के साथ। वह गुजरात के भरूच जिले से हैं और अपने पैतृक स्थानों पर जाया करते हैं।
हर साल गांव में। आम तौर पर, इतने उच्च पद का व्यक्ति अपना पहनावा नहीं बदलता।
सार्वजनिक तौर पर दिखावा करना अहंकार को ठेस पहुंचाता है। लेकिन उनकी गुजरात की वार्षिक यात्राएँ
पिछले दस वर्षों में जो कुछ हुआ है, उससे उन्हें यह विश्वास हो गया होगा कि इसके पीछे अच्छा कारण है।
अपना विचार बदलने के लिए उन्होंने मोदी से मिलने का फैसला किया।

1. अमेरिकी सरकार को भी अपने अहंकार से नीचे उतरना पड़ा और अपनी नीति को समाप्त करना पड़ा।
नरेंद्र मोदी की सरकार का आधिकारिक बहिष्कार तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने पॉवेल द्वारा दिए गए रात्रिभोज के निमंत्रण को कथित तौर पर अस्वीकार करने के बाद 13 फरवरी, 2013 को नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गांधीनगर का दौरा किया।

346 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मैंने जफर से पूछा कि क्या लॉर्ड पटेल के प्रति मोदी के रवैये में किसी प्रकार की कड़वाहट झलकती है?
जब आप उस बैठक की तस्वीरें देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे
वातावरण बेहद शांत और सुखद था। दरअसल, पटेल ने खुले तौर पर कहा कि यदि मुसलमानों को मोदी से कुछ मतभेद हैं, तो उन्हें उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए।
उनका समाधान करें। वह व्हार्टन विश्वविद्यालय की खुले तौर पर आलोचना करने वाले पहले मुस्लिम थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी के व्याख्यान को रद्द करने के लिए अमेरिका की आलोचना।
लॉर्ड पटेल के पत्र से उद्धृत करते हुए:
व्हार्टन द्वारा नरेंद्र मोदी को मना करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी खोज कमजोर होती है।
2002 के दंगों के मामलों में न्याय... किसी की बात सुनने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं होती।
कट्टर अनुयायी बनना या कट्टर आलोचक बनना... अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानती है
कोई सीमा नहीं। हम जितना अधिक लोगों और विचारों को सुनते हैं, उतना ही अधिक समृद्ध होते जाते हैं।
जब कोई शैक्षणिक संस्थान भाषण के प्रकार पर निर्देशात्मक रुख अपनाता है।
कैंपस में क्या सुना जा सकता है और क्या नहीं, यह बौद्धिक स्वतंत्रता का हनन करता है।

लोकतांत्रिक विचार जिसे अमेरिका, भारत और ब्रिटेन ने सदियों से संजोकर रखा है।
अनादि काल से... व्याख्यान रद्द करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे मोदी को और भी बुरा लगेगा।
उकसाने वालों को इस हद तक बदनाम किया गया है कि उन्होंने तर्क के सभी बिंदुओं को बुझा दिया है और
इस बहस के चलते ऐसी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा... एक गुजराती होने के नाते, मैं मानता हूँ
यह घोर अपमान की बात है कि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वे कितने भी गलत क्यों न हों,
उन्हें ऐसा लग सकता है कि वे वैश्विक मंच पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे कि इस मंच पर।
व्हार्टन, क्योंकि दर्शकों में से कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते... सबसे बड़ी जरूरत
यह समय उन लोगों को न्याय दिलाने का है जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाई।
2002 में हिंसा… 2002 के दंगों के मामलों में दोषसिद्धि की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही थी।
भारत में कहीं भी दंगों के बाद अन्य दोषसिद्धि... लेकिन अगर लोग बहिष्कार महसूस करते हैं
मोदी को अपने लक्ष्य हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका मानना उनकी गलतफहमी है। दरअसल,
व्हार्टन में मोदी की यात्रा का विरोध करके, वे केवल अपने समर्थकों को ही मजबूत कर रहे हैं।
वे न्याय के शत्रु हैं, और साथ ही साथ वे एक बहुत बड़ा अन्याय भी कर रहे हैं।

गुजरात में न्याय और न्याय की प्राप्ति की प्रक्रिया के संबंध में...
ज़फ़र कहते हैं, “यह मुस्लिम मत में एक बड़ा बदलाव है। सलीम खान ने एक बार मुझसे कहा था, ‘क्या गुजरात चुनावों में मोदी की जीत अल्लाह की इच्छा नहीं है? अगर अल्लाह चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बनें तो उनके रास्ते में बाधा डालने वालों के प्रयास सफल नहीं होंगे।’” लेकिन ज़फ़र मानते हैं कि यह लड़ाई अभी भी एक कठिन चुनौती है क्योंकि:
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 347

मीडिया द्वारा मोदी विरोधी भावना को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।
यह अंतिम सत्य है, चाहे गुजरात की जनता कुछ भी कहे या अदालतें कुछ भी कहें।
गुजरात के बारे में सकारात्मक घटनाक्रमों को मीडिया कभी कवर नहीं करता।
मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यही बातें कई पत्रकारों को सुनाई हैं।
इनमें प्राइम टाइम टीवी चैनलों के चैनल भी शामिल हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई और
सागरिका घोष। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आप जानते ही हैं कि टीवी चैनलों का क्या हाल होता है;
वे आपको अपने ही सवालों के जाल में फंसा लेते हैं। वे केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं जो...
मोदी की निंदा करें।
2007 में, बेहद कड़वे चुनावों की गहमागहमी में—ये वो "मौत का" थे

"सौदागर" दिनों के दौरान, एनडीटीवी ने हमें एक विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाया।
रिलायंस रिफाइनरी। जब मैं वहां गया, तो मैं दंग रह गया। उन्होंने इसे विभाजित कर दिया था।
प्रतिभागियों को दो अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया था - एक समूह मोदी समर्थक माना जा रहा था और
दूसरा मोदी विरोधी। कुछ ही मिनटों में कैमरे चालू होने वाले थे और वहाँ
मुझे मोदी समर्थक समूह में रखा गया था।
हर मुद्दे को स्कूली बहस समितियों के व्यंग्यचित्र में तब्दील करने का यह तरीका – एक टीम 'पक्ष में' और दूसरी 'विपक्ष में' – भारत में राजनीतिक बहस के स्तर को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अनिवार्य रूप से हर मुद्दे को ध्रुवीकृत कर देता है और यथार्थवादी मूल्यांकन को रोकता है। मैंने पूछा कि ज़फ़र ने NDTV से बैठने की व्यवस्था बदलने पर ज़ोर क्यों नहीं दिया? उन्होंने उस दिन की अपनी दुविधा का वर्णन किया:
मुझे भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के साथ मोदी समर्थक समूह के साथ बैठाया गया।
विरोध पक्ष में कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन थे। मैं
बजरंगियों के साथ बैठे हुए बहुत असहज महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने खुद से कहा कि मैं यहाँ सिर्फ रचना करने के लिए हूँ।
एक निष्प्रभावी प्रभाव, मैं यहाँ इस बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ कि चुनाव कौन जीतता है या हारता है।
पूरा विचार समुदायों के बीच पुल बनाने का है। लेकिन फिर भी मैंने फोन किया।

मैंने महेश भट्ट से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, “चिंता मत करो; डटे रहो।”
आपकी ईमानदारी। आप न तो मोदी विरोधी हैं और न ही समर्थक, आपके मन में जो भी है।
अपने मन और हृदय से, उन्हें पूरी ईमानदारी से यह बात बता दें। इससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा।
किसी के पक्ष या विपक्ष में होने की तुलना में इसका प्रभाव अधिक होता है।
मैंने बिलकुल वैसा ही किया। लेकिन मेरी पत्नी वहां से चली गई और दूसरी तरफ पहुंच गई।
उसने कहा कि वह मोदी समर्थक के रूप में देखे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है, हम एक हैं।
बहुत ही लोकतांत्रिक दंपति। आपको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो एक मौलिक अधिकार है।
इस्लाम का सिद्धांत। लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि उस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं असहज महसूस कर रहा था।
अंदर रहना बेहतर था क्योंकि मेरे साथ मौजूद ज्यादातर लोग हाशिये के तत्व जैसे थे।
और वीएचपी और बजरंग दल के गुंडे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या एनडीटीवी ने इसे कवर किया।
ऐसे लोग जानबूझकर मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीएचपी के लोग मोदी, मुसलमानों और मीडिया के खिलाफ हैं।

मैं मोदी समर्थक नहीं था। मैंने उसी क्षण उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।
उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर, जो जामनगर वीएचपी के अध्यक्ष भी थे, ने कहा

कुछ इस तरह कि अगर मुसलमानों को गुजरात पसंद नहीं है, तो वे कहीं और जा सकते हैं।
पाकिस्तान। मैंने उसे बोलने नहीं दिया और कहा, "यह तुम्हारा तरीका नहीं है।"
मुख्यमंत्री की बातें। आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं?” मैंने उन्हें चुनौती दी और
उन्हें कैमरे के सामने अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी।
मैं एनडीटीवी के एंकर को यह नहीं कह सका कि वह मोदी समर्थक बनाम मोदी विरोधी इस बहस में न उलझे।
विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो लोग पहले से ही बैठे हुए थे।
उस योजना के अनुसार। तब मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें इस तरह मुझे फंसाने नहीं दूंगा।
मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा। एंकर और टेलीविजन नेटवर्क आमतौर पर आपसे यही चाहते हैं।
वे वही कहेंगे जो उनकी सोच के अनुरूप हो। मैंने तय किया कि मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं।
कहने का मतलब यह है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठता हूँ।
वे मेरी या आसिफा खान जैसी लोगों की बात उस तरह कभी नहीं सुनते जिस तरह वे दूसरों की सुनते हैं
तीस्ता सेतलवाद, हालांकि उनके विपरीत, हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है।
मीडिया उन लोगों से बात करना पसंद करता है जिन्होंने दूसरों के माल का व्यापार किया है।
समस्याएं। मैं ऐसे लोगों को दुख के सौदागर कहता हूँ। हमारा देश इससे कहीं अधिक दूर होगा।

अधिक शांतिपूर्ण माहौल बनेगा और अंतर-सामुदायिक संबंध फिर से सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे।
अगर उनकी दुकानें बंद हो जाएं।
मैंने हाल ही में राजदीप सरदेसाई से उनके द्वारा लिखे गए एक लेख के बारे में बात की और
उन्होंने कहा कि आपकी समस्या तब आती है जब आप मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं, आपको
तीन प्रकारों में उलझे हुए हैं। सबसे प्रमुख श्रेणी धार्मिक कट्टरपंथियों की है, जैसे कि...
भारत के इमाम बुखारी। कुछ कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जो सामान्य नियमों का पालन नहीं करते।
इस्लामी दाढ़ी वाले, लेकिन दिल से बुखारी। दूसरे प्रकार के लोग जो आपको मिलते हैं वे हैं...
उपद्रवी लोग जिनका निजी और सार्वजनिक जीवन बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए, जब असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में होते हैं तो वे शॉर्ट्स पहनकर घूमते हैं।
वह इतालवी रेस्तरां में खाना खाता है, लेकिन जब वह हैदराबाद लौटता है तो वह पहनता है
पारंपरिक इस्लामी टोपी और कुर्ता-पायजामा। तीसरी श्रेणी जो आप प्रस्तुत करते हैं, वे हैं
दुनिया के जावेद अख्तर और शबनम हाशमी जैसे लोग जिन्हें समस्या है खुद को मुसलमान कहते हैं और फिर भी उत्पीड़न के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हैं।
मुसलमान।
लेकिन मुझ जैसे सच्चे मुसलमान, जिन्हें हम मुसलमान मानते हैं, उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। वे हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते।

मुसलमानों के प्रतिनिधि। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी फिल्मों में नायक खलनायक को पकड़ लेता है।
कॉलर पकड़कर उसे कहानी से बाहर कर देता है, बुखारीस को भी।
ओवैसी जैसे लोगों को दरकिनार कर देना चाहिए। अगर उनके साथ सख्ती से पेश आया जाता तो...
कानून और व्यवस्था तंत्र, उनका मर्दाना रवैया हवा में गायब हो जाएगा, और
यहां तक कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी उन्हें बचाने नहीं आएंगे। यहां तक कि जो लोग आज उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, वे भी नहीं आएंगे।
जेल में उनसे मिलने आने वालों की संख्या जल्द ही कम हो जाएगी। बाकी लोग उन्हें बस भूल जाएंगे।
इसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। लेकिन आप इसे राजनीतिक मजबूरियों के कारण नहीं करते।
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 349

ये धर्मनिरपेक्षवादी सोचते हैं कि उनके पास एक विशेष गंगा है, जिसके द्वारा जो कोई भी उसमें प्रवेश करता है
कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पार्टी धर्मनिरपेक्ष बन जाती है। लेकिन गुजराती मुसलमान अब
वे कहीं अधिक समझदार हैं। उन्होंने सुशासन और दंगा-मुक्त राज्य के लाभ देखे हैं।
और सर्वांगीण आर्थिक विकास जिसमें अब वे समान भागीदार हैं।
इसलिए, वे हर हाल में मोदी के सबसे कट्टर समर्थक बन गए हैं।
मीडिया का कहना है।
कृपया मुझे इस विरोधाभास को समझाएं। भारतीय विकास गाथा

अर्थव्यवस्था की शुरुआत नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुई थी, जब मनमोहन सिंह उनके सहयोगी थे।
वित्त मंत्री। आज अगर मैं कहूँ कि ये दोनों भारत के निर्माता थे... आर्थिक सुधारों के लिए मुझे कांग्रेस का चमचा नहीं कहा जाता।
हालाँकि, जिस क्षण मैं
अगर मैं कहूँ कि गुजरात की विकास गाथा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शुरू हुई, तो मेरी आलोचना होने लगती है।
नरेंद्र मोदी के चापलूस के रूप में।
गुजरात में हिंदू-मुस्लिम संबंधों का बदलता स्वरूप: मेरे वामपंथी मित्रों ने बार-बार आरोप लगाया है कि गुजराती हिंदुओं ने मुसलमानों को कंगाल करने और उन्हें राज्य से बाहर निकालने के लिए उन पर आर्थिक बहिष्कार लागू किया है। मैंने ज़फ़र से पूछा कि क्या 2002 के दंगों के बाद, या उससे पहले भी, मुसलमानों को हिंदुओं द्वारा आर्थिक बहिष्कार और अन्य प्रकार के सक्रिय भेदभाव का सामना करना पड़ा? उन्होंने यह कहा:
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेलजोल पूरी तरह से ठप हो गया था।
1970 और 1980 के दशक के दंगों से प्रभावित दशकों के दौरान गुजरात के कई हिस्सों में यही स्थिति थी।
1990 के दशक से लेकर 2002 तक उन्होंने व्यापारिक संबंध बनाए रखे।
हिंदू परिवारों ने भी ऐसा ही किया।
मुस्लिम दुकानों से खरीदारी और इसके विपरीत। लेकिन उनका सामाजिक संबंध नगण्य था।
इंटरैक्शन।
दंगों के दिनों में, एक मुस्लिम महिला कभी भी किसी सड़क से होकर गुजरने की हिम्मत नहीं करती थी।
हिंदू बहुल इलाका। दंगे खत्म होते ही बुर्का पहने हुए लोग भी।

महिलाएं हिंदू मोहल्लों में जाती हैं। पुराने शहर में हमारा एक इलाका है जिसे हम कहते हैं
ढालगरवाड़; आपने शायद ही कहीं और ऐसा माहौल देखा हो।
एक ऐसा देश जहां 600 कपड़ों की दुकानें पूरी तरह से मुसलमानों और उनके स्वामित्व में हैं
हमारे 95 प्रतिशत ग्राहक गुजराती हिंदू महिलाएं हैं। अगर नफरत भी हो, तो वह लंबे समय तक बनी रहती है।
कुछ दिनों तक। दंगा समाप्त होते ही, वे हिंदू महिलाएं केवल मुस्लिम परिवारों में जाती हैं।
कपड़े खरीदने की दुकानें। और ऐसा नहीं है कि यह एकाधिकार है। ढालगरवाड़ के बगल में है
रतन पोल में 100 प्रतिशत हिंदू स्वामित्व वाली कपड़ों की दुकानें हैं। लेकिन सभी हिंदू
जो महिलाएं ढालगरवाड़ जाती हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि वे क्यों जाती हैं।
इसी प्रकार, आज आपको कई हिंदू ऐसे मिलेंगे जो 100 प्रतिशत धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन कर रहे हैं।
कबाब और अन्य मुस्लिम व्यंजनों के लिए मुस्लिम क्षेत्र। पहले, कोई हिंदू क्षेत्र नहीं थे।
जुहापुरा में कदम रखते ही इसे मिनी-पाकिस्तान के रूप में देखा जाने लगा। अब आपको यहां कई 350 मोदी, मुस्लिम और मीडियाकर्मी मिलेंगे।

कालूपुर और दरियापुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों के बीच हिंदू भोजन कर रहे हैं।
तवा टिक्का और बारहंडी। इसी तरह मानेक के हिंदू बहुल इलाके में भी

अहमदाबाद के मध्य में स्थित चौक, जहां शाकाहारी भोजन का बाजार शुरू होता है
नियमित दुकानें रात 8 बजे बंद होने के बाद ही आपको कुछ दुकानें मिलेंगी।
बुर्का पहने महिलाओं सहित मुस्लिम परिवार रात का खाना खा रहे हैं या
रात के 2 बजे तक भी नाश्ता उपलब्ध रहता है।
अब बेहतर कानून व्यवस्था के चलते लोग घूमने-फिरने के लिए अधिक साहसी महसूस कर रहे हैं।
एक-दूसरे के घरों में। पहले तो मुस्लिम परिवार हिंदू व्यापारियों को भी आमंत्रित करते थे।
विवाह या अन्य पारिवारिक समारोहों के लिए उपस्थित होने वाले सहयोगियों के लिए, वे एक अलग हिंदू समारोह आयोजित करते थे।
उनके लिए यह समारोह पूरी तरह से गुजराती शाकाहारी भोजन पर आधारित होता है – यह कभी भी संयुक्त आयोजन नहीं होता।
इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवार शामिल थे। लेकिन अब हममें से कुछ ने यह कदम उठाया है।
हिंदू और मुस्लिम परिवारों के लिए संयुक्त समारोह आयोजित करने की पहल
बातचीत करें। मेरा विश्वास करें, हिंदू बड़ी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
इसके बावजूद गुजरात में कभी भी आर्थिक बहिष्कार वास्तव में नहीं हुआ है।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल की तरफ से हर दंगे के दौरान किए गए बेहतरीन प्रयास। हर दंगे के दौरान वे कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं।

उनके पर्चे लोगों से मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करने का आग्रह करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
ऐसा नहीं हुआ—2002 के बाद भी नहीं, जब नफरत अपने चरम पर थी। अन्यथा
मुसलमान जीवित नहीं रह पाते। हालांकि, दुनिया के तोगड़िया जैसे लोग कोशिश करते हैं।
उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन गुजरात में कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली।
दंगों के केंद्र में भी।
यह सिर्फ मोदी ही नहीं, बल्कि पूरा गुजराती समाज आगे बढ़ चुका है और
मुसलमानों के साथ एक नए समीकरण का पुनर्निर्माण करना। 2002 के बाद, हमने इसे अपने हाथ में लिया।
हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी मुस्लिम बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
क्योंकि उनका परिवार फीस देने या किताबें खरीदने में असमर्थ है। हिंदुओं ने इसके लिए हमें पैसे दिए। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब हमने एक कार्यक्रम को प्रायोजित किया था।
एक हिंदू मित्र ने कहा कि मुस्लिम लड़की की मेडिकल कॉलेज में शिक्षा के संबंध में,
वह उस लड़की की उस सेमेस्टर की फीस भर देगा। इससे मेरा मनोबल काफी बढ़ गया।
और इसने मुझे आश्वस्त किया कि मानवतावादी भावना गुजरात में भी जीवित है।
जो लोग कहते हैं कि गुजरात में हिंदू-मुस्लिम नफरत बहुत ज्यादा है,
एक मिथक को कायम रखना। वह शत्रुता कुछ समय तक जीवित रही।

दंगे। 2002 के बाद भी, जब हालात सामान्य हो गए और तनाव कम हो गया, तब भी ऐसा ही हुआ।
जिन हिंदुओं ने मुसलमानों को अपना जीवन फिर से बसाने में मदद की, वे कितना योगदान दे सकते हैं?
क्या मुसलमान अकेले ऐसा करते हैं? मेरी बहन और भाभी मुस्लिम बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती हैं।
गरीब परिवारों की लड़कियां। उस स्कूल में 450 छात्राएं हैं। वे नहीं पढ़ सकतीं।
स्कूल फीस के तौर पर 200 रुपये प्रति माह भी देना मुश्किल था। चुनौती यह थी कि अगर हम
उचित शुल्क नहीं लेते, तो हम एक अच्छा स्कूल कैसे चलाएँगे? हम अच्छे कैसे प्राप्त करेंगे?
शिक्षकों? इसलिए हमने कॉन्वेंट से पढ़ी-लिखी और अच्छी डिग्री प्राप्त सभी छात्राओं से संपर्क किया।
और हमने उनसे कहा कि हमें उनसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका समय चाहिए।
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 351

कुछ लोग दिन में निश्चित घंटों के लिए आते हैं; अन्य लोग निश्चित संख्या में आते हैं
वे इसे सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों के रूप में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित।
दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद में एक बेहद विशिष्ट हिंदू समुदाय का स्कूल है।
सी.एन. विद्यालया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक माना जाता है। पिछले 20 वर्षों में एक भी छात्र का नामोनिशान नहीं है।

उस स्कूल में एक मुस्लिम छात्र पढ़ता था। जब इस स्कूल के प्रबंधन ने
उन्हें पता चला कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं।
गरीब मुस्लिम परिवारों की लड़कियां खुद हमारे पास आकर बोलीं: “हम मैं आपके स्कूल में पढ़ाने वाली इन सभी महिलाओं को प्रशिक्षित करूंगा और उन्हें यहाँ लाऊंगा।
प्रशिक्षित शिक्षकों के समकक्ष।" हमारे शिक्षकों के पास नियमित स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा थी।
स्नातक डिग्री तो थी लेकिन शिक्षण कौशल की कमी थी। अब सी.एन. विद्यालया का उन्नयन हो रहा है।
हम अपने सभी शिक्षकों को प्रतिदिन तीन घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें लाभान्वित करते हैं।
इस स्कूल को इस्लामिक स्कूल कहा जाता है और हमारे सभी शिक्षक नमाज़ पढ़ने वाले और बुर्कावली हैं।
महिलाओं के लिए। सी.एन. विद्यालया प्रबंधन ने कहा, 'चिंता मत करो; हम भी करेंगे।'
उन्हें नमाज़ के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराएं।’ उन्होंने इसके लिए व्यवस्था भी की।
वज़ू (नमाज़ से पहले हाथ-पैर धोने की रस्म) के लिए। लेकिन मेरी बहन उन्होंने कहा, “उसकी चिंता मत करो। हम आने से पहले वे अनुष्ठान कर लेंगे। लेकिन
बात यह है कि उन्होंने हमारी मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाई। पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच व्यापारिक संबंध और वाणिज्यिक संबंध थे।
बातचीत तो हुई लेकिन सामाजिक मेलजोल नहीं हुआ। हममें से कुछ लोगों ने पहल करने का फैसला किया।

दोनों समुदायों के परिवारों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देना। और
इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी, जो एक पेशेवर कलाकार हैं,
वह हर साल मुस्लिम छात्रों के लिए एक कला कार्यशाला आयोजित करती हैं। जब उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया।
टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कवर की गई मुस्लिम बच्चों के लिए कार्यशाला, कई अन्य प्रकाशनों के अनुसार
हिंदू महिलाओं ने उन्हें फोन करके पूछा कि आप इस तरह की कार्यशालाएं क्यों नहीं आयोजित करतीं?
हमारे हिंदू मोहल्ले में भी। उसने कहा कि अगर वे उसे जगह दें तो वह वे खुशी-खुशी ऐसा करेंगे। एक परिवार जो एक कट्टर हिंदू बहुल इलाके में रहता है, जिसका नाम है...
मानेकबाग ने उन्हें अपने बंगले में जगह दी। वह बुर्का पहनने वाली एक मुस्लिम महिला थीं।
उस हिंदू परिवार में हिंदू महिलाओं के लिए 30 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
हमारी बेटी की शादी में सैकड़ों हिंदू परिवार आए थे। राज्य के अनुसार
वास्तविक सामाजिक शांति और सुरक्षा, अंतर-सामुदायिक संबंधों का अनुभव कर रहा है
अब वे काफी अधिक सहज हो गए हैं। मैं अपने साथी मुसलमानों से कहता हूं, हमें भी यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने की पहल। मुसलमान अब और इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते।
अलग-थलग, एकाकी व्यवहार। हमने अपने आस-पास के लोगों से परिचित होने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया है।

हिंदू भाइयों को हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी है। उदाहरण के लिए, कई हिंदू...
यह धारणा कि 'अल्लाह-ओ-अकबर' मुसलमानों का युद्धघोष (हमले का नारा) है।
हम किस तरह के मुसलमान हैं? हमें खुल कर बात करनी होगी और क्योंकि दान की शुरुआत यहीं से होती है।
घर पर, मैंने अपनी बेटी की शादी से शुरुआत की। लेकिन आज ऐसे सामाजिक 352 मोदी, मुसलमान और मीडिया

सत्ताधारी पार्टी के कारण पूरे गुजरात में बातचीत शुरू हो गई है। यह विभाजनकारी शक्ति के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। यह मूल्यों को बनाए रखकर सुरक्षा की भावना प्रदान कर रहा है।
कानून का शासन। लोग एक-दूसरे को पहले की तरह संदेह की नजर से नहीं देखते।
ऐसा तब होता था जब दंगों को नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से आयोजित किया जाता था।
पहले, एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा चालक किसी भी तरह की यात्रा करने से डरता था।
अब वह एक कुलीन हिंदू क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से ऐसा कर सकता है। मुस्लिम प्लंबर, बढ़ई और
अब मैकेनिक बिना किसी डर के हिंदू बहुल इलाकों में काम कर रहे हैं और
अब तो काम के लिए रात भर रुकने से भी डर नहीं लगता। नए अवसर मिल गए हैं।
‘अमन ओ-ईमान’ के कारण यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मोदी ने इसकी घोषणा नहीं की।

कांग्रेस पार्टी की तरह कोई भी 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम। अगर आपके पास है
सुशासन हो तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है।
मोदी के आलोचक हमसे कहते हैं, "आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी आरएसएस के प्रचारक थे।"
मैं उनसे कहता हूं, अगर आरएसएस मोदी के विचारों और समावेशी मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है
अगर विकास की बात हो, तो हम खुशी-खुशी आरएसएस का समर्थन करेंगे। देखिए, बड़ा मुद्दा यह है कि
मुसलमानों को हमेशा से जान माल की हिफाज़त (जीवन और संपत्ति की सुरक्षा) का ख्याल रखा जाता रहा है। आज,
मुसलमानों को इस बात का आश्वासन है कि वे अब डर में नहीं जी रहे हैं। और
उद्यमशीलता गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक उन्नति के द्वार भी खुले हैं।
ग्रामीण मुसलमानों के लिए भी खुला है। पटेलों का वर्चस्व है, उन्हें परवाह नहीं।
अगर मोदी मुख्यमंत्री हैं या केशूभाई या माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री हैं।
ये वे लोग हैं जिनके पास जमीन और अन्य संसाधन हैं, जिनमें प्रवासी भारतीयों से संबंध भी शामिल हैं।
मोदी के शासन से सबसे ज्यादा लाभ गरीब मुसलमानों को ही मिला है। कांग्रेस से संबद्ध वामपंथी “धर्मनिरपेक्षतावादियों” द्वारा फैलाया गया एक और मिथक यह है कि गुजरात सरकार और गुजराती हिंदुओं की शत्रुता के कारण लाखों मुसलमान गुजरात छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं। इस मुद्दे पर ज़फ़र का कहना है:
गुजरात की मुस्लिम आबादी में कोई गिरावट नहीं आई है। इसलिए,

नरसंहार की बात करना गैरजिम्मेदाराना है। नरसंहार एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए।
इसका प्रयोग इतनी लापरवाही से करें। दंगों के तुरंत बाद, कुछ लोग गुजरात छोड़कर चले गए। लेकिन लगभग
वे सभी जल्द ही लौट आए। अंसारी नाम का मुस्लिम दर्जी भी।
जिसका भयभीत चेहरा 2002 के दंगों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वह गुजरात लौट आया है।
कुछ महीने "धर्मनिरपेक्ष" वाम मोर्चे के शासित पश्चिम बंगाल में बिताने के बाद, जहाँ
तीस्ता सेतलवाद ने उसे भेजा था। अब वह अपने "धर्मनिरपेक्ष" लोगों से सुरक्षा चाहता है।
उन्होंने अपने शुभचिंतकों के खिलाफ उनके नाम का दुरुपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है।
और तस्वीर।
जब मैं इंग्लैंड में था और दंगे हो रहे थे, तब भी मैं अपने साथियों से यही कहा करता था।
वे मुसलमान जो सोचते थे कि भारत मुसलमानों के लिए नहीं है, कि भारत जैसा कोई देश नहीं है
हिंदू हृदय सम्राट या भारत के नए महमूद गजनवी? 353

भारत और दुनिया में अपने देश जैसा कोई स्थान नहीं है। इंग्लैंड में,
अपनी तमाम समानतावादी दावों के बावजूद, हम सभी एशियाई लोगों के लिए एक कांच की छत मौजूद है।
एक भारतीय होने के नाते, हमें एक सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन भारत में, हमारे पास

महाराष्ट्रियों और यहां तक कि बिहारियों की तरह "भूमिपुत्र" वाली राजनीति न अपनाएं।
वे इस वजह से असुरक्षित नहीं हैं। दरअसल, मोदी अन्य लोगों से कहते हैं।
राज्यों और यहां तक कि अन्य देशों से भी कहा जाता है, "गुजरात में आकर बसें, यहां निवेश करें, यहां विकास करें।"
आप अपने कौशल से मेरे राज्य की मदद कर सकते हैं।
मुझे मौलाना आजाद के वे शब्द याद हैं जिन्होंने मुसलमानों से विनती की थी।
जिन्होंने पाकिस्तान को चुना, अपनी वतन, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा।
कहा जाता है कि इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली के बाद कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बना।
इस्लाम के आधार पर मुसलमानों को एकजुट करने में संस्कृति और भाषा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
धर्म की तुलना में बंधनकारी कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

अध्याय 20

गैर-मुद्दों पर कमजोर विरोध
कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता और समर्थन क्यों खो दिया?

अब मैं आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, "मौत के सौदागर" को। आतंकवाद का "मौत का सौदागर", भ्रष्टाचार का "मौत का सौदागर", भाई-भतीजावाद का "मौत का सौदागर", सरकारी अक्षमता का "मौत का सौदागर", नौकरशाही की लापरवाही का "मौत का सौदागर", गरीबी और अज्ञानता का "मौत का सौदागर", अंधकार और निराशा का "मौत का सौदागर"। चो रामास्वामी, संपादक, थुगलक, चेन्नई में एक सभा में नरेंद्र मोदी का परिचय कराते हुए, 2008

मुझे पता है कि यह किताब नरेंद्र मोदी के पक्ष में "अत्यधिक एकतरफा" लग सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 12 वर्षों से लोगों ने केवल उनकी बेहद नकारात्मक छवि ही सुनी है। मैं इसे एक आवश्यक और बेहद ज़रूरी समाधान मानता हूँ। मेरा उद्देश्य नरेंद्र मोदी को पूर्णता का अवतार दिखाना नहीं है; मुझे यकीन है कि उनमें भी कुछ कमियाँ और खामियाँ हैं। लेकिन मैंने उनके और उनके काम को जितना भी देखा है, उनके पुराने दोस्तों, सहयोगियों, सहकर्मियों और अधिकारियों से जो कुछ भी जाना है, उससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि मोदी ने पक्षपातपूर्ण हितों और छोटी-मोटी राजनीति से ऊपर उठने का भरसक प्रयास किया है।
मैंने इस पुस्तक में जिन लोगों के कथन उद्धृत किए हैं, उन सभी की प्रामाणिकता की मैं पुष्टि करता हूँ। उनमें से कोई भी अपने कथनों से मुकरने की संभावना नहीं रखता। फिर भी, यदि पाठक इस पुस्तक में अनजाने में हुई किसी त्रुटि, तथ्यात्मक अशुद्धि या तथ्यों की गलत

व्याख्या की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो मैं क्षमा मांगने और सुधार करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मैंने यह यात्रा एक संशयवादी के रूप में शुरू की थी, लेकिन जैसे-जैसे मैंने गुजरात के कस्बों और गांवों की यात्रा की, भारत के लिए मेरे मन में आशा और सकारात्मकता का संचार हुआ।
ऐसा नहीं है कि मैंने गुजरात में मोदी के आलोचकों से मिलने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने गुजरात में मोदी के कांग्रेस समर्थित पेशेवर विरोधियों से मिलने से परहेज किया, जिनमें से कुछ मेरे पुराने दोस्त थे, लेकिन मैं जहां भी गया, मैंने स्थानीय कांग्रेसियों और भाजपा के असंतुष्टों से बात करने के लिए विशेष प्रयास किए। हर मामले में, मैंने मोदी के खिलाफ उनकी शिकायतों की पड़ताल की। हर मामले में, मुझे उनकी शिकायतें काफी गंभीर लगीं। गैर-मुद्दों पर कमजोर विरोध 355

यह आलोचना निराधार है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कांग्रेस की रणनीति अपनी पार्टी को सुधारने में ऊर्जा लगाने के बजाय भाजपा के भीतर मोदी विरोधी ताकतों को मजबूत करना रही है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस दिशाहीन है और पतन के कगार पर है। मैंने जिन अधिकांश कांग्रेसियों से मुलाकात की, वे अपने पार्टी नेताओं से बेहद नाखुश हैं और मोदी के खुलेआम प्रशंसक हैं। कई सम्मानित कांग्रेसी पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं; कई और भी ऐसा करने की राह पर हैं। मैं अपनी आगामी पुस्तक में ऐसे कुछ नेताओं के साक्षात्कार प्रकाशित करूंगा।
कांग्रेस की तुच्छ मुद्दों को उठाने की प्रवृत्ति: कांग्रेसियों द्वारा उठाए गए मुद्दे न केवल तुच्छ होते हैं, बल्कि अक्सर तथ्यों को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है। यही कारण है कि राज्य में उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। यहाँ एक उदाहरण दिया गया

है कि कांग्रेस पार्टी नमो के खिलाफ किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करती है, गुजरात की जनता के हित में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को ध्यान में रखते हुए, जो बिना सोचे-समझे वही छाप देता है जो उसे परोसा जाता है।
6 अगस्त, 2013 को अहमदाबाद स्थित हिमालय मॉल की प्रबंधन टीम ने अपने ग्राहकों को निम्नलिखित परिपत्र जारी किया:
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 9 अगस्त से 11 अगस्त 2013 तक हम "प्रतिपूर्ति योग्य मॉल प्रवेश" प्रणाली लागू करना। मॉल प्रवेश टिकट
छूट के रूप में प्रति व्यक्ति 20 रुपये का मूल्य होगा। राशि इस प्रकार होगी:
ग्राहक के बिल की राशि से प्रतिपूर्ति की जाएगी… उपरोक्त प्रणाली से मदद मिलेगी
ट्रैफ़िक को नियंत्रित करने, वास्तविक खरीदारों को आकर्षित करने और सभी के लिए व्यवसाय सुनिश्चित करने में हमारी मदद करें। किरायेदारों के लिए। शुरू में यह प्रणाली परीक्षण के आधार पर है। हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि...
आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक संपर्क करें।
मॉल कार्यालय…
यह उल्लेखनीय है कि इस परिपत्र में प्रवेश शुल्क के लिए किसी विशेष समुदाय को लक्षित नहीं किया गया है। मॉल के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर भी इस बात का कोई संकेत नहीं था कि मुस्लिम ग्राहकों से विशेष रूप से शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, दिवाली, नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों जैसे लोकप्रिय त्योहारों पर भारी भीड़ वाले मॉलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसे उपाय करना आम बात

है। हिमालय मॉल ऐसा करने वाला पहला मॉल नहीं है। और न ही यह प्रथा केवल गुजरात तक सीमित है।
356 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मैं उस समय गुजरात में था और मैंने देखा कि कैसे जाने-माने कांग्रेसी नेताओं ने इस मामूली घटना को एक बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विवाद में बदल दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि "मोदी के गुजरात" में मुसलमानों के साथ व्यवस्थित भेदभाव किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता पार्थ शास्त्री ने कांग्रेस द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट लिखी, जिसका शीर्षक था, "ईद पर अहमदाबाद मॉल मुसलमानों से प्रवेश शुल्क वसूल रहा है", जो 10 अगस्त, 2013 को टीओआई में प्रकाशित हुई थी।
ईद के उत्सव के माहौल में की गई यात्रा एक यादगार अनुभव में तब्दील हो गई।
नरेंद्र मोदी के गुजरात में कई मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। हिमालय
अहमदाबाद के पांच सबसे बड़े मॉलों में से एक, मॉल ने शुक्रवार को एक घोषणा की।
अल्पसंख्यक समुदाय के आगंतुकों से 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जिसे वापस कर दिया जाएगा।
उन्हें तभी छूट दी जाती थी जब वे मॉल से कुछ खरीदते थे, और अगर वे कुछ नहीं खरीदते थे तो उन्हें वहीं रखा जाता था।
कई लोगों को लगा कि ईद के दौरान जब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई तो यह एक विशिष्ट समूह के साथ भेदभाव था।
मॉल में भीड़ चरम पर थी। सुरक्षाकर्मी चुनिंदा तरीके से लोगों की तलाश कर रहे थे। हमने लोगों को देखा।

बिना कोई शुल्क दिए वहां से गुजर रहे थे। जब हमने सुरक्षा गार्डों से पूछा तो उन्होंने बताया कि...
उन्होंने कहा कि उन्हें आदेशों का पालन करना है और हमसे पैसे चुकाने को कहा...दीपा भटनागर।
हिमालय मॉल के मैनेजर (ऑपरेशंस) ने TOI को बताया कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी।
व्यस्त दिनों में आगंतुकों की जाँच करें। “हमने पहले भी इसी तंत्र का प्रयोग किया था।
उपद्रवियों को बाहर रखने के लिए हम पहले से ही व्यवस्था कर रहे हैं। हम प्रवेश शुल्क लेने की योजना बना रहे हैं।
आगामी त्योहारी मौसम, जिसमें दिवाली भी शामिल है, के दौरान शुल्क वापस किया जाएगा। यदि कोई शुल्क बकाया है तो उसे वापस कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, "खरीदारी हो जाने पर प्रवेश लगभग मुफ्त है।"
मॉल के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों की सामान्य आवाजाही के मुकाबले,
शुक्रवार को इनकी संख्या में भारी उछाल आया और यह लगभग 30,000 तक पहुंच गई। चयनात्मक के बारे में
प्रवेश शुल्क की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कुछ लोगों को बाहर रखने का फैसला किया है।
केवल महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। किसी को भी बाहर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
या विशिष्ट व्यक्तियों पर आरोप लगाएं,” उन्होंने कहा। हालांकि, इस संवाददाता ने देखा
प्रवेश की अनुमति देने का एक विशिष्ट पैटर्न। विशिष्ट आयु वर्ग के युवा।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जांच की जा रही थी और उनसे शुल्क चुकाने को कहा जा रहा था।
जबकि महिलाओं और कई अन्य लोगों को बिना किसी रोक-टोक के अंदर जाने की अनुमति दी गई थी।
आरोप लगाए गए। मॉल के अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल ईद के दौरान उन्होंने दो गुटों के बीच झड़पें देखीं।
मॉल के अंदर एक कांच की दीवार टूट गई। शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों की संख्या
कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई और पुलिसकर्मियों की एक टीम को अंदर तैनात कर दिया गया।
मॉल के बाहर ही, क्योंकि अधिकारी किसी भी तरह की "समस्या" नहीं चाहते थे।
हिमालय मॉल न तो मोदी के स्वामित्व में है और न ही उनसे दूर-दूर तक किसी का कोई संबंध है। यह सर्वविदित है कि बहुत से लोग मॉल में केवल विंडो शॉपिंग और वातानुकूलित वातावरण में समय बिताने के लिए जाते हैं।
गैर-मुद्दों पर कमजोर विरोध 357

विशेष रूप से चिलचिलाती गर्मी के महीनों में आराम। यह रिपोर्ट स्वीकार करती है कि त्योहारों पर मॉल में आने वाले लोगों की संख्या अनियंत्रित होती है। यह भी मानती है कि पिछली ईद पर मॉल के अंदर मुसलमानों के दो समूहों में झड़प हुई थी और कुछ संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था। इसलिए, प्रबंधन द्वारा अपने परिसर में इसी तरह की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष एहतियाती उपाय करना अनुचित नहीं है। लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स ने 10 अगस्त की रिपोर्ट में और मसाला जोड़ते हुए 12 अगस्त को एक पूरा लेख प्रकाशित किया, जिसका शरारती शीर्षक था "मोदी के अहमदाबाद में

भेदभाव"। टीओआई में पार्थ शास्त्री द्वारा लगाए गए बेतुके आरोप को दोहराने के बाद, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट निम्नलिखित पवित्र लगने वाले लेकिन राजनीतिक रूप से शरारती अनुच्छेद के साथ समाप्त होती है:
कई लोग सद्भावना चाहने वाले मुख्यमंत्री के साथ इसे अन्यायपूर्ण मानेंगे।
राज्य के नरेंद्र मोदी को उनके आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए
मॉल प्रबंधन। लेकिन यह ठीक उनकी राजनीति ही है जो उस संवेदनशीलता को जन्म देती है कि
मॉल द्वारा मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार करने के निर्णय के पीछे यही राजनीतिक कारण है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेतृत्व वाले संघ परिवार की विचारधारा से संघ, जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की प्रधानता में विश्वास रखता है और आरोप लगाता है
सभी गैर-हिंदुओं, विशेषकर मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया गया है।
परिवार का दावा है कि 2002 के बाद से गुजरात में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है।
यह मोदी सरकार की पहचान-निरपेक्ष शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
स्पष्टतः, मुसलमानों को चुपचाप हाशिए पर धकेलने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ हद तक।
जहां एक शॉपिंग मॉल खुलेआम उनके साथ भेदभाव कर सकता है। “मुसलमानों के हाशिए पर धकेले जाने” का जरा सा भी सबूत पेश किए बिना, यह लेख मुसलमानों में पीड़ित होने की भावना को भड़का रहा है। इस तरह की रिपोर्टिंग आम बात हो गई है। गुजरात के अखबारों को

अगर किसी भागकर शादी करने या घरेलू कलह की घटना की रिपोर्ट भी करनी पड़ती है, तो उसे तुरंत नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया जाता है, मानो हर जेबकतरों, हर छोटे-मोटे अपराध और यहां तक कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए वही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हों।
जब हिमालय मॉल की टीम और अन्य लोगों ने इस विकृत रिपोर्टिंग का विरोध किया, तो स्तंभकार प्रशांत पांडे ने इसे सिर्फ एक या दूसरे मॉल तक सीमित न रखते हुए सीधे नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुजरात को एक हिंदू फासीवादी राज्य में बदल दिया है। उनके द्वारा लिखे गए इस बेहद भड़काऊ लेख के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं:
358 मोदी, मुसलमान और मीडिया

आज टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद के एक मॉल ने मुसलमानों से शुल्क लेने का फैसला किया है।
(मुख्यतः युवा) शुभ तिथि पर मॉल में प्रवेश के लिए 20 रुपये "प्रवेश शुल्क" के रूप में लेते हैं।
ईद के दिन। इसका छिपा हुआ अर्थ यह धारणा है कि मुस्लिम युवा उपद्रवी। इसका थोड़ा नरम वैकल्पिक उपसंहार यह है कि मुस्लिम युवा ये ऐसे आवारा लोग हैं जो वातानुकूलित मॉलों में समय बिताते हैं लेकिन वास्तव में कुछ खरीदते नहीं हैं।
कुछ भी। क्या गुजरात के अलावा किसी और राज्य में इसकी अनुमति होगी?
बेशक, यह एक "निजी" मॉल है और इसमें मोदी को घसीटा नहीं जा सकता। चर्चा। लेकिन वास्तविकता में, सार्वजनिक व्यवहार को आकार देने में सरकार की भूमिका।
इस प्रकरण से यह स्पष्ट है। बात यह है कि लोगों के कुछ निश्चित विचार होते हैं।

दृष्टिकोण का—गुजरात के मामले में, मुसलमानों के प्रति अत्यधिक सतर्कता—यही कारण है कि
वे एक विशेष पार्टी (भाजपा) को सत्ता में लाने के लिए वोट देते हैं। फिर पार्टी इस पर प्रतिक्रिया देती है।
और इस तरह से कार्य करता है मानो वह केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो।
यह भूल जाता है कि एक बार चुने जाने के बाद, यह सभी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे गैर-प्रतिनिधि बनना होगा।
पक्षपातपूर्ण। इस प्रकार का राजनीतिक आचरण जनता की प्रतिगामी सोच को बढ़ावा देता है।
और भी अधिक मजबूत। इसके बजाय, एक अधिक उदार, एक अधिक "राष्ट्रवादी" पार्टी।
अपने अनुयायियों के विचारों को आधुनिकता की ओर मोड़ने का प्रयास किया होगा। लेकिन
नहीं, गुजरात में भाजपा ऐसा नहीं करती। यहाँ पार्टी जनता के समर्थन से चलती है और
इसके विपरीत भी। यह चौंकाने वाला है, और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे देखा है, कि मुस्लिम विरोधी भावनाएँ
आज अहमदाबाद में लोगों की भावनाएं बीस साल पहले की तुलना में कहीं अधिक खराब हैं...
गुजरात भले ही समृद्ध हो, लेकिन सामाजिक रूप से बेहद गरीब है। यहाँ के लोग मुश्किल से ही गुज़ारा कर पाते हैं।
उदारवादी कहलाना... मोदी को ही देख लीजिए। वो गर्व से खुद को हिंदू बताते हैं।
राष्ट्रवादी। स्पष्ट है कि वह हिंदुओं का नेता है, बाकी सब भाड़ में जाएं।

मानो इतना काफी नहीं था, वह इसे पहनने से इनकार करके अपनी बात पर और जोर देता है।
मुस्लिम टोपी। क्यों? क्या टोपी पहनने से वह अपवित्र हो जाएगा? हर एक
हम हिंदू मुसलमानों के साथ ईद मनाते हैं, है ना? हमारे नेता ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
तो फिर जश्न भी मनाएं?
यह किसी तथ्यात्मक समाचार रिपोर्ट या यथार्थवादी विश्लेषण की बजाय कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि द्वारा लिखे गए प्रचार पत्र जैसा लगता है। इस असंबंधित घटना को अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए टोपी वाले प्रकरण से जोड़कर, पत्रकार यह दर्शाता है कि वह एक पूर्व-निर्धारित राजनीतिक एजेंडे का आँख बंद करके अनुसरण कर रहा है और कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा प्रचलित वैचारिक बकवास को लाखों बार दोहरा रहा है।1 इस पुस्तक के पिछले अध्यायों को पढ़ चुके लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का आचरण उनके प्रति लगाए जा रहे घृणित आरोप से कितना भिन्न है। लेकिन दिल्ली में बैठे पांडे के पास और भी जहर उगलने को है:
1. खोपड़ी टोपी की कहानी पर मीडिया द्वारा मचाई गई शरारतों का विस्तृत विवरण जानने के लिए, अध्याय 16, "का" देखें।
खोपड़ी और पिल्ले।"
गैर-मुद्दों पर कमजोर विरोध 359

क्या सरकार इस मॉल के खिलाफ जांच शुरू करेगी? क्या वह सुनिश्चित करेगी?
क्या ऐसा आचरण दोबारा कभी नहीं दोहराया जाएगा? क्या मोदी इस घृणित कृत्य के बारे में बोलेंगे?

क्या मोदी ने अपने किसी भी भाषण में ऐसा आचरण किया है? असंभव। पहली बात तो यह है कि शायद मोदी
ऐसी बातों का समर्थन करता है। उन पथभ्रष्ट मुसलमानों को दूर रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो
नस्लीय भेदभाव हो तो ठीक है। इससे मोदी को और अधिक वोट ही मिलेंगे। दूसरा,
मोदी ने प्रतिगामी सामाजिक प्रवृत्तियों के खिलाफ बोलने का साहस शायद ही कभी दिखाया है।
उन्हें चुनौती देने की बजाय उनके साथ चलना पसंद है। और चुनावी वर्ष में, वह
अगर इससे उसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो उन्हें पंखा करने में भी खुशी महसूस करेगा। नतीजा: ऐसा मत करो।
गुजरात सरकार से किसी भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। और कोई कार्रवाई न करके,
सरकार दूसरों को भी इसी तरह के घृणित कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी... दुबई।
और इसके शेख, गुजरात या इसके वर्तमान नेताओं की तुलना में कहीं अधिक उदार हैं।
आजकल गुजरात से आने वाली ऐसी किसी भी खबर से मुझे आश्चर्य नहीं होता।
अगर मोदी एक दिन गुजरात को हिंदू राज्य घोषित कर दें तो मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा।
उसे रोकने वाली एकमात्र चीज संविधान ही है। राजनीतिक दृष्टि से, मोदी गुजरात के साथ पहले ही वो कर चुके हैं जो संविधान में वर्जित है। लेकिन
असल में, उन्हें प्रधानमंत्री बनने तक और उनकी पार्टी को बहुमत मिलने तक इंतजार करना होगा।

संविधान बदलने के लिए पर्याप्त संख्यात्मक शक्ति। मोदी समर्थकों, काम पर लग जाओ।
इस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करो!
असल सच्चाई यह है कि अहमदाबाद मॉल में जो कुछ हुआ वह चौंकाने वाला है।
लेकिन गुजरात के ध्रुवीकृत हिंदू राज्य से यह पूरी तरह से अपेक्षित था। यहां तक कि जब
यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का भेदभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है।
हर जगह। मोदी इन्हीं भावनाओं को हवा देते हैं। और चुनाव जीतते हैं। और फिर वे
वह ऐसे कृत्यों का संरक्षण न करके अपने लोगों को पुरस्कृत करता है। एक दूसरे से पोषित होता है। क्या हम ऐसा करते हैं?
क्या आप इसे पूरे भारत में चाहते हैं?
यह उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद के मुसलमानों ने कथित भेदभाव के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। ईद के दौरान मुस्लिम ग्राहकों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बावजूद, कांग्रेस समर्थक मीडिया ने भारत और विश्व भर के मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि मोदी मुसलमानों के कल्याण के लिए खतरा हैं और इसलिए उन्हें केंद्र में उनके सत्ता में आने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
कांग्रेस और वामपंथी दलों के इशारे पर मीडिया द्वारा चलाया जा रहा मोदी विरोधी यह निरंतर अभियान हमारे देश के भविष्य के लिए खतरनाक परिणाम ला सकता है। ऐसे समय में जब भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी मुसलमानों का एक वर्ग विस्फोटक अवस्था में है और आतंकवाद को अपनी वास्तविक और काल्पनिक शिकायतों का वैध समाधान मानने लगा है, तब काल्पनिक आधार पर मुसलमानों में उत्पीड़न की

भावना को बढ़ावा देने वाले लोग आग से खेल रहे हैं। इसका दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह है कि 360 मोदी, मुसलमान और मीडिया

यहां तक कि जायज़ शिकायतों को भी अविश्वास की नज़र से देखा जाता है। दुनिया में कहीं भी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों और मुख्यधारा के मीडिया ने मिलकर पहले से ही उत्तेजित धार्मिक अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के खिलाफ भड़काने का काम नहीं किया है, जबकि बहुसंख्यक उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
राजकोट में इसी तरह की एक घटना में, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के चौकीदार ने नौकरी से निकाले जाने पर खुद को आग लगा ली। चूंकि वह आवंटित आवास छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मालिकों ने उस पर मुकदमा दायर कर उसे आवास से बेदखल करने की कोशिश की। उन पर आरोप था कि उसने सोसाइटी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अपने परिवार के लिए अतिरिक्त कमरे बनाकर आवास का दुरुपयोग किया है। हाउसिंग सोसाइटी का मोदी या भाजपा से कोई संबंध नहीं था। यह एक निजी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच स्थानीय विवाद का मामला था। इसके बावजूद, इस खबर को गुजराती और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा गया और गुजरात और दिल्ली के प्राइम टाइम टीवी चैनलों पर भी प्रमुखता से दिखाया गया ताकि यह दावा किया जा सके कि "मोदी के गुजरात" में गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं।
सौभाग्य से, इस मामले में चौकीदार हिंदू था, मुसलमान नहीं। कांग्रेसियों ने उसे यह भयावह कदम उठाने से रोकने के बजाय, उसे आत्मदाह के लिए उकसाया। उन्होंने आत्मदाह की धमकी को फिल्माने की पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। यह आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट मामला था, लेकिन मीडिया ने इसे गरीबों के प्रति मोदी की संवेदनहीनता के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया।

गुजरात में रहते हुए मैंने देखा कि कांग्रेसी लोग युवा प्रेमियों के भाग जाने पर हंगामा मचा रहे थे और इसे इस बात का "सबूत" बता रहे थे कि मोदी के गुजरात में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गुजरात में यह एक आम मज़ाक है कि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर कांग्रेसी इतने बेकाबू हो गए हैं कि अगर कोई गृहिणी गलती से अपनी दाल या चपाती जला भी दे, तो वे इसका दोष मोदी पर मढ़ देते हैं।
गाय की हत्या पर प्रतिबंध को लेकर आग भड़काना: ऊपर बताए गए तुच्छ मुद्दों के विपरीत, मुस्लिम समुदाय के कसाई समुदाय का एक वर्ग मोदी सरकार के खिलाफ शिकायत का एक ठोस कारण बता सकता है। वे गुजरात में गाय की हत्या पर प्रतिबंध के अपेक्षाकृत सख्त कार्यान्वयन को लेकर भाजपा के साथ संघर्ष कर रहे हैं। गोमांस बकरी के मांस की तुलना में काफी सस्ता होता है। इसलिए, कई गरीब मुस्लिम परिवार इसे चुनते हैं। इसके अलावा, खाड़ी देशों को गोमांस का निर्यात एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है, खासकर इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार भारत से मांस निर्यात को बढ़ावा देकर "गुलाबी क्रांति" को प्रोत्साहित करने के लिए भारी सब्सिडी देती है। भारत में अधिकांश मांस निर्यातक
गैर-मुद्दों पर कमजोर विरोध 361

इसलिए, इस सब्सिडी को मुसलमानों के भीतर उन तत्वों को धमकाने के लिए रिश्वत के रूप में देखा जाता है जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं।
उत्तर भारत के अधिकांश लोगों के विपरीत, गुजराती लोग गायों को पवित्र मानते हैं और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए ठोस सकारात्मक कदम उठाकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कि तब भी जब गायें बूढ़ी हो जाती हैं और दूध देना बंद कर देती हैं। इसलिए सीमा पार गायों की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई

आम बात है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुलिस हमेशा गायों को अवैध रूप से वध के लिए ले जाने से रोकने के लिए गंभीर रहती है। अवैध शराब की बिक्री की तरह, इससे भी पुलिस को भारी रिश्वत मिलती है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सतर्कता समूहों पर भी वध किए गए जानवरों से भरे ट्रकों को पकड़ने और उन्हें पुलिस द्वारा जब्त करवाने में शामिल होने का आरोप है। यह मुद्दा दोनों पक्षों में तीव्र भावनाओं को जन्म देता है।
आम तौर पर, पारंपरिक गुजराती मुसलमान साझा सांस्कृतिक मूल्यों के कारण गौहत्या के पक्ष में नहीं हैं। गुजरात में गौहत्या के खिलाफ व्यापक विरोध को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेता भी इस मुद्दे को खुलकर नहीं उठा सकते, बल्कि पर्दे के पीछे से आग में घी डालते हैं। कांग्रेस समर्थित “धर्मनिरपेक्ष” गैर-सरकारी संगठन गौहत्या पर प्रतिबंध को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में पेश करते हैं, जिससे मुसलमानों में पीड़ित होने की भावना को बढ़ावा मिलता है, जबकि एक वर्ग स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है।
कृषि क्षेत्र के लिए अधिक बिजली की मांग: कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा मोदी पर लगाया गया अब तक का सबसे "गंभीर" आरोप यह है कि घरेलू उपयोग के लिए हर गांव में 24x7 बिजली की आपूर्ति होने के बावजूद वे कृषि क्षेत्र को आठ घंटे से अधिक समर्पित बिजली आपूर्ति देने से इनकार कर रहे हैं। कई बड़े भूस्वामी अधिक घंटों की बिजली चाहते हैं ताकि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से अधिक पानी निकाल सकें। गुजरात में अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने के बावजूद मोदी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका तर्क है कि भूमिगत जल पर निर्भरता कम किए बिना गुजरात में जल संकट बना रहेगा। इसलिए, उसे अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल का दोहन करने से बचना चाहिए। मोदी सरकार ने नहर

नेटवर्क, जल संचयन संरचनाओं और ड्रिप सिंचाई के विस्तार में भारी निवेश किया है, जिससे गुजरात उन कुछ राज्यों में से एक बन गया है जहां जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने लगी है। उन्होंने धरती के गर्भ से सारा पानी निकालने के दीर्घकालिक प्रभावों पर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। बिजली की कमी से जूझ रहे कांग्रेस शासनकाल के विपरीत, आज हर गांव को घरेलू उपयोग के लिए सुनिश्चित बिजली मिल रही है।

साथ ही खेतों के लिए भी, ट्यूबवेल मोटरों के असीमित उपयोग पर उचित प्रतिबंध लागू किया जाए। यही कारण है कि कांग्रेस अपनी पर्यावरण के लिहाज से अनुचित मांग के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने में असमर्थ है।
भाजपा के बागियों को शहीद बनाना: कांग्रेसियों द्वारा मोदी पर बार-बार लगाया जाने वाला एक और आरोप यह है कि केशूभाई, ज़ादाफ़िया और भाजपा के ऐसे कई दिग्गज नेताओं को मोदी ने दरकिनार कर दिया है। इसे उनके निरंकुश और असहिष्णु रवैये का अंतिम प्रमाण बताया जाता है। वामपंथी गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों द्वारा भी इसी आरोप को बार-बार दोहराया जाता है, जिसे मोदी की बेलगाम सत्ता की भूख का अकाट्य प्रमाण माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा नेता सदाचारी हैं। हिंदू-मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा देने सहित कई मोर्चों पर उनका दागदार इतिहास रहा है। इसलिए, मोदी के सत्ता में आने के बाद पार्टी छोड़ने वाले भाजपा के सबसे बुरे नेताओं के प्रति कांग्रेसियों द्वारा दिखाई गई सहानुभूति गुजरात में कोई सम्मान नहीं रखती।
यह बात विशेष रूप से इसलिए सच है क्योंकि कोई भी यह साबित नहीं कर पाया है कि मोदी ने केशूभाई और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया है, जबकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि केशूभाई के

तपस्वियों और असंख्य साधारण प्राणियों को। मोदी को, शिव की तरह, पसंद करना होगा।
नीलकंठ ने बहुत जहर निगला। लेकिन उन्होंने अच्छे लोगों को मजबूत करने की कोशिश की है।
अपनी पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार और अक्षमता पर लगाम कसते हुए, वह ऐसा नहीं कर सकता।
संतों की एक पार्टी बनाएं, खासकर इसलिए क्योंकि वह हमेशा से ही घेराबंदी में रहा है।
कांग्रेसियों के साथ-साथ दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी। वह संसद भंग नहीं कर सकते।
उन्हें जो पार्टी विरासत में मिली है, उसमें सुधार की ही गुंजाइश है। इस मामले में, यहां तक कि उनके अपने भी।
सबसे बड़े आलोचक भी यह स्वीकार करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक संगठन के रूप में कहीं अधिक स्वस्थ है।
यह केशूभाई के समय या किसी अन्य समय की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व किया है और संस्थागत नियंत्रण स्थापित करके शासन के मॉडल को बदल रहा है। केवल दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना।
चूंकि स्वयं
प्रमाण-पत्र पूरी तरह से वैध हैं, जो एक निवारक और संयम के रूप में भी कार्य करता है।

अध्याय 21

गुजरात के शहरों में नाइटलाइफ़
पैदल रास्तों पर पिकनिक
गुजरात पुलिस की बदलती भूमिका और धारणाएँ

हर रात तड़के सड़कों पर अकेली घूमती युवा महिलाओं की संख्या देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम गुजरात में कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अपराधी अन्य कई राज्यों, विशेषकर मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ इतनी बेखौफ होकर अपराध नहीं करते।
उत्तर प्रदेश की एक युवा महिला आईटी पेशेवर
मोदी साहब को सबसे ज़्यादा समर्थन मुस्लिम महिलाओं से मिलता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे अब गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनकी बेटियाँ भी उन्हीं अवसरों और आज़ादी का लाभ उठा सकती हैं जो उदार परिवारों की हिंदू महिलाओं को प्राप्त हैं... मेरी बेटी भी देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करती है। 15 साल पहले हमारे जैसे परिवार के लिए यह अकल्पनीय था... गुजरात महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है... अहमदाबाद में एक मुस्लिम टैक्सी मालिक।

गुजरात में अपने अध्ययन की शुरुआत में, मैं कुछ पारिवारिक मित्रों के साथ रुका था जो मेरे आने से लगभग आठ महीने पहले ही पटना से अहमदाबाद आए थे। पहली ही रात, उन्होंने मुझे गुजरात के शहरों की अनूठी रात्रिजीवन का अनुभव कराने पर ज़ोर दिया और मुझे रात 11 बजे के बाद शहर का भ्रमण कराया। वे मुझे यह दिखाना चाहते थे कि

गुजरात आना उनके लिए कितना मुक्तिदायक अनुभव था, क्योंकि पटना और बिहार के अन्य शहरों में तो पुरुष भी रात में बाहर निकलने से हिचकिचाते हैं, युवा महिलाओं की तो बात ही छोड़िए।
यह वह समय था जब दिल्ली और अन्य शहरों में बलात्कार विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था। अपहरण, बलात्कार और हत्याओं की लगातार घटनाओं से उपजे असुरक्षा के भाव ने भारत के कई शहरों और कस्बों में लाखों लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया था। दिल्ली में भी रात 10 बजे के बाद सड़कों पर अकेली महिलाएं शायद ही दिखाई देती हैं। लेकिन अहमदाबाद में महिलाओं के लिए स्थिति बिल्कुल अलग थी।
गुजरात के शहरों में नाइटलाइफ़ और फुटपाथों पर पिकनिक (365 दिन)

महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक जीवंत नाइटलाइफ़, और वह भी सभी वर्गों, जातियों और समुदायों को समाहित करते हुए।
सात्विक रात्रि पिकनिक
भारत में नाइटलाइफ़ को आमतौर पर महानगरों के पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग की जीवनशैली से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ है अमीरों के निजी घरों या पाँच सितारा होटलों में देर रात तक चलने वाली पार्टियाँ, जहाँ शराब परोसना अनिवार्य माना जाता है। यह पब और डिस्कोथेक में समय बिताने का भी पर्याय है, जहाँ शराब को एक आवश्यक साथी माना जाता है। इसके विपरीत, गुजराती शहरों की नाइटलाइफ़ अधिकतर शराब-मुक्त है और मुख्य रूप से सड़कों, फुटपाथों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में बिताई जाती है, जहाँ कई भोजनालय शाम के समय ही जीवंत होते हैं। यहाँ नियमित रूप से अपने पसंदीदा ठिकानों पर मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के साथ-साथ कामकाजी वर्ग के परिवार भी समान रूप से दिखाई देते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अभिजात वर्ग के घरों में निजी पार्टियाँ नहीं होतीं जहाँ लोग चुपके से शराब

परोसते हैं। लेकिन मनोरंजन का यह रूप गुजरात में अपेक्षाकृत कम प्रचलित है। गुजराती अभिजात वर्ग शराब पार्टियों का दिखावा नहीं करता, भले ही वे उन्हें आयोजित करें।
गुजरात के हर शहर में देर रात तक खुले रहने के अपने-अपने अनूठे ठिकाने हैं। उदाहरण के लिए, पुराने अहमदाबाद के बीचोंबीच स्थित रिहायशी और व्यावसायिक इलाका मानेक चौक, रात 8 बजे के बाद ही खाने- पीने के बाज़ार में गुलज़ार हो उठता है, जब रोज़मर्रा की दुकानें बंद हो जाती हैं। स्नैक्स और कुल्फी बेचने वाले ठेलों के बीच, सड़क पर साधारण मेज़-कुर्सियों वाले छोटे-छोटे भोजनालय नज़र आते हैं। इनमें पेरिस के कैफ़े जैसी चकाचौंध और माहौल तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा जीवंत और चहल-पहल भरे हैं। पेरिस या न्यूयॉर्क के कैफ़े में सिर्फ़ वयस्क जोड़े या दोस्तों के समूह ही नज़र आते हैं। लेकिन अहमदाबाद के रेस्तरां, भोजनालयों और ठेले पर पूरे परिवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अपने माता-पिता, दादा-दादी, चाची-मामा के साथ देर रात का खाना या रात के खाने के बाद स्नैक्स और आइसक्रीम का आनंद लेते नज़र आते हैं। मैंने देखा कि कुछ लड़कियाँ आधी रात के बाद तक स्कूटी पर मानेक चौक और शहर के अन्य चहल-पहल भरे स्थानों पर घूमने आती थीं।
विदिशा, जिससे मेरी मुलाकात मानेक चौक पर रात करीब 1:30 बजे हुई, उसकी उम्र 20 के आसपास है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में है। जब मैं उससे 13 जनवरी, 2013 को मिला, तो वह और उसकी सहेलियाँ अपनी स्कूटियों के पास खड़ी होकर बातें कर रही थीं। उसने मुझे बताया कि वह ट्यूशन खत्म करने के बाद रात करीब 11 से 11:30 बजे घर लौटती है। घर पर खाना खाने के बाद आधी रात के आसपास मानेक चौक आना उसकी रोज़ की आदत है। ज़्यादातर वह अपनी स्कूटी पर अकेली आती है। लेकिन कभी-कभी उसके चचेरे भाई-बहन भी उसके साथ आते

हैं। उसने ज़ोर देकर कहा कि उसे कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है।

देर रात बाहर रहने पर उसे यौन उत्पीड़न या अन्य प्रकार के गैरकानूनी व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार जब उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो जाता है या कोई अन्य यांत्रिक समस्या आ जाती है, तो कोई न कोई व्यक्ति उसकी स्कूटी को धक्का देकर उसके घर तक पहुंचा देता है। वह और उसके दोस्त—लड़के और लड़कियां दोनों— रोज रात में मानेक चौक पर समय बिताते हैं।
देश में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ आपको महिला स्ट्रीट वेंडर रात के 2 या 3 बजे तक अपना काम करती हुई दिखाई देंगी। इन ढाबों पर देर रात तक ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है, इसलिए स्ट्रीट वेंडर, जिनमें युवा लड़कियाँ भी शामिल हैं, ग्राहकों के जाने तक दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएँ, विशेष रूप से फल और सब्जियाँ बेचती रहती हैं। उदाहरण के लिए, 12 जनवरी, 2013 की रात को बापुनगर की तीन किशोर बहनें फल और गन्ना बेच रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि वे पूरी रात यहीं रहेंगी क्योंकि अगले दिन मकर संक्रांति थी - एक बड़ा त्योहार। इसलिए, उनकी पूरी रात अच्छी बिक्री होगी। त्योहारों के दौरान, कुछ हॉकर मार्केट लगभग पूरी रात खुले रहते हैं। सीजी रोड पर, मैंने एक युवा किशोरी से, उसके छोटे भाई के साथ, रात के 1:30 बजे अपनी ठेली को घर ले जाते हुए काफी देर तक बातचीत की।
फुटपाथों पर अड्डाबाज़ी
गुजरात के शहरी इलाकों की रात्रिजीवन का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि मुख्य सड़कों पर बने चौड़े फुटपाथों का व्यापक उपयोग पारिवारिक पिकनिक, प्रेम-प्रसंग करने वाले जोड़ों या फिर पुरुषों और महिलाओं (युवा और बुजुर्ग दोनों) के अड्डाबाज़ी (नियमित मिलन

स्थल) के रूप में किया जाता है। सबसे लोकप्रिय स्थान नदी पुलों के फुटपाथ होते हैं—चाहे वह अहमदाबाद की साबरमती नदी हो या सूरत की तापी नदी। सूरत, अहमदाबाद और अन्य शहरों में लोग सुबह तड़के तक नदी पुलों के फुटपाथों पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। परिवारों के लिए बड़े टिफिन बैग में खाना लाना और उसे घर से लाए गए अखबारों या चटाइयों पर फैलाना आम बात है। सड़क किनारे विक्रेता बच्चों के लिए स्नैक्स, गुब्बारे और खिलौने बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। बच्चे इधर-उधर दौड़ते हैं, खेलते हैं जबकि बड़े- बुजुर्ग घंटों बातें करते रहते हैं। गरीब और भीड़भाड़ वाले इलाकों के हिंदू और मुस्लिम जोड़े फुटपाथों पर या सड़क किनारे बेंचों पर बैठकर, परिवार की नजरों से दूर, सबके सामने 'निजी बातचीत' में मग्न रहते हैं, यह एक आम दृश्य है। यह केवल इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि गुजरात के शहरों में वास्तव में अपेक्षाकृत साफ-सुथरे फुटपाथ हैं जिन पर आरामदायक सार्वजनिक बेंचें लगी हुई हैं।
गुजरातियों को रात में नदी की ठंडी हवा का आनंद लेने का शौक होता है, इसलिए मोदी ने नदी तटों को नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्रों के रूप में विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी है। यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में यह आम बात है।
गुजरात के शहरों में नाइटलाइफ़ और फुटपाथों पर पिकनिक 367

विकसित देशों की तुलना में, भारत में गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य प्रतीत होता है जिसने नदी तट विकास को गंभीरता से लिया है। भारत की राजधानी में यमुना नदी के किनारे कूड़े के ढेर के रूप में इस्तेमाल होने के कारण इतने गंदे और दुर्गंधयुक्त हैं। दिल्ली में यमुना या कानपुर में गंगा के किनारे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संक्षिप्त यात्रा भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है।

गुजरात में नदी किनारे के विकास की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट से हुई, इसके बाद सूरत में तापी नदी के किनारे का विकास हुआ, लेकिन अब यह छोटे शहरों तक भी फैल रहा है। उदाहरण के लिए, बनासकांठा में कोई नदी नहीं है; इसके बीचोंबीच केवल एक नहर बहती है। इस छोटे से शहर में भी नहर के किनारे पेशेवर रूप से तैयार किए गए पार्क, शॉपिंग प्लाजा, सुव्यवस्थित सब्जी मंडी, हॉकर सेंटर और मनोरंजन सुविधाओं से युक्त एक लंबा पैदल मार्ग तेजी से विकसित किए जा रहे हैं।
मुस्लिम महिलाओं के लिए निहितार्थ
मुझे यह बात उल्लेखनीय लगी कि घनी आबादी वाले मुस्लिम बहुल इलाकों से परिवार देर रात घूमने के लिए हिंदू बस्तियों में आते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में रात के समय सड़कों पर ज्यादातर पुरुष ही दिखाई देते हैं, महिलाएं नहीं। इसी तरह, मुस्लिम बहुल शहरों के इलाकों में देर रात नाश्ते की दुकानों के आसपास अकेली मुस्लिम लड़कियां घूमती हुई दिखाई नहीं देतीं। वे सभी मौज-मस्ती के लिए हिंदू बस्तियों में आती हैं, जो सुरक्षा की भावना और संकीर्ण सोच से मुक्ति का संकेत है।
बार-बार होने वाले दंगों, विशेषकर 1990 के दशक में, के कारण दशकों तक चले धार्मिक ध्रुवीकरण के दौरान, मुसलमान हिंदू इलाकों में जाने से सचमुच डरते थे और इसके विपरीत भी। इस डर ने लोगों को तब भी रोके रखा जब दंगे नहीं हो रहे थे। आज अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि गुजरात के लगभग हर शहर में, 100 प्रतिशत हिंदू बहुल इलाकों में भी देर रात तक बुर्का पहने कई मुस्लिम महिलाएं दिखाई देती हैं। मैंने कई कामकाजी मुस्लिम परिवारों को देर रात नाश्ता या रात का खाना खाने के लिए बाहर आते देखा। वे स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी परिवारों से थे, महिलाएं बुर्का पहने हुए थीं, हालांकि किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका था। मैंने युवा बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं

को मोटरसाइकिलों पर पीछे बैठकर आते भी देखा। कॉर्पोरेट कार्यालयों के साफ-सुथरे पक्के परिसरों के बाहर, हिंदू और मुस्लिम परिवारों के छोटे लड़के-लड़कियों को गेंद और लंगड़ी टांग खेलते देखा गया। मेरे मेजबान परिवार ने मुझे बताया कि अहमदाबाद में ऐसे दृश्य काफी सामान्य और रोजमर्रा की बात हैं। बाद की यात्राओं के दौरान इसकी पुष्टि हुई। एक मुस्लिम टैक्सी मालिक ने मुझे बताया:
368 मोदी, मुसलमान और मीडिया

मेरी बेटी भी देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करती रहती है। यह
15 साल पहले हमारे जैसे परिवार के लिए यह अकल्पनीय था। आम धारणा यह थी कि
हिंदू और मुसलमान दोनों का मानना है कि गुजरात रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है।
महिलाओं के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ महिलाओं के अपहरण या दुर्व्यवहार की घटनाएँ नहीं होतीं।
दिल्ली में जिस तरह से छोटे बच्चों को फिरौती के लिए बंधक बनाया जा रहा है या उनकी तस्करी की जा रही है, उसी तरह से ये सब हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि गुजरात में अपराध बिल्कुल नहीं होता। दुनिया का कोई भी देश ऐसा दावा नहीं कर सकता। लेकिन
अन्य राज्यों की तुलना में अपराध दर काफी कम है और संगठित गिरोहों का प्रभाव भी कम है।
कड़ी निगरानी में लाया गया है।
मोदी साहब को सबसे ज्यादा समर्थन मुस्लिम महिलाओं से मिलता है क्योंकि वे

उन्हें लगता है कि उनके बेटे अब गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, वे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं।
जबकि उनकी बेटियाँ भी उन्हीं अवसरों और स्वतंत्रता का लाभ उठा सकती हैं जो उन्हें प्राप्त हैं।
उदारवादी परिवारों की हिंदू महिलाएं आनंद ले रही हैं। पुरुष रात के खाने के लिए घर आ रहे हैं।
और अपनी पत्नियों के साथ समय बिताना।
गुजरात के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और वर्तमान में वक्फ बोर्ड के प्रमुख ए.आई. सैयद ने बताया कि मुसलमानों में आपराधिक तत्वों के हाशिए पर चले जाने से मुस्लिम महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली है।
कांग्रेस शासन के दौरान, मुसलमानों के बीच गुंडा तत्वों को काफी छूट मिली।
प्रोत्साहन। उन दिनों कई मुस्लिम भाई (डॉन) हुआ करते थे।
इससे मुस्लिम महिलाओं का जीवन कहीं अधिक असुरक्षित हो गया। इसके अलावा, इसने मदद भी की।
इससे मुस्लिम समुदाय की नकारात्मक छवि प्रस्तुत हुई और पूर्वाग्रह पैदा हुआ।
उनके खिलाफ। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के बीच असामाजिक तत्वों के कारण।
नियम लागू कर दिए गए हैं और यह संदेश दे दिया गया है कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुसलमानों को आतंकित करके उन्हें डराने से, मुसलमान अपनी
हिंदू गुंडों से मुकाबला करने के लिए अपने डॉन। परिणामस्वरूप, महिलाएँ अधिक स्वतंत्र होकर नेतृत्व कर रही हैं
यहां तक कि पूर्व के पारंपरिक मुस्लिम इलाकों में भी जीवन व्यतीत करता है।

वास्तव में, मेरे लिए सबसे रोचक दृश्य किशोरियों और युवतियों का था, जिनमें से कई मुस्लिम थीं, जो आधी रात के बाद भी अकेले या किसी अन्य महिला को पीछे बिठाकर दोपहिया वाहन चला रही थीं। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया।
आजकल, जुहापुरा समेत कभी खौफनाक माने जाने वाले मुस्लिम बहुल इलाकों में भी रात के समय बड़ी संख्या में हिंदू मांसाहारी भोजन के लिए जाते नजर आते हैं। हालांकि, हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमानों की भारी भीड़ की तुलना में उनकी संख्या अभी भी कम है। पहली बात तो यह है कि बहुत कम गुजराती हिंदू मांसाहारी भोजन करते हैं।
गुजरात के शहरों में रात्रि जीवन और फुटपाथों पर पिकनिक 369

मांसाहारी भोजन। दूसरा, जुहापुरा जैसे 100 प्रतिशत मुस्लिम बहुल इलाके कांग्रेस नेताओं के गढ़ बने हुए हैं, जो विभाजनकारी भावना और आपसी अविश्वास को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके विपरीत, भाजपा नेताओं को दोनों समुदायों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने का जनादेश दिया गया है।
जीवंत अर्थव्यवस्था ने अपराध गिरोहों पर अंकुश लगाया। तीस्ता सेतलवाद के पूर्व दाहिने हाथ रहे रईस खान पठान, जिनका बाद में उनसे मतभेद हो गया था, बताते हैं कि कानूनों के समग्र रूप से सख्त कार्यान्वयन ने मुसलमानों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए अधिक अवसर प्रदान किए हैं।
आज मुसलमान अपने समुदाय के उन सरगनाओं के बचाव में खड़े नहीं होते, जो
अवैध शराब बनाने, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री आदि में शामिल।

लेकिन केवल पुलिस की कार्रवाई से गुंडों और अवैध धंधों में शामिल लोगों को हाशिए पर नहीं डाला जा सकता।
व्यापार। मेरा ही उदाहरण लीजिए; मेरा गुटखा बनाने का एक फलता- फूलता व्यवसाय था।
मेरा मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी आपूर्ति श्रृंखला गुजरात में थी। अब वहां सख्त नियम लागू हैं।
राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लागू करना, क्योंकि इससे कैंसर होने का खतरा होता है।
अधिकांश अन्य राज्यों में गुटखा प्रतिबंध सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। लेकिन गुजरात में हमें ऐसा करना पड़ा।
दुकान बंद करनी पड़ी। हालाँकि इस प्रतिबंध से मेरे फलते-फूलते व्यवसाय को भारी झटका लगा,
मैं आसानी से दूसरे व्यवसायों में जा सकता था और अच्छा पैसा कमा सकता था। आज,
आर्थिक उन्नति के लिए अनगिनत वैध रास्ते उपलब्ध हैं।
मुसलमानों के लिए शैक्षिक अवसरों में भारी वृद्धि के साथ-साथ,
आज के युवा मुसलमानों को अपराध के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता।
नशे में धुत होकर मौज-मस्ती किए बिना नाइटलाइफ़
जनवरी 2013 की अपनी यात्रा के दौरान, मैंने अहमदाबाद में लगातार तीन रातों तक कई युवा जोड़ों से बात की। इनमें से अधिकांश जोड़े 20 से 30 वर्ष की आयु के थे और उन्होंने बताया कि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। कुछ इंग्लैंड या अमेरिका से छुट्टियां मनाने घर आए थे। कई लोगों ने कहा कि वे लंदन या न्यूयॉर्क की तुलना में अहमदाबाद में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये युवा पुरुष विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि से थे, जिनमें डॉक्टर और आईटी पेशेवर शामिल थे। इनमें से कई युवतियां भी पेशेवर थीं। सप्ताहांत

में वे नियमित रूप से सीजी रोड पर मिलते थे और देर रात तक बैठकर बातें करते थे। महिलाओं ने मुझे बताया कि उनके ससुराल वाले जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उनके देर रात तक बाहर रहने पर परिवारों ने कभी कोई चिंता व्यक्त नहीं की क्योंकि वे अहमदाबाद में सुरक्षित महसूस करते हैं।
अहमदाबाद और अन्य शहरों की बाद की यात्राओं के दौरान भी ऐसी ही बातचीत दोहराई गई। लगभग सभी ने कहा कि 370 मोदी, मुसलमान और मीडिया एक महत्वपूर्ण कारण थे।

गुजरात के शहरों में उपद्रवी व्यवहार दुर्लभ होने का कारण राज्य में शराब की बिक्री पर आधिकारिक प्रतिबंध के चलते संयम की संस्कृति है। महात्मा गांधी के इस दृढ़ विश्वास के सम्मान में गुजरात में दशकों से शराबबंदी लागू है कि शराब समाज के शारीरिक और नैतिक कल्याण को कमजोर करती है।
बापू के राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रति मेरी दृढ़ प्रतिबद्धता के बावजूद, मैंने हमेशा राज्य द्वारा लगाए गए शराबबंदी का विरोध किया है, क्योंकि मैं इसे एक निरंकुश उपाय मानता था जिससे शराब की तस्करी और अवैध शराब के माफियाओं का उदय होता था। लेकिन जब मैंने गुजरातियों को शराबबंदी से सामाजिक सुरक्षा को जोड़ते हुए सुना, तो मुझे अपने इस विचार पर गंभीरता से पुनर्विचार करना पड़ा। मैं मानता हूँ कि मैंने उन संभ्रांत पार्टी-प्रेमी लोगों से संपर्क नहीं किया जो चोरी-छिपे शराब परोसते हैं। मैंने केवल आम लोगों और गरीब बस्तियों की महिलाओं से बात की। ये महिलाएं शराबबंदी की सबसे प्रबल समर्थक हैं, क्योंकि गरीबों में नियमित रूप से शराब पीने वाले लोग घरेलू हिंसा करने की अधिक संभावना रखते हैं। मुसलमानों में भी शराबबंदी काफी लोकप्रिय है।

घर की चारदीवारी में तो लोग शराब का सेवन कर लेते हैं, लेकिन गुजरात में शराब पर आधिकारिक प्रतिबंध के कारण कोई भी सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता। पुलिस को ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश हैं; यहां तक कि अगले दिन स्थानीय अखबारों में उनकी तस्वीरें भी प्रकाशित की जाती हैं। यही सबसे बड़ा निवारक कारक है। यहां तक कि जब लोग निजी पार्टियों में या दोस्तों के बीच शराब पीते हैं, तो वे संयम से पीते हैं ताकि अक्सर उनके माता-पिता को भी पता न चले। सार्वजनिक स्थानों पर शराबियों की पूर्ण अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारण है कि गुजरात महिलाओं के लिए कहीं अधिक सुरक्षित है।
मैंने युवाओं के कई समूहों से पूछा कि क्या उन्हें पब कल्चर और डिस्कोथेक पार्टियों की याद आती है। लगभग रात 12:30 बजे टहल रही दो युवतियों की बातों से ही सबकी राय स्पष्ट हो गई:
गुजरात में डिस्कोथेक तो हैं, लेकिन वहां शराब नहीं परोसी जाती। शराब से परहेज करना उचित नहीं है।
सुरक्षा और संरक्षा की भावना के लिए शराब बहुत छोटी कीमत है।
गुजराती
हम जानते हैं कि जीवन का आनंद कैसे लेना है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि शराब पीना आवश्यक नहीं है।
आनंद के लिए। शराब का सेवन किए बिना भी बहुत मज़ा लिया जा सकता है। मत करो
आप खुद ही देख लीजिए कि देर रात तक भी हमारे चारों ओर का वातावरण कितना शांत और तनावमुक्त रहता है।
रात का नजारा? आप युवा महिलाओं और यहां तक कि बच्चों वाले परिवारों को आनंद लेते हुए देखते हैं।

उनकी रात की सैर। दिल्ली में लोग रात 9 बजे बस में चढ़ने से डरते हैं क्योंकि
बसें शराबियों से भरी पड़ी हैं। कंडक्टर तो उन्हें कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं करते।
वे टिकट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये शराबी हिंसक हो सकते हैं। आपको टिकट नहीं मिलेंगे।
गुजरात में ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। वहां के लोग काफी शांत हैं और इस तरह के व्यवहार की प्रवृत्ति बहुत कम है।
सार्वजनिक स्थानों पर झगड़े करना या छोटी-छोटी बातों पर हिंसक झड़प में शामिल होना।
इसका संबंध सामाजिक बंधनों से है।
मैंने जिन लगभग सभी श्रमिक वर्ग के पुरुषों और महिलाओं से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि शराबखोरी के कारण पत्नियों पर होने वाली मारपीट और अन्य प्रकार के अपराधों में गरीब बस्तियों में भी कमी आई है, जब से शराब की अवैध बिक्री करने वाले माफियाओं पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया है। लगभग बीस साल पहले मैंने स्वयं गांधी आश्रम के ठीक पीछे एक झुग्गी बस्ती में शराब बनते हुए देखा था।
यह कहना उचित होगा कि गुजरात में दशकों से शराबबंदी लागू है, इसलिए इसके अच्छे या बुरे प्रभावों का श्रेय मोदी को नहीं दिया जा सकता। हालांकि, गुजरात में शराब से जुड़े अपराध और सामाजिक हिंसा में कमी आई है क्योंकि अब केवल छोटे-मोटे शराब तस्कर ही मामूली जीविका कमाने के लिए अवैध शराब के व्यापार में शामिल हैं। बड़े सरगना या तो धंधे से बाहर हैं या जेल में हैं। अन्य लोग अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक तंगी के कारण राज्य छोड़कर चले गए हैं। 372 मोदी, मुस्लिम और मीडिया

आज पुलिस में अनुशासन पहले से कहीं अधिक है। सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रवी व्यवहार, चाहे वह राजनीतिक नेताओं द्वारा किया गया हो या छोटे-मोटे बदमाशों द्वारा, से अधिक सख्ती से निपटा जाता है।
यही कारण है कि शराब भले ही चोरी-छिपे आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इसका सेवन दिखाई नहीं देता। अहमदाबाद में निजी डांस पार्टियां भी महानगरों के डिस्कोथेक या निजी फार्म हाउसों की तुलना में कहीं अधिक संयमित होती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में, आलीशान मॉल में स्थित शोरूम के मालिक, जहां अमीर और मशहूर लोग खरीदारी करने जाते हैं, नगर अधिकारियों से पब बंद करने का अनुरोध करने लगे हैं क्योंकि असामाजिक तत्व ऐसे स्थानों के आसपास जमा होते हैं और माहौल को असुरक्षित बना देते हैं। लगभग सभी पब और डिस्कोथेक अमीर गुंडों से निपटने के लिए मार्शल और बाहुबलियों को बाउंसर के रूप में रखते हैं, जो ऐसे स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं।
भारत के छोटे शहरों और कस्बों में भी पबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। उदाहरण के लिए, 12 जुलाई 2012 को असम के गुवाहाटी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक जी.एस. रोड पर एक पब के बाहर लगभग 30 लोगों ने एक 16 वर्षीय लड़की को निर्वस्त्र कर उसके साथ छेड़छाड़ की। वह अपनी एक दोस्त का जन्मदिन मनाने गई थी। लेकिन, उसके दोस्तों के चले जाने के बाद, उसे अलग कर लिया गया और उस पर हमला किया गया। आंध्र प्रदेश के तेनाली में, गांधी चौक नामक एक लोकप्रिय शॉपिंग सेंटर में एक स्थानीय बार से निकले शराबी लोगों के एक समूह ने 45 वर्षीय बेथाला कंथासुनीला नाम की महिला को पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने महिला को इसलिए पीटा और एक लॉरी के नीचे धकेल दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी, जो बी.टेक की छात्रा थी, पर हमला करने और उसे रास्ते में

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और पुलिस पर उनके प्रभाव के कारण। सरकार की शराब
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आउटलेट नीलामी
आदि एक भयावह दृश्य है जहाँ हर विचारधारा के राजनेता बड़ी संख्या में आते हैं।
बंदूकधारियों ने खुलेआम गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। चूंकि ग्रामीण इलाकों में शराब विरोधी आंदोलन ज्यादातर वामपंथी संगठनों द्वारा आयोजित किए गए हैं, जो गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों को संगठित करते हैं, इसलिए उन्हें नारीवादियों का भरपूर समर्थन मिला। हालांकि, जब शहरी समुदाय बार और पब संस्कृति के प्रसार के खिलाफ विरोध करते हैं, जो असामाजिक तत्वों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं, तो इसे प्रतिगामी और "दक्षिणपंथी" मांग बताकर निंदा की जाती है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना है।
जनवरी 2013 में गुजरात अध्ययन की शुरुआत में अहमदाबाद की अपनी पहली यात्रा के दौरान, शहर के मेरे एक ट्विटर फॉलोवर ने मुझे लिखा, “जब आप वहां हों, तो एक पुलिस स्टेशन जरूर जाएं। आप (खुशी से) चौंक जाएंगे।” गुजरात में पुलिस व्यवस्था में आए बदलाव को देखने के लिए मुझे प्रेरित करते हुए उनके संदेश में गर्व झलक रहा था। गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान, मैंने कई छोटे कस्बों और गांवों के पुलिस स्टेशनों का दौरा किया और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से हैं। सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में पुलिस का ढांचा और प्रदर्शन भारत के अन्य राज्यों के अधिकांश शहरों से कहीं बेहतर है। पुलिस स्टेशनों से कहीं अधिक, यह बदलाव कानून व्यवस्था की स्थिति के प्रति लोगों की सोच में दिखाई देता है। सार्वजनिक स्थानों पर

महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या महिलाओं के अपहरण और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं भारत के कई राज्यों में आम हो गई हैं। लेकिन गुजरात में ये घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। लेकिन महिलाएं केवल इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि अमीर और गरीब दोनों तरह के पुरुष भी सुरक्षित महसूस करते हैं। अहमदाबाद से गांधीनगर तक मुझे ले जाने वाली निजी टैक्सी के ड्राइवर, छब्बीस वर्षीय गोविंद कहते हैं:
गुजरात में रात के समय भी राजमार्ग पर डकैती या लूटपाट जैसी घटनाएं नहीं होती हैं।
ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसलिए, यह हमारे व्यवसाय के लिए अच्छा है। लेकिन यह सब
यह सिर्फ पुलिस की कार्रवाई के कारण नहीं है। इस सरकार ने रोजगार और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
सभी के लिए अवसर। उदाहरण के लिए, आसपास एक गरीब आदिवासी बस्ती है। अंबाजी मंदिर। इस बस्ती के कुछ पुरुष अपराधों में लिप्त रहते थे। लूट। उस समुदाय को अब कचरा पुनर्चक्रण का ठेका दिया गया है। 374 मोदी, मुसलमान और मीडिया

इसलिए वे नियमित आय का स्रोत पाकर बहुत खुश हैं और व्यस्त हैं।
इससे पैसा कमाया जा रहा है। सरकार की योजना गुजरात को जीरो-डिग्री विकास उद्योग बनाने की है।
'कम करें, रीसायकल करें और पुनः उपयोग करें' के नारे के साथ गार्बेज स्टेट। इसलिए यह सबके लिए फायदेमंद है।
सभी के लिए।
भारत की राजधानी: मज़ाक का पात्र
अहमदाबाद और अन्य शहरों की सड़कों पर मेरी लगभग सभी बातचीत में, भारत की राजधानी दिल्ली, कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध

में हमेशा एक नकारात्मक प्रतिरूप और मजाक का पात्र बनकर उभरती थी।
Aapke shehar mein to car parking ko lekar hi goliyan chal jaati hai, log ek doosre
ka sir phod dete hain. Zara si car mein kisi ne takkar laga di aur chota sa dent
पड़ गया, तो मारा मारी हो जाती है। (लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं
आपके शहर में कार पार्किंग को लेकर छोटे-मोटे झगड़ों के कारण। अगर कोई ज़रा सी भी
किसी दूसरे व्यक्ति की कार पर मामूली खरोंच लगने पर (गुजरात में) एक बड़ा झगड़ा हो जाता है।
आपको ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिलता। किसी की कार पर खरोंच लगने पर कोई इतना गुस्सा नहीं करता।
एक और वाहन। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों में रोड रेज बहुत आम हो गया है,
गुजरात में लोग ऐसे मुद्दों पर शायद ही कभी भड़क उठते हैं। गुजरात की अपनी यात्राओं के दौरान मैंने कम से कम आधा दर्जन बार इस बात को सच होते देखा, जिनमें दो बार तो मेरी टैक्सी ने अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। व्यवहार में यह अंतर आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले बहुत आम हैं। गुजरात में ऐसा नहीं है। फुटपाथ पर बैठकर कुल्फी का आनंद लेते हुए बातें कर रहे कुछ दंपतियों ने दंगा-मुक्त गुजरात को अधिक सुरक्षा की भावना से जोड़ने की बात कही।
जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने अंतहीन कर्फ्यू देखे। हर हिंदू और मुसलमान

त्योहारों के कारण झड़पें होती थीं। आज, हर समुदाय अपना त्योहार मना सकता है।
ईद हो या नवरात्रि, हम शांतिपूर्वक त्योहार मनाते हैं। हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे बच्चे
वे कर्फ्यू देखे बिना बड़े हो रहे हैं। उन्हें तो कर्फ्यू शब्द का मतलब भी नहीं पता।
मतलब, अब कोई भी अपनी शारीरिक सुरक्षा को लेकर उस तरह चिंतित नहीं रहता जैसा हम रहते थे।
हम बड़े हो रहे थे।
इसका यह मतलब नहीं है कि गुजरात अपराध मुक्त राज्य है, लेकिन सड़कों पर मैंने जिन लोगों से बात की, उनमें से अधिकांश का मानना था कि उनका राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। यही कारण है कि बलात्कार विरोधी आंदोलन, जो भारत के कई कस्बों और शहरों में फैल गया, गुजरात में उतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि वहां की महिलाएं अकेले बाहर निकलने में उतना असुरक्षित महसूस नहीं करतीं जितना कि भारत के अन्य हिस्सों में करती हैं।
गुजरात के शहरों में रात्रि जीवन और फुटपाथों पर पिकनिक 375

उच्च सुरक्षा वाले आयोजनों की पूर्व संध्या पर भी पुलिस की कम मौजूदगी: गुजरात के शहरों की सबसे उल्लेखनीय बात सड़कों पर पुलिस की कम उपस्थिति है। अहमदाबाद या अन्य शहरों में मैंने अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पैदल या गाड़ी से जितने दिन बिताए, मुझे कहीं भी वाहनों की जाँच के लिए पुलिस बैरिकेड नहीं दिखे – जो दिल्ली में बहुत आम बात है। जनवरी 2013 की मेरी यात्रा के दौरान यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक था क्योंकि मैं मकर संक्रांति (प्रसिद्ध पतंग उत्सव) और गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अहमदाबाद पहुँचा था। इसलिए, भारत और

विदेश से मंत्रियों, राजदूतों और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों का एक बड़ा दल प्रतिदिन अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच यात्रा कर रहा था। लेकिन शिखर सम्मेलन स्थल के अंदर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर, दोनों शहरों का बाकी हिस्सा हमेशा की तरह शांत प्रतीत हुआ। किसी ने भी मुस्लिम या दलित बस्तियों या गरीब झुग्गियों पर किसी तरह की कार्रवाई का जिक्र नहीं किया। मनमाने ढंग से लक्षित लोगों की निवारक हिरासत का भी कोई उल्लेख नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि मोदी स्वयं जिहादी मुस्लिम समूहों की निशाने पर हैं, जिन्होंने 2002 के दंगों का बदला लेने की कसम खाई है। फिर भी, मैंने एक बार भी वीआईपी आवाजाही के लिए यातायात को रुकते हुए नहीं देखा।
इसके विपरीत, दिल्ली में तो आम दिनों में भी, खासकर रात के समय, शहर की सड़कें पुलिस बैरिकेड्स से भरी रहती हैं। रात में मोटर चालकों, स्कूटर चालकों और ट्रक चालकों को नियमित रूप से जाँच के लिए रोका जाता है। ये बैरिकेड्स इतनी लापरवाही से लगाए जाते हैं और वाहनों की 'जाँच' इतनी बेतरतीब ढंग से की जाती है कि इससे आम नागरिकों को असुविधा ही होती है, जबकि पुलिस को ट्रक और निजी टैक्सी चालकों के साथ-साथ पार्टी के बाद नशे में धुत होकर घर लौट रहे युवा जोड़ों से भी लूटपाट करने का मौका मिल जाता है।
गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से पहले, दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में, पुलिस गुंडा तत्वों पर अंकुश लगाने के बहाने कठोर निवारक हिरासत कानूनों के तहत हजारों गरीब लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लेती है। इनमें से अधिकांश लोग निर्दोष रिक्शा चालक या फुटपाथ पर रहने वाले फेरीवाले, बेघर गरीब या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं। मुस्लिम युवा नियमित रूप से निशाने पर होते हैं। कोई यह पूछने की जहमत नहीं उठाता कि क्या निवारक हिरासत कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए लोग

वास्तव में गुंडे हैं, और यदि हैं, तो वे बाहर क्यों थे? वीवीआईपी से जुड़े कुछ कार्यक्रमों से पहले 'कार्रवाई' दिखाने के लिए उन्हें क्यों पकड़ा जाता है? गणतंत्र दिवस या जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले गुजरात के शहरों में ऐसी कोई कार्रवाई न तो देखी गई और न ही सुनी गई।
376 मोदी, मुसलमान और मीडिया

पुलिस में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व: यह उल्लेखनीय है कि पुलिस थानों में तैनात मुस्लिम पुलिसकर्मियों की संख्या में गुजरात सभी राज्यों में अग्रणी है। 12 नवंबर, 2012 के टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में थाना स्तर पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अनुपात से अधिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक आरटीआई पूछताछ के जवाब में, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित आंकड़े साझा किए: गुजरात में, जहां राज्य की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 9.1 प्रतिशत है, पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में से 10.6 प्रतिशत मुस्लिम हैं। चूंकि यह राज्य की कुल जनसंख्या में मुसलमानों के अनुपात से अधिक है, यह दर्शाता है कि गुजरात में पुलिस भर्ती में भी भेदभाव नहीं है। भारत के लगभग सभी अन्य राज्यों में, पुलिस थानों में मुसलमानों की संख्या उस राज्य की मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत से काफी कम है। उदाहरण के लिए, केरल की मुस्लिम जनसंख्या 24.7 प्रतिशत है, लेकिन पुलिस बल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल 11.6 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 25.2 प्रतिशत है, लेकिन पुलिस बल में उनका प्रतिनिधित्व केवल 8.4 प्रतिशत है। लेकिन गुजरात में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की संख्या में यह वृद्धि बिना किसी शोर-शराबे के और बिना कोई विशेष कोटा बनाए की गई है।

अमीर हो या गरीब, सभी वर्गों के मुसलमानों में अपनी सुरक्षा को लेकर आशावाद की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी शारीरिक भाषा स्वयं ही सब कुछ बयां करती है: एक मुस्लिम व्यवसायी के शब्दों में:
किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछिए, वह आपको बताएगा कि गुजरात में पुलिस व्यवस्था में
यह काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसमें किसी भी पक्ष का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है।
मुख्यमंत्री या सरकार में कोई और। मुस्लिम पुलिस स्टेशन
आजकल इन क्षेत्रों में काम का बोझ काफी कम हो गया है क्योंकि आपराधिक गतिविधियां कम हो गई हैं।
इन क्षेत्रों में कीमतें नाटकीय रूप से गिर गई हैं। इससे पहले, दरियापुर और कालूपुर में
अहमदाबाद असामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। अधिकांश दंगे अहमदाबाद में ही हुए थे।
पिछले 50 वर्षों में जो कुछ हुआ, वह इन्हीं क्षेत्रों से शुरू हुआ और वहां से फैलकर आगे बढ़ा।
शहर के बाकी हिस्सों में। लेकिन पिछले दस वर्षों में, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है।
पंजीकृत। एक तो, शराब और जुआघर लगभग गायब हो चुके हैं।
इन क्षेत्रों में। पहले तो, हिंदुओं की तो बात ही छोड़िए, मुसलमानों में शिक्षित लोग भी मारे जाते थे।
पहले उन इलाकों में जाने से हिचकिचाते थे। लेकिन अब उन इलाकों से डरने की कोई बात नहीं है।
और भी बहुत कुछ। नए निर्माण कार्यों के कारण उन क्षेत्रों में काफी नई निर्माण गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं।
समृद्धि है और अब वहां अपराध लगभग न के बराबर है। अपराध-प्रवण शहर

वे क्षेत्र जहां संगठित आपराधिक गिरोह मौजूद हैं। ऐसे गिरोह आपस में सहयोग नहीं करते।
अहमदाबाद या अन्य शहरों में दंड से मुक्ति।
गुजरात के शहरों में रात्रि जीवन और फुटपाथों पर पिकनिक 377

हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यह मानते हैं कि गुजरात में पुलिस व्यवस्था भारत के अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक पेशेवर है। हालांकि, पुलिस की मनमानी के मामले इससे पूरी तरह अछूते नहीं हैं। पुलिस भ्रष्टाचार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन गुजरात में शिकायत निवारण की एक प्रणाली मौजूद है जिसने पुलिस के अत्याचारों पर लगाम लगाई है।
मैंने अहमदाबाद में आईटी सेक्टर में काम करने के लिए लखनऊ से आई एक युवा मुस्लिम महिला से पूछा कि गुजरात में महिलाओं के खिलाफ अपराध 'बढ़ रहे हैं' जैसी राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के बारे में उनका क्या कहना है। उन्होंने जवाब दिया, “पुलिस विभाग के आंकड़ों से कानून-व्यवस्था का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में अपराधों की रिपोर्टिंग में अक्सर कमी रहती है। जिन राज्यों में अपराध दर कम है, जरूरी नहीं कि वे नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित जगह हों। सबसे महत्वपूर्ण सूचक नागरिकों की सुरक्षा की भावना है। अगर इसे ही पैमाना मानें, तो हर रात तड़के सड़कों पर अकेली घूमती युवा महिलाओं की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम गुजरात में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अपराधी उतनी बेखौफ होकर अपराध नहीं करते, जितनी कि कई अन्य राज्यों में, खासकर मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में।”

अध्याय 22

न्यास, धर्म और करुणा के बारे में
नमो का गांधी जी और गौतम बुद्ध से जुड़ाव

मुझे दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है कि आर्थिक मुद्दों पर गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं... अगर मेरी इतनी शक्तिशाली विरासत है, तो इसे दुनिया के ध्यान में लाना मेरा दायित्व है... बौद्ध धर्म में, मैं करुणा में निहित धर्म देखता हूँ। मेरा मानना है कि करुणा जीवन का सबसे मूल्यवान सार है। जब मैंने सरकार बनाई, तो ये मूल्य और भी गहरे हो गए। बुद्ध के बारे में जो बात मुझे आकर्षित करती है, वह है उनका समावेशी दर्शन; दूसरा, उनकी आधुनिकता; और तीसरा, संघ के महत्व में उनका विश्वास। - नरेंद्र मोदी, व्यक्तिगत साक्षात्कार, 2013

“नरेंद्रभाई पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में महात्मा गांधी के वैष्णव जन भजन पर एक घंटे का प्रवचन दिया करते थे। वे हमें बताते थे कि भाजपा कार्यकर्ता वह होना चाहिए जो दूसरों के दर्द को समझता और महसूस करता हो। भाजपा कार्यकर्ता को सभी के सुख (कल्याण) के लिए काम करना चाहिए और सभी के दुख (पीड़ा) को महसूस करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि लोग राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करें, तो हमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करना होगा। यदि भाजपा कार्यकर्ता सामाजिक भलाई के लिए काम करके नेतृत्व करते हैं, तो इससे हमारे राष्ट्र के साथ-साथ हमारे समाज को भी मजबूती मिलेगी।”
राजकोट स्थित भाजपा नेता विजयभाई रूपाणी ने भाजपा के संगठनात्मक कार्य के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को समाज सेवा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने हेतु नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मूल

संदेश का वर्णन इस प्रकार किया। जब मैंने उनसे मोदी के भाषणों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करने को कहा, तो विजयभाई ने बताया कि नरेंद्रभाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच करुणा और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने गांधीजी से जुड़े वैष्णव जन भजन में निहित सभी मूल्यों पर बल दिया। रूपाणी ने आगे कहा:
न्यास, धर्म और करुणा 379

संगठन का निर्माण करना और
पार्टी कार्यकर्ताओं की भर्ती करना ही काफी नहीं है; हमें राजनीतिक परिपक्वता भी होनी चाहिए।
समाज को अपने साथ लेकर चलें। अगर मैंने उन प्रशिक्षण सत्रों के विस्तृत नोट्स रखे होते तो...
जिसमें नरेंद्रभाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, वह संकलन
संगठन शास्त्र (ग्रंथ) पर एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं
संगठनों के निर्माण पर)।
For instance, he would emphasise the mantra: Pratyek karyakarta ke liye
kaam aur pratyek kaam ke liye karyakarta. (For every task, there must be a
एक जिम्मेदार पार्टी कार्यकर्ता होना चाहिए, और प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता के लिए, पहचान योग्य होना चाहिए।
काम)। दूसरे, उन्होंने हमें सिखाया कि उद्देश्य की भावना के बिना, एक व्यापक भावना का अभाव है।

मिशन के दौरान, एक पार्टी कार्यकर्ता एक पुर्जा बनकर रह जाता है (उठक-बैठक का हिस्सा)।
नियमित कार्यों को मशीनी ढंग से करना। भाजपा को प्रेरित करने में वे बहुत प्रभावी थे।
श्रमिकों को देश और समाज के लिए कुछ सार्थक करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भुगतान किया।
अच्छे और ईमानदार कर्मचारियों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि...
उन्होंने भवन निर्माण प्रणालियों पर बहुत ध्यान दिया।
मैंने मोदी के जमीनी स्तर से विकास के एजेंडे और गरीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शासन प्रणाली में सुधार लाने के उनके अथक प्रयासों में इन सब बातों के प्रमाण पहले ही देख लिए थे। लेकिन जब भी मैं गांधीजी के संदर्भ में उनका नाम लेता हूँ, लोग भड़क उठते हैं— जैसे कि मैंने कोई अपवित्र बात कह दी हो।
इसलिए मैंने अपने एक साक्षात्कार के दौरान मोदी से यह पूछना उचित समझा कि महात्मा गांधी के साथ उनका क्या संबंध था और वैष्णव जन भजन का उनके लिए क्या महत्व था। उन्होंने इस पर यह प्रतिक्रिया दी:
जी हां, मैंने कई स्थानों पर गांधीजी के वैष्णव जन भजन पर भाषण दिया है।
दरअसल, मैं घंटों लंबे भाषण देता था जिसमें बताता था कि गांधीजी को यह क्यों पसंद था।
भजन। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें और इस गीत के प्रत्येक शब्द पर गौर करें, तो इसकी रचना संभव हो पाती है।
500 साल पहले, हम पाएंगे कि इसमें कही गई हर बात आज भी प्रासंगिक है, खासकर

हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व पर जोर देते हैं।
ईमानदारी। संक्षेप में, यह सार्वजनिक जीवन और नैतिकता के लिए एक घोषणापत्र है। इसलिए, मैंने काम किया।
शब्दों के आसपास और कहेंगे: Jan pratinidhi to tene kahiye, jo peed parai
अगर आप खुश हैं, तो आप खुश रहेंगे। (जनता का)
प्रतिनिधि वह होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है; वह जो दूसरों के दर्द को दूर करता है।
वह दूसरों के दुखों को समझता है, फिर भी अपने अंदर जरा भी अहंकार या घमंड नहीं आने देता।
उसके दिल में)।
380 मोदी, मुसलमान और मीडिया

यह मेरे कर्मचारी विकास कार्यक्रमों का हिस्सा हुआ करता था। मैं पहले...
इस भजन की प्रत्येक पंक्ति का विश्लेषण करें और समझाएं कि गांधीजी ने इन्हें क्यों बढ़ावा दिया।
सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का समावेश; इसमें सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी ज्ञान समाहित है। यह एक
हमारे देश के लिए यह बड़ा दुर्भाग्य है कि यह भजन केवल 2 अक्टूबर को ही बजाया जाता है।
राजघाट पर। इसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का साधन बनना चाहिए था।
गांधी जी को यह भजन पसंद था क्योंकि इसमें गांधी जी के डीएनए और उनके तत्व मौजूद हैं।

गीत एक दूसरे से मेल खाते हैं। मैं इसे अपनी पार्टी के लिए आचरण के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता हूं और
आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच इस भजन को याद करने की एक पुरानी परंपरा है। आरएसएस में इस भजन को याद करने की परंपरा चली आ रही है। हर सुबह। उनका प्रातः स्मरण (सुबह का स्मरण) शुरू होता है। Gandhi ji’s name.
मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए उनके एक घंटे के भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी, क्योंकि मोदी के भाषणों की रिकॉर्डिंग उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुई थी। हालांकि, मुझे इस विषय के कुछ अंश मोदी द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए एक भाषण में मिले, जो चिंतन शिविरों की एक श्रृंखला का हिस्सा था। इस शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करना था। नीचे मैं उन अंशों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुझे मिल सके:
गांधी जी का पसंदीदा गीत वैष्णव जन था (वह व्यक्ति जिसने विष्णु को आत्मसात कर लिया हो)।
ईश्वर; एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति)। यदि इस गीत के शब्द आपकी डायरी में हैं
या आपके घर या कार्यालय में प्रतिध्वनि के लिए, आपको इससे अधिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी।
अपना जीवन कर्मयोगी की तरह जियो। मैंने इसे वर्षों तक सुना था, लेकिन अब मुझे इसकी शक्ति का एहसास हुआ।
एक दिन, अचानक सन् 1994-95 के आसपास की किसी सुबह, यह गाना मेरे कानों में गूंज उठा।
मेरे दिल में एक चिंगारी। अगर आप कर्मयोगी शब्द को वैष्णव जन से बदल दें,

employee should be a karmayogi. Vashnav jan or karmayogis are those:

इसलिए, उनका हृदय सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के हृदय के समान ही पवित्र है।
एक वैष्णव लोभ और छल के अभाव का प्रतीक है।
उन्होंने हर प्रकार की कामवासना और क्रोध का त्याग कर दिया है। उनके सद्गुणों ने उनकी पूरी पीढ़ी को मुक्ति दिलाई...
यह गीत सैकड़ों साल पहले लिखा गया था। उस दौर में भी,
नरसिंह मेहता भ्रष्टाचार और लालच के खतरों से भलीभांति परिचित थे। दोस्तों,
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस गीत की शक्ति को पहचानें और इसके संदेश को समझें।
कृपया इस गाने के बोल अपनी मेज पर रखें, आपको समझ आ जाएगा। महात्मा गांधी ने वह शक्ति कैसे प्राप्त की जो उनके पास थी? वे उस शक्ति को जानते थे।
इस गाने के बोलों के पीछे छिपे अर्थ को मैं समझना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह गाना एक प्रेरणा का स्रोत बने।
हममें से प्रत्येक के लिए शक्ति का।
मेरे साथ अपने साक्षात्कार में, मोदी ने विस्तार से बताया कि उन्होंने अपने काम के हर पहलू में महात्मा गांधी के विचारों को लागू करने का प्रयास कैसे किया है:
मेरा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है कि आर्थिक मुद्दों पर भी,
गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी 100 वीं जयंती पर दिए गए मेरे एक व्याख्यान में यह बात कही गई थी।
देवरभाई—जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष और एक करीबी सहयोगी थे—
मोरारजीभाई का उपन्यास गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता से संबंधित है। देवरभाई

वह मेरे ही गांव वड़नगर से थे और उन्होंने जमीन के लिए बेहतरीन काम किया था।

सुधार। मेरी सरकार ने उनकी 100 वीं जयंती मनाई थी , हालांकि कांग्रेस पार्टी और बाकी देश को तो यह बात याद भी नहीं थी।

लोगों ने हैरानी जताई और पूछा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के सदस्य को सम्मानित क्यों कर रही है।

नेता ? लेकिन मैं उन्हें राष्ट्र से संबंधित एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखता हूँ। उस दिन

मैंने साबरमती आश्रम में गांधीवादियों के साथ साझा किया था कि कैसे सभी निर्णय

मेरी सरकार के सभी सदस्य गांधीजी के विचारों और दृष्टिकोण से प्रभावित हैं।

भारत में किसी भी सरकार ने कभी गांधी जयंती मनाने के बारे में नहीं सोचा था।

महात्मा गांधी के जन्मस्थान पोरबंदर में। यह कभी एक छोटा सा स्थानीय गाँव हुआ करता था।

यह आयोजन 2003 में मेरी सरकार द्वारा इस परंपरा की शुरुआत करने तक चलता रहा। हमने तीन आयोजन किए।

वहां के कार्यक्रम :

 एक शाकाहारी भोजन महोत्सव , क्योंकि यह मुद्दा महात्मा गांधी से संबंधित है।

Gandhi.

 स्वच्छता अभियान।

 खादी का फैशन शो।

382 मोदी , मुसलमान और मीडिया

कुछ लोग फैशन शो का विरोध करते हैं और यहां तक कि उनमें तोड़फोड़ करने तक चले जाते हैं।
ऐसी घटनाएं। ऐसी घटनाएं मुझे बहुत दुखी करती हैं, भले ही मैं इनके बारे में बात न करूं।
उन्हें। अपनी ताकत को कार्यों के माध्यम से दिखाना मेरी प्रकृति है। इसलिए मैंने आयोजन किया।
उस नकारात्मक मानसिकता का मुकाबला करने के लिए एक फैशन शो।
उस अवसर पर मैंने एक मंत्र दिया, 'स्वतंत्रता से पहले, खादी का मतलब था...'
राष्ट्र; आजादी के बाद, खादी का इस्तेमाल फैशन के लिए किया जाए।’ मैंने एक विशेष खादी बनाई।
विनोबा जी के शिष्य बाल जी से निवेदन है कि वे इस अवसर पर उपस्थित रहें। द्वारकादास के कारण
जी, मेरे सर्वोदय समुदाय के लोगों से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। बाल जी मेरे बहुत करीबी थे।
विनोबा जी और गांधी जी जैसा पहनावा. जब से बाल जी आये, अन्य सर्वोदय लोग
वे भी आए थे। अब, एक फैशन शो उनकी सोच के अनुरूप नहीं है। लेकिन मैं मैंने एनआईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) के छात्रों से कहा कि वे मेरे प्रचार में मेरी मदद करें।
आधुनिक शैली में खादी। साथ ही, पृष्ठभूमि में वैष्णव भजन बज रहा है।
एनआईडी के छात्रों ने हमारे लिए खादी की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया—विभिन्न शैलियों में खादी का प्रदर्शन।
और वस्त्र। बाल जी ने मुझसे कहा, “नरेंद्रभाई, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।”

कि इस तरह खादी को बढ़ावा दिया जा सकता है।" इसने एक नया चलन शुरू किया। अब,
कई लोगों ने खादी फैशन शो आयोजित करना शुरू कर दिया है।
जब नवल किशोर शर्मा गुजरात के राज्यपाल थे (वे बहुत ही
कांग्रेस पार्टी के प्रतिभाशाली नेता ने सार्वजनिक रूप से इस नवाचार की प्रशंसा की।
खादी को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा कि जब वे खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे,
उन्हें खादी को इन तरीकों से बढ़ावा देने का कभी विचार ही नहीं आया। उदाहरण के लिए,
गांधी जयंती पर खादी बोर्ड खादी पर विशेष छूट प्रदान करता है, लेकिन मैं
खादी हाट तक जुलूस निकालकर कपड़ा खरीदने को एक अभियान बनाइए।
उस दिन हमारी सरकार खादी के प्रचार के लिए पूरे पृष्ठ के विज्ञापन जारी करती है।
लेकिन मैं लोगों को खादीधारी बनने के लिए प्रेरित नहीं करता— अर्थात्, केवल खादी के कपड़े पहनने के लिए।
और कुछ नहीं। मेरी अपील यह है कि यदि आपके पास कई प्रकार के कपड़े हैं तो
घर में, खादी को शामिल करना क्यों न सुनिश्चित करें? बस कर दीजिए! जब भी संभव हो खादी के उत्पाद खरीदना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान चलाया जा रहा है।
पूरे राज्य में। परिणामस्वरूप, हमने 40 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।
गांधी जयंती के उस एक सप्ताह में खादी की बिक्री।
मैंने खादी का रुमाल और किताब भेंट करने की यह परंपरा भी शुरू की।

गणमान्य व्यक्तियों को फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के बजाय, मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप देते हैं
अगर कोई फूल खिलता है, तो एक-दो दिन में ही वह कचरे के ढेर में जा गिरेगा।
यदि आप कोई पुस्तक देते हैं, तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच सकती है। इसलिए हर पहलू में
मेरे सामाजिक सुधार के प्रयासों में आपको गांधी जी की छाप दिखाई देगी। उदाहरण के लिए,
समरस गांव पर जोर (एक ऐसा गांव जिसने अपनी पंचायत का चुनाव किया है)
सामंजस्यपूर्ण सहमति (सद्भावपूर्ण सहमति) मूलतः गांधी की विचारधारा है। इसी प्रकार ज्योतिग्राम
प्रत्येक गांव को चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति प्रदान करने वाली योजना गांधी जी के विचारों से प्रेरित है।
यह धारणा कि जब तक आप गांवों का उत्थान नहीं करेंगे, तब तक आप भारत का उत्थान नहीं कर सकते।
न्यास, धर्म और करुणा 383

ज्योतिग्राम योजना के उद्घाटन के समय, मैं एक बड़ा मेला आयोजित करता था।
उस क्षेत्र में नए बिजली स्टेशन को उस जिले को समर्पित करने के लिए। उन सभी बड़े क्षेत्रों में
ऐसे आयोजनों में 2 से 2.5 लाख लोग आते थे, क्योंकि उस समय बिजली एक बड़ी समस्या थी।
गुजरात में। लेकिन मैंने उन सभी लोगों को सिर्फ राजनीतिक समर्थन पाने के लिए इकट्ठा नहीं किया था।

प्रत्येक मेले के साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती थी ताकि लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत कराया जा सके। बिजली के उपयोग—कुम्हार, लोहार या धोबी किस प्रकार बिजली का उपयोग कर सकते हैं?
उनके जीवन को बेहतर बनाना। बहुआयामी पहलुओं को दिखाने के लिए वास्तविक प्रदर्शन भी किए गए।
समाज के विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समूहों के जीवन में बिजली का उपयोग।
मेरा उद्देश्य अपने लोगों को यह समझाना था कि बिजली आपूर्ति का मतलब यह नहीं है कि
बस टीवी देखना। अगर बिजली आपके जीवन में कोई मूल्यवर्धन नहीं लाती है।
तो फिर इसका कोई खास उपयोग नहीं है। मैंने यह संदेश भी दिया कि गांधी कभी भी विरोधी नहीं थे।
एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से गांधीजी की एक बड़ी तस्वीर को देखते हुए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना।
गांधी जी का दिमाग वैज्ञानिक था; अन्यथा वे इतना अधिक समय क्यों लगाते?
क्या आपको माइक्रोस्कोप में रुचि है?
जब मैं पर्यावरण की बात करता हूँ, तो मैं साइकिल पर बैठे गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल करता हूँ।
एक पृष्ठभूमि के रूप में। मेरे द्वारा 1,00,000 शब्द बोलना या लंबे भाषण देना मायने नहीं रखता।
गांधी जी की एक तस्वीर जैसा प्रभाव हो। अगर मुझे ऐसा प्रभाव देखने को मिले, तो
इस विशाल विरासत को दुनिया के ध्यान में लाना मेरा दायित्व है।

महात्मा मंदिर को एक अनूठे सम्मेलन केंद्र के रूप में बनाने का विचार इसी प्रकार सामने आया।
मुझे गांधीनगर से यह जानकारी मिली। अभी महात्मा मंदिर की जनसंख्या 30 तक पहुंच चुकी है।
हालांकि हमने इसमें कई विशाल आयोजन किए हैं, फिर भी प्रतिशत पूर्णता दर यही है।
पहले से ही। इसके पूरा होने तक प्रतीक्षा करें, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। यह पूरी तरह से तैयार है।
गांधी की भावना से ओतप्रोत। उदाहरण के लिए, हमने पता लगाया कि बापू की भावना किस हद तक गांधी की भावना से ओतप्रोत है।
चलते समय उनका शरीर एक तरफ झुका हुआ होता था और उनके हाथ में उनकी खास लाठी होती थी। महात्मा गांधी के स्तंभ।
मंदिर ठीक उसी कोण पर झुके हुए हैं। मैंने छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान दिया है।
गांधी जी के जीवन का विस्तृत विवरण। जब यह पूरा हो जाएगा, तो मैं इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करूँगा।
ये तत्व। दांडी मार्च गांधीजी के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। मेरे पास
गांधीजी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति में एक दांडी कुटीर बनाई गई
महात्मा मंदिर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होगी। छत पर हम एक कलाकृति बनाएंगे।
गांधी गार्डन—यह दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस गार्डन होगा।
हम प्रौद्योगिकी की सहायता से गांधी जी के प्रत्येक वर्ष को जीवंत बनाएंगे।
उस अवधि से जुड़ी किसी विशेष घटना के साथ जीवन इस प्रकार जुड़ा हो कि

जो बच्चा बगीचे में घूमता है, उसे जानने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी और
गांधी के मूल सिद्धांतों को समझें।
महात्मा मंदिर की एक और अनूठी विशेषता मेरे मूल स्वभाव से जुड़ी है।
of bringing about connectivity among people (mein moolta jodne ki pravriti
(मैं नहीं हूँ)। इसीलिए हमने गुजरात के लोगों से कुछ मिट्टी लाने को कहा।
और महात्मा मंदिर की नींव रखने के लिए अपने गाँव का पानी दिया। इस प्रकार, 384 मोदी, मुसलमान और मीडिया

गुजरात के 18,000 गांवों से पानी और मिट्टी लाकर इसकी नींव रखी गई है।
महात्मा मंदिर के लिए। हम भारत के प्रत्येक राज्य से मिट्टी और पानी भी लाए थे।
साथ ही उन सभी देशों से भी जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं महात्मा मंदिर की नींव रखने के लिए वे चले गए और वहीं बस गए। गांधी वह एक विश्व नागरिक थे। इसीलिए हमने हर क्षेत्र की धरती और जल को महत्व दिया।
महात्मा मंदिर की नींव में दुनिया का योगदान रहा।
इसकी नींव 1 मई, 2010 को गुजरात के स्वर्ण जयंती वर्ष में रखी गई थी।
भारत के विभिन्न गांवों और राज्यों से लोग जुलूसों में शामिल हुए।
उनकी धरती और पानी। हमने उस अवसर पर गांधी जी की एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की थी।

मैं हर साल 2 अक्टूबर को बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पोरबंदर जाता हूं।
कई लोग पोरबंदर घूमने गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसके पीछे
गांधीजी की माता पुतलीबाई के पैतृक घर में 200 साल पुरानी वर्षा जल निकासी प्रणाली मौजूद है।
कटाई संरचना। मुझे लगा कि लोगों का बस जाकर पेशकश करना पर्याप्त नहीं है।
गांधीजी के जन्मस्थान पर फूल; आइए हम चीजों को इस तरह व्यवस्थित करें कि हर कोई
आगंतुक को उस घर का दौरा करना होगा और पारंपरिक वर्षा जल संचयन विधि देखनी होगी।
हमने पुतलीबाई के घर तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा विशेष पुल बनाया।
ताकि लोग देख सकें कि गांधीजी के पूर्वज पानी को कितना महत्व देते थे और उसका उपयोग कैसे करते थे।
200 साल पहले भी बारिश होती थी।
मैं गांधीजी के जीवन के हर छोटे-बड़े पहलू को अपने काम में शामिल करता हूँ। सामाजिक वानिकी में,
यानी, वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण में गुजरात भारत में पहले स्थान पर है।
मैं ज्योतिष में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने इस पर टिप्पणी की है।
मैं उन गिने-चुने नेताओं में से हूं जो अपने हाथों में कोई रत्न नहीं पहनते।
मैं अपनी उंगलियों को सौभाग्य लाने की उम्मीद में घुमाती हूँ।
हालाँकि, जब ज्योतिष की बात आती है

सकारात्मक संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए यह बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं इसका उपयोग करने में संकोच नहीं करता। कोई व्यक्ति
मुझे विभिन्न रत्नों को पहनने के फायदों के बारे में एक किताब भेजी थी।
वे अपने-अपने ज्योतिषीय ग्रहों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पुस्तक
इसमें प्रत्येक राशि के लिए लाभकारी विशिष्ट वृक्षों के बारे में भी बताया गया है।
इससे मुझे यह विचार आया कि हमारे वन विभाग को एक हिस्सा समर्पित करने का निर्देश दिया जाए।
हमारे वन महोत्सवों का उद्देश्य एक ऋषिवन (ग्रहीय वन) का निर्माण करना है।
प्रत्येक नगर निगम में। गुजरात सरकार ने आयोजन किया है।
सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में विभिन्न विषयों पर अनेक वन महोत्सव आयोजित किए जाते हैं।
वनरोपण एक जन आंदोलन है। रशीवन के विचार के माध्यम से मैं लोगों से वृक्षारोपण का आग्रह करता हूँ।
ऐसे पेड़ जिन्हें उनकी राशि के लिए लाभकारी माना जाता है।
हमने प्रत्येक गाँव को पंचवटी (हरित पट्टी) बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।
इसका नाम उस जंगल से लिया गया है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे।
उनके निर्वासन के वर्षों के दौरान)। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के अलावा, मेरी बुनियादी
यह धारणा थी कि भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। यहां तक कि गांवों में भी आपको यह देखने को मिलता है।

80 ‑‑ 90 ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑-‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑?
‑‑‑‑‑‑, ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ 385

‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑
‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑
‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑…
‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑, ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑
‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑
‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ (‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑) ‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑, ‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ “‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑” ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑
‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
‑‑ ‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑ ‑‑‑‑‑‑‑

मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम एक अखिल भारतीय अभियान शुरू करेंगे।
हमारे देश को कचरा मुक्त बनाएं—स्वच्छ और निर्मल भारत बनाएं।
महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में (और पवित्र भारत का भी आयोजन किया गया)।
गुजरात में कई पुराने सीढ़ीदार कुएं हैं, जो रिचार्ज हो रहे हैं।
हमारे जल संचयन प्रयासों के कारण। ये बेहद खूबसूरत संरचनाएं हैं अरबों की कीमत वाली कई परियोजनाओं का मैंने पुनरुद्धार किया है।
गांधी जी की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
इन सबमें।
परंपरागत कारीगरों के लिए हमने कई बड़े हाट बनाए हैं, जैसे दिल्ली हाट।
– जहाँ हम हस्तशिल्प उत्पादकों को आमंत्रित करते हैं कि वे आकर अपने उत्पाद बेचें।
सरकार उनके यात्रा खर्च के साथ-साथ भोजन और आवास की व्यवस्था भी करती है।
और भोजन। हमने आदिवासी कारीगरों को असम और नागालैंड भेजा ताकि वे बनाना सीख सकें।
उच्च गुणवत्ता वाले बांस के उत्पाद।
इसी प्रकार, अंबाजी मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और
देवी को नारियल चढ़ाएं। यह प्रथा थी कि उसी नारियल को
उन्हें पिछले दरवाजे से बाजार में भेजा जाता है और फिर दूसरों को बेच दिया जाता है।
भक्त देवी को नारियल चढ़ाते हैं। मैंने इसे रोककर पूछा, "क्या किसी के पास नारियल है?"

देवी को अर्पित की गई वस्तु को वहीं तुरंत तोड़ना पड़ता है। अंबाजी मंदिर
यह संस्था लोगों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराती है। इसलिए वे एक रसोईघर चला रहे थे।
खैर, हमने नारियल की गिरी का उपयोग करके एक विशेष व्यंजन बनाने की एक विधि तैयार कर ली।
उस समय आदिवासी बच्चों को पौष्टिक मिठाई मुफ्त में वितरित की जाएगी।
स्कूलों में दोपहर के भोजन में नारियल का ऊपरी छिलका (बाल) दिया जाता है।
आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को खिलौने बनाने के लिए निःशुल्क अनुमति दी गई थी। उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया था।
खिलौने बनाने की कला में। यह एक और मूल्यवर्धन है। इस प्रकार हमने नहीं किया है
नारियल चढ़ाने में भ्रष्टाचार को रोकने के साथ-साथ पोषण संबंधी लाभ भी पाए गए। 386 मोदी, मुसलमान और मीडिया

रोजगार समाधान। यह हमारी परंपराओं और गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है।
मूल्यों का रचनात्मक उपयोग।
समरस पंचायतें: गांधी जी के मूल मूल्यों का क्रियान्वयन। अपनी बातचीत और भाषणों में नरेंद्र मोदी अक्सर यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कई गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानियों और महान बुद्धिजीवियों से शिक्षा प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, जैसा कि अध्याय 3 और 5 में वर्णित है, 8 अक्टूबर, 2001 को मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला कदम समरस पंचायतों का चुनाव करने वाले

गांवों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा करना था - यह एक विशिष्ट गांधीवादी विचार था। उनके साथ मेरे एक साक्षात्कार के दौरान, मैंने उनसे पूछा कि उन्हें समरस पंचायतों का विचार कहां से आया। मोदी ने इस पर यह कहा:
हमारे कस्बे में दो लोग थे—डॉ. द्वारकादास जोशी और वसंतभाई Paresh. Dwarkadas Joshi was dedicated to Vinoba ji and Vasantbhai

was a

गांधीवादी और विवेकानंद से बहुत प्रभावित। वे सर्वोदयी भी थे। और थोड़ा क्रांतिकारी भी।
मैं अपने बचपन से ही व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। द्वारकादास जी, जो विनम्रता की मिसाल थे। उनकी आंखें, उनका भाषण और उनका
उनकी सादगी बहुत मार्मिक थी। बचपन में मैंने उन्हें बोलते सुना था।
विनोबा जी के इस कथन के बारे में कि जब संसदीय चुनाव होते हैं, तो ऐसा हो सकता है
चुनाव से पहले तनाव का माहौल रहता है, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता है।
लेकिन, जब पंचायत चुनाव होते हैं, तो गाँव स्थायी रूप से बदल जाता है।
विभाजित। ऐसे भी समय आते हैं जब विवाह टूट जाते हैं और बेटियों को भेज दिया जाता है।
इसी वजह से उन्हें अपने ससुराल से वापस आना पड़ा। तो फिर हम इस छोटी बच्ची को क्यों नहीं दिखा सकते?
परिपक्वता लाएं और पूरे गांव को मिलकर यह तय करने दें कि किसे किसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

क्या यह पंचायत की जिम्मेदारी है? इसलिए, यह विचार मेरे मन में अव्यक्त ही रहा।
बचपन से ही मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई है।
मैं इस विचार को पहले लागू नहीं कर सका क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं था।
सरकारी मामले। चूंकि मुझे संगठन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, इसलिए मैंने
उस पर ध्यान केंद्रित रखा और उसे पूरा करने के विभिन्न तरीकों और साधनों के बारे में सोचते रहे।
उस क्षेत्र में अच्छा काम।
लेकिन मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद, मैंने यह घोषणा की।
समरस पंचायतों के संबंध में। कांग्रेस पार्टी और मीडिया ने मेरी जमकर आलोचना की।
मुझे अलोकतांत्रिक और सत्तावादी कहा। उन्होंने मुझ पर विनाश का आरोप लगाया।
लोकतंत्र। तो एक दिन मेरी मीडियाकर्मियों से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा:
“अगर 51 बनाम 49 प्रतिशत लोकतंत्र हो सकता है, तो अगर 60 बनाम 40 या 90 बनाम 10 प्रतिशत लोकतंत्र हो सकता है तो क्या होगा?”
अगर 100 बनाम शून्य को भी लोकतंत्र माना जाए, तो फिर इसे लोकतंत्र क्यों नहीं माना जा सकता?
न्यास, धर्म और करुणा 387

गांधी की न्यासकारी का क्रियान्वयन
यह सर्वविदित है कि आरएसएस प्रचारक और भाजपा के संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान मोदी ने एक घुमंतू संन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। तब तक उनके पास कोई

संपत्ति नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, गांधीनगर में उनका एक साधारण सा घर है और निजी संपत्ति न के बराबर है।
उनके अधिकारियों ने मुझे बताया कि वे मुख्यमंत्री बंगले में सिर्फ एक ही कमरा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ही साधारण सा सामान है—एक पलंग, एक काम करने की मेज, कंप्यूटर, टीवी, कुछ कुर्सियाँ और किताबें। वे सादा गुजराती खाना खाते हैं और उनकी आदतें बेहद सरल हैं। हो सकता है कि वे महात्मा गांधी की तरह कम कपड़े न पहनते हों या मिट्टी की झोपड़ी में न रहते हों, लेकिन उनका निजी जीवन बेहद सादगी भरा है। वे घर में नौकरों की फौज नहीं रखते। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उनके लिए खाना बनाता है और उनके रहने वाले एक कमरे की देखभाल करता है। इस अकेले निजी कर्मचारी को भी रात 9 बजे घर जाने की इजाजत है।
गांधीजी की तरह, वे भी अपव्यय से बचने के प्रति बेहद सजग हैं और यहाँ तक कि अपना नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सस्ता सा दो रुपये का बॉलपॉइंट पेन भी कभी नहीं खोते। स्याही खत्म होने तक वह पेन उनके पास ही रहता है। कंघी और नेल कटर जैसी छोटी-छोटी निजी वस्तुएँ भी दशकों तक उनके पास रहती हैं।
गुजरात सरकार के अधिकारियों का कहना है कि वह जनता के धन की पूरी लगन से रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार की बर्बादी नहीं होने देते क्योंकि उन्होंने गांधीजी के न्यास के सिद्धांत को गहराई से आत्मसात कर लिया है और उनका मानना है कि उनका काम जनता के धन के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि इसका उपयोग केवल जनहित के लिए ही किया जाए।
सत्ता में आने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के उनके प्रयासों—न खाऊंगा, न खाने दूंगा—ने उन्हें कई विरोधियों का सामना करना पड़ा है, जो उन्हें तानाशाह कहते हैं। हालांकि गुजरात से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने

पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाले व्यवस्थागत सुधारों को लागू करके भ्रष्टाचार के स्रोतों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता से काम किया है। इस प्रक्रिया में, गुजरात में शासन में कई नवोन्मेषी सुधार देखने को मिले हैं।
गांधीजी के न्यास के दर्शन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से भी स्पष्ट हो गई कि सत्ता में आने के एक महीने के भीतर ही उन्होंने घोषणा कर दी कि नागरिकों द्वारा उन्हें दिए गए सभी उपहारों की नीलामी करके उन्हें एक विशेष कोष—कन्या केलवानी कोष—में दिया जाएगा, जिसका उपयोग गुजरात के सबसे गरीब जिलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। उन्होंने अक्सर कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे स्वयं को जनता की संपत्ति मानते हैं। “सरकार में शामिल होने के बाद मुझे जो भी उपहार मिलते हैं, वे गुजरात की जनता के हैं। महात्मा गांधी का न्यास का सिद्धांत ही मुझे प्रेरित करता है।”
388 मोदी, मुसलमान और मीडिया

महात्मा बुद्ध की छाप
नामो के आवास के पास स्थित उनके कार्यालय में प्रवेश करते ही गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने किसी अन्य ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति की प्रतिमा के बजाय बुद्ध की प्रतिमा ही क्यों चुनी? बुद्ध में उन्हें सबसे अधिक क्या आकर्षित करता है? मुझे यह उत्तर मिला:
महात्मा बुद्ध ने भी मेरे जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। मेरे निजी कमरे में
इसके अलावा, बुद्ध की तीन-चार मूर्तियाँ भी हैं। यह विशेष मूर्ति भेंट की गई थी।

मुझे यह तब पता चला जब मैं एक कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ गया था।
इसे बनाया गया है।
बस्तर के आदिवासी लकड़ी के एक विशाल टुकड़े के साथ - यही बात इसे खास बनाती है।
बौद्ध धर्म में, मैं धर्म को करुणा (दया) में निहित देखता हूँ। मेरा मानना है कि
करुणा जीवन का सबसे मूल्यवान सार है। जब मैंने सरकार बनाई,
ये मूल्य और भी गहरे रूप से समाहित हो गए। बुद्ध के बारे में जो बात मुझे आकर्षित करती है वह यह है कि...
दूसरा, उनका समावेशी दर्शन; दूसरा, उनकी आधुनिकता; और तीसरा, उनका विश्वास
संघ के महत्व में—संघ की अवधारणा में। यही उनके सभी कार्यों का आधार है।
दर्शनशास्त्र। मैं अक्सर सोचता था कि बुद्ध किस प्रकार सर्वत्र ग्रहणशील थे।
दुनिया। उनमें ऐसी क्या बात थी जो वे जहाँ भी जाते, हर जगह चिंगारी जगा देती थी, साधारण लोगों को भी प्रभावित कर देती थी।
मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे और उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों से अपील की।
क्या समूहों में भी ऐसा होता है? बौद्ध धर्म में बहुत अधिक ताम-झाम या उत्सव नहीं मनाया जाता है।
बड़े उत्सवों में व्यक्ति का ईश्वर से सीधा संबंध होता है।
उनकी संपूर्ण विचार प्रणाली मुझे गहराई से प्रभावित करती है।
इसके अलावा, बुद्ध जहाँ भी गए,
इस क्षेत्र में समृद्धि देखने को मिली। हालाँकि चीन की मान्यताएँ अलग थीं।

व्यवस्था के बावजूद, बुद्ध ने चीन पर भी अपना प्रभाव बनाए रखा है। हाल ही में,
मैं चीन गया और मुझे पता चला कि उनकी सरकार मुझे इससे परिचित करा रही थी।
वे अपनी संस्कृति में बौद्ध तत्वों पर बहुत गर्व करते हैं। मुझे पता चला कि चीन
ह्वेन-त्सांग पर एक फिल्म बन रही है। मैंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और उन लोगों को पत्र लिखा।
लोग कह रहे हैं कि उन्हें गुजरात में उनके प्रवास वाले हिस्से को नहीं भूलना चाहिए।
ह्वेन-त्सांग लंबे समय तक उस गाँव में रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था।
उस गाँव के एक छात्रावास के बारे में लिखा गया था जहाँ 1,000 विद्यार्थी भिक्षु रहते थे।
मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने उस क्षेत्र की खुदाई करवाई और पुरातात्विक अवशेष पाए।
ह्वेन-त्सांग द्वारा वर्णित चीजों के प्रमाण। इसका अर्थ है महात्मा बुद्ध के।
मेरे पूर्वजों पर दर्शनशास्त्र का कुछ प्रभाव अवश्य रहा होगा।
हमें अपने गांव के पास देवकी मोरी में भी इसी तरह के साक्ष्य मिले।
खुदाई के दौरान उन्हें एक सोने का बक्सा मिला, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थीं।
ये बड़ौदा स्थित एम.एस. विश्वविद्यालय में पड़े हैं। मुझे यह ख्याल आया कि कहीं भी नहीं
क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान बुद्ध की अस्थियों को अपने हाथों में धारण कर सकता है? केवल हम ही।

हमारे पास यह खजाना है। इसलिए, हम भगवान का एक विशाल मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं।
बुद्ध प्रतिमा ठीक उसी स्थान पर विराजमान है जहाँ से राख का डिब्बा निकाला गया था।
न्यास, धर्म और करुणा 389

इसका निर्माण सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा; इसके बजाय हम निजी संस्थाओं को इसे करने के लिए प्रेरित करेंगे।
मैं ताइवान के सहयोग से एक संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहता हूं।
जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और सिंगापुर। इसकी वास्तुकला में भी ये विशेषताएं होनी चाहिए।
इसका वैश्विक आकर्षण होना चाहिए, न कि पारंपरिक बौद्ध मंदिरों तक सीमित रहना चाहिए।
यह व्यापक रूप से माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव केवल पूर्वी भाग पर ही था।
भारत का हिस्सा होने के बावजूद, गुजरात इस बात का पर्याप्त प्रमाण देता है कि बौद्ध धर्म भी इससे कम महत्वपूर्ण नहीं था।
भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभावशाली। मुझे यह अपने स्वयं के संस्कारों में महसूस होता है।
हमारे क्षेत्र में बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। ‘खुशबू गुजरात की’ विज्ञापन
अमिताभ बच्चन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में उन गुफाओं को दिखाया गया है।
हमने श्रीलंका के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सरकार से कहा गया कि वे श्रीलंका से बौद्ध पर्यटकों को लाएंगे और हम

पर उनके कार्यों के प्रभाव को देख सकें। "वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष" दलों के अधिकांश विरोधियों के विपरीत, मोदी गरीबों की दुर्दशा पर केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते और उन्हें वोट बैंक बनाकर असहाय रूप से अपने अधीन नहीं रखते। उनके आलोचकों को मोदी के पुराने और वर्तमान सहयोगियों, उनके साथ काम करने वाले लोगों की बात सुननी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि उनके सभी विकास कार्यों के पीछे मूल प्रेरणा बापू का आदर्श वाक्य है - सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों को मजबूत करने की गहरी प्रतिबद्धता ताकि वे गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकें।
1. चट्टान पर उकेरी गई आकृति वास्तव में चार शेरों का प्रतीक है, लेकिन चौथा शेर दिखाई नहीं दे रहा है।
भारतीय सरकार द्वारा प्रयुक्त छवि।

उपसंहार
NaMo के साथ मेरी व्यक्तिगत बातचीत की कुछ झलकियाँ

गुजरात का अध्ययन शुरू करने से पहले, मैंने मोदी द्वारा अपने प्रचार के लिए कथित तौर पर नियुक्त की गई कई शक्तिशाली जनसंपर्क एजेंसियों के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं। कांग्रेस के ट्रोल सोशल मीडिया पर लगातार मुझ पर आरोप लगाते रहे कि मुझे एपीसीओ (APCO) के बहकावे में लाया गया है, जो कथित तौर पर मोदी की छवि को निखारने वाली प्रमुख एजेंसियों में से एक है। चूंकि मैंने एपीसीओ के किसी भी प्रतिनिधि को न तो कभी देखा और न ही उनसे कभी बात की, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि यह रहस्यमयी संस्था मुझसे क्यों छिपी रही। गुजरात सरकार के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, एपीसीओ की भूमिका केवल दो साल में एक बार होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के आयोजन तक सीमित है, जिसमें विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की भारी भागीदारी होती है। इसके अलावा, एपीसीओ की गुजरात या मोदी के प्रचार में कोई भूमिका नहीं है। गुजरात सरकार की एकमात्र जनसंपर्क एजेंसी जिसके बारे में मुझे पता चला, वह दिल्ली स्थित म्यूचुअल पीआर है। जनवरी 2013 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि वे दिल्ली और भारत के अन्य शहरों से आने वाले मेहमानों की यात्रा का समन्वय कर रहे थे। हालांकि, चूंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि गुजरात यात्रा के दौरान मैं अपने हवाई किराए और रहने का खर्च स्वयं वहन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे आगे कोई निमंत्रण नहीं भेजा। म्यूचुअल पीआर से किसी ने भी मुझे कोई सूचना पैकेज नहीं दिया, यहां तक कि गुजरात सरकार द्वारा पर्यटन, शिक्षा और अन्य कई मुद्दों पर प्रकाशित आधिकारिक पुस्तकें भी नहीं दीं। अमेरिकी समाचार पत्रों के लिए गुजरात पर लिखने वाले

सदानंद धूमे ने मुझे बताया कि उन्हें भी कभी किसी जनसंपर्क एजेंसी ने लुभाने की कोशिश नहीं की।
जब भी मुझे किसी जानकारी या नमो के पुराने भाषणों की आवश्यकता होती थी, मैं नियमित आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करता था—या तो गुजरात सरकार के सूचना विभाग से, या दिल्ली स्थित गुजरात के रेजिडेंट कमिश्नर से। वे अत्यंत विनम्र और सहायक रहे हैं, लेकिन मुझे बिना मांगे कुछ भी नहीं दिया गया, जानकारी को जबरदस्ती समझाने की तो बात ही दूर है। वास्तव में, गुजरात सरकार के सभी अधिकारियों की तरह, रेजिडेंट कमिश्नर और गुजरात के सूचना विभाग के अधिकारी इतने कम कर्मचारियों के साथ इतना अधिक कार्यभार संभालते हैं कि मुझे उनसे कुछ भी मांगने में हमेशा शर्म महसूस होती थी। इसी तरह, भाजपा से भी किसी ने मुझे मेरे लिखे हुए पर प्रतिक्रिया देने या कोई अतिरिक्त सुझाव देने के लिए कभी फोन नहीं किया।
मैंने नरेंद्र मोदी से बिना मिले या बात किए ही उन पर पहले छह या सात लेख प्रकाशित किए। हालाँकि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काफी हलचल मचाई। 391 उपसंहार

राजनीतिक हलकों में, मोदी ने न तो मुझसे सीधे संपर्क किया और न ही दूसरों के माध्यम से मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। गुजरात में उनकी जनसभाओं में शामिल होने पर भी उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। पत्रकारों के लिए बने घेरे में मुझे कार्यवाही की वीडियोग्राफी करते हुए वे देख सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी उपस्थिति को कभी स्वीकार तक नहीं किया। भरूच में एक ऐसे ही अवसर पर, जहाँ मैं उनके कृषि उत्सव को देखने गया था, पूर्व एनडीटीवी एंकर शिव ठुकराल भी मौजूद थे। शिव ने मेरे लेख पढ़े थे और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने मोदी से कभी बात नहीं की, तो वे बहुत हैरान

हुए। जैसा कि अक्सर होता है, मोदी के मंच से उतरने के बाद, पत्रकार मुख्यमंत्री के अस्थायी बैठक कक्ष में उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। ठुकराल भी बातचीत करने के लिए अंदर गए और मोदी से पूछा, "क्या आप मधु किश्वर से नहीं मिले?" मोदी ने बेपरवाही से कहा, "नहीं।" शिव ने आश्चर्य से पूछा, "ऐसा कैसे? उन्होंने आपके बारे में इतना कुछ लिखा है! वह यहीं हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बुलाते?" मोदी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी: "जब वो बात करना चाहेगी तो जरूर बात करेंगे" (अगर वह मिलने के लिए कहेंगी तो मैं उनसे मिलूंगा)।
जब तक मैंने औपचारिक रूप से साक्षात्कार का अनुरोध नहीं किया, तब तक मोदी पूरी तरह से अलग-थलग रहे। यहां तक कि जब हम लंबे साक्षात्कारों के लिए मिले, तब भी उन्होंने मेरे द्वारा प्रकाशित लेखों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, प्रशंसा या सराहना करना तो दूर की बात है। मुझे केवल एक बार यह संकेत मिला कि मोदी ने मेरे लेख पढ़े हैं, जब मेरी मित्र मेनका गांधी उनसे मिलने गईं। उनकी बातचीत के दौरान, वे मेरे गुजरात संबंधी लेखों पर चर्चा करने लगे। मोदी ने मेनका से कहा कि वह मुझसे पूछें कि क्या मैंने गुजरात सरकार द्वारा कांग्रेस शासित तीन पड़ोसी राज्यों को भेजे गए उन आपातकालीन फैक्स संदेशों को देखा है, जिनमें गोधरा कांड के बाद के दंगों को दबाने के लिए अतिरिक्त बल भेजने का अनुरोध किया गया था।1 यही एकमात्र समय था जब मोदी ने स्वेच्छा से कुछ जानकारी दी। उनके कार्यालय ने उन पत्रों की प्रतियां तभी उपलब्ध कराईं जब मैंने अनुरोध भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुझे मेरे द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के अलावा कभी कोई जानकारी या दस्तावेज नहीं भेजे। अक्सर वे इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे वह भी नहीं भेज पाते थे जो मैंने मांगा था।

मोदी जी ने मुझे कभी भी अपनी किसी सार्वजनिक रैली में आमंत्रित नहीं किया, न ही किसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए। मैंने जिन भी कार्यक्रमों में भाग लिया, वह अपनी स्वयं की पहल पर था। वास्तव में, कई बार मैंने गुजरात सरकार के सूचना विभाग से शिकायत की कि वे कम से कम मुझे मोदी जी के महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना तो भेजें ताकि मैं अपनी यात्राओं की योजना तदनुसार बना सकूँ।
मैं आभारी हूं कि मुझे गुजरात सरकार के किसी भी अधिकारी या उसके किसी भी मंत्री या विधायक से कोई विशेष सुविधा या रियायत नहीं मिली।
1 अध्याय 12 देखें।
मोदी, मुसलमान और मीडिया 392

अगर कभी देर रात मैं किसी भाजपा विधायक का साक्षात्कार ले रहा होता, तो मुझे उनके परिवार द्वारा बनाया गया सादा गुजराती भोजन परोसा जाता। इसी तरह, अगर दोपहर के भोजन के समय मैं किसी सरकारी अधिकारी के साथ लंबे साक्षात्कार में होता, तो कई बार संबंधित अधिकारी चाय के साथ कुछ नाश्ता भी मंगवा लेते थे। केवल दो अधिकारियों ने ही मुझे औपचारिक रूप से अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, किसी ने भी मुझे लुभाने की कोशिश नहीं की, न ही किसी ने मुझे भव्य भोजन या रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करने की जहमत उठाई। मैं पूरी लगन से अपना काम कर पाता था क्योंकि मुझ पर किसी भी प्रकार की बाध्यता का बोझ नहीं था।
लेकिन इस ठंडे बर्ताव से मुझे समझ आया कि मोदी पत्रकारों के बीच इतने अलोकप्रिय क्यों हैं। भारत में मीडियाकर्मी खुलेआम रिश्वत, पांच सितारा होटलों में दावतें, ज़मीन आवंटन जैसी विशेष

सुविधाएं, मुफ्त उपहार, महंगे तोहफे, हर तरह की सहूलियतें और हर तरह के भ्रष्ट आचरण को अपना दैवीय अधिकार मानते आए हैं। लेकिन मोदी ने इस खेल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। मुझे बताया गया है कि कोई भी पत्रकार या मीडिया संस्थान उनसे कोई विशेष सुविधा नहीं मांग सकता; न ही उनका कोई ऐसा खास समूह है जिसे वे अपनी मर्ज़ी से पालते-पोसते हों। अगर मैं सहूलियतें पाने की उम्मीद से गया होता, तो मैंने यह प्रोजेक्ट बहुत पहले ही छोड़ दिया होता।
समय निकालने के लिए भी मुझे नमो से जूझना पड़ा। वह दिन में 18 से 19 घंटे, साल में 365 दिन काम करते हैं और उनका शेड्यूल इतना व्यस्त और पहले से तय होता है कि उन्हें मुझे उतना समय देना मुश्किल लगता था जितना मुझे चाहिए था। मैंने हर बार कम से कम दो घंटे के सेशन मांगे, जो उनके लिए आसान नहीं था। कई बार तो मुझे लगा कि वह नखरे दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें गुस्से में ईमेल भी लिखे। उदाहरण के लिए, मैंने उनके ओएसडी को एक संदेश भेजा था: “कृपया यह संदेश माननीय मुख्यमंत्री को दे दें। मैं उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर श्री मोदी को मुझसे साक्षात्कार के लिए समय देने में कोई रुचि नहीं है, तो मैं उनसे बात किए बिना भी गुजरात का अध्ययन कर सकता हूँ, जैसा कि मैं अब तक करता आया हूँ। मैं उन्हें परेशान करने वाला या समय की भीख मांगने वाला नहीं दिखना चाहता। मुझे पता है कि वे बहुत व्यस्त हैं। उनके दिन का हर मिनट कीमती है। इसलिए उनके लिए समय निकालना आसान नहीं है। अगर यह उनके लिए उचित नहीं है, तो आइए इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दें। कोई मनमुटाव नहीं। अब से मैं उनसे समय नहीं माँगने वाला हूँ।”
इस संदेश से पहले और बाद में मुझे कई सत्रों के लिए समय मिला, लेकिन हर साक्षात्कार में उनसे पूरी जानकारी निकलवाना बहुत मुश्किल था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यह अध्ययन कुछ साल पहले शुरू क्यों नहीं किया, जब उनका समय प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान

होता, भले ही वे हमेशा से ही दिन में 18-19 घंटे काम करते रहे हों। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और साझा करने के लिए इतने समृद्ध अनुभव हैं, यह दुख की बात है कि अब तक किसी ने भी उन्हें जानने की कोशिश नहीं की है।

अपनी "धर्मनिरपेक्ष" साख का प्रदर्शन करने के लिए वही पुराने घिसे-पिटे सवाल पूछने के बजाय, गंभीरता से उनकी बात सुनकर कुछ हद तक सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।
मोदी जी के कार्यशैली और कार्यालय के बारे में कुछ उल्लेखनीय बातें हैं, जिनमें से मैं फिलहाल निम्नलिखित बातें साझा करना चाहूंगा: वे समय के पाबंद हैं। अधिकांश राजनेताओं के विपरीत, मोदी जी लोगों को अपने कार्यालय में इंतज़ार नहीं करवाते। अगर मुझे शाम 4 बजे बुलाया जाता, तो मुझे तय समय के कुछ ही मिनटों के भीतर अंदर बुला लिया जाता। सचिवालय में हुई एक बैठक को छोड़कर, हमारी सभी बैठकें उनके आवास के बगल में स्थित उनके कार्यालय में हुईं। अधिकांश मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों और घरों के विपरीत, मोदी जी के कार्यालय में उनसे मिलने के लिए लोगों की लंबी या छोटी कतारें नहीं लगतीं। सभी को तय समय के कुछ ही मिनटों के भीतर अंदर बुला लिया जाता है। उनके कार्यालय-सह-आवास में न्यूनतम कर्मचारी हैं। सुरक्षा जांच के बाद, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास केवल एक या अधिकतम दो लोगों को ही देखा। वे आगंतुकों को बिना मांगे ही पानी और चाय परोसते हैं। उनके कार्यालय से लगा हुआ एक छोटा सचिवालय है, लेकिन वह इतना शांत और कम लोगों वाला है कि वहां कोई आवाज भी सुनाई नहीं देती। मैंने आज तक जितने भी उच्च पदस्थ व्यक्ति के कार्यालय देखे हैं, उनमें से यह सबसे शांत कार्यालय है।

एक और अनोखी बात यह है कि जिनसे भी मुलाकात का समय मिलता है, उन्हें मोदी से बिना किसी रुकावट के व्यक्तिगत रूप से मिलने का पूरा मौका मिलता है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, वे पूरी मुलाकात के दौरान फोन कॉल की अनुमति नहीं देते। कोई भी अधिकारी या सचिव उनकी बैठकों के बीच में नहीं आता। यह एक मानक प्रक्रिया है, चाहे वे किसी गरीब मछुआरे से मिल रहे हों, किसी स्कूल शिक्षक से, या अपने किसी विधायक या अधिकारी से। उनसे मिलने गए हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा रहा है: मोदी जितने समय तक उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, चाहे वह पांच मिनट हो या पांच घंटे, उस व्यक्ति को मोदी का पूरा ध्यान मिलता है।
जब मैं पहली बार नरेंद्र मोदी से मिला, तो मैं बहुत बीमार था, मुझे ज़ुकाम और असहनीय सिरदर्द था। इंटरव्यू के बीच में ही मुझे कहना पड़ा, "नरेंद्रभाई, कम से कम मुझे एक कप चाय तो दे दीजिए।" उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, "माफ़ कीजिए, ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं आतीं। यह दफ्तर तो सिर्फ़ काम के लिए है।" लेकिन उन्होंने मेरे लिए चाय ज़रूर मंगवाई। कुछ दिनों बाद मैंने मज़ाक में उनके निजी सचिव से कहा, "आपके मुख्यमंत्री तो वाकई मज़ेदार हैं, चाय तक नहीं देते!" तब से जब भी हम मिलते हैं, मुझे बिना मांगे ही मेरी पसंदीदा काली चाय मिल जाती है। दरअसल, उनके स्टाफ़ को भी यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे काली चाय पसंद है। एक बार मोदी के साथ मेरा साक्षात्कार सुबह 9 बजे तय था और मुझे हवाई अड्डे से सीधे उनके कार्यालय-सह-निवास जाना था। मुलाकात से एक दिन पहले, मुझे उनके ओएसडी का फोन आया, जिसमें उन्होंने मुझसे नाश्ते में क्या खाना चाहूँगा, यह पूछा। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन मैंने सोचा कि...
मोदी, मुसलमान और मीडिया 394

नामो ने मुझे नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था। जब मैं उनके कार्यालय पहुँचा, तो स्वागत कक्ष में ही मुझे चाय के साथ गुजराती व्यंजन परोसे गए। यह सोचकर कि मैं उनके साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन जब मैं साक्षात्कार के लिए अंदर गया, तो नाश्ते का कोई नामोनिशान नहीं था। जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने कहा कि मुझे लगा था कि मैं आपके साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो आपके स्वागत कक्ष में बैठकर खाना खाए। उनका जवाब था, "माफ़ कीजिएगा, मैं चतुर्मास के कारण व्रत रख रहा हूँ। वैसे भी, जब लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनके साथ भोजन नहीं करता। इसमें बहुत समय बर्बाद होता है।"
मोदी के कार्यालय में यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि सभी आगंतुकों को उनकी मुलाकात के इंतजार के दौरान स्वागत कक्ष में चाय और/या नाश्ता परोसा जाता है। यह आगंतुक की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना किया जाता है। यहां तक कि साधारण किसान या छात्र जो उनसे मिलने जाते हैं, उनके कर्मचारियों द्वारा उन्हें भी यही शिष्टाचार दिया जाता है।2 उनके पुराने मित्रों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। वे उनसे बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि उन्होंने कभी किसी को अपने घर पर रात के खाने या दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया है। चूंकि वे सुबह के शुरुआती घंटों तक लगातार काम करते हैं, इसलिए मेहमानों के स्वागत का समय नहीं होता। अधिक से अधिक, उनके मित्र उनके साथ हल्का नाश्ता या फल साझा कर पाते हैं जो वे घर से लाते हैं।
अगर मैं किसी और राजनेता के बारे में लिख रहा होता, तो शायद मुझे दावतों और भोज के कई निमंत्रण मिलते। लेकिन मोदी के साथ मुझे वही सम्मान मिला जो उनके कार्यालय में किसी भी जाने-माने या अनजान व्यक्ति को मिलता है।

मोदी के साथ मेरी 14-15 घंटे लंबी बातचीत, जो छह मुलाकातों में हुई, का सबसे यादगार पहलू यह था कि मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं सुना—यहां तक कि तीस्ता सेतलवाद या तरुण तेजपाल जैसे लोगों के बारे में भी नहीं, जिन्होंने सालों से उनका पीछा किया है। उन्होंने बस इतना कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़े। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया।” चुनाव प्रचार के दौरान इतने आक्रामक दिखने वाले व्यक्ति से मुझे इस तरह के संयम की उम्मीद नहीं थी।
जो लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनमें से अधिकांश का कहना है कि वे बेहद कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, जो चुनावी सभाओं में उनके द्वारा दिखाए जाने वाले आक्रामक लड़ाकू के बिल्कुल विपरीत हैं। यहां तक कि जब वे मुझसे अपने साथ हुई अनगिनत अग्निकांडों और उन पर लगाए गए अपमानों के बारे में बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया।

2. पटना के एक अज्ञात मुस्लिम छात्र के स्वागत का विवरण देने के लिए,
ट्विटर के माध्यम से नमो से मिलने का समय मांगने वाले सुल्तान अलीमुद्दीन ने लिखा: “
नरेंद्र मोदी को मेरा ट्वीट,” मानुषी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया, http://www.manushi.in/articles.php? articleId=1750#.Uw3cNPSSxJM.
395 उपसंहार

एक समय ऐसा था जब उनकी आवाज़ में बेचैनी, आत्मदया या क्रोध झलकता था। लेकिन सभी के अनुसार, वे कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि

गुजरात में अपने द्वारा किए गए नवाचारों के बारे में बात करते समय उनका चेहरा चमक उठता है। वे कहते हैं कि उनके जीवन का ध्येय नकारात्मकता का मुकाबला सकारात्मक कार्यों से करना है, न कि लोगों द्वारा पहुँचाए गए नुकसान पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि वे अक्सर अपनी जनसभाओं में कहते हैं, "जितना अधिक कीचड़ आप मुझ पर फेंकेंगे, उतना ही कमल (भाजपा का चिन्ह) खिलेगा। जब लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, तो मैं उनका उपयोग पुल बनाने या सीढ़ी बनाने के लिए करता हूँ ताकि मैं दूसरों तक पहुँच सकूँ या ऊँचाई पर चढ़ सकूँ।"
उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बारे में भी कोई बुरा-भला नहीं कहा, यहाँ तक कि अहमद पटेल के बारे में भी नहीं, जो उनके मुख्य विरोधियों में से एक रहे हैं और मोदी के उत्पीड़न के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। वास्तव में, मोदी ने उस समय के बारे में गर्मजोशी से बात की जब उनके और पटेल के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि पटेल अक्सर मोदी को दिल्ली स्थित अपने घर पर गुजराती भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। इसी तरह, मैंने केशूभाई या दिल्ली के किसी भी नेता के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं सुना, जिन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनके उदय को रोकने की पूरी कोशिश की है। वास्तव में, मोदी ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा, "आप मुझे भाजपा के आंतरिक मामलों या पार्टी में मेरे किसी भी सहयोगी के बारे में बात करने के लिए राजी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि पत्रकारों को यह पसंद नहीं है। लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व के इस अंतर्निहित पहलू को बदलने वाला नहीं हूँ।" चूंकि मानुषी के संपादक के रूप में मेरी यह स्थापित प्रथा रही है कि मैं जिसका भी साक्षात्कार लेता हूं, उसे उसके नाम से प्रकाशित होने वाली सामग्री का पूरा पाठ भेजता हूं, इसलिए मैंने नामो से अपने साथ हुई लंबी वीडियो-रिकॉर्ड की गई बातचीत के पूरे अनुवाद को

पढ़ने का अनुरोध किया ताकि पांडुलिपि की सटीकता की जांच की जा सके। उनका जवाब था, “अगर मैं इसकी जांच करता हूं, तो आप जो भी प्रकाशित करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी आपकी ही रहे। मैं दूसरों के काम में दखल देने में विश्वास नहीं रखता।”
इसका अप्रत्यक्ष संदेश यह था, 'अगर आप मेरे बारे में अच्छा लिखते हैं तो मुझसे कोई एहसानमंद होने की उम्मीद न करें, ठीक वैसे ही जैसे अगर आप मेरे बारे में बुरा लिखते हैं तो मैं भी आपको बुरा नहीं मानूंगा। आप अपना काम करें, जैसा आपको ठीक लगे, मैं अपना काम कर रहा हूं। किसी भी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है।'

स्वीकृतियाँ

यह पुस्तक 1 कभी नहीं लिखी जाती यदि गुजरात के मेरे अध्ययन ने मुझे इस बात के पर्याप्त प्रमाण न दिए होते कि नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों को भड़काने के दोषी होने या अल्पसंख्यक विरोधी होने से बहुत दूर, वास्तव में हिंसा को शांत करने और गुजरात को बांटने वाली सांप्रदायिक और जातिगत खाई को पाटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त किए जाने से गोधरा कांड के बाद के गुजरात के मेरे अपने अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को और बल मिला। देश एसआईटी टीम का ऋणी है कि उन्होंने हर तरह के राजनीतिक दबावों और यहां तक कि बदनामी का भी सामना किया, ताकि उन्हें रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए मजबूर न किया जा सके।
अगर सोनिया कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों, विशेष रूप से सीपीएम में उसके साथियों ने नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द एक पूरी तरह से राक्षसी छवि गढ़ने के लिए सबसे खतरनाक रणनीति तैयार करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दिमाग का इस्तेमाल न किया होता, तो यह किताब कभी लिखी ही न गई होती।
अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों में मोदी से वास्तविक मुद्दों पर राजनीतिक रूप से लड़ने का साहस और ईमानदारी होती, बजाय इसके कि वे अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को चरित्र हनन और अप्रत्यक्ष आरोपों के जरिए नष्ट करने के लिए भाड़े के गुंडों का इस्तेमाल करें, जिसका एकमात्र उद्देश्य गुजरात में उनकी सरकार को गिराना और केंद्र में उनके सत्ता में आने से रोकना था, तो यह किताब कभी नहीं लिखी जाती।

यह किताब कभी लिखी ही नहीं जाती अगर भारत के प्रमुख राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा माफिया गतिविधियों और हर तरह के अपराधों को छिपाने के लिए "धर्मनिरपेक्षता" की बयानबाजी का इस्तेमाल न किया गया होता; अगर "धर्मनिरपेक्ष" होने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 12 वर्षों से मोदी के खिलाफ जहर उगलने को अपना मुख्य काम न बनाया होता।
अगर कांग्रेस-सीपीएम गठबंधन ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सबसे भ्रष्ट तत्वों के साथ-साथ भाजपा और आरएसएस के कुटिल तत्वों के साथ हाथ मिलाकर अपनी चालें न चली होतीं, तो यह किताब कभी नहीं लिखी जाती।

1. यह पुस्तक मोदिनामा लेख श्रृंखला की निरंतरता है जिसे मैंने प्रकाशित किया था।
गुजरात की अपनी शुरुआती यात्राओं के बाद मैंने मानुषी वेबसाइट (www.manushi.in) बनाई। यह अभी निर्माणाधीन है और जल्द ही मोदी शासन के तहत गुजरात पर कम से कम एक, या शायद दो और पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी।
397 आभार

एक ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा जिसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मोदी के शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के बीच की खाई को पाटने के दृढ़ संकल्प से उनका खतरा महसूस करना उनकी राजनीति के असली चरित्र को उजागर करता है और इस खेल का पर्दाफाश करना अनिवार्य बनाता है।
अगर प्रिंट मीडिया और टीवी पत्रकारों में सबसे "प्रख्यात" लोग कांग्रेस-सीपीएम गठबंधन द्वारा मोदी के खिलाफ रची गई बदनामी की मुहिम के बेशर्म लाउडस्पीकर न बन गए होते, तो मुझे 2002 के बाद के

गुजरात का यह अध्ययन करने की प्रेरणा न मिलती; अगर 24x7 टीवी समाचार चैनलों ने आम नागरिकों को यह देखने का मौका न दिया होता कि कैसे राजनीतिक चर्चा को विकृत किया जाता है और पक्षपातपूर्ण एजेंडों को सम्मानजनक बनाया जाता है; अगर पिछले 12 वर्षों से उन्मादी टीवी एंकरों द्वारा नफरत भरे नारों की सनक ने व्यापक आक्रोश पैदा न किया होता और मुझे उनके इस पागलपन के मूल कारणों की पड़ताल करने के लिए मजबूर न किया होता, तो मुझे 2002 के बाद के गुजरात का यह अध्ययन करने की प्रेरणा न मिलती।
अगर गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों का दावा करने वाले कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी के कई प्रतिनिधियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द एक भयावह और भय-भरी राजनीति न रची होती, तो मैं अपना सारा काम छोड़कर 2002 के बाद के गुजरात के अध्ययन को अपना मुख्य केंद्र न बनाता। ये लोग रोज़ाना मोदी पर कीचड़ उछालकर भारत में सबको यह यकीन दिलाना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई दुष्ट व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। इन भ्रष्ट नेताओं ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
अगर मैंने अकादमिक जगत के कुछ प्रमुख लोगों को "सांप्रदायिकता" से लड़ने के बहाने सुनियोजित दुष्प्रचार और सरासर झूठ के ज़रिए लोकतंत्र को कमज़ोर करने में स्वेच्छा से भागीदार बनते न देखा होता, तो मैं इस काम को इतने दृढ़ संकल्प के साथ हाथ में नहीं लेता। मेरी जानकारी के अनुसार, मोदी के पेशेवर विरोधियों में से किसी ने भी गुजरात में शोध करने में समय नहीं बिताया; कई तो राज्य में गए तक नहीं और फिर भी मोदी के खिलाफ़ अद्भुत जोश और दृढ़ विश्वास के साथ लिखते और बोलते रहे। उनमें से कुछ ने यह जानबूझकर किया, जबकि अन्य ने राजनीतिक रूप से सही होने के दबाव में आकर, शोध निधि, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निमंत्रण और प्रतिष्ठित

विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने वाले लोगों के साथ अपने करियर की संभावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया।
मेरा काम इस तथ्य से और भी कठिन हो गया कि उनमें से कई मेरे पुराने दोस्त और सहकर्मी हैं। लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह बहिष्कृत और बदनाम किया मानो मैंने उनके विचारों के विरुद्ध जाकर कोई जघन्य अपराध कर दिया हो।
मोदी, मुसलमान और मीडिया 398

सकारात्मक पक्ष की बात करें तो:
यह पुस्तक केवल इसलिए लिखी जा सकी क्योंकि ना मो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नफरत का पात्र बनने के बावजूद सकारात्मक ऊर्जा में दृढ़ रहने के लिए लगातार प्रयास करने का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है।
मैं गुजरात के उन सभी लोगों का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने 2002 के बाद के गुजरात के बारे में अपने विचार और अनुभव मेरे साथ साझा किए। इनमें किसान, व्यापारी, राजनेता, सरकारी अधिकारी, छात्र, पत्रकार, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, गृहिणी, नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र और सहयोगी शामिल हैं। इनमें से कई लोगों के उद्धरण इस पुस्तक में दिए गए हैं और अन्य लोगों के नाम आगामी पुस्तकों में उनके रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों के अंशों के साथ साझा किए जाएंगे। लेकिन भरूच जिले के बापू सादात अली, चैतन्य पटेल और उनके पिता चंद्रकांत पटेल, बड़ौदा के प्रोफेसर गुणवंत शाह और पीयूष पटेल; राजकोट के बृजेश पटेल, मुकुल जानी, जतिन संघानी और किरीटभाई; जूनागढ़ के दिव्याकांत, सिराजभाई और वहाबभाई; गोधरा के अहमदभाई सिंधी, गिर गाँव के यूसुफभाई, मुंद्रा बंदरगाह के पास द्रुब गाँव के हुसैनभाई, दोरदो के मियां हुसैन, अहमदाबाद के विष्णु पंड्या और किशोरभाई मकवाना—विशेष उल्लेख के पात्र हैं क्योंकि उनकी

औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत मेरे काम के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हुई।
मैं गुजरात सरकार के उन विभिन्न अधिकारियों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मुझे नमो के साथ काम करने के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए।
मैं गुजरात दंगों पर एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए www.gujaratriots.com का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने इस ब्लॉग को इसके भावनात्मक लहजे के कारण महज़ प्रचार सामग्री समझकर खारिज कर दिया था। लेकिन जब मैंने इसमें दिए गए समकालीन समाचार पत्रों की रिपोर्टों के लिंक से तथ्यों की जाँच शुरू की, तो मुझे इस युवा छात्र (जो गुमनाम रहना पसंद करता है) के अथक प्रयासों की सराहना हुई, जिसने गुजरात दंगों के पीछे की सच्चाई को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के लिए समकालीन समाचार रिपोर्टों को संकलित और विश्लेषण किया था।
मैं इस अवसर पर विकासशील समाजों के अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरे कई सहयोगियों की घोर शत्रुता के बावजूद मुझे 2002 के बाद के गुजरात का अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि सीएसडीएस शुरू से ही मोदी-विरोधी अभियानों का गढ़ रहा है। सीएसडीएस के संस्थापकों ने बौद्धिक स्वतंत्रता की एक मजबूत विरासत छोड़ी है, जिसने मुझे इस और कई अन्य विषयों पर मेरे राजनीतिक रूप से अप्रचलित विचारों के बावजूद केंद्र में बने रहने का अवसर दिया। मेरी सबसे पुरानी सहकर्मी प्रभा तिवारी को मेरा विशेष धन्यवाद, जो पिछले 20 वर्षों से मेरे लिए शक्ति और समर्थन का स्तंभ रही हैं। विभिन्न 399 आभारों के माध्यम से

होने, राजनीतिक शुद्धता को परिभाषित करने का एकाधिकार जताने वालों के बौद्धिक आतंक के सामने अडिग रहने, निंदा से विचलित न होने और आवश्यकता पड़ने पर अकेले खड़े रहने की शक्ति दी।

लेखक के बारे में

मधु पूर्णिमा किश्वर विकासशील समाजों के अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर और सीएसडीएस में भारतीय अध्ययन परियोजना की निदेशक हैं। वे 1978 में शुरू हुई 'मानुषी' - महिलाओं और समाज पर एक पत्रिका की संस्थापक संपादक भी हैं। मानुषी का मुद्रित संस्करण 2008 में ऑनलाइन संस्करण में परिवर्तित हो गया। (देखें www.manushi.in)। वह मानुषी संगठन की संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, जो लोकतांत्रिक सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है तथा सभी के, विशेषकर महिलाओं के मानवाधिकारों को मजबूत करती है। किश्वर मानुषी संगठन के साथ अपने काम को पेशेवर प्रतिबद्धता के बजाय "प्रेम का श्रम" मानती हैं। मानुषी संगठन का प्रबंधन एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

सीएसडीएस में उनका काम और मानुषी के साथ उनका प्रेमपूर्ण प्रयास, दोनों ही हमारे समाज के सामने आने वाली विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रभावी समाधान खोजने पर केंद्रित हैं। वे धैर्यपूर्वक अध्ययन, निष्पक्ष दृष्टिकोण, संबंधित लोगों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और जागरूक सक्रियता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं। वे किसी भी विचारधारा के जाल में फंसने से बचती हैं और सत्य, करुणा और अहिंसा पर आधारित राजनीति को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी /संपादित की हैं: □ उत्साही सुधारक, घातक कानून, सेज पब्लिशर्स, (2008)। □ लोकतंत्र को गहरा करना: शासन और वैश्वीकरण की चुनौतियाँ।

भारत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2005। □ ऑफ द बीटन ट्रैक: भारतीय महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय पर पुनर्विचार,

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999। राष्ट्रवाद की
सेवा में धर्म और अन्य निबंध, ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1998। हिंदी में अनुवादित।
शीर्षक राष्ट्रवाद की चाकरी में धर्म, वाणी प्रकाशन, 2005।
(संपादित) द डिलेमा एंड अदर स्टोरीज़, विजयदान देथा, मानुषी
द्वारा
Prakashan, 1997.
 Gandhi and Women, Manushi Prakashan, New Delhi, 1986. (Also
(तेलुगु में प्रकाशित)।
 उत्तरों की तलाश में: मानुषी द्वारा भारतीय महिलाओं की
आवाज़ें। (सह-संपादित)
(रूथ वनिता के साथ), ज़ेड बुक्स, लंदन, 1984। भारत में महिला भक्त
कवयित्रियाँ, महिला रहस्यवादियों का जीवन और कविताएँ
6 ठीं से 17 वीं शताब्दी (रूथ वनिता के साथ सह-संपादित), मानुषी
प्रकाशन,
नई दिल्ली, 1989।

लेखक से madhukishwar@manushi.in या madhukishwar@csds.in पर संपर्क किया जा सकता है।